



सत्यमेव जयते



एक कदम स्वच्छता की ओर

रक्षा मंत्रालय

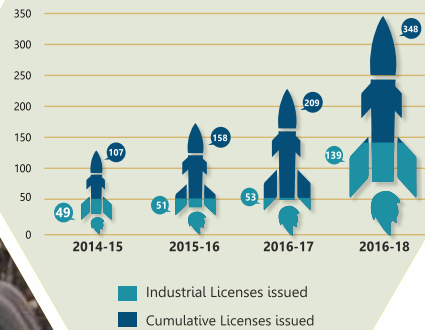
भारत सरकार



वार्षिक रिपोर्ट

2017-18

Growth of Private Defence Industry
(No. of Industrial Licenses Issued)





सी-17, ग्लोबमास्टर का सुखोई-30 एमकेआई फाइटरस द्वारा इस्कॉर्ट किया जाना

मुख पृष्ठ (दक्षिणावर्त)

- 1) तेजस हल्का युद्धक विमान (एलसीए): आकश में अपना प्रभुत्व दिखाते हुए
- 2) सब-सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण
- 3) निजी रक्षा उद्योगों का विकास
- 4) मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियान
- 5) मिसाइल फायरिंग-आईएनएस कोच्चि
- 6) हेलीकॉप्टर द्वारा सैनिकों को उतारा जाना

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18



सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

विषय सूची

1.	सुरक्षा परिवेश	1
2.	रक्षा मंत्रालय का संगठन और कार्य	7
3.	भारतीय सेना	15
4.	भारतीय नौसेना	29
5.	भारतीय वायु सेना	41
6.	भारतीय तटरक्षक बल	51
7.	रक्षा उत्पादन	59
8.	रक्षा अनुसंधान और विकास	83
9.	अंतर सेवा संगठन	103
10.	भर्ती एवं प्रशिक्षण	121
11.	पूर्व सैनिक पुनर्वास और कल्याण	143
12.	सशस्त्र बलों और सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग	157
13.	राष्ट्रीय कैडेट कोर	169
14.	विदेशों के साथ रक्षा सहयोग	177
15.	समारोह और अन्य कार्यकलाप	189
16.	सतर्कता यूनिटों के कार्यकलाप	201
17.	महिलाओं का सशक्तिकरण और कल्याण	209
18.	व्यापार के तरीकों का सरलीकरण, विकेन्द्रीकरण और उन्नयन करने की दिशा में प्रयास	219

परिशिष्ट

I	रक्षा मंत्रालय के विभागों के कार्यों की सूची	225
II	1 जनवरी, 2017 से आगे पदासीन मंत्री, सेनाध्यक्ष और सचिव	229
III	कार्यकारी सारांश	230
IV	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टें/ लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों के संबंध में वर्ष 2017-18 के लिए की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों की स्थिति	242

सुरक्षा परिवेश





सुरक्षा परिवेश

1.1 भारत की विदेश नीति और रक्षा रणनीति इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि परिवर्तनकारी राष्ट्रीय वृद्धि और विकास को प्राप्त करने के लिए एक शांतिपूर्ण और सक्षम माहौल का निर्माण हो। पश्चिम एशिया से लेकर हिन्द प्रशांत तक, क्षेत्रीय और वैश्विक विकास की एक जटिल और तेज गति की अप्रत्याशित परस्पर गतिविधि, भारत के सुरक्षा माहौल को आकार प्रदान करती है। सामरिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होकर भारत ने शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए साझेदार देशों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक रूपरेखाओं के लिए रचनात्मक संलग्नता का अनुसरण करते हुए परंपरागत और गैर-परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों के एक व्यापक वर्णक्रम को जारी रखा।

1.2 विगत वर्ष के दौरान बड़े भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक विकास हुए, जिनमें से कुछ हमारे तत्काल और विस्तारित पड़ोस के कुछ हिस्सों में निरंतर अस्थिरता और परिवर्तनशीलता का कारण

बने। प्रमुख शक्तियों के रणनीतिक अवस्थितियों का स्थानांतरित करके, इन अनिश्चितताओं ने प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता की ओर अग्रसर किया है। वर्ष के दौरान भारत ने सुरक्षा खतरों के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया और ऊर्जा सुरक्षा, सूचना और साइबर सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मुद्दों जैसे उभरते हुए पहलुओं सहित, अपनी सुरक्षा अनिवार्यताओं को भी सफलतापूर्वक संबोधित किया।

क्षेत्रीय सुरक्षा पर्यावरण

1.3 हिंद महासागर में भारत एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति रखता है। भारत के विदेशी व्यापार की एक बड़ी मात्रा और हमारी ऊर्जा आयात का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पश्चिम एशिया में उत्पन्न होता है और हिंद महासागर के माध्यम से होकर गुजरता है। हिंद महासागर समुद्री किनारों वाले सभी देशों के साथ-साथ भारत अपनी समुद्री सुरक्षा संबंधी कई क्षेत्रीय और बहुपक्षीय निकायों जैसे आईओआरए, एडीएमएम प्लस, आईओएनएस, रीकैप, एआरएफ आदि के साथ भी द्विपक्षीय संबंधों का एक

महत्वपूर्ण आयाम साझा करता है। भारत ने इस क्षेत्र और इससे आगे की समुद्री संलग्नता में काफी प्रगति की है। हमने सामुद्रिक पड़ोसियों को सूचना साझाकरण नेटवर्क स्थापित करने और सामुद्रिक अधिकार क्षेत्र की जागरूकता का साझा विकास करने में सहयोग करने हेतु प्रयासों की शुरुआत की है। एशिया और अफ्रीका के साथ भारत के विकास सहयोग के प्रमुख स्तंभों में समुद्री संपर्क एक है। भारत समविचार वाले देशों के साथ कार्य कर रहा है ताकि सामुद्रिक अधिकार क्षेत्र की अखंडता, पवित्रता और सुरक्षा को सुरक्षित रखा जा सके। एक तेजी से बढ़ते वैश्वीकरण की दुनिया में समुद्री व्यापार के बढ़ते महत्व को स्वीकारते हुए, भारत ने विशेष रूप से यूएनसीएलओएस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के आधार पर नौ-परिवहन और ओवर फ्लाइट, तथा निर्बाध व्यापार स्वतंत्रता का समर्थन किया है।

1.4 भारत के निकटतम पड़ोसियों की स्थिति काफी जटिल बनी हुई है। पाकिस्तान-अफगानिस्तान क्षेत्र में आतंकवाद में वृद्धि हुई है। श्रीलंका और नेपाल में, संघर्ष उपरांत ट्रांज़िशन प्रक्रियाओं की सफलता, सभी समुदायों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले एक समावेशी एजेंडे को विकसित करने के लिए राजनीतिक प्रणाली की क्षमता पर निर्भर करती है। बाहरी विकास सहायता के नए मानदंडों के माध्यम से इस क्षेत्र में आने वाले देशों की बढ़ती प्रवृत्ति, इन अपेक्षाकृत छोटे और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए चुनौती है। कुछ प्राप्तकर्ता देशों को ऐसी ऋण और सहायता से पहले ही प्रतिकूल परिणाम देखने को मिले हैं।

1.5 अफगानिस्तान में 'इस्लामी राष्ट्र' और तालिबान के उभरने से और बाहर के देशों द्वारा इसके समर्थन से इस क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति और भी जटिल हो गई है, और ये आतंकवाद और हिंसा को उकसाते रहे हैं। अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बल द्वारा अमेरिकी और नाटो सेना की मदद से, तालिबान और इस्लामी राष्ट्र के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तालिबान, हालाँकि अफगानिस्तान में अलग-अलग सैन्य और राजनैतिक उद्देश्यों का अनुसरण करता रहा है। अगस्त 2017 में अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया के लिए घोषित नई अमेरिकी नीति ने अफगानिस्तान में संचालन को और अधिक लचीला बनाने के संकेत दिये हैं। पाकिस्तान द्वारा अभी भी अफगानिस्तान में काम कर रहे इनके प्रतिनिधियों पर कार्रवाई किया जाना शेष है जिन्हें पाकिस्तान ने अपने यहाँ आश्रय दिया है।

1.6 बांग्लादेशी सुरक्षा बलों द्वारा की गई प्रभावी समन्वयित गतिविधियों की वजह से बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति में सुधार हो रहा है। हालाँकि, कट्टरता में वृद्धि का खतरा चिंता का एक कारण बना हुआ है जो बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति को प्रभावित कर सकता है, और इसका भारत के संभावित परिणामों पर भी असर पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की प्रगति जारी है। ऐतिहासिक संबंध, सांस्कृतिक जुड़ाव और सुरक्षा अनिवार्यता दोनों देशों को एक दूसरे के पारस्परिक लाभ के लिए आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु प्रेरित करती है। अगस्त 2017 के बाद से म्यांमार के राखीने राज्य से बड़ी संख्या में लोगों का बांग्लादेश में पलायन, बांग्लादेश में मानवतावादी संकट का कारण बना है।

1.7 भारत और भूटान परंपरागत रूप से अद्वितीय द्विपक्षीय संबंधों को साझा करते हैं, जो भरोसे और समझ पर आधारित हैं, और इन वर्षों में काफी परिपक्व हुए हैं। नियमित संबंधों और उच्च स्तरीय वार्ता की परंपरा ने दोनों देशों के विशेष संबंध को कायम रखा है। सुरक्षा मुद्दों और प्रभावी सीमा प्रबंधन में करीबी सहयोग द्विपक्षीय संबंधों की पहचान है। भूटान में लोकतांत्रिक संवैधानिक राजशाही की दिशा में एक क्रमिक और सुगम बदलाव हो रहा है और भूटान में आगामी संसदीय चुनाव अगले वर्ष 2018 में हैं।

1.8 भारत द्वारा मालदीव के क्षमता निर्माण में सहयोग जारी है। वर्ष 2016 में रक्षा सहयोग वार्ता की शुरुआत और चल रहे सैन्य कर्मचारियों की वार्ता ने रक्षा सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान किया है। द्वीप देशों में कट्टरता और बाहरी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव से क्षेत्रीय सुरक्षा के माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हाल के घटनाक्रम, जो देश में लोकतांत्रिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं हेतु खतरा पैदा करते हैं, सुरक्षा और स्थिरता के लिए दीर्घकालिक चुनौतियाँ भी पैदा करते हैं।

1.9 भारत और नेपाल साझी विरासत, सभ्यता, संस्कृति और लोगों के बीच परस्पर संबंधों में निहित एक विशेष और अनूठे संबंध को साझा करते हैं। दोनों देश करीबी सैन्य और सुरक्षा संबंधों को भी साझा करते हैं। संस्थागत द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से आपसी सुरक्षा मुद्दे पर भी नियमित रूप से नेपाल सरकार के साथ चर्चा की जाती है। नेपाल ने वर्ष 2017-18 में नए संविधान के तहत संघीय संसद, प्रांतीय असेंबली और स्थानीय निकायों के चुनावों को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है।

1.10 भारत और म्यांमार ने सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा म्यांमार के सफल दौरे और जुलाई 2017 में वरिष्ठ जनरल द्वारा भारत की यात्रा से संबंधों को और गति मिली है। उत्तरी राखीने में अराकन रोहिंग्या मुक्ति सेना द्वारा म्यांमार पुलिस चौकियों पर हमले और उत्तर म्यांमार सेना की कठोर प्रतिक्रिया के चलते अगस्त 2017 के बाद से म्यांमार के राखीने राज्य के लोगों ने भारी संख्या में पलायन कर लिया है। इस मानवतावादी संकट ने इस क्षेत्र के लिए गंभीर सुरक्षा प्रभावों को उत्पन्न कर दिया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन इन विस्थापित युवाओं का फायदा उठा सकते हैं। भारत ने मानवतावादी राहत सामग्री भेजी और वर्तमान संकट के लिए एक सौहार्दपूर्ण समाधान पाने में म्यांमार और बांग्लादेश की सहायता कर रहा है।

1.11 पाकिस्तान की राजनीतिक-सुरक्षा की स्थिति समस्याग्रस्त बनी हुई है। कानून प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियाँ मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए काफी हद तक उत्तरदायी नहीं मानी जा सकती और इनके द्वारा असंतुलित राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की अनिश्चित आर्थिक स्थिति और जुलाई 2017 में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सत्ता से निकाले जाने के बाद से राजनीतिक व्यवस्था में अपने आंतरिक स्थिरता हेतु गंभीर चुनौतियों को पैदा कर दिया है। पाकिस्तान की सेना राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों पर अपना कठोर नियंत्रण रखती है। पाकिस्तान, भारत के साथ एक टकराव संबंधी नीति का अनुपालन करना जारी रखे हुए है, जो कि मुख्यतः पाकिस्तानी सेना और आईएसआई द्वारा संचालित है। जम्मू और कश्मीर में अपने जेहादी संगठनों के माध्यम से यह छद्म युद्ध जारी रखे हुए है। पारंपरिक असमानता को दूर करने के लिए, पाकिस्तान ने अपने सैन्य आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। सीपीईसी के समझौते के तहत, चीन ने खुद को पाकिस्तान का सैन्य हार्डवेयर, तकनीकी-आर्थिक वित्तपोषक और राजनयिक समर्थन का प्राथमिक आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया है। पाकिस्तानी सेना अच्छे और बुरे आतंकवादियों के बीच अंतर रखने और भारत-विरोधी आतंकवादी समूहों को सामरिक सम्पदा के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निषिद्ध आतंकवादी संस्थाओं और व्यक्तियों को पाकिस्तान में राजनीतिक मुख्यधारा में आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

1.12 हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में श्रीलंका एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। विदेशी

संस्थाओं से उच्च ऋण घटक के साथ बढ़ता निवेश, चिंता का एक मुख्य विषय है। भारत ने रक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर श्रीलंका के साथ मिलकर काम करना जारी रखा, जिसमें सशस्त्र बलों की क्षमता का निर्माण करना और प्रशिक्षण शामिल था।

1.13 यद्यपि वर्ष 2017 में भारत-चीन के संबंध और अड़ि तक जटिल हो गए, एक विकास साझेदारी के समग्र संदर्भ के तहत भारत और चीन के बीच सामरिक वार्ता जारी रही, जिससे भारत और चीन के सीमावर्ती कर्मियों को डोकलाम क्षेत्र में शांतिपूर्ण रूप से हल करने में मदद मिली। दोनों पक्ष यह मानते हैं कि भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए एक आवश्यक पूर्व-आवश्यकता है। दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की है कि द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को उनके नेताओं के बीच की गई सहमति से निर्देशित किया जाना चाहिए, ताकि वैश्विक अनिश्चितता के समय में, भारत-चीन संबंध स्थिरता का एक कारक बन सके, और भारत और चीन के बीच उनके संबंध में, मतभेदों को विवाद बनाने की अनुमति नहीं मिले।

1.14 भारत के पूर्वी गतिविधि नीति ने हमारे विस्तारित पड़ोसियों के साथ भारत की शांतिपूर्ण उपस्थिति और एकजुटता के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति प्राप्त की है। क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के भारत के दृष्टिकोण (एसएजीएआर) ने सामुद्रिक अर्थव्यवस्था के पहलुओं हेतु अतिरिक्त क्षमता निर्माण, एचएडीआर, एसएआर और ईईजेड निगरानी को शामिल किया है। यह रक्षा कला क्षमताओं, जैसे कि युद्धपोतों के डिजाइन और निर्माण में, विकासशील देशों में भारत की उपलब्धियों का प्रदर्शन करके पूरक किया गया है। उत्तर कोरियाई परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों से उत्पन्न होने वाले कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति क्षेत्रीय और साथ ही वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। वैश्विक सुरक्षा के प्रति गंभीर खतरे के रूप में भारत ने उत्तर कोरिया द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों की निंदा की है और परमाणु और मिसाइल तकनीकों के प्रसार पर अपनी चिंता व्यक्त की है, जिनकी व्यापक तौर पर जाँच की जानी चाहिए।

1.15 जापान, मिसाइल रक्षा, बाह्य अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा के विशिष्ट संदर्भ में अपनी राष्ट्रीय रक्षा कार्यक्रम दिशानिर्देशों (एनडीपीजी) की समीक्षा कर रहा है। मालाबार अभ्यासों में जापानी भागीदारी, भारत-जापान सिविल परमाणु समझौते का

अनुसमर्थन, एशिया और अफ्रीका में संयुक्त विकास परियोजनाओं का पता लगाने और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में वृद्धि के लिए दोनों पक्षों के प्रयासों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत-जापान की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है।

1.16 हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं और बड़े भारतीय फैलाव की सुरक्षा के चलते, पश्चिम एशिया में सुरक्षा वातावरण भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष के दौरान सीरिया और यमन में जारी गृहयुद्ध ने प्रमुख खिलाड़ियों के बीच मतभेद को प्रकट किया गया है। ईरान और भारत की बीच चाबहर परियोजना के लिए हिस्सेदारी है जिसके माध्यम से गेहूँ की पहली खेप अफगानिस्तान को आपूर्ति की गई है। इराक में सुरक्षा बलों ने आईएस के खिलाफ अपने अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित दलों के साथ शांतिपूर्ण संवाद को प्रोत्साहित करना है। भारत इस क्षेत्र में कानूनी तौर पर स्थापित सरकारों का समर्थन करता रहा है।

1.17 भारत पिछले वर्ष शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का पूर्ण सदस्य बन गया। सभी पाँच मध्य एशियाई गणराज्यों से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और साथ ही साथ मजबूत सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारी भी है।

1.18 भारत और रूस ने परंपरागत रूप से रक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से मजबूत संबंध साझा किए हैं। यह संबंध ऐतिहासिक इंड्र-2017 के आयोजन के माध्यम से पिछले वर्ष जारी रहा, और नवंबर 2017 में व्लादिवोस्तोक से पहली बार ट्राई सर्विसेज संयुक्त व्यायाम और रक्षा सहयोग विस्तारित किए गए।

1.19 यूरोप में, आंतरिक और बाह्य कारक अभूतपूर्व चुनौतियाँ पैदा करते हैं। प्रवासन संकट पर आंतरिक विभाजन, आतंकवादी हमलों के बीच सुरक्षा की चुनौतियाँ, बढ़ती असमानता, झेनोफोबिया (विदेशी लोगों को पसन्द न करना) और नई राजनीतिक ताकतों का उदय यूरोपीय संघ के मूल मूल्यों के लिए चुनौती बनी हुई है।

1.20 भारत की अमेरिकी सामरिक भागीदारी ने उभरती वैश्विक व्यवस्था को बहुत महत्व प्रदान किया है। जून 2017 में प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा ने दोनों देशों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने और एक नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को कायम रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को

दोहराया है। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक संबंधों के साथ मिलकर भारत-अमेरिकी रक्षा साझेदारी में प्रगति हुई है। हिंद महासागर और व्यापक भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और नौ-परिवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रयास रहा है, और अमेरिका और अन्य भागीदारों के साथ भारत की संलग्नता के प्रमुख उद्देश्यों में से भी एक है।

आंतरिक सुरक्षा पर्यावरण

1.21 जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे सुरक्षा बलों के सतत प्रयासों के कारण, वर्ष के दौरान राज्य में हिंसा के स्तर में काफी कमी आई है, जिसमें पत्थर फेंकने की घटनाएँ हुई, और इसमें लगभग 55 प्रतिशत की कमी देखी गई। राज्य में खत्म किए गए आतंकवादियों की संख्या के संदर्भ में सुरक्षा बलों द्वारा पिछले पाँच वर्षों में यह सबसे सफलतम वर्ष रहा है। सरकार ने खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक को नियुक्त किया कि वे जम्मू और कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों और संबंधित व्यक्तियों के साथ वार्ता शुरू करें और इसे आगे बढ़ाएँ।

1.22 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति में भी वर्ष 2017 में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की हिंसा का भौगोलिक प्रसार वर्ष 2016 के 68 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017 में 58 प्रतिशत तक घट गया है। बेहतर सुरक्षा स्थिति में सुधार के परिणामों में बहुपक्षीय रणनीति, जिसमें सुरक्षा उपायों, विकास उपायों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और अधिकारों को सुनिश्चित करना आदि शामिल किया गया है। नक्सल प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बल की बड़ी उपस्थिति और सशस्त्र एलडब्ल्यूई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, आत्मसमर्पण, परित्याग और निष्कासन के माध्यम से स्थिति को बेहतर बनाने और हिंसा को कम करने में योगदान मिला है। कई विकास पहल, विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए सड़कों का निर्माण, मोबाइल टॉवर, कौशल विकास और वित्तीय समावेश आदि की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के अलावा आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि भी संचालित किए जा रहे हैं।

1.23 वर्ष 2017 में पूर्वोत्तर राज्यों की समग्र सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। क्षेत्र में उग्रवाद संबंधी घटनाओं की संख्या में

वर्ष 2016 (2016—484, 2017—308) की तुलना में 36 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 1997 से लेकर वर्ष 2017 में सबसे कम संख्या में विद्रोह की घटनाएं हुईं। इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों के मारे जाने की घटनाओं में भी 17 (2016) से घटकर 12 (2017) और आम नागरिकों के मारे जाने की घटनाओं में भी कमी 48 (2016) से 37 (2017) हो गई। इसी तरह अपहरण/अगवा करने की घटनाओं की संख्या में भी 40 प्रतिशत (2016—168, 2017—102) तक कमी आई है। वर्ष 2017 में काउंटर इंटरजेन्सी ऑपरेशंस के तहत 57 आतंकियों को निष्क्रिय कर दिया गया, 995 की गिरफ्तारी की गई और क्षेत्र में 432 हथियारों की बरामदी की गई। वर्ष 2013 की तुलना में, वर्ष 2017 के दौरान क्षेत्र में विद्रोहियों की घटनाओं में 58 प्रतिशत, नागरिकों की हताहतों की संख्या में 66 प्रतिशत तक, सुरक्षा बलों की मौत में 34 प्रतिशत तक और अपहरण/अगवा करने के मामलों में 67 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। जबकि सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में वर्ष 2017 में कोई विद्रोह प्रतिवेदित नहीं हुआ है, जबकि हिंसा के मामलों में असम में 56 प्रतिशत, नागालैंड में 67 प्रतिशत, मणिपुर में 28 प्रतिशत और मेघालय में 59 प्रतिशत

की कमी आई है। वर्ष 2017 में, मणिपुर राज्य में पूर्वी क्षेत्र की कुल घटनाओं का लगभग 54 प्रतिशत दर्ज किया गया और यह सबसे हिंसक राज्य बना रहा। अरुणाचल प्रदेश में वर्ष 2017 में हिंसक घटनाओं में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वार्ता/बातचीत की नीति के अनुसरण में, विभिन्न विद्रोही संगठनों ने सरकार के साथ संचालन (एसओओ) समझौतों में अपने आप को शामिल किया है और उनमें से कुछ ने सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किया है और कुछ ने अपने आप को भंग भी कर दिया है। परिणामस्वरूप, कई आतंकवादी संगठनों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया और समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। विद्रोहों को दबाने की निरंतर प्रक्रिया का संचालन कई संगठनों के खिलाफ जारी है, जैसे कि एनडीएफबी (Saoraigwra) समूह, जो हिंसक गतिविधियों में शामिल है। दिनांक 23.12.2014 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि के दौरान, एनडीएफबी/Saoraigwra के 1015 कैडर/लिकमैन को भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद की बरामदी के साथ गिरफ्तार किया गया है और 60 कैडर विरोधी विद्रोहियों के अभियानों को समाप्त कर दिया गया है।



रक्षा मंत्रालय का संगठन और कार्य





रक्षा मंत्रालय का संगठन और कार्य

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

2.1 स्वतंत्रता के बाद रक्षा मंत्रालय का गठन एक कैबिनेट मंत्री के अधीन किया गया था और प्रत्येक सेना को उसके अपने कमांडर-इन-चीफ के अधीन रखा गया। 1955 में, कमांडर-इन-चीफ का सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष तथा वायुसेनाध्यक्ष के रूप में पुनः नामकरण किया गया था। नवंबर, 1962 में रक्षा उपस्करों के अनुसंधान, विकास तथा उत्पादन संबंधी कार्य के लिए रक्षा उत्पादन विभाग का गठन किया गया था। नवंबर, 1965 में, रक्षा आवश्यकताओं के आयात प्रतिस्थापन के लिए योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए रक्षा पूर्ति विभाग बनाया गया। बाद में, इन दोनों विभागों को मिलाकर रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग बना दिया गया था। वर्ष 2004 में रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग का नाम बदलकर रक्षा उत्पादन विभाग रख दिया गया। 1980 में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग बनाया गया। वर्ष 2004 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया गया।

2.2 रक्षा सचिव, रक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और इसके अलावा, मंत्रालय के चारों विभागों के कार्यों में समन्वय बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

मंत्रालय और इसके विभाग

2.3 इस मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में नीति-निदेश बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजना है। मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के नीति-निर्देशों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए और अनुमोदित कार्यक्रमों का निष्पादन आबंटित संसाधनों के अंतर्गत किया जाए।

2.4 इन विभागों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:-

- (i) रक्षा विभाग, एकीकृत रक्षा स्टाफ, तीनों सेनाओं और विभिन्न अंतर सेवा संगठनों से संबंधित कार्य करता है। यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना मामलों, रक्षा नीति,

संसदीय मामलों, अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्यक्रमों के समन्वय संबंधी कार्य के लिए भी उत्तरदायी है।

- (ii) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं और यह विभाग रक्षा उत्पादन कार्यों, आयात किए जाने वाले सामान, उपकरणों और कलपुर्जों के देशीकरण, आयुध निर्माणी बोर्ड और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की विभागीय उत्पादन इकाइयों के बारे में योजना तैयार करने तथा उन पर नियंत्रण रखने से संबंधित कार्य करता है।
- (iii) रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं। इस विभाग का कार्य सैन्य उपकरणों और संभारतंत्र से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देना और तीनों सेनाओं द्वारा अपेक्षित साज-समान के अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यों के लिए योजनाएं तैयार करना है।
- (iv) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं और यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास, कल्याण तथा पेंशन संबंधी सभी मामलों को देखता है।

2.5 रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों और वित्त प्रभाग द्वारा निपटाई जाने वाली मदों की सूची इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट-I** में दी गई है।

2.6 इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान रक्षा मंत्रालय के मंत्रियों, सेनाध्यक्षों और मंत्रालय के विभागों के सचिवों और सचिव (रक्षा वित्त)/वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं) के पदों पर कार्यरत अधिकारियों से संबंधित सूचना इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट-II** में दी गई है।

मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ

2.7 कारगिल समीक्षा समिति पर मंत्रिसमूह की सिफारिशों के आधार पर मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ 1 अक्टूबर, 2001 को अस्तित्व में आया। सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष के समग्र नियंत्रण और कमान में यह संगठन सेनाओं के बीच सम्बद्धता तथा सहक्रियाशीलता प्राप्त करने के लिए इस मुख्यालय की स्थापना की गई है। इसके बनने से लेकर अब तक, इस मुख्यालय ने संयुक्त और एकीकृत योजना, आसूचना का समन्वय और रक्षा आपदा

प्रबंधन समूहों के जरिए मानवीय सहायता और आपदा राहत तथा अधिप्राप्तियों को प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत करने/सरल बनाने में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले वर्ष में इस मुख्यालय की महत्वपूर्ण उपलब्धियां आगे की पैराओं में दी गई हैं।



अंडमान एवं निकोबार त्रि-सेना कमान में रक्षामंत्री

2.8 **एकीकृत कमांडर्स कन्फ्रेंस-2017** : एकीकृत मुख्यालय रक्षा स्टाफ ने 10 और 11 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में एकीकृत कमांडर्स कन्फ्रेंस (यूसीसी) का आयोजन किया। यह सम्मेलन तीनों सेनाओं के बीच सभी संयुक्त मुद्दों पर उच्चस्तरीय वार्ता हेतु प्लेटफार्म मुहैया कराता है। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेनाओं के अध्यक्ष तथा रक्षा मंत्रालय एवं तीनों सेनाओं के संगठनों/संस्थाओं के अन्य वरिष्ठ सैन्य अफसरों एवं सिविलियन अधिकारियों ने भाग लिया।



2.9 **सेनाध्यक्षों की समिति द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के लिए विदाई समारोह एवं प्रतिभोज का आयोजन**: महामहिम राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने पर उनके सम्मान में सेनाध्यक्षों की समिति ने 21 जुलाई, 2017 को एक विदाई समारोह एवं प्रतिभोज की मेजबानी की। उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य

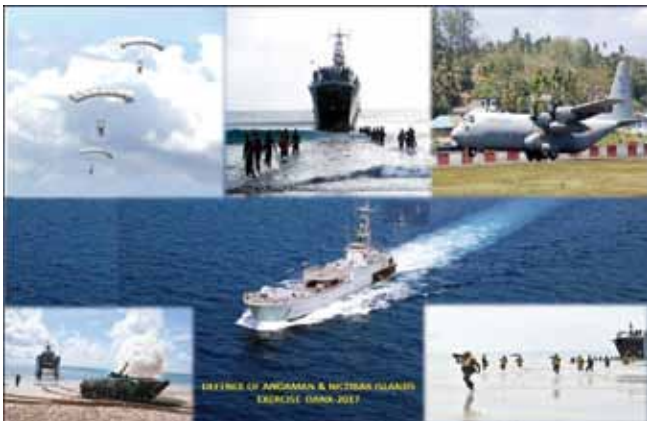
मंत्री, तीनों सेनाध्यक्ष तथा सैन्य सेवाओं और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ सैन्य एवं सिविल अफसरों ने इसमें भाग लिया।



2.10 **अभ्यास इंद्र:** भारत रूस रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाते हुए भारत और रूस की तीनों सेनाओं का प्रथम संयुक्त अभ्यास इंद्र 19-29 अक्तूबर, 2017 तक रूस के पूर्वी सैन्य जिले में आयोजित किया गया।



2.11 **अंडमान एवं निकोबार का रक्षा अभ्यास (डीएनएक्स):** यह अभ्यास अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं आस-पास के जल क्षेत्रों में नवम्बर, 2017 में चलाया गया। देश के मुख्य भू-भाग और द्वीपों पर तैनात तीनों सेनाओं के स्टेशनों की आस्तियों और कार्मिकों ने इस अभ्यास में भाग लिया।



2.12 **विशेष संयुक्त बलों के लिए प्रशिक्षण शिविर:** विशिष्ट संक्रियाओं के क्षेत्र में सेनाओं के बीच एकात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह शिविर मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वावधान में प्रतिवर्ष चलाया जाता है। यह अभ्यास अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इस वर्ष नवम्बर, 2017 में किया गया।

2.13 **मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) अभ्यास:** प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अभ्यास करने तथा उसकी तैयारी का आंकलन करने हेतु सशस्त्र बलों के साथ-साथ सिविल प्रशासनों एवं केन्द्रीय अभिकरणों के सभी पणधारियों की भागीदारी से हैदराबाद, शिलाँग और कारवार में तीन संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास चलाए गए।



2.14 **विदेशी भाषा विद्यालय:** नई दिल्ली स्थित विदेशी भाषा विद्यालय को सशस्त्र बलों के लिए प्रशिक्षण संस्थान के रूप में दिनांक 4 मई, 2017 को एकीकृत मुख्यालय रक्षा स्टाफ के अंतर्गत कर दिया गया।

2.15 **सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस:** हमारे पूर्व सैनिकों के प्रति श्रद्धा और प्रतिबद्धता के रूप में 14 जनवरी, 2018 को दूसरा सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली, इलाहाबाद, मुंबई, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, लखनऊ, जालंधर और जयपुर में रैलियां आयोजित की गईं। यह रैली पूर्व सैनिकों के साथ वार्ता करने और उनकी पेंशन एवं कल्याण के लिए सेना मुख्यालयों एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में उन्हें जानकारी देने के लिए एक संपर्क कार्यक्रम होता है। इस अवसर पर एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख ने तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों के साथ अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण भी किया।

सशस्त्र बल अधिकरण

2.16 सरकार ने संघ की सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को शीघ्रता से न्याय देने की व्यवस्था करने के लिए तीनों सेनाओं (सेना, नौसेना और वायुसेना) के सदस्यों के सेवा संबंधी मामलों से संबंधित हिदायतों और विवादों तथा कोर्ट मार्शल के निर्णयों से उत्पन्न अपीलों के अधिनिर्णय के लिए एक सशस्त्र सेना अधिकरण की स्थापना की है।

2.17 वर्तमान में, दिल्ली स्थित प्रधान पीठ सहित चेन्नै, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, कोच्चि, गुवाहाटी, जबलपुर और श्रीनगर, मुंबई स्थित क्षेत्रीय पीठें कार्यरत हैं।

सीमा सड़क संगठन

2.18 सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) एक सड़क निर्माण कर्ता संगठन है जो सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। 1960 में दो परियोजनाओं के साथ अपना अभियान शुरू करके अब बीआरओ की परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। बीआरओ की नौ परियोजनाएं उत्तर-पश्चिम भारत में (जम्मू और कश्मीर में 4, हिमाचल प्रदेश में 2, उत्तराखंड में 2 और राजस्थान में 1), पूर्वी भारत में आठ (सिक्किम में 1, अरुणाचल प्रदेश में 4, नागालैंड में 1, मिजोरम में 1 और त्रिपुरा में 1) तथा भूटान में 1 परियोजना स्थापित है। इनमें से त्रिपुरा स्थित एक परियोजना को फिलहाल स्थगित रखा गया है।

2.19 बीआरओ की रक्षा आवश्यकताओं के मद्देनजर मुख्यतः सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य सौंपा जाता है। इन सड़कों का विकास और रखरखाव विभिन्न शीर्षों के तहत मुहैया कराई गई निधियों के जरिए किया जाता है।

2.20 मंत्रिमंडल सचिवालय ने सीमा सड़क विकास मंडल और सीमा सड़क संगठन से संबंधित सभी मामलों को रक्षा मंत्रालय के अधीन लाने के लिए दिनांक 9 जनवरी, 2015 की अधिसूचना के तहत भारत सरकार कार्य आबंटन नियमावली, 1961 को संशोधित किया है। अब बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठन है।

2.21 सीमा सड़क संगठन ने कठिन, पृथक और दुर्गम भूभाग पर प्रतिकूल जलवायु वाली परिस्थितियों में सड़क निर्माण करने और उसका रखरखाव करने वाली एकमात्र एजेंसी के रूप में ख्याति अर्जित की है। बीआरओ ने देश के इन क्षेत्रों में लगभग

52,000 किमी सड़कों, 49,200 मी. लंबाई वाले 598 महत्वपूर्ण स्थायी पुलों और 19 एयरफील्डों का निर्माण किया है। वर्तमान में, 852 सड़कों (38118 किमी.) पर कार्य कर रहा है जिनमें नए निर्माण, ऋसगल लेन से डबल लेन में बदलने (22,803 किमी. लंबी 530 सड़कों पर) का कार्य और लगभग 18803 किमी. सड़कों का रखरखाव शामिल है। 852 सड़कों में 61 भारत-चीन सीमा सड़क शामिल है। 27 भारत-चीन सीमा सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और अन्य 23 सड़कों से उनको प्रारंभिक रूप से जोड़ा जा चुका है। बीआरओ पांच एयरफील्डों का रखरखाव भी कर रहा है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल स्थित रोहतांग सुरंग (8.80 किमी) और सिक्किम स्थित थेंग सुरंग (0.578 किमी.) भी निर्माणाधीन है। इन सुरंगों का लक्ष्य हासिल हो चुका है। थेंग सुरंग को वर्ष 2017-18 में पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

रक्षा (वित्त)

2.22 रक्षा मंत्रालय में वित्त प्रभाग, वित्तीय प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का कार्य देखता है। इस प्रभाग के प्रमुख सचिव (रक्षा वित्त)/ वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं) हैं और यह रक्षा मंत्रालय के साथ पूर्णतः एकीकृत है।

2.23 शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए, रक्षा मंत्रालय को वर्धित वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। इन शक्तियों का प्रयोग वित्त प्रभाग की सहमति से किया जाता है। रक्षा अधिप्राप्ति मामलों के संबंध में इन शक्तियों के कार्यान्वयन की पारदर्शिता और निर्धारित नीति संबंधी मार्ग-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया तथा रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

2.24 वित्त प्रभाग रक्षा मंत्रालय के रक्षा सेवा प्राक्कलनों, सिविल प्राक्कलनों तथा रक्षा पेंशनों से संबंधित प्राक्कलनों को तैयार करता है तथा उसकी मानीटरी करता है। रक्षा सेवा प्राक्कलनों से संबंधित वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 के वास्तविक व्यय और 2017-18 के लिए संशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान के ब्यौरे तालिका संख्या 2.1 में दिए गए हैं तथा इससे संगत ग्राफ/चार्ट इस अध्याय के अंत में दिया गया है।

2.25 रक्षा मंत्रालय के कार्यकरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की एक अद्यतन रिपोर्ट का सारांश इस वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्ट-III पर दिया गया है।

2.26 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों/ लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट की दिनांक 31.12.2017 के अनुसार स्थिति इस वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्ट-IV पर दी गई है।

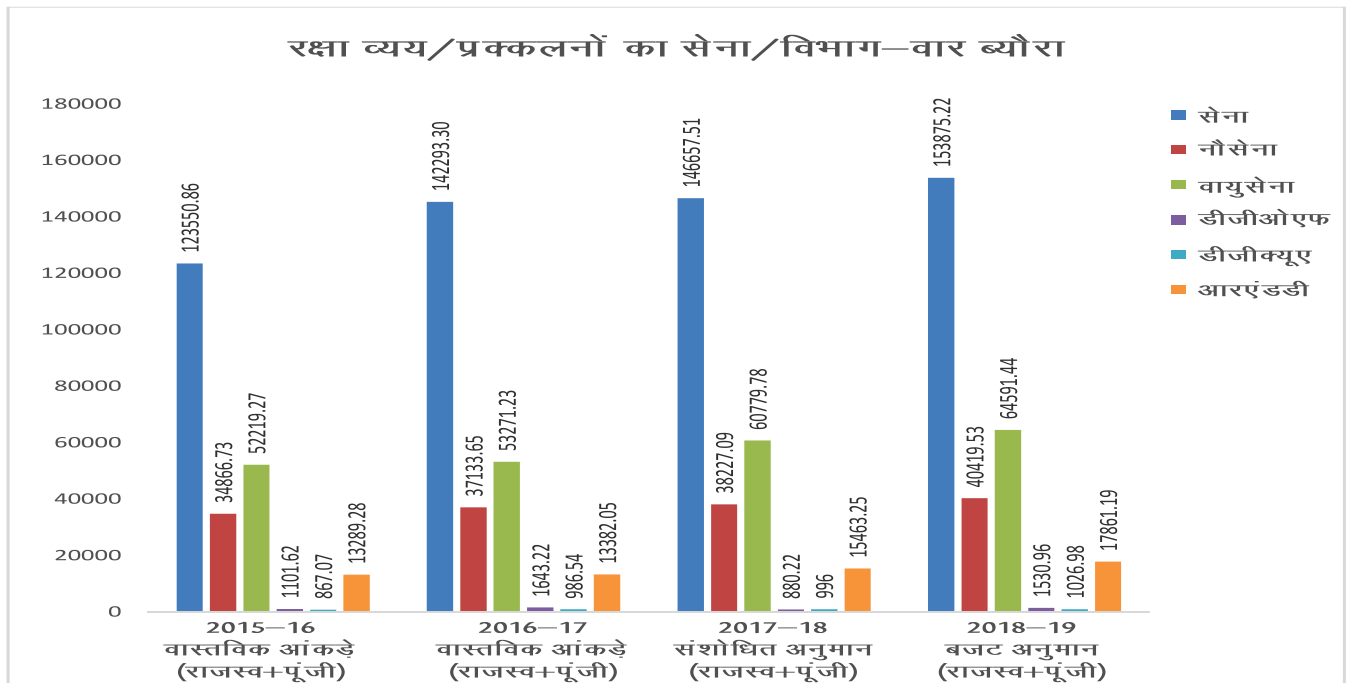
सारणी 2.1

रक्षा व्यय का सेना/विभाग-वार ब्यौरा

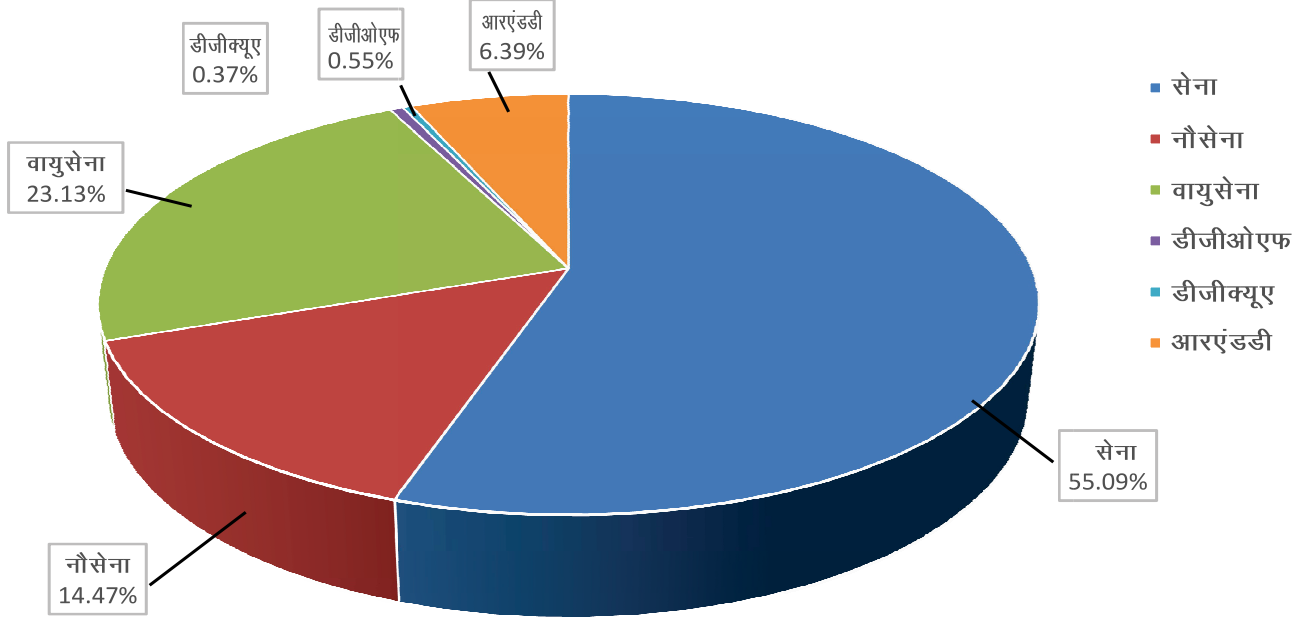
(करोड़ रु. में)

	2015-16 वास्तविक (राजस्व+पूंजी)	2016-17 वास्तविक (राजस्व+पूंजी)	संशोधित प्राक्कलन 2017-18 (राजस्व+पूंजी)	बजट प्राक्कलन 2018-19 (राजस्व+पूंजी)
सेना	123550.86	142293.3	146657.51	153875.22
नौसेना	34866.73	37133.65	38227.09	40419.53
वायुसेना	52219.27	53271.23	60779.78	64591.44
आयुध निर्माणी महानिदेशालय	1101.62	1643.22	880.22	1530.96
गुणता आश्वासन महानिदेशालय	867.07	986.54	996	1026.98
अनुसंधान तथा विकास	13289.28	13382.05	15463.25	17861.19
योग	225894.83	248709.99	263003.85	279305.32

- डी जी ओ एफ - आयुध निर्माणी महानिदेशालय
डी जी क्यू ए - गुणता आश्वासन महानिदेशालय
आर एंड डी - अनुसंधान तथा विकास



कुल रक्षा प्राक्कलन 2018-19 (बजट प्राक्कलन) की प्रतिशतता के रूप में सेना/विभाग-वार आबंटन





भारतीय सेना





भारतीय सेना

3.1 लगातार बदलती वैश्विक भौगोलिक व राजनीतिक गतिविधियाँ अक्सर राष्ट्र के लिए कई सुरक्षा चुनौतियों को भी सामने लाती हैं। इन दृष्टिगत चुनौतियों का सामना करने के लिए तथा अपनी परिचालन तैयारियों/अवस्थितियों की समीक्षा करते हुए, इस पूरे वर्णक्रम में भारतीय सेना बाहरी ताकतों और आंतरिक खतरों से देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार और प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त संकट/प्राकृतिक आपदाओं के समय में प्रभावित लोगों को सहायता और मदद प्रदान करने में भी भारतीय सेना सबसे आगे रही है।

जम्मू एवं कश्मीर

3.2 घाटी की पूरी स्थिति नियंत्रण में है, हालाँकि पिछले वर्ष उरी हमलों के बाद शुरू हुई हिंसा जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल (एलसी) के साथ युद्ध विराम उल्लंघनों (सीएफवी) में भी विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफी वृद्धि देखी गई है। घुसपैठ के प्रयासों और दुश्मन द्वारा कुटिल कार्रवाई के मामलों में भी वृद्धि हुई है।

3.3 दूरदराज के इलाकों में, आतंकवादी सुरक्षा बल के ठिकानों और उनके काफिले जैसे कमजोर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। स्थानीय आबादी की भावनाओं का अलगाववादी और विरोधी तत्वों द्वारा जोश पैदा करने और लोकतांत्रिक संस्थानों को अस्थिर करने के लिए भावनात्मक शोषण किया जा रहा है। सोशल मीडिया अभियान द्वारा समर्थित क्रांतिकारी और आंदोलनशील गतिशीलता में वृद्धि ने भी सुरक्षा बलों के समक्ष नई चुनौतियाँ रख दी हैं।

3.4 राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की हालिया कार्रवाई के चलते हुर्रियत के दूसरे दल के नेतृत्व ने अपनी गतिविधि कम कर दी है और अपने परिचालन क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया है।

3.5 **युद्ध विराम उल्लंघन (सीएफवी):** जम्मू-कश्मीर में वास्तविक ग्राउंड स्थिति रेखा (एजीपीएल), लाइन ऑफ कंट्रोल (एलसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर युद्ध विराम आम तौर पर आयोजित किया जाता है। वर्ष 2016 में 18 सितंबर, 2016 को उरी आतंकवादी हमले के बाद, युद्ध विराम उल्लंघन की गति काफी

बढ़ गई और इस वर्ष भी यह लगातार जारी रही। वर्ष 2016 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर 228 युद्ध विराम उल्लंघन हुए थे और अब तक इस वर्ष (11 अक्टूबर, 2017 तक) 538 युद्ध विराम उल्लंघन हो चुके हैं। जहाँ आवश्यक हो, उचित और प्रभावी प्रतिशोध, पाकिस्तान द्वारा शुरू की गई युद्ध विराम उल्लंघन के विरुद्ध किया गया। युद्ध विराम उल्लंघन की घटनाओं को हॉटलाइन, प्लैग मीटिंग्स और सैन्य अभियानों के महानिदेशालय द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से लिया जाता है।

3.6 घुसपैठ: जम्मू-कश्मीर में छद्म युद्ध को बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के माध्यम से घुसपैठ करने हेतु आतंकवादियों का सक्रिय प्रशिक्षण और सहयोग सीमा के पार से जारी है। अपने स्वयं के काउंटर घुसपैठ ग्रिड के प्रभावों के चलते आतंकवादियों की घुसपैठ को लाइन ऑफ कंट्रोल पर कम करने में काफी सफलता मिली है, जैसा कि निम्नानुसार वर्णित है:

(क) **घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करना:** वर्ष 2017 में (13 नवंबर, 2017 तक) सेना ने 32 घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया, जिसके परिणामस्वरूप 58 आतंकवादी मारे गए (वर्ष 2016 में सेना ने 27 घुसपैठ की कोशिशों को विफल किया, जिसके परिणामस्वरूप 37 आतंकवादी मारे गए थे)।

(ख) **सफल घुसपैठ:** मल्टी एजेंसी सेंटर के आकलन के मुताबिक, वर्ष 2017 में 30 सितंबर, 2017 तक, 291 में से 80 आतंकवादी सफलतापूर्वक घुसपैठ कर चुके थे (वर्ष 2016 में 371 में से 119 आतंकवादी घुसपैठ में सफल थे)।

आंतरिक इलाकों में स्थिति:

3.7 कार्रवाई में मार गिराए गए आतंकवादी: वर्ष 2017 में सेना द्वारा कुल 151 आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया था। इस वर्ष आज की तिथि तक [14 जनवरी, 2018,] सुरक्षा बलों ने आंतरिक इलाकों से 2 आतंकवादियों का सफाया किया है।

3.8 निष्कर्ष: सेना ने मानव अधिकार के उल्लंघन के प्रति 'शून्य सहनशीलता' के साथ लोगों के अनुकूल कार्यों के माध्यम से राज्य में आतंकवाद का सामना किया है। यह प्रयास काउंटर घुसपैठ ग्रिड को और मजबूत बनाने और उनके नेटवर्क के जाल को तोड़ने के लिए सटीक खुफिया आधारित आपरेशनों का

संचालन करने के लिए होगा, जिसमें सिविल प्रशासन को इसकी रिट की स्थापना में मदद करने और जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता लाने के लिए एक बड़ा कदम था।

उत्तर पूर्व

3.9 वर्ष के दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाओं के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में सुरक्षा की स्थिति जटिल, प्रवाही और गतिशील बनी रही। सुरक्षा बलों द्वारा किए गए खुफिया आधारित कार्यों के साथ मिलकर सक्रिय दृष्टिकोण अपनाए जाने के परिणामस्वरूप विद्रोह-प्रवण क्षेत्रों में हिंसा के फैलने में काफी कमी आई है। विद्रोही समूहों के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा व्यापक कार्यवाही के सफल निष्पादन के चलते, हिंसा के स्तर में लगभग 60% की कमी दर्ज की गई जिससे इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों और सरकारी मशीनरी की प्रभाविता को सुनिश्चित किया जा सके। रिपोर्ट्स बताते हैं कि सुरक्षा बलों द्वारा निरंतर संचालन के कारण विद्रोही समूह घोर प्रशासनिक और वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं और हिंसक गतिविधियों के लिए अपनी क्षमता बनाए रखने हेतु छुटपुट संगठन बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं।

3.10 असम: राज्य की सुरक्षा स्थिति काफी हद तक शांतिपूर्ण और नियंत्रण में रही है। सुरक्षा बलों द्वारा कैलिब्रेट किए गए, समन्वयित और समग्र कार्यवाही के चलते विद्रोही समूहों के संचालन की स्थिति काफी कम हो गई है। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (Saraigaora) {एनडीएफबी (एस)} की गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया गया, जिसके चलते उसके कार्यकर्ताओं के बीच काफी हताशा और मोहभंग की स्थिति बनी है। विद्रोही समूह घोर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं और हिंसा के छिटपुट कृत्यों का सहारा ले रहे हैं ताकि वे उनकी प्रासंगिकता को बनाए रख सकें।

3.11 नागालैंड: वर्ष 2015 से राज्य की सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन (के)] को सुरक्षा बलों द्वारा केंद्रित काउंटर विद्रोह के संचालन के माध्यम से हाशिए पर ला दिया गया है और वर्तमान में इसकी गतिविधियाँ पूर्वी नागालैंड और म्यांमार नागा हिल्स तक ही सीमित हैं। भारत-म्यांमार सीमा (आईएमबी) में सुरक्षा बलों द्वारा समेकित और निरंतर कार्रवाई ने भौतिक और मनोवैज्ञानिक, दोनों रूप से दोनों संगठनों पर अंकुश लगाया है।

3.12 नागा शांति समझौते के लिए फ्रेमवर्क समझौते पर 3 अगस्त 2015 को हस्ताक्षर किए गए और भारत सरकार द्वारा इस पर विभिन्न हितधारकों की सहमति प्राप्त करने का प्रयास प्रगति पर है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (किटोवी-नियोपाक) और अन्य छह विद्रोही समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक मुइवा) {एनएससीएन (आईएम)} के बढ़ते प्रभाव का सामना करने के अपने प्रयास में 'वर्किंग ग्रुप' बनाने के लिए एक साथ आए हैं। नागा नेशनल पीपुल्स ग्रुप (एनएनपीजी) के वर्किंग ग्रुप ने हाल ही में श्री आर. एन. रवि से मुलाकात की, जिससे कि नागा शांति प्रक्रिया को इसमें शामिल किया जा सके। सिविल सोसाइटी संगठन और नागा आदिवासी परिषद (नागालैंड के नागा जनजातियों के एनटीसी-एपेक्स बॉडी) भी शांति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एनएससीएन (के) पर दबाव बना रहे हैं। फरवरी 2018 में आगामी विधानसभा चुनावों के चलते और जनता की यह आम राय कि नागा शांति प्रक्रिया अपनी समाप्ति के करीब आ रही है, उनके सभी हितधारकों द्वारा राजनीतिक गतिविधियों में वृद्धि की गई है।

3.13 **मणिपुर:** राज्य की सुरक्षा की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यह सबसे ज्यादा अशांत राज्य रहा है। अधिकांश हिंसा को घाटी आधारित समूहों द्वारा किया जा रहा है क्योंकि वे ही मणिपुर में लगभग 60% हिंसा की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं। वर्ष 2017 के दौरान आदिवासी समूहों के बीच प्रतिद्वंद्विता और स्थानीय-बाहरी का विभाजन दिख रहा है।

3.14 इनर लाइन परमिट के कार्यान्वयन की माँग तथा इसका विरोध, मणिपुर में हो रहे विरोध के प्रमुख कारक हैं। "रास्ता रोको" और "बंद" की राजनीति की प्रबलता है और यह तीन मुख्य समुदायों में बढ़ती हुई अस्थिरता का कारण बना है: नामतः मेतई – नागा – कुकी। राज्य में नागा बहुल क्षेत्रों में एनएससीएन (आईएम) की गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। सिविल सोसाइटी संगठनों की बढ़ती गतिविधि के चलते फ्रेम-वर्क-एग्रीमेंट की सामग्री पर स्पष्टीकरण की माँग भी बढ़ी है और ये एनएससीएन (आईएम) के नागालीम के दावे के अनुसार मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के प्रति एक चिंता का विषय भी है।

3.15 **अरुणाचल प्रदेश:** अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है जहाँ हिंसक घटनाओं में कमी हुई है और घटनाओं में कम नागरिक मारे जाने और आतंकवादियों को पकड़ने की संख्या में वृद्धि के मामले में भी सुधार हुआ है। सुरक्षा बलों

द्वारा तत्परता से चलाये गए ऑपरेशन ने विद्रोहियों के संचालन को बहुत ही सीमित कर दिया है। लांगडींग, तिरप और चंगलांग जिलों के अलावा, असम सीमा पर 11 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को 30 सितंबर, 2017 से छह महीने तक के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया गया है। इससे पहले 14 पुलिस स्टेशनों के तहत आने वाले क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था।

3.16 नागा गुटों की उपस्थिति से राज्य के लांगडींग, तिरप और चंगलांग जिले काफी प्रभावित हैं जो इस क्षेत्र में अपनी रिट स्थापित करने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए हैं। एनडीएफबी (एस) और उल्फा (आई) के कार्यकर्ता असम और म्यांमार के साथ (आश्रय/पारगमन) सीमाओं को साझा करते हैं। एनएससीएन गुटों ने भी अपने कार्यकर्ताओं को जबरन इस भर्ती में शामिल किया है और इन क्षेत्रों में अपनी प्रासंगिकता दिखाने के लिए यूएनएलएफडब्ल्यूएसईए के तहत संयुक्त समूहों के प्रयास में शामिल हुये हैं।

3.17 **मेघालय:** गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए) हेतु अपने आधारभूत समर्थन के साथ राज्य शांतिपूर्ण बना हुआ है। जीएनएलए द्वारा उत्पन्न की गई हिंसा गारो हिल्स तक ही सीमित बनी हुई है। असम के गोलपारा और धुबरी आदि पड़ोसी जिलों में भी इन समूहों की गतिविधियों का फैलाव भी दिखाई देने लगा है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से असम की सीमा क्षेत्र में केवल 10 किमी बेल्ट क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है, जबकि पहले यह 20 किमी का बेल्ट क्षेत्र था।

3.18 **मिजोरम:** विद्रोही समूहों द्वारा हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रयासों के मामलों में वृद्धि के साथ राज्य शांतिपूर्ण रहा है। हाल ही में म्यांमार के जातीय सशस्त्र समूह (ईएजी) की गतिविधियों की भारत, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा के त्रिकोणीय जंक्शन में वृद्धि देखी गई है। म्यांमार की आबादी के पलायन को देखते हुये ईएजी द्वारा दक्षिण मिजोरम में हिंसा की गतिविधियों को फैलाने की संभावना है। म्यांमार के अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (एआरएसए) पर म्यांमार सेना की कार्यवाही के चलते म्यांमार से पड़ोसी देशों की ओर कुछ समुदायों के बड़े पैमाने पर पलायन किया है। इस प्रकार एक सक्रिय खुफिया ग्रिड स्थापित करने और भारत-म्यांमार सीमा में अपनी तरफ से स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं।

3.19 **त्रिपुरा:** राज्य अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा है और हिंसा की घटनाएँ कानून और व्यवस्था की सीमा के भीतर थीं। जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम त्रिपुरा और खोई जिलों से माँग के आधार पर, असम राइफल्स कॉलम्स को 21 सितंबर से 30 सितंबर, 2017 तक प्रभावित क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने व शासकीय प्राधिकार स्थापित करने हेतु सहायता के लिए तैनात किया गया था।

3.20 **सारांश:** वर्ष 2017 में हिंसा की गतिविधियों में काफी कमी आई जो सुरक्षा बलों के सार्थक प्रयासों को प्रतिबिंबित करता है जो सुरक्षा माहौल को अस्थिरता से शांति और सौहार्द में परिवर्तित करता है। यह क्षेत्र बड़े बदलावों और बड़े बुनियादी ढाँचे के मुहाने पर है और 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के हिस्से के रूप में संचार परियोजनाएँ यहाँ कार्यान्वित की जा रही हैं। जारी एनआरसी अपडेट और नागा शांति समझौते की सम्पूर्ण क्षेत्रीय प्रभावित होने की संभावना है, और इस दौरान जातीय संघर्षों की संभावना के चलते आने वाले महीनों में स्थिति पर लगातार नजर रखे जाने की जरूरत होगी।

भारत-चीन सीमा की स्थिति

3.21 भारत-चीन सीमा की स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। सीमा से लगे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ भारत और चीन में एलएसी की अलग-अलग धारणा है। दोनों पक्ष एलएसी के अपने संबंधित धारणाओं तक गश्त करते हैं। एलएसी के ऐसे क्षेत्रों में चीनी गश्ती द्वारा अपराधों के विशिष्ट मामलों को चीनी अधिकारियों के साथ हॉटलाइन, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग (बीपीएम) और फ्लैग मीटिंग के स्थापित तंत्र के माध्यम से लिया जाता है।

डॉकलाम स्टैंडऑफ

3.22 भारत-चीन के रिश्तों में डॉकलाम फेस ऑफ एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा है। भारत ने एक सुदृढ़ प्रदर्शित किया और अपने पक्ष को रखने के लिए निर्धारित 'संकल्प' का प्रदर्शन किया। भूटान के पठार क्षेत्र में डॉकलाम भारतीय संवेदनशीलता को दर्शाता है—जो अपनी अवस्थिति तथा सिलीगुड़ी गलियारे के नजदीक होने के चलते काफी चर्चा में रहा है।

3.23 पूरी अवधि को, दोनों पक्षों की गतिविधियों के आधार पर तीन अलग-अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है— 25 जून 2017 तक एक 'शांत' पक्ष, 26 जून से 14 अगस्त 2017 तक

दोनों पक्षों द्वारा बलिकोज़ चीनी मीडिया में बलों द्वारा एक दूसरे को पूरित किया जाना, और 15 से 28 अगस्त 2017 तक बाद में इसका 'सामान्य होना' और यहाँ से विस्थापन किया जाना।

3.24 28 अगस्त 2017 को अपने सैनिकों और पीएलए के बीच फेस-ऑफ प्वाइंट पर बलों के विस्थापन की सहमति हुई। बलों का परस्पर विस्थापन, दोनों पक्षों के बीच गहन राजनयिक संचार का परिणाम था, सुदृढ़ समाधान और मैदान पर अपनी सेना द्वारा दृढ़ निर्धारण का प्रदर्शन किया गया। विस्थापन के बाद, हालाँकि, सैनिकों को वहाँ से हटाया जाना अभी शेष है।

दोनों देशों के बीच सीमा रक्षा सहयोग

3.25 वर्ष के दौरान, दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग्स / बॉर्डर पर्सनल मीटिंग (बीपीएम) के कई दौर आयोजित किए गए, जिन्होंने सीमा रक्षा सहयोग में काफी योगदान दिया है। इसके अलावा, भरोसा निर्माण उपायों (सीबीएम) के रूप में निम्नलिखित गतिविधियाँ कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं:

(क) **न्यू बॉर्डर पर्सनल मैनेजमेंट (बीपीएम) मैकेनिज्म:** वर्तमान में उत्तरी सीमाओं पर पाँच स्थान हैं जहाँ बीपीएम आयोजित किए जाते हैं। दो अतिरिक्त स्थानों, अर्थात् मध्य क्षेत्र में लिपुलेख और पश्चिमी क्षेत्र में चुमार, पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) अप्रैल, 2017 में परम पूज्य दलाई लामा द्वारा अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच सीमा रक्षा सहयोग के लिए एक शांत अवधि रही, जिसके बाद चीन ने सभी बीपीएम को वहाँ से निलंबित कर दिया था। डॉकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान भी इसी प्रकार के समान व्यवहार को देखा गया।

(ग) **भारत और चीन के बीच हॉटलाइन:** भारत और चीन सीमा रक्षा सहयोग समझौते 2013 के तहत दोनों देशों के सैन्य मुख्यालयों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। जल्द ही इस तंत्र को संचालित करने के लिए चर्चा जारी है।

3.26 **अपराध:** वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में हुए अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो पीएलए की मजबूती और उत्तरी सीमाओं पर इसके दावों के प्रति संवेदनशीलता का भी संकेत है। वर्ष 2016 में इस अवधि के दौरान उत्तर सीमाओं में

कुल आपराधिक गतिविधियों की संख्या 334 (दिचू में 65 मछुआरों सहित) की तुलना में संबन्धित अवधि के लिए 235 (दिचू में 56 मछुआरों सहित) रही है।

मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग

3.27 हमारे राष्ट्रीय हितों और विदेश नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा सहयोग गतिविधियाँ एक महत्वपूर्ण उपकरण है। हाल के वर्षों में भारत के बढ़ते वैश्विक स्तर के साथ, भारतीय सेना द्वारा किए गए रक्षा सहयोग गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है। तदनुसार, मित्र देशों (एफएफसी) की बढ़ती संख्या ने भारतीय सेना के साथ अपनी संलग्नता में गहरी रूचि दिखायी है, जो कि न केवल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना के रूप में उभरी है बल्कि यह एक पेशेवर व अलौकिक बल के रूप में व्यापक युद्ध अनुभव और अनुकरणीय प्रशिक्षण मानकों के लिए भी जाना जाता है। आज की तिथि में भारतीय सेना 99 देशों के साथ रक्षा सहयोग गतिविधियों का संचालन करती है।

3.28 **संरचनागत सहभागिता:** भारत सरकार ने 55 देशों के साथ समझौता करार/रक्षा सहयोग समझौता निष्पादित किया है। भारतीय सेना 14 देशों के साथ द्विपक्षीय सेना-के साथ-सेना कर्मचारियों की वार्ता (कार्यकारी संचालन समूह समेत) का संचालन करती है। ये रक्षा सहयोग पहल की प्रगति के लिए औपचारिक आधार प्रदान करते हैं। नेपाल के साथ संलग्नता हेतु, रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने नेपाल-भारत द्विपक्षीय परामर्शदाता समूह (एनआईबीसीजीएस) के नाम पर रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त योजना तैयार की है। रूस के साथ एक समान बहु मंत्रालय संलग्नता है जिसमें 23 जून, 2017 को रूस में आयोजित रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक के दौरान 'भारत के विकास के लिए भावी मार्ग - रूस रक्षा सहयोग' पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

3.29 विदेश में 44 रक्षा स्कंधों में तैनात सेना से 31 सैनिकों सहित 70 सैन्य/रक्षा अटैचे हैं। इसी तरह, नई दिल्ली में 70 देशों के रक्षा सहयोगियों को मिलाकर विदेशी दूतावासों में रक्षा प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर 113 रक्षा अटैचे तक बढ़ा दिये गए हैं।

3.30 **नेपाल:** भारत और नेपाल के बीच जारी रक्षा सहयोग के रूप में सैन्य संबंधों को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें रक्षा उपकरणों, नेपाल सेना के लोगों को प्रशिक्षण, चिकित्सा टीमों

के दौरे, ट्रेकिंग टीमों और वरिष्ठ अधिकारियों की यात्रा के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत बनाना जारी है। इस प्रकार नेपाल सेना की क्षमता में भी वृद्धि की जा रही है।

3.31 **भूटान:** भूटान के साथ पारंपरिक निकट संबंधों को बनाए रखते हुए, हम रणनीतिक संबंधों को और अधिक विकसित करने के लिए रॉयल भूटान सेना और रॉयल बॉडी गार्ड की क्षमता निर्माण के उन्नयन हेतु सहायता प्रदान कर रहे हैं।

मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यास (एफएफसी)

3.32 मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें अनुभवों को बांटने, सैन्य संचालन की बदलती गतिशीलता को समझने, इंटर-ऑप्रेबिलिटी विकसित करने और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत सहित कई संयुक्त संचालन हेतु प्रक्रियाओं को साझा करने की गतिविधि शामिल होती है।

3.33 **संचालित किए गए अभ्यास:** भारतीय सेना लगातार मित्र देशों के साथ कई संयुक्त प्रशिक्षण/अभ्यास में निरंतर संलग्न होती रही है। 1 जनवरी, 2017 से अब तक निम्नलिखित संयुक्त प्रशिक्षण/अभ्यास किए गए हैं:

- (क) **अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट XII:** 12वां भारत-मंगोलिया प्लाटून स्तर का संयुक्त अभ्यास/प्रशिक्षण-अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट XII 5 से 18 अप्रैल, 2017 को वैरेंगते में किया गया।
- (ख) **अभ्यास सूर्य किरण XI:** 11वां भारत-नेपाल बटालियन स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण/अभ्यास - अभ्यास सूर्य किरण XI का आयोजन पिथौरागढ़ में 7 से 20 मार्च, 2017 तक किया गया।
- (ग) **अभ्यास सूर्य किरण XII:** 12वां भारत-नेपाल बटालियन स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण/अभ्यास - अभ्यास सूर्य किरण XII का आयोजन नेपाल में 3 से 16 सितम्बर, 2017 तक किया गया।
- (घ) **मित्र शक्ति-V:** 5वां भारत-श्रीलंका प्रशिक्षण/अभ्यास - अभ्यास मित्र शक्ति-V का आयोजन औंध, पुणे में 13 से 26 अक्टूबर, 2017 तक किया गया।

(ड) **अभ्यास सम्प्रीति-2017** : 7वां भारत-बांग्लादेश प्लाटून स्तर प्रशिक्षण/अभ्यास – अभ्यास सम्प्रीति-VII का आयोजन उमरोई और वैरंगते में 6 से 18 नवंबर, 2017 तक किया गया।

3.34 **दौरः** वर्ष 2017 के दौरान कई उच्च और कार्यात्मक स्तर के दौरों का संचालन किया गया। जापान, चेक गणराज्य, इजरायल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों ने भारत का दौरा किया जबकि सीओएएस ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की। इसके अलावा, वर्ष के दौरान 451 उच्च/कार्यात्मक स्तर की बातचीतों/कार्यक्रमों का आयोजन मित्र देशों के साथ किया गया।

3.35 **संयुक्त अभ्यासः** मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यास हमारे रक्षा सहयोग गतिविधियों के सबसे अधिक दृश्यमान घटक हैं। ये घटनाएं विश्व स्तर पर हमारी कार्यकुशलता का प्रदर्शन करती हैं और स्वयं के सैनिकों के लिए आदर्शों के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करती हैं। वर्ष के दौरान दो नए संयुक्त अभ्यास वियतनाम और म्यांमार के साथ स्थापित किए गए हैं।

3.36 वर्ष 2017 में ही अभ्यास इंद्र (रूस) का एकल से संयुक्त त्रि-सेवा अभ्यास इंद्र-2017 (भारत और रूस दोनों के लिए पहली बार) के रूप में उन्नयन किया गया, जिसमें 350 सदस्यीय भारतीय सेना दल ने एक दो सितारा रैंक ऑफिसर की अध्यक्षता में भाग लिया। मलेशिया के साथ अभ्यास हरिमाउ शक्ति का भी वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन किया गया। आज की तिथि तक भारतीय सेना ने 22 देशों के साथ 26 अभ्यास किए हैं। वर्ष 2017-18 के लिए, अनुसूचित किए गए 21 अभ्यासों में से, 12 अभ्यास दिसंबर, 2017 के अंत तक आयोजित किए जा चुके हैं और मार्च, 2018 तक शेष अभ्यास की योजना बनाई गई है। भारत में फील्ड फायरिंग अभ्यास सहित सिंगापुर के साथ अभ्यास आयोजित किया गया।

3.37 **अंतरराष्ट्रीय सेना खेल (रूस) 2017:** भारतीय सेना के अधिकारियों ने क्रमशः रूस और कजाखस्तान में 29 जुलाई से 12 अगस्त 2017 के बीच अंतरराष्ट्रीय सेना खेलों के टैंक बैथलॉन और स्निपर प्रतियोगिताओं (रूस) में भाग लिया। पहली बार टैंक बैथलॉन में भारत द्वारा अपने टैंक का इस्तेमाल किया गया जिसमें भारतीय सेना ने रूस और कजाकिस्तान में आयोजित विभिन्न

प्रतियोगिताओं में कई पर्यवेक्षकों को भेजा था।

3.38 **सैन्य समारोहों का आयोजन:** भारतीय सेना ने 62 सदस्यीय सर्विसेज बैंड के नेतृत्व में 26 अगस्त से 3 सितंबर, 2017 तक मास्को में आयोजित स्पेस काया सैन्य संगीत समारोह में हिस्सा लिया। हमारे पाइपरों ने 9 से 14 नवंबर, 2017 तक फ्रांस और बेलजियम में आयोजित डब्ल्यूडब्ल्यू-1 के वार्षिक स्मारक समारोह में भाग लिया। फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए दो भारतीय सैनिकों के अवशेषों को दफन करने के लिए 12 नवंबर, 2017 को फ्रांस के ला गॉर्ग्यू, फ्रांस में आयोजित समारोह में भारतीय सेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

आधुनिकीकरण और उपकरण

3.39 सेना के प्रमुख अधिग्रहण का आधुनिकीकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन देने के दौरान, नई क्षमताओं के निर्माण करने और कमियों को दूर करने पर भी जोर दिया गया है। खरीद की समय-सीमा को कम करने और कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए खरीद को तेज करने के लिए सेना द्वारा कई उपाय अपनाए गए हैं।

3.40 **अधिग्रहणः** भारतीय सेना का आधुनिकीकरण और क्षमता विकास तेज से गति से हो रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 (नवंबर 2017 तक) के लिए 30030 करोड़ रुपये के 13 (तेरह) अनुबंधों को सेना रक्षा उपकरणों की पूंजीगत खरीद के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जैसे हेलीकॉप्टर, मिसाइल, सिमुलेटर, आर्टिलरी गन, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ और ऐमुनिशन इत्यादि। विभिन्न हथियारों और सेवाओं का आधुनिकीकरण निम्नानुसार किया जा रहा है ताकि युद्ध की दक्षता को बढ़ाया जा सके:

(क) **यंत्रिकृत बल:** यंत्रिकृत अथवा मैकेनाइज्ड बलों की क्षमता को रात्रि-सक्षमता, गतिशीलता बढ़ाने और सटीकता तथा विद्यमान उपकरणों के उन्नयन के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है। टैंकों और बीएमपी की रात्रि-सक्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रात्रि-मुकाबला क्षमता और सटीकता को बढ़ाना है।

(ख) **पैदल सेना (इन्फैंट्री):** पैदल सेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाना, पैदल सैनिकों की जीवन क्षमता, मारक क्षमता और लड़ने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। राष्ट्रीय राइफल्स हेतु सब मशीन गनों

के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं और नवीनतम हथियारों और उपकरणों का अधिग्रहण जारी है ताकि पैदल सेना की क्षमता और जीवन को बचाया जा सके।

(ग) **तोप (आर्टिलरी):** तोपों की क्षमता का विकास, इसकी घातकता, सटीकता और निगरानी क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। अग्निशमन और सटीकता को बढ़ाने के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया जा रहा है। मानवरहित विमान (अनमैन्ड एरियल व्हीकल) (एसएटीसीओएम) प्रणाली का उन्नयन, यूएवी के हथियार और बंदूकों का उन्नयन प्रक्रियाधीन हैं, जिससे भारतीय सेना की अग्नि शक्ति और निगरानी क्षमता में भारी वृद्धि होगी।

(घ) **सेना के वायु रक्षा:** सेना के वायु रक्षा कोर की क्षमता में भी बढ़ोतरी की जा रही है। सतह से वायु की मारक क्षमता वाले मिसाइलों का प्रेरण जमीनी बलों को वायु रक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद देगा। इसके अलावा, वायु रक्षा गन और उपकरणों की खरीद/उन्नयन उन्नत चरणों पर हैं और इससे सतह आधारित वायु रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी।

(ङ) **आर्मी एविएशन (सेना उड़डयन):** आर्मी एविएशन अपनी गोलाबारी और निगरानी क्षमता में वृद्धि कर रहा है। चालू वित्त वर्ष में कई अनुबंधों को पूरा किया गया है। खोज और बचाव उपकरणों की खरीद और एयर टू एयर मिसाइल की खरीद उन्नत चरणों में हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टरों की खरीद से लड़ाई क्षमता में बढ़ोतरी होगी।

3.41 विभिन्न हथियारों के विशिष्ट अधिग्रहण के अलावा, विशेषज्ञ वाहनों को शामिल करने, रेल गतिविधि के लिए क्रिटिकल रोलिंग स्टॉक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, संचार और युद्धक्षेत्र प्रबंधन के लिए भी परियोजनाएं शामिल की गई हैं। इन सभी आधुनिकीकरण योजनाओं को लागू करने के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक मजबूत सेना किसी भी युद्धग्रस्त वातावरण में किसी भी चुनौती का सामना कर सकने के लिए तैयार है।

3.42 रक्षा खरीद प्रक्रिया—2016 के प्रावधानों को ध्यान में रखते

हुए खरीद प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और गति देने के लिए कई पहलें की गई हैं। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में सामरिक साझेदारी की नीति का भी प्रावधान किया है जिसका उद्देश्य प्रमुख रक्षा मंचों और उपकरणों के निर्माण में निजी क्षेत्र की सीमांत भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक पारदर्शी और वैकल्पिक तंत्र को संस्थागत बनाना है। सरकार नियमित रूप से जारी प्रापण परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेना सुरक्षा चुनौतियों के पूरे वर्णक्रम का सामना करने के लिए लैस हो सकें।

3.43 आर्मी डिजाइन ब्यूरो (एडीबी) को 31 अगस्त, 2016 को “डीआरडीओ और आईआईटी, अकादमी, डीपीएसयू और उद्योग जैसे प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के साथ सेना के एक अंतरफलक के रूप में काम करने वाली संस्था जो गहराई और उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और उत्पाद विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करते हों” के उद्देश्य के साथ निर्मित किया गया था, जिससे उन्हें उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को समझने और उनकी सराहना करने में सक्षम बनाया जा सके। एडीबी ने प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास तथा डीपीएसयू के लिए उत्पादन, निजी उद्योग के साथ—साथ विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में पूरे देश की स्वदेशी क्षमताओं और कुशलताओं का मापन किया है। उद्योग और क्षमताओं/उद्योग की कुशलताओं की सराहना करने के लिए सेना और उद्योग/शिक्षा के स्तर पर इसकी आधुनिकीकरण आवश्यकताओं/बाधाओं को समझने के लिए एडीबी विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों और प्रौद्योगिकी संस्थानों/अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों के साथ बातचीत कर रहा है।

3.44 उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में संलग्नता के लिए, भारतीय सेना की विभिन्न उपकरणों और प्रौद्योगिकी संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डालने वाली समस्याओं के दो संकलन प्रकाशित किए गए हैं। उद्योग और शिक्षा, दोनों से बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और अब हम सेना हेतु उपयुक्त समाधान के सृजन/विकास के लिए मार्गों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। तीसरे संग्रह का संकलन अभी जारी है।

3.45 एडीबी को आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड के माध्यम से बुनियादी अनुसंधान की सुविधा का भी अधिकार दिया गया है। अवधारणा की परिकल्पना को एक प्रोटोटाइप चरण में परिवर्तित करने के लिए

अनुसंधान को एडीबी द्वारा प्रौद्योगिकी विकास निधि के माध्यम से सुगमता से पूरा किया जा सकता है।

गोलाबारूद

3.46 भारतीय सेना के गोलाबारूद भंडारों में सुधार के लिए कई प्रमुख पहलें की गई हैं। इस बहुआयामी रणनीति का परिणाम गोला-बारूद का क्रमिक निर्माण करना है।

3.47 **योजना के अधीन अम्यूनिशन रोल:** गोला-बारूद का प्रबंधन आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) द्वारा मान के आधार पर पाँच वर्ष के लिए रोल रखकर किया जाता है ताकि यह अपने उत्पादन की योजना बना सके। माँगसूची को ओएफबी क्षमता को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक रूप से सहमत लक्ष्य पर रखा जाता है। वर्ष 2010 से 2014 के लिए माँगसूची पर पहले पाँच वर्ष तक ओएफबी पर फरवरी, 2010 तक की अवधि के लिए रखा गया था। माँगसूची पर दूसरा रोल अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2013 के दौरान 5 वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना के लिए वर्ष 2014 से 2019 की अनुमानित आवश्यकता के अनुसार रखा गया था। ओएफबी की निगरानी मासिक आधार पर की जा रही है, और कमियों पर प्रकाश डाला जा रहा है।

3.48 **अम्यूनिशन रोड मैप:** अम्यूनिशन की योजना पर पाँच वर्ष की रोल की मध्यावधि पाठ्यक्रम मूल्यांकन के दौरान, गंभीरताओं के निबटान हेतु अम्यूनिशन रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। अम्यूनिशन रोड मैप को रक्षा मंत्रालय द्वारा अम्यूनिशन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंजूरी दी गई है। अम्यूनिशन रोड मैप के तहत अनुमोदित अम्यूनिशन की खरीद योजना में ओएफबी पर अतिरिक्त आवश्यकताएं रखने और कुछ अम्यूनिशन वस्तुओं के पूर्व-आयात की व्यवस्था भी शामिल की गई है।

3.49 **अम्यूनिशन की आपातकालीन खरीद:** रक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर, 2016 में वीसीओएस को आपातकालीन खरीद की शक्तियाँ प्रदान कीं। इस प्रत्यायोजन के परिणामस्वरूप, भारतीय सेना की महत्वपूर्ण कमी को पूरा करने के लिए किए गए एक विचार के साथ कई महत्वपूर्ण अम्यूनिशन, हथियार, वाहनों और पुर्जों के सामान के लिए कई अनुबंधों को अंतिम रूप दिया गया। की गई खरीद से भारतीय सेना के उपकरणों की धारण क्षमता की स्थिति में सुधार हुआ है।

3.50 **महत्वपूर्ण अम्यूनिशन और पुर्जों के न्यूनतम स्टॉक स्तर को बनाए रखने हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि सशस्त्र बलों को परिचालन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यह हमेशा अच्छी तरह से लैस है, न्यूनतम मात्रा में महत्वपूर्ण अम्यूनिशन और महत्वपूर्ण पुर्जों को बनाए रखने के लिए खरीद के अधिकार, सेवा मुख्यालय (एसएचक्यू) को सौंपे गए हैं। इसलिए सशस्त्र बलों को यह शक्ति और जिम्मेदारी दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महत्वपूर्ण अम्यूनिशन और पुर्जों की न्यूनतम मात्रा को सभी स्तर और समय पर बनाए रखा जा सके।

3.51 **भारतीय उद्योग द्वारा भारतीय सेना के लिए अम्यूनिशन का निर्माण:** उद्योग के भीतर अम्यूनिशन के एक मजबूत वैकल्पिक स्रोत के रूप में क्षमता के निर्माण के दीर्घकालिक उद्देश्य के साथ, और साथ ही स्वदेशी क्षमता के विकास की सुविधा व आयात निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार ने भारतीय उद्योग द्वारा भारतीय सेना के लिए चयनित अम्यूनिशन के निर्माण को मंजूरी दी है।

आर्ममेंट (आयुध)

3.52 **आर्ममेंट एक्सरसाइज ओएफबी:** वार्षिक प्रावधान समीक्षा के आधार पर, ओएफबी पर हथियारों के निर्माण के लिए माँग सूची रखी गई है जिसके लिए ओएफबी की क्षमता और प्रौद्योगिकी को निर्धारित किया गया है।

3.53 **आर्ममेंट एक्सरसाइज इम्पोर्ट:** प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता के कारण तथा इसकी कमी को पूरा करने के लिए कुछ हथियारों का आयात भी किया जा रहा है।

3.54 **क्रिटिकल आर्ममेंट और माइन्स के लिए 100% स्टॉक स्तर को बनाए रखने हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन:** वित्तीय शक्तियों के साथ वीसीओएस को कुछ पहचान किए गए महत्वपूर्ण हथियारों और माइन्स के संबंध में 100% खरीद हेतु प्राधिकृत करने का अधिकार सौंपा गया है।

3.55 **वेपन नाइट साइट और निगरानी उपकरण:** आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल (एएफवी) और भारतीय सेना के गैर-एएफवी अनुप्रयोगों के लिए इमेज इन्सटेंसिफायर नाइट विजन डिवाइसेज (एनवीडी) की आवश्यकता को मैसर्स बीईएल और ओएलएफ द्वारा

आपूर्त किया जाता है। मैसर्स बीईएल से वर्तमान खरीद मामलों में हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर (एचएचटीआई), एचएचटीआई लेजर रेंज फाइंडर (एलआरएफ), पैसिव नाइट विजन गोगल्स (पीएनवीजी), पैसिव नाइट विजन बाइनकुलर्स (पीएनवीबी), आईएनएसएस के लिए पैसिव नाइट साइट (पीएनएस) आदि शामिल हैं। इंसास राइफल/एलएमजी और ओएलएफ में एएफवी प्लेटफार्मों के लिए इमेज इंटेन्सिफायर और थर्मल इमेजरी साइट शामिल हैं।

राष्ट्रीय राइफल्स

3.56 राष्ट्रीय राइफल्स ने अपनी स्थापना के बाद से राज्य की सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अमूल्य सहायता प्रदान की है। वर्ष 2017 के दौरान, राष्ट्रीय राइफल्स ने अपने संचालन कार्यों पर पुरजोर दबाव डाला है। समग्र बल के रूप में राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया गया है, जो अन्यथा अशांत बना हुआ रहता है।

3.57 अत्यधिक धैर्य और दृढ़ता से आकस्मिकता की भावना के साथ, राष्ट्रीय राइफल्स के सफल कार्यों व प्रयासों को बनाए रखा और इन्हें सफलतम प्रयासों में बदला गया है। पूरी अवधि के दौरान, राष्ट्रीय राइफल्स की इकाइयाँ आतंकवादियों और उनके समर्थकों पर लगातार दबाव डालने में सक्षम रहीं। बड़े पैमाने पर सेना के प्रयासों ने आतंकवादियों की ताकतों के खिलाफ इस क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति को बनाए रखा है।

3.58 **राष्ट्रीय राइफल्स की संचालनात्मक उपलब्धियाँ:** राष्ट्रीय राइफल्स ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान 142 आतंकवादियों (108 मारे गए, 34 गिरफ्तार) को निष्क्रिय किया है और युद्ध सामग्री के महत्वपूर्ण भंडारों को भी हासिल किया है।

3.59 **श्री अमरनाथ यात्रा (ओपी शिवा):** राष्ट्रीय राइफल्स इकाइयों और संरचनाओं ने प्रारंभिक और प्राधिकारयुक्त तैनाती, आक्रामक वर्चस्व और स्वस्थ खुफिया नेटवर्क के माध्यम से यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्ण सहायता में भक्तों के आने-जाने में चिकित्सीय सुविधा प्रदान किए जाने को भी शामिल किया गया था।

3.60 **लोगों के अनुकूल ऑपरेशन:** सेना और सरकार के बारे में लोगों की धारणा को आकार देने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन किया गया। 'आवाम'

और 'जवान' के बीच आराम के स्तर को बढ़ाने के अलावा इसने लोगों को सेना के रूप में एक बदलाव प्रदर्शित किया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा स्थापित युवा रोजगार और मार्गदर्शन नोड्स (वाईईजीएन), राज्य के युवाओं को प्रभावी रूप से लक्षित कर उन्हें उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर तलाशने में मदद दे रहा है, इस प्रकार उन्हें गलत तरीकों से धन अर्जन और आतंकवाद के माध्यम से सत्ता पाने की गलत समझ से उन्हें दूर रखा जा रहा है।

3.61 राष्ट्रीय राइफल्स का निर्माण, दुनिया में एकमात्र विशेष रूप से तैयार संरक्षित काउंटर इनसरजेंसी/आतंकवाद रोधी बल, एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के साथ एक रणनीतिक निर्णय के बेहतरीन उदाहरणों में से एक रहा है। इसकी हासिल की गई विशेषज्ञता अमूल्य है और व्यापक राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करने के लिए इसे हमेशा के लिए संरक्षित रखने की आवश्यकता है। पूरी तरह से आतंकवाद को खत्म करना और जनता को मुख्यधारा में शामिल होने के लिए, विशेष रूप से युवाओं को प्रोत्साहन जारी रखना सेना का विशेष प्रयास होगा। ऐसा करने से, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और मानव अधिकारों के उल्लंघन की पूर्ण रोकथाम में राष्ट्रीय राइफल्स एक आवश्यक मार्गदर्शक मापदंड साबित होगा।

प्रादेशिक सेना

3.62 प्रादेशिक सेना अधिनियम वर्ष 1948 में लागू किया गया था। प्रादेशिक सेना (टीए) की अवधारणा, लाभप्रद रोजगार वाले नागरिकों के लिए अंशकालिक सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना है जो प्रदान किए सैन्य प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप बाद में सक्षम सैनिक बनते हैं।

3.63 **काउंटर इनसरजेंसी/आतंकवाद रोधी गतिविधियों और आंतरिक सुरक्षा में प्रादेशिक सेना इकाइयों का योगदान:** वर्तमान में जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व में काउंटर इनसरजेंसी/ काउंटर टेररिज्म माहौल में लगभग 75 प्रतिशत प्रादेशिक सेना इकाइयाँ तैनात की गई हैं और पेशेवर तरीके से निर्धारित कार्य करने के लिए नियमित सेना के सहायक के रूप में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

3.64 नई प्रादेशिक सेना बटालियनों की स्थापना:

(क) **महाराष्ट्र सरकार के लिए पारिस्थितिकीय पैदल सेना (प्रादेशिक सेना) बटालियन की स्थापना:** सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र में वनीकरण और संबंधित गतिविधियों के लिए महाराष्ट्र राज्य हेतु 136 पारिस्थितिकीय पैदल सेना (प्रादेशिक सेना) बटालियन की महाराष्ट्र में स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह इकाई औरंगाबाद में तैयार की जा रही है और यह 9 दिसंबर, 2017 से प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है।

(ख) **अंडमान निकोबार कमान के लिए पैदल सेना (प्रादेशिक सेना) बटालियन की स्थापना:** सरकार ने अंडमान निकोबार कमान के लिए 172 पैदल सेना (प्रादेशिक सेना) बटालियन मद्रास की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में स्थापना के तहत यह यूनिट अगस्त, 2017 से प्रभावी हो चुकी है। वर्तमान में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भर्ती जारी है। यह इकाई 1 मई, 2019 से प्रभावी रूप से कार्य करने लगेगी।

(ग) **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के लिए एक समग्र पारिस्थितिकीय कार्यबल (सीईटीएफ) बटालियन की स्थापना:** सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के लिए 137 समग्र पारिस्थितिकीय कार्यबल (सीईटीएफ) प्रादेशिक सेना बटालियन, 39 गोरखा राइफल्स की स्थापना को मंजूरी दी है। बटालियन की भूमिका साँपे गए कार्यों को पूर्ण करने में एनएमसीजी की सहायता करना है।

3.65 **पारिस्थितिकीय कार्य बल बटालियन (प्रादेशिक सेना):** देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित पारिस्थितिकीय कार्य बल बटालियन (प्रादेशिक सेना), देश के विषम और मुश्किल क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय को बहाल करने में उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। इन इकाइयों ने करीब 652.77 लाख पौधे लगाए हैं और करीब 72,618 हेक्टेयर क्षेत्र को पौधों से आच्छादित किया है। सभी के द्वारा पारिस्थितिकीय कार्य बल बटालियन (प्रादेशिक सेना) के प्रयासों की बहुत सराहना की गई है।

3.66 **प्रादेशिक सेना दिवस समारोह:** प्रादेशिक सेना

प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 9 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रपति भवन में अधिकारियों, जूनियर कमीशन अधिकारियों (जेसीओ), अन्य रैंक (ओआर) प्रादेशिक सेना और उनके परिवारों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया। प्रादेशिक सेना द्वारा हाफ-मैराथन का आयोजन करिअप्पा परेड ग्राउंड, दिल्ली कैंट में 2 अक्टूबर 2017 को किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रादेशिक सेना को एक जीवंत और प्रतिबद्ध संगठन के रूप में परिलक्षित करना तथा सभी रैंकों और सशस्त्र बलों के परिवारों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में 3,000 से ज्यादा कर्मियों ने जबरदस्त उत्साही भागीदारी निभाई और लेफ्टिनेंट कर्नल (माननीय) कपिल देव (भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान) और सैन्य संचालन महानिदेशक द्वारा झण्डा दिखा कर मैराथन की शुरुआत की गई। प्रादेशिक सेना सिम्फनी बैंड ने 8 अक्टूबर, 2017 को इंडिया गेट पर एक बैंड डिस्प्ले का आयोजन किया। इस आयोजन को नागरिकों की एक बड़ी भीड़ ने देखा, और इस आयोजन ने शाम के माहौल को देशभक्ति के वातावरण में मंत्र-मुग्ध कर दिया।



प्रादेशिक सेना हॉफ मैराथन



इंडिया गेट पर प्रादेशिक सेना सिम्फनी बैंड द्वारा बैंड प्रदर्शन



भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के साथ प्रादेशिक सेना परिवार

3.67 वर्ष 2017–18 की सीओएस सिल्वर ट्रॉफी: इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) राजस्थान राइफल्स और 119 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) असम को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है क्योंकि इन्हें 43 प्रादेशिक सेना इकाइयों (इन्फैंट्री एंड होम एंड हेल्थ यूनिट) के बीच सबसे उत्कृष्ट इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) के रूप में घोषित किया गया है।

3.68 सम्मान और पुरस्कार 2017: स्वतंत्रता दिवस 2017 के अवसर पर प्रादेशिक सेना के कर्मियों को निम्नलिखित बहादुरी/विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं:

(i)	कीर्ति चक्र	—	01
(ii)	सेना मेडल	—	01
(iii)	मेंशन इन डिस्पैचिज़ (ऑपरेशन रक्षक)	—	01
(iv)	सीओएस प्रशस्ति पत्र	—	06
(v)	वीसीओएस प्रशस्ति पत्र	—	01
(vi)	जीओसी—इन—सी प्रशस्ति पत्र	—	72

संयुक्त राष्ट्र मिशन

3.69 भारतीय सैनिक आज दुनिया भर के सात संयुक्त राष्ट्र मिशनों में तैनात हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा बलों के हिस्से के रूप में भारतीय सेना, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में शांति और

स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसने लंबे समय तक बड़ी सैनिक प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने की एक अद्वितीय क्षमता का प्रदर्शन किया है। संयुक्त राष्ट्र और शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए, 153 भारतीय सेना के सैनिकों ने अब तक सर्वोच्च बलिदान किया है।

3.70 भारतीय दल की व्यावसायिकता और कार्यकुशलता को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। भारतीय दलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनके संबंधित मिशन के फोर्स कमांडरों द्वारा बार-बार सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मिशन में सहयोगियों की उपलब्धता और उपलब्धता में वृद्धि के लिए वित्तीय शक्तियों और फास्ट ट्रैक खरीद प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात सैनिकों हेतु दिये जाने वाले प्रवासी भत्ता को सितंबर, 2017 में बढ़ा दिया गया है।

3.71 **कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र मिशन (एमओएनयूएससीओ):** वर्ष 2004 के बाद से भारत ने मिशन में कर्मचारी अधिकारी (एसओएस) और सैन्य पर्यवेक्षकों (एमआईएलओबी) के साथ एक इन्फैंट्री ब्रिगेड ग्रुप तैनात किया गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राष्ट्रीय सेना के समर्थन में भारतीय सैनिकों ने व्यापक अभियान चलाए हैं। रैपिड डिमोरेबल बटालियन (आरडीबी) को मिशन क्षेत्र में भी संचालन किया गया है, और इस प्रकार कमांडर, भारतीय यूएन ब्रिगेड के लिए जनादेश की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक गतिशील और शक्तिशाली

उपकरण उपलब्ध कराया गया है। मिशन के पुनर्गठन की वजह से, एक भारतीय इन्फैंट्री बटालियन समूह को अगस्त, 2017 में मिशन से पृथक कर दिया गया है।

3.72 लूबेरो में दो सशस्त्र समूह कार्यकर्ताओं को निष्प्रभावी करके और दो अन्य घायल करके लूबेरो के अपने पोस्ट पर सशस्त्र समूहों के एक बड़े हमले का सफलतापूर्वक सामना किया गया है।

3.73 दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनआईएमआईएस): मिशन में भारत द्वारा दो इन्फैंट्री बटालियन समूहों और दो अस्पतालों सहित सात सैन्य दल तैनात किये गये हैं। सरकारी बलों और विपक्षी सशस्त्र बलों के बीच चल रहे संघर्ष ने सुरक्षा स्थिति को अस्थिर किया और इसे अप्रत्याशित रूप से प्रभावित किया है। आईएनडीबीएटीटी-॥ के सैनिकों ने 12 जुलाई, 2017 को मेडिसिन सैन्स फ्रंटियर्स (एमएसएफ) से 13 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला।

3.74 लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल): यूएनआईएफआईएल के तहत भारतीय सेना के योगदान में इन्फैंट्री, भारतीय चिकित्सा दल और कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं। लेबनान और इजरायल के कब्जे वाले चेबा

फार्मों के बीच विथड्रावल लाइन के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ ब्लू लाइन की निगरानी के लिए इन्फैंट्री को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। मिशन क्षेत्र में स्थिति स्थिर पर अप्रत्याशित बनी हुई है।

3.75 संयुक्त राष्ट्र मुक्ति पर्यवेक्षक सेना (यूएनडीओएफ): मिशन को दूसरी लाइन की सैन्य तंत्र सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने यूएनडीओएफ में एक सैन्य तंत्र दल को तैनात किया है। यह मिशन दोनों के लिए अनिवार्य कार्यों को पूरा करने हेतु पुनर्गठित किया जा रहा है, इसके कार्य क्षेत्र में इजरायल और सीरियाई दोनों पक्षों पर शांति सैनिकों में भारतीय दल के कारकों को शामिल किया गया है।

3.76 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापन केंद्र (सीयूएनपीके): देश में शांति प्रशिक्षण संबंधित प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (सीयूएनपीके) नोडल एजेंसी है। प्रत्येक वर्ष, यह सभी तीन सेवाओं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और मित्र देशों से कई अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। सीयूएनपीके द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों की व्यापक सामग्री और दोषरहित आचरण के लिए संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न मित्र देशों ने इसकी काफी सराहना की है।





भारतीय नौसेना





भारतीय नौसेना

4.1 भारत एक समुद्र तटीय राष्ट्र है और देश की सीमा पर कई व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय नौपरिवहन मार्ग स्थित हैं, जो हिंद महासागर के पार जाते हैं। आयतन की दृष्टि से हमारा 95% से अधिक और मूल्य की दृष्टि से 68% व्यापार समुद्र से होता है। दुनिया भर में नए बाजारों की तलाश करती तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के लिए, व्यापार के ये आंकड़े भविष्य में और आगे बढ़ेंगे।

4.2 भारत का आर्थिक पुनरुत्थान सीधे अपने विदेशी व्यापार और ऊर्जा की जरूरतों से जुड़ा हुआ है, जिनमें से अधिकांश समुद्र के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। वाणिज्यिक व्यापार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 40% से अधिक का गठन करता है और भविष्य में इसके और बढ़ने की संभावना है। एक सुरक्षित समुद्री वातावरण का रखरखाव आर्थिक गतिविधियों के अबाधित अनुगमन को सक्षम बनाता है, इसलिए देश के समग्र आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

4.3 पिछले दशक में भारत की समुद्री पर्यावरण पर निर्भरता

देखी गई है क्योंकि इसकी आर्थिक, सैन्य और तकनीकी शक्ति बढ़ती जा रही है, इसकी वैश्विक बातचीत सांझी हुई है और इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यताएं और राजनीतिक हित धीरे-धीरे हिंद महासागर क्षेत्र से परे फैला है। इसलिए यह माना जा सकता है कि 21वीं सदी भारत के लिए 'सागरों की सदी' होगी और महासागर भारत के वैश्विक पुनरुत्थान में एक प्रमुख संबल सिद्ध होंगे।

4.4 क्षेत्र में हमारी बहु-आयामी क्षमताओं और सक्रिय उपस्थिति के कारण भारतीय नौसेना (भारतीय नौसेना) भारतीय महासागर क्षेत्र में समुद्री नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। भारत के समुद्री पड़ोस में गतिशील वातावरण है, बढ़ी हुई अस्थिरता के साथ, गहराती भू-राजनीतिक और जातीय गलतियों, बढ़ती सैन्य क्षमताओं और सुरक्षा चुनौतियों की विस्तृत श्रृंखला, भारत पर पारंपरिक और उप-पारंपरिक खतरों का एक संयोजन है जो समुद्रों में और उनमें से ही उभरती हैं। इन खतरों और चुनौतियों के कारण भारतीय नौसेना को मुकाबले के संचालन के लिए पूरे विस्तृत श्रेणी में प्रभावी रहना पड़ता है और भविष्य की चुनौतियों

को पूरा करने के लिए खुद को लगातार नयी आकृति प्रदान करनी होती है।

4.5 भारतीय नौसेना देश की समुद्री संप्रभुता की प्रमुख समर्थक और जमानतदार है और समुद्री उपयोग की असंख्य गतिविधियों का इस्तेमाल करती है। इसे नौसेना द्वारा अपनी चार भूमिकाओं – सैन्य, कूटनीतिक, रक्षीदल और सौम्यता के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। नौसेना की सैन्य भूमिका का उद्देश्य किसी भी उस हस्तक्षेप या कार्य की खिलाफत करना है जो राष्ट्रीय रुचियों के विरुद्ध है, और शत्रुता की स्थिति में शत्रु को कुचलने की क्षमता न रखता हो। नौसेना की रक्षीदल की भूमिका का एक प्रमुख उद्देश्य तटीय और अपतटीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारतीय तट रक्षक और अन्य केन्द्रीय और राज्य संस्थाओं के साथ संयोजन में चोरी-विरोधी उपायों को लागू करना है।

4.6 भारतीय नौसेना की संपत्ति और संसाधनों का उपयोग करके समुद्री प्रक्षेत्र जागरूकता (एमडीए) का उच्च स्तर बनाए रखा जाता है। भारतीय नौसेना किसी भी आकस्मिकता का उचित उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक नई लक्ष्य आधारित तैनाती अवधारणा कार्यान्वित की गई है। लक्ष्य के लिए तैयार जहाजों और विमानों को संचार और अवरुद्ध बिंदुओं के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के साथ 'विशिष्ट-स्थानों' में तैनात किया जा रहा है। तैनात परिसंपत्तियां संचालन के पूरे विस्तार में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। अक्टूबर 2008 के बाद से अदन क्षेत्र की खाड़ी में अग्रिम पंक्ति के बेड़े का एक जहाज लगातार तैनात किया गया है, जो वहां आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के लिए उपस्थित है और भारतीय और विदेशी देशों के व्यापारी जहाजों को सुरक्षित अनुरक्षण प्रदान करता है।

4.7 तत्काल सहायता वाले जहाजों (आईएसवी) और अन्य परिसंपत्तियों की तैनाती के माध्यम से अपतटीय विकास क्षेत्रों (ओडीए) सहित अपतटीय संपत्तियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। ओडीए प्लेटफार्मों की सुरक्षा और संरक्षा को सत्यापित करने के लिए नियमित अभ्यास किए गए हैं जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

4.8 भारतीय नौसेना आईओआर में मित्र देशों की नौसेना की क्षमता बनाने और बढ़ाने के लिए, सक्रिय रूप से गतिविधियां कर रही है। इस वर्ष के अन्त में, भारत विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) निगरानी के लिए धातु सामग्री और मंच प्रदान कर रहा

है, जिसमें जहाज और विमान शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने मैत्रीपूर्ण राष्ट्रों के समुद्री ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय नौसेना की पहलों में मित्र देशों को परिचालन और तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए दिया गया योगदान भी शामिल है।

4.9 एक नया परिवर्तनशील चक्र कार्यान्वित किया गया है, जो जहाज पर एक केंद्रित और क्रमिक परिवर्तन के लिए समय समय पर किये जाने वाले रखरखाव और छंटनी के समय पूर्ण परिचालनों के पैमानों की अनुमति देता है। नया परिवर्तनशील चक्र, जहाजों के प्रशिक्षण और सुरक्षा निरीक्षणों पर ऑपरेशनल कमांडरों के संचालन के लिए उनकी तैनाती से पहले, उनके प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे जहाजों की 'युद्ध तत्परता' और 'सुरक्षा मानक' – दोनों में वृद्धि की उम्मीद है।

विदेशी संचालन

4.10 **नैवडैक्स-17:** एक उन्नत हल्के विमान (एएलएच) के साथ भारतीय नौसेना का सुनयना नामक जहाज, भारत में स्वदेशी जहाज और विमान निर्माण की क्षमता का प्रदर्शन करने के 18 से 24 फरवरी, 2017 के दौरान अबू धाबी में आयोजित नौसेना रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी (एनएवीडीएक्स) 2017 में सम्मिलित हुआ।

4.11 पूर्वी बेड़े की विदेश में तैनाती (ओएसडी)

(क) भारतीय नौसेना के एस सह्याद्री, शिवालिक, कामोर्ता और ज्योति जहाजों सहित पूर्वी बेड़े को मई-जून 2017 में दक्षिणी हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत में तैनात किया गया था। जहाजों ने सिंगापुर, क्वानतान, जकार्ता, सुरबाया, पोर्ट मोरेस्बी और फ्रेमेंटल बंदरगाहों का दौरा किया।

(ख) **एशियान और इंद्र 17 के लिए ओएसडी:** पूर्वी बेड़े जहाजों सतपुड़ा और कट्ट को थाईलैंड में रूसी नौसेना और आसियान अंतर्राष्ट्रीय बेड़े की समीक्षा (आईएफआर) के साथ एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र-17 के लिए तैनात किया गया था। जहाजों ने सिंगापुर, हैफोंग, वियतनाम, मनीला, फिलीपींस, सैसेबो (जापान), प्लादिवोस्तोक, रूस, बंदर सेरी बागवान (ब्रुनेई), सिहानौकविले (कंबोडिया), बेलवान (इंडोनेशिया),

लामेकबांग (आसियान आईएफआर के लिए थाईलैंड) और पोर्ट केलंग (मलेशिया) बंदरगाहों का दौरा किया।

4.12 **पश्चिमी बेड़े की विदेश में तैनाती:** पश्चिमी बेड़े के जहाज मुंबई, त्रिशूल और आदित्य अप्रैल-मई 2017 में विदेश में तैनाती पर भूमध्य सागर /अटलांटिक महासागर रवाना हुए:

(क) जहाजों ने 17 से 20 अप्रैल, 2017 तक सौदा बे, ग्रीस का दौरा किया और ग्रीक (यूनानी) नौसेना के साथ अभ्यास किया। उन्होंने 24 से 30 अप्रैल, 2017 तक टाउलॉन, फ्रांस में पूर्व-वरुण (फ्रेंच नौसेना के साथ सालाना आयोजन) में भाग लिया। इसके बाद, जहाजों ने वेलेनिया (स्पेन), अलेक्जेंड्रिया (मिस्र), हाइफा (इजराइल) और मई 2017 के अंत में मुंबई आने से पहले जेद्दा (सऊदी अरब) बंदरगाहों का दौरा किया।

(ख) भारतीय नौसेना के जहाज तरकश को अप्रैल से जुलाई 2017 तक विदेशों में तैनात किया गया था। यह जहाज मई 2017 में प्लेमाउथ और लंदन, यू.के. गया था और रॉयल नेवी के साथ वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास पूर्व-कोंकन में भाग लिया। जहाज ने लिस्बन (पुर्तगाल), कैसाब्लांका (मोरक्को), लागोस (नाइजीरिया), लुआंडा (अंगोला), पोर्ट ऑफ वाल्विस बे (नामीबिया), केप टाउन (दक्षिण अफ्रीका) और पोर्ट लुइस (मॉरीशस) का भी दौरा किया।

4.13 **आईएनएसवी म्हादेई के विदेश में तैनाती:** नवंबर-दिसंबर, 2016 में केवल महिला चालक दल (छह अधिकारी) के साथ, भारतीय नौसेना जलयान (भारतीय नौसेना एसवी) म्हादेई ने गोवा से केप टाउन (दक्षिण अफ्रीका) के लिए कूच किया। पोत ने जहाज के छह अधिकारियों (दो महिला अधिकारियों सहित) केप टू रियो रेस 2017 में भाग लिया। दौड़ के सफल समापन पर 22 जनवरी 2017 को उसने रियो डी जनेरियो में प्रवेश किया और 1 फरवरी, 2017 को वहां से रवाना हो गया। इसके बाद, यह जहाज 25 फरवरी, 2017 को केप टाउन और 22 मई 2017 को गोवा पहुंचा।

प्रमुख अभ्यास

4.14 **अभ्यास परिक्षण:** पश्चिमी नौसेना कमान ने 7 से 9 अगस्त, 2017 तक 'अभ्यास परिक्षण' नामक एक

परिचालन स्तर की शीर्ष त्रि-सेवा के युद्ध खेल का आयोजन किया। इस युद्ध खेल में क्षेत्र के, नौसेना मुख्यालय के प्रतिनिधियों और सेना और वायु सेना के संचालन संबंधी कमांडो ने भाग लिया।

4.15 **डीएनएक्स-17:** अंडमान निकोबार कमान (एएनसी) में 20 से 25 नवंबर, 2017 के दौरान संयुक्त सेवा अभ्यास 'अंडमान और निकोबार अभ्यास' (डीएनएक्स-17) आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना/आईसीजी जहाजों, भारतीय नौसेना / आईएएफ / आईसीजी विमानों और सेना के एएनसी और सेना के अन्य कमानों से, आईएन, आईए और आईएएफ ने अभ्यास में भाग लिया।



डीएनएक्स-17

विदेशी नौसेना के साथ अभ्यास

4.16 **मालाबार अभ्यास 2017:** पूर्व मालाबार का 21 वां संस्करण 9 जुलाई से 17 जुलाई, 2017 तक, चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना और जापान समुद्री स्व-रक्षा बल (जेएमएसडीएफ) ने इस अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग और अंतर-क्षमता को बढ़ाना था।

4.17 **वरुण -17:** पश्चिमी बेड़े के जहाज मुंबई, त्रिशूल और आदित्य ने फ्रांस के टूलॉन में 17 अप्रैल 2017 को वरुण अभ्यास में भाग लिया।

4.18 **कोंकण -17:** आईएनएस तरकश ने यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के साथ मई 2017 में अभ्यास, कोंकण -17 में भाग लिया। जहाज इस शिविर में अभ्यास के दौरान प्लेमाउथ और

लंदन गया और 'इंडिया-यूके ईयर ऑफ कल्चर' के हिस्से के रूप में एचएमएस ट्राइकोमाली द्वि-शताब्दी समारोह और लंदन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया।

4.19 **सिमबैक्स -17:** सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के साथ 12 मई से 21 मई 2017 को सिंगापुर में वार्षिक अभ्यास, पूर्व-सिम्बैक, आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना के शिवालिक, सह्याद्री, कामोर्ता और ज्योति नामक जहाजों ने इस अभ्यास में भाग लिया।

4.20 **इंद्र-17:** भारत-रूस संयुक्त त्रि-सेवा अभ्यास इंद्र-17 व्लादिवोस्तोक, रूस संघ में, 19 से 29 अक्टूबर, 2017 तक आयोजित किया गया था। यह दोनों देशों के बीच त्रि-सेवा का पहली द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। व्लादिवोस्तोक में नौसेना संचालन का हिस्सा आयोजित किया गया।



व्लादिवोस्तोक में उद्घाटन समारोह

4.21 **ऑसिनडैक्स -17:** ऑस्ट्रेलिया के तट पर संयुक्त राजकीय ऑस्ट्रेलियाई नौसेना- भारतीय नौसेना (पूर्व-ऑसिनडैक्स) द्वारा 13 से 19 जून, 2017 तक आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में शिवालिक, कामोर्ता और ज्योति नामक जहाजों ने भाग लिया।

4.22 **स्लिनैक्स -17:** पूर्वी नौसेना कमान ने 7 से 14 सितंबर, 2017 तक श्रीलंका-भारत नौसेना अभ्यास, स्लिनैक्स 17 की मेजबानी की। श्रीलंका के नौसेना के जहाज सयुरा और सागर और भारतीय नौसेना के जहाज घड़ियाल और कोरा ने इस अभ्यास में भाग लिया।

4.23 **नसीम-अल-बहर:** मस्कट से बाहर 16 से 22 दिसंबर, 201 तक भारतीय नौसेना और रॉयल ओमान नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था। भारतीय

नौसेना के जहाज तेग और त्रिकांड, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी शंकुश और एक पी8आई विमान ने अभ्यास में भाग लिया।

हिंद महासागर क्षेत्र की तटीय नौसेनाओं के साथ समन्वित गश्त (सीओआरएपीएटी)

4.24 **भारत - थाईलैंड समन्वित गश्त (सीओआरएपीएटी):** भारत-थाई कोरपैट (वर्ष 2005 से आयोजित) साल में दो बार आयोजित किया जाता है। 24वीं भारत-थाईलैंड समन्वित गश्त 13 अप्रैल से 21 अप्रैल, 2017 तक आयोजित की गयी। आईएनएस चीता, भारतीय नौसेना विमान डोर्नियर के साथ थाईलैंड नौसेना के जहाज लांगलॉम और थाईलैंड नौसेना डोर्नियर 228 में समन्वयित गश्त में भाग लिया। उद्घाटन समारोह 13 अप्रैल, 2017 को फुकेत में आयोजित किया गया था और 20 अप्रैल, 2017 को पोर्ट ब्लेयर में समापन समारोह संपन्न हुआ।

4.25 **हिंद महासागर क्षेत्र की तटीय नौसेनाओं के साथ समन्वित गश्त (सीओआरएपीएटी)**

(क) वर्ष 2002 से भारत-इंडोनेशिया कोरपैट साल में दो बार, आयोजित किया जाता है। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच 29वां कोरपैट 9 से 25 मई, 2017 तक आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह 9 से 12 मई, 2017 तक पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना पोत कार्मुक और भारतीय नौसेना विमान डोर्नियर ने इंडोनेशियाई पोत सुतेदी सेनोपुत्र और इंडोनेशियाई विमान सीएन-235 के साथ इस अभ्यास में भाग लिया। इस समन्वित गश्त का समापन समारोह 22 से 24 मई, 2017 तक इंडोनेशिया के बोलावां में सम्पन्न हुआ।



भारत-इंडोनेशिया कोरपैट

(ख) भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच 30वां भारत-इंडोनेशिया कोरापैट 24 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2017 तक आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह 24 से 26 अक्टूबर, 2017 तक इंडोनेशिया के बेलवान में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना के जहाज सुकन्या, भारतीय नौसेना के विमान डोर्नियर -235, इंडोनेशियाई जहाज इमाम बोनजोल और इंडोनेशियाई कासा विमान पी-862 ने इस अभ्यास में भाग लिया। समन्वित गश्त का समापन समारोह 3 नवंबर, 2017 को पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया।



भारत - इंडोनेशिया समन्वित गश्त

डकैती प्रतिरोध

4.26 हिंद महासागर क्षेत्र में नौपरिवहन को सुरक्षा प्रदान करने की अपनी व्यापक भूमिका के भाग के रूप में, भारतीय नौसेना ने एक जहाज को अदन की खाड़ी में आतंकवाद विरोधी गश्त के लिए तैनात किया है। दिसंबर 2017 तक भारतीय नौसेना के कुल 65 युद्धपोतों को तैनात किया गया है, जिन्होंने सुरक्षित रूप से 3788 से अधिक (405 भारतीय ध्वज से ध्वजांकित) जहाजों का मार्गरक्षण किया, जिनमें 24,858 से अधिक नाविकों को तैनात किया गया था। अब तक भारतीय नौसेना ने चोरी के 44 प्रयासों को ध्वस्त कर दिया और 120 समुद्री डाकू पकड़े। भारतीय नौसेना भारतीय समुद्री क्षेत्रों में समुद्र में अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने और सोमालिया सहित उच्च समुद्र में जल पर्यटन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय व्यापार का बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना की मौजूदगी को बनाए रखा जा रहा है।



डकैती प्रतिरोध संचालन

4.27 मेजबान सरकारों के अनुरोध पर मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स के ईईजेड में निगरानी के लिए भारतीय नौसेना के जहाजों और विमानों को नियमित रूप से तैनात किया जा रहा है।

तटीय सुरक्षा

4.28 भारतीय नौसेना समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्रक अभिकरण है जिसमें तटीय सुरक्षा और अपतटीय सुरक्षा शामिल है। विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों और संगठनों के साथ समन्वय में तटीय सुरक्षा मुद्दों को आवश्यक गतिशीलता प्रदान की गई है। भारतीय नौसेना तटीय सुरक्षा के लिए नौकाओं की खरीद, रखरखाव और दोहन के लिए बीएसएफ/सीआईएसएफ/राज्य समुद्री पुलिस को सहायता दे रही है।

4.29 भारतीय नौसेना और आईसीजी के 51 स्टेशनों को जोड़ने और कई विविध संवेदकों को एकीकृत करने के लिए कार्यक्षेत्र की जागरूकता को विकसित करने और अंतर-एजेंसी समन्वय के लिए राष्ट्रीय नियोग प्रतिबंध संचार-व्यवस्था प्रज्ञता (एनसी 3 आई) तंत्र का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा रहा है। भारतीय नौसेना सभी समुद्री साझेदारों के बीच समन्वय भी बढ़ा रही है जिनमें भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय वायु सेना, केंद्रीय और राज्य की समुद्री संस्थाओं और समुद्री खुफिया संस्थाओं के लिए समुद्री कार्यक्षेत्र की जागरूकता और तंत्र केंद्र संचालन शामिल है। इसके अलावा, नौसेना आईओआर और उससे आगे दोनों में, अनुकूल राष्ट्रों के बीच सफेद शिपिंग और हवाई यातायात की जानकारी साझा करने के लिए समझौतों का अनुसरण कर रही है।

4.30 सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा

तंत्र को व्यवस्थित करने, अंतर-संस्थाओं के समन्वय में सुधार और समुद्री, तटीय और अपतटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से तटीय और अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। समुद्री सुरक्षा सांचे को एकीकृत करने के लिए भारतीय नौसेना सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से मछुआरों और तटीय समुदायों के साथ जुड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। भारतीय नौसेना सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ, मौजूदा तंत्रों को मजबूत कर रही है और इस तरह के अभ्यासों की जटिलता में वृद्धि कर रही है।

विदेशी सहयोग

4.31 **सागर संचालन प्रशिक्षण-विदेशी जहाज:** संचालन सागर प्रशिक्षण के अंतर्गत सेशेल्स तटरक्षक सेना का विमान टोपाज़ (6-11 फरवरी, 2017) और मॉरीशस तट रक्षक सेना का विमान वैलियन्ट (8-13 मई, 2017) के प्रथम कर्मचारी समुद्री जांच (एसएससी) किया गया था जिसे संबंधित जहाजों और उनके उपकरण के अनुकूल बनाया गया था।



सागर संचालन प्रशिक्षण – विदेशी जहाज

4.32 **मालदीव में एसएआर संचालन:** मई 2017 में, मालदीव सरकार ने नागरिक सामान उतारने के छोटे जलपोत, मारिया 3 के बारे में सहायता और बचाव (एसएआर) सहायता के लिए अनुरोध किया था, जिसमें कर्मीदल (एक महिला सहित) के छह सदस्य गायब हो गये थे। मालदीव में तैनात भारतीय नौसेना के एक उन्नत हलके हेलीकॉप्टर (एएलएच) को तुरंत रवाना किया गया था और माल जहाज के ईईजेड निगरानी के लिए तैनात भारतीय नौसेना के जहाज किर्च को खोज के लिये भेजा गया। इसके बाद, 20 मई, 2017 को एसएआर संचालन बढ़ाने के लिए एक भारतीय नौसेना डोर्नियर विमान को तैनात किया गया था। डोर्नियर ने मारिया 3

की पहचान की और किर्च को लैंडिंग क्राफ्ट में निर्देशित किया। खराब मौसम और समुद्र के विषम मिज़ाज के बावजूद, किर्च ने मारिया 3 के चालक दल के सभी सदस्यों को बचाया और चालक दल के सदस्यों को मालदीव सरकार को सौंप दिया।

4.33 **समुद्री चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान का 33वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन:** 31 अगस्त से 1 सितंबर, 2017 तक भारतीय नौसेना एचएस अश्विनि, मुंबई में समुद्री चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान का 33वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम ने बहु-नौसेना चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में विचारों और अवधारणाओं के आयामी ढांचे के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। नौ सहायक विदेशी नौसेना (इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, बांग्लादेश, केन्या, ओमान, श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम) के 22 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

4.34 **आईएनएस घड़ियाल द्वारा बांग्लादेश में राहत सामग्री:** बांग्लादेश में रोहिंगिया शरणार्थी संकट के बाद, एक उभयचर जहाज, आईएनएस घड़ियाल, को 777 टन राहत सामग्री के साथ 25 से 28 सितंबर, 2017 के बीच बांग्लादेश सरकार को सौंपा गया था।



आईएनएस घड़ियाल द्वारा बांग्लादेश में राहत सामग्री

4.35 **बांग्लादेशी मछुआरों का बचाव:** भारतीय नौसेना के जहाज सुमित्रा को बंगाल की उत्तरी खाड़ी में तैनात किया गया ताकि चक्रवात 'मोरा' के बाद तत्काल सहायता मिल सके। इस तैनाती के दौरान, जहाज ने समुद्र में फंसे बांग्लादेश के 33 मछुआरों को बचाया। समुद्र में खोज और बचाव अभियान पूरा होने पर, सुमित्रा ने एचएडीआर सहायता प्रदान करने के लिए 1 जून, 2017 को चंडीगढ़ में प्रवेश किया। बांग्लादेश सरकार ने मुश्किल हालातों में राहत सामग्री के लिए और समुद्र में बांग्लादेश के नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार और भारतीय नौसेना

पोत सुमित्रा के चालक दल के सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।



आईएनएस सुमित्रा द्वारा बांग्लादेशी मछुआरों का बचाव

4.36 **खोज और बचाव सम्मेलन विशेष एसएआर पुरस्कार – भारतीय नौसेना एस सुमित्रा:** अनुसूचित व्यावसायिकता, प्रतिबद्धता और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड द्वारा आईएनएस सुमित्रा को विशेष एसएआर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

4.37 **म्यांमार में राहत अभियान:** चटगांव से नौकायन के बाद, भारतीय नौसेना के जहाज सुमित्रा ने चक्रवात 'मोरा' के बाद म्यांमार को राहत सहायता प्रदान की। यह 6 से 8 जून, 2017 तक यांगून में रहा और आवश्यक सहायता प्रदान की।



म्यांमार को राहत सहायता

4.38 **गोवा समुद्री सम्मेलन (जीएमसी) :** गोवा के नौसेना युद्ध कॉलेज में 1 नवंबर, 2017 को पहला गोवा समुद्री सम्मेलन (जीएमसी आयोजित किया गया। नौसेना प्रमुख/समुद्री संस्थाओं के प्रमुख/बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। गोवा के नौसेना युद्ध कॉलेज में रक्षामंत्री द्वारा 1 नवंबर, 2017 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय समुद्री चुनौतियों को संबोधित

करना था, जिसमें समुद्री खतरों और बल संरचना, समुद्री डोमेन जागरूकता, समुद्री सुरक्षा वास्तुकला, और हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने पर चर्चा की गई।

4.39 **श्वेत जहाज समझौते पर हस्ताक्षर :** भारतीय नौसेना हमारी रुचियों के अनुसार हमारे समुद्री क्षेत्र की जागरूकता बढ़ाने के लिए, विभिन्न मित्रतापूर्ण विदेशी नौसेनाओं के साथ मिलकर श्वेत जहाज सूचना के आदान-प्रदान के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए काम कर रही है। इस दिशा में, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इजराइल, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, ओमान, स्पेन, सिंगापुर, श्रीलंका, यूके, अमेरिका और वियतनाम समेत 13 देशों के साथ श्वेत जहाज करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इन देशों में से सात ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मॉरीशस, सिंगापुर, श्रीलंका, अमेरिका और वियतनाम के साथ कार्यान्वित किए गए हैं।

4.40 **विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की निगरानी:** मेजबान सरकार के अनुरोध पर भारतीय नौसेना मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स के ईईजेड निगरानी नियमित रूप से करती है:

(क) **मालदीव के ईईजेड की निगरानी:** ईईजेड की निगरानी के दौरान आईएनएस कंकारसो की एक विशेष टीम में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) जहाज हुरवी पर पानी के नीचे पतवार की जोड़ाई की थी, जिससे एमएनडीएफ के लिए जहाज की संचालन क्षमता उपलब्ध कराई।

(ख) **सेशेल्स और मॉरीशस की ईईजेड की निगरानी:** भारतीय नौसेना के जहाज तरकस को ईईजेड निगरानी के लिए तैनात किया गया था और अक्टूबर-नवंबर 2017 में सेशेल्स और मॉरीशस को बाहरी द्वीप समर्थन प्रदान किया गया था। इस जहाज ने कर्मियों और भंडार को पोर्ट लुइस से बाहरी द्वीप तक स्थानांतरित किया था (जो पोर्ट लूईस से लगभग 600 समुद्री मील उत्तर में है)। इसमें जनरेटर के भागों का स्थानांतरण किया गया था, जिन्हें द्वीप को बिजली प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया।

4.41 **वाटरजेट तेज गश्ती पोतों की आपूर्ति:** भारत ने मॉरीशस तटरक्षक बल के लिए दो वाटरजेट तेज गश्ती पोतों की आपूर्ति की। भारतीय नौसेना की देखरेख के अंतर्गत मैसर्स

जीएसएल में बहादुर और विजय नामित जहाजों का निर्माण किया गया था। भारतीय नौसेना के जहाजों ने दोनों जहाजों को मॉरीशस तक पहुंचाया, जहां उन्हें क्रमशः 10 दिसंबर, 2016 और 16 अगस्त 2017 को मॉरीशस तटरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था।

4.42 **एसएलएनएस सयुराला का कार्यान्वयन:** श्रीलंकाई नौसेना (एसएलएन) के लिए मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला एओपीवी, 22 जुलाई, 2017 को श्रीलंका को सौंप दिया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा एओपीवी को 2 अगस्त, 2017 को कोलंबो में एसएलएनएस सयुराला के रूप में प्रस्तुत किया गया था।



एसएलएनएस सयुराला का कार्यान्वयन

नौसेना-से-नौसेना का परस्पर संपर्क

4.43 **आईओआर के लिए तटीय अभ्यास:** हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे एचएडीआर प्रयासों के समन्वय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर, भारतीय नौसेना ने 'वार्षिक त्रि-सेवा एचएडीआर अभ्यास' में भाग लेने के लिए श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार से 'पर्यवेक्षकों' आमंत्रित किया, जिसे पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना द्वारा 18 से 20 मई 2017 तक आयोजित किया गया। इसके अलावा, हिंदमहासागर के तटवर्ती देशों के मध्य स्तर के नेताओं को नीले पानी के संचालन का अनुभव प्रदान करने के लिए, भारतीय नौसेना ने 25 अक्टूबर, 2017 को 'अभ्यास सम्बन्ध' का आयोजन किया, जिसमें 18 सहायक विदेशी देशों से 'पर्यवेक्षकों' को भारतीय नौसेना की क्षमताओं को दिखाया गया था, जिनमें श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, मॉरीशस, मालदीव, सेशेल्स, मोज़ाम्बिक, ओमान, म्यांमार, थाईलैंड,

इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, कतर, तंजानिया और मेडागास्कर शामिल हैं।



संबंध -17

4.44 **नौसेना-से-नौसेना कर्मचारी वार्ता:** भारतीय नौसेना ने इस वर्ष के दौरान कई मित्र देशों की नौसेना के साथ कर्मचारी वार्ता आयोजित की। 'कर्मचारी वार्ता' के दौरान, बांग्लादेश, फ्रांस, सिंगापुर, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, इंडोनेशिया और ओमान (उद्घाटन) के साथ समुद्री सहयोग और द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चाएं आयोजित की गईं। 'कर्मचारी वार्ता' के दौरान परिचालन अंतःक्रिया, हाइड्रोग्राफी में सहयोग, श्वेत नौवहन सूचना का प्रशिक्षण और साझा करने जैसे कुछ आम मुद्दों पर चर्चा की गई।



एडमिरल का कप

4.45 **नौसेनाध्यक्ष का कप:** भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए), एजीमाला में 2 दिसंबर से 8 दिसंबर, 2017 तक

अंतरराष्ट्रीय नौकायन रेगाटा के आठवें संस्करण, नौसेनाध्यक्ष का कप रेगाटा –2017 आयोजित किया गया। भारत से दो टीमों (भारतीय नौसेना ए और एनडीए) को छोड़कर 26 देशों ने नौकायन रेगाटा में भाग लिया। वियतनाम की टीम ने एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। 27 देशों (भारत सहित) के 8 महिला और 47 पुरुष प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना ए की टीम समग्र रूप से दूसरे स्थान पर रही। सैनिक छात्र प्रवीण प्रभाकर को व्यक्तिगत पुरुष वर्ग में रजत पदक से सम्मानित किया गया।

प्रवर्तन और संचालन से हटाना

4.46 **आईएनएस किल्टन का प्रवर्तन:** परियोजना– 28 जंग विरोधी पनडुब्बी (एएसडब्ल्यू) का तीसरा जहाज, आईएनएस किल्टन, 16 अक्टूबर 2017 को रक्षामंडल द्वारा संचालित किया गया था। किल्टन को प्रवर्तन में लाना परिष्कृत युद्धपोतों के डिजाइन और निर्माण में भारत की विशेषज्ञता का एक प्रतिमान है और स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। जहाज भारतीय नौसेना के आंतरिक डिजाइन संगठन, नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है, और मैसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा तैयार किया गया है। आईएनएस किल्टन कार्बन फाइबर प्रबलित कम्पोजिट सामग्री से बना पूरे संरचना के साथ पहला प्रमुख युद्धपोत है। पहली बार संमिश्रित उत्कृष्ट संरचना के एक प्रमुख युद्धपोत पर हथियार और संवेदक स्थापित/अंतर-स्थापित किए गए हैं।



आईएनएस किल्टन का प्रवर्तन

4.47 **लैंडिंग क्राफ्ट उपयोगिता (एमके IV) का प्रवर्तन:** एलसीयू (मार्क IV) परियोजना के आठ में से पहले जहाज आईएन

एलसीयू एल 51 को 28 मार्च, 2017 को अंडमान निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ, वाइस एडमिरल द्वारा पोर्ट ब्लेयर में संचालन में शामिल किया गया। दूसरे जहाज, आईएन एलसीयू एल 52 को 21 अगस्त 2017 को पोर्ट ब्लेयर में लेफ्टिनेंट गवर्नर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा संचालन में शामिल किया गया।



आईएन एलसीयू (एमके IV)

4.48 **आईएनएस तिलानचांग और आईएनएस तारसा का प्रवर्तन:** अनुवर्ती वॉटरजेट फास्ट अटैक क्राफ्ट परियोजना के तीसरे और चौथे जहाज (तिलानचांग और तारसा) को 9 मार्च, 2017 और 26 सितंबर, 2017 को कारवार और मुंबई में क्रमशः वाइस एडमिरल, फ्लैग ऑफिसर वेस्टर्न नवल कमान के कमांडिंग-इन-चीफ द्वारा प्रवर्तित किया गया।



आईएनएस तिलानचांग और आईएनएस तारसा का प्रवर्तन

4.49 **आईएनएस कलवरी का प्रवर्तन** परियोजना–75 की पहली पनडुब्बी, कलवरी, को मैसर्स एमडीएल ने 21 सितंबर, 1927 को भारतीय नौसेना को सौंपा था। प्रधान मंत्री द्वारा 14 दिसंबर, 2017 को पनडुब्बी को संचालन में शामिल किया गया।

4.50 **संचालन से हटाना:** भारतीय नौसेना में 30 साल की शानदार सेवा के बाद 6 मार्च, 2017 को विमान वाहक आईएनएस विराट को नौसेना से विदाई दी गई। 2017 में भारतीय नौसेना के जहाजों में आग्रे, मटंगा, कारवार, काकीनाडा और पनडुब्बी सिंधुरक्षक को भी संचालन से हटाया गया था।

जहाजों का शुभारंभ

4.51 **एनओपीवी – शची और श्रुति:** पलैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान, वाइस एडमिरल की पत्नी ने 25 जुलाई, 2017 को आरएनएल शिपयार्ड, पिपावाव, गुजरात में पांच नौसैनिक अपतटीय गश्ती जहाजों में से पहले दो जहाजों शची और श्रुति के शुभारंभ किया था।

4.52 **यार्ड 11876 (खांडेरी):** परियोजना-75 की खांडेरी नामक दूसरी पनडुब्बी का शुभारंभ रक्षा-राज्य मंत्री की पत्नी ने 12 जनवरी, 2017 को एमडीएल में (यार्ड 11876) किया था।



खांडेरी का शुभारंभ

4.53 **फ्लोटिंग डॉक नेवी-2:** कट्टुपल्ली में मैसर्स एल एंड टी शिपयार्ड में निर्मित, एफडीएन-2 का 20 जून 2017 को चेन्नई के पास कट्टुपल्ली में शुभारंभ किया गया था। एफडीएन-2 7 मीटर तक ड्राफ्ट के जहाजों की डॉकिंग और 8000 टन तक विस्थापन में सक्षम होगा।



एफडीएन-2 का शुभारंभ

नौसेना विमानन

4.54 नौसेना विमानन आधुनिकीकरण के अपने रास्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुँच गया है। नौसेना की वायु शाखा को भविष्य के एक सक्षम, पेशेवर रूप से काबिल और सक्रिय रूप से तैयार करने के लिए कई पहलें की गई हैं। इस दिशा में, पी8आई, हॉक एजेटी और मिग-29 जैसे आधुनिक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, 16 एएलएच एमके एफ, 12 डोर्नियर्स और आठ चेतक हेलीकाप्टरों की खरीद के लिए अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया है।

4.55 **मिग29के/केयूबी:** मिग29के/केयूबी एक बहुभूमिका युक्त, जहाज आधारित लड़ाकू विमान है जिसे हवाई लक्ष्य को नष्ट करने के साथ-साथ सतह के जहाजों और दुश्मन की किनारे की वस्तुओं को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। विमान में हवा से हवा, हवा से जमीन और हवासे समुद्री लक्ष्यों पर वार करने के लिए उच्च गति-से-वजन अनुपात, उच्च गतिशील प्रदर्शन, आधुनिक वायुयान और हथियार हैं। अनुबंध के अनुसार 45 विमानों की प्रदायगी की गई है, जिनमें से 38 को स्वीकार किया गया है।



मिग 29 के कॉकपिट में रक्षा मंत्री

महत्वपूर्ण दिलचस्प घटनाएं

4.56 **सागर में सांसद/विधायक दिवस:**

- (क) प्रधान मंत्री के निर्देशों के अनुपालन में 10 जनवरी 2017 को केरल राज्य के सांसदों / विधायकों के लिए कोच्चि में सागर में एक दिन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की तटीय सुरक्षा वास्तुकला की एक झलक दिखाना और समुद्र से आने वाले खतरों और चुनौतियों का मूल्यांकन करने में राज्य के वरिष्ठ नेतृत्व की सहायता करना था।

(ख) तमिलनाडु राज्य के सांसदों/विधायकों और राज्य सरकार के अधिकारियों ने लिए 18 अप्रैल, 2017 को सागर में एक दिन आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना के रणवीर, चेन्नई और सुमेधा जहाजों ने चेन्नई से किए गए इस आयोजन में भाग लिया। 17 सांसदों, 137 विधायक और 71 मीडिया कर्मियों सहित कुल 654 अतिथि कार्यक्रम के लिए चेन्नई और सुमेधा आए थे।

4.57 **भारतीय नौसेना की पनडुब्बी शाखा को राष्ट्रपति के रंगों का पुरस्कार:** राष्ट्रपति ने दिसंबर 8, 2017 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी शाखा को राष्ट्रपति के रंगों से सम्मानित किया।



पनडुब्बी शाखा के लिए राष्ट्रपति के रंगों का पुरस्कार

4.58 **तट से तट तक पहुँच कार्यक्रम – वलसुरा:** भारतीय नौसेना ने आईएनएस वलसुरा के प्लैटिनम जयंती उत्सव के एक भाग के रूप में, देश के दोनों तटों के बच्चों और युवाओं के साथ जुड़ने के लिए "तट से तट" नामक एक अद्वितीय सामाजिक आउटरीच कार्यक्रम के साथ इस घटना को उत्सवित किया। पांच कारों में एक विशाल सड़क यात्रा ने सभी प्रमुख नौसेना प्रतिष्ठानों और नौसैनिक समुद्री विरासत मार्गों के स्थानों को छूते हुए 6000 किलोमीटर की दूरी तय की। भारतीय नौसेना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नौसेना टीम ने स्थानीय आबादी, युद्ध के सेनानियों और विधवाओं से बातचीत की और स्कूलों और कॉलेजों का दौरा किया।

4.59 **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस:** 21 जून, 2017 को नौसेना के सभी ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सभी नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों सहित नौसेना स्टेशनों और जहाजों/पनडुब्बियों पर तैनात लोगों सहित कई इकाइयों के लाभ के लिए बहुपक्षीय गतिविधियों का आयोजन किया गया।



अंतर्राष्ट्रीय योगदिवस

4.60 **नविका सागर परिक्रमा:** छह नौसैनिक महिला अधिकारियों ने भारत में निर्मित एक 56 फीट लंबे पोत, आईएनएसवी तारिणी पर नविका सागर परिक्रमा आरंभ की है। यह भारत का पहला पूरी तरह महिला भारतीय दल है, जो दुनिया का चक्कर लगाने निकला है। 10 सितंबर, 2017 को रक्षा मंत्री द्वारा झंडी दिखाकर गोवा से अभियान को रवाना किया गया था और अप्रैल 2018 में इसके गोवा वापस आने की उम्मीद है।



आईएनएसवी के प्रशिक्षु कर्मीदल रक्षा मंत्री से बातें करते हुए

भारतीय वायु सेना





भारतीय वायु सेना

5.1 भारतीय वायु सेना खुद को पूर्ण परिदृश्य क्षमता के साथ एक सामरिक एयरोस्पेस शक्ति में बदलने के लिए समर्पित और केंद्रित आधुनिकीकरण योजना का अनुसरण कर रही है। मौजूदा उपकरणों की निरंतर उन्नति और नए हथियार मंचों को शामिल कर यह सुनिश्चित किया गया है कि वायुसेना आधुनिकीकरण के वांछित मार्ग पर बढ़ना जारी रखेगी। भविष्य में रफेल विमान, हमलावर हेलीकाप्टर, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, युद्ध समर्थन घटकों, जमीन से हवा में मार करने वाले निर्देशित शस्त्र (एसएजीडब्ल्यू) और एयर डिफेंस रडार को शामिल करने से इसकी परिचालन क्षमता और बढ़ेगी। वायुसेना सभी संवेदकों, हथियार प्रणालियों और कमान एवं नियंत्रण संरचनाओं को एकीकृत कर नेटवर्क केंद्र संचालित (एनसीओ) करने की अपनी क्षमता को मजबूत बना रही है।

5.2 भारतीय वायुसेना केंद्रित, निरंतर और विकसित स्वदेशीकरण कार्यक्रमों के जरिए 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है। वायुसेना ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि विदेश निर्मित रक्षा उपकरणों पर भारत की उच्च निर्भरता लगातार कम होती रहे।

अधिग्रहण और उन्नयन

5.3 **एसयू-30 एमकेआई:** भारतीय वायुसेना में एसयू-30 एमकेआई विमान को शामिल करने का कार्य प्रगति पर है। एसयू-30 एमकेआई विमान की वर्तमान खेप प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से एचएएल में निर्मित की जा रही है। 'ब्रह्मोस' सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दृश्य सीमा से परे (बीवीआर) 'अख्र' मिसाइल जैसे उन्नत स्वदेशी हथियारों को स्वदेशी तौर पर एकीकृत किया और विमान से चलाया गया है।



एक एसयू-30 एमकेआई पर ब्रह्मोस मिसाइल

5.4 **हल्का लड़ाकू विमान (तेजस):** प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'मेक इन इंडिया' अभियान के अनुरूप, 1 जुलाई, 2016 को अत्याधुनिक वैमानिकी के साथ एक उन्नत बहु-भूमिका वाले विमान, तेजस के पहले स्क्वाड्रन का गठन किया गया था। इस विमान ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस फ्लाईपास्ट, एयरो इंडिया और वायु सेना दिवस के फ्लाईपॉस्ट में भाग लिया।



हल्के लड़ाकू विमान

5.5 **रैफल:** 23 सितंबर, 2016 को 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए फ्रांस की सरकार के साथ अंतर सरकारी समझौते (आईजीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रथम स्क्वाड्रन को फरवरी 2021 तक और दूसरे स्क्वाड्रन को 2022 अप्रैल तक पूर्ण रूप से सुसज्जित कर लिया जाएगा।



रैफल

5.6 **सी-17 ग्लोबमास्टर III:** सी-17 विमान, उन्नत सीमा के साथ एक भारी सैन्य मालवाहक विमान है और गर्मियों में उच्च ऊँचाई वाले हवाई क्षेत्र से संचालन करने में सक्षम है। मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) संचालन में इस

विमान का सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है और हाल ही में गुजरात और बिहार में बाढ़ राहत कार्यों के दौरान लोगों और सामग्रियों के परिवहन के लिए तथा बांग्लादेश में रोहंगिया शरणार्थियों को राहत सामग्री भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था।



सी-17 ग्लोबमास्टर: एक लंबे दुलाई मिशन के लिए वायुवाहक

5.7 **हरक्यूलिस सी-130जे:** सी-130जे हर मौसम में परिवहन करने वाले विमान को विशेष अभियानों के लिए बनाया गया है। विमान ने नेपाल, बिहार और जम्मू-कश्मीर में हुए कई एचएडीआर संचालनों में अपनी क्षमता प्रमाणित कर दी है। इसने वायुसेना स्टेशन पठानकोट में राष्ट्र-विरोधी तत्वों के खिलाफ अभियान में और श्रीनगर में अर्ध-सैनिकों की तैनाती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2017 में, भारतीय वायु सेना में छह अतिरिक्त सी-130 जे विमानों को शामिल किया है और नाइट विजन गॉगल्स की खरीद के जरिए इसकी परिचालन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।



भारतीय वायु सेना के रंग में सी-130जे विमान

5.8 **उन्नत हल्का हेलीकाप्टर एमके-IV:** उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को एएलएच एमके-4 संस्करण में आगे विकसित किया गया है। सशस्त्र भूमिका निभाने के लिए इसमें रॉकेट, बंदूकें और एयर-टू-एयर मिसाइलों को एकीकृत कर इसे एक सशस्त्र प्लेटफार्म में परिवर्तित किया गया है।



एएलएच एमके -4

5.9 **एमआई-17 वी5 हेलीकाप्टर:** एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर को उच्च ऊँचाई वाले अभियानों के लिए, विशेष रूप से पूरे ग्लास कॉकपिट, उन्नत वैमानिकी, मौसम रडार और शक्तिशाली हवाई इंजन के साथ बनाया गया है। परिवहन, पैराट्रूपर प्रेरण, खोज और बचाव, चिकित्सा निकासी, अग्निशमन और परमाणु रासायनिक जैविक युद्ध जैसे विभिन्न नागरिक और सैन्य अभियानों के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। इसकी रात में देख सकने की गॉगल अनुकूलता इसे कम दृश्यता और रात के समय निर्बाध संचालन में सक्षम बनाती है।



एसएचबीओ में भाग लेते हुए: एमआई -17 वी5

5.10 **हॉक एमके -132 (एडवांस्ड जेट ट्रेनर):** हॉक एमके -132 भारतीय वायु सेना के लड़ाकू प्रशिक्षण में अग्रणी है। यह एक ट्रांसोनिक एंजिन सीट, जमीन पर हमला करने वाला और युद्ध प्रशिक्षण विमान है और अप्रशिक्षित लड़ाकू पायलटों को प्रशिक्षित कर परिचालक युद्धक विमान पर संक्रमण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है।



एसकेएटी रंगों में हॉक एमके -132: उत्कृष्टता का मानवीकरण

विमान उन्नयन

5.11 **मिराज -2000 का उन्नयन:** मिराज 2000 विमान की युद्धक प्रभावशीलता को 'उन्नत विमानन सुइट' के साथ बढ़ाया गया है और नए हथियारों के एकीकरण से इसे एक अधिक शक्तिशाली मंच बना दिया गया है। प्रारंभिक परिचालन मंजूरी डिजाइन और विकास (डी एंड डी) फ्रांस में ओईएम द्वारा पूरा कर लिया गया था और मैसर्स एचएएल द्वारा बेड़े का उन्नयन (फ़्लीट अपग्रेड) किया जा रहा है।



एडी विन्यास में मिराज -2000 का उन्नयन

5.12 **मिग-29 अपग्रेड:** मिग-29 विमान को अत्याधुनिक वैमानिकी और स्मार्ट एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड हथियारों के साथ उन्नत किया जा रहा है। मिग-29 की उड़ान के दौरान पुनः ईंधन भराई की क्षमता में वृद्धि ने इसकी लड़ाकू क्षमता को काफी बढ़ाया है। परियोजना के पहले चरण को रूस

में डिजाइन और विकसित किया गया था। दूसरे चरण में बाकी विमानों की श्रृंखला का उन्नयन भारत में बेस रिपेयर डिपो, नासिक में किया जा रहा है।



मिग 29 उन्नयन: बडी ईधन भराई

5.13 **जगुआर दरीन-III अपग्रेड:** जगुआर विमान को दरीन-III मानकों तक उन्नत किया जा रहा है, जिसमें उन्नत वैमानिकी का एकीकरण शामिल है। दरीन-III विमान की वैमानिकी के साथ संगत, हवा-से-हवा और जहाज-विरोधी हथियार प्रणालियों के एकीकरण के साथ, जगुआर की युद्ध क्षमता में काफी सुधार होगा।



जगुआर: दीप प्रवेश स्ट्रोक विमान

5.14 **एमएलएच अपग्रेड:** मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर के उन्नयन के अनुबंध पर जनवरी 2017 में हस्ताक्षर किए गए थे। उन्नयन से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (ईडब्ल्यू) और बेड़े की रात्रिकालीन परिचालन क्षमता में सुधार होगा।



एमएलएच अपग्रेड

5.15 **विंटेज उड़ान की बहाली:** द्वितीय विश्व युद्ध युग का विंटेज विमान भारतीय वायु सेना के भारतीय उड़डयन और विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग है। बहाली के बादए एक टाइगर मॉथ और एक हार्वर्ड विमान भारतीय वायु सेना के रंगों में काम कर रहे हैं। अधिकांश हवाई प्रदर्शनों का अभिन्न हिस्सा होने के कारणए दोनों पूरे देश में दर्शकों को उत्साहित करते हैं। वे युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के अलावा हमारी समृद्ध उड़डयन विरासत की याद दिलाते हैं।



हार्वर्ड एयरक्राफ्ट: फ्लाइंग प्रदर्शन

अस्त्र, मिसाइल और चेतावनी प्रणाली

5.16 **सेंसर फ्यूज्ड हथियार (एसडब्ल्यूएफ):** भारतीय वायुसेना ने सेंसर फ्यूज्ड हथियार और संबद्ध उपकरण खरीदे हैं। टैंकों और अन्य मशीनकृत वाहनों की एकाग्रता के विरुद्ध इनका उपयोग किया जा सकता है। अस्त्र एकीकरण सितंबर, 2017 में पूरा हो गया है।

5.17 **मिडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (एमआरएसएम):** डीआरडीओ द्वारा सत्यापन फायरिंग परीक्षण के सफलता से पूरा होने के बाद, एमआरएसएम प्रणाली को वायुसेना में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है, यह बहुत कम ऊँचाई से अधिक ऊँचाई तक और मध्यम दूरी से बहुत नज़दीक की दूरी के लक्ष्यों पर वार करने में सक्षम है। भारतीय वायु सेना की आधुनिक आईएसीसीएस प्रणाली के नेटवर्क के जरिए यह हथियार सभी प्रकार के शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों को खत्म कर सकता है, जिसमें घने अवरुद्ध वातावरण वाले बहुत कम आरसीएस भी शामिल हैं।

5.18 **स्पाइडर एलएलक्यूआरएम सिस्टम:** पायथान 5 और डर्बी मिसाइलों से लैस निम्न स्तर त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल प्रणाली स्पाइडर को भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया है। यह प्रणाली एकाधिक लक्ष्य संबद्धता के साथ संतृप्ति हमलों के

लिए एक व्यापक प्रतिक्रिया प्रदान करती है, इस प्रकार यह कम दूरी की एडी क्षमता बढ़ाती है।



स्पाइडर सिस्टम

5.19 **पेचोरा एवं ओएसए-एके:** पेचोरा मिसाइलों को 10 साल के लिए एक नए पट्टे के साथ नवीनीकृत किया जा रहा है। उपकरण को मौजूदा वाल्व आधारित प्रौद्योगिकी से डिजिटलीकृत करने की योजना है। ओएसए-एके मिसाइलों को भी भारत डॉयनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद की मदद से नवीनीकृत किया गया है।



पेचोरा मिसाइल



ओएसए-एके

5.20 **आईजीएलए:** आईजीएलए मिसाइलों प्रक्षेपण प्रणाली का जीवन विस्तार परीक्षण, एचईएमआरएलए बीडीएल और भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके पश्चात् भारतीय वायु सेना द्वारा बिजली की जांच और गतिशील फायरिंग की जा रही है। नवीकरण का कार्य भी बीडीएल, हैदराबाद के साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।

5.21 **एईडब्ल्यू एवं सी (स्वदेशी) सिस्टम:** एम्ब्रेयर-145 विमान पर स्थापित, डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित पहली वायुवाहित प्रारंभिक चेतावनी एवं नियंत्रण (एई डब्ल्यू एंड सी) प्रणाली को फरवरी 2017 में भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था। अत्याधुनिक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन सारणी आधारित रडार प्रणाली दूर तक की हवाई सामग्री की स्थिति का पता लगा सकती है और वायु रक्षा कमान और नियंत्रण केंद्रों को शीघ्र चेतावनी प्रदान करती है। एई डब्ल्यू एवं सी भारत द्वारा सैन्य क्षमताओं के विकास में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी छलांग है।



एईडब्ल्यू एंड सी

5.22 **सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो:** सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो (एसडीआर) को भारतीय वायु सेना के विभिन्न हवाई और जमीनी प्लेटफार्मों पर एकीकृत किया जाएगा, इससे भारतीय वायु सेना की नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता में वृद्धि होगी।

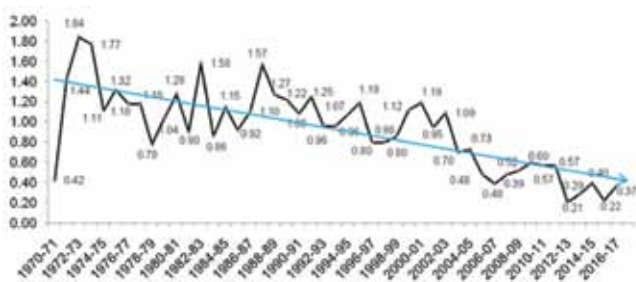


एसडीआर

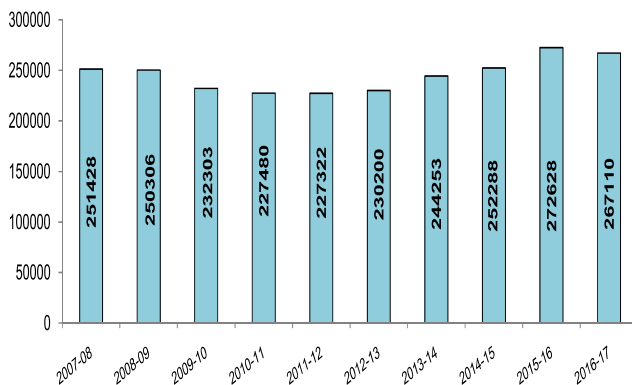
एयरोस्पेस सुरक्षा

5.23 भारतीय वायु सेना और सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप पिछले दशक के दौरान, भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के एयरोस्पेस सुरक्षा रिकॉर्ड में सुधार हुआ है।

5.24 **विमान दुर्घटना दर:** वित्तीय वर्ष के दौरान, वार्षिक विमान दुर्घटना दर की, उड़ान के 10,000 घंटे में वर्ग। दुर्घटनाओं की संख्या के रूप में गणना की गई, पिछले कुछ वर्षों में इसमें एक प्रगतिशील गिरावट देखी गई है। पिछले पैंतालीस वर्षों में वर्ग। की दुर्घटना दर को नीचे दर्शाया गया है:



5.25 **फ़्लाइंग प्रयास:** एक तरफ उड़ान के प्रयासों में निरंतर वृद्धि हुई है और दूसरी तरफ दुर्घटनाओं की दर कम हुई है। यह दर्शाता है कि भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए सुरक्षा उपाय सही दिशा में हैं। इस प्रकार संरक्षित संपत्ति उड़ान में वृद्धि के साथ, परिचालन क्षमता में सीधे योगदान देती है। पिछले दस वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय वायुसेना के वित्तीय वर्ष-वार फ़्लाइंग प्रयासों को नीचे दर्शाया गया है:



5.26 **एयरो मेडिकल सिमुलेटर की खरीद और उन्नयन:** एयरोस्पेस सुरक्षा प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य के साथ, भारतीय वायु सेना एयरक्रू के परिचालन प्रशिक्षण में इन सिमुलेटरों के

उपयोग को बढ़ाने के लिए मौजूदा हवाई चिकित्सा सिमुलेटर के उन्नयन और नए सिमुलेटरों की खरीद की प्रक्रिया में है। एयरो मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर (एएमटीसी) 1 और 2 में दो निष्कासन प्रक्रिया सिमुलेटर स्थापित किए गए हैं और एक लड़ाकू विमान से एयरक्रू में निकलने से पहले की सही प्रक्रिया और आसन के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगस्त 2017 में आईएएम और 1 एवं 2 एएमटीसी में स्थापित स्थानिक डिसओरिएंटेशन (एसडी) सिमुलेटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उन्नयन किया गया है। 1 एएमटीसी के लिए 5 वायु सेना अस्पताल और उच्च प्रदर्शन मानव अपकेंद्रित्र के लिए नए डीआईएसओ सिमुलेटर की खरीद की प्रक्रिया चल रही है।

आधुनिकीकरण और नए स्थापन

5.27 **भारतीय वायु सेना के नए अड्डों का विकास:** भारतीय वायु सेना ने उत्तर-पूर्व में भारतीय वायु सेना के 30 हवाई अड्डों और सात एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) को संयुक्त उपयोग के लिए खोल दिया है और नागरिक अनुसूचित उड़ानों की अधिक संख्या को समायोजित करने के लिए विभिन्न हवाई अड्डों के निगरानी घंटों को विस्तारित किया है। इसके अलावा, भारतीय वायु सेना के भीतर प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र के 20 मार्गों को नागरिक एयरलाइंस द्वारा सशर्त इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, जिससे यात्रा का समय कमी हुई है, ईंधन की बचत हो रही है और कार्बन पदचिह्न को कम किया जा रहा है। यह उन विभिन्न एटीएस मार्गों के अलावा है, जो पहले से ही भारतीय वायु सेना के स्थापित प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र के माध्यम से आवागमन कर रहे हैं। नागरिक विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आर सी एस) – उड़ान के अंतर्गत 24 सैन्य हवाई क्षेत्रों से नागरिक उड़ानों को संचालित करने का प्रस्ताव किया था, जिनमें से 15 एयरोड्रोम भारतीय वायु सेना के हैं। भारतीय वायु सेना के हवाई अड्डों से इन सभी आरसीएस उड़ानों के परिचालन के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा मंजूरी दे दी गई है। आरसीएस उड़ानों को तत्काल शुरु करने के लिए एआई द्वारा इन अड्डों पर अस्थायी व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2017 में भारतीय वायु सेना द्वारा 30 आरसीएस मार्गों को भी मंजूरी दे दी गई है बशर्ते कि आरसीएस के विभिन्न हवाई अड्डों के लिए/से आरसीएस उड़ानों के अंतर्गत अंतिम मील कनेक्टिविटी भारतीय वायु सेना के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र माध्यम से होती हो।

5.28 **रंग कोडित ज़ोनिंग मानचित्र:** रक्षा मंत्रालय द्वारा रियल एस्टेट परियोजनाओं सहित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करने के अधिकार कमान मुख्यालय को सौंपे गए हैं, जिससे भारत सरकार के 'कारोबार में आसानी' के दर्शन के अंतर्गत प्रसंस्करण समय कम हो गया है। भारतीय वायु सेना के सभी हवाईअड्डों के लिए रंग कोडित ज़ोनिंग मानचित्र (सीसीजेडएम) तैयार किए गए हैं और विस्तृत निर्देशों के आधार पर इमारतों/संरचनाओं/बिजली पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए मामलों के प्रसंस्करण के अधिकार स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरणों को सौंपे गए हैं।

5.29 **एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर (एमएफआई) का आधुनिकीकरण:** भारतीय वायु सेना ने एमएफआई प्रोजेक्ट चरण-1 के अंतर्गत उन्नत नौवहन एड्स और कैट -2 एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम के साथ 25 ठिकानों का आधुनिकीकरण किया है।

5.30 **पीसीडीए (पी) इलाहाबाद में एयर फोर्स पेंशन सेल:** 1986 से पहले वायु सेना से सेवानिवृत्त लोगों के मामलों की निगरानी और समयबद्ध तरीके से उन्हें हल करने और प्रभावी संपर्क के लिए पीसीडीए (पी) इलाहाबाद में एक पेंशन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया

5.31 रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण और निर्माण का समर्थन करना, भारतीय वायुसेना के मुख्य क्षेत्रों में एक है, यह रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता को कम करता है। इसके लिए, वायुसेना में हल्के युद्धक विमान, आकाश मिसाइल, एडवांस लाइट हेलीकाप्टर (एएलएच) को शामिल किया गया है। भारतीय वायु सेना भविष्य में अधिक सक्षम और शक्तिशाली एलसीए एमके-आईए को शामिल करने की योजना बना रही है। भारतीय वायुसेना एलसीएच, आरपीए, मध्यम विद्युत रडार, निम्न स्तर ट्रैकिंग रडार और अन्य प्रणालियों के डीओडी का भी सक्रिय रूप से समर्थन करती है और विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक हथियारों के विकास के लिए डीआरडीओ के साथ मिलकर समन्वय करती है।



हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टर

5.32 रक्षा विनिर्माण आधार और पर्यावरण व्यवस्था को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण योजना को अपनाया जा रहा है। भारतीय वायु सेना ने रक्षा उपकरणों की एक श्रृंखला की पहचान की है जिन्हे 'मेक' श्रेणी के अंतर्गत निर्मित किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में निजी क्षेत्र को शामिल करने का प्रयास कर रहा है। 'मेक इन इंडिया' के उद्देश्य से भारत में विमान निर्माण की प्रमुख प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने के लिए एवेरो प्रतिस्थापन विमान के एक मामले में प्रगति हो रही है। हथियार प्रणाली में बंद और 'रणनीतिक भागीदार' मॉडल के अंतर्गत एकल इंजन लड़ाकू विमान केए-226 टी हेलीकाप्टरों का निर्माण 'मेक इन इंडिया' पहल को प्रोत्साहन देगा। इससे रोजगार पैदा होगा और कौशल स्तर में वृद्धि होगी। इसके साथ-साथ देश में एयरोस्पेस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का दोहन करने में भी मदद मिलेगी।

5.33 **एमटी वाहन:** भारतीय वायुसेना ने नई पीढ़ी के वाहनों के साथ अपने एमटी वाहन बेड़े का आधुनिकीकरण किया है, जिससे क्षेत्रीय इकाइयों की क्षमता काफी हद तक बढ़ी है। वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 415 एम टी वाहन खरीदे गए थे। भारतीय वायु सेना ने सबसे पहले जीईएमपोर्ट का इस्तेमाल किया और लगभग 700 वाहनों के लिए आपूर्ति आदेश देने की प्रक्रिया जारी है। भारतीय वायुसेना, सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति को बढ़ावा देने के लिए एयर फील्ड सहायता वाहन और एयरक्राफ्ट स्पेशलिस्ट वाहनों के अनुकूलित निर्माण के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है।

डिजिटल भारत

5.34 **एफसीईएल परियोजना:** भारतीय वायु सेना ने आईएफ कैप्टिव 3जी डब्ल्यूसीडीएमए मोबाइल नेटवर्क

एएफसीईएल स्थापित किया है। नेटवर्क वॉयस कॉल और डेटा सेवाओं के साथ पूरी तरह से काम कर रहा है। आंतरिक पहल में निम्नलिखित अनुप्रयोगों का विकास हुआ है, जिन्हें उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुत करने से पहले प्रमाणित किया गया है:

- (क) त्वरित मैसेजिंग ऐप (एफसीएएटीएटी)
- (ख) भारतीय वायु सेना डायरेक्टरी सर्च ऐप
- (ग) कॉन्फ्रेंस शेड्यूलर ऐप
- (घ) कॉलर-आईडी ऐप
- (ङ) वायु सेना केंद्रीय लेखा कार्यालय (एएफसीएओ) ऐप और वेबसाइट
- (च) मेडवाच ऐप



भारत के राष्ट्रपति एएफसीईएल परियोजना का उद्घाटन करते हुए

5.35 **ई-रखरखाव प्रबंधन प्रणाली (ई-एमएमएस):** भारतीय वायु सेना के लिए केंद्रीकृत और वेब आधारित ई-रखरखाव समाधान के कार्यान्वयन के लिए फरवरी 2013 में, सेना और मैसर्स विप्रो लिमिटेड के बीच 637 करोड़ रुपए (करोड़ों को छोड़कर) के ई-एमएमएस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना की अवधारणा डिजिटल इंडिया मॉडल पर आधारित है और यह दुनिया में सबसे बड़ी रखरखाव मरम्मत ओवरहाल (एमआरओ) आईटी कार्यान्वयन परियोजनाओं में से एक है। इससे भारतीय वायु सेना को अपनी कागज आधारित विरासती रखरखाव प्रणाली को ऑनलाइन सिस्टम में बदलने में मदद मिलेगी। यह परियोजना

भारतीय वायु सेना के 170 साइटों पर लागू की जाएगी, जिसमें संपत्ति के पूरे परिदृश्य को आवृत किया जाएगा। वर्तमान में पुणे और ग्वालियर के वायुसेना स्टेशनों में प्रायोगिक चरण चल रहा है। इन दोनों जगहों पर, विविध प्रकार के महत्वपूर्ण विमान डिजिटल प्रलेखन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। दिसंबर 2018 तक सभी 170 ठिकानों में इसे पूरा करने के लिए कई अन्य क्रियान्वयन गतिविधियां जारी हैं।

5.36 **भारतीय वायुसेना में वेतन की केन्द्रीकृत वितरण प्रणाली (सीडीएस):** 3 अप्रैल 2017 को भारतीय वायु सेना में औपचारिक रूप से वेतन की केन्द्रीकृत वितरण प्रणाली (सीडीएस) शुरू की गई थी। सीडीएस के कार्यान्वयन से पुरानी प्रणाली की अंतर्निहित सीमाएं समाप्त हो गई हैं जिनकी वजह से "वेतन" शीर्ष के अंतर्गत व्यय के संकलन में देरी हो सकती थी, इसके अलावा निम्नलिखित लाभ अर्जित किए जा सकते हैं:

- (i) पहचान पत्र का वितरण और राजस्व मुहरों का उपयोग।
- (ii) वेतन पुस्तिका की व्यवस्था।
- (iii) स्टेशन में किसी व्यक्ति की उपलब्धता या छुट्टी, टी/डी, अस्पताल में भर्ती आदि के कारण उसकी अनुपरिस्थिति के बावजूद वेतन और भत्तों का त्वरित भुगतान।
- (iv) किए जाने वाले खर्च का "वेतन और भत्ते" शीर्ष के अंतर्गत त्वरित संकलन जिससे संदिग्ध खाते को नीचे शून्य तक लाया जा सकता है।

5.37 **ई-भुगतान पहल:** लेखा शाखा ने केंद्रीकृत ई-भुगतान पहल के माध्यम से डिजिटलीकरण में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, पहले यह कार्य 157 निजी लेखा इकाइयों द्वारा किया जाता था। केंद्रीकृत वेतन संवितरण प्रक्रिया क्षेत्रीय इकाइयों से विभिन्न आदानों को डिजिटल रूप से प्राप्त करने और उनके केंद्रीय प्रसंस्करण द्वारा कार्य करती है, इस प्रकार यह लगभग कागज विहीन गतिविधि बन गई है। पूरी प्रक्रिया को किसी भी अतिरिक्त मानव शक्ति या किसी अतिरिक्त लागत के बिना आंतरिक रूप से विकसित कंप्यूटर अनुप्रयोग के माध्यम से स्वचालित किया गया है।





भारतीय तटरक्षक बल





भारतीय तटरक्षक बल

6.1 राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा अंतरिम तटरक्षक संगठन का गठन करने का अनुमोदन दिए जाने पर 1 फरवरी, 1977 को भारतीय तट रक्षक बल (आईसीजी) की स्थापना हुई थी। तटरक्षक अधिनियम, 1978 के अधिनियमन के साथ 19 अगस्त, 1978 को, इस सेवा को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। तटरक्षक बल की शुरुआत 1978 में हुई थी जिसमें भारतीय नौसेना से दो युद्ध पोत और सीमा शुल्क विभाग की पांच गश्ती नौकाएं शामिल थीं। स्थापना के बाद से, इस सेवा ने शांति काल में सौंपे गए कार्यों को करने और युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के प्रयासों का पूरक बनने के लिए सतह और हवाई दोनों क्षेत्रों में एक विस्तृत श्रृंखला की क्षमता हासिल कर ली है।

6.2 **संगठन:** महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक बल (डीजीआईसीजी), तटरक्षक बल की कमान और नियंत्रण संभालते हैं। संगठन के पांच क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, जो गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। इन क्षेत्रों को 14

जिलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक तट रक्षक जिले में एक या एक से अधिक तटरक्षक स्टेशन शामिल हैं, जिनका कुल संख्या 42 है। इसके अलावा, समुद्र तट के साथ विभिन्न स्थानों पर 10 तटरक्षक वायु प्रतिष्ठान अर्थात् एयर स्टेशन (सीजीएस), एयर परिक्षेत्र (सीजीई) और हवा के संचालन के लिए स्वतंत्र एयर स्क्वाड्रन आदि शामिल हैं।

6.3 **कर्तव्य और कार्य:** तटरक्षक बल के कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

- (क) समुद्री क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों, अपतटीय टर्मिनलों, प्रतिष्ठानों और अन्य संरचनाओं एवं उपकरणों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- (ख) संकट के समय सहायता सहित समुद्र में मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करना
- (ग) समुद्री पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करना और समुद्री प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना।

- (घ) तस्करी विरोधी अभियानों में सीमा शुल्क और अन्य अधिकारियों की सहायता करना।
- (ङ) समुद्री क्षेत्र में लागू होने वाले प्रचलित कानूनों के प्रावधानों को लागू करना।
- (च) समुद्र में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और वैज्ञानिक आंकड़ों के संग्रह के उपायों सहित, निर्धारित किये जाने वाले अन्य मामलों में काम करना।

6.4 समय के साथ, भारतीय तट रक्षक को राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव, राष्ट्रीय तेल फैलाव आपदाओं और अपतटीय तेल क्षेत्रों में सुरक्षा के समन्वय प्राधिकरण का काम सौंपा गया है। आईसीजी समुद्री सीमाओं के लिए प्रमुख खुफिया एजेंसी भी है और यह एशिया में नौकाओं के खिलाफ समुद्री डाकू और हथियारबंद डकैती का मुकाबला करने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौते के तहत सूचना साझा करने के लिए भारत में केन्द्र बिन्दु के रूप में काम करता है।

6.5 **मौजूदा बल स्तर:** वर्तमान में, भारतीय तटरक्षक बल के पास भारत के समुद्री क्षेत्रों की नियमित निगरानी के लिए 62 जहाजों, 72 नावें/होवरक्राफ्ट और 62 विमान की क्षमता है।

तटीय सुरक्षा

6.6 भारतीय तटरक्षक बल को तटीय पुलिस द्वारा गश्त किए जाने वाले पानी सहित क्षेत्रीय पानी में अतिरिक्त तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक को तटीय कमांड का कमांडर नामित किया गया है और वे केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में समग्र समन्वय के लिए जिम्मेदार है।

6.7 **तटीय सुरक्षा अभ्यास:** भारतीय तटरक्षक बल, नौसेना के समन्वय में, पूरे तट रेखा के गश्त और निगरानी का काम कर रहा है। मानक संचालन प्रक्रिया के समन्वित गश्त और सत्यापन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए 2009 के बाद से कुल 169 तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए गए हैं।

6.8 **तटीय सुरक्षा संचालन:** विशेष आर्थिक क्षेत्र में गश्त करने और अतिरिक्त तटीय सुरक्षा के लिए तटरक्षक जहाजों और विमानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। 2009 के बाद से, सभी हितधारकों के साथ समन्वय में कुल 300 कस्टम सुरक्षा अभियान किए गए हैं।

6.9 **सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम:** तटतटरक्षक दल सामुदायिक साक्षात्कार कार्यक्रमों के माध्यम से मछुआरों के साथ नियमित रूप से संपर्क करता है। मछुआरों में जागरूकता उत्पन्न करने और खतरा चेतावनी ट्रांसमीटर, जीवन रक्षक नौकाओं और लाइफ जैकेट जैसे जीवनरक्षक उपकरणों के उपयोग के बारे में अवगत कराने के लिए 2009 से, सुरक्षा और संरक्षा के मुद्दों पर 6008 सामुदायिक बातचीत कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

मील के पत्थर और महत्वपूर्ण उपलब्धियां

6.10 वर्ष 2017 के दौरान तीन अपतटीय पेट्रोल जलयान, एक तेज पेट्रोल जलयान और छह इंटरसेप्टर नौकाएं शामिल की गई हैं। वर्ष 2017 के दौरान तीन इंटरसेप्टर नावों को भी शामिल किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

द्विपक्षीय सहभागिता

6.11 वर्ष 2017 के दौरान, भारतीय तट रक्षक बल ने अन्य देशों के तटरक्षक बलों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की हैं:

क्रम सं.	आयोजक	प्रतिभागी	टिप्पणियां
1.	भारतीय तट रक्षक बल, नई दिल्ली	श्रीलंका तट रक्षक बल (एसएलसीजी)	4 जनवरी, 2017 को उच्च स्तरीय बैठक
2.	जापान के तट रक्षक बल, जापान	भारतीय तट रक्षक बल	16-20 जनवरी, 2017 को वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक
3.	भारतीय तट रक्षक बल, नई दिल्ली	वियतनाम तट रक्षक बल (वीसीजी)	29 मई, 2017 को वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक

क्रम सं.	आयोजक	प्रतिभागी	टिप्पणियां
4.	ऑस्ट्रेलियाई समुद्री सीमा कमान, ऑस्ट्रेलिया	भारतीय तट रक्षक बल	26-28 जुलाई, 2017 को सहयोग मजबूत करने और प्रशिक्षण के मार्ग तलाशने के लिए
5.	भारतीय तट रक्षक बल, कोलकाता	बांग्लादेश तट रक्षक बल	27-30, अगस्त 2017 को क्षेत्रीय कमांडर स्तर की पहली बैठक
6.	भारतीय तट रक्षक बल, नई दिल्ली	शाही ओमान पुलिस, तट रक्षक बल (आरओपीसीजी)	30 अक्टूबर, 2017 को उच्च स्तरीय बैठक
7.	कोरिया तट रक्षक बल, कोरिया गणतंत्र	भारतीय तट रक्षक बल	12-14 दिसंबर, 2017 के दौरान उच्च स्तरीय बैठक

6.12 आईसीजीएस समर्थ ने जापान के योकोहामा में, 16-20 जनवरी, 2017 के दौरान आयोजित आईसीजी-जेसीजी के संयुक्त कार्यक्रम में भाग लिया था।

बहुपक्षीय कार्यक्रम

6.13 बांग्लादेश के तटरक्षक दल 'ताजुद्दीन' ने फरवरी, 2017 में भारतीय तटरक्षक दल के साथ गोवा और चेन्नई में आयोजित "मित्रता सेतु" नामक समुद्री अभ्यास में भाग लिया।

6.14 भारतीय तट रक्षक की 40वीं वर्षगांठ और रीकैप की 10वीं वर्षगांठ की स्मृति में, 8-10 फरवरी, 2017 के दौरान गोवा में "सुरक्षित और संरक्षित सागर के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी" आयोजित की गई थी, इस संगोष्ठी में 15 देशों और विभिन्न राष्ट्रीय हितधारकों ने भाग लिया।

6.15 तट रक्षक बल ने 11-12 दिसंबर, 2017 को, नई दिल्ली में रीकैप सूचना साझाकरण केंद्र के साथ 10वीं क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया। डीजी (नौवहन), प्रमुख बंदरगाहों और भारतीय जहाज-मालिकों की एसोसिएशन के प्रतिभागियों के साथ 17 देशों के कुल 34 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

6.16 मॉरीशस सरकार के साथ चल रहे रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में, 7 मार्च, 2017 को एक सद्भावना संकेत के रूप में, इंटरसेप्टर बोट सी-139 को स्थायी आधार पर मॉरीशस सरकार को सौंप दिया गया।

6.17 प्रशिक्षण और विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी उद्देश्यों के लिए 5 सितंबर, 2017 को, आईसीजीएस वरुण को स्थायी रूप से श्रीलंका सरकार को सौंप दिया गया है।

6.18 आईसीजी मालदीव ध्रुव हेलीकॉप्टर को 21 अप्रैल, 2010 को मालदीव में तैनात किया गया है, जिसमें 5 अधिकारी और 19 नामांकित कर्मचारी शामिल हैं, इस हेलीकॉप्टर ने 112 चिकित्सकीय निकासियां की हैं और 119 लोगों को बचाया है।

6.19 तट रक्षक बल के डोर्नियर सीजी 787 और सीजी 776 को क्रमशः 27-31 अगस्त, 2017 और 16-22 सितंबर, 2017 को विशेष आर्थिक क्षेत्र निगरानी के लिए मालदीव भेजा गया था।

6.20 **भारतीय तटरक्षक जहाजों की विदेशों में तैनाती:** भारतीय तटरक्षक जहाजों द्वारा किए गए विदेशी दौरो का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	जहाज	अवधि	देश
(क)	आईसीजीएस समर्थ	29 दिसंबर, 2016 से 1 जनवरी, 2017 तक 7-10 जनवरी, 2017 17-21 जनवरी, 2017 2-5 फरवरी, 2017	मलेशिया फिलीपींस जापान सिंगापुर

क्रम सं.	जहाज	अवधि	देश
(ख)	आईसीजीएस समुद्र पावक	24-28 जनवरी, 2017 30 जनवरी से 2 फरवरी, 2017 4-7 फरवरी, 2017 10-14 फरवरी, 2017	कतर सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात ओमान
(ग)	आईसीजीएस सारथी	10-14 मार्च, 2017 18-22 मार्च, 2017 27-31 मार्च, 2017	मॉरिशस सेशेल्स मालदीव
(घ)	आईसीजीएस शूर	26 मार्च से 2 अप्रैल, 2017 4-8 अप्रैल, 2017	मालदीव श्री लंका
(ङ)	आईसीजीएस वैभव	22 अप्रैल से 3 मई, 2017	मालदीव
(च)	आईसीजीएस सारथी	8-12 अक्टूबर, 2017 18-22 अक्टूबर, 2017 2-6 नवंबर, 2017	मलेशिया इंडोनेशिया श्री लंका
(छ)	आईसीजीएस समर्थ	25-28 अक्टूबर, 2017 30 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2017 4-7 नवंबर, 2017 8-11 नवंबर, 2017	ओमान संयुक्त अरब अमीरात कतर सऊदी अरब
(ज)	आईसीजीएस शौर्य	1-5 दिसंबर, 2017 1-15 दिसंबर, 2017 20-23 दिसंबर, 2017 28 दिसंबर, 2017 से 1 जनवरी, 2018	फिलीपिंस दक्षिण कोरिया हांगकांग सिंगापुर

भारतीय तटरक्षक बल की उपलब्धियां

6.21 तटरक्षक बल की कुछ अन्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैं, जो राष्ट्र की सेवा में तटरक्षक बल द्वारा निभाई गई भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं:

क्रम सं.	1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 की अवधि के दौरान उपलब्धियां	
(क)	प्रतिबंधित जब्ती	3500 करोड़
(ख)	खोज और बचाव (एसएआर) मिशन	276
(ग)	खोज और बचाव (एसएआर) प्रयास	771
(घ)	समुद्र में जीवन रक्षा	950
(ङ)	सागर में चिकित्सा निकासी	49
(च)	शिकार ट्रेवलरों की गिरफ्तारी	11 नावें 69 नाविक
(छ)	समुद्री वन्य जीवन उल्लंघन पर गिरफ्तारी	25 नौकाएं 235 कर्मीदल
(ज)	मछुआरों का प्रत्यावर्तन	श्रीलंका से 354 भारतीय मछुआरों की भारत से 22 श्रीलंकाई मछुआरों की

6.22 खोज और बचाव

(क) **प्रमुख (बीकन) अभ्यास:** 2017 में आयोजित 12वें और 13वें बीकन अभ्यास में रक्षा और नागरिक एजेंसियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

(ख) **एसएआर संप्रेषण अभ्यास:** 2017 में विदेशी एसएआर एजेंसियों के साथ निम्नलिखित एसएआर संप्रेषण अभ्यास आयोजित किए गए थे:

क्रम सं.	तारीख	एसएआर कॉमेक्स के बीच आयोजित	देश
(क)	1 जून, 2017	एमआरसीसी चेन्नई—आरसीसी हिरोशिमा	जापान
(ख)	28 जून, 2017	एमआरसीसी पोर्ट ब्लेयर—एमआरसीसी कोबे	जापान
(ग)	26 अक्टूबर, 2017	एमआरसीसी चेन्नई—एमआरसीसी कोलंबो	श्री लंका
(घ)	3 नवंबर, 2017	एमआरसीसी चेन्नई—एमआरसीसी यंगून	म्यांमार
(ङ)	8 नवंबर, 2017	एमआरसीसी मुंबई—आरसीसी (पश्चिम) कोकपो	कोरिया
(च)	10 नवंबर, 2017	एमआरसीसी पोर्ट ब्लेयर—एमआरसीसी फिलीपिंस	फिलीपिंस
(छ)	07 दिसंबर, 2017	एमआरसीसी पोर्ट ब्लेयर—आरसीसी नगोया	जापान

(ग) राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड (एनएमएसएआरबी) की सोलहवीं बैठक 10 जुलाई, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान समुद्री और वैमानिकीय खोज और मछली पकड़ने की नौकाओं और छोटे जहाजों के लिए सुरक्षा प्रावधानों और बचाव के प्रयासों में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।

(घ) 4 अप्रैल, 2017 को, आईसीजीएस शूर को एक टग और श्रीलंका नौसेना के जहाज (एसएलएनएस) सागर के साथ कोलंबो, श्रीलंका के बाहर एक पनामा कंटेनर पोत, एमएससी डेनिएला को अग्निशमन सहायता देने के लिए तैनात किया गया था। 30 घंटे तक लगातार प्रयासों के बाद, 6 अप्रैल, 2017 को आग पर नियंत्रण किया गया था।

(ङ) आईसीजीएस राजकिरण ने 5 जून, 2017 को, पारादीप से 9 समुद्री मील पूर्व मछली पकड़ने की एक उलट गई नाव से बचे 6 लोगों की जीवन रक्षा की। प्रारंभिक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के बाद, बचाए गए लोगों को पारादीप लाया गया और फिशरी के अधिकारियों को सौंप दिया गया।

(च) सीजी 809 ने 26 जून, 2017 को दक्षिण गोवा के काबो-डे-रामा किले से गायब नौसेना अधिकारी पूर्व-आईएनएस विक्रमादित्य को बचाया।

6.23 चिकित्सा निकासी

(क) **'टग एस्टीम' से चिकित्सा निकासी:** आईसीजीएस सी-418 ने 19 जनवरी, 2017 को, हृदय रोग और टग एस्टीम पर सवार निर्जलीकरण वाले 2 मरीजों को निकाला।

(ख) **'एमवी पैनमैक्स-4' से चिकित्सा निकासी:** तटरक्षक हेलीकाप्टर, सीजी 821 ने 25 जनवरी, 2017 को एमवी पैनमैक्स-4 पर सवार एक बीमार चालक को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला।

(ग) **'बीडब्ल्यू पुमा' से चिकित्सा निकासी:** आईसीजीएस समुद्र पहरेदार ने 22 मई, 2017 को, एक सिंगापुर फ्लैग पोत एमटी बीडब्ल्यू प्यूमा से एक घायल रूसी इंजीनियर को बाहर निकाला।



चिकित्सा निकासी – 'एमटी बीडब्ल्यू पुमा'

(घ) **गोवा के बाहर 'एमवी लकी सेवन' से चिकित्सा निकासी:** सीजी हेलोएक्स-सीजीई (गोवा) ने 16 जुलाई, 2017 को एमवी लकी सेवन जहाज से चालक दल के 4 सदस्यों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला, जिन्हें मानसून के खराब मौसम के बीच समुद्र में बीमारी और चोट का सामना करना पड़ा था। बचाए गए दल को मीरामार बीच पर बंदरगाहों के उप-कप्तान (गोवा) को सौंप दिया गया।

(ङ) **गोवा में द्वीप के प्रकाश स्तंभ से चिकित्सा निकासी:** 4 जून 2017 को, भारतीय तट रक्षक चेतक विमान सीजी 811 ने लाइट हाउस विभाग के एक कर्मचारी को द्वीप के लाइट हाउस से निकाल कर वेंगुरुला पहुंचाया।



रक्षा उत्पादन





रक्षा उत्पादन

7.1 रक्षा उत्पादन विभाग (डी डी पी) की स्थापना नवंबर, 1962 में रक्षा के लिए आवश्यक हथियारों/प्रणालियों/प्लेटफार्मों/उपस्करों का उत्पादन करने के लिए व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से की गई थी। गत वर्षों में, इस विभाग ने आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के माध्यम से विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए व्यापक उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। इन यूनिटों द्वारा किए जा रहे विनिर्मित उत्पादों में हथियार एवं गोलाबारूद, टैंक, बख्तरबंद वाहन, भारी वाहन, लड़ाकू विमान एवं हेलिकॉप्टर, युद्ध पोत, पनडुब्बियां, प्रक्षेपास्त्र, गोलाबारूद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, विशेष मिश्र धातुएं और विशेष प्रयोजन वाले इस्पात शामिल हैं। विभाग द्वारा अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है।

7.2 रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख संगठन हैं:

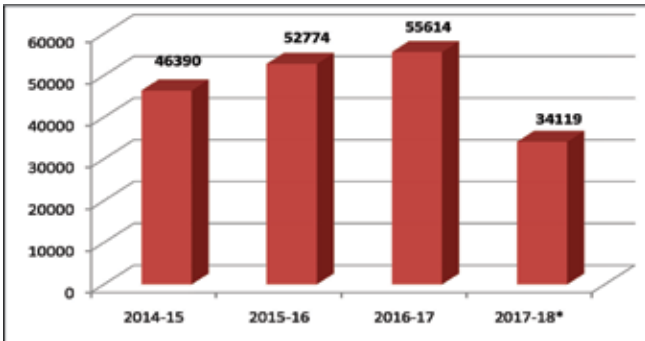
- आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ एफ बी)
- हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल)
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी ई एल)
- भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल)
- बी ई एम एल लिमिटेड (बी ई एम एल)
- मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)
- माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एम डी एल)
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस ई)
- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल)
- हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एच एस एल)
- गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी क्यू ए)
- वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी ए क्यू ए)

- मानकीकरण निदेशालय (डी ओ एस)
- योजना एवं समन्वय निदेशालय (डाइरेक्टोरेट आफ पी एण्ड सी)
- रक्षा प्रदर्शनी संगठन (डी ई ओ)

7.3 रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से, आयुध निर्माणियां और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम अपनी क्षमताओं को निरंतर आधुनिक और उन्नत बनाने के साथ-साथ अपनी उत्पादन रेंज में विस्तार कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी अंतरण के माध्यम से बहुत से उत्पादों एवं उपस्करों का उत्पादन करने के अलावा इन हाउस अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहलों के माध्यम से कई प्रमुख उत्पादों का विकास किया गया है।

7.4 कर पश्चात् लाभ सहित आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों का उत्पादन एवं कारोबार, क्रमशः सारणी सं० 7.1 व सारणी सं० 7.2 में दर्शाया गया है।

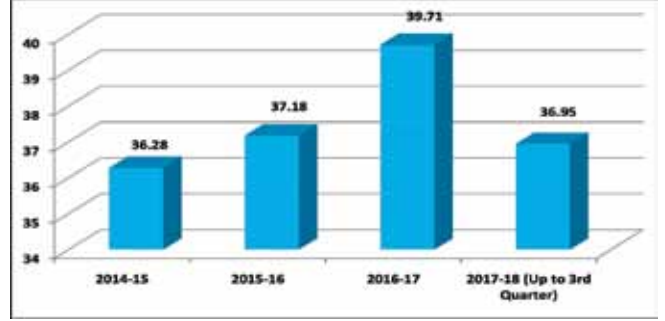
(करोड़ रुपए में)



चित्र: 7.1 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और ओएफबी के उत्पादन मूल्य में वृद्धि

* दिसंबर, 2017 तक (अनंतिम)

7.5 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणियों ने, विभाग द्वारा पालन किए जा रहे नीति के अनुरूप में, अपनी जरूरतों का बहुत सारा काम बाहर से करवाया है और पिछले वर्षों में एक व्यापक विक्रेता आधार विकसित किया है, जिसमें भारी उद्योगों के अलावा अनेक मध्यम और लघु उद्यम भी शामिल हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और आयुध निर्माणी बोर्ड अपने विनिर्मित उपस्करों एवं उत्पादों में स्वदेशी मात्रा बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन मूल्य को प्रतिशत के रूप में आउटसोर्सिंग मूल्य में वृद्धि के लिए भी प्रयासरत हैं। जैसाकि चित्र-7.2 में नीचे दिखाया गया है।



चित्र: 7.2 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और ओएफबी द्वारा आउटसोर्सिंग का मूल्य, उत्पादन मूल्य का % के रूप में

7.6 वर्ष 2017-18 के दौरान कुछ प्रमुख विकास/उपलब्धियों में शामिल है:-

- स्टेकहोल्डरों से परिचर्चा के पश्चात रक्षा उपस्करों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण के लिए सरकार और निजी भारतीय उद्योग के बीच सहयोग के सरलीकरण के लिए जनवरी, 2018 में एक नई और सरलीकृत 'मेक-II' प्रक्रिया की शुरुआत की गई है।
- विभाग में जनवरी, 2018 से एक रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ की शुरुआत की गई है। यह सभी प्रकार के रक्षा उत्पादन संबंधी प्रश्नों के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए विषय वार नोडल अधिकारी नामोदिष्ट किए गए हैं:-
- एक बहु-स्टेकहोल्डर टास्क फोर्स, जिसमें सरकार, सेना अकादमियां, औद्योगिक प्रोफेशनल और स्टार्ट अप के प्रतिनिधि शामिल हैं, का गठन जनवरी, 2018 में किया गया है, ताकि वैश्विक संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा अवधारणा में 'कृत्रिम ज्ञान' के व्याप्त सामरिक प्रभावों के समग्र मुद्दों का अध्ययन किया जा सके।
- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 14 दिसंबर, 2017 को प्रथम स्कोर्पियन श्रेणी की स्वदेश में निर्मित पनडुब्बी 'आईएनएस' कलवरी का जलावतरण किया गया।
- आरंभिक प्रचालन स्वीकृति के साथ अगस्त, 2017 में एचएएल के बेंगलुरु यूनिट में हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर का उत्पादन शुरू हो गया है।

- (vi) एचएएल विनिर्मित जेर्नियर डीओ-228 सिविल संस्करण विमान को डीजीसीए से 21 दिसंबर, 2017 को 'एयरवर्दीनेस प्रमाण पत्र' प्राप्त हुआ है, जिससे इसकी उड़ान योजना में उपयोग के लिए अवसर खुल गए हैं।
- (vii) ब्रिज लेयर टैंक-टी-72 की आपूर्ति अगस्त, 2017 में आरंभ हो चुकी है।
- (viii) ऑल टेरेन व्हीकल (एटीवी) की सुपुर्दगी डीजी बीएसएफ को अगस्त, 2017 में की गई थी।
- (ix) पांच सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम नामतः एचएएल, बीडीएल, मिधानि, एमडीएल और जीआरएसई का निवेश को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि मार्च, 2018 तक सूचीकरण को फलीभूत किया जा सके
- (x) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा 24 अप्रैल, 2017 को विशेष रसायनों, अवयवों, सामग्री, उपस्कर और प्रौद्योगिकियों (एलसीओएमईटी) को 6 श्रेणियों के अंतर्गत युद्ध सामग्री सूची की अधिसूचना के साथ विभाग ने युद्ध सामग्री सूची मदों के निर्यात के लिए आवेदनों को प्रोसेस करने हेतु एक संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित की है।
- (xi) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा संयुक्त रूप से स्वदेश में विकसित त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह-से-हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र (क्यूआर-सैम) का टेस्ट फायर 4 जून, 2017 को ओडिशा में बालेश्वर से किया गया था।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

7.7 जहां भी प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, वहां रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और स्वदेशीकरण करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

7.8 मई, 2001 में, रक्षा उद्योग क्षेत्र को, जो कि अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था, लाइसेंस के अधीन 26 प्रतिशत तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित शत-प्रतिशत तक की भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया था। हाल ही में, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य

एवं उद्योग मंत्रालय ने प्रेस नोट सं. 5 (2016 श्रृंखला) (प्रेस नोट द्वारा अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत www.dipp.nic.in पर उपलब्ध) के माध्यम से एफडीआई सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक एवं जहां कहीं भी देश में आधुनिक और नवोन्नत प्रौद्योगिकी अथवा रिकार्ड किए जाने वाले अन्य कारणों से प्राप्त होने की संभावना हो 49 प्रतिशत से अधिक कर दी है। इसके अलावा, रक्षा उद्योग औद्योगिक (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1951 और शस्त्र अधिनियम 1959 एवं शस्त्र नियमावली, 2016 के तहत लघु शस्त्र एवं गोलाबारूद का विनिर्माण औद्योगिक लाइसेंस के शर्ताधीन हैं। अन्य शर्तों को डीआईपीपी वेबसाइट (www.ddip.nic.in) पर एफडीआई के अंतर्गत देखा जा सकता है, जो समेकित एफडीआई नीति परिपत्र 2017 द्वारा अनुप्रमाणित है।

7.9 गृह मंत्रालय ने दिनांक 19 मई, 2017 की अपनी अधिसूचना द्वारा अनुसूची के खण्ड-2 और (3) के अंतर्गत यथाउल्लिखित शस्त्रों की श्रेणी एवं गोलाबारूद और रक्षा मदें, जो नई शस्त्र नियमावली 2016 में यथाउल्लिखित शर्तों के अधीन हैं, के संबंध में सचिव भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को शक्तियां एवं कार्य प्रत्यायोजित कर दिए हैं।

7.10 लाइसेंस शुदा रक्षा मदों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी) और गृह मंत्रालय (एमएचए) से प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करने तथा संबंधित विभागों के प्रस्तावों पर रक्षा मंत्रालय की सिफारिशें देने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय, थल सेना मुख्यालय, डी जी क्यू ए, डी जी ए क्यू ए, रक्षा विभाग महानिदेशक (अर्जन), ओ एफ बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और बी ई एल जैसे विविध क्षेत्रों से सदस्यों सहित संयुक्त सचिव (डी आई पी) इस स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं।

7.11 इसके अलावा, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की समाप्ति के पश्चात, विद्यमान एफडीआई नीति के अंतर्गत विदेशी निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन देने का कार्य संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को सौंप दिया गया है। डीआईपीपी को विदेशी निवेश फॅसिलिएशन पोर्टल पर भरे गए आवेदनों की जांच करने और इसे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को भेजने की जिम्मेवारी दी गई है। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई संबंधी प्रस्ताव की जांच रक्षा उत्पादन विभाग में की जाती है।

7.12 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी) ने 206 कंपनियों को कवर करते हुए निजी कंपनियों को कई प्रकार की रक्षा मदों के विनिर्माण के लिए नवंबर, 2017 तक 343 औद्योगिक लाइसेंस (आई एल) जारी किए हैं। 112 औद्योगिक लाइसेंस कवर करने वाली 69 लाइसेंस प्राप्त कंपनियों ने उत्पादन आरंभ करने की सूचना दी है।

7.13 रक्षा उद्योग क्षेत्र को, भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोलने के पश्चात सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में विभिन्न रक्षा उपस्करों के विनिर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में अब तक 40 एफ डी आई प्रस्तावों/संयुक्त उद्यमों को अनुमोदन दिया जा चुका है। अप्रैल, 2000 से सितंबर, 2017 तक रक्षा औद्योगिक क्षेत्र को 25.51 करोड़ रुपए (5.12 मिलियन यू. एस. डालर) की राशि की एफडीआई प्राप्त हुई (स्रोत <http://www.dipp.nic.in> पर एफडीआई आंकड़े)।

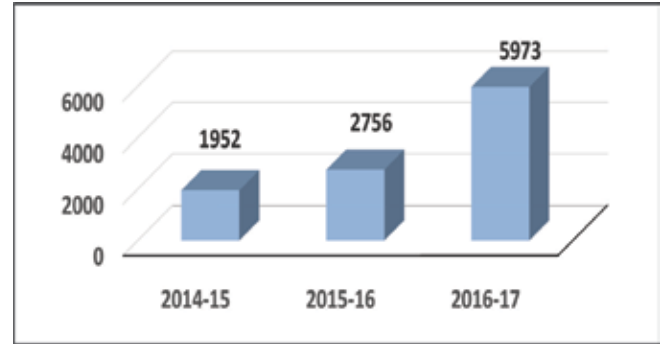
7.14 विभाग ने निजी क्षेत्र के रक्षा उद्योगों के लिए एक सुरक्षा नियमावली को अंतिम रूप दिया है। सुरक्षा नियमावली में कंपनियों के लिए फिजिकल दस्तावेजीकरण और आईटी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। यह सुरक्षा नियमावली प्रकाशन/रिपोर्ट के तहत डीडीपी की वेबसाइट (www.ddpmod.gov.in) पर उपलब्ध है। इस सुरक्षा नियमावली को अनुपालन के उद्देश्य से तीन भागों श्रेणी 'क', 'ख', 'ग' वर्ग में बांटा गया है। उत्पादों/हथियारों/उपस्करों पर निर्भर करते हुए, कंपनियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन करने की जरूरत होगी। यह रक्षा उत्पादन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इन श्रेणियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

श्रेणी 'क' : इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उत्पाद सुरक्षा की दृष्टिकोण से उच्च रूप से वर्गीकृत और संवेदनशील होंगे और इन मदों के निर्माण में उच्च स्तर की सुरक्षा की जरूरत होगी।

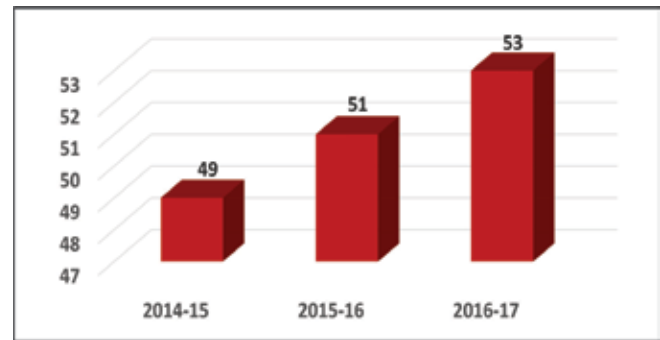
श्रेणी 'ख' : इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में अपरिष्कृत उत्पादों, सब-असेंबलियों, मुख्य हथियारों उपस्कर/प्लेटफार्म की उप-प्रणालियों और कम संवेदनशील प्रकृति के कुछ तैयार उत्पाद शामिल हैं।

श्रेणी 'ग' : इस श्रेणी के तहत आने वाले उत्पादों में वे उत्पाद शामिल होंगे, जो कोई वर्गीकृत/गुप्त सूचना से संबंधित नहीं हैं और वे सामान्य प्रकृति के हैं। इस श्रेणी के उत्पादों का सामान्यतः सेना के प्रयोगार्थ विनिर्दिष्ट रूप से अभिकल्पित या आशोधित नहीं

किया गया है। अतः इन्हें न्यूनतम स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता होगी।



चित्र 7.3 उत्पादन (करोड़ रुपये में)



चित्र 7.4 कंपनियों की संख्या जिन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया है (संचयी)

भारतीय रक्षा उद्योग की निर्यात प्रोफाइल रक्षा निर्यात

7.15 नवंबर, 2014 में अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए आवेदन स्वीकार करने हेतु ऑनलाइन प्रणालियों की शुरुआत के पश्चात, प्रणाली को आगे और सुप्रवाही बनाया गया है ताकि यह उद्योग अनुकूल हो सके। अब अनुज्ञप्तियां ऑनलाइन जारी की जा रही हैं ताकि समय की बचत की जा सके और प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। इस प्रणाली को नियमित रूप से बेहतर बनाया जा रहा है, जो औद्योगिक संघों/निजी निर्यातकों से समय-समय पर प्राप्त फीडबैक पर आधारित है।

7.16 विशेष रसायन अवयवों, सामग्री, उपस्कर और प्रौद्योगिकी (एससीओएमईटी) श्रेणी 6 शीर्षक 'युद्ध सामग्री सूची, जो अब तक आरक्षित थी, को लोकप्रिय बनाया गया है और 13 मार्च, 2015 को अधिसूचना सं. 115(आरई-2013/2009-2014) के द्वारा अधिसूचित सैन्य मदों की सूची विखंडित कर दी गई।

7.17 युद्ध सामग्री सूची के लिए निर्यात प्राधिकार जारी करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को संशोधित किया गया है और इसे वेबसाइट पर गया है। संशोधित एसओपी के अंतर्गत हिस्सों, घटकों, उप-असेम्बलियों इत्यादि के निर्यात हेतु अंतिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र पर सरकारी प्राधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने/मुहर लगाए जाने की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है।

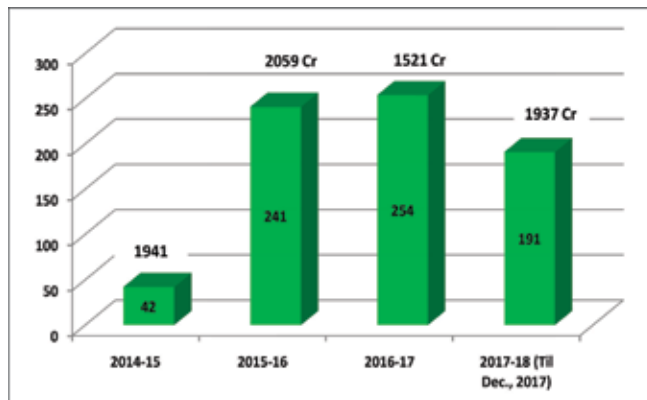
7.18 भारत को 2017 में वासेनार अरेंजमेंट की सदस्यता प्राप्त हुई है।

7.19 सैन्य विमानों और उड़्डयानिकी को युद्ध सामग्री सूची की श्रेणी 6ए010 में शामिल किया गया है और अधिसूचना सं. 05/201-2020 दिनांक 24 अप्रैल, 2017 के द्वारा डीडीपी को इसके लिए निर्यात लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

7.20 उन उत्पादों, जहां क्षमता की सीमितताएं हैं, (सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों) में उनके वार्षिक उत्पादन का 10 प्रतिशत तक निर्यात करने की अनुमति दी गई है ताकि देश के बाहर के बाजार अवसरों को भी तलाशा जा सके।

प्रभाव

7.21 ओएफबी व डीपीएसयू और निजी क्षेत्र (रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति पर आधारित) से निर्यात वित्त वर्ष 2016-17 के 1521.26 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2017-18 (दिसंबर, 2017 तक) में 1937.75 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा, दिसंबर, 2017 तक जारी अनुज्ञप्तियों की संख्या 191 है।



चित्र संख्या 7.5: निर्यात (करोड़ रुपए में तथा निर्गत की गई एनओसी)

आयुध निर्माणी संगठन

7.22 भारतीय आयुध निर्माणियां सबसे पुराना और सबसे बड़ा औद्योगिक स्थापना है जो उत्कृष्ट युद्धभूमि उपकरणों से सैन्य बलों को सुसज्जित करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रारंभिक उद्देश्य के साथ आयुध निर्माणी बोर्ड के अंतर्गत कार्य करता है।

7.23 आयुध निर्माणियों की प्रमुख सक्षमता:

हथियार	छोटे मध्यम और बड़े कैलीबर हथियार एवं मोर्टार उपकरण
गोलाबारूद, विस्फोटक एवं प्रोप्लेंट	छोटे, मध्यम एवं बड़े कैलीबर गोलाबारूद, मोर्टार बम, संकेतक एवं संबद्ध मर्दे, रॉकेट एवं एरियल बम, फ्यूज, विस्फोटक, रसायन व प्रोप्लेंटस
सैन्य वाहन	ट्रक, सुरंगरोधी एवं विशेष सुरक्षा वाले वाहन
कवचित वाहन	टैंक व इसके संस्करण, कवचित सैनिक वाहक (एपीसी) एवं इंजन
औजार एवं ऑप्टिकल डिवाइस	नाइट एण्ड डे विजन साइट्स और औजार
पैराशूट	ब्रेक पैराशूट, मैन ड्रापिंग एवं रसद गिराने वाला पैराशूट
टूल्स कंफर्ट एवं सामान्य वस्तुएं	तम्बू, परिधान, वैयक्तिक उपकरण, ब्रिजेज, नौकाएं, केबल्स इत्यादि

7.24 **उत्पादन उपलब्धियां:** वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कारोबार 21,392 करोड़ रुपए का था। वर्ष 2017-18 के लिए अनुमानित कारोबार 23,500 करोड़ रुपए है, जिसके प्रति 31 दिसंबर, 2017 तक 12,543 करोड़ रुपए की उपलब्धियां हैं। वर्ष 2016-17 में ओएफबी द्वारा तकरीबन 80 प्रतिशत आपूर्तियां भारतीय सेना के लिए की गई हैं।

7.25 **आधुनिकीकरण:** ओएफबी ग्राहकों की वर्तमान और दीर्घकालिक भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता उत्पादों के विनिर्माण के लिए पुरानी मशीनों के स्थान पर नवोन्नत मशीनें लगाकर निरंतर रूप से आधुनिकीकरण कर रहा है। इसे प्राप्त करने के लिए एक व्यापक आधुनिकीकरण योजना तैयार

की गई है और अगले पांच वर्षों के लिए 11820 करोड़ रुपए की आधुनिकीकरण योजना है। आधुनिकीकरण पर 12वीं योजना के दौरान 5359 करोड़ रुपए का कुल व्यय किया गया था।

7.26 गुणता प्रबंधन:— गुणता प्रबंधन की प्रक्रिया को इनपुट सामग्री निरीक्षण के लिए जांच सुविधाओं को सृजित करना और प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन करना, लेखा परीक्षा विनिर्माण प्रक्रिया के लिए गुणता लेखा परीक्षा समूहों की स्थापना करना, एनक्यूडीबीएमएस (नेटवर्क गुणता डाटा आधारित प्रबंधन प्रणाली) की शुरुआत करना, डीजीक्यूए और ओएफबी के प्रतिनिधियों के साथ विफलता समीक्षा बोर्ड (एफआरबी) का गठन करना है, विनिर्माण और अंतिम स्वीकार्यता निरीक्षण के दौरान त्रुटि के कारणों का विश्लेषण करना और उपचारात्मक कार्रवाई का परामर्श देना है।

7.27 इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास: ओएफबी ने इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के द्वारा निम्नलिखित प्रणालियों को विकसित किया है:

- बख्तरबंद रिकवरी वाहन
- गृह मंत्रालय के लिए एमपीवी का आधुनिकीकरण/ उन्नत संस्करण
- आरजीबी-60 और आरजीबी-12 पनडुब्बी का गोलाबारूद
- इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल (धनुष) के साथ 155 एमएमx45 कैलीबर एफएच गन का विकास
- 155 एमएम गन प्रणाली का 155 एमएम-बीएमसीएस के लिए स्वदेशी प्रोपेलेंट का विकास
- 155 एमएम गोलाबारूद के लिए इलेक्ट्रॉनिक पीडी फ्यूज
- टी-72 टैंक के लिए कमांडर थर्मल इमेजिंग साइट

7.28 उपलब्धियां और पुरस्कार:

- ओएफबी ने सहयोग करने और भारतीय रक्षा एवं निर्यात बाजार की जरूरतों का संयुक्त रूप से समाधान करने के लिए एक फ्रेमवर्क की स्थापना के लिए बीईएमएल और मिधानि के साथ अम्ब्रेला समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। इस एमओयू में इस समय चल रही परियोजनाएं और

नई परियोजनाएं शामिल होंगी।

- रक्षा मंत्री ने 30 मई, 2017 को रक्षा राज्य मंत्री, सचिव (डीपी), अपर सचिव (डीपी) और तीनों सेनाओं के उप-प्रमुखों की उपस्थिति में विडियो लिंक के माध्यम से 16 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र ओएफ, मेडक की 80 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है जो ओएफ मेडक को इसकी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनाएगा। सौर ऊर्जा संयंत्र, कार्बन फुटप्रिंट की कमी की दिशा में ओएफबी के योगदान को चिन्हित करेगा।
- आयुध निर्माणी, मेडक ने इन-हाउस आरएण्डडी के जरिए बीएमपी-11 शस्त्रास्त्र उन्नयन का कार्य शुरू किया है। दो वाहनों (बीएमपी-11 गनर रुपांतरण और बीएमपी-11 के कमांडर रुपांतरण) का कार्य पूरा कर लिया गया है। दोनों वाहनों का एक व्यापक आंतरिक परीक्षण (फायरिंग और रनिंग) का कार्य जून, 2017 माह के दौरान सफलतापूर्वक पूरा कर दिया गया है।
- आयुध निर्माणी मेडक को वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए रक्षा मंत्री का सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन निर्माणी को विजेता के रूप में चुना गया है।
- आयुध निर्माणी, वरणगांव ने औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन में अपनी उत्कृष्टता के लिए 11वां महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2015-16 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। आयुध निर्माणी, वरणगांव ने लगातार दूसरे वर्ष भी ऊर्जा उत्कृष्टता में अपनी प्रथम स्थिति को बनाए रखा है, वरणगांव ने ऊर्जा कार्य निष्पादन में प्रणालीगत अप्रोच, प्रभावी ऊर्जा अनुवीक्षण और इलेक्ट्रिक, थर्मल, हिटिंग वैंटीलेशन और कंडीशनिंग प्रणाली (एचवीएसी) एवं कंप्रेसड एयर जेनरेशन और डिमांड साइड मैनेजमेंट पर ऊर्जा कुशलता में फोकस करने के लिए सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एण्ड मैनेजर (एसईईएम) केरल द्वारा संस्थापित औद्योगिक क्षेत्र (आयुध) में एसईईएम राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन पुरस्कार 2016 (गोल्ड) भी जीता है।
- आयुध निर्माणी, अंबरनाथ ने अंतरराष्ट्रीय रिसाइक्लिंग ब्यूरो (बीआईआर), वुसेल्स, बेल्जियम के महानिदेशक

के करकमलों से मुंबई में सितंबर, 2017 में विश्व नॉन फेरस पुरस्कार, 2017 में सर्वश्रेष्ठ रिसाइकलर(ज्यूरी) का पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार एमटीएलईएक्स एस द्वारा संस्थापित/आयोजित है।

7.29 डिजिटल इंडिया पहल:

- ई-ग्रिवान्सेस- ओएफबी में जुलाई, 2013 से ऑनलाइन क्लेंट ट्रेकिंग सिस्टम/सीपीजीआरएएमएस की शुरुआत की गई है। प्राप्त 2251 शिकायतों में से, 2170 मामलों (96%) का निपटान 31 दिसंबर, 2017 तक कर दिया गया था। शिकायतों के निपटान की मॉनीटरिंग ओएफबी द्वारा उचित स्तर पर की जाती है।
- ई-अधिप्राप्ति-दो लाख से अधिक मूल्य की सभी अधिप्राप्ति, ई-अधिप्राप्ति के जरिए की जाती हैं।
- ई-नीलामी- स्कैप और डिस्पोज की जाने वाली मर्दों से संबंधित सभी नीलामी के मामलों एमएसटीसी ई-नीलामी के द्वारा किए जाते हैं।
- ई-भुगतान-अधिकतम मामलों में, कर्मचारियों के साथ-साथ विक्रेताओं को, उनके बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के द्वारा सीधे भुगतान किए जाते हैं।
- ई-सेवाएं- प्रयोक्ता द्वारा फीड बैक प्रदान करने को सुकर बनाने के लिए वेबसाइट ofb.gov.in पर लिंक उपलब्ध कराया गया है।

7.30 मेक इन इंडिया:

- ओएफबी की स्वदेशी रूप से मर्दों का विकास करने की काफी सुदृढ़ और गहरी परंपरा रही है। केंद्रीय सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल ने ओएफबी के स्वदेशीकरण के प्रयासों को निश्चित रूप से आगे और बढ़ाया है। इस पहल से ओएफबी को शस्त्रों एवं गोलाबारूद के विनिर्माता के रूप में अपनी प्रमुख शक्ति को और सुदृढ़ करने के साथ-साथ भारतीय उद्योगों की विकसित हो रही क्षमता के बढ़ते योगदान के साथ हमारे सैन्य बलों के लिए एकल सबसे बड़ा आत्म-निर्भर बनकर योग्य स्वदेशी आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरकर सामने आएगा,

जिससे अंततः आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और रक्षा उपकरणों के आयात में कमी आएगी।

- आयुध निर्माणी ने स्वदेशी रूप से निर्मित, अभिकल्पित और विकसित उत्पादों को सफलतापूर्वक अपने शस्त्रागार में जोड़ा है जिनमें मल्टी बैरल राकेट लांचर पिनाका, टैक्टिकल गेम चेंजर 155x45 एमएम धनुष आर्टीलरी गन, रोबस्ट और सुरक्षित सुरंग रक्षित वाहन (एमपीवी), और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा, ओएफबी ने टी-72 और टी-90 टैंकों, आईसीवी बीएमपी-॥ भारतीय नौसेना के लिए एके-630 गन, 84एमएम राकेट लांचर और 40 एमएम प्री-फ्रैगमेंटेड एंटी एयरक्राफ्ट गोलाबारूद का पर्याप्त मात्रा में स्वदेशीकरण किया है। ओएफबी ने वायुसेना के लिए विभिन्न रिड्यूस्ड डेंजर जोन (आरडीजैड) और भारतीय नौसेना के लिए आरजीबी-12 एवं आरजीबी-60 राकेटों का भी विकास किया है।
- ओएफबी की मौजूदा उत्पादन रेंज में बड़ी मात्रा में पारंपरिक शस्त्र और गोलाबारूद शामिल हैं। तथापि, ओएफबी सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपकरणों एवं आईआईटी चेन्नई के सहयोग से भावी इंफैंट्री कॉम्बेट व्हीकल (एफआईसीवी) के की रूपरेखा पर कार्य कर रहा है। इसके अलावा, इन हाउस आरएण्डडी प्रयासों के साथ, ओएफबी डीआरडीओ के साथ समन्वय और आईआईटी मुंबई की इनपुट से आर्टीलरी गोलाबारूद के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज का विकास कर रहा है। ओएफबी, एआरडीई एवं आईआईटी कानपुर के साथ गठजोड़ करके प्रिंसीपल गाइडेड आर्टीलरी शेल के विकास में शामिल हैं।

7.31 **स्वच्छ भारत:** सभी आयुध निर्माणियों में 01 दिसंबर से 15 दिसंबर, 2017 तक स्वच्छ भारत पखवाड़ा मनाया गया, जिसके दौरान साफ-सफाई में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, पौधारोपण, निर्माणियों/संपदा के भीतर स्वच्छता अभियान चलाए गए।

7.32 **राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान:** राष्ट्रीय कौशल विकास की शुरुआत कौशल कार्यकलापों के क्षेत्र में एकरूपता लाने के लिए की गई थी। आयुध निर्माणियां राष्ट्र के कौशल विकास अभियान में सार्थक और सक्रिय योगदान कर रही हैं। ओएफबी ने 2017 में संविदाकर्मी सहित ट्रेड अप्रेंटिसों की कुल

नफरी को 2.5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाया है, जिसके बाद विभिन्न ट्रेडों में लगभग 7038 ट्रेड अप्रेंटिस को, इन क्षेत्रों में रोजगार एवं कौशल को बढ़ाते हुए, भर्ती किया है।

7.33 वर्षा जल संग्रहण: कुल 1495 मौजूद/पुराने भवनों में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की गई है, जिनमें से 525 भवनों में वर्ष 2017-18 के दौरान वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की गई थी। 2017-18 से पहले, विभिन्न आयुध निर्माणियों में 970 भवनों में पहले से ही वर्षा जल संग्रहण लगाया जा चुका था। पूरी की गई परियोजनाओं में 1428 रूँप टॉप वाटर वाले भवनों को ड्रेन नेटवर्क के जरिए पांड से जोड़ा गया और 67 भवनों को व्यक्तिगत भवनों के रिचार्ज पिट्स से जोड़कर पूरा किया गया है। इसके अलावा, 2360 मौजूद/पुराने भवनों को 2018-19 के दौरान पूरा कर लिए जाने की योजना है।

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

7.34 हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) भारत की अग्रणी एयरोस्पेस कंपनी, का विश्व के 100 शीर्ष एयरोस्पेस उद्योगों में से 35वां स्थान है। एचएएल ने अब तक 17 प्रकार के विमान/हेलीकॉप्टरों का स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकास किया है, जिनमें एचटीटी-40 (बेसिक प्रशिक्षक विमान) और हल्का उपयोग वाले विमान (एलयूएच) सबसे नवीनतम हैं। चालू विनिर्माण कार्यक्रम में हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए)-तेजस, बहुभूमिका वाले सुपरसोनिक युद्ध लड़ाकू विमान एसयू-30 एमकेआई, हल्का परिवहन विमान डीओ-228, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर (ध्रुव) रूस एलसीएच, चेतक, चीतल हेलीकॉप्टर शामिल हैं। कंपनी का भारतीय रक्षा सेनाओं के लिए फ्लीट सहायता में 80 प्रतिशत तक दखल है। कंपनी ने दिसंबर, 2017 तक 8865 करोड़ रुपए (अंतिम) का कारोबार किया है। दिसंबर, 2017 के अंत तक 233 करोड़ रुपए का निर्यात किया है।

7.35 वर्ष 2017-18 के दौरान मुख्य घटनाएं/ उपलब्धियां

(i) एचएएल ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) का सफलतापूर्वक विकास करने के लिए केंद्र से मिलीट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन (सीईएमआईएलएसी)

के लिए प्रारंभिक प्रचालनात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (आईओसी) प्राप्त किया है।

- (ii) एचएएल ने सुखोई-30 एमकेआई विमान पर अस्त्र, बियांड विज्युअल रेंज मिसाइल, लगाया है जिसका भारतीय वायुसेना द्वारा वास्तविक लक्ष्य पर पूर्ण प्रचालनात्मक विन्यास में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
- (iii) एचएएल के सुखोई इंजन प्रभाग, कोरापुट द्वारा कच्ची सामग्रियों से निर्मित 50वें एएल-31एफपी इंजन को भारत-रूस राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के आयोजन के अवसर पर भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था।
- (iv) नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) ने डीओ-228 को नागर प्रमाण-पत्र से नवाजा है। इस मेक-इन-इंडिया विमान को अब एयर लाइनों द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के लिए भारत के अंदर प्रयोग में लाया जा सकता है।
- (v) स्वदेशी रूप से उन्नत हॉक एमके 132 विमान, "हॉक-आई" को रक्षा मंत्री द्वारा देश को समर्पित किया गया है।
- (vi) 8 कि.ग्रा भार के लघु मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) की सफलतापूर्वक विकसित पहली इकाई को रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की उपस्थिति में सीआरपीएफ को 7 सितंबर, 2017 को सौंपा गया है।



लघु यूएवी की पहली इकाई को रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की उपस्थिति में सीआरपीएफ को 7 सितंबर, 2017 को सौंपा गया है।

(vii) एईएसए (एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अर्रे) युक्त जगुआर डारिन III विमान ने प्रथम उड़ान 10 अगस्त, 2017 को भरी थी।

(viii) हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) के प्रोटोटाइप उड़ान परीक्षण ने 6 जून, 2017 को अपनी 1000वीं उड़ान पूरी करके प्रमुख सफलता हासिल की और एलसीएच की इस उड़ान को स्वदेशी आईएडीएस से पूरा किया गया था।

(ix) एचएएल में भारत सरकार के 10 प्रतिशत शेयर के विनिवेश के लिए मार्केट रेग्युलेटर सेबी के साथ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) को 29 सितंबर, 2017 को पूरा किया गया है।

7.36 वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त पुरस्कार:

(i) कारपोरेट प्रबंधन के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा 'स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार 2014-15' से नवाजा गया है।

(ii) एचएएल को निम्नलिखित श्रेणियों में 30 मई, 2017 को रक्षा मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया :-

- "निष्पादन में उत्कृष्टता" के लिए संस्थागत पुरस्कार।
- एचएएल, हैदराबाद प्रभाग को "डीपीएसयू का सर्वोत्तम निष्पादन प्रभाग" पुरस्कार।

(iii) "सर्वोत्तम पीएसयू-सार्वजनिक क्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम" श्रेणी में कौशल विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए 'गोल्ड ट्रॉफी' से सम्मानित किया गया है।

(iv) "कंबाइंड इंटीरोगेटर एंड ट्रांसपोंडर (सीआईटी)" परियोजना के लिए गोल्डन पीकॉक नवाचार उत्पाद/सेवा पुरस्कार-2017 से सम्मानित किया गया है।

(v) 'कुमुदवती नदी संरक्षण परियोजना' के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए "बीटी-सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार 2017" से सम्मानित किया गया है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)

7.37 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), 1954 में रक्षा मंत्रालय के अधीन स्थापित, एक नवरत्न कंपनी है, जिसकी रडारों एवं हथियार प्रणालियों, सोनारों, संचार, नेटवर्क केंद्रित प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक वायफेयर, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स एवं टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बुनियादी क्षमताओं के साथ पूरे भारत में नौ इकाइयां हैं। गैर-रक्षा क्षेत्र में, बीईएल की उत्पाद श्रेणी में ईवीएम, टैबलेट पीसी, माइक्रोसर्किट, सेमी कंडक्टर, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स, घरेलू सुरक्षा प्रणालियां, सोलर प्रणालियां इत्यादि शामिल हैं।

7.38 **अनुसंधान एवं विकास:** बीईएल ने आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी नौ इकाइयों में अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) सुविधाएं स्थापित की हैं। कंपनी ने भावी कार्यक्रमों एवं विभिन्न प्रौद्योगिकियों, ज्ञान प्रबंधन पोर्टल इत्यादि की पहचान करते हुए एक तीन वर्षीय आर एण्ड डी योजना तैयार की है। प्रति वर्ष औसतन 10 नए उत्पाद शुरू किए जाते हैं। बीईएल अपने कारोबार का लगभग 9 प्रतिशत भाग आर एण्ड डी पर खर्च करता है।

7.39 वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:

(i) स्वदेशी रूप से विकसित क्यूआर-सैम का सफल फायरिंग परीक्षण।



क्यूआर-सैम का फायरिंग परीक्षण

(ii) 100वीं उन्नत एल-70 गन की फ्लैगिंग।

(iii) 16 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का आयुध निर्माणी, मेदक में और नवोन्नत इलेक्ट्रॉनिक आर्टिलरी फ्यूज

विनिर्माण काम्पलैक्स का पुणे में उद्घाटन। नौसेना के लिए ऑन-लाइन मॉल सूची प्रबंधन प्रणाली, भारतीय वायुसेना एवं सेना के लिए जम्मू में सेवा सहायता केंद्र और बीईएल उत्कृष्टता अकादमी।



नवोन्नत इलेक्ट्रॉनिक आर्टिलरी फ्यूज विनिर्माण काम्पलैक्स का पुणे में उद्घाटन

(iv) जीते गए पुरस्कारों में स्वदेशीकरण, डिजाइन प्रयास, निर्यात के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (नौसैन्य प्रणाली एसबीयू) का सर्वोत्तम निष्पादन प्रभाग, डन एवं ब्रेडस्ट्रीट भारत का शीर्ष पीएसयू पुरस्कार, संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए ऐसोचेम पुरस्कार, एफएलएम कार्यान्वयन हेतु “भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सर्वोत्तम संस्थागत कार्य” के लिए सीवीसी सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार इत्यादि शामिल हैं।

7.40 **भावी चुनौतियां:** रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार को निजी भागीदारी के लिए खोले जाने से प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ गई है। विकास जारी रखने के लिए, बीईएल ने संगठनात्मक संरचना में बदलाव करने, नए उत्पाद विकास पर और अधिक बल देने, विविधीकरण, प्रक्रियाओं/अवसंरचना में सुधार करने इत्यादि जैसी कई रणनीतियां अपनाई हैं।

7.41 **स्वदेशीकरण:** बीईएल ने अपने कारोबार का लगभग 87 प्रतिशत भाग स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी से अर्जित किया है। हाल के वर्षों में विकसित कुछ प्रमुख उत्पादों में आकाश हथियार प्रणाली, लेजर रेंज फाइंडर युक्त हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, 3डी टैक्टीकल कंट्रोल रडार, वैपन लोकेटिंग रडार, एकीकृत हवाई कमान और नियंत्रण प्रणाली, एल-70 गन अपग्रेड, लो लेवल लाइट वेट रडार, पोत आधारित एकीकृत ईडब्ल्यू प्रणाली

और नई पीढ़ी के सोनार शामिल हैं।

7.42 **आधुनिकीकरण:** बीईएल प्रौद्योगिकी/उत्पादों की बदलती आवश्यकताओं के साथ तालमेल रखने के लिए अपनी अवसंरचना का निरंतर आधुनिकीकरण करता रहा है। हाल के वर्षों में स्थापित प्रमुख सुविधाओं में नया रडार असेम्बली हैंगर, “ब्लोइंग सैंड एवं डस्ट टेस्ट सुविधा”, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कम्पैटीबिलिटी चैम्बर, पल्स करंट इंजेक्शन टेस्ट सुविधा, नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा असेम्बली लाइन और स्वचालित टीआर मॉड्यूल असेम्बली लाइन इत्यादि शामिल हैं।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल)

7.43 भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) को रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1970 में निगमित किया गया था। यह कंपनी देश में टैंकरोधी निर्देशित मिसाइलों (एटीजीएम) के विनिर्माण में अग्रणी है। बीडीएल नई पीढ़ी की एटीजीएम, सतह से हवा में मार करने वाली हथियार प्रणालियों (सैम), सामरिक महत्व के हथियारों, लांचरों, अंतर्जलीय हथियारों, डिफेंस और परीक्षण उपकरणों के विनिर्माण में शामिल है। बीडीएल अपने सभी प्रमुख उत्पादों के क्षमता संवर्धन के द्वारा सशस्त्र सेनाओं की मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में, बीडीएल के कारपोरेट कार्यालय को तेलंगाना राज्य वित्त निगम (टीएसएफसी), नानकरामगुडा, गाचीबॉवली में स्थानांतरित किया गया है।

7.44 मिलान, कॉनकर्स-एम, इनवार और आकाश प्रभाग को एरोस्पेस मानक एएस 9100 सी के तहत पहले ही प्रत्यायित किया जा चुका है और इस समय सशक्त एएस 9100 डी का मार्च, 2018 तक उन्नयन करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

7.45 बीडीएल आकाश (सेना) आकाश हथियार प्रणाली, स्वदेशी रूप से उत्पादित प्रमुख उत्पादों में से एक और भारतीय सेना/भारतीय वायु सेना को आपूरित, का अग्रणी इंटीग्रेटर है। बीडीएल भारतीय सेना के लिए मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआर सैम) का भी एक अग्रणी इंटीग्रेटर है। हाल ही में, भारतीय सेना के लिए इसका उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए डीआरडीओ, हैदराबाद और बीडीएल, हैदराबाद के बीच 1918 करोड़ रुपए मूल्य की एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं।



आकाश

7.46 **स्वदेशीकरण:** बीडीएल, आत्म-निर्भरता में वृद्धि करने, विदेशी मुद्रा प्रवाह में कमी लाने और लागत कम करने के उद्देश्य से एटीजीएम के स्वदेशीकरण के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। कोनकर्स-एम, इनवार और मिलान-2टी जैसे उत्पादों का क्रमशः 90%, 78.6% एवं 71% स्वदेशीकरण हासिल कर लिया गया है।

7.47 **कैपेक्स एवं आधुनिकीकरण:** वर्ष 2017-18 के लिए संयंत्र एवं मशीनरी के आधुनिकीकरण और अन्य अवसंरचनात्मक विकासों के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पर 140 करोड़ रुपए चिह्नित किए गए हैं।

7.48 **वित्तीय निष्पादन:** वर्ष 2016-17 में बीडीएल ने 4887 करोड़ रुपए का कीर्तिमान बिक्री कारोबार (निवल) अर्जित किया है। वर्ष 2017-18 में 5300 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री का लक्ष्य है।

7.49 **कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सतत विकास:** बीडीएल ने सीएसआर के अंतर्गत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के लोगों के बेहतर जीवन के लिए 21.52 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च से मिड-डे मील, वृद्ध लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, आरओ जल उपचार संयंत्र, इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट (महिला शौचालय) का निर्माण इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किए हैं।

बीईएमएल लिमिटेड

7.50 बीईएमएल, 1964 में स्थापित एक लघु रत्न (श्रेणी-1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, के विनिर्माण कॉम्प्लेक्स, कोलार गोल्ड फील्ड (केजीएफ), बेंगलुरु, मैसूर और पालाक्कड़ में तथा सहायक इस्पात फाउंड्री- विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तारीकरे, चिकमंगलूर जिले में हैं। यह कंपनी खनन व निर्माण, रक्षा एवं

रेल व मेट्रो उत्पादों के क्षेत्रों की वृहत रेंज की डिजाइन, विकास, विनिर्माण, बिक्री एवं बिक्री पश्चात् के क्रियाकलापों में लगी हुई है। कंपनी का अंतरराष्ट्रीय व्यापार एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 66 देशों में फैला हुआ है।



माइन प्लो युक्त एमबीटी टी 90

7.51 **अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) में सुधार करने के लिए सक्रिय कार्य:** अमोघ-1, इंफेंट्री के लिए लाइन ऑफ साइट (एसएसीएलओएस) टैंकरोधी निर्देशित मिसाइल (एटीजीएम) का एक अर्ध-स्वचालित कमांड है। परीक्षण फायरिंग करके मिसाइल डिजाइन को मान्यता प्रदान की गई है। आगे के परीक्षणों और अर्हता के लिए मिसाइलों का विनिर्माण किया जा रहा है। अमोघ-11 के विकास के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी गाइडेंस, मैकेनाइज्ड इंफेंट्री के लिए लाइन ऑफ साइट (एसएसीएलओएस) टैंकरोधी निर्देशित मिसाइल (एटीजीएम) के एक अर्ध-स्वचालित कमांड का कार्य प्रगति पर है। अमोघ-111 के प्रणाली विन्यास, एक तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फोरगेट, 11 आर सीकर आधारित एटीजीएम को अंतिम रूप दे दिया गया है। मिसाइल की उप प्रणालियों के डिजाइन का कार्य प्रगति पर है।



परीक्षण के अधीन अर्जुन एआरआरवी

7.52 **स्वदेशीकरण:** खनन एवं निर्माण उत्पादों और रेल उत्पादों में स्वदेशीकरण का स्तर 90 प्रतिशत, मेट्रो कारों में 60 प्रतिशत है। रक्षा उत्पादों अर्थात् पीएमएस ब्रिज, एटीटी, एयरक्राफ्ट वेपन लोडर, 50टी ट्रेलर में स्वदेशीकरण का स्तर 90 प्रतिशत है। हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए इंजन असेम्बली, उच्च तुंगता किट, स्टीयरिंग पंप एवं ब्रेक सिलेंडर का स्वदेशीकरण वर्ष 2017-18 में कर लिया गया है।

7.53 **प्राप्त पुरस्कार:**

- वर्ष 2014-15 के लिए स्वयं पहल श्रेणी में डिजाइन प्रयासों के अंतर्गत बीई 1800ई एक्सकावेटर के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार।
- 'तीव्र गति से विकास करने वाले संगठन-मिनी रत्न' श्रेणी के अंतर्गत हिंदुस्तान पीएसयू पुरस्कार।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)

7.54 मिधानि विशिष्ट धातु एवं धातु एलॉयज का विनिर्माण करने वाली "लघु रत्न श्रेणी-1" की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 20 नवंबर, 1973 को भारतीय रक्षा उद्योग के सामरिक क्षेत्रों और परमाणु ऊर्जा, उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों, विमान इत्यादि जैसे क्षेत्रों के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण सामग्रियों का विनिर्माण करने के लिए की गई थी। मिधानि ने वाणिज्यिक उत्पादन 1983 में आरंभ किया था और तब से यह ग्राहकों को विशिष्ट धातुओं एवं मिश्र धातुओं (एलॉयज) की आपूर्ति सफलतापूर्वक करता रहा है।

7.55 **वित्तीय निष्पादन:** वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, मिधानि ने 809.71 करोड़ रुपए का सर्वाधिक बिक्री कारोबार किया है और कंपनी ने गत दस वर्षों के दौरान लगभग 13.7 प्रतिशत की प्रभावशाली चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) अर्जित की है।

7.56 **समझौता ज्ञापन (एमओयू) की उपलब्धि:** वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए, मिधानि को समझौता ज्ञापन निष्पादन में "उत्कृष्ट" दर्जा दिया गया है। मिधानि ने इस वर्ष लगातार 5वीं बार "उत्कृष्ट" रेटिंग हासिल की है।

7.57 **ग्राहकों को समय पर सुपुर्दगियां:** समय पर सुपुर्दगियां सुनिश्चित करना प्रबंधन का प्रमुख क्षेत्र रहा है। सुपुर्दगियों में तेजी लाने और विलंबित सुपुर्दगियों के लिए संविदागत शास्तियों एवं हर्जाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए,

मिधानि ने अपनी पुरानी इन-हाउस उत्पादन सुविधाओं के स्थान पर विश्व में उपलब्ध समकालीन प्रौद्योगिकियों से विस्तार चरण संवर्धन, विस्तार कार्य और सुधार आरंभ किया है तथा मौजूदा उत्पादों के लिए नए अनुप्रयोगों का भी विकास कर रहा है।

7.58 **अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) में सुधार करने के लिए सक्रिय कार्रवाई:** मिधानि का अनुसंधान एवं विकास अपने ग्राहकों के लिए नए ग्रेडों एवं उत्पादों का विकास करने, प्रोसेस विकास और आशोधन एवं उत्पाद में सुधार करने में लगा हुआ है। प्रौद्योगिकी में तीव्रता लाने के लिए महत्वपूर्ण उद्योग शैक्षणिक सहयोग की पहचान करते हुए आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की और आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, इस साझेदारी में प्रशिक्षण एवं विकास संबंधी कार्यकलापों के आलावा, उत्पाद, प्रोसेस एवं नए एलॉयज डिजाइनों के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास पर ध्यान दिया जाएगा।

7.59 **आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कार्यक्रम:** गत तीन दशकों के दौरान कंपनी के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कार्यक्रम ने अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित करने और उत्पादन टनेज क्षमता और उत्पाद विविधता में वृद्धि करने में योगदान दिया है। पुनरुद्धार/उन्नयन/उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए मिधानि का प्रथम चरण का आधुनिकीकरण लगभग 400 करोड़ रुपए के पूंजी परिव्यय से सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इनमें 20 टन मैनीपुलेटर के साथ 6000 टन की नई फोर्ज प्रेस, रैडियल एक्सियल रिंग रोलिंग मिल, एक नए फास्टेनर संयंत्र, आर एंड डी भवन, वैक्यूम डिगैसिंग (वीडी)/ वैक्यूम ऑक्सीजन डिकार्बुराइजिंग (वीओडी) युक्त 20 टन इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी और लैडल रिफाइनिंग भट्टी (एलआरएफ) की स्थापना प्रमुख हैं। इस समय लगभग 1000 करोड़ रुपए पर द्वितीय चरण का आधुनिकीकरण कार्य चल रहा है।

7.60 **स्वदेशीकरण का स्तर:** मिधानि में विनिर्मित ज्यादातर विशेष धातुएं/एलॉयज आयात प्रतिस्थापन कार्यनीति का एक भाग हैं जिसका उद्देश्य विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भारत की निर्भरता को कम करना और आत्म-निर्भरता हासिल करना है। मिधानि ने पावर ट्रांसमिशन गियर और हेलीकॉप्टर परियोजनाओं के पिनिनियन के लिए नए एलॉयज एमडीएन 9201 तथा रेलवे डीजल लोकोमोटिव के टर्बो चार्जर के लिए एमडीएन 713सी कास्ट और हिप्पड ब्लेड का विकास किया है। मिधानि ने पीटी-1 एम, पीटी-7एम, बीटी-3

बी, बीटी-3बीएम, बीटीआई-डी जैसे विभिन्न प्रकार के रूसी मूल के टाइटेनियम एलॉयज का प्रमाणन और स्वदेशी विकास भी आरंभ किया है। हमारे देश में पहली बार मिधानि ने उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटीकल थर्मल पावर प्लांट अनुप्रयोग के लिए सुपर एलॉय 617सीसी के वृहत फोर्जिंग्स का विकास किया है।

7.61 **कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:** मिधानि की सीएसआर नीति का उद्देश्य कंपनी के संचालन क्षेत्र में और इसके आसपास रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए दीर्घ, मध्यम एवं अल्प अवधि की कंपनी की विशिष्ट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी रणनीतियों का विकास करना है। मिधानि द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों के लिए 3.24 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यकलापों और प्रगति के अधीन विभिन्न गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है:—

- (क) कौशल विकास
- (ख) शिक्षा का संवर्धन
- (ग) स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना
- (घ) स्कूलों और विभिन्न संस्थाओं को अवसंरचनात्मक सहायता मुहैया कराना
- (ङ.) अन्य कार्यकलाप

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)

7.62 माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम शिपयार्डों में एक अग्रणी शिपयार्ड है जो युद्धपोतों एवं पनडुब्बियों के निर्माण में लगा हुआ है। एमडीएल ने भारतीय नौसेना के लिए प्रतिस्पर्धी लागत पर युद्ध पोत के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्नत मिसाइल विध्वंसकों, स्टील्थ फ्रिगेट और पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता हासिल कर ली है और इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है तथा प्रमुख स्थिति प्राप्त कर ली है।

7.63 **वित्तीय निष्पादन:** कंपनी ने वर्ष 2016-17 में 3529.7 करोड़ रुपए का उत्पादन मूल्य और 525.12 करोड़ रुपए का करोपरांत लाभ अर्जित किया है। एमडीएल ने सरकारी राजकोष को 199.08 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान किया है।

7.64 **सुपुर्दगियां एवं कमीशनिंग:** पी75 परियोजना की स्कोपीन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी, आईएनएस कलवरी की सितंबर, 2017 में सुपुर्दगी की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा 14 दिसंबर, 2017 को इसका जलावतरण किया गया था।



स्कोपीन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी, 'कलवरी' का 14 दिसंबर, 2017 को जलावतरण किया गया



वर्ष 2014-15 के लिए रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 30 मई, 2017 को वितरित किए गए

7.65 **अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलाप:**

- 31 दिसंबर, 2017 तक अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों पर 32.70 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
- परिशुद्धता में बढ़ोतरी करने के लिए मॉडल दृष्टि हेतु अवेवा युक्त गतिशील इंटरफेस वाले 3डी परिवेश में सरल हेड एंड बॉडी ट्रैकिंग शामिल करने के लिए वर्चुअल रियलिटी लैब का उन्नयन किया गया।
- एमडीएल वॉटरफ्रंट को गहरा बनाने की सार्थकता के लिए सीडब्ल्यूपीआर, पुणे के साथ आदर्श अध्ययन पूरा किया गया है।
- डिजाइन में हस्तक्षेप से बचने की दृष्टि से संगतता सुनिश्चित करने हेतु 3डी परिवेश में हीटिंग वेंटीलेशन

एंड एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) अभिन्यास बनाया गया है।

- पोत विस्तृत डिजाइन में श्रमप्रभाविकी को कार्यान्वित किया गया है।
- ईओडी कैमरा और प्लूम विश्लेषण के लिए प्लेटेड मास्ट स्ट्रक्चर पर बाह्य प्रवाह साकार करने के लिए कंप्यूटेशनल फ्लूड डायनामिक्स (सीएफडी) विश्लेषण।
- पायलट मेगा ब्लॉक की 3डी कैड (3-डाइमेंशनल कंप्यूटर डिजाइन) मॉडलिंग, हरित सामग्री के हटाने, यूनिट स्तर पर श्रीकेज एलाउंस से मॉड्यूलर निर्माण में सुविधा हुई है जिससे फैब्रिकेशन एवं इरेक्शन प्रक्रिया चरण में फायदा हुआ है।

7.66 **आधुनिकीकरण:** एमडीएल ने परियोजनाओं का अवसंरचनात्मक आधुनिकीकरण सफलतापूर्वक प्राप्त किया है जिसमें 300टी गोलिथ क्रैन, वेट बेसिन, बिल्डिंग एवं अनुषंगी कार्य, पनडुब्बियों के लिए द्वितीय असेम्बली लाइन के रूप में नई पनडुब्बी असेम्बली वर्कशॉप (एसएसए) शामिल हैं और पोत निर्माण एवं पनडुब्बी सुविधाओं का विस्तार करने की भी योजना है जिसमें पनडुब्बी जलावतरण सुविधाएं, नई 400टी गोलिथ क्रैन, अतिरिक्त आउटफिट असेम्बली शॉप और नाहावा यार्ड में एक नया वर्कफ्रंट सृजित करना शामिल है।

7.67 **स्वदेशीकरण:** एमडीएल में पहले ही से समर्पित स्वदेशीकरण विभाग है और इसका एक "मेक इन इंडिया" वेबपेज है जो रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से जुड़ा हुआ है। छह प्रमुख मदों का स्वदेशीकरण किया गया है और पांच मदों का स्वदेशीकरण किया जा रहा है। पोत निर्माण में स्वदेशीकरण का लक्ष्य 75% है।

7.68 **आउटसोर्सिंग:** खरीदी गई/विनिर्मित मदों के लिए 581 पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं (जिसमें 266 एमएसएमई विक्रेता शामिल हैं) के जरिए डोर्स, हैचेज, लैंडर्स, बोलाडर्स, स्कटल, बुलवर्क स्टैंचियन, टैंक, उपस्कर, सीट और छोटी असेम्बलीज जैसी मदों की आउटसोर्सिंग की जा रही है।

7.69 **कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:** वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट 16.48 करोड़ रु. है और गत दो वित्तीय वर्षों से 20.63 करोड़ रु. को अग्रेनीत किया गया है। थाणे जिले की खराड़े ग्राम

पंचायत के समग्र विकास के लिए इसे गोद लेने और महाराष्ट्र के बीड़ जिले के सूखा प्रभावित पारनेर गांव में चुआन संबंधी कार्यकलाप, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 1000 निजी शौचालयों का निर्माण, स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि में योगदान जैसी विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं।

7.70 **सतत विकास कार्यक्रम:**

(क) नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए, एमडीएल ने 840 केडब्ल्यूपी का सोलर फोटोवोल्टेक (एसपीवी) पावर संयंत्र लगाया है और और 650 केडब्ल्यूपी के एक अतिरिक्त एसपीवी पावर संयंत्र का आर्डर मार्च, 2018 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इस एसपीवी पावर संयंत्र से प्रति वर्ष 8,67,200 यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होने की संभावना है।

(ख) हरित एवं सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने के रक्षा मंत्रालय के दृष्टांत पर, एमडीएल, बीईएल और एचएएल ने ओएफबी के विभिन्न परिसरों में वीजीएफ को छोड़कर 975 करोड़ रु. की कुल लागत के 150 मेगावाट के सौर (एसपीवी) ऊर्जा संयंत्र के लिए 24 नवंबर, 2017 को एक समझौता ज्ञापन किया है।

7.71 **पुरस्कार:**

(क) एमडीएल की जल तरंग छमाही हिंदी पत्रिका को 7 दिसंबर, 2017 को स्कोप सम्मेलन, नई दिल्ली में उत्कृष्ट पत्रिका की श्रेणी में स्कोप से प्रथम पुरस्कार हासिल हुआ है।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन केंद्र (टीओएलआईसी), मुंबई द्वारा जल तरंग पत्रिका को 21 जुलाई, 2017 में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।

(ग) आशीर्वाद द्वारा 27 सितंबर, 2017 को मुंबई में जल तरंग को 'श्रेष्ठ गृह पत्रिकाएं' पुरस्कार दिया गया है।

(घ) रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (2014-15) 30 मई, 2017 को प्रदान किया गया।

(ड.) फिलिपींस में 27 अक्टूबर, 2017 को आयोजित आईसीक्यूसीसी-2017 के दौरान क्वालिटी सर्कल 'गोल्ड' पुरस्कार (संख्या 2) प्रदान किए गए।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)

7.72 गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई), कोलकाता को, जो प्रारंभ में एक पोत मरम्मत योर्ड था, भारत सरकार द्वारा 1960 में अपने नियंत्रण में लिया गया था और यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है आज, जीआरएसई ने पोत निर्माण और सामान्य इंजीनियरिंग के क्षेत्र में व्यापक क्षमताएं विकसित की हैं। कंपनी विभिन्न प्रकार के जलयानों, टम्स एवं बार्जेज से लेकर युद्धपोतों, फ्रिगेट्स, बल्क कैरियर, समुद्र विज्ञान अनुसंधान जलयानों, उच्च शक्ति वाले डीजल इंजनों और पोर्टेबल स्टील ब्रिजेज का विनिर्माण करती है।

7.73 **वित्तीय निष्पादन:** वर्ष 2016–17 में कंपनी ने 930.41 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी का कर पूर्व लाभ 20.89 करोड़ रुपए है और निवल लाभ 12.23 करोड़ रुपए है। कंपनी की निवल पूंजी 1081.51 करोड़ रुपए है।

7.74 **सुपुर्दगियां एवं कमीशनिंग:** जीआरएसई ने तीन युद्धपोतों अर्थात वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट (तरासा), लैंडिंग क्राफ्ट युटिलिटी (एलसीयू एल-52) पनडुब्बीरोधी वारफेयर कार्वेट (किल्टन) की सुपुर्दगी की है। तीन युद्धपोतों अर्थात लैंडिंग क्राफ्ट युटिलिटी की 21 अगस्त, 2017 को, वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट (आईएनएस तरासा) की 26 सितंबर, 2017 को और पनडुब्बीरोधी वारफेयर कार्वेट (आईएनएस किल्टन) की 16 अक्तूबर, 2017 को कमीशनिंग की गई थी।



वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट (तरासा)



लैंडिंग क्राफ्ट युटिलिटी (एलसीयू एल-52)



पनडुब्बीरोधी वारफेयर कार्वेट (किल्टन)

7.75 **पुरस्कार एवं अभिज्ञान:**

- (i) रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार।
- (ii) पासे सिटी फिलिपींस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समागम गुणवत्ता नियंत्रण सर्कल-2017 (आईसीक्यूसीसी-2017) के दौरान 'गुणता नियंत्रण' कार्यकलापों में सर्वोत्तम निष्पादन के लिए जीआरएसई की दो गुणता सर्कल टीमों को गोल्ड पुरस्कार।
- (iii) दो श्रेणियों के लिए स्कोप निगम संचार उत्कृष्टता पुरस्कार।
- (iv) राष्ट्रीय गुणता संकल्पना समागम 2017 (एनसीक्यूसी-2017) के दौरान जीआरएसई की गुणता सर्कल टीमों को चार पुरस्कार।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल)

7.76 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) एक लघु रत्न,

समूह-1 दर्जे की कंपनी है जो भारतीय रक्षा सेनाओं एवं निर्यात बाजार सहित अन्य विविध ग्राहकों के लिए उन्नत उच्च प्रौद्योगिकी वाले युद्धपोतों का इन-हाउस डिजाइन बनाने एवं निर्माण करने में सक्षम है। जीएसएल ने 12000 से अधिक सकल टनेज की वास्तविक सुपुर्दगी की है जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय शिपयार्डों में सर्वाधिक है। शिपयार्ड ने संविदागत सुपुर्दगी से पहले सभी परियोजनाओं की सुपुर्दगी करके एक कीर्तिमान उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा, निर्यातों से 500 करोड़ रु. से भी अधिक के कारोबार (उत्पादन मूल्य का 40%) के साथ भारत में रक्षा पोतों के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। श्रीलंका को एक उन्नत ओपीवी, मॉरीशस को दो एफपीवी और म्यांमार को एक डैमेज कंट्रोल सिम्युलेटर की संविदागत सुपुर्दगी अनुसूची से पहले सफल सुपुर्दगी करने से राष्ट्र की साख में वृद्धि हुई है।

7.77 वित्तीय निष्पादन: वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने 1030.20 करोड़ रुपए का उत्पादन मूल्य अर्जित किया है। वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी का कर पूर्व लाभ 177 करोड़ रुपए है जो गत छह वर्षों के दौरान सर्वाधिक है।

7.78 वर्ष के दौरान सुपुर्दगियां/जलावतरण: पांचवें और छठे जलयान की सुपुर्दगी के साथ शिपयार्ड ने छह पोतों (प्रथम पोत अक्तूबर, 2015 में और अंतिम पोत नवंबर, 2017 में) की सीजी ओपीवी परियोजना सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। सभी छह पोतों की सुपुर्दगी निर्धारित तारीख से पूर्व की गई थी। शिपयार्ड ने सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भी पर्याप्त प्रगति की है। स्टील प्लेटों, गियर बॉक्स, स्टीयरिंग गियर सिस्टम, फिन स्टैबलाइजर सिस्टम, हेली ग्रिड, डोर्स (वॉटर एंड वेदर टाइट) और जैमिनी बोट के स्वदेशीकरण से हाल ही में पूरी की गई तटरक्षक अपतटीय गश्ती जलयान (सीजी ओपीवी) परियोजना (छह जलयान) में 62 प्रतिशत स्वदेशी मात्रा के स्थान पर मौजूदा पांच सीजी ओपीवी परियोजना में स्वदेशी मात्रा बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई है।

7.79 पोत मरम्मत: जीएसएल में रक्षा और वाणिज्यिक जलयानों की मरम्मत करने के लिए एक व्यापक संरचना, तकनीकी ज्ञान एवं विशेषज्ञता समर्पित प्रकोष्ठ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, शिपयार्ड ने सेल प्रशिक्षण पोत तरंगिनी, एनओपीवी 'सुनाया', टग्स एवं क्राफ्ट का मरम्मत कार्य किया है।

7.80 आधुनिकीकरण: यार्ड की 'अवसंरचना संवर्धन योजना'

को चार चरणों में निष्पादित किया जा रहा है जिसमें से चरण 1 व 2(6000 टन शिपलिफ्ट व ड्राई बर्थ) को मार्च, 2011 में पूरा कर लिया गया था और चरण 3ए (पोत निर्माण बेज व फैंब्रिकेशन बेज) को अगस्त, 2016 में पूरा कर लिया गया था। शेष चरण 3बी एवं 4, जिसमें जीआरपी हल के लिए इरेक्शन सुविधा और आगामी एमसीएमवी परियोजना के लिए कमाण्ड एवं कंट्रोल केंद्र शामिल हैं, को वर्ष 2020 के अंत तक पूरा किए जाने की संभावना है। इनके पूरा हो जाने पर जीएसएल भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र शिपयार्ड होगा जिसके पास सुरंग प्रतिरोधी उपाय जलयानों के लिए विशेष जीआरपी हल का निर्माण करने की सुविधा होगी।

7.81 अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी): भावी आवश्यकताओं के लिए उत्पाद के विकास के रूप में, जीएसएल ने 60 मीटर तीव्र गश्ती जलयान के निर्यात के लिए डिजाइन विकसित किया है। उन्नत एएसडब्ल्यू शैलो वाटर क्राफ्ट्स के डिजाइन का विकास किया है।

7.82 जीते गए पुरस्कार: विभिन्न विधाओं में प्राप्त उत्कृष्टता के अभिज्ञान में शिपयार्ड को निम्नलिखित पुरस्कारों से नवाजा गया है:-

- (क) उत्कृष्टता टर्नएराउंड श्रेणी के लिए राष्ट्रपति द्वारा 11 अप्रैल, 2017 को स्कोप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- (ख) सर्वोत्तम निष्पादन शिपयार्ड 2015-16, सर्वोत्तम निर्यात निष्पादन 2014-15, डिजाइन प्रयास स्वयं की पहल परियोजना 2014-15 के लिए रक्षा मंत्री द्वारा 30 मई, 2017 को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- (ग) प्रथम श्रीलंका अपतटीय गश्ती जलयान (एसएलओपीवी) के परियोजना प्रबंधन के लिए पीएमए राष्ट्रीय परियोजना उत्कृष्टता पुरस्कार 2016।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल)

7.83 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड सबसे बड़ा और रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) के अधीन सामरिक रूप से अवस्थित शिपयार्ड है। अब तक, यह यार्ड रक्षा और समुद्री क्षेत्र के लिए 179 जलयानों (11 वेलहैड प्लेटफार्मों सहित) का निर्माण और 1954 जलयानों की मरम्मत कर चुका है।

7.84 **वित्तीय निष्पादन:** गत दो वर्षों के दौरान एचएसएल ने निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में कंपनी ने 629 करोड़ रुपए का कारोबार किया है जो इस यार्ड के पिछले 76 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक है और इसने 650 करोड़ रुपए की कुल आय अर्जित की है जो गत पांच वर्षों के दौरान सर्वाधिक है। इसके अलावा, कंपनी ने 35 वर्षों के अंतराल के बाद वित्तीय वर्ष 2016-17 में 38 करोड़ रुपए का प्रचालनात्मक लाभ अर्जित किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 53.77 करोड़ रुपए का करोपरांत लाभ अर्जित किया है।

7.85 रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और रक्षा अर्जन तथा कार्यक्रम प्रशासन (डीएपीए), कोरिया गणराज्य के बीच 21 अप्रैल, 2017 को पोत निर्माण में रक्षा उद्योग सहयोग के लिए एक अंतर-सरकारी समझौता ज्ञापन किया गया था।

7.86 **पोत निर्माण:** रक्षा मंत्रालय ने फ्लीट सहायता पोत (एफएसएस) तथा एसओवी के निर्माण के लिए एचएसएल को नामित किया है।

7.87 **पनडुब्बी रिफिट/निर्माण:** भारतीय नौसेना की ईकेएम श्रेणी की पनडुब्बी के एमआरसीएम में यार्ड द्वारा प्राप्त विशेषज्ञता पर विचार करते हुए रक्षा मंत्रालय ने जुलाई, 2017 में आईएनएस सिंधुवीर ईकेएम श्रेणी की पनडुब्बी की रिफिट करने के लिए एचएसएल को नामित किया है।



आईएनएस सिंधुवीर का जुलाई, 2017 में आगमन

7.88 **पुरस्कार:** एचएसएल ने प्रोजेक्ट्स ऑन शार्पिंग वर्क, नई वेल्डिंग तकनीक तथा रड्जर कैरियर बेयरिंग्स मोडिफिकेशन की श्रेणी में वर्ष 2015-16 के लिए रक्षा मंत्री का उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया है।

7.89 एचएसएल को प्रौद्योगिकी विकास-इंजन एक्जास्ट (सिल्वर मेडल) तथा प्रौद्योगिकी नवाचार-पोत पर बड़े सेंसर तथा एक जटिल डोमेन स्थापित करने की श्रेणी में वर्ष 2015-16 के लिए सोसाइटी फॉर डिफेंस टेक्नोलोजिस्ट (एसओडीईटी) के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किया गया है।

7.90 **आधुनिकीकरण:** भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक की भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए पनडुब्बी तथा वेपन इंटेनसिव युद्ध पोत, मशीनरी तथा आधारभूत संरचना का नवीकरण तथा प्रतिस्थापन कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त, कोरिया गणराज्य की सरकार के साथ किए गए अंतर-सरकारी समझौते ज्ञापन से कोरिया की विशेषज्ञता का प्रयोग करके उन्नयन तथा आधुनिकीकरण सुविधाओं में विश्व श्रेणी के पोत निर्माण उद्योग के क्षेत्र में गणना होने लगेगी।

7.91 सूचना स्वतः ट्रांजेक्शन तथा डिजाइन एवं विनिर्माण के समेकन में तारतम्यता बनाए रखने के क्रम में एचएसएल ने एसएपी ईआरपी सोल्यूशन का कार्यान्वयन करने के लिए मैसर्स टेक महिन्द्रा लि. से भागीदारी की है। ईआरपी प्रणाली की इन नवीनतम विशेषताओं से एसएपी में पीएलएम को अंतः स्थापित करने में इसकी 3डी विशेषताओं सहित डिजाइन सॉफ्टवेयर, अवीवा मैरीन के समेकन में सफलता मिलेगी।

गुणता आश्वासन महानिदेशालय(डीजीक्यूए)

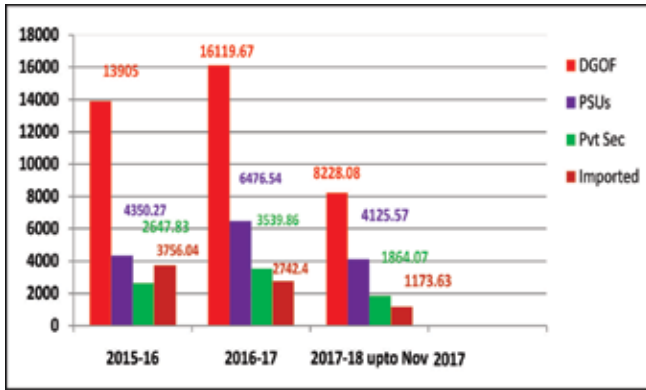
7.92 डीजीक्यूए एक अंतर सेवा संगठन है, जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यरत है। डीजीक्यूए, सेना, नौसेना (नौसेना आर्मामेंट को छोड़कर) तथा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा आयुध निर्माणियों से खरीदी गई नौसेना के लिए सामान्य प्रयोग में आने वाली आयातित तथा स्वदेशी दोनों प्रकार की मर्दों के समग्र रक्षा सामान और उपस्करों की गुणता आश्वासन के लिए जिम्मेवार है।

7.93 **संगठनात्मक ढांचा और कार्य:** डीजीक्यूए संगठन 11 तकनीकी निदेशालयों में संगठित है, जो उपस्करों की विभिन्न रेंज के लिए जिम्मेवार हैं। तकनीकी निदेशालय कार्यात्मक प्रयोजन के लिए दो स्तरों में संगठित है, जो नियंत्रणालयों तथा फील्ड गुणता आश्वासन स्थापनाओं में गठित है। इसके अतिरिक्त, हथियारों और गोलाबारूद को प्रमाणिक करने के लिए आर्मामेंट में प्रूफ स्थापनाएं हैं।

7.94 उपलब्धियां:

(क) सामान की गुणता आश्वासन:

- (i) डीजीक्यूए संगठन ने वर्ष 2017-18 (नवंबर, 2017 तक) कुल 15391.35 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा सामान का निरीक्षण किया है।
- (ii) गत तीन वर्षों के दौरान सामान का विनिर्मातावार मूल्य (करोड़ रुपए में) इस प्रकार है।



आश्वस्त किए गए सामान की गुणता का मूल्य (करोड़ रुपए में)

(ख) 155 एमएम कैलिबर एफएच गन 'धनुष': डीजीक्यूए एकीकृत कार्यात्मक जांच तथा संगठनात्मक प्रूफ फायरिंग और पीएफएफआर, बीएफएफआर तथा एनएफएफआर (विभिन्न फायरिंग रेंज) पर प्रयोक्ता निष्पादन के दौरान भी जुड़ा रहा है।



155 एमएम कैलिबर एफएच तोप 'धनुष'

(ग) डीजीक्यूए तकनीकी मूल्यांकन: डीजीक्यूए ने वर्ष 2017-18 (सितंबर, 2017 तक) कुल 65 तकनीकी मूल्यांकन किए हैं और कई जटिल उप-प्रणालियों सहित विभिन्न प्रकार के

सामान अमीशन, और उपस्करों के 28 प्रयोक्ता परीक्षणों में भाग लिया है। वर्ष 2017-18 के दौरान (सितंबर, 2017 तक) विभिन्न उपस्करों और सामान के 18 पीडीआई और 54 जेआरआई किए हैं।

(घ) सीपीई इटारसी में तोपों के प्रूफ का वैधीकरण:

- (i) एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजी)-आर्मामेंट अनुसंधान तथा विकास स्थापना (एआरडीई) तथा भारत फोर्ज लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम : एटीएजीएस-एआरडीई, पुणे को 152 एमएम/52 कैलिबर गन बैरल की प्रूफ फायरिंग के लिए 'मिशन मोड प्रजोक्ट' के रूप में 155 एमएम/52 कैलिबर एटीएजीएस के विकास का कार्य सौंपा गया है। बीएफएल पुणे द्वारा विकसित प्रथम 155/52 कैलिबर एटीएजीएस के आंतरिक परीक्षण और प्रूफ फायरिंग के लिए एआरडीई पुणे की सहायता के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहायता देने के संबंध में नियंत्रण प्रूफ स्थापना (सीपीई) इटारसी को सौंपा गया है, ताकि बैरल की ताकत को सिद्ध किया जा सके। सीपीई इटारसी में जून, 2015 को 155 एमएम/52 कैलिबर एटीएजीएस बैरल रजिस्ट्रेशन नं. एआरडीई/बीएफएल/20009-1/14 का सफलतापूर्वक फायरिंग परीक्षण किए गए थे।
- (ii) भारत 52 - भारत फोर्ज लिमिटेड, पुणे: 155 एमएम/52 कैलिबर होबित्जर का फायरिंग परीक्षण - मैसर्स बीएफएल, पुणे ने अपने 10 अप्रैल, 2017 के पत्र सं. भारत 52/ट्रायल्स प्रूफ/01 के तहत 155 एमएम/52 कैलिबर होबित्जर के फायरिंग परीक्षण भुगतान आधार पर प्रूफ रेंज तथा प्रूफ स्टॉक संघटकों का आवंटन करने का अनुरोध किया था। 155 एमएम/52 कैलिबर गन के फायरिंग परीक्षण 10 अक्टूबर, 2017 को नियंत्रण प्रूफ स्थापना, (सीपीई) इटारसी में पूर्व मैसर्स बीएफएल द्वारा किए गए थे।
- (iii) भारतीय फील्ड गन (आईएफजी) की सॉफ्ट रिकोइल प्रणाली- ईएमई स्कूल बड़ोदा तथा भारत फोर्ज लि. के बीच संयुक्त उद्यम : सॉफ्ट रिकोइल प्रणाली सहित टाटा 2.5 टन पर लगी हुई 105

एमएम हल्की फील्ड गन (एलएफजी) की फायरिंग का प्रमाणीकरण—ईएमई स्कूल बड़ोदरा ने अपने दिनांक 21 जुलाई, 2016 के पत्र सं.24501/एटीबी/पीसी—VIII/टी—4/टीआरजी—2 के तहत डीजीक्यूए से आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने से पूर्व मैसर्स बीएफएल द्वारा विकसित सॉफ्ट रिकोइल प्रणाली सहित टाटा 2.5 पर स्थापित 105 एमएम एलएफजी का फायरिंग प्रमाणिकरण किए जाने का अनुरोध किया गया था। सॉफ्ट रिकोइल प्रणाली सहित टाटा 2.5 एमएम पर स्थापित 105 एमएम एलएफजी की परीक्षण फायरिंग सीपीई, इटारसी में दो चरणों में 9 नवंबर और 23 नवंबर, 2016 को सफलतापूर्वक की गई थी।

(ड) **आयुध मास्टर जनरल (एमजीओ) उद्योग सहयोग की वार्षिक बैठक (एएमआईसीओएम)** : सेना की एमजीओ शाखा, जो भारत सरकार की 'भारत में बनाओ' पहल का पूरा-पूरा लाभ उठाने तथा प्रभावकारिता और कारगरता बनाए रखने के संबंध में हथियार प्रणालियों, वाहनों और उपस्करों को वृहत रूप से सुसज्जित रखने के लिए भारतीय सेना की सक्रियात्मकता को तैयार रखने के लिए जिम्मेवार है, ने वार्षिक एमजीओ उद्योग सहयोग बैठक करके एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया है ताकि जरूरतों, क्षमताओं और सरोकारों को साझा करके भारतीय सेना और उद्योग एक प्लेटफार्म के रूप में कार्य कर सके।

(च) एएमआईसीओएम—17 का आयोजन एक एमजीओ—सीआईआई की पहल के रूप में 25—26 जुलाई, 2017 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में किया गया था। इस सेमिनार में प्रमुख विषय फास्ट ट्रेक स्वदेशीकरण के लिए नई रणनीतियों का ईजाद करना था। इसमें डीजीक्यूए को आमंत्रित किया गया था और इस सेमिनार में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया था :

- एडीजीक्यूए (ईई) द्वारा 'पंजीकरण/क्षमता सत्यापन/क्षमता मूल्यांकन' की प्रक्रिया पर प्रस्तुतीकरण।
- एडीजीक्यूए (वी) द्वारा 'क्यूए सिद्धांतों, दिशा निर्देशों और प्रक्रियाओं' पर प्रस्तुतीकरण।
- एक के बाद एक निम्नलिखित विचार—विमर्श हुए।

❖ भारत सरकार की, 'भारत में बनाओ' पहल के

अंतर्गत परिव्ययनीय आधार पर उद्योग के लिए डीजीक्यूए को फील्ड रेंज उपलब्ध कराने के लिए एसओपी पर विचार—विमर्श।

❖ वाहनों के पंजीकरण के संबंध में ग्रीन चैनल पालिसी तथा ड्राफ्ट ज्वाइंट सर्विस गाइड पर विचार—विमर्श।

(छ) **डीजीक्यूए दिवस 2017— हीरक जयंती मनाई गई** डीजीक्यूए दिवस 2017— 28 सितंबर, 2017 को हीरक जयंती मनाई गई। यह कार्यक्रम डॉ. डी.एस कोठारी सभागार, डीआरडीओ, भवन नई दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ और फस्ट डे कवर जारी किया गया और डीजीक्यूए वेबसाइट पर वेंडर रजिस्ट्रेशन का लिंक भी शुरू किया गया।

7.95 **भावी चुनौतियां:**

(क) **ग्रीन चैनल नीति** : 'भारत में बनाओ' राष्ट्रीय विजन व्यवसाय का सरल तरीके से संवर्धन करने की बात को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र सेनाओं में लगातार जरूरत/वृहत रूप से उपयोग में लाई जा रही मर्दों की सामान्य श्रेणियों की आपूर्ति करने वाली उन फर्मों को ग्रीन चैनलों का दर्जा देने की एक योजना शुरू की है, जिन फर्मों का कारोबार गत तीन वर्षों में औसतन 1000 करोड़ रुपए या इससे अधिक रहा है और जो फर्म गत पांच वर्षों से मुनाफा कमा रही हैं वे ग्रीन चैनल दर्जा पाने की हकदार हैं। तदनुसार, रक्षा उत्पादन विभाग ने एक ग्रीन चैनल नीति तैयार की है और इसे रक्षा मंत्री के अनुमोदन से दिनांक 24 मार्च, 2017 के रक्षा मंत्रालय के आदेश सं. 43(5)/2015/डी(क्यूए) के तहत जारी किया है।

(ख) **6 चुनिंदा आयुध निर्माणियों में पायलट परियोजना का कार्यान्वयन** : रमन पुरी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने चुनिंदा 6 निर्माणियों अर्थात् आयुध निर्माणी, खमरिया (ओएफके), आयुध निर्माणी, बडमाल (ओएफबीएल), आयुध निर्माणी अंबाझरी (ओएफएजे), आयुध निर्माणी, मेढक (ओएफएमके), आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर (ओएफसी) तथा गन कैरीज निर्माणी (जीसीएफ) में पायलट परियोजना लागू करने का निर्णय लिया है। परियोजना की पुनरीक्षा समिति से, अपनी अंतिम रिपोर्ट मार्च, 2018 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(ग) **आधुनिकीकरण:** डीजीक्यूए ने अपनी मौजूदा परीक्षण सुविधाओं को राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण बोर्ड (एनएबीएल) की तर्ज पर उन्नत बनाया है। 36 प्रयोगशालाओं को एनएबीएल प्रत्यायन पुरस्कार दिया गया है। डीजीक्यूए स्वदेशी प्रयोजन के लिए वेंडरों को प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाएं तथा प्रूफ सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

(घ) **प्रशिक्षण संबंधी पहल:** गुणता आश्वासन रक्षा संस्थान (डीआईक्यूए) अपने गुणता प्रबंधन के क्षेत्र में डीजीक्यूए अधिकारियों तथा अन्य संगठनों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(ङ) **निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर):**

(i) **स्वच्छ भारत अभियान:** स्वच्छ भारत अभियान के रूप में, 15 दिसंबर, 2017 से डीजीक्यूए मुख्यालय तथा इसकी स्थापनाओं में स्वच्छ पखवाड़ा मनाया गया था। इस अवधि में निम्नलिखित कार्यकलाप सफलतापूर्वक किए गए।

- शपथ समारोह/स्वच्छता प्रतिज्ञा दिलाई गई।
- परिसर में कूड़ा करकट तथा सामान का निष्पादन व्यवस्थित तरीके से किया गया।
- पुरानी फाइलों तथा कार्यालय उपकरणों की छटाई की गई।
- कार्यालय परिसर में पनप रहे मच्छरों तथा अन्य कीड़ों की रोकथाम के लिए कीड़े मकौड़ों पर एक सेमिनार की गई।
- 'सफाई के महत्व पर' निबंध तथा पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए मिनी मैराथन का आयोजन किया गया।

(ii) **दिव्यांगों के साथ मित्रवत व्यवहार:** संगठन, दिव्यांगों को उनकी जरूरत के अनुसार कोरिडोरों में फर्नीचर आदि के लिए उनके साथ मित्रवत व्यवहार करता है।

(iii) **नहीं बालिकाओं को बचाना (बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ):** संगठन अपने कर्मचारियों में जागरूकता फैलाकर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ में सहयोग कर रहा है, ताकि निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

- भ्रूण हत्या को रोकना।
- बालिकाओं को बचाना और सुरक्षा देना।
- बालिकाओं को शिक्षित करना।
- सभी सार्वजनिक स्थलों पर बालिकाओं की सुरक्षा व संरक्षा करना।

(iv) **पेड़ लगाना और रक्त दान करना:** कुल 23,000 पेड़ लगाए गए हैं और स्वैच्छिक रक्त दान कैंपों के माध्यम से 911 यूनिट रक्त दान किया गया। अन्य गतिविधियों में वृद्धावस्था गृहों/अनाथालयों, लघु दौड़ और योग का भी आयोजन किया गया।



उन्नत शिल्का

वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए)

7.96 डीजीएक्यूए सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, आयुध निर्माणियों, डीआरडीओ आदि के लिए गुणता आश्वासन नियामक प्राधिकरण है और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, आयुध निर्माणियों, डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, तेल शोधक कारखानों तथा निजी ट्रेड फर्म आदि के लिए डिजाइन, विकास, उत्पादन, ओवरहाल, मरम्मत, उन्नयन तथा संशोधन के दौरान सेना विमानों, संबद्ध सहायक उपकरणों, वायु आर्मामेंट, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) मिसाइलों आदि के लिए गुणता आश्वासन प्रदान करता है। डीजीएक्यूए सेना वैमानिक भंडारों की विदेशी खरीद के दौरान तकनीकी मूल्यांकन, फील्ड परीक्षण, प्रेषण पूर्ण निरीक्षण (पीडीआई) के लिए एक अहम कार्य करता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान डीजीएक्यूए ने 31 दिसंबर, 2017 तक 8547.73 करोड़ रुपए मूल्य के सेना वैमानिकी सामान के लिए गुणता आश्वासन संबंधी सेवाएं प्रदान की हैं।

मानकीकरण निदेशालय (डीओएस)

7.97 मानकीकरण महानिदेशालय अपने प्रारंभ से ही प्रचुरोद्भव से कम कर रहा है ताकि तीनों सेनाओं में सामानता स्थापित करने, उपस्करों/संगठकों में डुप्लिसिटी को कम करने के बारे में संपूर्ण मांग सूची का इष्टतम प्रयोग किया जा सके। मानकीकरण महानिदेशालय को सौंपे गए कर्तव्यों में मौजूदा विभिन्न मानकीकरण दस्तावेजों, मदों का वर्गीकरण, विभिन्नता तथा प्रवेश नियंत्रण के लिए नई और उन्नत सतत् प्रक्रिया ईजाद करके मानकीकरण और वर्गीकरण का कार्य कर रहा है।

7.98 **लक्ष्य और उपलब्धियां:** अध्यक्ष मानकीकरण उपसमिति की समिति ने (सीसीएसएससी) ने वर्ष 2017–18 तक (101 नए तथा 863 संशोधित मामले) 964 मानकीकरण दस्तावेजों का लक्ष्य निर्धारित किया है। 01 अप्रैल, 2017 तक, 5228 सक्रिय मानकीकरण दस्तावेज उपलब्ध हैं।

7.99 नाटो (मित्र राष्ट्र समिति-135) मानकीकरण निदेशालय ने एपेक्स वर्गीकरण इकाई की एक स्तरीय सदस्यता के साथ वर्गीकरण तथा भारतीय सेना की संपूर्ण इंवेंटरी का कैटलॉग करने के लिए अग्रिम वेब आधारित साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर स्वीकृत वर्गीकरण प्रणाली की नई अवधारणा को लागू किया है। प्रणालीबद्ध वर्गीकरण तथा रक्षा मांग की कैटलाग में सहायता देने के अतिरिक्त नई वर्गीकरण प्रणाली अंतरराष्ट्रीय संचारिकी सिस्टम प्रणाली पर भारतीय उद्योग को सक्षम बनाने और उनकी वैश्विक रक्षा खरीद प्रणाली में भागीदारी को बढ़ाने में भी कारगर हुई है। मित्र राष्ट्र समिति-135 की दो स्तरीय सदस्यता के लिए पूर्व अपेक्षित वर्गीकरण प्रणाली/साफ्टवेयर का संतोषजनक परीक्षण नवंबर, 2017 में पूरा कर लिया गया है।

योजना एवं समन्वय निदेशालय

7.100 योजना एवं समन्वय निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। निदेशालय मुख्यतः विभिन्न सक्षम नीतियों जैसे भारत में बनाओं पहल, एफडीआई नीति /औद्योगिकी लाइसेंस नीति का सरलीकरण, निजी क्षेत्र को समान अवसर उपलब्ध कराने, रक्षा तकनीकी हब का सृजन करने तथा स्वदेशी मार्ग से खरीद को वरीयता देने जैसी कारगर नीति के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी प्रक्रिया का विस्तार करके रोबस्ट स्वदेशी उद्योग स्थापित करने, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिदेशित है। इसके

अतिरिक्त, निदेशालय रक्षा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने और अन्य देशों के लिए रक्षा उपस्करों का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है।

7.101 इसके अतिरिक्त, निदेशालय सेना मुख्यालयों के पूंजीगत अर्जन प्रस्तावों पर डीडीपी की भावी योजनाओं के लिए सलाह प्रदान करता है और रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया— (डीपीपी) को कारगर बनाने के लिए अहम भूमिका भी निभाता है। निदेशालय नौसेना शिपयार्डों के आधुनिकीकरण के लिए जारी प्रयासों में और गति प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाता है।

रक्षा प्रदर्शनी संगठन (डीईओ)

7.102 डीईओ का मुख्य कार्य भारत और विदेशों में रक्षा प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना और सहयोग करना है, ताकि भारतीय रक्षा उद्योगों द्वारा विकसित और विनिर्मित रक्षोन्मुखी उत्पादों और सेवाओं का निर्यात इष्टतम रूप से बढ़ाया जा सके।

7.103 **भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी:** भारतीय रक्षा उद्योग को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए, एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराए जाने के संबंध में डीईओ भारत में एरो इंडिया तथा डिफेंसपो इंडिया नामक दो द्विवर्षीय अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। एरो इंडिया, एरो स्पेस तथा विमानन उद्योग के लिए तथा भारत में डिफेंसपो भूमि तथा नौसेना प्रणालियों के लिए है।

(i) एरो इंडिया 1996 में शुरू हुआ था, ने एरो स्पेस रक्षा नागरिक उड्डयन, हवाई अड्डा आधारभूत संरचना तथा रक्षा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के रूप में अपना स्थान बना लिया है। एरो इंडिया 2017 का 11वां संस्करण वायु सेना स्टेशन, येलहंका , बेंगलूरु में 14–18 फरवरी, 2017 को आयोजित किया गया था।

(ii) डिफेंसपो इंडिया ने 1999 में शुरू किए गए एरो इंडिया, डिफेंसपो इंडिया में अनुपूरक प्रदर्शन हासिल किया है। डिफेंसपो इंडिया का 10वां संस्करण 2018 में आयोजित किया जाएगा। डिफेंसपो इंडिया सतत वृद्धि के मार्ग को स्पष्ट रूप से प्रशस्त कर रहा है और उसे प्रत्येक संस्करण से जबरदस्त तथा अप्रत्याशित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्युत्तर मिल रहा है। इस प्रदर्शनी से भारत को

रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए एक प्रभावकारी अवसर प्राप्त हो रहा है तथा यह रक्षा उद्योग में गठजोड़ तथा संयुक्त उद्यमों के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में भी कार्य कर रहा है। बी2बी बैठकों, प्रदर्शनी प्रेस सम्मेलनों, शुरू किए जाने वाले उत्पादों के साथ रक्षा खरीद प्रक्रिया तथा ऑफसेट नीति पर नियमित रूप से परस्पर सेमिनार की जाती हैं, ताकि अत्याधुनिक विकास से भागीदारों को अद्यतन बनाए रखा जा सके। इन प्रदर्शनियों से अंतरराष्ट्रीय सरकार तथा सेना अभिकरणों को अप्रत्याशित नेटवर्क भी उपलब्ध होता है। हम विदेशी भागीदारों के जबरदस्त प्रत्युत्तर के लिए धन्यवाद करते हैं।

(iii) इन प्रदर्शनियों के अलावा, डीईओ ने निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भाग लिया है/आयोजित की हैं।

- **भारतीय नौसेना (जीजेएसएम) – 2017 की पनडुब्बी आर्म का स्वर्ण जयंती समारोह** : भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आर्म नौसेना (जीजेएसएम-2017) का स्वर्ण जयंती समारोह विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश में 6-9 दिसंबर, 2017 में आयोजित किया गया था। इस संगठन द्वारा कई और आयोजन किए गए हैं।

7.104 विदेश में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी:

(i) भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमताओं में निर्यात संबंधी कारगरता उपलब्ध कराने के प्रयोजन से डीईओ भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा विनिर्मित रक्षा उत्पादों के लिए बाजार विकसित करने के प्रयोजन से विदेश में बड़ी रक्षा

अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के रूप में इंडिया पैवेलियन के नाम से आयोजित करता है।

- (ii) चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित ओवरसीज अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भारतीय पैवेलियनों का आयोजन किया गया है।
- लैटिनअमेरिका एरो स्पेस एंड डिफेंस (एलएएडी)-2017, 4-7 अप्रैल, 2017 तक रियो-डि-जेनिरियो, ब्राजील में।
 - इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एक्सीबिशन एंड कांफ्रेंस (आईएमडीईएक्स) – 2017, 16-18 मई, 2017 में सिंगापुर में।
 - पेरिस एयर शो-2017, 19-25 जून, 2017 में पेरिस, फ्रांस में।
 - इंटरनेशनल एविएशन एंड स्पेस सैलोन एमएकेएस-2017, 18-23 जुलाई, 2017 में मास्को, रूस में।
 - डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्युपमेंट अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी तथा कांफ्रेंस (डीएसईआई)-2017, 12-15 सितंबर, 2017 में लंदन, यू.के. में।
 - सियोल इंटरनेशनल एयरोस्पेस एंड रक्षा प्रदर्शनी (सियोल एडीईएक्स)- 2017, 17-22 अक्टूबर से सियोल, दक्षिण कोरिया में।
 - डिफेंस एंड सिक्योरिटी –2017, 6-9 नवंबर, 2017 तक बैंकाक, थाइलैंड में।

सारणी सं. 7.1

कार्यकारी परिणाम

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों तथा आयुध निर्माणी बोर्ड का उत्पादन मूल्य

(करोड़ रुपए में)

डीपीएसयू का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (दिसंबर, 2017 तक) (अंतिम)
एचएएल	16288	17152	17104	8939
बीईएल	6659	7775	9244	6674
बीईएमएल	2599.93	2736.90	2623.90	2027.68

डीपीएसयू का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (दिसंबर, 2017 तक) (अंतिम)
बीडीएल	2770.05	4297.82	5011.00	2729.96
जीआरएसई#	1612.66	1660.75	927.19	701.39
जीएसएल	569.55	725.96	1030.19	1010.39
एचएसएल	294.16	593.29	629.04	311.85
एमडीएल#	3592.60	4106.22	3523.67	2887.08
मिधानि	640.04	678.78	695.64	386.84
ओएफबी	11364	13047	14825	8451
कुल	46389.99	52773.72	55614.29	34119.07

#2015-16 से 2017-18 में वित्तीय आंकड़ों में परिवर्तन, आईजीएपी से आईएंडडी एस की लेखाकरण प्रणाली में परिवर्तन होने के कारण हुआ है।

सारणी सं. 7.2
डीपीएसयू का कर उपरांत लाभ

(करोड़ रुपए में)

डीपीएसयू का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (दिसंबर, 2017 तक) (अंतिम)
एचएसएल	2388	1998	2616	995
बीईएल	1167	1307	1548	538
बीईएसएल	6.67	63.66	84.44	66.38
बीडीएल	418.57	564.88	524.06	72.60
जीआरएसई	43.45	162.05	12.23	31.01
जीएसएल	78.24	62.28	117.41	110.39
एचएसएल	-202.84	19.00	53.77	-39.60
एमडीएल	491.59	575.23	525.12	322.19
मिधानि	102.13	118.03	127.29	46.74
कुल	4492.9	4870.1	5608.3	2142.7



रक्षा अनुसंधान और विकास





रक्षा अनुसंधान और विकास

पृष्ठभूमि

8.1 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 1 जनवरी 1958 को अपनी स्थापना के बाद से देश का एक प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बल बनने के लिए काफी लंबा सफर तय किया है। केवल 10 प्रयोगशालाओं के साथ एक बहुत छोटे संगठन के रूप में शुरुआत के बाद डीआरडीओ ने बहुआयामी रूप से विकास किया है और पूरे देश में फैली हुई 50 प्रयोगशालाओं के एक विशाल नेटवर्क के साथ एक मजबूत और परिपक्व संगठन के रूप में उभरा है।

8.2 डीआरडीओ रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील वृद्धि और देश के अनुसंधान एवं विकास के बुनियादी ढांचे और क्षमता में वृद्धि के प्रति समर्पित है। इसका उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिकियों से स्वतंत्र बनाना और सबसे संवेदनशील वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञता के एक भंडार का निर्माण करना है। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय को रक्षा नीति के समर्थन में वैज्ञानिक और

तकनीकी सलाह देने; सैन्य संचालन आवश्यकताओं के लिए रक्षा उपकरणों का मूल्यांकनकर्ता होने और राज्य की अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के विकास के लिए रक्षा उद्योगों को स्थानांतरित करने के लिए नए तकनीकी ज्ञान का सृजन करने जैसी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है।

8.3 डीआरडीओ देश के लिए उत्पादों/प्रणालियों को बनाने के लिए, आमतौर पर ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओएफबी) और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (डीपीएसयू) के साथ निलकर काम करता है। हालांकि, डीआरडीओ ने आवश्यकता और भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को व्यापक बनाने के लिए, अपने दायरे में भारतीय निजी क्षेत्र को भी शामिल किया है। यह सरकार के 'मेक इन इंडिया' दृष्टिकोण के समन्वय में है जिसका उद्देश्य भारत को एक ऐसा वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र बनाना है, जिसके उत्पाद श्रेष्ठ गुणवत्ता का पर्याय बन सकें और वैश्विक उपभोक्ताओं के बीच भरोसे को बढ़ावा दे सकें। डीआरडीओ, आज और अतीत में हमेशा से प्रणालियों/उत्पादों/ प्रौद्योगिकियों के विकास के

द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया है, जिससे भारतीय उद्यमियों/ उद्योगों और व्यावसायियों के लिए भारत में निर्माण करने के लिए अवसर प्रदान किया जा सके।

संगठनात्मक संरचना

8.4 सचिव डीडी अनुसंधान एवं विकास एवं डीआरडीओ के अध्यक्ष डीआरडीओ का नेतृत्व संभालते हैं। डीआरडीओ प्रयोगशालाओं को सात प्रौद्योगिकी समूहों—एयरोनॉटिकल प्रणाली (एईआरओ), आर्ममेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग प्रणाली (एसीई), इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्युनिकेशन सिस्टम्स (ईसीएस), लाइफ साइंसेज (एलएस), माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कम्प्यूटेशनल प्रणाली (एमईडी एंड सीओएस), मिसाइल एंड स्ट्रैटेजिक प्रणाली (एमएसएस) और नवल सिस्टम्स एंड मटीरियल्स (एन एस एंड एम) में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक समूह महानिदेशक (डीजी) के अंतर्गत कार्य करते हैं। डीआरडीओ के सात डीजी कार्यालय बेंगलोर (एरो एंड ईसीएस), पुणे (एसीई), दिल्ली (एमईडी एंड सीओएस और एलएस), हैदराबाद (एमएसएस) और विशाखापटनम (एनएस एंड एम) में स्थित हैं। प्रत्येक क्लस्टर डीजी के अंतर्गत स्थित प्रयोगशालाओं की सूची तालिका संख्या 8.1 में दी गई है।

8.5 दिल्ली स्थित डीआरडीओ मुख्यालय (एचक्यू), संगठन के समग्र कामकाज का समन्वय करता है, यह सरकार और क्लस्टर मुख्यालय और प्रयोगशालाओं के बीच का एक अंतरफलक है। कॉर्पोरेट मुख्यालय की गतिविधियों की देखरेख के लिए पाँच कॉर्पोरेट डीजी (अप्रैल 2017 में सीसी अनुसंधान एवं विकास डीजी के रूप में नामित) अर्थात् डीजी मानव संसाधन (एचआर), डीजी प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज इंटरैक्शन (पीसी एंड एसआई), डीजी रिसोर्सिंग एंड मैनेजमेंट (आर एंड एम), डीजी प्रणाली एनालिसिस एंड मॉडलिंग (एसएम) और डीजी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट (टीएम) हैं। इसके अलावा, एक डीजी (आर एंड डी) भी है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक ब्रम्होस – भारत रूसी संयुक्त उद्यम के रूप में कार्य करता है, इसमें डीआरडीओ एक भागीदार है।

8.6 डीआरडीओ के पास कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन (सीईपीटीएम), प्रौद्योगिकी संस्थान (आईटीएम) और भर्ती और आकलन केंद्र (आरएसी) केंद्र नामक तीन मानव संसाधन संस्थान हैं।

8.7 संगठन के पास डीआरडीओ के अधीन तीन प्रमाणीकरण एजेंसियाँ अर्थात् उत्पादों की उद्गान योग्यता के लिए सैन्य उद्गान

तालिका 8.1

संवैधानिक प्रयोगशालाओं के साथ तकनीकी कार्यक्षेत्र आधारित समूहों के प्रमुख

समूह के निदेशालय	प्रयोगशालाएं एवं प्रतिष्ठान
डीजी (एईआरओ)	एडीई, एडीआरडीई, सीएबीएस, जीटीआरई
डीजी (एसीई)	आयुध: एआरडीई, एचईएमआरएल, पीएक्सई लड़ाकू वाहन: सीवीआरडीई, डीटीआरएल, आर एवं डीई (ई), एसएसईए वीआरडीई
डीजी (ईसीएस)	सीएचईएसएस, डीएआरई, डीईएएल, डीएलआरएल, आईआरडीई, एलएसटीईसी, एलआरडीई
डीजी (एलएस)	डीईबीईएल, डीएफआरएल, डीआईबीईआर, डीआईएचएआर, डीआईपीएएस, डीआईपीआर, डीआरडीई, डीआरएल (टी), आईएनएमएस
डीजी (मेड एवं सीओएस)	माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: अनुराग, एमटीआरडीसी, एसएसपीएल कम्प्यूटेशनल सिस्टम: सीएआईआर, जेसीबी, एसएजी
डीजी (एमएसएस)	एसएसएल, डीआरडीएल, आईटीआर, आरसीआई, टीबीआरएल
डीजी (एनएस एवं एम)	नौवहन प्रणालियाँ: एनएमआरएल, एनपीओएल, एनएसटीएल सामग्रियाँ: डीएलजे, डीएमआरएल, डीएमएसआरडीई

योग्यता एवं प्रमाणन केंद्र (सीएएमआईएलएसी), अग्नि एवं विस्फोटकों के लिए अग्नि विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केंद्र (सीएफईईएस) तथा सूचना सुरक्षा उत्पादों के ग्रेडिंग के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण समूह (एसएजी) मौजूद हैं। ये प्रमाणन एजेंसियां डीआरडीओ के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य संगठनों के लिए भी सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, सीएमआईएलएसी के तत्वावधान में सैन्य उड़ान योग्यता (आरसीएमए) के लिए पूरे देश में विभिन्न स्टेशनों पर क्षेत्रीय केंद्र स्थित हैं।

8.8 इसके अलावा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अधीन बेंगलुरु में वैमानिकी विकास एजेंसी जैसा एक स्वायत्त निकाय, दिल्ली में ब्रह्मोस एयरोस्पेस जैसा एक संयुक्त उद्यम और एक डीमड विश्वविद्यालय अर्थात् पुणे में रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (डीआईएटी) है।

जनशक्ति

8.9 डीआरडीओ में कुल 24,029 कर्मचारी हैं, जिनमें से 7,435 रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (डीआरडीएस) में, 8,964 सैन्य अनुसंधान एवं तकनीकी संवर्ग (डीआरटीसी) और 7,630 प्रशासन एवं संबद्ध संवर्ग में कार्यरत हैं।

बजट

8.10 चालू वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, डीडीआर एवं विकास को 14,818.74 करोड़ रुपए (बीई) आबंटित किए गए हैं, जो कुल रक्षा बजट का 5.4% है। पूंजी शीर्ष के अंतर्गत कुल 7,552.32 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 7,266.42 करोड़ रुपए राजस्व शीर्ष के अंतर्गत आवंटित किए गए हैं।

कार्यक्रम एवं परियोजनाएं

8.11 डीआरडीओ परियोजनाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

- **मिशन मोड (एमएम):** ये कठोर समय सीमा के साथ उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के आधार पर आरंभ किया जाता है और आम तौर पर इन परियोजनाओं के संचालन में उपयोगकर्ताओं की प्रमुख राय के साथ एक से अधिक प्रयोगशालाएं शामिल होती हैं।

- **प्रौद्योगिकी प्रदर्शन (टीडी):** इन्हें सामान्यतः डीआरडीओ द्वारा भावी या आसन्न एमएम परियोजनाओं के लिए फीडर प्रौद्योगिकियों के रूप में शुरू किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी विशेष तकनीक का विकास, परीक्षण और प्रदर्शन करना होता है।

- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी):** ये आम तौर पर बुनियादी अनुसंधान/अनुप्रयुक्त शोध होते हैं, जिन्हें प्रयोगशालाओं द्वारा भविष्य की प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के संरेखण के द्वारा आरंभ किया जाता है।

- **बुनियादी ढांचा और सुविधाएं (आईएफ):** इन परियोजनाओं में आम तौर पर उन्नत परीक्षण और योग्यता की सुविधाएं शामिल होती हैं, इन्हें आईएफ मोड के माध्यम से आरंभ किया जाता है। यह अनिवार्य रूप से एक पूंजी निवेश है जो तैयार/विकसित की गई प्रौद्योगिकी/प्रणाली की वैधता में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

- **उत्पाद समर्थन (पीएस):** इस श्रेणी की परियोजनाओं को एक सीमित अवधि के लिए प्रणाली के उत्पादन या रखरखाव/तकनीकी सहायता के रूप में किया जाता है, इनका उद्देश्य मौजूदा प्रणाली का उन्नयन करना होता है।

- **उपयोगकर्ता परीक्षण (यूटी):** इस श्रेणी के दायरे में परीक्षण के दौरान डीआरडीओ समर्थन सहित उपयोगकर्ता परीक्षण का संचालन शामिल है।

8.12 कैलेंडर वर्ष के दौरान 21,489 करोड़ रुपए (डीआरडीओ का हिस्सा: 6114 करोड़ रुपए) की कुल लागत पर 62 नई परियोजनाओं मंजूर की गई हैं और करोड़ 3756 रुपए की कुल लागत पर 49 परियोजनाओं (डीआरडीओ का हिस्सा: 2819 करोड़ रुपए) को बंद कर दिया गया है।

8.13 डीआरडीओ द्वारा वर्तमान में लगभग 71,265 (उपयोगकर्ता हिस्सेदारी सहित) करोड़ रुपए की राशि से 324 परियोजनाएं (सामरिक परियोजनाओं को छोड़कर) चलाई जा रही हैं। चल रही 324 परियोजनाओं में से 52 बड़ी परियोजनाओं (लागत \geq 100 करोड़ रुपए) की लागत 64,239 करोड़ रुपए (डीआरडीओ की हिस्सेदारी कुल हिस्सेदारी का 70%) है।

8.14 सुरक्षा के लिए कैबिनेट समिति (सीसीएस) द्वारा 11 बड़े कार्यक्रम मंजूर किए गए हैं, जिनकी लागत 52,000 करोड़ रुपए (डीआरडीओ का हिस्सा: 23,841 करोड़ रुपए) है। सीसीएस कार्यक्रम की कुल लागत का लगभग 54% उपयोगकर्ताओं द्वारा वित्त पोषित है। इनमें से चार सीसीएस परियोजनाएं मिसाइलों के डिजाइन और विकास से संबंधित हैं: भारतीय नौसेना और भारतीय नौसेना के भारतीय विमान वाहक (आईएसी) के लिए लंबी दूरी की सतह-से-हवा में वार करने वाली मिसाइल (एलआरएसएएम) और भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के लिए मध्यम दूरी की सतह-से-हवा में वार करने वाली मिसाइल। (एमआरएसएएम)। एयरोनॉटिक्स के क्षेत्र में निम्नलिखित सीसीएस परियोजनाएं हैं: हल्के युद्धक विमान (एलसीए) वायुसेना एमके-1, एलसीए वायुसेना एमके -II, एलसीए नौसेना एमके-1, एलसीए नौसेना एमके -II, हवाई पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण (ईडब्ल्यू एंड सी) प्रणाली, मध्यम ऊँचाई लंबी सहनशीलता (एमएएलई) मानव रहित हवाई वाहन 'रुस्तम-II' और कावेरी इंजन। हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण (इंडिया) प्रोग्राम को मंजूरी दे दी गई है लेकिन धन की मंजूरी अभी दी जानी है।

8.15 वर्ष 2017 में डीआरडीओ की परियोजनाओं में कई महत्वपूर्ण मुकाम/उपलब्धियां हासिल की गईं, जिनमें से कुछ अगले अनुच्छेदों में वर्णित हैं:

हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए) 'तेजस': स्वदेशी तौर पर विकसित एलसीए एक उन्नत तकनीक, सुपरसोनिक, हल्के वजन का सभी मौसमों में, बहु-भूमिका निभाने वाली लड़ाकू विमान है जो कई युद्धक भूमिकाओं के लिए तैयार है। वर्ष 2016 के दौरान, रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 83 एलसीए तेजस एमके -1, विमान के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लागत से अधिग्रहण की आवश्यकता (एओएन) प्रदान की, जो डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रणाली के लिए सबसे बड़ी स्वीकृति है। आज तक तेजस विमान (चालू वर्ष में 406 सहित) के 3716 उड़ान परीक्षण पूरे हो चुके हैं। एलसीए विमान ने आईसीएफ 45 स्कवार्डन एलसीए सीरीज उत्पादन विमान के साथ पहली बार गणतंत्र दिवस फ्लाइट पास्ट में भाग लिया। एलसीए ने 14 से 18 फरवरी, 2017 के दौरान आयोजित एरो इंडिया शो में भी भाग लिया। 11 मई, 2017 को आईएएफ बेस, पश्चिम बंगाल से किए गए परीक्षण के दौरान तेजस विमान (एलएसपी4) से रडार दिशा निर्देशित मोड में दृश्य सीमा से परे हवा-से-हवा में वार करने वाली डर्बी मिसाइल छोड़ी गई

थी, जिसमें मिसाइल ने प्रत्यक्ष चोट हासिल की। ओपेस क्लीन कॉन्फिगरेशन में विमान संकुल विस्तार के लिए पैरामीटर पहचान परीक्षण (पीआईडी) भी पूरे किए गए थे।



वायु वाहित पूर्व चेतावनी और नियंत्रण (ईडब्ल्यू एंड सी) प्रणाली: ईडब्ल्यू एंड सी प्रणाली में विमान और समुद्री सतह के लक्ष्य के बारे में हवा और जमीन के स्टेशनों को चेतावनी प्रदान करने और शत्रुतापूर्ण उत्सर्जन को खोजने और उपलब्ध कराने के लिए एक विमान पर लगे सेंसर शामिल होते हैं। वर्ष के दौरान, 487 घंटे और 20 मिनट की कुल अवधि में 230 मिशनों के लिए उड़ानें भरी गई थी। 14 फरवरी, 2017 को ईडब्ल्यू एंड सी विमान रु1135 आईओसी विन्यास में भारतीय वायु सेना द्वारा स्वीकार किया गया और 20 अप्रैल, 2017 से प्रभाव सहित परिचालन दोहन के लिए भारतीय वायु सेना के भटिंडा बेस में तैनात किया गया। ईडब्ल्यू एंड सी विमान ने 2017 में गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार उड़ान भरी और आगरा में अकरामन अभ्यास में भाग लिया।



मध्यम ऊँचाई लंबी सहनशीलता (एमएएलई) मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) 'रुस्तम-II': तीनों सशस्त्र बलों के लिए खुफिया कार्य, निगरानी और पुनर्निर्माण (आईएसआर) भूमिकाओं को पूरा करने के लिए 24 घंटे की सहनशीलता के साथ एक

बहु-मिशन मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) विकसित किया जा रहा है। अब तक, सात एयरफ्रेम (एएफएस) साकार हो गये हैं और स्वदेश में विकसित डेटाबैंक प्रणाली के साथ वैमानिकी परीक्षण रेंज (एटीआर), चित्रदुर्ग से रूस्तम-द्वितीय की नौ डिजाइन सत्यापन (वर्ष 2017 में आठ सहित) उड़ानें (डीवीएफ) पूरी की गई हैं। चित्रदुर्ग, कर्नाटक में एटीआर को 2 किमी के रनवे के साथ चालू किया गया है और यह श्रृंखला 28 मई 2017 को रक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थी।



नियंत्रित हवाई वितरण प्रणाली (सीएडीएस): एयरड्रॉप टेक्नोलॉजी में विशिष्ट मिलन बिंदुओं पर पेलोड की तेजी से तैनाती के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता है। अगस्त 2017 के दौरान, एक सीएडीएस-1 टी 19 सेल रैम एयर पैराशूट फंक्शन मैनुअल/ऑटो कंट्रोल मोड परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

लघु टर्बो फैन इंजन: डीआरडीओ देशी छोटे टर्बो फैन इंजन (एसटीएफई) के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास में शामिल है। विकास परीक्षण के लिए 5 इंजन सेट और निर्भय एकीकरण के लिए मैट्स बीएटीएल द्वारा 3 इंजन सेट विकसित करने का प्रस्ताव है। तीन प्रोटोटाइप (टी1, टी2 और टी3) तैयार किए गए हैं। टी1 इंजन के साथ उप-प्रणालियों/एलआरयू के समेकित प्रदर्शन को मान्य किया गया है। टी3 इंजन को इंजन के साथ स्थापित ईंधन एकीकृत प्रणाली (एफआईएस) से संयोजित किया गया और 90% तक एनएच स्पीड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

शामिल की गई मिसाइलों का उपयोगकर्ता परीक्षण: वर्ष के दौरान उपयोगकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित का परीक्षण किया गया—अग्नि -2 मिसाइल - 4 मई 2017, अग्नि -3 मिसाइल - 27 अप्रैल, 2017, अग्नि -4 मिसाइल - 2 जनवरी, 2017 और पृथ्वी -2 मिसाइल - 2 जून, 2017।

सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस': ब्रह्मोस एक दो चरण युक्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसमें पहले चरण में एक ठोस प्रणोदक बूस्टर और दूसरे चरण में तरल रैमजेट होता है। मिसाइल लक्ष्य के रास्ते पर विभिन्न उड़ानों को अपनाती हुई 'फायर करो और भूल जाओ' के सिद्धांत पर काम करती है। ब्रह्मोस में पूरी उड़ान के दौरान सुपरसोनिक गति से 290 किमी तक की उड़ान सीमा होती है और वह 300 किलो तक के पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। 11 मार्च, 2017 को, आईटीआर चंडीपुर से एक विस्तृत श्रेणी के साथ 'ब्रह्मोस' का एक उन्नत संस्करण फायर किया गया। 22 नवंबर, 2017 को पहली बार एक एसयू-30 एमकेआई विमान से भी ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया था।



बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (कार्यक्रम एडी): डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों का बचाव करने के लिए दो स्तर युक्त बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (बीएमडी) कार्यक्रम का विकास किया है। 2017 में दो अवरोधन परीक्षणों के माध्यम से बीएमडी प्रणाली के सफल प्रदर्शन आयोजित किया गया। 11 फरवरी, 2017 को 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक एकसो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर, पृथ्वी वायु रक्षा (पीडीवी) द्वारा उच्च ऊंचाई पर अवरोधन का प्रदर्शन किया गया था और 1 मार्च 2017 एवं दिसंबर 28, 2017 को उन्नत वायु रक्षा (एएडी) मिसाइल का उपयोग कर एंडो-वायुमंडलीय अवरोधन किया गया था, इस प्रकार ऑपरेशन परिदृश्य में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली के सभी तत्वों को मान्य किया गया है।

दृश्य सीमा से परे एयर-टू-एयर मिसाइल (बीवीआरएएएम) 'अस्त्र': अत्यधिक कलाबाजी दिखाने वाले सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को नियंत्रित और नष्ट करने के लिए डीआरडीओ द्वारा बीवीआरएएएम 'अस्त्र' (60 किमी) को अत्यधिक विश्वसनीय बनाने के लिए उच्च एकल शॉट मार क्षमता विकसित की जा रही है।

वर्ष के दौरान, सितंबर 2017 में एसयू-30 एमकेआई विमान से सात अख्र मिसाइलों को सफलतापूर्वक चलाया गया था, जिसमें सुपरसोनिक वायु प्रक्षेपण, युद्ध प्रक्षेपण और बंशी पीटी, विनाश, स्वदेशी कू-बैंड आरएफ खोजक मूल्यांकन और बहु-लक्षित लांच परिवृश्य प्रमाणित हुआ था।



निर्भय सब-सोनिक क्रूज मिसाइल: निर्भय भारत की स्वदेश में डिजाइन की गई पहली और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसमें 1000 किमी की सीमा होती है और यह 300 किलो तक हथियार ले जाने में सक्षम है। प्रणाली में प्राथमिक नेविगेशन के रूप में रिंग लेजर जाइरोस्कोप (आरएलजी) आधारित इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली और माइक्रो इलेक्ट्रो-मैकेनिकल प्रणाली (एमईएमएस) आधारित माध्यमिक नेविगेशन प्रणाली शामिल है। परीक्षण 7 नवंबर, 2017 को ओडिशा तट पर आईटीआर, चांदीपुर में एक परीक्षण रेंज से मिसाइल का एक सफल उड़ान परीक्षण किया गया था।



लंबी दूरी की जमीन-से-वायु मिसाइल (एलआरएसएएम):

एलआरएसएएम में 70 किमी की दूरी की क्षमता है, यह भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ और इज़रायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज

(आईएआई), इज़राइल का एक संयुक्त विकास कार्यक्रम है। मिसाइलों का उद्देश्य भारतीय नौसेना के तीन पी15 वर्ग विध्वंसकों को तैयार करना है। वर्ष के दौरान, मई 2017 में 'आईएनएस कोच्चि' से एक ऑपरेशनल फ्लाइंग टेस्ट (ओएफआर) आयोजित किया गया था जिसमें ऑपरेशन के केंद्रीकृत मोड में एक समुद्र स्कीमिंग मिसाइल के अवरोध को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया। वर्ष 2017 में डीआरडीओ द्वारा पांच आरआरएसएएम मिसाइलों का पहला बैच भारतीय नौसेना को सौंपा गया।

तीसरी पीढ़ी की हेलीकाप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 'हैलीना': हैलीना उन्नत लाइट हेलीकाप्टर (एएलएच-डब्ल्यूएसआई) पर एकीकरण के लिए इमेजिंग इन्फ्रा-रेड (आईआईआर) के साथ 7 किमी लॉक-ऑन-बिफोर-लॉन्च (लोबेल) रेंज की क्षमता वाली तीसरी पीढ़ी की हेलीकाप्टर से छोड़ी जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। हैलीना की हथियार प्रणाली में चार लांचर, आठ मिसाइल और एक आग नियंत्रण प्रणाली शामिल हैं। अप्रैल 2017 में, बेंगलूर में कैप्टिव फ्लाइंग ट्रायल (सीएफटी) आयोजित किया गया था जिसमें हैलीना के लिए योजना को लक्षित करने में सफलता प्राप्त की गई थी। हैलीना ने मई 2017 के दौरान एचएएल बेंगलुरु से आईएएफ हेलीकॉप्टर में धावा मारने की उड़ान भरी थी, जिसमें लांच नियंत्रण प्रणाली की लक्ष्य से निपटने की क्षमता को प्रमाणित किया गया था। सितंबर 2017 में, राजस्थान में निर्देशित भूमि उड़ान परीक्षण में आईआईआर फील्ड ऑफ व्यू (एफओवी) खोजी के प्रत्यक्ष ड्राइव प्रदर्शन को प्रमाणित और सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया। अक्टूबर और नवंबर 2017 के दौरान एचएएल बेंगलूर और चेन्नई में आईएएफ के लिए टैंक के खिलाफ बेहतर आईआईआर एफओवी खोजी के रेंज का आकलन किया गया था।



एंटी टैंक मिसाइल 'प्रॉस्पिना': 'नाग' तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक मिसाइल (एटीएम) है जिसमें 'फायर एंड फॉरगेट' और 'टॉप अटैक' क्षमताएं हैं, जिनका इस्तेमाल दिन-रात में कभी भी किया जा सकता है। इसे 'नमिका' नामक एक विशेष रूप से संशोधित इन्फैंट्री कमान वाहन (आईसीवी) बीएमपी-2 वाहन पर तैनात किया गया है। मार्च 2017 में अधिकतम सीमा (4 किमी) पर 1.5⁰ एफओवी आईआईआर खोजक का प्रयोगशाला परीक्षण और मूल्यांकन किया गया था। मई/जून 2017 के दौरान उच्च संकल्प आईआईआर खोजी के ट्रैकिंग परीक्षण किए गए थे जिसमें आईआईआर खोजी की अधिकतम सीमा क्षमता स्थापित की गई थी। जून 2017 में पीएफएफआर, पोखरण में नाग का खोजी मूल्यांकन परीक्षण और उड़ान परीक्षण किया गया था। सितंबर 2017 में न्यूनतम सीमा अर्थात् 500 मी. स्थिर लक्ष्य उड़ान परीक्षण और गतिशील लक्ष्य का 2.5 किमी उड़ान परीक्षण किया गया था और अक्टूबर 2017 के दौरान मुआला बांध, अहमदनगर में एनएएमआईसी, फ्लोटेशन परीक्षण किये गए थे।



त्वरित प्रतिक्रिया सतह-से-वायु मिसाइल (क्यूआरएसएएम): क्यूआरएसएएम हथियार प्रणाली क्षेत्र के वायु रक्षा क्षेत्र के लिए दो वाहन विन्यास के साथ लगभग 30 किलोमीटर की सीमाओं पर कई लक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए, चलते समय खोज करने, नज़र रखने और छोटे अंतरालों पर फायर करने में सक्षम है। वर्ष के दौरान, आईटीआर चांदीपुर से नकली लक्ष्य के खिलाफ मिसाइल के दो विकास उड़ान परीक्षण किए गए।



नई पीढ़ी की रेडिएशन-विरोधी मिसाइल (एनजीएआरएम): डीआरडीओ 100 किमी की दूरी वाली एनजीएआरएम के डिजाइन और विकास में कार्यरत है। उपयुक्त संशोधन के बाद एकेयू-58 लांचर का उपयोग एसयू-30 एमकेआई विमान पर मिसाइल एकीकरण के लिए किया जाएगा। वर्ष के दौरान, एएफ स्टेशन, पुणे में एसयू-30 एमकेआई विमानों के साथ, मिसाइल के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर एकीकरण का प्रदर्शन करने वाले कैप्टिव फ्लाइंग ट्रायल (सीएफटी-2) किए गए। दो निष्क्रिय होमिंग हेड सीकर प्राप्त कर लिए गए हैं और रेडोम के साथ खोजी का प्रयोगशाला परीक्षण मूल्यांकन पूरा हो चुका है। इसके अलावा, दोहरी पल्स रॉकेट मोटर की एकीकृत स्थैतिक फायरिंग को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है।

स्टैंड-ऑफ एंटी-टैंक (एसएएनटी) गाइडेड मिसाइल: डीआरडीओ स्टैंड-ऑफ एंटी टैंक (एसएएनटी) गाइडेड मिसाइल के डिजाइन, विकास और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन में शामिल है। मार्च 2017 के दौरान, 3 बीआरडी, चंडीगढ़ में एमआई-35 हेलीकॉप्टर से इंस्ट्रूमेंटेशन और ट्रांसफर संरेखण परीक्षण किए गए, जिनमें कुल 8 उड़ानें भरी गई थीं और पूरे हेलीकॉप्टर संकुल को कवर किया गया था। जुलाई 2017 में 3बीआरडी, चंडीगढ़ में परिष्कृत और उन्नत टी, एल्गोरिथम पर एक संयुक्त कैप्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन और ट्रांसफर संरेखण परीक्षण भी किया गया, जिसमें चार हेलीकॉप्टर उड़ानों का आयोजन किया गया था और सभी उड़ानों में विभिन्न स्थानों पर एसएएनटी हथियार प्रणाली के कंपन डेटा को मापा गया था। एसएएनटी हार्डवेयर के पूरे सेट में 2 उड़ानों के लिए तैयारी के साथ एसएएनटी मिसाइलों को साकार किया गया है और सॉफ्ट का काम पूरा हो गया है।

स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वीपन (एसएएडब्ल्यू): लंबी दूरी, स्टैंड-ऑफ, हवा से सतह का सटीक हथियार, एसएएडब्ल्यू (125 किलोग्राम वर्ग) जमीन के लक्ष्य को संयोजित करने में सक्षम है। नवंबर 2017 में जगुआर विमान से विभिन्न उड़ान परिस्थितियों में तीन रिलीज परीक्षणों को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

आकाश एमके-1 एस सर्फेस-टू-एयर मिसाइल: आकाश एमके-1एस, स्वदेशी आरएफ खोजी के साथ आकाश मिसाइल का उन्नयन है। 5 दिसंबर, 2017 को बंशी लक्ष्य के खिलाफ आयोजित उड़ान परीक्षण के दौरान, मूल मिसाइल विन्यास के साथ स्वदेशी आरएफ खोजक के एकीकरण को प्रमाणित किया गया।

कु-बैंड सक्रिय राडार साधक (कु-बैंड एआरएस): डीआरडीओ ने उत्पादन के लिए स्वदेशी कु-बैंड खोजियों का विकास करने की एक परियोजना शुरू की है। मेसर्स बीईएल की भागीदारी के साथ पांच खोजियों का पहला बैच विकसित किया जा रहा है। इस खेप से दो खोजियों के स्वीकृति परीक्षण (एटी) किए गए हैं और खोजियों में से एक ने, दिसंबर 2017 में आकाश मैक -1एस मिशन में पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण पूरा किया है। पुणे वायुसेना स्टेशन पर एसयू-30 विमान पर अरुण हथियार प्रणाली विन्यास में अलग-अलग उड़ान संबद्ध प्रोफाइल के साथ कैप्टिव फ्लाइंग ट्रायल (सीएफटी) में इस खोजी का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया।

टीबीआरएल रामगढ़ रेंज में इंस्ट्रूमेंट और मैकेनाइज्ड ड्राप टेस्ट सुविधा (आईएमडीटीएफ): 12.15 मीटर ऊँचाई से प्रणाली को हथियारों पर गिराने के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए टीबीआरएल में आईएमडीटीएफ स्थापित किया गया है। नाटो मानक के अनुसार आईएम अनुपालन (एसटीएएनएजी) के लिए, योग्यता प्रमाणन हेतु गोला-बारूद प्रणाली पर 8 परीक्षणों की आवश्यकता होती है और डीआरडीओ ने पहले ही इन 8 परीक्षणों को पूरा कर इसकी क्षमता को स्थापित किया है।

एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन प्रणाली (एटीएजीएस): डीआरडीओ ने भारतीय सेना की आर्टिलरी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च श्रेणी, सटीकता और स्थिरता युक्त 155 मिमी X 52 कैलिबर एटीएजीएस की डिजाइन और विकास का

कार्यभार संभाला है। वर्ष के दौरान, 6 सितंबर, 2017 को, दो बंदूक प्रणालियों के लिए डीआरडीओ तकनीकी परीक्षण पूरा किया गया, जिसमें विस्तारित रेंज पूर्ण बोर (बोट टेल) और (बेस ब्लीड) गोला-बारूद द्वारा प्राप्त अधिकतम सीमा पीएसक्यूआर के वांछित मानकों से अधिक अर्थात् क्रमशः 38 किमी और 48 किमी रही। 4 जनवरी 2017 को डीजी आर्टी के समक्ष और 23 सितंबर 2017 को रक्षामंत्री के समक्ष दोनों बंदूक प्रणालियों की फायरिंग का प्रदर्शन किया गया।



गाइडेड पिनाक रॉकेट प्रणाली: डीआरडीओ ने मार्गदर्शन, नेविगेशन और नियंत्रण (जीएनसी) किट को मौजूदा पिनाक एमके-द्वितीय रॉकेट्स से एकीकृत करके निर्देशित पिनाक रॉकेट प्रणाली विकसित की है, इस प्रकार स्वतंत्र उड़ान पिनाक रॉकेट को एक निर्देशित पिनाक बना दिया गया है। अपेक्षित डिजाइन, विश्लेषण, हार्डवेयर प्राप्ति, परीक्षण आदि केवल एक वर्ष के कम समय में पूरे किए गए थे। जनवरी, 2017 में, आईटीआर बालासोर में, दो चरणों में 75 किलोमीटर की दूरी तक 'गाइडेड पिनाक' रॉकेट का परीक्षण आयोजित किए गए। परीक्षण के दौरान निर्देशित पिनाक रॉकेट का विन्यास और प्रणाली की कार्यक्षमता प्रमाणित हुई थी।



युद्ध सामग्री का नया परिवार (एनएफएम) : डीआरडीओ द्वारा लड़ाई के वर्तमान सामान सुधारने के लिए और इसके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए छह प्रकार के हथियार अर्थात् सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्युनिशन 'निपुण', एंटी टैंक प्वायंट अटैक म्युनिशन 'विभव', एंटी टैंक बार म्युनिशन 'विशाल', डायरेक्शन फ्रेगमेंटेशन म्युनिशन 'पार्थ', एंटी टैंक म्युनिशन 'प्रचंड' और जंपिंग फ्रेगमेंटेशन म्युनिशन 'यूएलकेए' को विकसित किया और बनाया जा रहा है। वर्ष के दौरान विभव और विशाल के लिए पीएसक्यूआर आधारित उपयोगकर्ता परीक्षणों को पूरा किया गया। प्रचंड के 50 प्रोटोटाइप के पहले बैच पर उप-प्रणाली/मॉड्यूल स्तर कार्यात्मक परीक्षण और सभी पर्यावरणीय परीक्षणों (नमूना आधार पर) को संतोषजनक ढंग से पूरा किया गया। उल्का युद्ध सामग्री के लिए मार तंत्र के साथ अंतिम एकीकरण परीक्षण के पूरा होने के साथ-साथ 10 सेटों पर कार्यात्मक परीक्षण और छह सेटों पर थर्मल परिचक्र परीक्षण भी पूरा किया गया। युद्ध सामग्री निपुण के लिए निजी उद्योगों के टीओटी की पहचान की गई।

155 मिमी आर्टिलरी गन की द्वि-मॉड्यूलर चार्ज प्रणाली (बीएमसीएस): उच्च ऊंचाई क्षेत्र में संचालन के लिए डीआरडीओ ने 155 मिमी तोपखाना बंदूक के लिए बीएमसीएस के विकास में एक सक्रिय कदम उठाया है। वर्ष के दौरान, जुलाई 2017 में, बीएमसीएस के साथ 52 सीएल बंदूक (निश्चित स्थापना) से गतिशील फायरिंग की गई थी।

कैनोपी विच्छेद प्रणाली (सीएसएस): सीएसएस को 15 तेजस

विमानों, 12 एचजेटी-36 विमानों, दो एलसी, ट्रेनर विमानों और नौसेना संस्करण तेजस और ट्रेनर विमानों और पहले एचटीटी-40 विमानों पर एकीकृत किया गया है। सभी विमान सीएसएस के साथ परीक्षण उड़ान से गुजर रहे हैं। वर्ष के दौरान, डीआरडीओ ने प्रमुख उत्पादन एजेंसियों के रूप में चिह्नित निजी उद्योगों के लिए कैनोपी विच्छेदन तंत्र के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के लिए एआरडीई में 20 जनवरी 2017 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

अर्जुन बख्तरबंद पुनर्प्राप्ति और मरम्मत वाहन (अर्जुन एआरआरवी): एआरआरवी का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थितियों की एक विस्तृत विविधता के अंतर्गत संचालन के क्षेत्र में एमबीटी अर्जुन से संबंधित कार्यों की पुनर्प्राप्ति, मरम्मत और पुनःपूर्ति करना है। सभी प्रमुख वसूली और मरम्मत समुच्चयों को विकसित और प्राप्त किया गया है। वर्ष के दौरान, अक्टूबर 2017 में अर्जुन एआरआरवी का पहला प्रोटोटाइप रक्षामंत्री के सीवीआरडीई के दौरे के दौरान विकास साझेदार, मैसर्स बीईएमएल से सीवीआरडीई को सौंप दिया गया। उपयोगकर्ता सहायता प्राप्त तकनीकी परीक्षण (यूएटीटी) प्रगति पर है।

इलेक्ट्रिक गन और बुर्ज ड्राइव प्रणाली (एलीगेंट): डीआरडीओ बख्तरबंद वाहनों (एएफवीएस) के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ एक बंदूक नियंत्रण प्रणाली की डिजाइन और विकास कर रहा है। परियोजना में प्रायोगिक उत्पादन/उत्पादन संदर्भ के लिए दो सहित कुल सात प्रोटोटाइप विकसित किए जाने हैं। वर्ष के दौरान, एकीकृत बुर्ज परीक्षण के गतिशील परीक्षण रिग के लिए विन्यास को अंतिम रूप दिया गया था। स्टेप-अप कनवर्टर का बैच परीक्षण पूरा किया गया। सीएन आधारित जायरो ईएलओआईआर, द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया था और प्रदर्शन परीक्षण चल रहा है।

कंपोजिट सोनार डोम: डीआरडीओ ने पी15, श्रेणी जहाज के लिए पहला स्वदेशी समग्र सोनार गुंबद विकसित किया है। इस विकास से, भारत बहुसंख्यक आवश्यकताओं, जटिल ज्यामिति और ध्वनिक पारदर्शिता के साथ उच्च संरचनात्मक कठोरता युक्त बड़ी समग्र संरचना को साकार करने की क्षमता वाले चयनित राष्ट्रों के समूह में शामिल हो गया है। वर्ष के दौरान, समग्र सोनार गुंबद को आईएनएस कोलकाता और आईएनएस चेन्नई में स्थापित किया गया और समुद्री परीक्षणों का आयोजन किया गया।



पहिएदार कवच प्लेटफार्म (डब्ल्यूएपएपी): डब्ल्यूएपएपी विविध युद्ध और 26 टन जीवीडब्ल्यू तक युद्ध समर्थन भूमिकाओं के लिए मॉड्यूलर डिजाइन के साथ एक विन्यास योग्य बहु उपयोगिता बख्तरबंद मंच है। वर्ष के दौरान, मई 2017 में एपी-2 की इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का कार्यात्मक परीक्षण आयोजित किया गया था और जून 2017 के दौरान मुला बांध, अहमदनगर में तैराकी क्षमता के परीक्षणों का आयोजन किया गया था।



बार माइन परत (बीएमएल): इस प्रणाली का उपयोग तटीय टैंक-विरोधी सुरंगों को गाड़ कर जल्दी से सुरंग क्षेत्र बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रणाली में करीब 500 बार सुरंगें आ सकती हैं और उन्हें 6 मीटर से 30 मीटर के अंतराल पर रखा जा सकता है। वर्ष 2016 में सूरतगढ़ में डीआरडीओ द्वारा आंतरिक परीक्षण आयोजित किए गए थे। ग्रीष्मकालीन चरण उपयोगकर्ता परीक्षण जुलाई 2017 में पूरे किए गए।

एडवांस लाइट टोड एरे सोनार (एएलटीएस): एएलटीएस विशेष रूप से महासागर की सतह के नीचे की परतों में चलने वाली पनडुब्बियों का पता लगाने, स्थानीयकरण और वर्गीकरण के लिए एक कुशल संवेदन प्रणाली है। यह पनडुब्बी-विरोधी युद्ध

अभियानों में उपयोगी है और युद्धपोतों के लिए उच्च गति टॉपेडो लॉन्च करने में सक्षम मूक पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए उपयुक्त सेंसर है। वर्ष के दौरान, तकनीकी परीक्षण पूरे हो गए और सोनार के सक्रिय और निष्क्रिय कार्यों को सत्यापित करने के लिए 20-21 अक्टूबर, 2017 के दौरान पहला उपयोगकर्ता एसोसिएटेड परीक्षण (यूएटी-01) को आयोजित किया गया।



यूएसएचयूएस-2: यूएसएचयूएस-2 एक पनडुब्बी सोनार है, जिसे पनडुब्बी की लंबी अवधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो चार ईकेएम पनडुब्बियों पर स्थापित किया गया है और इन पनडुब्बियों पर स्थित मौजूदा रूसी सोनारों के अप्रचलित घटकों का मुकाबला करता है। यूएसएचयूएस-2 के तैयार मॉडल की डिजाइन और विकास एनपीओएल में किया जा रहा है और मैसर्स बीईएल, बेंगलूर में इनका उत्पादन किया जाता है। जनवरी 2017 में मैसर्स बीईएल, बेंगलूर में पहली प्रणाली का फैक्टरी स्वीकृति परीक्षण (एफ एटीएस) पूरा हुआ। 24 मार्च, 2017 को यूएसएचयूएस-2 सोनार भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। यूएसएचयूएस-2 प्रणालियों में से पहली प्रणाली, सितंबर 2017 से रूस के सेवरोद्विक्स में पनडुब्बी के मध्यम रिफिट के दौरान आईएनएस सिंधुकेसरी पर स्थापित की गई है। भारतीय नौसेना ने 440 करोड़ रुपये की कुल लागत से पनडुब्बियों पर लगे वर्तमान रूसी सोनारों के प्रतिस्थापन के लिए चार यूएसएचयूएस-2 प्रणालियों का आदेश दिया है।

तटीय सुरक्षा के लिए वायु जनित सोनार (एससीएस): डीआरडीओ एक योग्य कम आवृत्ति डंकिंग सोनार (एलएफडीएस) का विकास कर रही है, जो नौसेना द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाले एएलएच एमके-3 हेलीकाप्टरों के लिए एक हवाई सोनार

प्रणाली है। हेलीकॉप्टर मंच पर स्थापित प्रणाली नौसेना परिचालन परिदृश्यों के लिए हवाई एएसडब्ल्यू क्षमता प्रदान करेगी। प्रमुख प्रणाली इंटीग्रेटर/प्रोडक्शन एजेंसी द्वारा तीन एलएफडीएस प्रणालियां प्रदान की जाएंगी, जिनमें से 1 प्रणाली का उपयोग योग्यता के लिए किया जाएगा, दूसरी प्रणाली इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर डिस्प्ले प्रणाली (आईएडीएस), एएलएच स्थापना, एएफएससी चेक और एडीआर के साथ एकीकरण और एचएएल में शोषण के लिए निर्धारित की जाएगी और तीसरी प्रणाली को एचएएल में स्थापना और परीक्षण के दौरान अतिरिक्त मामलों के लिए प्रस्तुत स्थिति में उपलब्ध रखा जाएगा। वर्ष के दौरान मंच और इंटरफ़ेस नियंत्रण दस्तावेज़ (आईसीडी) के लिए नये केबिन का लेआउट पूरा हो गया है। स्थापना (मैकेनिकल) दस्तावेज़ भी पूरा हो गया है। आरसीएमए को प्रमाणन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ सौंप दिए गए हैं।

हल माउंटेड सोनार श्रृंखलाओं के लिए गियर का निर्देशन: भारतीय और विदेशी जहाजों के लिए आसानी से अनुकूलनीय 4.5 टन तक वजन ट्रांसड्यूसर सारणियों को संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया निर्देशित गियर जिसे सीधे सोनार नियंत्रण से एकीकृत किया जा सकता है, 24 मार्च 2017 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। भारतीय नौसेना ने पहली प्रणाली पी16 ए क्लास जहाज पर स्थापित कर ली है। अब तकए भारतीय नौसेना ने 108 करोड़ रुपए की कुल लागत से पी15, पी15 बी और पी16 ए सहित विभिन्न वर्गों के लिए 9 और प्रणालियों के आदेश जारी किए हैं।

उन्नत हल्के वजन के टारपीडो (एएलडब्ल्यूटी): एएलडब्ल्यूटी जहाज, हेलीकॉप्टर या फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाने वाला एक पनडुब्बी-विरोधी टारपीडो है। एएलडब्ल्यूटी में कम गति (25 समुद्री मील) पर 25 किमी और उच्च गति (50 समुद्री मील) पर 12 किमी की दोहरी गति क्षमता और सहनशीलता है। जनवरी 2017 में तकनीकी परीक्षण किया गया था जिसमें टारपीडो की आसान गोताखोरी को प्रमाणित किया गया था। जुलाई 2017 के दौरान 105 केडब्ल्यू बीएलडीसी मोटर्स का स्वीकृति परीक्षण पूरा हुआ। दो मोटरों परीक्षण किया गया है और उपयोगकर्ता द्वारा एएलडब्ल्यूटी परीक्षणों के लिए मंजूरी दी गई है।



एआईपी के लिए भूमि आधारित प्रोटोटाइप: डीआरडीओ मुख्य प्रणाली समाकलक (एलएसआई) के रूप में मैसर्स एल एंड टी, मुंबई के सहयोग से और अन्य उद्योग साझेदारों अर्थात् मैसर्स थर्मैक्स, पुणे और मैसर्स सीडीएसी, तिरुवनंतपुरम के सहयोग से भारतीय पनडुब्बियों के लिए वायु स्वतंत्र प्रणोदन (एआईपी) प्रणाली के लिए भूमि आधारित प्रोटोटाइप (एलबीपी) के लिए स्वदेशी तकनीकों के विकास में शामिल है। वर्ष के दौरान, एआईपी विकास ने पी -75 पनडुब्बियों के लिए परिभाषा चरण को मंजूरी दी और प्रयोक्ता परीक्षणों में 14 दिन की सहनशीलता हासिल की गई।

जगुआर दरीन तृतीय उन्नत विमान (डी-जेएजी प्रणाली) के लिए आंतरिक रडार चेतावनी जैमर (आरडब्ल्यूजे) प्रणाली: डी-जेएजी एक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्धक (ईडब्ल्यू) प्रणाली है जो रडार चेतावनी और जैमिंग के लिए है जिसमें रडार चेतावनी रिसीवर (आरडब्ल्यूआर) और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर उपाय (ईसीएम) के कार्य शामिल हैं। यह प्रणाली लक्ष्य अधिग्रहण, ट्रैकिंग और मिसाइल मार्गदर्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले हवाई, जहाज-जनित और जमीन-आधारित रडारों का अवरोधन और पहचान करती है। वर्ष के दौरान, जेएस -163 विमानों पर शीतलन प्रणाली को विमान में लगाने के परीक्षण पूरे किए गए थे। सीईडब्ल्यू (एलपीआरएफ और एचपीआरएफ) के ईएमआई/ईएमसी परीक्षण भी जून 2017 में पूरे कर लिए गए थे।

मिग-29 उन्नत विमान (डी-29 प्रणाली) के लिए आंतरिक ईडब्ल्यू प्रणाली: डी-29 चेतावनी और जैमिंग के लिए एक एकीकृत ईडब्ल्यू प्रणाली है जिसमें आरडब्ल्यूआर, ईसीएम, और ईएसएम कार्य शामिल हैं और चुनिंदा खतरे वाले रडारों को चुनने के लिए यह अत्याधुनिक सक्रिय चरणबद्ध सारणियों का

इस्तेमाल करती है। वर्ष के दौरान, एकाधिक एमीटर परीक्षण किए गए।

डिजिटल रडार चेतावनी रिसीवर (डी आर 118): डीआर118 डिजिटल रडार चेतावनी रिसीवर एसयू-30 एमकेआई के लिए एक अत्याधुनिक, छह चैनल डिजिटल रडार चेतावनी रिसीवर है। यह एक हवाई, सामरिक ईडब्ल्यू प्रणाली है जो परिदृश्य में उपस्थित जमीन-आधारित, हवाई या जहाज के उत्सर्जकों के बारे में पायलट को स्थिति के बारे में सतर्क करने का कार्य करता है। वर्ष के दौरान, पूर्व स्वीकृत एटीपी के अनुसार चरण-1 का उपयोगकर्ता मूल्यांकन मई 2017 में आयोजित किया गया था। द्वितीय चरण उपयोगकर्ता मूल्यांकन चल रहा है।

सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो (एसडीआर): डीआरडीओ, विकास भागीदारों के रूप में सीडीएसी और डब्ल्यूईएसईई के साथ और उत्पादन सहयोगी के रूप में बीईएल के साथ गतिशील और स्थिर बल दोनों के लिए भारतीय नौसेना की आवश्यकता के अनुसार वायरलेस सुरक्षित संचार क्षमता प्रदान करने के लिए नवल कॉम्बैट (एसडीआर-एनसी), टैक्टिकल (एसडीआर-टीएसी), एयरबोर्न (एसडीआर-एआर), मैनपैक (एसडीआर-एमपी) और हाथ में पकड़ने योग्य (एसडीआर-एचएच) नेटवर्क-सक्षम, इंटरऑपरेबल और मॉड्यूलर एसडीआर जैसे परिवार के विकास के लिए काम कर रहा है। वर्ष के दौरान, आईएनएस 'तरकश' और आईएनएस 'गंगा' पर एसडीआर-एनसी का यूईटी (समुद्री परीक्षण) पूरा हो गया। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने आईडीडीएम श्रेणी के अंतर्गत उत्पादन एजेंसी को ऑर्डर देने के लिए मंजूरी दे दी है। एसडीआर-टीएसी, एसडीआर-एमपी और एसडीआर-एआर के डेवलपर समुद्री परीक्षण भी पूरे किए गए थे।

एस-बैंड हब और ग्राउंड सैटकॉम टर्मिनलों के लिए त्रि-सेवाएं: डीआरडीओ ने उत्पादन साझेदार के रूप में बीईएल के माध्यम से चार प्रकार के सैटेलाइट टर्मिनल हार्डवेयर अर्थात् मैनपाकसैटकॉम टर्मिनल (एमएसटी), सैटकॉम मैसेजिंग टर्मिनल (एसएमटी), हैंडहेल्ड सैटकॉम टर्मिनल (एचएसटी) और सैटकॉम द हॉल टर्मिनल (एसओटीएम) को पूरा किया है। वर्ष के दौरान किए गए कुछ प्रमुख परीक्षणों में निम्नलिखित शामिल हैं: क) जनवरी 2017 के दौरान भारतीय सेना के खुफिया निदेशालय के साथ भुज में एमएसटी परीक्षण किया गया था। ख) अप्रैल 2017 के दौरान एचएसटी के प्रयोक्ता परीक्षण ग) सितंबर 2017 में त्रिवेंद्रम

और जम्मू और कश्मीर में एमएचए टीम द्वारा एमएसटी, एचएसटी और एसएमटी के परीक्षण, घ) अक्टूबर, 2017 में एमएच, टीम द्वारा एमएसटी, एचएसटी और एसएमटी के पुष्टि परीक्षण भी किए गए थे।

डिजिटल ट्रोपो स्कैटर/ भारतीय वायु सेना के लिए एलओएस संचार प्रणाली: ट्रोपो बिखराव संचार प्रणाली काफी दूरी से माइक्रोवेव रेडियो संकेतों को संदेश देती है। अक्टूबर 2017 के दौरान एडीआरडीओ द्वारा विकसित एलओपी बैंड ओडीडीएम ट्रोपो मोडेम का इस्तेमाल करते हुए जयपुर और जोधपुर के बीच ट्रोपो स्कैटर कम्युनिकेशन लिंक की स्थापना की गई। लिंक प्रदर्शन परीक्षण आयोजित किए गए थे और परिणाम वांछित विनिर्देश के अनुसार थे।

भारतीय नौसेना के प्रमुख जहाजों, विमानों और हेलीकाप्टरों के लिए ईडब्ल्यू प्रणाली 'समुद्रिका': डीआरडीओ ने सात ईडब्ल्यू प्रणालियों के एक परिवार के विकास का कार्यभार ग्रहण किया है जिसमें तीन जहाज-जनित प्रणाली (शक्ति, नयन और तुषार) और चार हवाई प्रणालियां (सर्वधरी, सारंग, सारक्षी और निकाश) शामिल हैं। उपर्युक्त सभी उत्पादों का डिजाइन पूरा हो चुका है और हार्डवेयर प्राप्ति करने का काम चल रहा है। मैसर्स बीईएल ईडब्ल्यू प्रणाली के उत्पादन के लिए प्रमुख उत्पादन एजेंसी होगा। वर्ष के दौरान, फरवरी 2017 में 'नयन' कर्मित प्रणाली के सागर स्वीकृति परीक्षण (एसएटी) पूरे हुए, जिसके बाद अप्रैल 2017 में यूएटी चरण-1 और अक्टूबर 2017 में यूएटी चरण-2 पूरा किया गया। मार्च-2017 के दौरान उपयोगकर्ता के लिए 'शक्ति' ईडब्ल्यू सुइट के चरण-द्वितीय प्रयोगशाला प्रदर्शन भी पूरा किया गया।

भारतीय नौसेना के लिए 'वरुण' ईएसएम प्रणाली: 'वरुण' एक आधुनिक ईएसएम प्रणाली है जो स्पंदित, निरंतर तरंग (सीडब्ल्यू), नाडी पुनरावृत्ति आवृत्ति (पीआरएफ) चंचलता, आवृत्ति चपल रडारों के अवरोधन, पहचान, वर्गीकरण और पहचान करने में सक्षम है, जिसमें आवृत्ति बैंड पर अवरोधक (एलपीआई) रडार की कम संभावना शामिल है। मार्च-2017 के दौरान आईएनएस किरण के जहाज पर द्वितीय 'वरुण' उत्पादन प्रणाली का बंदरगाह स्वीकृति परीक्षण पूरा हुआ। आईएनएस किर्च और आईएनएस कृपाण के जहाज पर स्थापित पहली और दूसरी 'वरुण' उत्पादन प्रणालियों के सागर स्वीकार्यता परीक्षण (एसएटी) अप्रैल 2017

में पूरे हुए थे। उत्पादन एजेंसी द्वारा नौसेना के लिए उत्पादन प्रणालियों का अनुसूचित वितरण चल रहा है।

भारतीय वायु सेना के लिए परियोजना हिमराज: इस परियोजना का उद्देश्य आईएफ द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि आधारित ईएलआइएनटी मोबाइल स्टेशन को डिजाइन और विकसित करना है। जीबीएमई प्रणाली के 6 नग के लिए उत्पादन का आदेश मैसर्स बीईएल (एच) के निष्पादन के अधीन है। जून 2017 के दौरान सीएस के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज के पूरा होने के साथ नियंत्रण स्टेशन (सीएस) के साथ कोमिट का अंतिम एकीकरण पूरा हुआ। सितंबर 2017 के दौरान जीबीएमईएस प्रणाली के पहले उत्पादन का फैक्ट्री स्वीकृति परीक्षण (एफएटी) आयोजित किया गया था। एटीपी के अंतर्गत जीबीएमईएस (हिमराज) का एफओपीएम भी पूरा हो चुका है।

सेना के लिए सीमा निगरानी प्रणाली (बीओएसएस): डीआरडीओ ने घुसपैठ का पता लगाने के लिए सैनिकों की गश्त को कम करने और सीमावर्ती क्षेत्रों की दिन/रात निगरानी के लिए थर्मल और डे कैमरे, एलआरएफ, जीपीएस और डीएमसी तथा बीएफएसआर-एक्सआर को मिलाकर ईओ पेलोड का डिजाइन और विकास पूरा किया है। उपयोगकर्ता तैयारी की समीक्षा का चरण-1 अगस्त 2017 में पूरा किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में दो प्रणालियां स्थापित की गई हैं और उपयोगकर्ता दोहन के अंतर्गत हैं।

भारतीय वायु सेना के लिए मध्यम शक्ति रडार (एमपीआर) 'अरुधरा': एमपीआर 'अरुधरा' स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई, देश की पहली पूरी तरह से सक्रिय एपर्चर, घूर्णन, बहुबीम, बहुकार्य सहित तेज गति की चरणबद्ध सारणी रडार है। इसमें कम आरसीएस, उच्च गति और उच्च कलाबाजी वाले लक्ष्यों के पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए एक मोड प्रदान किया गया है। रडार ने सभी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा किया है और उपयोगकर्ता परीक्षण के सभी तीन चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिनमें कोलार, जामनगर और ग्वालियर में 100 घंटे का सहनशीलता परीक्षण भी शामिल है। एमपीआर 'अरुधरा' ने 2017 में गणतंत्र दिवस परेड भाग लिया था।



भारतीय वायु सेना के लिए निम्न स्तर परिवहन योग्य रडार (एलएलएलटी) 'अश्विनी': 'अश्विनी' जमीन आधारित एस बैंड है जो पूर्ण रूप से सक्रिय चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली के घुमावदार ईडब्ल्यू परिचालन वातावरण के अंतर्गत हवाई लक्ष्यों का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए एयर स्पेस निगरानी के लिए घूर्णन करता है। डीआरडीओ मूल्यांकन परीक्षण और कोलार और ग्वालियर में अश्विनी रडार के उपयोगकर्ता परीक्षणों के तीनों चरण पूरे हो गए हैं, जिनमें रखरखाव मूल्यांकन परीक्षण भी शामिल हैं। एलएलटीआर 'अश्विनी' को गणतंत्र दिवस परेड 2018 में भागीदारी के लिए चुना गया है।



सेना आर्टिलरी के लिए हथियार का पता लगाने वाला रडार (डब्ल्यूएलआर) 'स्वाति': 'स्वाति' अपने कवरेज के प्रभावी क्षेत्र के भीतर, दुश्मन के सभी हथियारों का सटीक और सही स्थान प्रदान करता है और साथ ही विभिन्न स्थानों पर विभिन्न हथियारों

से किए गए फायर का भी पता लगाता है। डीआरडीओ ने 2 मार्च 2017 को स्वदेशी तौर पर विकसित प्रथम बंद उत्पादन मॉडल (एफओपीएम) डब्ल्यूएलआर प्रणाली 'स्वाति' औपचारिक रूप से भारतीय सेना को सौंप दिया। उत्पादन एजेंसी द्वारा सेना को उत्पादन प्रणालियों की अनुसूचित प्रदायगी प्रगति पर है।



सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार (एईएसएआर) 'उत्तम': सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार (एईएसएआर) 'उत्तम' हमारे स्वदेशी लड़ाकू विमानों एलसीए 'तेजस' के लिए एक एयरबोर्न फायर कंट्रोल रडार है। यह एक मल्टी-मोड रडार है जिसे अलग-अलग हवाई प्लेटफॉर्मों पर लगाने के लिए विन्यासित किया जा सकता है। एक प्रोटोटाइप रडार और एक पूर्णतः योग्य रडार विकसित और तैयार किया गया है। सीएबीएस, बंगलोर में एलआरडीई और प्रणाली परीक्षण तथा एकीकरण रिग (एसटीआईआर) में रडार परीक्षण मंच पर दोनों प्रणालियों का एकीकरण और व्यापक आधार मूल्यांकन किया गया है। योग्य रडार नोज काँ पर स्थापित तेजस एलएसपी -2 विमान को संशोधित करने के लिए तैयार है।

प्रोटोटाइप निर्देशित ऊर्जा लेजर प्रणाली: प्रोटोटाइप 10 केडब्ल्यू डायरेक्ट एनर्जी लेजर प्रणाली को हवाई और नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने और यूएवी जैसे हवाई लक्ष्य के लिए विकसित किया गया है। प्रणाली को ट्रेलर पर एकीकृत किया गया है और लक्षित अधिग्रहण, ट्रैकिंग और रोपवे को स्थानांतरित करने और सीईएस साइट पर 700 एम की सीमा तक हवाई लक्ष्यों की कार्यात्मक रूप से जांच के लिए कार्यात्मक परीक्षण किया गया है। पूर्व-परीक्षण तत्परता की समीक्षा पूरी हो चुकी है। 2 किलोवाट डीएलएस स्थापित वाहन को 4x4 टाटा वाहन पर तैयार किया गया है और एटीआर चित्रदुर्ग में एक किलोमीटर तक की दूरी पर

परीक्षित किया गया है।

एएनयू राउटर: परियोजना का उद्देश्य वाणिज्यिक मल्टीकोर प्रोसेसर टाइल जीएक्स 36 और स्वदेशी अवधानी प्रोसेसर का उपयोग करके स्वदेशी रूटर का डिजाइन और विकास करना है। वर्ष के दौरान, पीडीआर समिति ने प्रारंभिक डिजाइन की समीक्षा की और उसे अनुमोदित किया। मैसर्स सी-डीओटी के साथ गहन हार्डवेयर प्लेटफॉर्म का विकास किया जा रहा है।

नई ऑपरेटिंग प्रणाली (एएनयूओएस): इस परियोजना के दायरे में मौजूदा वाणिज्यिक और खुले स्रोत की ऑपरेटिंग प्रणाली और स्वदेशी भरोसेमंद ओएस कर्नेल की डिजाइन और प्रोटोटाइप को दृढ़ कर ना शामिल है। वर्ष के दौरान, आरएचईएल 6.2 पर आधारित कठोर बनाए गए अनुराग लिनक्स (एएचएल) v3 को युद्ध प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) के साथ एकीकृत किया गया और वेडब्ल्यूईएसईई में प्रदायगी की गई। सीएबीएस की वैमानिकी प्रणाली के लिए एएसएल और एएचएल समाधान आधारित एसयूएसई 11.3 के लॉन्च कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए आरएचईएल 5.4 पर आधारित एएचएल समाधान विकसित किया गया है।

ईडब्ल्यू पीओडी के लिए सी-एक्स-केयू बैंड माइक्रोवेव पावर मॉड्यूल (एमपीएम): परियोजना में ईडब्ल्यू -पीओडी और उच्च दक्षता के सी-केयू बैंड 100 डब्ल्यू (मिन) सीडब्ल्यू माइक्रो-टीडब्ल्यूटी के लिए सी-केयू बैंड 100 डब्ल्यू (सीडब्ल्यू) कॉम्पैक्ट एमपीएम के साथ चरण और लाभ का डिजाइन और विकास शामिल है। स्वदेशी ट्यूब के साथ एमपीएम का एटीपी सफलता पूर्वक पूरा हुआ। 8 फरवरी, 2017 को आलोचनात्मक डिजाइन समीक्षा (सीडीआर) की गई थी। उपयोगकर्ता (डीएलआरएल) को वितरित करने के लिए मैसर्स बीईएल में दस इंजीनियरीकृत एमपीएम का निर्माण किया जा रहा है।

उपग्रह डेटा लिंक के लिए केयू-बैंड माइक्रोवेव पावर मॉड्यूल (एमपीएम): पहला उत्पादन मॉडल निर्मित किया गया है और बीईएल में उसका परीक्षण किया जा रहा है। एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के क्षेत्रीय निदेशालय (आरक्यूएक्यूएएए), आईएएफ के साथ योग्यता परीक्षण (क्यूटी) पूरा किया गया है। पावर बर्न-इन परीक्षण के साथ कार्यात्मक परीक्षण सफलता पूर्वक पूरा हो चुका है।



सत्यपित करें संगठित करें, सुनिश्चित करें, विश्लेषण करें (वीवाईओएमए): डीआरडीओ ने 'सिग्नल इंटेलिजेंस रिपोर्टर्स' और 'सिग्नल इंटेलिजेंस सारांश' के अर्थ बोध की सुविधा, सोशल नेटवर्क विश्लेषण, स्थानिक और सैद्धांतिक विजुअलाइजेशन के साथ डिजिटल मानचित्रों पर सूचना के भंडार का उपयोग करना आसान बनाने के लिए एक नई परियोजना आरंभ की है। वर्ष के दौरान ए सॉफ्टवेयर प्रणाली की प्रारंभिक डिजाइन समीक्षा पूरी हुई थी।

भारतीय समुद्री स्थिति जागरूकता प्रणाली (आईएमएसएसएस): आईएमएसएसएस को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है जिसमें भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के आधार पर व्यापक स्थिति चित्र शामिल है। वर्ष के दौरान, आईएमएसएसएस के बिल्ड 1 का विकास कार्य पूरा हो गया और पश्चिमी नौसेना कमान (डब्ल्यूएनसी) और पूर्वी कमान (ईसी) पर इसका क्षेत्रीय परीक्षण भी किया गया।



मल्टी एजेंट रोबोटिक्स प्रणाली (एम एआरएस): परियोजना का उद्देश्य एक मल्टी एजेंट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क विकसित करना

है जो लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई विषम रोबोट प्लेटफार्मों के साथ संदर्भ आधारित सहयोग को सक्षम करता है। तीन प्लेटफार्मों अर्थात्, बॉलबोट, संतरी और मिनी यूजीवी के पहले प्रोटोटाइप का निर्माण और संयोजन पूरा हो गया है। दो संतरी रोबोटों के साथ बहु-रोबोट अन्वेषण, स्थानीयकरण और मैपिंग एल्गोरिथम का प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा किया गया है। एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और फ्रेमवर्क के साथ विभिन्न खुफिया एल्गोरिदम का एकीकरण योजना के अनुसार प्रगति कर रहा है।

चैफ कारतूस: चैफ सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल और प्रभावी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोधी उपाय उपकरणों में से एक है। वर्ष के दौरान ए आईएएफ और सीएएमआईएलएसी के सहयोग से चैफ कारतूस के परीक्षण के चार चरण आयोजित किए गए थे।

बुलेट प्रूफ जैकेट (बीपीजे): भारतीय सेना के दिशा निर्देशों (जीएसक्यूआर 1438) के अनुसार डीआरडीओ ने सफलता पूर्वक बीपीजे तैयार किया है। विकसित तकनीकी समाधान मैसर्स एमकेयू, कानपुर को स्थानांतरित कर दिया गया है।

'अस्त्र' मिसाइल से जुड़ा सिलिका राडार-गुंबद (आरएडीओएमई): राडार गुंबद (रेडोम) लक्ष्य की खोज करने वाले मिसाइल के एक महत्वपूर्ण घटक है, यह प्रतिकूल वातावरण से नेविगेशन प्रणाली की सुरक्षा करता है। राडार डोम के निर्माण के लिए, फ्यूज्ड सिलिका (SiO₂) एक पसंदीदा सिरामिक सामग्री है। वर्ष के दौरान, अस्त्र मिसाइल के लिए स्वदेशी फ्यूज्ड सिलिका रेडोम का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। इन रेडोमो का इस्तेमाल भविष्य में क्यूआरएसएसएम, प्रलय, रुद्र एमएम-2 और एनजीआरएसएम मिसाइल में भी किया जाएगा।

एनबीसी सूट एमके-वी: एनबीसी सूट एमके-वी को जेएसक्यूआर के अनुसार विकसित एसीएस के आधार पर एनबीसी मोजे सहित दो उद्योगों के साथ विकसित किया गया है। सेना द्वारा 50,000 सूटों के आपूर्ति आदेश को निष्पादित किया जा रहा है। डीआरडीई द्वारा विकसित स्वचालित रासायनिक एजेंट डिटेक्टर और अलार्म (एसीएडीए) और केमिकल एजेंट मॉनिटर (सीएएम) के लिए प्रयोगशाला परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं और आइटम उपयोगकर्ता परीक्षणों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

सौर हिम मेल्टर: केरोसिन जैसे पारंपरिक ईंधन, जिसके हवाई परिवहन की आवश्यकता पड़ती है और लागत और

रसद समस्याओं में वृद्धि होती है, पर निर्भरता को कम करने के लिए बर्फ पिघलाने के लिए सौर यंत्र (सौर हिम मेल्टर) विकसित किया गया है। प्रोटोटाइप विकसित किया गया है और दक्षिण पुल्लू, खारदोंग ला और चांग ला में परीक्षण आयोजित किए गए हैं।

एनबीसी ड्रग्स: एनबीसी ड्रग्स ने सीबीआरएन आपात स्थितियों के लिए एक किट के रूप में एनबीसी और अन्य जीवन रक्षक दवाएं विकसित की है, जिन्हें 24 मार्च, 2017 को रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना को सौंपा।

8.16 कंपनी की पहल

सेवाओं का इंटरैक्शन: वर्ष के दौरान डीआरडीओ और एओएन द्वारा 13,760.32 करोड़ रुपए की कुल लागत से प्रेरण के लिए प्रदान की गई विकसित/विकसित की जाने वाली प्रमुख प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल हैं: कम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल (एसआरएसएम) प्रणालीय बीएमपी-2 का बीएमपी-2एम में उन्नयन 155 मिमी/52 कैल ट्रैकड (एसपी) रेजिमेंट के लिए बीएमपी-द्वितीय आधारित कैरियर कमांड पोस्ट ट्रैकड (सीसीपीटी) वाहनों की खरीद, भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए हुमसा यूजी सोनार बंड विस्फोटक डिवाइस एमके-2, सुरंग विरोधी कार्मिक ब्लास्ट 'निपुण' एनएफएम, शिशुमार श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए चार बैटरी मॉनिटरिंग प्रणालियां और नौसेना संचार के लिए सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो (एसडीआर)। डीआरडीओ वारा विकसित प्रणालियों का उत्पादन मूल्य (शामिल और शामिल करने के लिए अनुमोदित) आज 2.65 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। सेवाओं की वार्षिक अधिग्रहण योजना (एएपी) 2017-19 का विश्लेषण किया गया है और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाओं को आरंभ करने तथा बढ़ाने के लिए सभी प्रयोगशालाओं के साथ साझा किया गया है। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित प्रणालियों को शामिल करने और सशस्त्र बलों के आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए सेवाओं के साथ नियमित रूप से बातचीत करने के लिए तंत्र की स्थापना की है, जो सचिव, डीडी आर एवं विकास और वायुसेना, सेना तथा नौसेना के प्रमुख/उप प्रमुख अधिकारियों के साथ वार्षिक संयुक्त समीक्षाय सेना के निदेशालय के साथ त्रैमासिक इंटरैक्शन मीटिंग्स (क्यूआईएम); वायु सेना के साथ तिमाही प्रगति समीक्षा (क्यूपीआर)य नौसेना के साथ वार्षिक समन्वय बैठकों (आईएनआरडीओ), आर्मी के लिए वीसीओएसएस/

डीसीओएस स्तर पर की जाने वाली अर्धवार्षिक समीक्षा द्वारा की जाती है।

उद्योग इंटरफ़ेस: डीआरडीओ ने डीपीएसयू/ओएफएस/पीएसयू और निजी उद्योगों के लिए स्तरीय कार्य पर जोर देने के साथ उद्योगों के लिए टीओटी की पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करने के लिए टीटी दिशानिर्देशों/एसओपी को प्रख्यापित किया है। वर्ग-क (सैन्य प्रौद्योगिकियों) और वर्ग-ख (आरंभ/वाणिज्यिक उपयोग की प्रौद्योगिकियों) के लिए टीओटी की सुविधा के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ ने सीआईआई, पीएचडीसीसी, एनआरडीसी और एसोचैम जैसे चार प्रमुख उद्योग निकायों के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। टीओटी लाइसेंस शुल्क को अंतिम रूप देने और टीओटी के लिए उद्योग के चयन को अंतिम रूप देने के लिए एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का कार्यान्वयन किया गया है। वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (एलएटीओटी) के लिए 108 लाइसेंसिंग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। विस्फोटक, प्रणोदक, खानों और हथियार प्रौद्योगिकियों पर पहली बार निजी उद्योगों को टीओटी स्थानांतरित किया गया था।

डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रणालियों की निर्यात क्षमता में भी वृद्धि हुई है। कई देशों ने डीआरडीओ द्वारा विकसित रडार, सोनार, टॉरपीडो, ईडब्ल्यू प्रणाली, आईडब्ल्यू और सी प्रणाली, ब्रिजिंग प्रणाली, मिसाइल आदि प्रणालियों को हासिल करने में रुचि दिखाई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा उद्योगों को निर्यात के लिए दिए गए एनओसी से पता चलता है कि दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्रों के कुल मूल्य का लगभग 55% डीआरडीओ प्रौद्योगिकियों पर आधारित उत्पादों के लिए हैं।

डीआरडीओ द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों, विशेष रूप से एमएसएमई को धन उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) योजना का कार्यान्वयन और निष्पादन किया गया है। मुख्य रूप से प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा, जो घटकों/संयोजनों के कर्नेल का निर्माण करेगा, जिनका आगे रक्षा उपकरणों/प्रणालियों/उप-प्रणालियों/प्लेटफार्मों को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। पिछले साल लॉन्च किए गए वेब पोर्टल में 600 से ज्यादा उद्योगों को पंजीकृत किया गया है और पहले दौर में, छह परियोजनाएं अनुमोदन और उद्योगों को सौंपे जाने के उन्नत चरणों में हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी: डीआरडीओ ने अबू धाबी में नवडेक्स-2017, टोक्यो, जापान में मास्ट एशिया -2017 और सिओल, दक्षिण कोरिया में सियोल इंटरनेशनल एयरोस्पेस एंड डिफेंस एक्जिबिशन (एडेक्स-2017) सहित कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। यह 20 राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी भागीदारी की, जिसमें तिरुपति में 104वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस -017, गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो -2017, बेंगलुरु में एरो इंडिया -2017, पुणे में 5वां भारतीय विज्ञान सम्मेलन और पुणे में एक्सपो-2017, बेंगलुरु में भारतीय प्रौद्योगिकी कांग्रेस -2017, डीआरडीओ भवन में पनडुब्बी प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी, चेन्नई में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल-2017 और बेंगलुरु में भारत विनिर्माण शो और कॉन्फ्रेंस -2017 आदि शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: वर्ष 2017 में, डीआरडीओ ने अमरीका, ब्रिटेन, रूस और सिंगापुर के साथ नियमित वार्षिक द्विपक्षीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास बैठकें की। डीआरडीओ ने जनवरी/फरवरी 2017 में यूएस डीओडी के साथ संयुक्त रूप से मेडिकल और केम बायो डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला के दौरान संभावित सूचना आदान-प्रदान और परियोजना समझौतों में सहयोग के लिए कुछ मजबूत संभावनाओं की पहचान की गई है। डीआरडीओ द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका (जेटीजी के अंतर्गत) और रूस (आईआरआईजीसी के अंतर्गत) के साथ छह परियोजना समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। डीआरडीओ ने एनडीसी के प्रतिनिधियों (ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, यूके, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि) सहित विदेशी यात्राओं की मेजबानी की और वर्ष 2017 के दौरान एरो इंडिया में प्रमुख प्रौद्योगिकी कार्यक्रम आयोजित किया। डीआरडीओ ने एससीओएमटी वस्तुओं के आयात/निर्यात से संबंधित मामलों पर डीजीएफटी, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत अंतर मंत्रालयीय कार्य दल (आईएमडब्ल्यूजी) के एक हिस्से के रूप में भाग लिया। डीआरडीओ ने एमटीसीआर (आयरलैंड), कुछ परंपरागत हथियार सत्र (जिनेवा) और ऑस्ट्रेलियाई समूह (पेरिस) में भी भाग लिया। डीआरडीओ ने एमसीए और डीजीएफटी के साथ मिलकर उद्योग आउटरीच कार्यक्रमों में भाग लिया और एससीओएमईटी सूची के संयोजन और दिल्ली और बेंगलुरु में आयोजित वासेनार व्यवस्था में भाग लिया।

योजना प्रबंधन में पहल: डीआरडीओ ने अपनी प्रयोगशालाओं/समूह डीजी के विस्तृत विचार-विमर्श और तीनों सेवाओं के साथ

बातचीत की श्रृंखला के बाद अपनी तेरहवीं पंचवर्षीय योजना (2017-22) का प्रोजेक्शन दस्तावेज़ विकसित किया है। मुख्यालय आईडीएस के तत्वावधान में, डीआरडीओ और तीनों सेवाओं के बीच परस्पर परामर्श और सहमति के माध्यम से योजना, खासकर डीआरडीओ की 'मिशन मोड' (एमएम) परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया। पहली बार, एम.एम. परियोजनाएं, रक्षा मंत्रालय/क्षा मंत्रालय की एकीकृत योजना में विधिवत रूप से विचार-विमर्श कर रही हैं, योजना तैयार करने की प्रक्रिया में बहुत आवश्यक तालमेल रख रही है। दूरदर्शी दस्तावेज एक मार्ग और उद्योग, शिक्षाविदों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोगियों को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करेगा।

शैक्षणिक संवाद: वर्ष 2016 में तीन उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र अर्थात् जादवपुर विश्वविद्यालय में उन्नत प्रौद्योगिकी का जगदीश चंद्र बोस केंद्र (जेसीबीसीएटी) आईआईटी बॉम्बे और मद्रास में सेंटर ऑफ द प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी (सीओपीटी) और आईआईटी दिल्ली में संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (जेएटीसी) स्थापित किए जिन्होंने इस साल अपना संचालन शुरू किया और अब पूरी तरह कार्यात्मक हैं। चालू वर्ष के दौरान, साइबर सुरक्षा, उच्च शक्ति निर्देशित ऊर्जा, रोबोटिक्स और मानव रहित प्रौद्योगिकियों के चिह्नित क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए जेसीबीसीएटी को 36.85 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 6 परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गई। सीओपीटी को फ्यूचरिस्टिक एयरो इंजन के केंद्रित क्षेत्रों में लंबी अवधि की उड़ान के लिए हाइपरसॉनिक प्रणोदन, ठोस प्रणोदक दहन मॉडलिंग और विमान और संबंधित प्रौद्योगिकियों की मोर्फिंग के क्षेत्र में 109.39 करोड़ रुपए की लागत की 39 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। बैलिस्टिक, विशेष संरचनाओं और सुरक्षा, विद्युत चुम्बकीय डिवाइस और टेराहर्ट्ज; स्मार्ट और बुद्धिमान वस्त्र; मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस और मस्तिष्क मशीन इंटरफेस और फोटोनिक्स, प्लासोनिक्स और क्वांटम फोटोनिक्स के चिह्नित क्षेत्रों में निर्देशित अनुसंधान का करने के लिए जेएटीसी के लिए 157.82 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 23 परियोजनाएं भी स्वीकृत की गईं। डीआरडीओ की अतिरिक्त भित्ति (ईआर) पहल के माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के लिए 150.65 करोड़ रुपए की लागत की 64 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई और डीआरडीओ के अधीन काम करने वाले चार अनुसंधान बोर्डों (एयरोनॉटिक्स, नौसेना, आर्ममेंट्स एंड लाइफ साइंसेज) के

माध्यम से 34.17 करोड़ रुपए की कुल लागत पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के लिए 97 अनुसंधान परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था।

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर): करीब 155 आईपीआर आवेदन (विदेशी देशों में 13 सहित) दायर किए गए थे। इस अवधि के दौरान 78 पेटेंट (विदेशी देशों में 5 सहित) प्रदान किए गए थे। इसके अलावा, भारत में 1 कॉपीराइट और 2 डिज़ाइन पंजीकृत किए गए। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के बीच आईपीआर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाओं में इस अवधि के दौरान पांच आईपीआर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

8.17 सरकार की पहलों का कार्यान्वयन: 'स्वच्छ भारत' के लिए वार्षिक और पांच साल की कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और योजना के अनुसार हैं स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण आदि गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सभी प्रयोगशालाओं में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया गया। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में, प्रयोगशालाओं में सक्रिय रूप से ई-खरीदारी आरंभ की गई है, रक्षा यात्रा प्रणाली

के माध्यम से ई-टिकट का कार्यान्वयन किया गया है और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए, प्रयोगशालाओं और मुख्यालयों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। जिसमें हर महीने वीसी में 100 से अधिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सरकार द्वारा शुरू किए गए 'मेक इन इंडिया' के मिशन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ प्रयोगशालाओं द्वारा इस विषय पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' से संबंधित पहलों के लिए भी एक एकीकृत तरीके से कदम उठाए गए हैं।

विशेष उल्लेख: भारत के प्रधान मंत्री ने 27 जुलाई, 2017 को रामेश्वरम में डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया।

8.18 अपने अधिकांश प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सराहनीय उपलब्धियों के साथ, डीआरडीओ रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपने मिशन के भाग के रूप में भारतीय सशस्त्र बल को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां / प्रणालियां प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।



भारत के प्रधान मंत्री ने 27 जुलाई, 2017 को रामेश्वरम में डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया।



अंतर सेवा संगठन





अंतर सेवा संगठन

9.1 निम्नलिखित अंतर-सेवा संगठन सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करते हैं:-

- (i) सेना इंजीनियर सेवा
- (ii) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा
- (iii) रक्षा सम्पदा महानिदेशालय
- (iv) मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय
- (v) जन संपर्क निदेशालय
- (vi) सेना खेल-कूद नियंत्रण बोर्ड
- (vii) सशस्त्र सेना फिल्म और चित्र प्रभाग
- (viii) राष्ट्रीय रक्षा कालेज
- (ix) इतिहास प्रभाग
- (x) रक्षा प्रबंधन कालेज
- (xi) रक्षा सेना स्टाफ कालेज

(xii) रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

सेना इंजीनियर सेवा (एमईएस)

9.2 सेना इंजीनियर सेवा (एमईएस) सामरिक और संक्रियात्मक स्तर पर तीनों सेनाओं को सहयोग प्रदान करता है। यह संगठन व्यावसायिक और तकनीकी रूप से सक्षम अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों से परिपूर्ण है।

9.3 सेना इंजीनियर सेवा सेना मुख्यालय में इंजीनियर-इन-चीफ के समग्र नियंत्रण में कार्य करती है, जो सभी प्रकार के कार्यों से संबंधित मुद्दों पर रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के प्रमुखों का सलाहकार होता है। इसके पास 17,000 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक बजट संबंधी कार्यभार है। रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के एक भाग के रूप में, काफी संख्या में आधारभूत संरचना परियोजनाओं को किये जाने की योजना बनाई गई है। सेना इंजीनियर सेवा मित्र विदेशी सरकारों के लिए विदेश में आधारभूत संरचना का सृजन करके सैन्य राजनयिक पहलों में

भी सहयोग देता रहा है। सेना इंजीनियर सेवा संगठन जो प्रवीण कार्मिकों से युक्त है, दराज अवस्थितियों में भाग और विपरीत जलवायु स्थितियों में दूर-कार्मिकों को पूरे देश में हर प्रकार के भू तैनात किया जाता है और वे शांति के समय कार्य सेवा सहयोग प्रदान करते हैं और युद्ध के दौरान समर्पित सहयोग प्रदान करने हेतु भी सुसज्जित होते हैं।

9.4 वार्षिक प्रमुख निर्माण कार्य कार्यक्रम (एएमडब्ल्यूपी)

(क) **एएमडब्ल्यूपी 2016-17** : वर्ष 2016-17 में तटरक्षक सहित तीनों सेनाओं के लिए 12,754.90 करोड़ रु. की सीमा के समक्ष 15501.31 करोड़ रु. की लागत पर निर्माण कार्य सूचीबद्ध किए गए थे जिसमें से 9839.68 करोड़ रु. की लागत पर निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(ख) **वित्तीय**: वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत तटरक्षक और एमएपी सहित तीनों सेनाओं के लिए 7693.20 करोड़ रु. आवंटित किए गए थे जिसमें से एमईएस द्वारा उपगत कुल व्यय 7645.05 करोड़ रु. था। राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत तटरक्षक सहित सभी तीनों सेनाओं के लिए 10514.37 करोड़ रु. का बजट आवंटित किया गया था। वित्तीय वर्ष में इस शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय 10126.42 करोड़ रु. था।

9.5 प्रगतिधीन प्रमुख परियोजनाएं

(क) **केन्द्रीय आयुध डिपो (सीओडी) आगरा और जबलपुर का आधुनिकीकरण :**

(i) समग्र "आधुनिकीकरण अभियान" के भाग के रूप में सेना आयुध डिपो का आधुनिकीकरण आधारभूत संरचना तथा स्वचालन के साथ उन्नयन किया जा रहा है। सीसीएस ने सीओडी आगरा और जबलपुर की आधुनिकीकरण परियोजना को 751.89 करोड़ रु. की लागत से 11 अप्रैल, 2017 को अनुमोदित किया था। डीआरडीओ द्वारा मूल रूप से निष्पादित होने वाला कार्य एमईएस को मार्च, 2008 में अंतरित कर दिया गया था। आधुनिकीकरण परियोजना में प्रमुख रूप से एकीकृत भंडारण तथा सुधार प्रणाली के साथ सुसज्जित पीईबी भंडारण भवन का निर्माण, सहायक सेवाओं के साथ मैकेनाइज्ड हैंडलिंग उपकरण तथा प्रशासनिक / ओटीएम भवन सम्मिलित हैं।

(ii) सीओडी आगरा और जबलपुर में परियोजना का चरण-I पूरा हो गया है और परियोजना के चरण-II की समग्र प्रगति क्रमशः 49 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है। सीओडी आगरा और जबलपुर में एकीकृत भंडारण प्रणाली के लिए क्रमशः 14.9 करोड़ रु. और 10.4 करोड़ रु. की दो निविदाओं को स्वीकार किया गया है और निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ख) **उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में सैन्य टुकड़ियों की रिहायशी और जीवनयापन संबंधी दशाओं में सुधार (एचएए पायलट परियोजना):**

(i) उच्च तुंगता वाले क्षेत्र में सैन्य टुकड़ियों की आवासीय तथा जीवनयापन की स्थिति में सुधार लाने के लिए अभिकल्पन तथा निर्माण तकनीक के चयनार्थ चरण-I और चरण-II की पायलट परियोजनाएं 54 प्लाटून अवस्थिति पर 194.86 करोड़ रु. के समग्र व्यय के साथ सफलतापूर्वक पूरी हो गई हैं।

(ii) चरण-III में 12 प्लाटून अवस्थिति में से 11 का कार्य पूरा हो गया है और परिसंपत्तियों को प्रयोक्ताओं को सौंप दिया गया है। एक स्थान पर कार्य प्रगति पर है। सृजित की गई परिसंपत्तियों का परीक्षण मूल्यांकन प्रगति पर है और 320 प्लाटून स्थानों को सम्मिलित करते हुए प्रमुख परियोजना का आरंभ परीक्षणों के पश्चात किया जाएगा।

(ग) **पूर्वी कमान में आधारभूत संरचना विकास :**

(i) सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) ने पूर्वी क्षेत्र में आधारभूत संरचना के लिए 9243.64 करोड़ रु. की लागत को वर्ष 2010 में अनुमोदन प्रदान किया था। इनमें से 7374.70 करोड़ रु. की लागत का निर्माण कार्य एमईएस द्वारा निष्पादित किया जा रहा है जिसके लिए विशेष रूप से अधिकार प्राप्त सीसीई संगठनों का गठन किया गया था। कार्य के क्षेत्र में सैन्य टुकड़ियों के लिए स्थायी रक्षा तथा रियासश, संचार नेटवर्क और अन्य सामरिक आधारभूत संरचना सम्मिलित हैं।

(ii) वर्तमान में 105 निर्माण कार्यों के लिए भूमि मुहैया करवाई गई है जिन पर योजना बनाई जा रही है / क्रियान्वयन हो

रहा है। आज की तारीख के अनुसार पांच निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं। 30 निर्माण कार्यों पर क्रियान्वयन हो रहा है तथा 8 निर्माण कार्य निविदा योजना के अन्तर्गत हैं। 11 डीपीआर तैयार हो गई है और प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन हैं। उनकी संवीक्षा की जा रही है 16 डीपीआर तैयार की जा रही है तथा 30 निर्माण कार्य डीपीआर पूर्व स्तर पर हैं।

(घ) **राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय (एनएडब्ल्यूएम एंड एम):**

- (i) 500 करोड़ रु. की लगभग लागत से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तथा राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय के निर्माण संबंधी परियोजना को मंत्रिमंडल द्वारा 11 दिसम्बर, 2015 में अनुमोदित किया गया था।
- (ii) राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय की डिजाइन के चयन हेतु विश्व स्तरीय डिजाइन तथा वास्तुशिल्पीय प्रतिस्पर्धा अगस्त, 2016 में आयोजित की गई थी। दोनों प्रतिस्पर्धाओं संबंधी जूरी में ई-एन-सी शाखा में एडीजी (वास्तुकला) सहित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के 25 सदस्य सम्मिलित थे। विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने के पश्चात जूरी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय प्रत्येक के लिए तीन प्रविष्टियों का चयन किया था। उक्त का परिणाम 03 मार्च, 2017

को घोषित किया गया था।

- (iii) कार्यनिष्पादन एजेंसी के नामांकन हेतु सरकारी स्वीकृति पत्र और निर्माण के लिए परियोजना निदेशक को शक्तियों का प्रत्यायोजन 21 जून, 2017 को जारी किया गया था। कार्यनिष्पादन एजेंसी के प्रमुख ब्रिगेडियर रैंक के परियोजना निदेशक होंगे जिनकी सहायता के लिए 04 अधिकारी और अन्य सहायक स्टाफ होगा। आज की तारीख के अनुसार राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के लिए डीपीआर तैयार करने संबंधी परामर्शदात्री संविदा को अंतिम रूप दिया गया है। परियोजना निदेशक एनडब्ल्यूएम एंड एम द्वारा मुख्य कार्य हेतु निविदा 01 नवम्बर, 2017 को अपलोड कर दी है।

(ड.) **एमईएस द्वारा सोलर फोटो वाल्टेक (एसपीवी) परियोजनाएं:**

प्रथम चरण में एमईएस को रक्षा मंत्रालय की ओर से देश में सेना, नौसेना तथा वायु सेना के 113 स्थानों पर 150 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। इसके समक्ष 156.93 मेगावाट के एसपीवी के कार्य का एमईएस द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये कार्य हर प्रकार से दिसम्बर, 2018 में प्रारंभ होने हैं। जबकि कुछ परियोजनाएं कुछ स्टेशनों पर पहले ही प्रारंभ हो गई हैं, 5 मेगावाट तक के कुछ कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। आज की तारीख तक एमईएस द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे एसपीवी कार्यों की प्रगति निम्नवत है :

सारणी संख्या 9.1

सेना	नियोजित (एमडब्ल्यू)	कुल स्टेशन	प्रदत्त प्रशासनिक अनुमोदन एमडब्ल्यू	जारी किया गया टेंडर (एमडब्ल्यू)	प्राप्त टेंडर (एम डब्ल्यू)	टिप्पणियां
(क) एएमडब्ल्यूपी 2015-16						
वायु सेना	10.43	12	10.43	10.43	5.92	सभी निर्माण कार्यों के पूरा होने की प्रस्तावित तारीख 31 मार्च, 2018 है।
सेना	27.115	17	37.115	27.115	17.115	
नौसेना	1	1	1	0	0	
कुल	38.545	30	38.545	37.545	23.035	

(ख) एएमडब्ल्युपी 2006-17						
वायु सेना	24.36	26	24.36	17.51	14.01	सभी निर्माण कार्यों के पूरा होने की प्रस्तावित तारीख 31 मार्च, 2018 है।
सेना	73.67	44	64.52	59.12	58.92	
नौसेना/ आईडीएस	20.355	13	17.305	12.05	12.05	
कुल	118.355	83	106.185	88.68	84.98	
कुल योग	156.93	113	144.73	126.225	108.015	

9.6 वैवाहिक आवास परियोजना (एमएपी) कार्य :

(क) **एमएपी चरण-II** : एमएपी चरण-II में 13681.90 करोड़ रु. की लागत पर 69992 आवासीय यूनिटें स्वीकृत की गई थी जिसमें से एमईएस 3500.00 करोड़ रु. की लागत से निर्माण कार्य कर रहा है। तथापि 88 आवासीय यूनिटों का निर्माण कार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका था। इसलिए चरण-II में 69904 आवासीय यूनिट का निर्माण हो रहा है जिसमें से 60694 आवासीय यूनिटें डीजीएमएपी द्वारा और 9210 आवासीय यूनिटें एमईएस द्वारा निर्मित की जा रही है। एमईएस 1400.00 करोड़ रु. की लागत पर बाहरी सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। एमईएस सभी स्टेशनों पर क्रमशः 300.00 करोड़ रु. और 100.00 करोड़ रु. की लागत से फर्नीचर तथा वृक्ष संवर्धन के प्रावधान के लिए भी उत्तरदायी हैं। वर्तमान में 5539 आवासीय यूनिटें पूरी हो गई हैं और उनके एमईएस द्वारा सौंप दिया गया है तथा 38086 आवासीय यूनिटों का डीजीएमएपी द्वारा निर्माण किया जा रहा है तथा शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है।



एमएपी (फेज II) के तहत पिथौरागढ़ में 1054 आवासीय यूनिटों का निर्माण

(ख) **एमएपी चरण-III** : एमएपी चरण-III में कुल 71102 आवासीय यूनिटें चरण-III और चरण-IV (अब चरण-III के साथ मिलाकर) अनुमोदित की गई थी। इनमें से 70432 आवासीय यूनिटें सेना के लिए तथा 670 वायु सेना के लिए हैं। डीजीएमएपी और एमईएस के बीच कार्य भार को क्रमशः 57 प्रतिशत तथा 43 प्रतिशत के अनुपात में विभाजित किया गया है। वर्तमान में उक्त कार्यों के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है।

प्रमुख कार्यक्रम / निर्णय / नीतियां

9.7 निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम / निर्णय / नीतियों का क्रियान्वयन किया गया / जारी किए गए हैं जिनका संगठन की कार्य प्रणाली और कार्य निष्पादन पर बड़ा प्रभाव होगा।

(क) **एमईएस संगठन और अधिकारी स्थापना 2016-17**: 16 एमईएस स्थापनाएं नए तरीके से स्थापित की गई हैं।

(ख) **कतिपय महत्वपूर्ण मामले विचाराधीन हैं जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :**

- डीडब्ल्युपी 2007 में संशोधन।
- आवास मानदंड 2009 में संशोधन।
- एमईएस निर्माण के लिए हरित भवन मानदंडों (गृह) का पालन-स्वीकृति आदेश 14 दिसम्बर, 2017 को जारी किए गए हैं।
- एमईएस में कार्य भार तथा गुणवत्ता को पूरा करने के लिए नई निर्माण प्रौद्योगिकी (डिजाइन भवन) का पालन।
- सीपीडब्ल्युडी की तर्ज पर एमईएस में भवनों और सड़कों के लिए अनुरक्षण मानदंडों में संशोधन।

9.8 सेना, वायु सेना तथा नौसेना के लिए पूरा हुई महत्वपूर्ण परियोजनाएं :

(क) **कमान अस्पताल, लखनऊ में नर्सिंग विद्यालय का उन्नयन** : उक्त कार्य 8.09 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया था और 28 फरवरी, 2017 को पूरा हो गया था।

(ख) **आईएमए में (चरण-1) प्रेरणा हॉल एवं कार्यालयों के साथ एसीसी विंग के 450 कैडेटों के लिए आवास सुविधा**: उक्त कार्य 14.71 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया था और वह 31 मार्च, 2017 को पूरा हो गया था।

(ग) **मिनिकाय में तटरक्षक स्टेशन के लिए ओटीएम आवास सुविधा**: उक्त कार्य 23.42 करोड़ रु. की लागत के साथ स्वीकृत किया गया था और वह कार्य 2017 में पूरा हो गया था।

(घ) **वायु सेना स्टेशन महाराजपुर में आधारभूत संरचना**: उपर्युक्त कार्य 10.23 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया था और फरवरी, 2017 में पूरा हो गया था।

9.9 पूरे हो चुके एमएपी आवास:

(क) उमरोई (चरण-II)

(ख) पिथौरागढ़ में एमएपी (चरण-II) के अन्तर्गत 1054 आवासीय यूनिटों का निर्माण

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (एएफएमएस)

9.10 सशस्त्र सेना चिकित्सा का रक्षा कार्मिकों और उनके परिवारों को समर्पित और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने का विशिष्ट रिकार्ड है। चिकित्सा सेवाएं, युद्ध में तैनात किए जाने के समय अर्ध-सैनिक संगठनों के कार्मिकों और देश के अशांत और दूर-दराज क्षेत्रों में संक्रिया कर रहे अन्य केन्द्रीय पुलिस/आसूचना संगठनों और जीआरईएफ यूनिटों को भी दी जाती है। एएफएमएस देश के भीतर भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सेवा भी प्रदान करता है। प्राकृतिक विपदा, आपदा और संक्रियात्मक क्षेत्रों में यह सिविलियन नागरिकों को भी सेवा देती है।

9.11 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं (एएफएमएस) में सेना, नौसेना एवं वायु सेना की चिकित्सा सेवाएं तथा सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय सम्मिलित हैं। सशस्त्र सेना चिकित्सा

सेवा में प्रत्येक चिकित्सा सेवा में लेफ्टिनेंट जनरल अथवा समकक्ष रैंक के भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना, प्रत्येक में महानिदेशक, चिकित्सा सेवाएं और महानिदेशालय, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (डीजीएएफएमएस) जो सेवा के प्रमुख हैं, रक्षा मंत्रालय के चिकित्सा सलाहकार और चिकित्सा सेवा परामर्शदायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। एएफएमएस में एमएससीए एमएमसी (एनटी), एडीसी और एमएनएस के अफसर शामिल हैं। 132 सशस्त्र सेना अस्पताल हैं एएमसीए एडीसीए एमएस और एएमसी (एनटी) की प्राधिकृत नफरी क्रमशः 7139, 725, 5317 और 373 है।

9.12 वर्ष के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय/कार्यकलाप:

(I) **एएफएमएस में कार्मिक संख्या में बढ़ोत्तरी**: सरकार ने मई, 2009 में 3530 कार्मिकों के प्रत्येक तीन समान चरणों में 10,590 कार्मिकों तक एएफएमएस की कार्मिक शक्ति के संवर्धन को अनुमोदित किया था। तीन चरणों में कार्मिकों की भर्ती पूरी हो गई है। सरकार ने प्रशिक्षण प्रारूप और लीव रिजर्व के अन्तर्गत एएफएमएस में प्रारंभिक चरण में 525 चिकित्सा अधिकारियों और 32 दंत चिकित्सा अधिकारियों की संख्या अनुमोदित की है।

(II) **एएफएमएस में कमीशन**:

(क) **सिविल स्रोतों से अल्प सेवा कमीशन**: वर्ष 2017 में 180 महिलाओं सहित 510 चिकित्सा अधिकारियों को अल्प सेवा कमीशन प्रदान किया गया था। को अल्प सेवा कमीशन प्रदान किया गया था।

(ख) **एएफएमसी, पुणे के कैडेटों को अल्प सेवा कमीशन / स्थायी कमीशन प्रदान करना** : वर्ष 2017 के दौरान एएफएमसी से कुल 102 कैडेटों (स्थायी कमीशन 51, अल्प सेवा कमीशन -51) को एएफएमसी में स्थायी कमीशन / अल्प सेवा कमीशन प्रदान किया गया है।

(ग) **अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को विभागीय स्थायी कमीशन प्रदान करना**: वर्ष 2017 के दौरान 59 सेवारत अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को विभागीय स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है।

(घ) **अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एएमसी**

(एनटी) में विभागीय स्थायी कमीशन प्रदान करना : वर्ष 2017 के दौरान एएमसी (एनटी) के 05 सेवारत अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को विभागीय स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है।

(ड) जेसीओ / अन्य रैंकों को एएमसी (एनटी) में अल्प सेवा कमीशन प्रदान करना: वर्ष 2017 के दौरान एएमसी के 06 जेसीओ / अन्य रैंकों को अल्प सेवा कमीशन प्रदान किया गया है।

(III) सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे: यह कालेज रक्षा सेनाओं में सुनिश्चित कैरियर संभावनाओं के साथ अंडर-ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा और परिचर्या, विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। एमबीबीएस के लिए प्रवेश एनईईटी-यूजी के द्वारा केन्द्रीकृत रूप से संचालित किया गया था और वर्ष 2017 के लिए एएफएमसी, पुणे में प्रवेश के लिए कुल 51228 उम्मीदवारों ने ऑन-लाइन आवेदन किया। उनकी योग्यता के आधार पर 1690 उम्मीदवारों को साक्षात्कार, के लिए बुलाया गया था। छंटाई किए गए उम्मीदवारों के लिए एएफएमसी में अंग्रेजी भाषा, तार्किकता और बुद्धिमत्ता (टीओईएलआर) के लिए एक कम्प्युटर आधारित परीक्षा भी आयोजित की गई थी और अंततः वर्ष 2017 के लिए 130 (105 लड़के और 25 लड़कियां) विद्यार्थियों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था।

(IV) एएफएमसी का आधुनिकीकरण:

(क) एएफएमएस अस्पतालों और यूनिटों की चिकित्सा उपस्कर प्रोफाइल का आधुनिकीकरण: डीजीएएफएमएस के कार्यालय ने वार्षिक अधिग्रहण योजना (एएपी) में वरीयता प्राप्त अधिप्राप्ति के जरिए सशस्त्र सेना अस्पतालों के आधुनिकीकरण पर मुख्य रूप से बल दिया है। 102 करोड़ रु. मूल्य के विशिष्ट चिकित्सा उपस्करों को वित्तीय वर्ष 2014-15 में अधिप्राप्त किया गया था। 110 करोड़ रु. और 122 करोड़ से अधिक के आपूर्ति आर्डर क्रमशः वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिए गए हैं। पूंजीगत बजट वर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 37.77 करोड़ रु. का आर्डर 31 अक्तूबर, 2017 तक दिया गया है। इसने सैनिकों उनके आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकगण को मुहैया करवाई जा रही नैदानिक, चिकित्सीय तथा विशिष्ट सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण सुधार में परिवर्तित किया गया है।

(ख) 7 वायु सेना अस्पताल, कानपुर में ज्वाइंट रिप्लेसमेंट केन्द्र की स्थापना: 7 वायु सेना अस्पताल में

स्थापित ज्वाइंट रिप्लेसमेंट केन्द्र (जेआरसी) ने सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों दोनों के लिए ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सेवाएं आरंभ कर दी हैं। इस केन्द्र जनवरी, 2016 से कुल 745 ज्वाइंट रिप्लेसमेंट किए गए हैं जिनमें से 405 सर्जरी भूतपूर्व सैनिकों की गई हैं।

(ग) सेना अस्पताल (आर एंड आर) दिल्ली में कार्डियो कोरासिक वेस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) केन्द्र: सेना अस्पताल (आर एंड आर) दिल्ली में अतिविशिष्ट स्कंध के रूप में 200 बेड का सीटीवीएस केन्द्र स्थापित किया गया है। इस केन्द्र को उच्च प्रयोजनीय अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, 6 ऑपरेशन थेटों, कार्डिक कैथेटराइजेशन प्रयोगशालाओं, इलेक्ट्रो पैथोलोजी प्रयोगशाला, आईसीयू, विशिष्ट सीटीवीएस उपकरणों, प्रयोगशाला तथा ओपीडी सेवाओं से सुसज्जित किया गया है।

(घ) चिकित्सा उपकरणों की अधिप्राप्ति: विभिन्न सशस्त्र सेना अस्पतालों में आवश्यक जीवन रक्षक तथा नियमित उपयोग के चिकित्सा उपकरणों की बड़ी मात्रा में अधिप्राप्ति करने हेतु बृहत अभियान का रोगी देखभाल सेवाओं और सभी रोगीगण की संतुष्टि पर बड़ा और सकारात्मक प्रभाव हुआ है।

(ड) एयरो-मेडिकल सिमुलेटरों की अधिप्राप्ति और उन्नयन: भारतीय वायु सेना एरोस्पेस सुरक्षा में यथेष्ट उद्देश्य अर्जित करने के लिए इन सिमुलेटरों का प्रयोग करके विमान कर्मीदल के संक्रियात्मक प्रशिक्षण में वृद्धि करने हेतु नए सिमुलेटरों को अधिप्राप्ति करने तथा मौजूदा एयरो-मेडिकल सिमुलेटरों का उन्नयन करने की प्रक्रिया में हैं।

(V) सशस्त्र सेना चिकित्सा भंडार डिपो का स्क्वाड्रन (एएफएमएसडी एवं आपूर्ति शृंखला प्रबंधन):

(क) टेलीमेडिसिन:

(i) टेलीमेडिसिन चरण-I: दूरदराज स्थित सैन्य चौकियों को रेजिमेंटल सहायता चौकी (आरएपी) से जोड़ने के लिए रेडियो आधारित टेलीमेडिसिन की रक्षा जैब इंजीनियरी एवं इलेक्ट्रोसायन प्रयोगशाला (डीईबीईएल) के साथ योजना बनाई गई है।

(ii) टेलीमेडिसिन चरण-II: रेजिमेंटल सहायता चौकी (आरएपी) को विशिष्ट अस्पताल से जोड़ने के लिए डीईबीईएल द्वारा विकसित टेलीमेडिसिन साफ्टवेयर का

प्रयोग करके डीईबीईएल के साथ भी योजना बनाई गई है। सेना साइबर समूह द्वारा टेलीमेडिसिन साफ्टवेयर के साइबर सुरक्षा परीक्षण का प्रथम चरण पूरा हो गया है।

(iii) **इसरो टेलीमेडिसिन नोड्स:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सशस्त्र सेना को 2001 में 18 टेलीमेडिसिन नोड्स प्रारंभिक रूप से मुहैया करवाए थे। सभी नोड्स कार्य कर रहे हैं और सेना अस्पताल अनुसंधान एवं रेफरल तथा विकास शिक्षा एवं संचार यूनिट इसरो अहमदाबाद द्वारा संचालित सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) के नियमित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। इस वर्ष 12 सीएमई आयोजित की गई हैं। वर्ष 2017 के दौरान दो अतिरिक्त नोड्स अधिष्ठापित किए गए हैं।

(ख) **मरकरी-निम्बस टेलीमेडिसिन के साथ राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) पर टेलि-शिक्षा परियोजना:**—वर्तमान में एएफएमएस में 7 प्रमुख स्नातकोत्तर शिक्षण स्थापनाएं हैं जो अनेक मौलिक विषयगत विधाओं में उन्नत पाठ्यक्रम संचालित करती हैं। सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल (आर एंड आर) तथा कमान अस्पताल (सीएच) और भारती चिकित्सा परिषद (एमसीआई) एवं राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता प्रदान की थी जो भारतीय नर्सिंग परिषद (एनसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय और नर्सिंग विद्यालय हैं। एमसीआई, एनबीई तथा एनसीआई नियमित सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) को सेमीनारों विचार-गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के रूप में आयोजित करने को अधिदेशित करते हैं। एन के एन परियोजना को सूचना प्रौद्योगिकी प्राथमिकता अधिप्राप्ति योजना (आईटीपीपीपी) वित्तीय वर्ष 2017 में अनुमोदित की गई है और सभी कमान अस्पतालों तथा सेना अस्पताल (एमएच), सिकन्द्राबाद के लिए बजट आवंटित किया गया है।

(ग) **चिकित्सा सेवाओं का डिजिटलीकरण:** भारतीय वायु सेना की चिकित्सा सेवाओं के डिजिटलीकरण के भाग के रूप में वेब आधारित अस्पताल सूचना प्रणाली (एचआईएस) कार्यान्वित की गई है। प्रणाली का उद्देश्य भारतीय वायु सेना के सभी अस्पतालों में रोगी देखभाल से संबंधित सभी प्रक्रियाएं स्वचालित करना है। स्टेशन चिकित्सा देखभाल (एसएमसी) में रोगी अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए “मेडनेट” नामक साफ्टवेयर प्रयोग किया जा रहा है।

(घ) **चिकित्सा बोर्डों की ई-पुनरीक्षा:** डीजीएमएस (वायु) ने चिकित्सा बोर्डों की ई-पुनरीक्षा के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। बोर्डिंग केन्द्रों में स्थापित सभी बोर्डों (वायु सेना चिकित्सा संस्थान (आईएएम)) / वायु सेना केन्द्रीय चिकित्सा स्थापना (एएफसीएमई) / चिकित्सा मूल्यांकन केन्द्र (एमईसी) (पूर्व) की ई-पुनरीक्षा वायु सेना मुख्यालय में की जा रही है। यह विमान कर्मियों के शीघ्र उन्नयन का सुनिश्चित करती है।

(ङ) **धनवंतरि साफ्टवेयर उन्नयन:** अनुप्रयोग साँफ्टवेयर धनवंतरि आईटी जो अस्पतालों पंजीकरण भर्ती करने डिस्चार्ज करने स्थानांतरित करने (आरएडीटी) की कार्यप्रणालियों में सक्षम बनाता है, उसे सैन्य अस्पतालों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। इसने परिवेश में संचालित विभिन्न स्थानीय साँफ्टवेयर की कार्यप्रणाली को बदल दिया है और बाडों से डिस्चार्ज करने संबंधी नोट चीफ वार्ड मास्टर (सीडब्ल्यूएम) डिस्चार्ज परेड, संचालन व्यवस्था का सृजन, ओपीडी पंजीकरण इत्यादि जैसी अतिरिक्त कार्य प्रणालियों को जोड़ दिया है। कमान अस्पताल (पश्चिमी कमान) के लिए चिकित्सा स्टोर माड्युल भी विकसित किया गया है।

(च) **आई रीच कार्यक्रम:** भारतीय वायु सेना की पेरीफेरी चिकित्सा सेवाओं में क्षमता निर्माण के लिए तथा स्वास्थ्य देखभाल में वृद्धि हेतु नवाचारपरक कार्यक्रम नामक आई-रीच (सामुदायिक स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए संसाधनों तथा विशेषज्ञों की सहभागिता के साथ) प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम भारतीय वायु सेना की प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा में वृद्धि के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल फिजीशियन के लिए लक्ष्य आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी तथा मौजूदा संचार सुविधाओं पर आधारित हैं।

(छ) **मोबाइल स्वास्थ्य एप ‘मेडवाच’ का शुभारंभ:** भारतीय वायु सेना की 85वीं वर्षगांठ पर “मेडवाच” नामक नवाचार मोबाइल स्वास्थ्य एप लांच किया गया है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा एंड्रॉयड आधारित एप के रूप में विकसित किया गया था। एप में “गोल्डन ऑवर” के दौरान मूल जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने के लिए क्रम वार प्राथमिक सहायता प्रबंधन, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर स्वास्थ्य सूचना तथा वार्षिक चिकित्सा जांच चिकित्सा श्रेणी एवं टीकाकरण के लिए अनुस्मारक टूल, सम्मिलित हैं।

(ज) **संयुक्त औषधि सूची 2016:** वर्ष 2016 से पहले, सेवारत कार्मिकों के लिए सीडीएल (संयुक्त औषधि सूची) और ईईसएचएस लाभार्थियों के लिए ईडीएल (अनिवार्य औषधि सूची) दो पृथक औषधि सूचियां अनुरक्षित की जाती थी। यह अनुभूत किया गया कि सेवारत के लिए सीडीएल और ईसीएचएस के लिए ईडीएल ने अपेक्षित रोगीगण संतुष्टि अर्जित नहीं की है। अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा एएफएमएस अधिप्राप्तिकर्ता एजेंसियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) अनिवार्य चिकित्सा सूचियों (ईएमएल), राष्ट्रीय अनिवार्य औषधि सूचियों (एनएलईएम) और अन्य सरकारी संगठनों से प्राप्त सूचना को ध्यान में रखते हुए अधिकारी बोर्ड (बीओओ) की बैठक आयोजित की गई थी। अब अधिकारी बोर्ड द्वारा एक संयुक्त औषधि सूची (सीडीएल) तैयार की गई है जो डीजीएएफएमएस द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित है।

(VI) **मित्र देशों के लिए विदेशी सहायता प्रदान करना:** 4.30 करोड़ रुपए की मूल्य की चिकित्सा सामग्री मित्र देशों (ताजिकिस्तान सेशलस तथा डोमिनीशिया राष्ट्र) के लिए उपलब्ध करवाई गई है।

(VII) **वर्ष के दौरान क्रियान्वित किए महत्वपूर्ण कार्यक्रम:**

(क) फरवरी, 2017 में पुणे स्थित एएफएमआरसी की 55वीं बैठक के आयोजन के दौरान 8.35 करोड़ रु. की लागत पर 156 अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था।

(ख) **एएफएमआरसी की पूरी हुई परियोजनाएं:** 01 अक्तूबर, 2016 से 30 सितम्बर 2017 तक की अवधि के दौरान सेना चिकित्सा अनुसंधान महाविद्यालय (एएफएमआरसी) की 75 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।

(ग) **नए प्रस्ताव:** प्राप्त हुए 264 नए प्रस्तावों में से सशस्त्र सेना अनुसंधान समिति की 55वीं बैठक में 171 प्रस्तावों को विचारार्थ संस्तुत किया गया है।

(घ) **बाम्बे मेडिकल कांग्रेस:** बाम्बे मेडिकल कांग्रेस का 73वां वार्षिक सम्मेलन आईएनएसएस में 11-12 फरवरी, 2017 को आयोजित किया गया था। उक्त सम्मेलन में 301 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जिसमें समकालीन हित संबंधी विषयों पर विचार करने के लिए मंच और रक्षा तथा सिविलियन डाक्टरों के बीच प्रायः

विचार-विमर्श के लिए आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया था।

(ङ) **वरिष्ठ नौसेना चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा अधिकारियों का 38 वां सम्मेलन:** वर्ष 2017 के लिए वरिष्ठ नौसेना चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा अधिकारियों का 38वां सम्मेलन समुद्रीय औषधि एवं सम्बद्ध विज्ञान के 38वें वार्षिक सम्मेलन के संयोजन से 30 अगस्त, 2017 को मुम्बई में आयोजित किया गया था।

(च) **समुद्रीय औषधि एवं सम्बद्ध विज्ञान का 33 वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन:** समुद्रीय औषधि एवं सम्बद्ध विज्ञान का 33वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन 31 अगस्त, 01 सितम्बर, 2017 को आईएनएसएस में आयोजित किया गया था। 08 मित्र देशों (इंडोनेशिया, यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, कीनिया, ओमान, श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम) की नौसेनाओं के 22 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया था।

(छ) **भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी का 56वां वार्षिक सम्मेलन:** भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी (आईएसएम) का 56वां वार्षिक सम्मेलन 25-27 अगस्त, 2017 को आईएम, भारतीय वायु सेना में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में प्रमुख एरोस्पेस मेडिसिन पेशेवरों और वैज्ञानिकों एरो मेडिकल समस्याओं पर विचार करने तथा उनका निराकरण करने के लिए सहभागिता हेतु अकादमिक मंच उपलब्ध करवाया गया।

(ज) **सेना मेडिसिन, पर 42वां आईसीएमएम विश्व सम्मेलन, नई दिल्ली (19-24 दिसम्बर, 2017):** सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं, भारत ने सेना मेडिसिन पर अन्तर्राष्ट्रीय समिति (आईसीएमएम) के 42वें विश्व सम्मेलन की 19-24 दिसम्बर, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मेजबानी की थी। अन्तर्राष्ट्रीय सेना मेडिसिन समिति (आईसीएमएम) सभी सदस्य देशों की सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के बीच सहयोग और ज्ञान के संबंधों को बनाए रखने और सुदृढ़ करने के प्रमुख मिशन के साथ 1921 में सृजित एक अन्तर्राष्ट्रीय तथा अंतर-सरकारी संगठन है। वर्तमान में 1949 में स्थायी सदस्य के रूप में भारत सहित आईसीएमएम के 112 सदस्य राष्ट्र और छह सहयोग सदस्य राष्ट्र हैं। भारत ने इस प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय समारोह की पहली बार मेजबानी की है।

सम्मेलन में 227 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और 74 देशों के प्रमुख सेना मेडिसिन के विशेषज्ञों सहित कुल 1187 प्रतिनिधियों ने भाग

लिया था। भारत के राष्ट्रपति ने 24 नवम्बर, 2017 को सम्मेलन में समापन भाषण दिया था।

(झ) **स्वच्छ भारत अभियान:** नई जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नीति पर्यावरण मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निरूपित की गई है और सभी यूनिटों को कड़ाई से कार्यान्वयन हेतु अग्रेषित की गई।

(ज) **परिवार कल्याण संगठन:** सशस्त्र सेनाओं में परिवार कल्याण संगठन डीजीएफएमएस के अंतर्गत 139 परिवार कल्याण केन्द्रों के प्राधिकार के साथ 1969 में स्थापित किया गया था। परिवार कल्याण केन्द्र जो सेना, नौसेना, वायु सेना तथा डीजीओएफ के अन्तर्गत विभिन्न सशस्त्र सेना अस्पतालों से सम्बद्ध हैं, वे छावनी क्षेत्रों में सेवारत कार्मिकों और वहां निवासी सिविलियनों को परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

(VIII) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

(क) **मालदीव के साथ रक्षा सहयोग:** 02 चिकित्सा अधिकारियों और 04 पैरामेडिक्स के साथ भारतीय एफएमएस के दल ने माले में 25 बैड वाले सेनहिया एमएनडीएफ हॉस्पिटल की स्थापना और उसकी शुरुआत करने में सहायता के लिए 09 सितम्बर, 2016 को मालदीव राष्ट्रीय रक्षा सेना (एमएनडीएफ) चिकित्सा सेवा में भाग लिया था। चिकित्सा दल को एक वर्ष की अवधि के लिए तैनात किया जाता है।

(ख) **ओमान के साथ रक्षा सहयोग:** सरकार ने ओमान के लिए 03 चिकित्सा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को अनुमोदित किया है। ओमान अताशे से प्राप्त समझौता ज्ञापन का प्रारूप रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ग) **सऊदी अरब के लिए प्रतिनियुक्ति:** हज यात्रा के लिए भारत और दक्षिण एशिया से हज यात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए 9 चिकित्सा अधिकारियों के दल को सऊदी अरब में तैनात किया गया था।

(घ) **भारत-ताजिकिस्तान मित्रता अस्पताल, ताजिकिस्तान:** राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की सिफारिशों और सीओएस के निदेशानुसार क्वाधोन टेप्पा, ताजिकिस्तान में वर्ष 2012 में 50 बैड के स्थायी अस्पताल की स्थापना की गई थी। चिकित्सा दल के दूसरे दल को भारत-ताजिकिस्तान मित्रता

अस्पताल में अगस्त, 2016 में तैनात किया गया था। सरकार ने उक्त दल को 31 जुलाई, 2018 तक की स्वीकृति प्रदान की है।

(ड.) भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे सदभावना रूपी उपायों के रूप में अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश तथा मालदीव जैसे देशों के सशस्त्र सेना कार्मिकों को भारत में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं।

(IX) **विदेशी नागरिकों को चिकित्सा / दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण:** चिकित्सा / दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में विदेशी छात्रों को प्रशिक्षण एफएमएस द्वारा मित्र पड़ोसी देशों द्वारा प्रयोजित किए गए उम्मीदवारों को, इन देशों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर अपने प्रशिक्षण संस्थानों / अस्पतालों में 20 एमडी/एमएस पाठ्यक्रमों और पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों में विदेशी छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

रक्षा संपदा महानिदेशालय

9.13 रक्षा संपदा महानिदेशालय, नई दिल्ली, 62 छावनियों में रक्षा भूमि और नागरिक प्रशासन के प्रबंधन से संबंधित सलाहकार और कार्यपालक का कार्य करता है। यह महानिदेशालय, वर्तमान में जम्मू, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और जयपुर स्थित छह प्रधान निदेशालयों के माध्यम से कार्य करता है। ये प्रधान निदेशालय बारी-बारी से कई फील्ड कार्यालयों जैसे कि 38 रक्षा संपदा कार्यालयों, 03 सहायक रक्षा संपदा कार्यालयों और 62 छावनी बोर्डों जैसे कार्यालयों को देश के चारों ओर फैले छावनी बोर्डों और रक्षा भूमियों के दैनंदिन प्रबंधन का कार्य सौंपता है।

9.14 रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में देश भर में लगभग 17.57 लाख एकड़ रक्षा भूमि है जिसका प्रबंधन तीनों सेनाओं और अन्य संगठनों जैसे कि आयुध निर्माणी बोर्ड, डीआरडीओ, डीजीक्यूए, सीजीडीए आदि द्वारा किया जाता है। सेना के नियंत्रण और प्रबंधन में सर्वाधिक अर्थात् 14.147 लाख एकड़ भूमि है और इसके बाद वायु सेना और नौसेना के पास क्रमशः 1.40 लाख एकड़ और 0.44 लाख एकड़ भूमि है। अधिसूचित छावनियों के अंदर लगभग 1.57 लाख एकड़ रक्षा भूमि है और शेष लगभग 16.00 लाख एकड़ भूमि छावनियों से बाहर है।

9.15 भूमि का ब्यौरा छावनी भूमि प्रबंधन नियमावली (सीएलएआर) 1937 में निर्धारित सामान्य भूमि रजिस्टर

(जीएलआर) में और छावनी में बाहर स्थित रक्षा भूमि का ब्यौरा अधिग्रहण, अभिरक्षा, त्याग (एसीआर) नियमावली, 1944 में निर्धारित सैन्य भूमि रजिस्टर (एमएलआर) में अनुरक्षित होता है। दोनों ही रजिस्टर प्रत्येक रक्षा संपदा कार्यालय सर्किल में रखे जाते हैं। जीएलआर को छावनी बोर्डों के प्रबंधनाधीन स्थित भूमि के लिए भी प्रत्येक छावनी बोर्ड कार्यालय में रखा जाता है। रजिस्टर के अभिलेख में सर्वे संख्या, क्षेत्र कब्जादारी / मालिक का नाम, हस्तांतरण / बिक्री लेनदेन तथा अन्य संक्षिप्त ब्यौरे होते हैं।

9.16 महानिदेशालय ने सभी भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, सर्वेक्षण तथा सभी रक्षा भूमियों का सीमांकन तथा रक्षा भूमि पर नियंत्रण एवं प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया है। सभी रक्षा संपदा कार्यालयों और छावनी बोर्डों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के बारे में जीएलआर और एमएलआर में सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के लिए डीजीडीई द्वारा रक्षा भूमि साफ्टवेयर विकसित किया गया है। रक्षा भूमि की प्रमुख विशेषता यह है कि विभिन्न कार्यालय से संबंधित भूमि आंकड़ों को एक स्थान पर समेकित किया जा सकता है।

9.17 छावनियों की संपूर्ण बाहरी सुरक्षा भूमि का सीमांकन सर्वेक्षण और छावनियों के भीतर रक्षा भूमि का विस्तृत बहुभुज सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है। छावनी बोर्डों और क्रमशः छावनियों के बाहरी और छावनियों के भीतर रक्षा भूमि का लगभग 98.62 प्रतिशत और 99.85 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। कुल रक्षा भूमि की 79.85 प्रतिशत से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया / जारी कर दिया गया है जबकि अन्य भूमि के संबंध में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रक्षा भूमि के 30 प्रतिशत के संबंध में सर्वेक्षण का द्वितीय चरण जारी है।

9.18 राष्ट्रीय स्रोत के रूप में भूमि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए भूमि की लेखा परीक्षा का कार्य भी डीजीडीई को सौंपा गया है। तीन वर्षों की अवधि (2011-12 और 2013-14) और द्वितीय चक्र (2014-15) के प्रथम वर्ष हेतु भू-लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रचारित किया गया है। रक्षा भूमि लेखा परीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 2015-16 हेतु भूमि की लेखा परीक्षा पूरी हो चुकी है और यह रिपोर्ट अंतिम रूप में है। वर्ष 2016-17 हेतु 14 डीईओ सर्किल से संबंधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाधीन है।

9.19 रक्षा भूमि का प्रबंधन भूमि रिकार्डों के उचित रख-रखाव

के लिए आवश्यक रूप से आधार प्रस्तुत करता है। भूमि रिकार्डों का अनुरक्षण, देश में सभी 103 फील्ड कार्यालयों अर्थात् 38 रक्षा संपदा कार्यालयों, 3 सहायक रक्षा संपदा कार्यालयों, 62 छावनी बोर्डों में अत्यधिक संख्या, पर्याप्त भंडारण स्थान की कमी, अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी और पुराने होते दस्तावेजों से संबंधित समस्याओं, आदि के कारण इनके अनुरक्षण और सुरक्षा मानकों से ग्रस्त है। दस्तावेजों के अनुरक्षण और सुरक्षा हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा इन मामलों का समाधान किया जा रहा है। सभी डीईओ कार्यालयों में रिकार्ड कक्षाओं का सुधार (जीर्णोद्धार) और एयू एंड आरसी की स्थापना की कार्रवाईयां पूरी हो चुकी हैं। रिकार्डों की तालिका बनाना, स्कैनिंग और माइक्रो-फिल्मिंग जैसी कार्रवाईयां एक सतत् प्रक्रिया है। इनमें से डीईओ कार्यालयों और छावनी बोर्डों में चरण-I का कार्य पूरा हो चुका है। चरण-II का कार्य प्रक्रियाधीन है। डिजिटाइज्ड दस्तावेजों की माइक्रो-फिल्मिंग का कार्य एक पायलट परियोजना के रूप में डीईओ, सिकंदराबाद द्वारा किया गया है। अन्य डीईओ में एक केन्द्रीयकृत रूप में डिजिटाइज्ड रिकार्डों के माइक्रो-फिल्मिंग कराए जाने का निर्णय लिया गया और जिसके लिए डीजीडीई स्तर पर एक तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) गठित की गई।

9.20 रक्षा संपदा विभाग सशस्त्र सेनाओं के लिए रिहायशी आवासों और भूमि को किराए पर लेने/अर्जित करने का कार्य भी करता है। जम्मू और कश्मीर में अचल सम्पत्ति का अर्जन जे एंड के आरएआईपी अधिनियम, 1968 के अधीन किया जाता है।

9.21 रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय की ओर से छावनियों में नागरिक प्रशासन के नियंत्रण, मॉनीटर और निरीक्षण हेतु उत्तरदायी है। भारत में 62 छावनियां हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित 19 राज्यों में स्थित हैं। छावनी बोर्ड "बॉडी कारपोरेट" होते हैं जो केन्द्रीय सरकार के समग्र नियंत्रण में और छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कार्य करते हैं। छावनी बोर्डों के आधे सदस्य निर्वाचित होते हैं। स्टेशन कमांडर, छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इन निकायों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण और नियंत्रण मध्यवर्ती स्तर पर जनरल आफिसर्स कमांडिंग-इन-चीफ और प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा द्वारा और उच्चतम स्तर पर रक्षा संपदा महानिदेशालय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

9.22 शिक्षा प्रदान करने के लिए छावनी बोर्ड, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और इंटरमीडिएट/कनिष्ठ महाविद्यालय चला रहे हैं। छावनी बोर्डों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और महाविद्यालयों की संख्या 204 है। इसके अतिरिक्त 46 "कौशल विकास केन्द्र", टेलरिंग, एम्ब्रायडरी, ब्यूटीशियन पाठ्यक्रम, स्टैनोग्राफी, सिलाई, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीकल और इलैक्ट्रॉनिक्स और आईटी अनुप्रयोग में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। बोर्डों ने 36 'दिव्यांग बच्चों हेतु केन्द्र' स्थापित किए हैं जो उनकी आवश्यकताओं, जैसे चिकित्सा जांच, परामर्श, फिजियोथेरेपी और विशेष शिक्षा को पूरा करते हैं। छावनी बोर्ड छावनी और नजदीकी क्षेत्रों की सामान्य जनता को विभिन्न चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु 88 अस्पताल और डिस्पेंसरियां चलाई जाती हैं।

9.23 छावनी बोर्ड ने पर्यावरण की सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण, पोलिथिन बैगों पर प्रतिबंध और नगरपालिका सॉलिड कूड़ा प्रबंधन आदि जैसे उपाय किए हैं। सभी छावनियों में 'समाधान' नामक लोक शिकायत निवारण प्रणाली और 'सुविधा' नामक कर्मचारी सूचना प्रणाली भी कार्यान्वित की गई है।

(i) भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत छावनी क्षेत्रों को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। प्रथम कदम के रूप में छावनियों को ओडीएफ (खुला शौच-मुक्त) क्षेत्र घोषित करने हेतु प्रयास किए गए हैं। इसके लिए, स्वच्छता सेवाओं से संबंधित संपूर्ण सिविक अवसंरचना को सुधारा गया है। नई सीवर लाइनें डाली जा रही हैं, एसटीपी (सीवेज परिशोधन संयंत्र) लगाए जा रहे हैं (जहां भी आवश्यक हो), जन शौचालयों की मरम्मत की जा रही है/निर्मित किया जा रहा है, एसडब्ल्यूएम (सॉलिड कूड़ा प्रबंधन) परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, नालों को ढका/अंडरग्राउंड प्रणाली में बदला जा रहा है और गहन सफाई के साथ-साथ व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

(ii) 'डिजिटल इंडिया' पहल के तहत छावनी प्रशासन के विभिन्न पहलुओं से डिजिटल प्लेटफार्मों में बदलने हेतु छावनी बोर्डों ने तेजी से कदम उठाए हैं। सभी छावनी बोर्डों द्वारा अपने प्रशासन को जनता हेतु अधिक उत्तरदायी बनाए जाने के लिए एक ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण प्रणाली 'समाधान' लागू की गई है। बोर्डों द्वारा स्टाफ की शिकायतों के निपटान हेतु एक सॉफ्टवेयर 'सुविधा' भी अधिष्ठापित की गई है। ई-गवर्नेंस

पहल में, छावनी बोर्ड अपने कार्यालयों की प्रक्रिया को सतत् रूप में स्वचालित बना रहे हैं। बोर्डों द्वारा भंडारों की अधिप्राप्ति हेतु जीईएम पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने हेतु कदम उठाए गए हैं। महत्वपूर्ण रिकार्डों, विशेष रूप से भूमि अभिलेखों और अभिलेखों की तालिकाओं की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन पूर्ण हो चुका है। भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु रक्षा भूमि सॉफ्टवेयर के लिए रक्षा भूमि सॉफ्टवेयर को अधिष्ठापित किया गया है। अधिकतर बोर्ड अपने निवासियों को पहले ही कर, जन्म/मृत्यु पंजीकरण, अस्पताल प्रबंधन इत्यादि की ई-सेवाएं पहले ही उपलब्ध करा रहे हैं। ये ऑनलाइन सम्पत्ति कर भुगतान, जल-शुल्क भुगतान, इत्यादि द्वारा ई-सुपुर्दगी सेवा भी मजबूती से प्रदान करता है।

(iii) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान छावनी बोर्डों ने रूफ-टॉप सोलर पैनल से सोलर ऊर्जा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है और इन्हें एलईडी के रूप में बदला गया है। लगभग 48 प्रतिशत मौजूदा स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों में पहले ही बदला जा चुका है और 31 मार्च, 2018 तक ये आंकड़ा 70 प्रतिशत पहुंचने का अनुमान है। जहां तक सोलर ऊर्जा के कार्य का संबंध है, 1368.5 किलोवाट की क्षमता को पहले ही अधिष्ठापित किया जा चुका है जिसके 31 मार्च, 2018 तक 2815 किलोवाट पहुंचने का अनुमान है।

(iv) 21 जून, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी छावनी बोर्डों में बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। छावनी बोर्ड स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके परिवारों ने, अधिकारियों, स्टाफ और सभी वर्ग-समूह के लोगों तथा स्थानीय निवासियों ने इस समारोह में भाग लिया।

(v) छावनी बोर्ड अपने राजस्व में वृद्धि हेतु राजस्व के स्थानीय स्रोतों और छावनियों के निवासियों को कुशल और जिम्मेदारीपूर्ण प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए सभी संभव कदम उठा रहे हैं।

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

9.24 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ) का कार्यालय रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना मुख्यालयों और अंतर-सेवा संगठनों (आईएसओ) के मुख्यालय कार्यालयों को सिविलियन जनशक्ति और अवसंरचनात्मक सहयोग उपलब्ध कराता है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ) संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण)

और मुख्य आसूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) का कार्य भी करते हैं।

9.25 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय निदेशक (ईएंडए) और निदेशक (एचआर) के अंतर्गत निम्नलिखित दस प्रभागों के द्वारा अपना कार्य करता है:-

(क) **जनशक्ति योजना और भर्ती प्रभाग:-** यह प्रभाग सशस्त्र बल मुख्यालय संवर्ग/कॉडर-बाह्य पदों के विभिन्न प्रवर्गों पर भर्ती, अनुकंपा के आधार पर नियोजन, विभिन्न ग्रेडों के भर्ती नियमों को तैयार करना/में संशोधन करना, संवेदनशील संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त की दोबारा जांच, एएफएचक्यू सिविलियन कॉडरों की कॉडर समीक्षा/पुनर्गठन आदि के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2017-18 में यूनियन कैबिनेट के अनुमोदन से एएफएचक्यू सिविल सेवा संवर्ग का पुनर्गठन किया गया, एएफएचक्यू सिविलियन संवर्ग के 10 भर्ती नियमों को संशोधित किया गया और एएफ एचक्यू में 222 नए पदधारियों (59 समूह 'ख' और 163 समूह 'घ') को भर्ती किया गया।

(ख) **कार्मिक और विधिक प्रभाग:-** कार्मिक और विधिक प्रभाग तीनों सेनाओं और 27 अंतर-सेवा संगठनों में तैनात लगभग 200 ग्रेडों में तैनात सिविलियन कार्मिकों की तैनाती/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति सहित संवर्ग प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। यह प्रभाग सीएओ कार्यालय के अदालती मामलों को भी देखता है। वर्ष 2017-18 के दौरान 616 परिवीक्षाधीन कार्मिकों की परिवीक्षा अवधि को समाप्त किया गया; विभिन्न एएफएचक्यू सिविलियन संवर्ग में 528 कर्मचारियों (समूह 'क' 34, समूह 'ख' 318, समूह 'ग' 176) को पदोन्नति प्रदान की गई और एमएसीपी, एएफएचक्यू सिविलियन संवर्ग के 507 कर्मचारियों को वित्तीय लाभ प्रदान किए गए। एफआर 56 (जे) के तहत कुल 346 मामलों की पुनरीक्षा की गई।

(ग) **विभागीय, अनुशासन, समन्वय और कल्याण विभाग:-** यह विभाग एएफएचक्यू सिविलियन कर्मचारियों के अनुशासनात्मक मामलों के साथ समन्वय, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामले, कल्याणकारी कार्यकलाप, जेसीएम, महिला प्रकोष्ठ, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, विभागीय कैंटीनें, एएमए की नियुक्ति, रक्षा सिविलियन चिकित्सा सहायता निधि (डीसीएमएएफ) इत्यादि को देखता है। इसके साथ रक्षा मंत्रालय (पुस्तकालय) का प्रबंधन भी करता है और सैनिकों के मनोरंजन की पठन सामग्री की खरीद हेतु एनडीएफ

अनुदान प्रदान करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान रक्षा मंत्रालय (पुस्तकालय) में 875 किताबों, 156 जनरलों/अवधिकों के अंशों और 36 अखबारों को शामिल किया गया है।

(घ) **रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान (डीएचटीआई):-** डीएचटीआई सेना मुख्यालयों और अंतर-सेवा संगठनों में तैनात सिविलियन कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अधिदेष्टित है। डीएचटीआई संवर्ग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अतिरिक्त तीनों सेना मुख्यालयों और अंतर-सेवा संगठनों के अधिकारियों हेतु अर्द्धि प्राप्ति, आरटीआई, कैबिनेट नोट, संसदीय प्रक्रिया पर विशेष पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान डीएचटीआई द्वारा दिल्ली में 120 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त संपूर्ण देश में फैले यूनिट संवर्गों में 33 पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।

(ङ) **प्रशासन प्रभाग:-** यह प्रभाग सीएओ/ए-2 के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्मिकों को छोड़कर रक्षा मंत्रालय (सेना)/अंतर-सेवा संगठनों में कार्यरत सिविलियन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों, प्रशासनिक कार्यों (चिकित्सा, पेंशन और बजट मामलों को छोड़कर) से संबंधित मामलों का निपटान करता है।

(च) **चिकित्सा पेंशन और बजट प्रभाग:-** यह प्रभाग रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय में कार्यरत सभी सिविलियन कर्मचारियों के चिकित्सा, पेंशन और बजट से संबंधित सभी मामलों का निपटान करता है। यह प्रभाग ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग और सीएओ कार्यालय की वेबसाइट की मरम्मत से संबंधित सभी कार्यों का भी निपटान करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान वर्ष 2016 से पूर्व पेंशन के 4780 पुनर्निर्धारण के मामले प्रक्रियाबद्ध किए गए और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार समयबद्ध रूप से 3849 ई-पीपीओ जारी किए गए।

(छ) **वित्त और सामग्री प्रभाग:-** यह प्रभाग अंतर-सेवा संगठनों को सामग्री प्रबंधन में सहयोग प्रदान करता है जिसमें कार्यालय उपकरण-भंडार, फर्नीचर, लेखन सामग्री और आईटी उपकरणों की अधिप्राप्ति शामिल है। वर्ष 2017-18 के दौरान निगरानी और आगमन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली (एसएसीएमएस) को राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी) और सेना भवन में प्रचालनगत किया गया है।

(ज) **संकार्य प्रभाग:**— यह प्रभाग रक्षा मुख्यालय जोन में कार्यालय आवास नवीनीकरण/रख-रखाव हेतु जवाबदेह है। वर्ष 2012-18 के दौरान डीएचक्यू जोन में बिजली आपूर्ति में वृद्धि के लिए 11 केवीए विद्युत स्टेशन स्थापित किया गया है।

(झ) **क्वार्टर प्रभाग:** यह प्रभाग एएफएचक्यू/अंतर सेवा संगठनों में तैनात सेना के अफसरों को रक्षा मंत्रालय पूल वैवाहिक आवास का आवंटन, किराया आवास के बिलों का भुगतान और एनएसी-एचआरए प्रदान करने तथा उनके प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों का निपटान करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान सेना अधिकारियों को अतिरिक्त 341 आवासीय क्वार्टर जारी किए गए जिसके परिणामस्वरूप प्रतीक्षा अवधि में पर्याप्त रूप से कमी आई है। एएफएचक्यू/आईएसओ में तैनात सेना अधिकारियों का एक विस्तृत डाटा-बेस तैयार किया जा रहा है।

(ञ) **विशेष परियोजना प्रभाग:** यह प्रभाग संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी कार्यालय को सौंपी गई विशेष परियोजनाओं से संबंधित मामलों, जिनमें प्रयोक्ता को सप्रत्ययीकरण कार्रवाई और सौंपा जाना शामिल है। विशेष परियोजनाओं में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय, नौसेना भवन, थलसेना भवन का निर्माण, सेना भवन और साउथ ब्लॉक स्थित निगरानी और आवागमन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली (एसएसीएमएस) के साथ सिविल और इलैक्ट्रिक कार्य की मॉनीटरिंग शामिल है। उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (विशेष परियोजना) भी संपदा अधिकारी के रूप में कार्य करता है।

9.26 वर्ष 2017-18 के दौरान इंडिया गेट के पूर्व में 'सी' हैक्सागन पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निर्माण हेतु शहरी विकास मंत्रालय से एक औपचारिक अनुमति ली गई। शहरी विकास मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय को प्रस्तावित युद्ध संग्रहालय के निर्माण हेतु प्रिंसेस पार्क स्थित 14.173 एकड़ की भूमि आवंटित की। राष्ट्रीय महत्व के दो स्मारकों का निर्माण निर्धारित समय पर पूरा हो जाने की संभावना है।

सुरक्षा कार्यालय

9.27 सुरक्षा कार्यालय रक्षा मुख्यालय सुरक्षा जोन में शामिल 22 भवनों में वास्तविक सुरक्षा प्रदान करने, निगरानी और प्रवेश नियंत्रण, सुरक्षा भंग और अग्निशमन के लिए जिम्मेदार है। यह डीएचक्यू सुरक्षा जोन में सुरक्षा भंग की रोकथाम और अग्निशमन

व्यवस्थाओं की देखभाल हेतु भी जिम्मेदार है।

9.28 वर्ष 2017-18 के दौरान सुरक्षा कार्यालय क्षेत्र में एक छोटा आर्म फायरिंग सिमुलेटर, रक्षा सुरक्षा सैनिकों को फायरिंग अभ्यास उपलब्ध कराने के लिए अधिष्ठापित किया गया है।

जनसम्पर्क निदेशालय

9.29 जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेनाओं तथा रक्षा मंत्रालय के अधीन अंतर-सेवा संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की महत्वपूर्ण घटनाओं, कार्यक्रमों, उपलब्धियों तथा मुख्य नीतिगत निर्णयों के बारे में मीडिया तथा जनता में सूचना प्रसारित करने के लिए एकमात्र प्राधिकृत एजेंसी है। इस निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके देश-भर में 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मीडिया सहायता एवं सेवाएं प्रदान करते हैं ताकि प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके। यह नियमित रूप से साक्षात्कार, प्रेस कान्फ्रेंस और प्रेस दौरे आयोजित करके नेतृत्व और रक्षा मंत्रालय तथा सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विनिमय को भी सुकर बनाता है।

9.30 यह निदेशालय सशस्त्र सेनाओं के लिए 13 भाषाओं में पाक्षिक पत्रिका 'सैनिक समाचार' प्रकाशित करता है। इस निदेशालय का प्रसारण अनुभाग सैनिकों के लिए 40 मिनट का कार्यक्रम तैयार करता है जिसका प्रसारण सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए आकाशवाणी से प्रतिदिन किया जाता है। इसका फोटो अनुभाग रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण घटनाओं की फोटो कवरेज उपलब्ध कराता है। डीपीआर के फोटो अनुभाग के फोटो अभिलेखागार के डिजिटाइजेशन का प्रयास किया जा रहा है।

9.31 गत वर्ष की भांति इस निदेशालय ने मीडिया के लोगों के लिए उनकी रक्षा विषयों के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए 28 अगस्त से 28 सितंबर, 2017 तक रक्षा संवाददाता पाठ्यक्रम का आयोजन किया। संपूर्ण देश से 36 पत्रकारों, जिनमें 11 महिलाएं थीं, ने एक महीने तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम में भाग लिया जो सेना, नौसेना और वायु सेना की विभिन्न स्थापनाओं से संचालित किया गया था।

9.32 इस वर्ष के दौरान जनसंपर्क निदेशालय ने श्रीमती निर्मला सीतारमण के रक्षा मंत्री (आरएम) का कार्यभार ग्रहण करने, फिलिपीन्स में क्लार्क स्थित 'चौथी आसियान रक्षा मंत्रियों'

की बैठक प्लस (एडीएमएम प्लस) में रक्षा मंत्री का शामिल होना, अमेरिकी रक्षा सचिव का भारत दौरा, फ्रांस के रक्षा मंत्री का भारत दौरा, सिंगापुर गणतंत्र का भारत दौरा और अन्य रक्षा मंत्री स्तर के परस्पर क्रियाकलापों सहित विभिन्न घटनाओं की कवरेज उपलब्ध कराई।

9.33 वृहत् नीतिगत निर्णयों, जैसे कि रक्षा मंत्री द्वारा सशस्त्र सेनाओं को पर्याप्त वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, तत्पश्चात् युद्ध हताहतों के निकट संबंधियों को अतिरिक्त अनुग्रह राशि प्रदान करना, गैर-पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं को निर्धनता अनुदान में वृद्धि, भारत में उच्च तकनीकी रक्षा उपस्करों के विनिर्माण हेतु स्वदेशी उद्यम के साथ संबद्धता की रूपरेखा को रक्षा अर्जन परिषद् द्वारा अंतिम रूप देने की मीडिया कवरेज उपलब्ध कराना है। निदेशालय ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली स्थित सैन्य औषधियों पर 42वीं आईसीएमएम वर्ल्ड कांग्रेस के समापन समारोह में राष्ट्रपति के शामिल होने, जिसमें संपूर्ण विश्व के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और मंत्रालय की एजेंसियों द्वारा अन्य आयोजित कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर प्रचारित किया गया।

9.34 वर्ष के दौरान जनसंपर्क निदेशालय ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर युद्ध विवरण की विभिन्न घटनाओं, डीआरडीओ द्वारा “निर्भय” सब-सोनिक क्रूज मिसाइल के सफल फ्लाइंग परीक्षण का आयोजन, टैंक-रोधी निर्देशित मिसाइल ‘नाग’ का सफल फ्लाइंग परीक्षण, स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के साथ सतह से वायु मिसाइल ‘आकाश’ की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग, भारतीय वायु सेना के एसयू-30 एमकेआई युद्धक विमान से ब्रह्मोस के फ्लाइंग परीक्षण में भारत ने इसके भूमि, समुद्र, वायु से रणनीतिक क्रूज मिसाइल परीक्षण को पूरा करने में सफलता पाने, भारतीय वायु सेना के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर लैंडिंग ऑपरेशन, ‘एयरो इंडिया-2017 यूनिफाइड कमांडर्स कान्फ्रेंस’ पर कवरेज उपलब्ध कराया है।

9.35 जनसंपर्क निदेशालय भारत और विदेश, दोनों में अन्य मित्र देशों की सशस्त्र सेनाओं के साथ तीनों सेनाओं द्वारा आयोजित विभिन्न संयुक्त सैन्य अभ्यासों को भी कवर करता है। भारत-रूस रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 19-29 अक्टूबर, 2017 के दौरान रूस के पूर्वी सैन्य जिले में पहली बार भारत और रूसी सशस्त्र सेनाओं ने तीनों रूपों में “अभ्यास इंदिरा-2017” का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया

नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास, 11वां भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास, मालाबार नौसेना अभ्यास को भी प्राथमिकता प्रदान की गई। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक ने पश्चिमी और दक्षिणी तट पर आए चक्रवात ‘ओखी हिट’ में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराई थी। जनसंपर्क निदेशालय ने इन एचएडीआर कार्रवाईयों से जुड़े प्रयासों को प्रचारित किया था।

9.36 निदेशालय गणतंत्र दिवस समारोहों सहित विजय चौक पर समापन समारोह से जुड़ी सभी मीडिया सुविधाओं की व्यवस्था करता है और ‘परेड ऑन राजपथ’ की एक कमेंट्री पुस्तक प्रस्तुत करता है। अन्य महत्वपूर्ण कैलेंडर घटनाएं, जैसे कि राजपथ पर स्वतंत्रता दिवस समारोह, स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा मंत्री का वार्षिक प्रचालित संदेश, संयुक्त कमांडर संगोष्ठी, प्रधान मंत्री की एनसीसी रैली और राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित रक्षा समारोहों को भी तदनुसार प्रचारित किया जाता है।

सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड (एसएससीबी)

9.37 सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड (एसएससीबी) तीनों सेनाओं में विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का आयोजन एवं समन्वय करता है। एसएससीबी के तत्वावधान में 19 खेलों में चार टीमों (आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स) की अंतर-सैन्य चैंपियनशिप आयोजित की जाती है और राष्ट्रीय चैंपियनशिप/खेलों में भाग लेने के लिए सेनाओं की टीम के चयन हेतु 14 खेलों के लिए ट्रायल आयोजित किए जाते हैं।

9.38 वर्ष 2017 के दौरान एसएससीबी ने स्पोर्ट्स फेडरेशन/संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिपों, जिन्हें खेल और युवा मामले मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, में वरिष्ठ पुरुषों की टीम का क्षेत्ररक्षण किया। सैन्य टीमों ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विभिन्न खेलों में पदक जीते।

9.39 वर्ष के दौरान 100 से अधिक सेना के खिलाड़ियों ने वुशु चैंपियनशिप, सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप, एशियन एथलैटिक्स चैंपियनशिप, एशियन कराटे चैंपियनशिप, थाइलैंड ओपन फेंसिंग चैंपियनशिप, एशियन इन्डोर मार्शल आर्ट गेम्स और साइक्लिंग ट्रेक एशिया कप सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिपों में भारत का नेतृत्व किया और 16 स्वर्ण, 9 रजत और 10 कांस्य पदक और ओपन अंतरराष्ट्रीय हैंड बाल चैंपियनशिप में एक टीम ने सिल्वर मैडल जीते।

सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग (एएफएफपीडी) (सेना चित्रण प्रभाग)

9.40 सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग, रक्षा मंत्रालय का एक अंतर-सेवा संगठन है जिसे तीनों सेनाओं के प्रशिक्षण हेतु फिल्म बनाने और प्रोत्साहनपरक उद्देश्यों, जैसे रिकार्ड उद्देश्यों हेतु रक्षा मंत्रालय के समारोह प्रकार्यों और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों की फोटो और वीडियो कवरेज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एएफएफपीडी के पास द्वितीय विश्वयुद्ध की दुर्लभ फिल्मों और फोटो, वर्तमान और अतीत की रक्षा प्रशिक्षण फिल्मों का विशाल संग्रह है।

9.41 एएफएफपीडी ने वर्तमान वर्ष में एआरटीआरएसी (सेना प्रशिक्षण कमांड) के सहयोग से सेना हेतु दस प्रशिक्षण फिल्मों पूरी कर जारी की हैं, 11 प्रशिक्षण फिल्मों निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, 4 पूरी हो चुकी हैं और उपयोगकर्ता के अनुमोदन की प्रतीक्षा में हैं। एक फिल्म संपादन स्तर पर और 6 शूटिंग स्तर पर हैं।

9.42 इस प्रभाग की केन्द्रीय रक्षा फिल्म लाइब्रेरी (सीडीएफएल) विभिन्न यूनिटों/विरचनाओं/प्रशिक्षण स्थापनाओं/कमानों की विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण फिल्मों के वितरण के लिए उत्तरदायी है। यह लाइब्रेरी 35 एमएम साइजों में 587 शीर्षक (पाजिटिव), 543 मास्टर निगेटिव, 16 एमएम साइजों में 1165 शीर्षक, वीएचएस फार्मेट में 225 शीर्षक, यू-मैटिक फार्मेट में 272 शीर्षक, 166 बेटाकैम फार्मेट, वीसीडी फार्मेट में 34 शीर्षक और डीवीडी और एचडी फार्मेट में 89 शीर्षक, 253 एएफवीसी और विश्वयुद्ध-II के 26901 फोटोग्राफ रखती है। वर्ष के दौरान 1579 डीवीडी को विभिन्न सेना/नौसेना/वायुसेना की यूनिटों/विरचनाओं को उधार के रूप में प्रेषित/जारी किया गया है।

9.43 सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग के पास द्वितीय विश्वयुद्ध की दुर्लभ फिल्मों और फोटो हैं जिसे ब्रिटेन से प्राप्त किया गया है और यह अत्यंत ऐतिहासिक महत्व की सामग्री है जिसे इस प्रभाग की केन्द्रीय रक्षा फिल्म लाइब्रेरी में अनुरक्षित और संरक्षित रूप में रखा गया है। ये फोटो और फिल्मों भारतीय सेनाओं को द्वितीय विश्वयुद्ध की विभिन्न रंगशालाओं, इसकी परेडों, समारोहों, व्यक्तियों और प्रशिक्षण गतिविधियों, इत्यादि के दौरान कार्रवाई करते हुए प्रदर्शित करती हैं। यह प्रभाग अनेक अन्य ऐतिहासिक फिल्मों के साथ बैटल ऑफ चाइना, डेजर्ट विकट्री, जेपनीज सरेंडर,

नाजीज़ स्ट्राइक्स, बर्मा कैम्पेन, चर्चिल दि मैन, लंदन विकट्री परेड, इत्यादि जैसी कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों को भी संरक्षित करता है। विश्वयुद्ध-II फिल्मों की कुछ प्रतियां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई), पुणे में संरक्षित हैं।

9.44 इस प्रभाग की मोबाइल सिनेमा यूनिट (एमसीयू) सैनिकों के लिए वृत्त चित्र फिल्मों को भी अधिप्राप्त करती है/वितरित करती है। वर्ष के दौरान एमसीयू ने उधार के आधार पर विभिन्न रक्षा स्थापनाओं को 82 विषयों पर फिल्में जारी की हैं।

राष्ट्रीय रक्षा कालेज

9.45 राष्ट्रीय रक्षा कालेज रक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्था है जो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध-नीति शिक्षा का एक उत्कृष्ट केंद्र है। इस कालेज में प्रशिक्षण के लिए भारतीय और विदेशी सशस्त्र बलों के ब्रिगेडियर/समकक्ष पदधारित तथा प्रशासनिक सेवा के निदेशक और उससे उच्च अफसर नामित किए जाते हैं। एनडीसी के 57वें पाठ्यक्रम में कुल 100 अधिकारी समाविष्ट थे जिनमें सेना (40), नौसेना (6), वायुसेना (12), सिविल सेवा (16), मित्र देशों के (26) अधिकारी शामिल थे। नामित अधिकारियों के ग्यारह माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्य केन्द्र बिंदु राष्ट्रीय सुरक्षा होता है जिसमें घरेलू, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के सभी आयाम शामिल होते हैं जिससे भावी नीति निर्धारकों को राष्ट्रीय रणनीति की योजना बनाने के लिए आवश्यक बहुविध आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य वैज्ञानिक और संगठनात्मक पहलुओं की व्यापक समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि मिल सके। पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन के कैम्पसूल, लेक्चर/पैनल विचार-विमर्श, युद्ध-नीतिक अभ्यास गेम, युद्ध-क्षेत्र भ्रमण, अनुसंधान कार्यकलाप/थीसिस लिखना एवं सेमिनार सम्मिलित हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस पाठ्यक्रम के लिए छह अध्ययन कैम्पसूल आयोजित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत योग्य अधिकारियों को मद्रास विश्वविद्यालय से एम.फिल की डिग्री प्रदान की जाती है। कुछ अधिकारियों ने अपने क्षेत्र और देश में बहुत महत्वपूर्ण पद हासिल किए हैं।

9.46 पाठ्यक्रम के दौरान पाठ्यकृत अधिकारियों को विभिन्न विदेशी प्रतिनिधियों और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उच्च अधिकारियों से परस्पर अंतर-क्रिया का लाभ प्राप्त होता है। 11 अप्रैल, 2017 को महाविद्यालय में पाठ्यक्रम अधिकारियों को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया गया। 12 अप्रैल,

2017 को यूनाइटेड किंगडम के रक्षा राज्य सचिव ने महाविद्यालय का दौरा किया और पाठ्यक्रम अधिकारियों को संबोधित किया।

9.47 राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और सामरिक अध्ययन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भारतीय रक्षा कालेज के बीच संकायों का आदान-प्रदान और संयुक्त सेमिनारों के आयोजन हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। एक प्रमुख रक्षा प्रशिक्षण संस्थान के रूप में महाविद्यालय ने रक्षा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और एशियन क्षेत्रीय फोरम (एआरएफ) के संस्थानों के प्रमुखों की वार्षिक बैठक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया।

इतिहास प्रभाग

9.48 पहले ऐतिहासिक अनुभाग के रूप में जाने जाने वाले इतिहास प्रभाग की स्थापना 26 अक्टूबर, 1953 को स्वतंत्रता के समय से आज तक भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए सैन्य ऑपरेशनों का इतिहास संकलित करने हेतु की गई थी। आज तक इसने जम्मू तथा कश्मीर में ऑपरेशनों का इतिहास 1947-48, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय (गोवा), भारत के सैन्य परिधान, वीरता की कहानियां, 1965 का भारत-पाक युद्ध : एक इतिहास, 1971 का भारत-पाक युद्ध : एक इतिहास और पराक्रम (पीवीसी एवं एसी विजेता) का आख्यान, आदि सहित 18 खंड संकलित व प्रकाशित किए हैं। इस प्रभाग ने द्वितीय विश्वयुद्ध 1939-45 में भारतीय सशस्त्र सेना के आधिकारिक इतिहास को बारह खंडों में पुनर्मुद्रित भी किया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ शांति स्थापना मिशनों में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा चलाए गए ऑपरेशनों के इतिहास को भी प्रकाशित किया गया है। इनमें कांगो में संयुक्त राष्ट्रसंघ ऑपरेशनों में भारतीय सशस्त्र सेनाओं का इतिहास, कोरिया में सीएफआई का इतिहास 1953-54, ऑपरेशन शांति (भारतीय सैनिक मिश्र में) और वृहत् जिम्मेदारी (इंडो-चाइना में शांति के लिए लड़ाई) शामिल हैं। कुछ पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई हैं।

9.49 वर्तमान में यह प्रभाग दो शीर्षकों अर्थात् 'विश्वयुद्ध-1 में भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका' और 'कारगिल युद्ध का इतिहास' पर कार्य कर रहा है। यह प्रभाग रिकार्डों के डिजिटलीकरण में व्यस्त है।

9.50 इतिहास प्रभाग, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अनुसंधान, अभिलेख और संदर्भ कार्यालय के रूप

में भी कार्य करता है। इसे रक्षा मंत्रालय, तीनों सेना मुख्यालयों, सैन्य मामलों से संबंधित विविध अभिलेख और संक्रियात्मक अभिलेख नियमित आधार पर संरक्षण तथा इस्तेमाल के लिए प्राप्त होते हैं। यह प्रभाग रेजिमेंटल इतिहासों और सैन्य इतिहास से संबंधित हस्तलिपियों की, प्रकाशन से पूर्व जांच करता है। यह प्रभाग फैंलोशिप स्कीम भी संचालित करता है जिसके तहत सेना इतिहास में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक तीन वर्षों में फैंलोशिप प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत अब तक दो अनुसंधान अध्येताओं को लाभान्वित किया गया है।

9.51 इस प्रभाग का हेराल्डिक प्रकोष्ठ तीनों सेना मुख्यालयों और तटरक्षक तथा रक्षा मंत्रालय को समारोह संबंधी सभी मामलों, जैसे नई स्थापनाओं के नामकरण और अधिग्रहण, बैजों और कलगियों का डिजाइन बनाने और स्मृति चिन्हों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। यह प्रकोष्ठ भारतीय वायु सेना के इतिहासों की समीक्षा भी करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा रंगों और मानकों के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

9.52 विभागीय पुस्तकालय में कुछ दुर्लभ पुस्तकें, आवधिक पत्रिकाएं और सैन्य महत्व के विदेशी प्रकाशनों सहित पांच हजार से अधिक पुस्तकें हैं। पिछले एक वर्ष में पुस्तकालय में 150 और पुस्तकें आई हैं।

रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय (सीडीएम)

9.53 सीडीएम त्रि-सेना प्रशिक्षण स्थापना है जो तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों, अर्ध-सैनिक बलों, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को संकल्पनात्मक, निर्देशात्मक और कार्यात्मक स्तरों पर ज्ञान केंद्रित वातावरण में उन समकालीन प्रबंधन विचारों, अवधारणाओं तथा व्यवहारों, जिनसे प्रभावी निर्णय लेना तथा दक्ष संसाधन पबंधन होता है, में कौशल प्रदान करता है। उच्च रक्षा पबंधन पाठ्यक्रम (एचडीएमसी) वह फ्लैगशिप पाठ्यक्रम है जिसे 44 सप्ताहों की अवधि के लिए चलाया जाता है। एचडीएमसी के अतिरिक्त, सीडीएम सार्क देशों के लिए अनेक प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी), रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम तथा त्रि-सेनाओं के भागीदारों और मित्र देशों के भागीदारों के लिए वरिष्ठ रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम (एसडीएमसी) संचालित करता है। यह कालेज अत्याधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित नेटवर्क वातावरण के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करता है।

9.54 सीडीएम ने 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017

तक मेजर जनरल और समकक्ष रैंक के अधिकारियों के लिए एक उच्च रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम, दो वरिष्ठ रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम, नौ प्रबंधन विकास कार्यक्रम और एक संयुक्त सक्रियात्मक पुनरीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन किया। महाविद्यालय ने बाहरी कैम्पूल के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय सहित उच्च शिक्षा के विभिन्न संस्थानों पर 1350 अधिकारियों को रक्षा प्रबंधन जानकारी प्रदान करने के अतिरिक्त तीनों सेनाओं सहित वीआरओ, पीएमएफ और सरकारी संगठनों के 550 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

9.55 2016 से सीडीएम वांछित 'ए+' ग्रेडिंग के साथ 5200 एनएएससी प्रमाणित संस्थानों में से टॉप 60 में आता है। महाविद्यालय 'नेट मूल्यांकन' की विधाओं में एक उत्कृष्ट केन्द्र है। सीडीएम "परियोजना प्रबंधन" में आईएमपीए प्रमाण-पत्र हेतु भारतीय सशस्त्र सेनाओं हेतु एकमात्र प्रमाणित प्रशिक्षण संगठन (एटीओ) है। महाविद्यालय भारतीय सैन्य सेवा में "डाटा मूल्यांकन और विज्युलाइजेशन" प्रशिक्षण प्रदान करने में भी अग्रणी है।

9.56 वर्ष 2017-18 में सीडीएम में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत द्वीपों के 21 देशों के सैन्य अधिकारियों (कर्नल और समकक्ष) सहित शिक्षा प्रदान की है जिसका एक वृहत् अंतर्राष्ट्रीय स्तर है।

रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय

9.57 रक्षा सेवा स्टाफ कालेज (डीएसएससी), तमिलनाडु में नीलगिरि के परिसर में स्थित विश्व का एकमात्र प्रीमियर त्रि-सेना संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान है जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं, सिविल सेनाओं/अर्ध-सैनिक बलों और मित्र देशों के चयनित अफसरों

को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। यह स्टाफ कालेज, विशिष्ट व्यावसायिकता स्तर तथा "ड्यूटी ऑनर ऑफ वेल्थ" के सद्गुण को दृढ़ता से परिपुष्ट करके सशस्त्र सेनाओं के उन्नत स्तर पर श्रेष्ठ स्टाफ अधिकारियों और तारकीय नेतृत्वकारियों का सृजन करते हुए मध्यम स्तर के सैन्य अधिकारियों हेतु अवलंब के रूप में सेवारत परिपुष्ट वातावरण देता है।

9.58 डीएसएससी को श्रेष्ठ विश्व-स्तरीय स्टॉफ और कमान प्रशिक्षण देने वाले एक फ्लैगशिप संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान के रूप में प्रदान की गई सराहनीय सेवा के मान्यतास्वरूप राष्ट्रपति द्वारा सितंबर, 2016 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

9.59 यह स्टाफ कालेज, वर्तमान में आधारभूत विकास सहित असमानान्तर विस्तार की नवचेतना का अनुभव प्राप्त कर रहा है जो इस शानदार संस्थान के बहु-फलकीय दैदीप्यमान को सुयोजित करती है। यह कालेज स्वयं 500 छात्र अफसरों को प्रशिक्षण प्रदान कर उत्तरोत्तर स्फूर्ति दे रहा है। वर्तमान स्टाफ पाठ्यक्रम की संख्या बढ़ाकर 466 की गई है जिसमें सिविल सेवाओं/अर्धसैनिक बलों से तीन अफसर, तटरक्षक से 2 अफसर और 31 विभिन्न देशों से 36 अंतर्राष्ट्रीय अफसर शामिल हैं।

रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

9.60 रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय, तीनों सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों और अन्य संबद्ध रक्षा स्थापनाओं में योजना एवं नीति निर्धारण से संबंधित विषयों पर साहित्य उपलब्ध करवाता है। सामान्य पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा इसे रक्षा तथा संबद्ध विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त है। वर्ष के दौरान इस पुस्तकालय ने 875 पुस्तकें खरीदीं और 156 पत्रिकाएं/आवधिक पत्रिकाएं तथा 36 समाचार-पत्र मंगवाए।



भर्ती एवं प्रशिक्षण





भर्ती एवं प्रशिक्षण

10.1 सशस्त्र बलों ने हमेशा से ही देश के प्रति सेवा, बलिदान, देशभक्ति और समग्र संस्कृति के आदर्शों को अपने में संजोया है। सशस्त्र बलों में भर्ती स्वैच्छिक है और यह भारत के सभी नागरिकों के लिए खुला है, जो किसी एक जाति, वर्ग, धर्म और समुदाय के आधार पर नहीं है, बल्कि निर्धारित शारीरिक, चिकित्सा और शैक्षिक मानदंडों को पूरा करने के आधार पर होती है।

10.2 **यूपीएससी के माध्यम से सशस्त्र बलों में कमीशन अधिकारियों की भर्ती:** सशस्त्र बलों में कमीशन अधिकारियों की मुख्य रूप से यूपीएससी के माध्यम से भर्ती की जाती है, और यूपीएससी इस हेतु निम्नलिखित दो अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं का आयोजन करता है:

(क) **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और नौसेना अकादमी (एनए):** एनडीए और एनए में प्रवेश के लिए यूपीएससी वर्ष में दो बार प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। 10+2 परीक्षा पास कर चुके या फिर 12वीं कक्षा अध्ययन कर रहे उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने के लिए

पात्र हैं। यूपीएससी लिखित परीक्षा में सफल होने पर, पात्र उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के साक्षात्कार से गुजरना होता है, जो पाँच दिनों तक चलता है। आवेदन करने के समय उपयोग किए गए सेवा के विकल्प के अनुसार, चिकित्सकीय रूप से फिट (स्वस्थ) होने और एनडीए योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) में आने पर, सफल उम्मीदवार एनडीए या एनए में शामिल होते हैं। प्रशिक्षण की पूर्णता पर, उन्हें संबन्धित सेवा अकादमियों में उनके प्री-कमीशन प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

(ख) **संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई):** यूपीएससी द्वारा वर्ष में दो बार सीडीएसई परीक्षा आयोजित की जाती है। विश्वविद्यालय के स्नातक या स्नातक के अंतिम वर्ष के छात्र परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र होते हैं। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को एसएसबी साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षाओं से गुजरना होता है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को एसएसबी साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षाओं से गुजरना होता है। योग्यता सूची में आने वाले योग्य उम्मीदवारों को भारतीय सैन्य

अकादमी/वायु सेना अकादमी और नौसेना अकादमी में 18 महीने और स्थायी कमीशन के लिए 11 महीनों के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स (लघु सेवा आयोग अधिकारी) (एसएससीओ) बनने हेतु प्रशिक्षण से गुजरना होता है। एसएससीओ की सेवा 10 वर्षों की अवधि के लिए हटी है जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, वे 10 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के बाद स्थायी आयोग का चयन कर सकते हैं या पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद छोड़ सकते हैं, जिसे रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय द्वारा मामले के आधार पर विचार/स्वीकृत किया जाता है।

भारतीय सेना

10.3 यूपीएससी के माध्यम से भर्ती के अलावा, कमीशन अधिकारियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों के माध्यम से भी सेना में भर्ती की जाती है:

(क) **10+2 तकनीकी प्रवेश योजना (टीईएस):** भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में न्यूनतम कुल 70% अंकों के साथ 10+2 सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार 10+2 (टीईएस) के तहत कमीशन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। एसएसबी में सफल होने और चिकित्सा बोर्ड द्वारा फिट घोषित होने पर, वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, गया में एक वर्ष के मूल सैन्य प्रशिक्षण से गुजरते हैं और इसके बाद स्थायी आयोग में जाने से पूर्व संबंधित क्षेत्रों में तीन वर्ष की इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं। कमीशन किए जाने पर, आगे उन्हें एक वर्ष तक उस शाखा/सेवा हेतु कमीशनिंग प्रशिक्षण में रखा जाता है, जिसमें उन्हें कमीशन/प्रमाणित किया गया है।

(ख) **विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यूईएस):** अधिसूचित इंजीनियरिंग विषयों में पूर्व-अंतिम वर्ष के विद्यार्थी यूईएस के तहत कमीशन अधिकारी के रूप में सेना के तकनीकी बलों में स्थायी कमीशन हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। सेना मुख्यालय द्वारा नियुक्त स्क्रीनिंग टीमों द्वारा योग्य उम्मीदवारों को कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से चुना जाता है। इन उम्मीदवारों को एसएसबी और चिकित्सा बोर्ड के सामने पेश होना आवश्यक होता है। सफल उम्मीदवारों को भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए), देहरादून में एक वर्ष का प्री-कमीशन प्रशिक्षण पूर्ण करना होता है। इस प्रवेश के माध्यम से कैडेट कमीशनिंग पर एक वर्ष पूर्व-तारीख वरिष्ठता के भी हकदार बन जाते हैं। हालाँकि, इस प्रवेश के लिए

चयन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।

(ग) **तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टीजीसी):** इंजीनियरिंग के अधिसूचित पाठ्यक्रम से इंजीनियरिंग स्नातक, जो कम से कम दूसरी श्रेणी में स्नातकोत्तर हों, सेना शिक्षा कोर और एमएससी कृषि/डेयरी फॉर मिलिट्री फार्म में अधिसूचित पाठ्यक्रम में इस प्रवेश के माध्यम से स्थायी कमीशन के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। एसएसबी और चिकित्सा बोर्ड के बाद, चयनित उम्मीदवारों को आईएमए, देहरादून में एक वर्ष प्री-कमीशन प्रशिक्षण से गुजरना होता है। इस प्रवेश के माध्यम से इंजीनियरिंग स्नातक कमीशनिंग पर एक वर्ष पूर्व-तारीख वरिष्ठता के हकदार भी बन जाते हैं।

(घ) **शॉर्ट सर्विस कमीशन (तकनीकी) प्रवेश:** शॉर्ट सर्विस कमीशन (तकनीकी) प्रवेश योजना योग्य तकनीकी स्नातकों/स्नातकोत्तरों को तकनीकी बलों में भर्ती के लिए अवसर प्रदान करता है। एसएसबी और चिकित्सा बोर्ड के बाद, चयनित उम्मीदवारों को ओटीए, चेन्नई में करीब 49 सप्ताह प्री-कमीशन प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर, उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल किया जाता है। इस प्रवेश के माध्यम से कैडेट्स कमीशनिंग पर एक वर्ष की पूर्व-तारीख वरिष्ठता के भी हकदार बन जाते हैं।

(ङ) **एनसीसी (विशेष प्रवेश योजना):** न्यूनतम 'बी' ग्रेड के साथ एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारक विश्वविद्यालय के स्नातक और जो स्नातक परीक्षा में 50% कुल अंक पाने वाले इस प्रविष्टि के माध्यम से शॉर्ट सर्विस कमीशन हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तीसरे वर्ष में अध्ययनरत छात्रों को आवेदन करने की अनुमति है, बशर्ते उन्होंने पहले दो वर्षों में न्यूनतम 50% सकल अंक हासिल किए हों। ऐसे उम्मीदवारों को तीनों वर्षों को मिलाकर समग्र तौर पर कम से कम 50% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में चुने जाने पर भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवारों के पास ओटीए में शामिल होने के समय स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या तीसरे वर्ष में अध्ययनरत उम्मीदवारों को ओटीए में प्रशिक्षण शुरू होने की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर डिग्री हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। उम्मीदवारों को ओटीए, चेन्नई में लगभग 49 सप्ताह का प्री-कमीशन प्रशिक्षण पूर्ण करना होता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर, उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल किया जाता है।

(च) **शॉर्ट सर्विस कमीशन (न्यायाधीश अधिवक्ता सामान्य प्रवेश):** एलएलबी में न्यूनतम 55% अंकों के साथ लॉ ग्रेजुएट, जिनकी उम्र 21 से 27 वर्ष के बीच है, न्यायाधीश अधिवक्ता सामान्य शाखा के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों को सीधे एसएसबी साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया जाता है। सफल उम्मीदवारों को ओटीए चेन्नई में करीब 49 सप्ताह के प्री-कमीशन प्रशिक्षण पूर्ण करना होता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर, उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल किया जाता है।

(छ) **शॉर्ट सर्विस कमीशन (लघु सेवा आयोग) महिला (एसएससीडब्लू):** पात्र महिला उम्मीदवारों को भी सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में भर्ती किया जाता है। कमीशन कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, कोर ऑफ इंजीनियर्स, सिग्नल, आर्मी एजुकेशनल कोर, मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, आर्मी सप्लाइ कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और आर्मी एयर डिफेन्स में प्रदान किया जाता है। महिलाओं को तीन पाठ्यक्रमों में शॉर्ट सर्विस कमीशन की पेशकश की जाती है, नामतः गैर-तकनीकी स्नातक, दस वर्ष की अवधि के लिए तकनीकी और स्नातकोत्तर / विशेषज्ञ, जो अतिरिक्त चार वर्षों से स्वैच्छिक आधार पर बढ़ाई जा सकती है। 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद सेना और जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन का विकल्प भी है। ट्रेनिंग की अवधि 49-सप्ताह की है जो अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रदान की जाती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला (तकनीकी) प्रवेश के लिए बी.ई./बी.टेक के या अधिसूचित संकायों में अंतिम वर्ष/सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र आवेदन करने के लिए पात्र हैं। चयनसूची में आए उम्मीदवारों को एसएसबी में साक्षात्कार और उसके उपरांत चिकित्सकीय जाँच के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, गैर-तकनीकी स्नातक स्ट्रीम के लिए आवेदकों का चयन यूपीएससी के माध्यम से किया जाता है और लिखित परीक्षा के बाद उन्हें एसएसबी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। गैर-तकनीकी धारा से कुल 20% आबंटित सीटें न्यूनतम 'बी' ग्रेड के साथ एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारक महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं, साथ ही उनके पास स्नातक परीक्षा में 50% सकल अंक होने चाहिए। जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के लिए विधि स्नातकों से, जो न्यूनतम 55% सकल अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रक्षा कर्मियों की विधवाएं जो निर्धारित-योग्यता मानदंडों को पूरा करती हैं, उन्हें आयु सीमा

में चार वर्ष की छूट दी जाती है, और प्रत्येक पाठ्यक्रम की 5% सीट (तकनीकी और गैर- तकनीकी धारा में प्रत्येक 2.5) उनके लिए आरक्षित होती हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला (तकनीकी), एनसीसी प्रवेश और जज एडवोकेट जनरल ब्रांच को लिखित परीक्षा से छूट प्रदान की गई है।

(ज) **सेवा प्रवेश:** अधिकारी कैडर में जूनियर कमीशन अधिकारी और अन्य रैंकों की भर्ती सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से निम्नलिखित में की जाती है:

(i) **सेना कैडेट कॉलेज (एसीसी) प्रवेश:** 20 से 27 वर्ष की आयु वर्ग और न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा में योग्य अन्य रैंक (ओआर), 10+2 उत्तीर्ण योग्यता वाले नियमित कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैन्य प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद, उम्मीदवारों को एसएसबी और चिकित्सा बोर्ड द्वारा जाँच की जाती है। सफल उम्मीदवारों को तीन वर्ष के लिए आर्मी कैडेट कॉलेज विंग, देहरादून में प्रशिक्षित किया जाता है, जिसके अंत में वे स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं। इसके बाद आईएमए, देहरादून में एक वर्ष की अवधि हेतु उन्हें प्री-कमीशन प्रशिक्षण पूर्ण करना होता है।

(ii) **विशेष कमीशन अधिकारी (एससीओ) योजना:** इस प्रवेश के तहत 28 से 35 वर्ष की आयु समूह के जेसीओ/एनसीओ/ओआर, जो सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट उत्तीर्ण (कक्षा 10+2 पैटर्न) हैं, वे एसएसबी और चिकित्सा बोर्ड के उपरान्त परमानेंट कमीशन के लिए पात्र हैं। उन्हें ओटीए, गया में एक वर्ष का प्री-कमीशन प्रशिक्षण पूर्ण करना होता है। बाद की पदोन्नति और कार्यकारी पदोन्नति के नियम नियमित अधिकारी के समान ही हैं। ये अधिकारी सब यूनिट कमांडर / क्वार्टर मास्टर के रूप में इकाइयों में कार्यरत होते हैं और मेजर के रैंक तक विभिन्न अतिरिक्त रेजीमेंटों के कार्यों में नियुक्तियों पर कार्यरत हैं। लगभग 20 से 25 वर्षों की अवधि की सेवा करने उपरांत वे 57 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह योजना मौजूदा जेसीओ और ओआर कैरियर की संभावनाओं में सुधार ही नहीं करती है, बल्कि सेना में समर्थन कैडर अधिकारियों की

कमी को पूरा करने में भी मदद करती है।

- (iii) **परमानेंट कमीशन (विशेष सूची) (पीसी एसएल):** इस प्रवेश के अंतर्गत, एससीबी और चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्क्रीनिंग के बाद एक सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट पास (कक्षा 10+2 पैटर्न) योग्यता वाले, जेसीओ/एनसीओ/ओआर 42 वर्ष की आयु तक और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के साथ इस कमीशन के लिए पात्र हैं। आईएमए में चार सप्ताह के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद उन्हें परमानेंट कमीशन (विशेष सूची) प्रदान किया जाता है।

10.4 अधिकारी प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रियाओं का स्वचालन: ऑनलाइन प्रक्रियाएं जो पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करने तक सीमित थीं, इसे अब उन्नत कर दिया गया है। उम्मीदवार अब पाठ्यक्रम की सूचनाएं देख सकते हैं, आवेदन जमा कर सकते हैं (यूपीएससी और सर्विस प्रवेश को छोड़कर), एसएसबी तारीखों का चयन कर सकते हैं (यूपीएससी प्रविष्टियों सहित), योग्यता सूचियों को देख सकते हैं, नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं, पूछताछ/फीडबैक ले सकते हैं तथा प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया में हर स्तर पर चयन प्रक्रिया का अपडेट भी देख सकते हैं।

10.5 प्रवेश संख्या: वर्ष 2017 के दौरान अधिकारियों के रूप में प्री-कमीशन प्रशिक्षण के लिए प्रवेश दिये गए उम्मीदवारों की संख्या को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 10.1

क्र.सं.	अकादमी	प्रविष्टि	प्रवेश
1.	एनडीए	सेना	417
		नौसेना	97
		वायु सेना	115
		कुल	629
2.	आईएमए	आईएमए (डीई)	203
		एसीसी	107
		एससीओ	39
		पीसी (एसएल)	19
		ईसीसी	14
		कुल	382

क्र.सं.	अकादमी	प्रविष्टि	प्रवेश
3.	ओटीए	एसएससी (एनटी)	135
		एसएससीडब्लू (एनटी)	19
		एनसीसी	75
		एनसीसी (डब्ल्यू)	09
		जे ए जी	11
		जे ए जी (डब्ल्यू)	12
		कुल	261
4.	तकनीकी प्रविष्टियां	एसएससी (तकनीकी)	214
		एसएससीडब्लू (टेक)	40
		10 + 2 टीईएस	178
		टी जी सी	69
		कुल	501
		कुल योग	1773

10.6 जूनियर कमीशन ऑफिसर (जेसीओ) और अन्य रैंक (ओआर) की भर्ती: सेना में नियुक्ति क्षेत्रीय भर्ती कार्यालयों, दो गोरखा भर्ती डिपो, एक स्वतंत्र भर्ती कार्यालय और 59 सेना भर्ती कार्यालयों के अलावा 48 रेजिमेंटल केंद्रों के माध्यम से किया जाता है जो अपने अधिकार क्षेत्र के संबंधित क्षेत्रों में सेना भर्ती रैलियों के माध्यम से भर्ती करते हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर और अन्य रैंकों की भर्ती जैसे सैनिक जनरल ड्यूटी, सैनिक व्यापारी, सैनिक तकनीकी, सैनिक क्लर्क/स्टोर कीपर व्यापार और सैनिक नर्सिंग सहायक, हवलदार शिक्षा, हवालदार ऑटो कार्टोग्राफर और धार्मिक शिक्षक जेसीओ (आरटी जेसीओ), जेसीओ कैटरिंग श्रेणियों के लिए भर्ती ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के माध्यम से की जाती हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और अन्य रैंकों की मौजूदा भर्ती में इच्छुक उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के तहत 1.6 किमी की दौड़ शामिल है, जिसके बाद दस्तावेज की जाँच, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण (पीएफटी), शारीरिक मापन परीक्षण (पीएमटी) और चिकित्सकीय (मेडिकल) परीक्षा शामिल हैं। इसके बाद उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक लिखित परीक्षा होती है, जो उपरोक्त सभी परीक्षणों में योग्य पाये गए हैं। अंत में, एक योग्यता सूची तैयार की जाती है और पत्र उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए संबंधित रेजिमेंटल/प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जाते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में

देश के प्रत्येक जिले को वर्ष में कम से कम एक बार शामिल किया गया है।

10.7 **संशोधित भर्ती रैली प्रणाली:** भारतीय सेना देश में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, जो प्रत्येक वर्ष लगभग 60,000 युवाओं को सेना में शामिल करता है। इससे पहले, भर्ती एक 'ओपन रैली प्रणाली' के माध्यम से की जाती थी जिसमें उम्मीदवार रैली के लिए आवेदन किए बिना भर्ती में भाग ले सकते थे। अब रैलियों में लोगों की भारी भीड़ को कम करने के उद्देश्य से 'संशोधित भर्ती प्रणाली' शुरू की गई है जिसमें उम्मीदवार को ऑनलाइन पंजीयन करने की जरूरत होती है, और उन्हें एक विनियमित कॉल-अप सिस्टम द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस प्रकार बड़ी भीड़ के कारण उठने वाले प्रशासनिक और अनुशासन संबंधी समस्याओं को भी दूर किया गया है। अभी तक, ऐसी 225 रैलियाँ 'संशोधित भर्ती प्रणाली' के माध्यम से आयोजित की गई हैं और लगभग 55 लाख उम्मीदवारों ने भर्ती निदेशालय की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया है। संशोधित भर्ती रैली प्रणाली निम्नलिखित चरणों में कार्यान्वित की जा रही है:

(क) **चरण-I: कॉल अप सिस्टम के साथ खुली रैली प्रणाली का प्रतिस्थापन:** भारतीय सेना में जूनियर कमीशन अधिकारियों/अन्य रैंकों की भर्ती के लिए ऑन लाइन पंजीकरण को 18 जुलाई, 2015 से कार्यान्वित किया गया है जो बहुत ही सफल रहा है, और जिसने पूरी भर्ती प्रक्रिया में क्रांति ला दी है। इस पहल ने हमारी भर्ती प्रणाली को सुव्यवस्थित किया है और सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया है क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों/ ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवार इस लोकप्रिय कैरियर विकल्प के लिए आवेदन करने हेतु इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं।

(ख) **चरण-II: शारीरिक और चिकित्सा परीक्षणों से पहले ऑनलाइन परीक्षा हेतु पायलट प्रोजेक्ट:** ऑनलाइन परीक्षा के लिए पायलट प्रोजेक्ट को हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है और यह परियोजना कार्यान्वयन हेतु प्रक्रियाधीन है। एक बार कार्यान्वित की जाने के उपरांत यह सबसे प्रमुख उपलब्धि होगी। प्रारंभ में पायलट परियोजना को तीन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है और इसके बाद में अखिल भारत स्तर पर कार्यान्वित किया जाएगा:

- (i) मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, अंबाला
- (ii) मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, चेन्नई
- (iii) मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, जयपुर

10.8 **भर्ती रैलियाँ:** भर्ती वर्ष 2016-17 में कुल 52447 उम्मीदवार भर्ती किए गए हैं। भर्ती वर्ष 2017-18 के लिए 100 रैलियों की योजना बनाई गई थी।

भारतीय नौसेना (आईएन)

10.9 जहाजों, पनडुब्बियों, विमान को प्रभावी रूप से संभालने और तटीय प्रतिष्ठानों को इष्टतम स्तर तक देखरेख के लिए भारतीय नौसेना कर्मियों की भर्ती संचालित करती है। नौसेना में भर्ती अखिल भारत आधार पर की जाती है। वर्दीधारी कर्मियों को भर्ती / शामिल किए जाने की संख्या योग्य आवेदकों (पुरुष और महिला) की संख्या पर निर्भर करती है जो लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, उन्हें सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) साक्षात्कार, मेडिकल परीक्षा और योग्यता सूची में उनकी सापेक्ष स्थिति के अनुसार होती है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अथवा इसके उपरांत, लिंग, धर्म / जाति / पंथ के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता है।

10.10 **भर्ती की पद्धति:** भारतीय नौसेना की भर्ती प्रणाली एक सुव्यवस्थित, पारदर्शी, शीघ्र और उम्मीदवार अनुकूल प्रक्रिया है। भारतीय नौसेना में दो प्रकार के प्रवेश होते हैं, अर्थात् यूपीएससी प्रवेश और गैर-यूपीएससी प्रवेश।

(क) **यूपीएससी प्रवेश:** यूपीएससी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) में परमानेंट कमीशन (पीसी) प्रवेश के रूप में प्रवेश के लिए वर्ष में दो बार परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। उम्मीदवार 10+2 (पीसीएम) परीक्षा के पूर्ण किया या 12वीं कक्षा में अध्ययनरत इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। लिखित परीक्षाओं के बाद उम्मीदवारों की सूची यूपीएससी द्वारा तैयार की जाती है। इसके बाद, उम्मीदवारों को बेंगलुरु, भोपाल, कोयम्बटूर और विशाखापत्तनम स्थित सेवा चयन बोर्डों में भेजा जाता है। अंतिम योग्यता के लिए पात्र उम्मीदवारों के परिणाम यूपीएससी को भेजे जाते हैं। मेडिकल फिट उम्मीदवारों का, जो पात्र हैं, एनडीए/ नौसेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाता है। एनडीए/आईएनए प्रशिक्षण पूर्ण होने पर, नौसेना कैडेट को

नौसेना समुद्र के प्रशिक्षण के लिए कोच्चि में जहाजों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। ग्रेजुएट स्पेशल एंट्री स्कीम (जीएसईएस) के लिए, यूपीएससी वर्ष में दो बार संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) आयोजित करती है। बी टेक डिग्री या बी टेक के स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र हैं। सफल उम्मीदवार नौसेना उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम (एनओसी) के लिए नौसेना अकादमी में शामिल होते हैं।

(ख) **गैर-यूपीएससी प्रवेश:** गैर-यूपीएससी प्रवेश परमानेंट कमीशन (पीसी) और शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) दोनों की जरूरतों को पूरा करती हैं। इस मामले में, योग्यता परीक्षा में प्रतिशत के आधार पर रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के आईएचक्यू द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। सूचीबद्ध उम्मीदवार तब साक्षात्कार के लिए एसएसबी भेजे जाते हैं। इसके बाद, योग्य उम्मीदवारों की योग्यता सूची को रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार तैयार किया जाता है।

(ग) **10+2 (कैडेट प्रवेश योजना):** यह योजना भारतीय नौसेना के कार्यकारी, इंजीनियरिंग और विद्युत शाखाओं में परमानेंट कमीशन प्रवेश के लिए है। इस योजना के अंतर्गत, 10+2 (पीसीएम) योग्यता वाले उम्मीदवारों को, सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयन के बाद, बी.टेक कोर्स के लिए भारतीय नौसेना अकादमी भेजा जाता है। पाठ्यक्रम के सफल समापन पर उन्हें नौसेना के कार्यकारी, विद्युत और इंजीनियरिंग शाखाओं में परमानेंट कमीशन प्रदान किया जाता है।

(घ) **विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यूईएस):** यूईएस को अगस्त, 2005 में एक शॉर्ट सर्विस कमीशन योजना के रूप में पुनः प्रारम्भ किया गया था। इंजीनियरिंग कॉलेज के सातवीं और आठवीं सेमेस्टर के छात्र नौसेना के कार्यकारी और तकनीकी शाखाओं में शामिल होने के लिए पात्र हैं। वर्ष 2014 से यह योजना परमानेंट कमीशन के कार्यकारी अधिकारियों की स्थापना के लिए भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के आईएचक्यू से नौसेना चयन दल और कमान मुख्यालय, पूरे देश में एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों का दौरा उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए करते हैं। अखिल भारत स्तर पर योग्यता के आधार पर सूचीबद्ध उम्मीदवारों का सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार लिया जाता है। उसके बाद, सफल उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षाओं से गुजरना होता है। अखिल भारत स्तर पर अंतिम चयन सूची एसएसबी साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और रिक्तियों की

उपलब्धता के आधार पर तैयार की जाती है।

10.11 **महिला अधिकारी:** महिलाओं को नौसेना में शामिल किया जा रहा है, जो कार्यकारी पर्यवेक्षक (पर्यवेक्षक, पायलट इन मैरिटाइम रिसोन्सेंस स्ट्रीम, नेवल आर्ममेंट इंस्पेक्टर कैडर, एयर ट्रेफिक कंट्रोलर (एटीसी), लॉ एंड लॉजिस्टिक), शिक्षा शाखा और नौसेना की इंजीनियरिंग शाखा की वास्तुकला में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारी के रूप में शामिल हैं।

10.12 **शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को परमानेंट कमीशन:** सरकार ने वर्ष 2008 से कार्यकारी शाखा (विधि संवर्ग), शिक्षा शाखा और इंजीनियरिंग शाखा (नौसेना वास्तुकला) के पुरुष और महिला, दोनों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों के रूप में स्थायी रूप से परमानेंट कमीशन प्रदान करने की शुरुआत की है।

10.13 **एनसीसी के माध्यम से भर्ती:** विश्वविद्यालय के स्नातकों को जिनके पास न्यूनतम 'बी' ग्रेडिंग के साथ नौसैनिक एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र है और इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले स्नातकों को नौसेना में नियमित कमीशन अधिकारियों के रूप में शामिल किया जाता है। इन स्नातकों को यूपीएससी द्वारा आयोजित सीडीएसई में उपस्थित होने से छूट दी गई है और केवल एसएसबी साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। वे भारतीय नौसेना अकादमी में नौसेना उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम (एनओसी) में सीडीएसई कैडेटों के साथ शामिल होते हैं।

10.14 **विशेष नौसेना आर्किटेक्चर प्रवेश योजना:** 'विशेष नौसेना आर्किटेक्ट एंट्री स्कीम' (एसएनईएस) नामक विशेष योजना के अंतर्गत सरकार ने भारतीय नौसेना के इंजीनियरिंग ब्रांच में नौसेना आर्किटेक्ट अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के तौर पर शामिल करने हेतु अनुमोदन दिया है। एक अधिकार प्राप्त नौसेना टीम कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी चेन्नई, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सीयूएसएटी) और आंध्र विश्वविद्यालय का दौरा करती है, जहाँ बी टेक (नौसेना वास्तुकला) पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। चयनित उम्मीदवार निकटतम सैन्य अस्पताल में मेडिकल परीक्षा से गुजरते हैं और फिट पाये जाने पर, उन्हें आगे प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाता है।

नाविकों की भर्ती

10.15 **भर्ती की प्रणाली:** रिक्तियों की उपलब्ध संख्या के अनुसार नौसेना में भर्ती 'पात्र भर्ती पुरुष आबादी' की राज्यवार योग्यता के अनुसार अखिल भारत आधार पर किया जाता है। किसी विशेष राज्य से भर्ती कर्मियों की संख्या और योग्यता में उनकी सापेक्ष स्थिति वहाँ के पात्र आवेदकों की संख्या पर निर्भर करती है जो लिखित परीक्षा, शारीरिक फिटनेस परीक्षा, और चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। जाति / वर्ग या धर्म के आधार पर रिक्तियों का कोई कोटा नहीं है। सभी प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों और रोजगार समाचारों में विज्ञापन के माध्यम से इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रचार सामग्री भी बड़ी संख्या में स्कूलों/कॉलेजों को भेजी जाती है और सभी जिला सैनिक बोर्डों द्वारा स्थानीय प्रशासन व स्थानीय मीडिया के माध्यम से ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में प्रचार अभियान चलाता है। नौसेना में नाविकों की भर्ती एक लिखित परीक्षा, शारीरिक फिटनेस परीक्षण और चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया के बाद की जाती है।

10.16 **प्रविष्टियों के प्रकार:** शैक्षिक योग्यता के अनुसार नाविकों की भर्ती के लिए विभिन्न प्रवेश प्रणालियाँ निम्नानुसार हैं:

(क) गणित और भौतिकी विषय के साथ कुल 60% या उससे अधिक अंकों के साथ आर्टिफिसर अपरेंटिस (एएएस), 10+2 (पीसीएम), 10+2/समकक्ष परीक्षा और जिसमें

इन विषयों में से कम से कम एक विषय लिया गया हो जैसे रसायन विज्ञान/जीवविज्ञान/कंप्यूटर विज्ञान।

(ख) सीनियर सेकेन्डरी भर्ती (एसएसआर), 10+2 (पीसीएम), गणित और भौतिकी के साथ 10+2/ समकक्ष परीक्षा में योग्य और जिसमें इन विषयों में से कम से कम एक विषय लिया गया हो जैसे रसायन विज्ञान/जीवविज्ञान/कंप्यूटर विज्ञान।

(ग) मैट्रिक एंट्री रिफ्रुट्स (एमईआर) के तहत रसोइया, स्टेवाड्स, वादकों और सेनेटरी हाईजेनिस्ट-मैट्रीक्यूलेशन की भर्ती।

(घ) प्रत्यक्ष प्रवेश (उत्कृष्ट खिलाड़ी)।

10.17 **एनसीसी प्रमाणपत्र धारक:** नौसैनिक एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारकों को एए/एसएसआर प्रवेश के लिए अर्हता हेतु कट ऑफ अंकों के न होने के बावजूद लिखित परीक्षा में शामिल होने की छूट दी जाती है। एनसीसी उम्मीदवारों को विभिन्न एनसीसी प्रमाणपत्रों और गणतंत्र दिवस शिविर/दल में भाग लेने के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, जो निम्नानुसार योग्यता सूची तैयार करने के लिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ जोड़े जाते हैं:

तालिका संख्या 10.2

एनसीसी प्रमाण पत्र का प्रकार	प्राप्त किए गए अतिरिक्त अंक		
	प्रमाण पत्र के लिए	गणतंत्र दिवस दल/शिविर के लिए	कुल संभावित अतिरिक्त अंक
सी	6	4	10
बी	4		8
ए	2		6

भर्ती के लिए प्रचार

10.18 हमारे देश के युवाओं को भारतीय नौसेना में अधिकारियों (महिला अधिकारियों सहित) और नाविकों के तौर पर अवसरों के बारे में ज्यादा जानकारी देने हेतु उपाय किए गए हैं। बेहतर प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए अपनाए गए प्रचार के तरीके निम्नानुसार हैं:

(क) **प्रेस विज्ञापन:** विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के माध्यम से रोजगार समाचार/इम्प्लॉइमेंट न्यूज़ और विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्रों में विभिन्न प्रवेशों के लिए विज्ञापन जारी किए जाते हैं।

(ख) **पत्रिकाओं/जर्नलों (दैनिक समाचार पत्रों) में विज्ञापन:** ये आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों की पत्रिकाओं/

जर्नलों में प्रकाशित किए जाते हैं।

(ग) **होर्डिंग्स (विज्ञापन-बोर्ड):** नौसेना में शामिल होने के लिए देश के युवाओं को आकर्षित करने के लिए डीएवीपी ने स्वीकृत स्थानों पर होर्डिंग्स लगाने की योजना बनाई है।

(घ) **मुद्रित प्रचार:** डीएवीपी और निजी व्यावसायिक एजेंसियों के माध्यम से तैयार किए गए सूचना फोल्डर्स, पत्रक, ब्रोशर, डाटा कार्ड, पोस्टर और ब्लो-अप व्यापक रूप से वितरित किए जाते हैं।

(ङ) **प्रदर्शनी और मेले:** प्रत्येक वर्ष भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान नई दिल्ली में डिफेंस पैविलियन में एक स्टाल स्थापित किया जाता है, जहाँ सभी तीन सशस्त्र बलों में भर्ती के बारे में जानकारी आगंतुकों को प्रदान की जाती है। यह कैरियर उन्मुख या छात्रों के लिए आयोजित अन्य संगठित मेलों में भी किया जाता है।

(च) **प्रचार सामग्री का वितरण:** प्रत्येक वर्ष नौसेना के बारे में जानकारी देने वाले छपी हुई प्रचार सामग्री और नौसेना में भर्ती के लिए विभिन्न प्रवेश प्रणालियों के बारे में जानकारी देश भर के लगभग 8000 स्कूलों को वितरित की जाती है।

(छ) **नौसेना भर्ती वेबसाइट का पुनर्विकास:** पुनर्विकसित वेबसाइट(www.joinindiannavy.gov.in),जिसे दिसंबर 2016 में फिर से शुरू किया गया,ने भर्ती प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को काफी सुविधा प्रदान की है तथा जिसमें सभी अधिकारियों व नाविकों के प्रवेश हेतु आवेदनों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आमंत्रित किया गया है।

10.19 **अफसरों के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण:** केरल के एझीमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) 2452 एकड़ में तटीय ऊपरी क्षेत्र में फैला हुआ है और बुनियादी सुविधाओं के मामले में, दोनों अकादमिक गतिविधियों और बाहरी गतिविधियों के लिए यहाँ विश्व स्तर की सुविधाएं मौजूद हैं; जिसमें शामिल हैं राज्य प्रयोगशालाएँ, कार्यशालाएँ, स्विमिंग पूल और खेल क्षेत्र। अकादमी में आधुनिक आवासीय सुविधाएं, एक उत्कृष्ट मैस और पांच दस्ते (स्क्वाड्रन), जिनमें से प्रत्येक की अपनी व्यापक सुविधाएं हैं। आईएनए पहले से ही 1200 अधिकारी कैडेटों को प्रशिक्षित कर रहा है। आईएनए के बुनियादी ढांचे को चरण-2 में विस्तारित किया जा रहा है जो 2020 तक पूरा होने की संभावना है और इसके

माध्यम से अतिरिक्त 1200 कैडेटों को सुविधा मिलने की संभावना है।

भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए), एझीमाला

10.20 आईएनए में पहला बी.टेक. कोर्स 22 जून 2009 को शुरू हुआ। 21वीं सदी की तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए नौसेना के विकास में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। अकादमी में यूपीएससी की परीक्षाओं के माध्यम से और सीधे आईएचक्यू के रक्षा मंत्रालय (नौसेना)/डीएमपीआर द्वारा उम्मीदवारों की 10+2 योग्यता के आधार पर कैडेटों को शामिल किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के साथ नौसेना द्वारा बी.टेक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। शैक्षणिक पाठ्यक्रम एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है। तकनीकी प्रशिक्षण के अलावा, अकादमी मानविकी और नौसैनिक इतिहास के स्वस्थ मिश्रण के साथ अपने कैडेट को प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह उदार शिक्षा के सिद्ध लाभ के साथ समझौता किए बिना उच्चतम तकनीकी विशेषज्ञता के साथ अधिकारियों को प्रदान करने के नौसेना के लक्ष्य के अनुरूप है। पाठ्यक्रम न केवल बी.टेक. की डिग्री के लिए पर्याप्त अकादमिक आधार प्रदान करता है बल्कि एक अधिकारी कैडेट के समग्र परिवर्तन को भी अच्छे सेवा अधिकारियों हेतु प्रदान करता है जो हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर होते हैं।

10.21 **बी टेक स्ट्रीम:** 'एक्स' अधिकारियों, इलेक्ट्रॉनिक्स संचार इंजीनियरिंग (ईसीई), 'एल' अधिकारियों और 'ई' और 'एनए' अधिकारियों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग (एमई) के लिए एफ्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स (एईसी) में बी.टेक. प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। तदनुसार, बी टेक (एईसी), बी टेक (ईसीई) और बी टेक (एमई) की डिग्री बी.टेक. पाठ्यक्रम पूरा होने पर जेएनयू द्वारा प्रदान की जाती है। पहले तीन सेमेस्टर में एक सामान्य पाठ्यक्रम पूरा होने पर, शेष पांच सेमेस्टर के लिए कैडेट अलग-अलग धाराओं में पृथक तौर पर रखा जाता है। एनडीए से बाहर निकलने वाले कैडेटों की परस्पर बातचीत को आसान बनाने के लिए, नौसैनिक कैडेटों हेतु बी.टेक. पाठ्यक्रम जुलाई, 2016 से एनडीए में शुरू किया गया है। एनडीए में नौ कैडेट्स एनडीए में बी.टेक. (एईसी) के छह सेमेस्टर पूरा करने के बाद आईएनए में शामिल हो जाएंगे। इन कैडेटों के लिए बी.टेक. के लिए अंतिम दो सेमेस्टर आईएनए में आयोजित किए जाएंगे।

10.22 **नाविकों के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण:** आईएनएस चिल्का भारतीय नौसेना का प्रमुख नाविक प्रशिक्षण संस्थापना है। वर्तमान में आईएनएस चिल्का में प्रशिक्षण भार लगभग 6500 प्रशिक्षु वार्षिक है (दो के बैच में प्रति बैच में 300 आईसीजी प्रशिक्षुओं सहित 3 हजार प्रशिक्षु)। वर्ष 2009 के बाद से बढ़ी हुई प्रेरणा के कारण बुनियादी ढांचे को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है ताकि प्रवेश की बढ़ती दर के साथ तारतम्य बिठाया जा सके।

विदेशी प्रशिक्षण

10.23 **विदेशी नौसेना कर्मियों का प्रशिक्षण:** भारतीय नौसेना चार दशक से भी अधिक समय के लिए विदेशी कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहा है, जिसके दौरान इसने 41 से अधिक मित्र देशों के 15000 से अधिक विदेशी कर्मियों को प्रशिक्षित किया है। नौसेना का उद्देश्य मित्र विदेशी देशों (एफएफसी) के साथ क्षमता और परस्पर संबंध बनाने के लिए बेहतरीन प्रशिक्षण साझा करना और प्रदान करना है।

10.24 **भारतीय नौसेना मोबाइल प्रशिक्षण टीमों की प्रतिनियुक्ति (आईएन एमटीटी):** अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण के बढ़ते प्रशिक्षण भार की ओर ध्यान देने के लिए, जो महत्वपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं, देश-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों में अनुकूलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। विशेष रूप से गठित मोबाइल प्रशिक्षण टीमों (एमटीटी) द्वारा अनुकूलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अब तक, भारतीय नौसेना ने ओमान, म्यांमार, केन्या, वियतनाम, मॉरीशस, बांग्लादेश और नाइजीरिया को एमटीटी प्रतिनियुक्त किया है। कुछ अन्य एफएफसी से अनुरोध पर विचार किया जा रहा है। यह प्रयास दुनिया भर में हमारे अपने प्रशिक्षण पदचिह्नों पर बोझ को कम करेगा।

प्रशिक्षण – राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी)

10.25 आईएचक्यू रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने कमांड्स को निर्देशित किया है कि एनसीसी प्राधिकारियों के साथ संपर्क बढ़ाए और बंदरगाहों के साथ-साथ एनएसी कैंपों के संचालन को प्रोत्साहित करे या भारतीय नौसेना पोतों पर लघु अवधि के समुद्री विमानों के साथ प्रशिक्षण हेतु एनसीसी कैडेटों को शामिल करे। उपरोक्त के अलावा, आईएचक्यू रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने कमांड्स को यह भी निर्देश दिया कि समय-समय पर क्षेत्रीय एनसीसी मुख्यालयों से संपर्क करे और एनसीसी प्रशिक्षण से जुड़े

मुद्दों पर चर्चा करे। नौसेना एनसीसी के लिए प्रशिक्षण, भारतीय नौसेना के लिए यह प्राथमिकता क्षेत्र रहा है, और शिविरों के संचालन को नियमित आधार पर सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें नौकायन जहाजों के संचालन शामिल है, जो कैडेटों को समुद्र में जीवन पर जोखिम के प्रति मूल्यवान सीख प्रदान करता है। भारतीय नौसेना के विभिन्न कमांड्स पर प्रत्येक वर्ष कई सागर संलग्नक और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। ये प्रत्येक शिविर 12 दिन की अवधि के होते हैं, जिसमें नौकायन युद्धपोतों के साथ भी एक दिन का प्रशिक्षण शामिल होता है। इन शिविरों में लगभग 240–360 एनसीसी कैडेटों की भागीदारी होती है। इसके अलावा, नौसेना एनसीसी कैडेटों के पेशेवर प्रशिक्षण की परिणति के रूप में, एक 'नौ सैनिक' शिविर प्रत्येक वर्ष तय किया जाता है, जिसमें लगभग 590 कैडेट भाग लेते हैं। इस शिविर में समुद्री नौकायन जहाज पर नौकायन संचालन भी शामिल है।

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) अधिकारियों की भर्ती

10.26 भारतीय वायु सेना में कमीशन अधिकारियों, जैसे यूपीएससी प्रवेश और गैर-यूपीएससी प्रवेश के रूप में दो प्रकार की भर्ती होती हैं।

10.27 यूपीएससी प्रवेश केवल उन उम्मीदवारों के लिए लागू होता है, जो वायु सेना की फ्लाइट शाखा में परमानेंट कमीशन अधिकारियों के रूप में शामिल होना चाहते हैं। यूपीएससी एक वर्ष में लिखित परीक्षा दो बार आयोजित करती है। इसमें स्नातक या अंतिम वर्ष के स्नातक के लिए 10+2 परीक्षा और सीडीएसई प्रवेश पूरा होने पर उम्मीदवारों के लिए एनडीए प्रवेश दिया जाना शामिल है।

10.28 गैर-यूपीएससी प्रवेश वायुसेना, फ्लाइट, ग्राउंड ड्यूटी (तकनीकी शाखा) और ग्राउंड ड्यूटी (गैर-तकनीकी शाखाओं) की विभिन्न शाखाओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसमें एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (एएफसीएटी), फ्लाइट ब्रांच और मौसम विज्ञान शाखा (मेटेरिओलॉजी ब्रांच) में परमानेंट कमीशन को छोड़कर, ग्रेजुएट्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट जो आईएएफ की सभी शाखाओं के लिए सामान्य है, शामिल हैं। मौसम विज्ञान शाखा के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं है। एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट वाले विश्वविद्यालय के स्नातक एनसीसी विशेष प्रवेश के लिए पात्र

हैं और उन्हें एएफसीएटी के लिए आवेदन नहीं करना है। सर्विस एंटी कमीशन (एसईसी) पहले से ही भारतीय वायु सेना में पहले से ही सेवा कर रहे एयरमैन के लिए एक प्रवेश पद्धति है।

10.29 **महिलाओं के लिए एनसीसी विशेष प्रवेश:** पहली बार, एनसीसी विशेष प्रवेश को 'सी' सर्टिफिकेट के साथ महिला एयर विंग कैडेट्स के लिए विस्तारित किया गया है। इससे उन्हें एसएसबी के लिए सीधे किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट में प्रवेश की सुविधा मिल सकती है और वे आईएएफ की फ्लाइंग शाखा में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी बन सकती हैं।

10.30 **एनसीसी विशेष प्रवेश के लिए एसएससी और पीसी हेतु विकल्प की शुरुआत:** परमानेंट कमीशन (पीसी) या शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) का विकल्प अब पुरुषों के लिए एनसीसी विशेष प्रवेश तक विस्तारित कर दिया गया है। इससे पहले, केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए परमानेंट कमीशन हेतु विकल्प के तौर पर उपलब्ध था। इसके अलावा, महिला उम्मीदवारों के लिए भी परमानेंट कमीशन की शुरुआत की गई है। दोनों प्रविष्टियां केवल फ्लाइंग ब्रांच के लिए हैं।

10.31 **प्रेरणा प्रचार प्रदर्शनी वाहन (आईपीईवी):** आईपीईवी, 8 अक्टूबर, 2015 को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, इसने देश के उत्तरी, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में सफलतापूर्वक चार सड़क अभियान को पूरा कर लिया है। वर्ष 2016 के दौरान, इस अभियान ने भारत के दक्षिणी भाग को 263 संस्थानों तक पहुंचाते हुए 9960 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और 53,140 छात्रों के साथ परस्पर बातचीत का परिणाम दिया। आईपीईवी ने हाल ही में पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 23 अगस्त 2017 से नवंबर 12, 2017 तक कुल 67 संस्थानों की कुल 2,984 किमी की दूरी तय की और 29,468 छात्रों के साथ परस्पर बातचीत की।

एयरमैन की भर्ती

10.32 भारतीय वायु सेना के एयरमैन संवर्ग में भर्ती, अखिल भारत योग्यता आधार पर अनुसूचित चयन टेस्ट के माध्यम से की जाती है, जो आम तौर पर 14 एयरमैन चयन केंद्रों पर एक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। ये चयन केंद्र भौगोलिक रूप से फैले हुये हैं और आईएएफ में एयरमैन के रूप में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को उचित सुगमता प्रदान करते हैं। जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र या समुदाय के नाम पर कोई भी भेदभाव

किए बगैर, देश के सभी पात्र नागरिकों के लिए चयन परीक्षा खुली हुई है। अनुसूचित चयन टेस्टों के अलावा, राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने के लिए इन क्षेत्रों से युवाओं को अवसर प्रदान करने हेतु दूरस्थ/ लो रिस्पांस / सीमावर्ती / दंगा प्रभावित / नक्सल प्रभावित/आदिवासी क्षेत्रों या पहाड़ी जिलों और देश के द्वीप क्षेत्रों में इसे आयोजित किया जाता है।

10.33 एएफसीएटी और एयरमैन भर्ती के लिए अनुसूचित टेस्ट के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली। आईएएफ में अधिकारी और हवाई कैडर के लिए चयन आज तक मैन्युअल रूप से किया जाता रहा है। हालाँकि यह प्रणाली काफी प्रभावी और मजबूत मानी जाती है, फिर भी यह परीक्षण क्षमता की कमी के चलते सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए अवसरों को सीमित करता है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को चयन परीक्षा में भाग लेने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने और बाद में चिकित्सा परीक्षा और नामांकन की आवश्यकता होती है। इसमें न केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है बल्कि इन खर्चों पर भी गरीब उम्मीदवारों पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है।

10.34 प्रणाली में सुधार करने और इसे अधिक उम्मीदवार अनुकूल बनाने के लिए, साथ ही साथ एक ही समय में संगठनात्मक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, अक्टूबर 2016 में आईटी के कार्यान्वयन हेतु ऑनलाइन अधिकार की जाँच और अधिकारियों और हवाई कैडर के मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन सिस्टम की स्वीकृति दी गई। आईएएफ ने भारत सरकार की एक उन्नत कम्प्यूटिंग अभिकरण सीएडीएसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे अक्टूबर, 2017 में परियोजना शुरू करने के लिए कहा गया है।

10.35 इस परियोजना को एएफसीएटी और एयरमैन भर्ती (स्टार) के लिए चयन टेस्ट हेतु जनवरी 2018 से लागू किया जाएगा। नई प्रणाली में, पूरे देश में फैले 760 परीक्षा केंद्र होंगे और किसी एक उम्मीदवार को अपने निवास स्थान से अधिकतम 100 किमी की यात्रा परीक्षा केंद्र तक पहुँचने के लिए करने की आवश्यकता होगी।

10.36 ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संचालन से समय की बचत के साथ-साथ पारदर्शिता, सटीकता, निष्पक्षता भी बढ़ेगी। एएफसीएटी और स्टार परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में सूचना के परिणामस्वरूप न्यूनतम मानव हस्तक्षेप किया जाएगा और इसमें

उत्तरदायित्व के साथ उच्च सुरक्षा उपाय शामिल होंगे। इसके अलावा, यह परियोजना "डिजिटल इंडिया" के दृष्टिकोण में भी योगदान करती है।

प्रशिक्षण

10.37 **वायु सेना अकादमी (एएफए):** वायु सेना अकादमी पायलटों और ग्राउंड ड्यूटी अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है। वर्ष 1971 से, अकादमी भारतीय वायुसेना की बढ़ी हुई प्रशिक्षण आवश्यकताओं और भारतीय सेना, नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की आवश्यकताओं की भी देखरेख कर रही है। मित्र देशों के कई अधिकारी और कैडेट भी एकेडमी में प्रशिक्षण लेते रहे हैं।

10.38 **वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण सत्र: ई-प्रशिक्षण:** भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप, आईएएफ ने प्रारम्भिक वायु योद्धाओं के लिए वर्तमान प्रशिक्षण पद्धति में एक प्रतिमान परिवर्तन लाने का नेतृत्व किया है। इसके लिए, वायुसेना स्टेशन जलाहल्ली, बेंगलुरु में 400 प्रारम्भिक प्रशिक्षुओं हेतु एक ई-प्रशिक्षण परियोजना को सफलतापूर्वक शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में इसी प्रकार के मॉडल को दोहराए जाने का प्रस्ताव है।

10.39 **भारतीय वायु सेना में एनएसक्यूएफ प्रमाणित उम्मीदवारों की भर्ती:** एनएसडीसी के साथ साझेदारी में, भारतीय वायु सेना, नियमित चयन में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) प्रमाणित व्यक्तियों को शामिल करने की योजना बना रही है, क्योंकि आवश्यक चयन प्रक्रियाओं के बाद पहचाने गए ट्रेडों में एयरमेन के रूप में प्रारम्भिक चरण में, ऑटो फिट और ऑटो टेक ट्रेडों को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहचाने जाने के लिए चिन्हित किया गया है।

10.40 **विदेशी प्रशिक्षण:** भारतीय वायुसेना, भारतीय विदेश मंत्रालय की भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग योजना (आईटीईसी) के तहत मित्र विदेशी देशों (एफएफसी) से प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देती है। प्रशिक्षण वर्ष 2017-18 (1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018 तक) के लिए, विदेश मंत्रालय ने आईएएफ के 39 प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में 125 विभिन्न पाठ्यक्रमों में 22 देशों के कुल 754 रिक्रियों का आवंटन किया है। आईएएफ अधिकारियों को भी विभिन्न मित्र विदेशी देशों (एफएफसी) में पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया जाता है।

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी)

10.41 **अधिकारियों की भर्ती:** अधिकारियों को द्वि-वार्षिक तौर पर तटरक्षक के रूप में भर्ती किया जाता है। तटरक्षक में सहायक कमांडेंट की रिक्रियों को रोजगार समाचार और दिसंबर/ जनवरी और जून/जुलाई महीने में प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाता है। भर्ती के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए पांच वर्ष और ओबीसी के लिए तीन वर्ष की छूट भी स्वीकार्य है। कोस्ट गार्ड चयन बोर्ड (सीजीएसबी) के माध्यम से निम्नलिखित धाराओं में अधिकारियों की भर्ती की जाती है:

(क) **सामान्य ड्यूटी:** 21 से 25 वर्ष आयु वर्ग के बीच पुरुष/ महिला उम्मीदवार जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि और जिन्होंने 12वीं कक्षा में गणित और भौतिकी एक मुख्य विषय के रूप में लिया हो तथा शिक्षा की 10+2+3 योजना या समकक्ष हों, जनरल ड्यूटी स्ट्रीम के अधीन अधिकारियों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ख) **सामान्य ड्यूटी (पायलट/नेविगेटर):** 21 से 25 वर्ष आयु वर्ग के बीच पुरुष/ महिला उम्मीदवार जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि और जिन्होंने 12वीं कक्षा में गणित और भौतिकी एक मुख्य विषय के रूप में लिया हो तथा शिक्षा की 10+2+3 योजना या समकक्ष हों, जनरल ड्यूटी स्ट्रीम (पायलट/नेविगेटर) के अधीन अधिकारियों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ग) **जनरल ड्यूटी (कमर्शियल पायलट लाइसेंस शॉर्ट सर्विस प्रवेश):** 19 से 25 वर्ष आयु वर्ग वाले उम्मीदवार जो 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण हों और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी/मान्य वर्तमान में कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) रखते हों, सीपीएल शॉर्ट सर्विस प्रवेश में अधिकारियों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(घ) **महिलाओं के लिए जनरल ड्यूटी (लघु सेवा नियुक्ति योजना):** 21 से 25 वर्ष आयु वर्ग के बीच महिला उम्मीदवार जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि और जिन्होंने 12वीं कक्षा में गणित और भौतिकी एक मुख्य विषय के रूप में लिया हो तथा शिक्षा की 10+2+3 योजना या समकक्ष हों, जनरल ड्यूटी स्ट्रीम के अधीन अधिकारियों के

लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ड) **तकनीकी शाखा:** 21 से 25 वर्ष आयु वर्ग के बीच पुरुष जिनके पास इंजीनियरिंग (नौसेना वास्तुकला / मैकेनिकल / समुद्री / ऑटोमोटिव / मेक्ट्रॉनिक्स / औद्योगिक एवं उत्पादन / धातु विज्ञान / डिजाइन / वैमानिकी / एयरोस्पेस / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / दूरसंचार / इंस्ट्रुमेंटेशन / इंस्ट्रुमेंटेशन और कंट्रोल / इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार / विद्युत अभियांत्रिकी / विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स) की या समकक्ष योग्यता हो, टेक्नीकल स्ट्रीम के अधीन अधिकारियों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(च) **विधि शाखा:** 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग के बीच महिला/पुरुष उम्मीदवार जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि है, विधि धारा में अधिकारी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। हालाँकि, कोस्ट गार्ड संगठन या भारतीय सेना या नौसेना या वायु सेना में समकक्ष रैंक में सेवारत कर्मचारी के मामले में या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पांच वर्ष तक तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए तीन वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

10.42 **अधिकारी के रूप में अधीनस्थ अधिकारियों का नियोजन:** कोस्ट गार्ड में सेवारत एक वर्ष के अनुभव वाले प्रधान अधिकारी या उत्तम अधिकारियों के रैंक के अधीनस्थ अधिकारियों को और दो वर्ष के अनुभव वाले अधिकारी, तटरक्षक महानिदेशालय के महाप्रबंधक द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त पर, अधिकारियों के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं।

10.43 **अधिकारियों की श्रेणी से नीचे कार्मिकों की भर्ती (पीबीओआर):** कोस्ट गार्ड में पीबीओआर द्वि-वार्षिक तौर पर भर्ती की जाती है। कोस्ट गार्ड में पीबीओआर हेतु रिक्तियों को रोजगार समाचार और दिसंबर/जनवरी और जून/जुलाई के महीने में प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाता है। पीबीओआर की निम्नलिखित मुख्य धाराओं में भर्ती की जाती है:

(क) **यांत्रिक:** 18 से 22 वर्ष के आयु वर्ग के बीच मैट्रिक पास और मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा वाले पुरुष उम्मीदवार यांत्रिक के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

(ख) **नाविक (जनरल ड्यूटी):** गणित और भौतिकी विषय के साथ 12वीं कक्षा पास करने वाले और 18 से 22 वर्ष की आयु वर्ग के पुरुष उम्मीदवार नाविक (जनरल ड्यूटी) के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

(ग) **नाविक (डोमेस्टिक ब्रांच):** मैट्रिक पास और 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग के बीच के पुरुष उम्मीदवार नविक (डोमेस्टिक ब्रांच) के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

(घ) **पंजीकृत फोलोवर्स:** मैट्रिक पास या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समक्ष शैक्षिक योग्यता वाले 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के बीच के पुरुष उम्मीदवार पंजीकृत फोलोवर्स के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

(ड.) भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, सभी 'ख' और 'ग' श्रेणी के पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है और इन पदों की उपयुक्तता के लिए केवल कौशल परीक्षण का आयोजन किया जा रहा है।

अन्य संगठन

सैनिक स्कूल

10.44 सैनिक स्कूलों को केन्द्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है और सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय के समग्र शासन के अधीन आते हैं। वर्तमान में, देश के विभिन्न हिस्सों में 26 सैनिक स्कूल हैं। कई राज्यों से नए सैनिक स्कूल खोलने की मांग बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, बिहार और कर्नाटक राज्यों में दो-दो सैनिक स्कूल हैं। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, अमेठी और झांसी में तीन नए सैनिक स्कूल खोलने हेतु संबंधित राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है, इसी प्रकार उत्तराखंड (रुद्रप्रयाग), महाराष्ट्र (चंद्रपुर), ओडिशा (संबलपुर) और तेलंगाना (वारंगल) में एक-एक, राजस्थान में झुनझुनू और अलवर में दो, स्थापित करने के लिए प्रयास जारी हैं। अरुणाचल प्रदेश (पासीघाट) में एक नया सैनिक स्कूल खोलने के लिए समझौता ज्ञापन पर कार्रवाई की जा रही है। 1 अप्रैल, 2018 से शुरू होने वाले सैनिक स्कूल झुनझुनू को शुरू करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

10.45 सैनिक स्कूलों के उद्देश्य में सामान्य व्यक्ति की पहुंच के भीतर गुणवत्ता सार्वजनिक विद्यालय की शिक्षा शामिल करना, एक बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उसे राष्ट्रीय

रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए तैयार करना और सशस्त्र बलों के अधिकारी के कैडर में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना शामिल है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के प्रत्येक बैच में लगभग एक चौथाई कैडेट सैनिक स्कूल से हैं। 138 एनडीए/आईएनए कोर्स के लिए, जो जुलाई 2017 में 348 कैडेट्स से शुरू हुई, इसमें से कुल 115 कैडेट सैनिक स्कूलों में से हैं, और जो एनडीए पाठ्यक्रम का लगभग 33% है।

10.46 सैनिक स्कूल लड़कों को कक्षा छठी और कक्षा नौवीं में प्रवेश देते हैं। कक्षा छठी के लिए उनकी आयु 10–11 वर्ष और कक्षा नौवीं में प्रवेश के लिए 1 जुलाई को उनकी आयु 13–14 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष जनवरी में आयोजित अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की योग्यता (मेरिट) के आधार पर ही प्रवेश दिया जाता है। सैनिक स्कूल मिजोरम में लड़कियों का प्रवेश प्रायोगिक आधार पर वर्ष 2018–19 से आरंभ होगा। ओएमआर आधारित प्रवेश परीक्षा की शुरुआत शैक्षणिक सत्र वर्ष 2018–19 से प्रभावी की जाएगी।

10.47 अकादमिक उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी ने कई उपाय अपनाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड और एनडीए के परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। इस दिशा में प्रत्येक स्कूल कैडेटों के लिए विशेष प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का संचालन किया जा रहा है, साथ ही स्टाफ के लिए भी उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय सैन्य विद्यालय (आरएमएस)

10.48 राष्ट्रीय सैन्य विद्यालय, सैन्य प्रशिक्षण महानिदेशालय के तत्वावधान में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के प्रमुख और प्रतिष्ठित आवासीय पब्लिक स्कूल हैं। ये विद्यालय हिमाचल प्रदेश में चेल, राजस्थान में अजमेर और ढोलपुर, कर्नाटक में बेलगाम और बेंगलोर में स्थित हैं। सबसे नया राष्ट्रीय सैन्य विद्यालय, 16 जुलाई 1962 को ढोलपुर में स्थापित किया गया था। यह स्कूल सीबीएसई से संबद्ध हैं और इन स्कूलों का उद्देश्य "गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना और एनडीए के माध्यम से रक्षा सेवाओं में शामिल होने के लिए कैडेट्स को तैयार करना है"।

10.49 राष्ट्रीय सैन्य विद्यालय एक आम प्रवेश परीक्षा (सीईटी) और साक्षात्कार के माध्यम से लड़कों को प्रवेश देते हैं। कक्षा छठी और नौवीं कक्षा के लिए सीईटी लिखित परीक्षा ऑप्टिकल

मार्क रीडर (ओएमआर) के आधार पर पूरी तरह से स्वचालित होती है। उम्मीदवारों का परीक्षण चार विषयों में किया जाता है जैसे कि अंग्रेजी, इंटेलिजेंस टेस्ट, गणित और सामान्य ज्ञान। आरएमएस में 70% सीटें जूनियर कमीशन ऑफिसर्स/अन्य रैंकों के लिए आरक्षित होती हैं, 30% सीटें कमीशन ऑफिसरों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं और शेष 13% नागरिक श्रेणी के लिए हैं। प्रत्येक श्रेणी में सीट का 15% और 7% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए क्रमशः आरक्षित हैं। 50 सीट (स्कूल में से किसी में 15 से ज्यादा नहीं) युद्ध या शांति के दौरान अलग-अलग व्यक्तियों के बच्चों के लिए आरक्षित होते हैं, जो 'कार्रवाई के दौरान मारे' (केआईए) जाते हैं।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए)

10.50 एनडीए एक प्रमुख त्रि-सेवा संस्था है जो उन सभी संबंधित सेवाओं हेतु कैडेटों को प्रशिक्षित करती है जो उन्हें अपने पूर्व-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करने से पहले कैडेट को जरूरी होते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए और कमी के लिए तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एनडीए की क्षमता को 1800 कैडेटों से 1920 कैडेट्स तक बढ़ाया गया है, जो कि एनडीए में एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन जैसे 16वीं स्क्वाड्रन की स्थापना के लिए मंजूरी के साथ 16वीं स्क्वाड्रन के निर्माण के लिए काम वर्ष 2015 में शुरू किया गया था और यह मार्च 2018 तक पूरा होने की उम्मीद है। भविष्य की तकनीक को शामिल करने और भावी सैन्य अगुवाओं को लैस करने के लिए, एनडीए ने नौसेना और वायु सेना के कैडेटों के लिए बी टेक पाठ्यक्रम शुरू किया है। एनडीए कैडेटों ने खेल, सांस्कृतिक और अकादमिक मोर्चों में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भी अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की है।

सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईएलआईटी)

10.51 एमआईएलआईटी एक त्रि-सेवा प्रशिक्षण संस्थान है जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अधिकारियों और डीआरडीओ वैज्ञानिकों के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करता है। एमआईएलआईटी में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख पाठ्यक्रम तकनीकी स्टाफ ऑफिसर कोर्स (टीएसओसी) (आर्मी), टीएसओसी (वायु सेना), टीएसओसी (नौसेना) और नौसेना तकनीकी स्टाफ कोर्स (एनटीएससी) के साथ 18 अन्य पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम जो कि मुख्य रूप से सैन्य प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। यह संस्थान

गिरिनागर परिसर, पुणे में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ स्थित है। यह डीआईएटी में एम-टेक पाठ्यक्रम/ अन्य पाठ्यक्रमों में डीआईएटी हेतु प्रशासकीय और संकाय संबंधी समर्थन प्रदान करता है। संस्थान अन्य संस्थानों जैसे श्रीलंका, डीएससीएससी जैसे सैन्य प्रौद्योगिकी पर कैम्पूल भी आयोजित करता है। एमआईएलआईटी विभिन्न विषयों में प्रति वर्ष लगभग 700 अधिकारी नियुक्त करती है। संस्थान में टीएसओसी और एनटीएससी के अधीन आने वाले अधिकारियों को एमएससी डिग्री हेतु सावित्री फुले, पुणे विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रदान की गई है। संस्थान में कई प्रयोगशालाएं और सुविधाएं हैं जिनमें कार्यात्मक हथियार, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, विमान स्टेच्यू मॉडल सहित अन्य तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय (आरआईएमसी)

10.52 राष्ट्रीय भारतीय अकादमी (एनडीए) और नौसेना अकादमी (एनएवीएसी) में शामिल होने के लिए चयनित लड़कों को तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय (आरआईएमसी) वर्ष 1922 में स्थापित किया गया था। अखिल भारत प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रत्येक वर्ष 25 कैडेटों को वर्ष में दो बार (जनवरी और जुलाई) भर्ती किया जाता है। आरआईएमसी हेतु लड़कों का चयन राज्य सरकारों के माध्यम से आयोजित एक लिखित परीक्षा द्वारा होता है। जनसंख्या के आधार पर संबंधित राज्यों के लिए सीट आरक्षित हैं। यह कॉलेज कक्षा आठवीं में लड़कों को प्रवेश देता है।

भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए), देहरादून

10.53 वर्ष 1932 में स्थापित, भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून का उद्देश्य सेना के अधिकारियों के रूप में शामिल होने वाले व्यक्तियों के बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक गुणों का समग्र विकास करना है। भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश की विभिन्न प्रणालियाँ हैं:

- (क) एनडीए से स्नातक स्तर की पढ़ाई पर।
- (ख) आर्मी कैडेट कॉलेज से स्नातक होने पर, जो भारतीय सैन्य अकादमी का ही एक विंग है।
- (ग) सीधे प्रवेश स्नातक कैडेट, जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं और सेवा चयन बोर्ड के माध्यम

से चयनित होते हैं।

- (घ) तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टीजीसी) के लिए।
- (ङ) इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यूईएस) के तहत अध्ययन के अंतिम/पूर्व-अंतिम वर्ष में।

10.54 भारतीय सैन्य अकादमी मैत्रीपूर्ण देशों से कैडेटों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए), चेन्नई

10.55 वर्ष 1963 में स्थापित, अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय (ओटीएस) को 1 जनवरी 1988 को इसकी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) के रूप में पुनःनामित किया गया। इसका मुख्य कार्य, वर्ष 1965 से पहले एमर्जेंसी कमीशन हेतु कैडेटों को प्रशिक्षित करना था। वर्ष 1965 के बाद से, अकादमी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए कैडेटों को प्रशिक्षित कर रहा है।

10.56 दिनांक 21 सितंबर 1992 से सेना में महिला अधिकारियों के प्रवेश के साथ, लगभग 80-85 महिला अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए), चेन्नई से सेना सेवा कोर, सेना शिक्षा कोर, न्यायाधीश एडवोकेट जनरल विभाग, कोर ऑफ इंजीनियर्स, सिग्नल, विद्युत और मैकेनिकल इंजीनियर्स और सेना शिक्षा कोर में कमीशन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

10.57 अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) निम्नलिखित के लिए प्री-कमीशन प्रशिक्षण प्रदान करता है:

- (क) स्नातक के लिए लघु सेवा आयोग (गैर तकनीकी)
- (ख) स्नातक के लिए लघु सेवा आयोग (तकनीकी)
- (ग) जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) कोर्स।

अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए), गया

10.58 सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी (सीसीएस) ने 3 दिसंबर, 2009 को गया, बिहार में दूसरी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) की स्थापना को मंजूरी दी है। इस अकादमी में प्रशिक्षण जुलाई 2011 में शुरू हुआ। वर्तमान में 322 कैडेट्स अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए), गया में प्रशिक्षण ले रहे हैं और इसकी क्षमता को 750 कैडेटों तक धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा।

वर्तमान में अकादमी 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना (टीईएस) और विशेष कमीशन अधिकारी (एससीओ) पाठ्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

आर्मी वार कॉलेज (एडब्ल्यूआर), महू

10.59 आर्मी वार कॉलेज, महू सर्व सुविधायुक्त परिवेश में रणनीतिक और परिचालन के स्तर पर सभी हथियारों के प्रशिक्षण हेतु प्रमुख भारतीय सेना संस्थान और भारतीय सेना के सभी अधिकारियों के लिए मातृ संस्था भी है। कॉलेज युद्ध कला में पेशेवर सैन्य ज्ञान प्रदान करता है, जो कि सीखने के अनुकूल वातावरण में सैन्य मामलों में सहकार्यता और क्रांति पर विशेष जोर देता है। आर्मी वार कॉलेज, भारतीय सेना के सभी अधिकारियों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण भी प्रदान करता है और रणनीति और सैन्य-तंत्र के क्षेत्र में नई अवधारणाओं और सिद्धांतों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। आर्मी वार कॉलेज में भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षणरत मित्र देशों के अधिकारी भी भारत के वैश्विक और क्षेत्रीय रणनीतिक परिप्रेक्ष्य के साथ उन्मुख होते हैं और उच्च रक्षा प्रबंधन की बारीकियों के मुताबिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

जूनियर लीडर्स विंग (जेएलडब्ल्यू), बेलगाम

10.60 बेलगाम स्थित जूनियर लीडर्स विंग, जूनियर ऑफिसर्स, जेसीओ और एनसीओ को उप-इकाई स्तरीय तकनीकी और स्पेशल मिशन तकनीकों में प्रशिक्षण दे रहा है ताकि उन्हें तीव्र तनाव और मांग के तहत अलग-अलग इलाकों में कार्य सौंपा जा सके और वे ऑपरेशनल मिशन को पूरा कर सकें, और युद्ध और शांति में प्रभावी ढंग से एकीकृत करते हुए वे अपने उप-इकाई के निर्देशन और संचालन हेतु सक्षम हो सकें। यह सेना के अधिकारियों और एनसीओ, अर्ध सैनिक बलों, केंद्रीय पुलिस संगठन और कमांडो प्रकार के संचालन में मित्र देशों को प्रशिक्षित करता है और उन्हें सभी प्रकार के इलाकों और परिचालन वातावरण में विशेष मिशन समूहों या अग्रणी स्वतंत्र मिशन के हिस्से के रूप में सशक्त बनाने के लिए सक्षम बनाता है।

जूनियर लीडर्स अकादमी (जेएलए), बरेली

10.61 जेएलए, बरेली, सभी प्रकार के हथियारों से लैस संस्थान है, जो भारतीय सेना, अर्ध सैनिक बलों और मित्र देशों के जूनियर

लीडर्स (जेसीओ और सीनियर एनसीओ) को नेतृत्व और प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ वर्तमान में उनकी क्षमता को वास्तविक बनाने में तथा भविष्य की भूमिकाओं हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। यह संस्थान प्रत्येक वर्ष 8208 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल (एचएडब्ल्यूएस), गुलमर्ग

10.62 स्कूल का उद्देश्य अत्यधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय युद्ध (एमडब्ल्यू) के सभी पहलुओं में चयनित कर्मियों को प्रशिक्षित करना है और ऐसे विषम इलाकों में लड़ाकू तकनीकों का विकास करना है। एचएडब्ल्यूएस ने क्रमशः दो सीरिज पाठ्यक्रम, एमडब्ल्यू और शीतकालीन वारफेयर (डब्ल्यूडब्ल्यू) सोनामर्ग और गुलमर्ग में अधिकारियों, जेसीओ और एनसीओ के लिए आयोजित किया है। प्रशिक्षण अवधि मुख्य तौर पर जनवरी से अप्रैल (डब्ल्यूडब्ल्यू श्रृंखला) और मई से अक्टूबर (एमडब्ल्यू श्रृंखला) तक आयोजित किया जाता है। स्कूल के कार्मिकों ने कुछ लोगों ने दुनिया के कुछ सर्वोच्च शिखरों तक अपनी पहुंच बनाई है जिसमें माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा और यूएसए की माउंट मैकिली शामिल हैं।

काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल (सीआईजेडब्ल्यू), वीरांटे

10.63 सीआईजेडब्ल्यूएस, अधिकारियों, भारतीय सेना के जेसीओ/एनसीओ, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस संगठनों और मित्र देशों के साथ कम तीव्रता वाले संघर्ष के संचालन (एलआईसीओ) संबंधी पाठ्यक्रम संचालित करता है, जिससे कि विद्रोह/आतंकवाद को समाप्त करने (सीआई/सीटी) के माहौल में इसका सफलता पूर्वक संचालन किया जा सके। पूर्वोत्तर के अशांत क्षेत्रों में शामिल होने से पहले इकाइयों के लिए यह पूर्व-प्रेरण प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। सीआई/सीटी संचालन के क्षेत्र में नई अवधारणाओं और सिद्धांतों के मूल्यांकन हेतु यह नोडल अभिकरण है।

काउंटर इंसर्जेंसी प्री इंडक्शन ट्रेनिंग बैटल स्कूल

10.64 चूंकि सीआईजेडब्ल्यू विद्यालय की क्षमता बहुत सीमित थी और इकाइयों की गतिविधि की विशिष्ट परिस्थितियों और प्रशासनिक समस्याओं के कारण, उन्हें अपने आपरेशन क्षेत्रों

के आसपास के स्थानों पर इकाइयों को प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक माना जाता था। इसलिए, उत्तरी कमान में जाने वाली इकाइयों के लिए खेरु, सरोल और भालरा में सेना के संसाधनों के माध्यम से कोर युद्ध स्कूलों को वहाँ स्थापित किया गया है। विद्रोह का खात्मा करने के लिए प्रशिक्षण के अलावा, विशेष रूप से उत्तरी कमान में इन स्कूलों को, नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अत्यधिक ऊँचाई वाले पर्वतीय युद्ध क्षेत्रों में उनकी भूमिका के लिए प्रशिक्षण इकाइयाँ माना जाता है।

इन्फैंट्री स्कूल, महु

10.65 इन्फैंट्री स्कूल भारतीय सेना का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है, और यह युवा अधिकारियों, प्लाटून हथियार, मोर्टार, एंटी टैंक और गाइडेड मिसाइल, मीडियम मशीन गन और स्वचालित ग्रेनेड लॉन्चर, सेक्शन कमांडर, ऑटोमैटिक डाटा प्रोसेसिंग, स्निपर और बटालियन सपोर्ट हथियार हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन करता है। इसके अलावा, यह इन्फैंट्री क्लर्क प्रशिक्षण विंग में इन्फैंट्री क्लर्क प्रशिक्षण भी आयोजित कर रहा है। संस्था में न केवल इन्फैंट्री के प्रशिक्षण अधिकारी, जेसीओ और ओआर हैं बल्कि अन्य हथियारों और सेवाओं के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ मित्र देशों, अर्ध सैनिक बलों और सिविल हथियारबंद पुलिस बलों के कर्मचारियों का भी इस प्रशिक्षण में शामिल होता है।

कॉलेज ऑफ मैटेरियल्स मैनेजमेंट

10.66 अक्टूबर 1925 में किर्कि में स्थापित यह कॉलेज भारतीय सेना ऑर्डिनेंस कोर (आईएओसी) स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शन का ही एक विस्तार है। स्कूल को बाद में फरवरी, 1939 में आईएओसी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नामित किया गया था और जबलपुर में इसके वर्तमान स्थान पर इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। जनवरी 1950 में, आईएओसी स्कूल आर्मी ऑर्डिनेंस कोर (एओसी) एक स्कूल बन गया। एओसी स्कूल का नाम बदलकर कॉलेज ऑफ मैटेरियल्स मैनेजमेंट (सीएमएम) रखा गया, और वर्ष 1987 में जबलपुर विश्वविद्यालय (रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय) से इसे संबद्ध किया गया। वर्ष 1990 में सीएमएम को स्वायत्तशाषी का दर्जा दिया गया। कॉलेज को 'गवर्नमेंट कॉलेज' के रूप में भी पंजीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की मंजूरी भी दी गई है।

10.67 यह कॉलेज भारतीय सेना की प्रमुख 'ए' श्रेणी की स्थापना होने के नाते सभी सेनाओं और सेना ऑर्डिनेंस कोर के कर्मचारियों को सभी सैन्य, सेवाओं और अर्ध सैनिक बलों के चयनित कर्मियों को प्रभावी और गतिशील प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे उन्हें सैन्य-तंत्र का निर्वहन करने और आपूर्ति श्रृंखला कार्यों, युद्ध के पूरे क्षेत्र में, युद्ध अथवा शांति, दोनों हेतु विभिन्न स्तर पर प्रबंधन शामिल है। कॉलेज द्वारा युवा अगुवाओं और सैनिकों को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान के साथ सूचना का प्रबंधन करने में भी सक्षम बनाया जाता है, ताकि आवश्यकता के समय में तुरंत ही सूचना तकनीकी समाधान की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। कॉलेज अफगान नेशनल आर्मी के बैचों को सभी सैन्य तथा प्रशासनिक और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कोर्स (एलएमसी) के लिए विशेष सैन्य-तंत्र प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। एक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ प्रशिक्षण सुविधाओं में काफी सुधार किया गया है, जिसमें बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना, नवीन विचारों की प्राप्ति और सर्वोत्तम प्रबंधन तकनीकों का एकीकरण कॉलेज द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों में शामिल किया गया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली एमबीए की डिग्री को सामग्री प्रबंधन से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में बदल दिया गया है ताकि भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक योग्यता की अधिक स्वीकार्यता और उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके। यूजीसी अधिनियम के तहत गठित एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने कॉलेज को पांच-सितारा (उच्चतम) मान्यता प्रदान की है। कॉलेज ने 14 अक्टूबर, 2017 से आईएसओ 9001:2015 पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया है।

10.68 गणतंत्र दिवस 2017 के अवसर पर कॉलेज को "जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, आर्मी ट्रेनिंग कमांड यूनिट साइटेशन" से सम्मानित किया गया है। यह पहली बार है कि प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रशासन के सभी क्षेत्रों में कॉलेज को अपनी योग्यता हेतु मान्यता दी गई है।

स्कूल ऑफ आर्टिलरी, देवलाली

10.69 स्कूल ऑफ आर्टिलरी, देवलाली, आर्टिलरी युद्ध विज्ञान और कार्यप्रणाली के विभिन्न उप-विषयों के शैक्षणिक केंद्र के तौर पर, आर्टिलरी हथियारों पर अधिकारियों, जेसीओ और एनसीओ को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करता है, और इसमें एयर ओब्सर्वेशन पोस्ट ड्यूटी के लिए पायलटों का प्रशिक्षण भी शामिल है। इसके

अलावा, भारत और विदेशों, दोनों के सिद्धांतों, अध्ययन और आर्टिलरी उपकरणों की जाँच व समीक्षा भी यहाँ की जाती है।

10.70 भारतीय सेना के अधिकारियों, जेसीओ और एनसीओ की एक बड़ी संख्या को प्रशिक्षण देने के अलावा, स्कूल ने वर्ष के दौरान मित्र देशों के कई अधिकारियों और कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया है।

आर्मी एयर डिफेन्स कॉलेज, गोपालपुर

10.71 आर्मी एयर डिफेन्स कॉलेज (एएडीसी) ने आर्टिलरी की मुख्य शाखा से वायु रक्षा आर्टिलरी में बदले जाने से पहले इसे अक्टूबर, 1989 तक गोपालपुर स्थानांतरित कर दिया गया था, जहाँ यह स्कूल ऑफ आर्टिलरी की एक शाखा के रूप में कार्य करता रहा। कॉलेज में एयर डिफेन्स आर्टिलरी, अन्य हथियारों और सशस्त्र बलों के कर्मियों तथा मित्र देशों की सेना में सेवारत हवाई रक्षा संबंधित विषयों में कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

10.72 एएडीसी कई पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। कुछ पाठ्यक्रमों में लांग गूनेरी स्टाफ कोर्स (अधिकारी), यंग ऑफिसर्स कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कोर्स, सीनियर कमांड एयर डिफेन्स कोर्स, लांग गूनेरी स्टाफ कोर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर / गैर कमीशन ऑफिसर, तकनीकी अग्नि नियंत्रण पाठ्यक्रम, एयरक्राफ्ट रिकग्निशन कोर्स, यूनिट प्रशिक्षक और चालक दल आधारित प्रशिक्षण और स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग कोर्स हैं।

सेना शिक्षा कोर (ईसी) प्रशिक्षण कॉलेज एवं केंद्र, पंचमढी

10.73 ईसी प्रशिक्षण कॉलेज एवं केंद्र, पंचमढी सशस्त्र बलों हेतु शैक्षणिक प्रशिक्षण में उत्कृष्टता का एक रक्षा पीठ है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध एक स्वायत्त कॉलेज है जिसके पास स्वयं के पाठ्यक्रमों व और डिग्री को डिज़ाइन करने, आचरण, परीक्षा और पुरस्कार देने के लिए अकादमिक और प्रशासनिक शक्तियां मौजूद हैं।

10.74 नक्शा शिल्प विभाग, दस सप्ताह की अवधि का मैप रीडिंग प्रशिक्षक कोर्स ईसी अधिकारियों और जेसीओ/ या भारतीय सेना के सभी शस्त्र और सेवाओं, अर्ध सैनिक बलों के कर्मियों हेतु और मित्र देशों के कर्मियों के लिए पाठ्यक्रम के रूप में संचालित करता है।

10.75 ओआर को अपनी इकाइयों में प्रभावी प्रशिक्षक बनाने के लिए, भारतीय सेना की सभी सेना और सेवाओं हेतु 12 सप्ताह की अवधि का यूनिट शिक्षा प्रशिक्षक (यूईआई) कोर्स संचालित किया जाता है।

10.76 विदेशी भाषा विंग (एफएलडब्ल्यू), जो ईसी प्रशिक्षण कॉलेज एवं केंद्र के तीन प्रभागों में से एक है, न केवल सशस्त्र बलों को विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने का एक प्रमुख केंद्र है, बल्कि यह राष्ट्रीय शैक्षिक वातावरण में भाषा प्रयोगशालाओं को डिजिटल करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है, जिसकी प्रवेश क्षमता 20 छात्र प्रति बैच है।

सैन्य संगीत विंग, पंचमढी

10.77 तत्कालीन कमांडर-इन-चीफ जनरल (बाद में फील्ड मार्शल) के.एम.करिअप्पा के संरक्षण में अक्टूबर 1950 में सैन्य संगीत विंग (एमएमडब्ल्यू) की स्थापना की गई थी। एआरई प्रशिक्षण कॉलेज और सेंटर, पंचमढी के एक हिस्से के रूप में इसके पास 200 से अधिक संगीत रचनाओं का खजाना है और भारत में सैन्य संगीत के मानक को बनाए रखने में भी इसे उत्कृष्टता हासिल है, जो विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से भर्ती हुये बैन्डमैन, पाइपर्स और ड्रमर्स को प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

रिमाउंट एवं वैटिनरी कोर सेंटर एवं स्कूल, मेरठ

10.78 मेरठ कैन्ट स्थित रिमाउंट वैटिनरी कोर (आरवीसी) सेंटर और कॉलेज का उद्देश्य पशु प्रबंधन और पशु चिकित्सा पहलुओं पर अधिकारियों, जेसीओ और सभी सैन्य और सेवाओं, पीएमएफ, सीएपीएफ, भारतीय नौसेना और एफएफसी को प्रशिक्षण प्रदान करना है। यहाँ अधिकारियों के लिए ग्यारह पाठ्यक्रम और जेसीओ और ओआर के लिए सात पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षित छात्रों की कुल संख्या 250 है।

आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट (एसआई), पुणे

10.79 अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में संभावित मेडल विजेता बनाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न स्थानों पर चयनित विषयों में सेना खेल नोड्स की स्थापना के साथ सेना खेल संस्थान, पुणे की भी स्थापना की गई है। खाद्य, आवास, विदेशी शैक्षिक दौरे और प्रशिक्षण के साथ एक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और

उपकरणों के लिए उपयुक्त मात्रा में निधियां निर्धारित की गई हैं जिसमें विदेशी कोचों के माध्यम से प्रशिक्षण भी शामिल है।

10.80 सेना के लगभग 213 विशिष्ट खिलाड़ियों को सात विषयों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, नामतः एथलेटिक्स, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, डाइविंग, भालाफेंक, भारोत्तोलन और कुश्ती। इसके अलावा, 11 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के 161 प्रतिभावान युवा लड़कों को भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के साथ मिलकर ब्याज स्पोर्ट्स कंपनी में प्रशिक्षित किया जा रहा है। खिलाड़ियों को अनुभवी भारतीय और विदेशी कोचों द्वारा प्रशिक्षित किया और भारत और विदेशों में उनकी प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया जाता है। संस्थान में खेल चिकित्सा विज्ञान केंद्र (एसएमसी) भी है जो देश में अपनी तरह का विशेष केंद्र है। राष्ट्रीय शिविर में बड़ी संख्या में एथलीट और नोड के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इसके साथ ही नोड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय शिविर की भी योजना तैयार की जा रही है।

आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग (एआईपीटी), पुणे

10.81 वर्ष 2005 में आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग (एसपीटी) का नाम बदलकर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग (एआईपीटी) कर दिया गया। यह सेना की इकाइयों और उप-इकाइयों में शारीरिक प्रशिक्षण के संचालन के बारे में सैन्य कर्मियों को व्यवस्थित और व्यापक निर्देश/प्रशिक्षण देने वाली एक प्रमुख संस्था है। यह खेल-कूद में मनोरंजन के माध्यम से सेना में मानकों को सुधारने हेतु और भौतिक प्रशिक्षण के पूरक के साथ खेल-कूद में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन पाठ्यक्रमों में अधिकारी, जेसीओ और सैन्य कर्मियों, अर्ध सैनिक बलों के ओआर और मित्र देशों से सेवा कर्मी भाग लेते हैं। यह जेसीओ और ओआर के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है जिसमें मुक्केबाजी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तैराकी और जीवन-रक्षक, कराटे और योग पाठ्यक्रमों से संबन्धित छह संबद्ध विषय शामिल हैं।

कॉम्बैट आर्मी एवीएटर स्कूल (सीएटीएस), नासिक रोड

10.82 मई 2003 में नासिक रोड पर निर्मित कॉम्बैट आर्मी एवीएटर स्कूल (सीएटीएस) का उद्देश्य विमानन कौशल और

युद्ध के विभिन्न अभियानों में विमानन इकाइयों में प्रबंधन, विमानन प्रशिक्षक को प्रशिक्षण देने और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने के साथ-साथ ग्राउंड ट्रूप्स को सैनिकों के साथ समन्वय स्थापित करने में विमानन सामरिक सिद्धांत के विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना है। विद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में प्री-बेसिक पायलट कोर्स, बेसिक आर्मी एविएशन कोर्स, प्री क्वालिफाइड फ्लाईंग इंस्ट्रक्टर कोर्स, एविएशन इंस्ट्रक्टर हेलीकॉप्टर कोर्स, हेलीकॉप्टर कनवरशन ऑन टाइप, फ्लाइंट कमांडर कोर्स और न्यू इक्विपमेंट कोर्स शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सैन्य महाविद्यालय (एमसीईएमई), सिकंदराबाद

10.83 एमसीईएमई का प्रमुख कार्य ईएमई के सभी रैंकों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें कर्मचारियों सहित इंजीनियरिंग, हथियार प्रणालियों और उपकरणों के रखरखाव, मरम्मत और निरीक्षण के विशेष संदर्भ के साथ जानकारी और प्रशिक्षण, प्रबंधन को वरिष्ठ, मध्य तथा पर्यवेक्षकीय स्तर पर प्रदान करना शामिल है। एमसीईएमई को 1760 कर्मियों (सभी रैंक) को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। यह अधिकारियों के लिए 13 पाठ्यक्रम और जेसीओ/ओआर के लिए 61 विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है।

10.84 कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण पैकेज (सीबीटी) और डिजिटाइज्ड चार्ट विकसित किए गए हैं, जो एमसीईएमई में पढ़ाए जा रहे उपकरणों के कामकाज, मरम्मत, रखरखाव, सर्विसिंग के पहलुओं और उपकरणों के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक हिस्से के सही इस्तेमाल पर संपूर्ण तकनीकी जानकारी प्रदान करते हैं।

सैन्य पुलिस कोर(सीएमपी) केंद्र और स्कूल, बंगलोर

10.85 स्कूल की भूमिका अधिकारियों और जेसीओ/ओआर को मिलिट्री पुलिस कर्तव्यों के लिए कानून प्रवर्तन, जांच, सतर्कता और यातायात प्रबंधन में प्रशिक्षित करना है। अधिकारियों के लिए चार पाठ्यक्रम और सीएमपी कोर के जेसीओ/ओआर के लिए उन्नीस पाठ्यक्रम, तथा अफगान नेशनल आर्मी और श्रीलंका सेना के लिए मिलिट्री पुलिस संवर्ग पर तीन विशेष तौर पर तैयार पाठ्यक्रम

संचालित किए जा रहे हैं। एक कैलेंडर वर्ष के दौरान प्रशिक्षित होने वाले छात्रों की कुल संख्या 941 है।

आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल (एएटीएस), आगरा

10.86 आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल (एएटीएस) को पहले सेना एयर ट्रांसपोर्ट सपोर्ट स्कूल (एएटीएस) के रूप में नामित किया गया था। एक ही एजेंसी के अंतर्गत सभी एयरबोर्न ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता के प्रत्युत्तर में आर्मी एयर ट्रांसपोर्ट सपोर्ट स्कूल को 15 जनवरी, 1992 से सेना एयरबोर्न स्कूल के रूप में पुनः नामित किया गया है।

सेना का संचार प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (एमसीटीई), महु

10.87 एमसीटीई, महु कॉम्बैट कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, रेजिमेंटल सिग्नल कम्युनिकेशंस और क्रिप्टोलॉजी में सिग्नल अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। पाँच प्रशिक्षण संकायों और स्कंधों के अलावा, कॉलेज के पास इसका प्रशासन विभाग है जो स्टाफ और छात्रों को प्रशासकीय और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करता है, कॉलेज का एक संकल्पनात्मक अध्ययन कक्ष है जो संचार सिद्धांत विकसित करने और प्रशिक्षण सामग्री निर्मित करने के लिए स्थापित किया गया है, और इसके अलावा कॉलेज का एक आधुनिक और अच्छी तरह से व्यवस्थित पुस्तकालय तथा एक घरेलू प्रिंटिंग प्रेस भी है। प्रशिक्षुओं को औपचारिक रूप से अध्ययन करने और प्रशिक्षित करने के लिए एक औपचारिक व्यवस्था प्रदान की गई है ताकि उन्हें वर्तमान और भविष्य के कार्यों के लिए अपेक्षित कौशल, ज्ञान और क्षमताओं से लैस किया जा सके।

मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो, (एमआईएनटीएसडी), पुणे

10.88 भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्ध सैनिक बलों के सभी रैंकों और मित्र देशों के कर्मियों के लिए खुफिया सूचना प्राप्ति, काउंटर इंटेलिजेंस और सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण देने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल और डिपो (एमआईएनटीएसडी) एक प्रमुख संस्थान है। राजस्व खुफिया विभाग के सिविल अधिकारियों को भी इस संस्थान में प्रशिक्षित किया जाता है। स्कूल में 90 अधिकारियों और 1390 जूनियर

कमीशन अधिकारियों/गैर-कमीशन अधिकारियों को एक बार में सभी हथियारों की प्रशिक्षण देने की क्षमता है। स्कूल प्रत्येक वर्ष लगभग 350 अधिकारियों और 1100 जूनियर कमीशन अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है।

इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कूल (ईएमई), वडोदरा

10.89 ईएमई स्कूल अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम और जेसीओएस/ओआर के लिए डिप्लोमा प्रमाणपत्र स्तर के पाठ्यक्रम संचालित करता है। कई विदेशी अधिकारियों और जेसीओ/ओआर तथा मित्र देशों से प्रशिक्षु ईएमई स्कूल में आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।

सैन्य विधि संस्थान, कैम्पटी

10.90 शिमला में सैन्य विधि संस्थान स्थापित किया गया है। वर्ष 1989 में, संस्थान को कैम्पटी स्थानांतरित कर दिया गया। स्कूल के कर्तव्यों की सूची में सेना के सभी हथियारों और सेवाओं हेतु अधिकारियों के लिए कानूनी शिक्षा की एक व्यापक प्रणाली प्रदान करना शामिल है। स्कूल सैन्य और संबद्ध कानूनों के क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान, विकास और प्रसार कार्य का संचालन भी करता है।

बख्तरबंद कोर केंद्र एवं स्कूल (एसीसीएंडएस), अहमदनगर

10.91 वर्ष 1948 में, प्रशिक्षण स्कन्ध, रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र और बख्तरबंद कोर डिपो और रिर्कोडर्स को अहमदनगर स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ पहले से ही लड़ाकू वाहन स्कूल संचालित था, जिसमें सभी को बख्तरबंद कोर केंद्र और स्कूल के निर्माण के लिए विलय कर दिया गया, और साथ ही बख्तरबंद कॉर्प्स रिर्कोडर्स बनाने के लिए आपस में मिला दिया गया। इन विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए छह स्कन्ध मौजूद हैं, अर्थात् स्कूल ऑफ आर्मर्ड वेल्फेयर, स्कूल ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग रेजिमेंट, ड्राइविंग और मॉटेनेंस रेजिमेंट, ऑटोमोटिव रेजिमेंट और आर्ममेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रेजिमेंट।

विदेशी प्रशिक्षण

10.92 **भारत में मित्र देशों के लिए प्रशिक्षण:** भारत के विदेशी प्रशिक्षण सहयोग की संभावना और इसके विस्तार में

उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, भारतीय सेना की व्यावसायिकता और प्रशिक्षण मानकों पर प्रतिबिंबित भारतीय सेना से जुड़ने के लिए दुनिया भर के देशों से अनुरोध में उत्तरोत्तर वृद्धि देखी गई है। मित्र देशों के पाठ्यक्रमों की सदस्यता के लिए मांग लगातार बढ़ रही है। प्रशिक्षण वर्ष 2017-18 में 238 विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 2650 रिक्तियों की पेशकश की गई है, जो 56 मित्र देशों के लिए प्रदान की गई है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान रिक्तियों की पेशकश में 300 से अधिक की वृद्धि हुई है।

10.93 **निर्मित पाठ्यक्रम/ग्रुप ट्रेनिंग:** चयनित क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और क्षमता की वृद्धि के लिए विशेष तौर पर निर्मित पाठ्यक्रम/ग्रुप ट्रेनिंग का आयोजन पड़ोसी मित्र देशों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं/आकांक्षाओं और भारत के लिए सामरिक महत्व के देशों हेतु किया जा रहा है। वर्तमान प्रशिक्षण वर्ष में 1464 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए ऐसे 54 पाठ्यक्रमों की योजना अफगानिस्तान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, नाइजीरिया, म्यांमार और बांग्लादेश के लिए की तैयार की गई है।

10.94 **विदेश में भारतीय सेना का प्रशिक्षण:** विदेशों द्वारा पाठ्यक्रमों की सदस्यता भी हमारे विदेशी प्रशिक्षण प्रयासों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि लक्ष्यीकरण, तकनीकी उन्नयन और रक्षा सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से मित्र देशों के साथ प्रशिक्षण के माध्यम से सहयोग प्रदान करता है। विदेशों में पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए आने वाले कर्मियों की संख्या वर्ष 2013-14 में 58 से बढ़कर, वर्तमान वित्तीय वर्ष में 90 हो गई है। इसका उद्देश्य भविष्य में इस विशिष्ट क्षेत्र में अधिक संख्या में पाठ्यक्रमों की सदस्यता प्राप्त करना है।

10.95 **मित्र देशों के साथ कर्मिकों द्वारा प्रशिक्षण दौरे/आदान-प्रदान:** भारतीय सेना प्रशिक्षण संस्थानों से प्रतिनिधिमंडलों के विदेश दौरे/कई मित्र देशों से प्रतिनिधिमंडल का आगमन और कार्यक्रमों का मित्र देशों के साथ आदान-प्रदान हमारी रक्षा प्रतिबद्धता नीति के हिस्से के तौर पर आयोजित किए

जाते हैं। इस वर्ष के लिए तैयार की गई योजना के अनुसार 14 मित्र देशों के 229 कर्मियों ने भारत देश की यात्रा की और 200 कर्मिकों ने 26 विदेशी यात्रा 16 मित्र देशों में की।

आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट (एएमयू) महू

10.96 शूटिंग सेना की सबसे बड़ी विशेषता होती है। वर्तमान में, एएमयू में लगभग 85 सटीक निशानेबाजों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दो ओलंपिक रजत पदक, एथेंस ओलंपिक 2004 और लंदन ओलंपिक 2012 के दौरान इन निशानेबाजों द्वारा जीते गए हैं। इसके अलावा, एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक आईएसएसएफ विश्व कप 2017 में सूबेदार जीतू राय द्वारा जीता गया है।

आर्मी रोइंग नोड (एआरएन), पुणे

10.97 एआरएन में 2.2 किमी लम्बी एक विश्व स्तर की रोविंग चैनल है, जो कि दुनिया में इस तरह का एकमात्र चैनल है। वर्तमान में सेना के करीब 80 शीर्ष कर्मियों को इस नोड में प्रशिक्षित किया जा रहा है। सेना के अधिकारियों ने एशियाई खेलों और ओलंपिक सहित कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश को गौरवान्वित किया है।

आर्मी याचिंग नोड (एवाईएन), मुंबई

10.98 एवाईएन में प्रशिक्षित सेना के नाविक राष्ट्रीय सर्किट पर अपना दबदबा बनाया है और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एशियाई खेलों और ओलंपिक में भाग लेकर कई पदक भी जीते हैं। वर्तमान में सेना के 60 नाविक एआईएन, मुंबई में नौकाओं के विभिन्न वर्गों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

आर्मी इक्वेस्ट्रियन नोड (एएएन), मेरठ

10.99 एईएन में शो-जंपिंग, ड्रेसेज और इवेंटिंग के लिए विश्व स्तर के बुनियादी प्रशिक्षण ढांचे विद्यमान हैं। सेना के इक्वेस्ट्रियन टीम ने महाद्विपीय स्तर (एशियाई खेलों) में अंतरराष्ट्रीय पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है।





पूर्व सैनिक पुनर्वास और कल्याण





पूर्व सैनिक पुनर्वास और कल्याण

11.1 पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू), देश में पूर्व सैनिकों (ईएमएम) के कल्याण और पुनर्वास की विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम बनाता है। विभाग के दो प्रभाग अर्थात् पुनर्स्थापन और पेंशन प्रभाग हैं और इसके 3 संबद्ध कार्यालय हैं, नामतः केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय (केएसबी सचिवालय), महानिदेशालय (पुनर्वास) (डीजीआर) और केंद्रीय संगठन, पूर्व सैनिकों अंशदान योजना (सीओ ईसीएचएस)। केएसबी सचिवालय, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के साथ ही कल्याणकारी निधियों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। केएसबी सचिवालय को अपने कार्य में 32 राज्य सैनिक बोर्डों (आरएसबी) और 392 जिला सैनिक बोर्डों (जेएसबी) से सहायता मिलती है, जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होते हैं। पुनर्वास महानिदेशालय का कार्यालय ईएसएम के सेवानिवृत्ति-पूर्व और सेवानिवृत्ति-उपरांत प्रशिक्षण, पुनः नियोजन और स्व-नियोजन आदि की विभिन्न नीतियों/कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। डीजीआर

को अपने कार्य में पाँच कमांड्स में से प्रत्येक में 5 पुनर्वासन महानिदेशालय क्षेत्रों (डीआरजेड) से सहायता मिलती है। सीओ, ईसीएचएस पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी होता है।

कल्याण

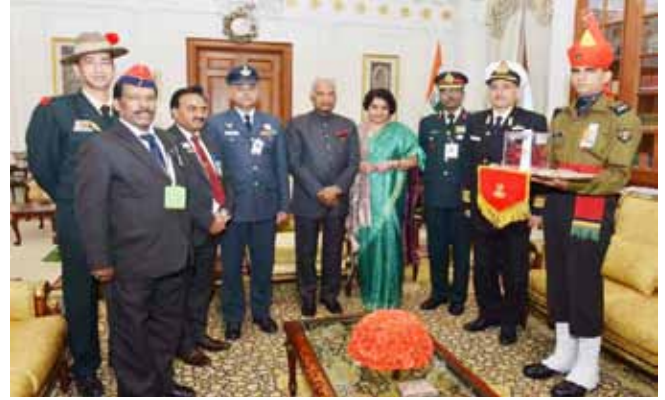
11.2 केएसबी सचिवालय, युद्ध में मारे गए शहीदों की विधवाओं विकलांग सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास और कल्याण के पुनर्वास और कल्याण के लिए भारत सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी भारत सरकार का शीर्ष निकाय है। कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य की राजधानियों में स्थित आरएसबी और जिला स्तर पर स्थित जेडएसबी के जरिए कार्यान्वित की जाती है। आरएसबी/जेडएसबी की स्थापना का खर्च, केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा साझा किया जाता है। निधियन पैटर्न,

विशेष श्रेणी के राज्यों, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 75:25 और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आरएसबी/जेएसएसबी की स्थापना/रखरखाव के लिए प्रदान किया जाने वाले केन्द्रीय हिस्से की इस प्रयोजनार्थ केएसबी सचिवालय को आवंटित रक्षा सेवाएं अनुमान (डीएसई) को आवंटित बजट से प्रतिपूर्ति की जाती है। केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में 31 दिसंबर, 2017 तक 27.41 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

11.3 राज्य की राजधानी/जिला मुख्यालयों में अपने पेंशन संबंधी मामलों और सीएसडी कैंटीन, अस्पताल आदि की सुविधाएं लेने जैसे अन्य मामलों के निपटान के लिए पूर्व-सैनिकों के अल्पावधिक दौरों के दौरान उन्हें उपयुक्त और किफायती आवास प्रदान करने के लिए केएसबी सचिवालय, डीएसई के सैनिक विश्राम गृहों (एसआरएच) के निर्माण की लागत का 50% हिस्सा साझा करता है। सैनिक विश्राम गृहों का रख-रखाव, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने संसाधनों/निधियों से किया जाता है। 23 जुलाई, 2017 को तत्कालीन रक्षा मंत्री द्वारा दिल्ली में केन्द्रीय सैनिक विश्रामगृह (एसआरएच) का उदघाटन किया गया। सीएसआरएच से दिल्ली आने वाले पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं की बोर्डिंग/लॉजिंग की समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी।

सशस्त्र सेना ध्वज दिवस

11.4 देश के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा बलिदान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष देश भर में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना ध्वज दिवस मनाया जाता है। इस दिन, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं/विकलांग पूर्व-सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण/पुनर्वास के लिए सांकेतिक ध्वज पिन से लगाकर जनता से स्वैच्छिक अंशदान एकत्र किया जाता है। 7 दिसंबर, 2017 को सशस्त्र सेना ध्वज दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर, 2017 की अवधि के दौरान ध्वज दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियों, उदाहरणार्थ टी. वी. स्पॉट का प्रसारण, मशहूर हस्तियों/आईकॉन्स के संदेश, मुद्रण/सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया।



केएसबी सचिवालय के अधिकारी 7 दिसंबर, 2017 को भारत के राष्ट्रपति को सांकेतिक ध्वज पिन करते और दान संग्रहित करते हुए



केएसबी सचिवालय के अधिकारियों ने 7 दिसंबर, 2017 को भारत के प्रधानमंत्री को सांकेतिक ध्वज पिन करते और दान संग्रहित करते हुए

सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष

11.5 युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं, ईएसएम और उनके आश्रितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए निधियन का प्रमुख स्रोत डीएसई बजट के अलावा, सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष (एएफएफडीएफ) है। एएफएफडीएफ कोष पर अर्जित ब्याज में से 7.5% कोष में वापस लगा दिया जाता है और शेष राशि का उपयोग पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों की कल्याण और पुनर्वास योजनाओं के लिए किया जाता है। 29 दिसंबर, 2017 तक लगभग 24 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की गई है। 31 दिसंबर, 2017 तक एएफएफडीएफ का कोष 290.70 करोड़ रुपये है। इस निधि का संचालन, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली प्रबंधन समिति और सचिव, डीईएसडब्ल्यू की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति के तत्वावधान में केएसबी सचिवालय द्वारा किया जाता है।

रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष (आरएमईडब्ल्यूएफ) योजनाएं

11.6 इससे पहले, इस निधि को रक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष (आरएमडीएफ) के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर अब रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष (आरएमईडब्ल्यूएफ) रख दिया गया है। इस निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता पहचाने गए व्यक्तियों की जरूरतों उदाहरणार्थ पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों के दरिद्रता अनुदान, बाल शिक्षा और विवाह अनुदान आदि के लिए प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान (31 दिसंबर, 2017 तक) आरएमईडब्ल्यूएफ के तहत पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों के पक्ष में 46.02 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष (आर्मी बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड)

11.7 आम जनता के सदस्यों द्वारा रक्षा मंत्री को बहुत-सारे अनुरोध किए जाने के बाद, रक्षा मंत्रालय, पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग में एक नया कोष नामतः 'सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष (आर्मी बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड) (एबीसीडब्ल्यूएफ) स्थापित किया गया है जिसने युद्ध में मारे गए और घायल सैनिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, खासतौर पर फरवरी, 2016 में सियाचिन घटना के बाद, जिसमें एक हिमस्खलन में 10 सैनिक दबे रह गए थे। यह कोष चैरिटेबल एंडॉमेंट्स अधिनियम, 1890 के तहत बनाया गया है। रक्षा मंत्री द्वारा उपसचिव को इस कोष का संरक्षक/कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस कोष के प्रबंधन और प्रशासन की निगरानी, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली एक प्रबंध समिति द्वारा की जाएगी।

11.8 सेना के युद्धों में, जो प्राणघातक हैं, 60% या उससे अधिक विकलांगता और विकलांगता की वजह से अवैध ठहराए गए हताहत के मामलों में 2.00 लाख वित्तीय सहायता और 60% से कम विकलांगता वाले मामलों में 1.00 लाख वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सेना समूह बीमा से वित्तीय सहायता, अनुग्रह राशि और सेना कल्याण कोष से सहायता से अतिरिक्त सहायता होगी। इस कोष से युद्ध में मारे गए 162 सैनिकों के पहले बैच के लिए 3.24 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना

11.9 पूर्व सैनिकों और पूर्व भारतीय तटरक्षक बल के आश्रित बच्चों और विधवाओं की उच्चतर शिक्षा/तकनीकी शिक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना 2006 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पूर्व सैनिकों के बच्चों और विधवाओं को सालाना 5500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्तियों की संख्या को 4000 से बढ़ाकर 5500 कर दिया गया है जिसका लड़कों और लड़कियों के बीच समान रूप वितरण किया जाएगा। इस योजना को प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय रक्षा कोष से वित्त पोषित किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि, लड़कों के लिए 2,000/- रुपए और लड़कियों के लिए 2,250/- प्रति माह है जिसका भुगतान वार्षिक आधार पर किया जाता है। 31 दिसंबर, 2017 तक 14680 लाभार्थियों को 37.93 करोड़ रुपये की राशि संवितरित कर दी गई है।

एएफएफडीएफ की अन्य कल्याण योजनाएं

11.10 **गंभीर रोगों के लिए वित्तीय सहायता:** गैर-पेंशनभोगी पीबीओआर और उनके आश्रितों सहित अधिकारियों को, अधिकतम व्यय 1.25 लाख रुपए (हृदय रोगों, जोड़ प्रत्यार्पण आदि के लिए) और 0.75 लाख प्रतिवर्ष (कैंसर और डायलिसिस के उपचार के लिए) के अध्यक्षीन क्रमशः 90% और कुल व्यय के 75% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना नेपाल में रह रहे भारतीय ईएसएम के लिए भी लागू है, जब तक देश में ईसीएचएस चालू नहीं हो जाता।

11.11 **संशोधित स्कूटर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता:** 50% या उससे अधिक विकलांगता वाले उन पूर्व-सैनिकों को संशोधित स्कूटर की खरीद के लिए 57,500/- रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद विकलांग हुए हों। इस योजना के तहत 31 दिसंबर, 2017 तक 6,24,441/- रुपये संवितरित किए गए हैं।

11.12 **युद्ध स्मारक छात्रावास (डब्ल्यूएमएचएस) को अनुदान:** पूर्व सैनिकों/युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं की संतानों के कल्याण के लिए भारतीय सेना के संबंधित रेजिमेंटल सेंटर द्वारा युद्ध स्मारक छात्रावास चलाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत, पूर्व सैनिकों/युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों की संतानों को 1350/-रुपये प्रति माह प्रति बच्चा प्रदान किए जाते हैं। योजना

के तहत 31 दिसंबर 2017 तक 24.99 लाख रुपये संवितरित किए गए हैं।

11.13 **पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्रों (पीआरसी) को अनुदान:** रखरखाव/अनुरक्षण के लिए 30,000/- रूपए प्रति वर्ष प्रति कैंदी के अलावा, 20.00 लाख वार्षिक अनुदान (पीआरसी किर्की के संबंध में 1 अप्रैल, 2016 से बढ़ाकर 1.00 करोड़ रूपए कर दिया गया है) और पीआरसी मोहाली को 10.00 लाख रूपए प्रदान किए जाते हैं। ये केन्द्र पैराप्लेजिक/ टेट्राप्लेजिक पूर्व-सैनिकों के पुनर्वास के लिए स्वायत्त संगठन के रूप में संचालित किए जा रहे हैं।

चिकित्सा/दंत महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण

11.14 केएसबी सचिवालय को ईएसएम के वार्डों के लिए भारत सरकार के नामित के तौर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एमबीबीएस और बीडीएस सीटें आवंटित की गई हैं। शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए कुल 20 सीटें आवंटित और संवितरित की गईं।

11.15 **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आरएसबी के डीएसडब्ल्यू के निदेशकों/सचिवों की वार्षिक बैठक:** 6 अप्रैल, 2017 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आरएसबी के डीएसडब्ल्यू के निदेशकों/सचिवों की वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी। सचिव, ईएसडब्ल्यू ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का मुख्य उद्देश्य पूर्व-सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन को गति प्रदान करना था और पूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी।

11.16 **क्षेत्रीय बैठकें:** चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गईं:

- (क) डीएसडब्ल्यू के निदेशकों की तीसरी दक्षिण क्षेत्रीय बैठक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार एवं पांडिचेरी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों सहित 31 मई 2017 को हैदराबाद में ईएसडब्ल्यू के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।
- (ख) डीएसडब्ल्यू के निदेशकों की तीसरी उत्तर क्षेत्रीय बैठक ईएसडब्ल्यू के सचिव की अध्यक्षता में देहरादून (उत्तराखंड) में 19 जुलाई, 2017 को आयोजित की गई

थी। उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

- (ग) डीएसडब्ल्यू के निदेशकों की तीसरी केन्द्रीय क्षेत्रीय बैठक, ईएसडब्ल्यू की अध्यक्षता में 13 दिसंबर, 2017 को भोपाल (मध्य प्रदेश) में आयोजित की गई थी। केन्द्रीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

11.17 **स्वच्छता पखवाड़ा:** 1 दिसंबर, 2017 से 15 दिसंबर, 2017 की अवधि के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया था। 1 दिसंबर, 2017 को सभी कर्मचारी सदस्यों ने स्वच्छ भारत अभियान की शपथ ली थी। इस अवधि के दौरान, सुझावों/अभिनव विचारों को साझा करने और स्वच्छता संबंधी कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए एसएपी के अलावा एक कार्यशाला भी आयोजित की गई और एक स्लोगन लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसके कार्यक्रमों में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के दो विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। उन्होंने नागरिकों को शामिल करके प्रेरणा, प्रोत्साहन, व्यवहार परिवर्तन अभियानों के माध्यम से, नागरिकों में व्यवहार परिवर्तन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।



पुनर्वास

11.18 पुनर्स्थापन महानिदेशालय (डीजीआर) का मुख्य बल पूर्व-सैनिकों के पुनर्स्थापन, पुनर्वास और कल्याण पर है। प्रतिवर्ष लगभग 60,000 सशस्त्र बल कर्मचारी सेवानिवृत्ति होते हैं या उन्हें सक्रिय सेवा से कार्यभार मुक्त किया जाता है, जिनमें से ज्यादातर 35 से 45 वर्ष की अपेक्षाकृत कम आयु श्रेणी में होते हैं और उन्हें अपने परिवारों के गुजारे के लिए दूसरे कैरियर की जरूरत है। ये

कर्मचारी राष्ट्र निर्माण के लिए उपलब्ध एक मूल्यवान, अनुशासित, सुप्रशिक्षित, समर्पित और प्रतिभाशाली पूल हैं। निम्नलिखित के माध्यम से पुनर्स्थापन का प्रयास किया जाता है:-

- पूर्व-सैनिकों को नए काम/नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करने और उन्हें पुनः नियोजन तलाशने में मदद करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके उनके कौशल का उन्नयन करना।
- सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास।
- पूर्व-सैनिकों को कॉर्पोरेट क्षेत्र में पुनः नियोजन की सुविधा के लिए पूर्व-सक्रिय कार्रवाई।
- स्व-नियोजन योजनाओं के जरिए रोजगार प्रदान करना।
- उद्यमी उद्यमों में सहायता करना।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

11.19 डीजीआर को सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों को दूसरे कैरियर में संक्रमण को आसान बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ऐसा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनर्स्थापन पाठ्यक्रमों के जरिए कॉर्पोरेट जगत में उत्कृष्टता के लिए अपेक्षित कौशल से लैस करके किया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि डीजीआर द्वारा सभी कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्र कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप हों, जुलाई 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ समझौते ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। अगस्त 2016 से डीजीआर सिर्फ केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के संस्थानों में, नियामक निकायों के साथ संरेखित नियामकों/संस्थानों द्वारा संचालित संस्थानों में ही पुनर्स्थापन कार्यक्रम चला रहा है, और डीजीआर द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रम न्यूनतम एनएसक्यूएफ स्तर 5 के है (सिवाय जब किसी व्यक्ति के लिए क्षेत्र में परिवर्तन शामिल हो, जहां यह स्तर 4 का होगा)। एमएसडीई ने मानकों और लागतों के संबंध में कौशल प्रशिक्षण संबंधी "सामान्य नियम" भी प्रकाशित किए हैं। रक्षा मंत्रालय को संक्रमण प्राप्त करने और रक्षा कर्मियों के लिए कौशल प्रशिक्षण में लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा वाधवानी फाउंडेशन के कौशल

विकास नेटवर्क ट्रस्ट (एसडीएनटी) के साथ भी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन पहलों से लागतों के मानकीकरण सुनिश्चित करने के अलावा, डीजीआर द्वारा पुनर्स्थापन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के मानक को उन्नत करने में मदद मिली है।

11.20 **अधिकारियों का प्रशिक्षण:** 2016-17 से परिकल्पित सभी अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में संशोधन किया गया था और केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों को जारी रखा गया था जो सरकार/सरकार के स्वायत्त संस्थानों द्वारा संचालित किए जाते हैं। अधिकारी पाठ्यक्रम, प्रबंधन में अल्पावधिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (3-6 माह), होंगे जो चयनित कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का हिस्सा होंगे। अधिकारी पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है।

11.21 **जेसीओ/ओआर और समतुल्य प्रशिक्षण:** डीजीआर, अवधि जेसीओ/ओआर के लिए डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक का समतुल्य पाठ्यक्रम आयोजित करता है। ये पाठ्यक्रम मान्यताप्राप्त संस्थानों में संचालित किए जाते हैं और सरकार द्वारा 100 % पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान किया जाता है। मार्च 2016 तक, रेजिमेंट सेंटर (किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति या पेंशन ड्रिल के दौरान 4 सप्ताह की अवधि) और अखिल भारतीय संस्थानों, दोनों पर जेसीओ/ओआर/समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। अप्रैल 2016 से, डीजीआर द्वारा रेजिमेंटल केंद्रों पर आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बंद कर दिए गए हैं और प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई है। सेना, विभिन्न रेजिमेंटल केंद्रों पर एनएसडीसी प्रोटोकॉल के अनुरूप, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए संक्रमण ला रही है। डीजीआर ने अपनी भूमिका पूरे भारत में प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने तक सीमित कर रहा है। अगस्त 2016 से, केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है जो सरकारी संस्थानों या सरकारी निकायों/विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे हैं या एनएसडीसी द्वारा न्यूनतम एनएसक्यूएफ स्तर 4 के अनुरूप प्रमाणित हैं। उन्नत मानकों और जेसीओ/ओआर के लिए कौशल प्रशिक्षण के मानकीकरण से, नौकरी/पुनर्स्थापन की बेहतर संभावनाओं की आशा है। डीजीआर द्वारा नौकरी उन्मुखी पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन से जेसीओ/ओआर और समतुल्य के प्लेसमेंट के लिए और अधिक मार्ग प्रशस्त होंगे।

11.22 जनवरी 2017 से दिसंबर 2017 तक दिए गए प्रशिक्षण का विवरण निम्नानुसार है:

(क) संस्थानों में अधिकारी	: 476
(ख) संस्थानों में जेसीओ/ओआर	: 5,192
(ग) कुल कैलेंडर वर्ष 2017 में	: 5,668

रोजगार के अवसर:

11.23 ईएसएम के लिए केंद्र सरकार में रोजगार के अवसर: केंद्र सरकार ने सिविल जीवन में उनके पुनर्स्थापन के लिए ईएसएम के लिए सरकारी नौकरियों में निम्नलिखित सीमा तक आरक्षण प्रदान किया है:

- (क) सभी अर्ध-सैनिक बलों में सहायक कमांडेंट के स्तर तक पदों में रिक्तियों का 10%
- (ख) केंद्र सरकार के विभागों में समूह 'ग' के सीधी भर्ती पदों में रिक्तियों का 10%; और समूह 'घ' में सीधी भर्ती पदों में रिक्तियों का 20%
- (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समूह 'ग' पदों में 14.5% रिक्त पद और समूह 'घ' में 24.5% रिक्त पद (विकलांग पूर्व सैनिकों/युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए 4.5% सहित) आरक्षित रखे गए हैं।
- (घ) **सरकारी क्षेत्र के बैंकों में समूह 'ग' पदों में 14.5%** रिक्त पद और समूह 'घ' में 24.5% रिक्त पद (विकलांग पूर्व सैनिकों/युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए 4.5% सहित) आरक्षित रखे गए हैं।
- (ङ) **रक्षा सुरक्षा कोर में 100%** डीजीआर, डाटा संकलित करने और इन आरक्षणों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है।

11.24 **रोजगार के लिए पंजीकरण:** डीजीआर मुख्य रूप से रक्षा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान कर स्थापित होने में मदद करने के लिए उत्तरदायी है। डीजीआर की विभिन्न योजनाओं जैसे सामान्य रोजगार (सरकारी/पीएसयू/कॉर्पोरेट में नौकरियों), सुरक्षा एजेंसी योजना, सीएनजी योजना, सीओसीओ योजना, पेट्रोल पम्प प्रबंधन और कोयला परिवहन कंपनी आदि में आगे पंजीकरण

के लिए पूर्व सैनिक डीजीआर के पास पंजीकृत हैं (शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन)। डीजीआर और आरएसबी के माध्यम से स्व-नियोजन योजनाओं से इतर स्थायी/अनुबंधात्मक नौकरियों के लिए प्रायोजित कर्मियों के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

(क) डीजीआर के जरिए : 9604 (31 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार)

(ख) आरएसबी/जेडएसबी के जरिए : 14622 (30 जून, 2017 की स्थिति के अनुसार)

11.25 **सुरक्षा एजेंसी योजना:** इस योजना का उद्देश्य ईएसएम (अधिकारी) के जरिए ईएसएम द्वारा किसी भी प्रकार के अर्जन को आसान बनाना है जब तक उसे रोजगार न मिल जाए और साथ ईएसएम को खाली न रहने देना एवं समाज में सकारात्मक योगदान देना है। कई सरकारी कार्यालय, केंद्रीय सरकार क्षेत्र के उपक्रम, बैंक, कॉर्पोरेट्स और शैक्षिक संस्थान आदि डीजीआर पैनलबद्ध सुरक्षा एजेंसियों से सुरक्षा कवर की मांग कर रहे हैं। इस योजना के तहत 2017 के दौरान नियोजित ईएसएम की संख्या 33,394 हैं और कुल 458 सुरक्षा एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है।

स्व रोजगार के लिए योजनाएं

11.26 **डीजीआर के जरिए रोजगार के अवसर:** डीजीआर, अधिकारियों और जेसीओ/ओआर और उनके समकक्ष और विधवाओं के लिए दूसरे कैरियर के रूप में उनके रोजगार और कल्याण के लिए योजनाएं संचालित करता है। प्रमुख योजनाएं और सृजित रोजगार नीचे दिए गए हैं:

- (क) **कोयला परिवहन योजनाएं और टिपर संलग्नक:** इस योजना कोल इंडिया लिमिटेड और डीजीआर के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर चलाई जाती है। इस योजना के तहत, ईएसएम (अधिकारी) से एक कंपनी बनती है जिसमें तीन ईएसएम (अधिकारी) होते हैं और कंपनी अधिनियम, 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 2013) के तहत पंजीकृत है। यह कंपनी कोयले के परिवहन और लदान का काम करती है। यह सेवा कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी सहायक कंपनियों को प्रदान की जाती है। वर्ष 2017 में, इस योजना से 21 अधिकारी, 127 जेसीओ/ओआर

और 67 विधवा/विकलांग ईएसएम/आश्रित लाभान्वित हुए हैं।

- (ख) **मदर डेयरी दूध बूथ और फल एवं सब्जी (सफल) दुकान:** मदर डेयरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ईएसएम (जेसीओ और ओआर) को पहले से निर्मित और पूरी तरह से सुसज्जित दूध की दुकानें/बूथ प्रदान करता है, जबकि इसकी फल एवं सब्जियों की दुकानें, (सफल) एनसीआर में ईएसएम और उनके आश्रित बेटों के लिए खुली हैं। वर्ष 2017 में, मदर डेयरी और सफल योजना से 320 ईएसएम लाभान्वित हुए हैं।



- (ग) **गोपालजी खाद्य और डेयरी लिमिटेड:** यह ईएसएम जेसीओ/ओआर और उनके समकक्ष के लिए समय पर खरी उतरी अच्छी आमदनी वाली स्व-रोजगार योजना है।
- (घ) **गोपालजी फार्म फ्रेश लिमिटेड:** यह ईएसएम जेसीओ/ओआर और उनके समकक्ष के लिए समय पर खरी उतरी अच्छी आमदनी वाली स्व-रोजगार योजना है।
- (ङ) **ईएसएम (अधिकारी) द्वारा एनसीआर में सीएनजी स्टेशन का प्रबंधन:** आईजीएल द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर, डीजीआर, एनसीआर में इन सीएनजी पंपों का प्रबंधन करने के लिए आईजीएल के लिए ब्रिगेडियर/समतुल्य रैंक तक के सेना, नौसेना और वायु सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों का प्रायोजक नाम रहा है। इस पैनल की चयन प्रक्रिया, आईजीएल का पूर्ण विशेषाधिकार है। इस योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है जिससे फरीदाबाद और गुरुग्राम को शामिल करते हुए पूरा एनसीआर कवर हो जाए। इस योजना से 31 दिसंबर, 2017 तक 35 ईएसएम (अधिकारी) लाभान्वित हुए हैं।



- (च) **सेना के अधिशेष श्रेणी ट 'ख' वाहनों का आवंटन:** वे पूर्व सैनिक और रक्षा कार्मिकों की विधवाएं, जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हुई है, सेना के अधिशेष श्रेणी ट 'ख' वाहनों के आवंटन के पात्र हैं। वर्ष 2017 के दौरान डीजीआर के पास कुल 33 ईएसएम पंजीकृत थे।
- (छ) **8% आरक्षण कोटे में से एलपीजी/खुदरा आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) के आवंटन के लिए डीजीआर पात्रता प्रमाणपत्र जारी करना:** ईएसएम/सशस्त्र बल कर्मियों की विधवाओं/आश्रितों को तेल उत्पाद एजेंसी के आवंटन संबंधी मौजूदा सरकारी नीति के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएण्डएनजी) के पास एलपीजी एजेंसी और खुदरा आउटलेट (पेट्रोल और डीजल) के वितरण के लिए में 8% आरक्षित कोटा है। डीजीआर का कार्यालय, पात्र ईएसएम/विधवा/आश्रित को अपेक्षित पात्रता प्रमाण पत्र जारी करता है जिसे चयन के समय तेल कंपनी को मूल में प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। अंतिम चयन, तेल कंपनी द्वारा लाट के ड्रा द्वारा किया जाता है। 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 की अवधि के दौरान ईएसएम/विधवाओं/ आश्रितों को कुल 384 डीजीआर पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
- (ज) **कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा संचालित खुदरा आउटलेटों का प्रबंधन:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नीति के अनुसार, अधिकतम तीन वर्ष तक सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों और जेसीओ द्वारा अनुबंधित आधार पर प्रबंधन के लिए कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी संचालित (सीओसीओ) खुदरा आउटलेट उपलब्ध कराए जाते हैं। यह योजना पूरे

भारत में संचालित है। अधिकारियों को अपने संबंधित आरएसबी के माध्यम से डीजीआर और जेसीओ के कार्यालय द्वारा प्रायोजित कराया जाना आवश्यक है। 1 जनवरी, 2017 से दिसंबर 31, 2017 की अवधि के दौरान तेल विपणन कंपनियों से प्राप्त मांग से डीजीआर कार्यालय द्वारा कुल 66 अधिकारियों को प्रायोजित किया गया है।

11.27 **ईएसएम नौकरी मेले:** अगस्त 2014 में डीजीआर और भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर, सभी तीनों सेवा मुख्यालयों की मदद से पूरे भारत में डीजीआर ईएसएम नौकरी मेलों का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन काफी अधिक सफल रहे हैं और कॉर्पोरेट क्षेत्र में ईएसएम के रोजगार के लिए ऐसा सरल, प्रत्यक्ष और निःशुल्क मंच उपलब्ध कराने में अपने वांछित उद्देश्य को हासिल करने के लिए संचालित किए जाते हैं। वर्ष 2017 में ईएसएम के लिए पाँच नौकरी मेले आयोजित किए गए थे जिनका विवरण नीचे तालिका संख्या 11.1 में दिया गया है:

तालिका संख्या 11.1

स्थान	तारीख	भागीदारी		प्रस्तुत की गई रिक्तियाँ (लगभग)
		कॉर्पोरेट नियोक्ता	ईएसएम	
लखनऊ	22 जनवरी, 2017	38	2485	1200
विशाखापटनम	26 फरवरी, 2017	42	2600	1150
अहमदाबाद	9 जुलाई, 2017	30	650	600
रांची	22 सितंबर, 2017	27	1600	750
मुंबई	25 नवंबर, 2017	45	1100	1000

11.28 **प्रचार और जागरूकता अभियान:** लखनऊ, विशाखापटनम, अहमदाबाद, रांची और मुंबई में आयोजित नौकरी मेलों के लिए विभिन्न समाचार पत्रों (हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं) में विज्ञापन जारी किए गए थे। इसके अलावा, ईएसएम नियोजनीयता के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में पूरे भारत में विज्ञापन प्रकाशित कराए गए थे। इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट जगत के समक्ष ईएसएम की संभावनाओं और सामान्य रूप से, पर्यावरण का प्रदर्शन करना था। इसके अतिरिक्त, सैनिक पुनर्वास पत्रिका (द्विभाषी पत्रिका) के दो संस्करण प्रकाशित किए गए थे, जिनमें

सेवानिवृत्त होने वाले और सेवानिवृत्त हो चुके सैनिकों के लिए बहुमूल्य जानकारी शामिल होती है; ईएसएम के प्रभावी पुनर्स्थापन के लिए डीजीआर द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों का विवरण भी इसमें शामिल था। ईएसएम पुनर्वास के लिए योजनाओं के विवरण वाले पोस्टर भी मुद्रित किए गए थे और हर जगह मुद्रित प्रचार सामग्री वितरित की गई थी। इसके अलावा, ईएसएम के पुनर्स्थापन के लिए 'ट्विटर' के माध्यम से भी डीजीआर गतिविधियों का प्रभावी प्रचार किया गया था।



स्वास्थ्य देखभाल

11.29 1 अप्रैल, 2003 से पूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) लागू की गई थी। इस योजना का अक्टूबर 2010 में विस्तार किया गया था। ईसीएचएस का उद्देश्य देशभर में व्याप्त ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों, सेवा चिकित्सा सुविधाओं और सिविल पैनलबद्ध/सरकारी अस्पतालों के नेटवर्क के जरिए पूर्व सैनिकों (ईएसएम) और उनके आश्रितों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। यह योजना, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की तर्ज पर बनाई गई है और इसे भारत सरकार

द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। इसका प्रयास, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए पैनलबद्ध अस्पतालों का उपयोग करके यथासंभव नकद रहित उपचार सुनिश्चित करना है।

11.30 इस योजना के लिए नीति ढांचा सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसका कार्यकारी नियंत्रण पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। योजना का प्रबंधन सशस्त्र बलों के मौजूदा ढांचे द्वारा किया जाता है ताकि प्रशासनिक व्यय को न्यूनतम किया जा सके।

11.31 ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक 'बाह्य रोगी देखभाल' प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं जिनमें परामर्श, आवश्यक जांच और दवाओं की व्यवस्था शामिल हैं। सेवा अस्पतालों, सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता के साथ-साथ ईसीएचएस के पास सिविल चिकित्सा सुविधाओं के जरिए विशेष परामर्श, जांच और 'आंतरिक रोगी देखभाल' (अस्पताल में भर्ती) प्रदान की जाती है।

ईसीएचएस नेटवर्क

11.32 **केंद्रीय संगठन:** सर्वोच्च स्तर पर दिल्ली में स्थित केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस है, जो रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय में एडजुटेंट जनरल के माध्यम से स्टाफ कमेटी के प्रमुखों के अधीन कार्य करता है। केन्द्रीय संगठन की अध्यक्षता सेवारत मेजर जनरल द्वारा की जाती है। ईसीएचएस का कार्यकारी नियंत्रण पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग (डीओईएसडब्ल्यू) में निहित होता है।

11.33 **क्षेत्रीय केंद्र:** पूरे देश में कुल 28 क्षेत्रीय केंद्र फैले हैं। क्षेत्रीय केंद्र, केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस और सेवा मुख्यालयों कमांड की मौजूदा श्रृंखला के तहत कार्य करते हैं। ये क्षेत्रीय केंद्र, अपने अधीन ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स के संचालन और कामकाज की निगरानी करते हैं और साथ ही, ईसीएचएस वाले सिविल अस्पतालों के पैनलबद्ध के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हैं और ऑनलाइन बिलिंग के लिए भी उत्तरदायी होते हैं।

11.34 **पॉलिक्लिनिक:** सरकार द्वारा नेपाल में छह पॉलिक्लिनिकों सहित कुल 432 ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक स्वीकृत की गई हैं। आज की स्थिति के अनुसार, भारत में 426 ईसीएचएस पॉलिक्लिनिकों में से 424 को कार्यात्मक बना दिया गया है। इन पॉलिक्लिनिकों को पूरी तरह भाड़े के प्रशिक्षित पेशेवरों

द्वारा संचालित किया जाता है जिनमें कुछ रिक्तियां ईएसएम के लिए आरक्षित होती हैं। स्टेशन मुख्यालय, कर्मचारियों को भाड़े पर लेने और पॉलिक्लिनिकों का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के साथ ही भूमि के समय पर अधिग्रहण और ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक भवनों के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होता है।

वर्तमान स्थिति

11.35 **ईसीएचएस सदस्यता:** इस योजना के तहत कुल लाभार्थी 52 लाख अनुमानित है।

11.36 **पॉलिक्लिनिक और सिविल पैनलबद्ध चिकित्सा सुविधाएं:** विगत एक वर्ष में (जनवरी 2017 से) ईसीएचएस के पास 240 अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाएं सूचीबद्ध की गई हैं। अब इस योजना में ईसीएचएस लाभार्थियों को नकदरहित उपचार प्रदान करने के लिए 2540 सिविल अस्पताल पैनलबद्ध हैं। अब इसकी पहुँच कश्मीर घाटी तक बढ़ा दी गई है हालाँकि, आपात स्थिति में, सदस्यों को भुगतान पर गैर-पैनलबद्ध अस्पताल में चिकित्सा कराने की अनुमति है। उनके चिकित्सा उपचार बिलों की अनुमोदित (सीजीएचएस) दर पर प्रतिपूर्ति की जाती है।

11.37 **बजट:** ईसीएचएस में प्रशासनिक व्यय बहुत कम होता है, क्योंकि इस योजना में मौजूदा सेवा अवसंरचना का इस्तेमाल होता है और पॉलिक्लिनिक में दवाओं का वितरण 100% अनुबंधित कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। ईसीएचएस को बजट आवंटन में समय बीतने के साथ-साथ बढ़ोत्तरी हुई है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आबंटन 2911.50 करोड़ रूपए है।

11.38 **शिकायत और मुकदमा न्यूनकरण योजना (सीएलआरएस):** ईसीएचएस ने सीएलआरएस का शुभारंभ किया है, जिसमें शिकायतों और मुकदमों में कमी लाने के लिए पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों सहित सभी हितधारकों, सभी सोपानकों पर ईसीएचएस कर्मचारियों और अस्पतालों/अन्य सेवा प्रदाताओं को केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस के साथ सीधे संचार के लिए आमंत्रित किया जाता है। इससे देखभाल नीति तैयार करने और कार्यान्वयन के उपायों पर अधिक फोकस करने में मदद मिलेगी जिससे पूर्व-सैनिकों के समय और संसाधनों की बचत होगी जिन्होंने निस्वार्थ तरीके से देश की सेवा की है।

11.39 **ईसीएचएस टोल-फ्री हेल्पलाइन:** सदस्यता, उपचार और रोजगार संबंधी प्रश्नों के समाधान के लिए 1800-114-115

पर सभी ईसीएचएस सदस्यों के लिए ईसीएचएस टोल- फ्री हेल्पलाइन उपलब्ध कराई गई है। यह सेवा सोमवार से शुक्रवार तक 0900-1700 कार्य-समयावधि के दौरान उपलब्ध है। ईसीएचएस के बारे में पैनलबद्ध सुविधाओं की सूची, सदस्यता के रूपों और नवीनतम नीतियों आदि सहित सभी जानकारी www.echs.gov.in पर उपलब्ध है।

पेंशन सुधार

11.40 परिपक्वता पूर्व सेवानिवृत्ति के मामलों में विकलांगता तत्व प्रदान करना: सरकार ने 19 मई 2017 को सशस्त्र बलों के उन कार्मिकों को विकलांगता तत्व प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किया है, जिन्हें सैन्य सेवा के कारण या उससे अधिक हुई विकलांगता के बावजूद सेवा में बनाए रखा गया था और बाद में, जिन्होंने 1 जनवरी, 2006 से पहले समयपूर्व/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। यह निर्णय लिया गया है कि सभी 2006 से पहले से सभी सशस्त्र सेना कर्मियों को, जिन्हें विकलांगता और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अन्यथा के बावजूद सेवा में बनाए रखा गया था, इसके अध्यक्षीन सेवानिवृत्ति/सेवा पेंशन या सेवानिवृत्त/सेवा ग्रेच्युटी के अलावा विकलांगता तत्व/युद्ध में घायल का दर्जा प्रदान किया जाएगा कि उनकी विकलांगता, सैन्य सेवा की वजह से थी या सैन्य सेवा से अधिक बढ़ गई और उन्होंने इस विकलांगता के बदले में एकमुश्त मुआवजा नहीं लिया था।

11.41 डीएससी कार्मिकों के लिए दूसरी सेवा पेंशन के लिए सेवा में कमी माफ करना: सरकार ने डीएससी (रक्षा सुरक्षा कोर) के कर्मियों के संबंध में दूसरी सेवा पेंशन प्रदान करने के लिए सेवा में कमी को माफ करने के संबंध में 20 जून, 2017 का पत्र जारी किया है। यह निर्णय लिया गया है कि अर्हक सेवा में अभाव की माफी मैरिट पर और उचित मामलों में प्रदान की जाए ताकि व्यक्ति कम से कम एक सेवा पेंशन के लिए योग्य बन जाए। डीएससी कार्मिक के संबंध में दूसरी सेवा पेंशन प्रदान करने के लिए अर्हक सेवा में कमी में माफी की कोई मैरिट नहीं है। सेवा पेंशन प्रदान करने के लिए सेवा में कमी को माफ करने के पीछे यह इरादा है कि व्यक्ति बिल्कुल बेसहारा न रह जाए बल्कि कम से कम एक सेवा पेंशन का योग्य होना चाहिए और यह स्पष्ट किया जाता है कि दूसरी सेवा पेंशन प्रदान करने के लिए कोई माफी अनुमत नहीं होगी।

11.42 सशस्त्र बल पेंशनभोगियों/पेंशनभोगियों के परिवार को निर्धारित चिकित्सा-भत्ता (एफएमए): सरकार ने ऐसे मामलों में सशस्त्र बल पेंशनभोगियों/पेंशनभोगियों के परिवार को निर्धारित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) प्रदान करने के संबंध में रक्षा मंत्रालय का दिनांक 29 अगस्त 2017 का पत्र जारी किया है जिन मामलों में सेवानिवृत्ति की तारीख 1 अप्रैल, 2003 से पूर्व थी और जिन्होंने सशस्त्र बल अस्पतालों में बाह्य रोगी विभाग/एमआई कमरे की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं लिया है और जो ईसीएचएस के सदस्य नहीं हैं। 1 जुलाई, 2017 से एफएमए की राशि को 500/- रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000/- रूपए प्रति माह कर दिया गया है।

11.43 नामांकन न किए जाने के मामले में पेंशन/परिवार पेंशन के बकाए का भुगतान: सरकार ने (i) उन मामलों में पेंशन के बकाए का भुगतान, जिनमें पेंशन (नामांकन) नियमावली, 1983 के बकाए के भुगतान के तहत कोई वैध नामांकन नहीं किया गया है; और (ii) परिवार पेंशन के बकाए का भुगतान करने के संबंध में 29 अगस्त, 2017 का आदेश जारी किया गया है। कानूनी उत्तराधिकारी-प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि मृत पेंशनभोगी का कोई नामिति या "वसीयत" न होने की स्थिति में, पेंशन के बकाए का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

- (i) कानूनी प्राधिकार प्रस्तुत न किए जाने पर, पेंशन वितरण एजेंसी (पीडीए) के आदेश के तहत, यदि बकाया पेंशन दावे की कुल राशि 25,000/- रूपए से अधिक नहीं है, बशर्त वह दावाकर्ता के अधिकार के बारे में संतुष्ट हो।
- (ii) यदि दावा की गई बकाया पेंशन की कुल राशि 25,000/- रूपए से अधिक है किंतु 2,50,000/- से अनधिक है, तो भुगतान के लिए देय सकल राशि के लिए प्रतिभूतियों के भुगतान पर, जो राष्ट्रपति की ओर से, संविधान के अनुच्छेद 299(i) के तहत विधिवत अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाए और स्वीकार किया जाए, विधिवत स्टांपित फार्म आईएफएए-642 फॉर्म में क्षतिपूर्ति बांड के निष्पादन पर रक्षा लेखा प्रमुख नियंत्रक (पेंशन) के आदेशों के तहत।
- (iii) कोई भी संदेह होने पर और ऐसे मामलों में, जिनमें बकाया राशि 2,50,000/- रूपए से अधिक है, भुगतान

केवल कानूनी प्राधिकार प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को ही किया जाएगा।

11.44 **7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिश पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर पेंशन का संशोधन:** सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन— 1 जनवरी, 2016 से पूर्व रक्षा बल पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की पेंशन का संशोधन करने के संबंध में 4 सितंबर, 2017 का आदेश जारी किया है। इस आदेश के जरिए (i) 1 जनवरी, 2016 तक विकलांगता तत्व प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर, 2015 को आहरित विकलांगता तत्व की मौजूदा दर को 2.57 गुणक से गुणा कर विकलांगता पेंशन के विकलांगता तत्व को संशोधित किया गया है; (ii) विकलांग/मृत्यु के मामलों में कैडेट (सीधे)/एनओके को देय अनुग्रह भुगतान, सैन्य प्रशिक्षण की वजह से या उसके द्वारा गंभीर होने के कारण चिकित्सा आधार/कैडेट (सीधे) की मृत्यु को अवैध किए जाने की स्थिति में अब तक लागू शर्तों पर ही दिए जाएंगे। (क) 9000/— प्रतिमाह की मासिक अनुग्रह राशि और (ख) विकलांगता के मामले में, यदि विकलांगता की डिग्री 100% से कम होती है, यथानुपात कमी किए जाने के अध्यक्षीन, विकलांगता की अवधि के दौरान 100% विकलांगता के लिए 16,200/— रूपए प्रति माह की दर से अनुदान पुरस्कार देय होगा; (पपप) अब, 1 जुलाई, 2017 से 6750/— प्रति माह की बढ़ी एकसमान दर पर सतत उपस्थिति भत्ता (सीएए) देय होगा चाहे रैंक कुछ भी क्यों न हो।

11.45 सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन— 1 जनवरी, 2016 को या उसके बाद घोड़ासाजी में (in harness) सेवानिवृत्त या मृत अधिकृत अधिकारियों, कनिष्ठ अधिकृत अधिकारियों और अन्यस रैंकों के संबंध कैजुअल्टी पेंशन पुरस्कारों के संदर्भ में अधिसूचित पेंशन पुरस्कारों सहित पेंशन/उपदान/पेंशन/परिवार पेंशन की गणना को विनियमित करने प्रावधानों में संशोधन के संबंध में 4 सितंबर, 2017 का आदेश जारी किया है। इस आदेश के जरिए, 2016—के बाद रक्षा बलों के पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में सरकार का निर्णय कार्यान्वित किया है।

11.46 सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन— 1 जनवरी, 2016 से पूर्व रक्षा बल पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की पेंशन

का संशोधन, के संबंध में दिनांक 5 सितंबर, 2017 का आदेश जारी किया है। इस आदेश के जरिए, 2016 से पूर्व रक्षा बल पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की पेंशन के संबंध में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में सरकार का निर्णय कार्यान्वित किया गया है।

11.47 **पीएसयू में अवशोषितों के लिए पूर्ण पेंशन की बहाली:** सरकारी ने उन रक्षा सेवा कर्मियों के संबंध में पूरी पेंशन बहाल करने के संबंध में 18 सितंबर, 2017 को आदेश जारी किया है जिन्होंने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में अवशोषण पर एकमुश्त भुगतान आहरित कर लिया था। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 23 जून, 2017 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए, 2010 की सिविल अपील सं. 6048 और 6371 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 1 सितंबर, 2016 के आदेशों के लाभ, उन सभी अवशोषित लोगों को प्रदान करने का निर्णय लिया है जिन्होंने 100% एकमुश्त राशि ले ली थी और जिनके मामले में, 100% एकमुश्त राशि के भुगतान की तारीख से 15 साल की अवधि के समापन के बाद उनकी पूरी पेंशन बहाल कर 15 वर्ष की अवधि के बाद 1/3 पेंशन बहाल की गई थी। यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के 23 जून, 2017 के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान, पीएसयू/स्वायत्त निकायों में अवशोषित सभी सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों पर भी यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

11.48 **तलाकशुदा बेटियों के लिए परिवार पेंशन:** 17 नवंबर, 2017 को रक्षा मंत्रालय के पत्र अनुसार सशस्त्र बल कर्मियों की तलाकशुदा बेटियों को परिवार पेंशन देने के मामले में, जिन मामलों में सक्षम न्यायालय में तलाक की कार्यवाही, कर्मचारी/पेंशनभोगी या उसके पति/उसकी पत्नी के जीवनकाल के दौरान शुरू कर दी गई थी किंतु तलाक उसकी मृत्यु के बाद हुआ बशर्ते दावाकर्ता पेंशन प्रदान किए जाने के लिए अन्य सभी शर्तों को पूरा करती हो। ऐसे मामलों में, परिवार की पेंशन तलाक की तारीख से शुरू होगी।

प्रमुख विशेषताएं

11.49 सेना के युद्धों में, जो प्राणघातक हैं, 60% या उससे अधिक विकलांगता और विकलांगता की वजह से अवैध ठहराए गए हताहत के मामलों में 2.00 लाख वित्तीय सहायता और 60% से कम विकलांगता वाले मामलों में 1.00 लाख वित्तीय सहायता

प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय, पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग में एक नया कोष नामतः "सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष (आर्मी बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड) (एबीसीडब्ल्यूएफ)' स्थापित किया गया है। यह सेना समूह बीमा से वित्तीय सहायता, अनुग्रह राशि और सेना कल्याण कोष से सहायता से अतिरिक्त सहायता होगी। इस निधि के प्रबंधन और प्रशासन की निगरानी रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली एक प्रबंध समिति द्वारा की जाएगी। यह योजना 17 जुलाई, 2017 को अधिसूचित की गई है और यह 1 जनवरी, 2016 से लागू कर दी गई है।

11.50 जून 2017 से दृष्टिबाधित ईएसएम के लिए विशेष पेंशन को 500/- रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 4000/- रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है।

11.51 सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष से वित्तपोषित रक्षामंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष (आरएमईडब्ल्यूएफ) योजना के तहत गैर-पेंशनभोगी पूर्व-सैनिकों/विधवाओं (65 वर्ष से अधिक आयु) को दरिद्रता अनुदान की दर 1 अप्रैल, 2017 से 1000/- रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 4000/- रूपए प्रतिमाह कर दी गई है।

11.52 **प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट (एएलसी) के लिए स्वीकृति:** सरकार ने 22 अगस्त, 2017 को प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट (एएलसी) की अवधारणा संचालित करने को भी अनुमोदन प्रदान किया है। 29 अगस्त 2017 को सभी कमांड मुख्यालयों और क्षेत्रीय केंद्रों को कार्यान्वयन संबंधी अनुदेश दिए गए हैं। इसके अलावा, डीजीएफएमएस कार्यालय के समन्वय में, चिकित्सा खरीद की जिम्मेदारी वरिष्ठ कार्यकारी चिकित्सा अधिकारियों (एसईएमओ) को विकेंद्रीकृत कर दी गई है।

11.53 **वयोवृद्ध रोगी देखभाल और सहायता (वीपीसीए)**
दल: 8 सितंबर, 2017 को वयोवृद्ध रोगी देखभाल और सहायता (वीपीसीए) दल अनुमोदित किए गए हैं और ऐसे वातावरण में प्रकाशित किए गए हैं जिनमें ये दल दुराचारों को बंद करने के साथ ही हमारे वृद्धों की परेशानियां दूर करने के लिए स्टेशन कमांडर के तहत जाँच करेंगी। इन्हें दिल्ली, जलंधर और त्रिवेंद्रम में शुरू किया गया है और छह माह की परीक्षण अवधि के बाद पूरे भारत में शुरू किया जाएगा।





सशस्त्र बलों और सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग





सशस्त्र बलों और सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग

12.1 देश की सरहदों की रक्षा करने की मुख्य जिम्मेदारी के अलावा, सशस्त्र बल प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्यों में कानून और व्यवस्था के रख-रखाव और/या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में नागरिक प्राधिकारियों को समय पर सहायता भी प्रदान करते हैं। प्रतिवेदन अवधि के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा प्रदान की गई सहायता का विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है।

भारतीय सेना

12.2 वर्ष के दौरान, भारतीय सेना की माँग 43 बार की गई थी जिसमें नागरिक प्राधिकारियों की सहायता में 6 मेडिकल टीमों और 33 इंजीनियर टास्क फोर्स (ईटीएफ) को शामिल करते हुए 104 कॉलम तैनात किए गए थे। उदाहरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तौर पर प्रदान की गई सहायता का विवरण आगे के अनुच्छेदों में दिया गया है।

कानून और व्यवस्था बनाए रखना

12.3 **दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल):** गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर, 8 जून 2017 से प्रभावी करते हुये दार्जिलिंग और कलिमपोंग जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा सेना की माँग की गई, जहाँ शांति का उल्लंघन हो रहा था और स्थिति उपलब्ध पुलिस बलों के नियंत्रण से परे थी। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सिविल प्रशासन हेतु सेना कॉलम तत्काल प्रदान किए गए थे। कलिमपोंग और दार्जिलिंग में तैनात कॉलम को क्रमशः 18 और 20 जुलाई, 2017 को वापस बुला लिया गया था।

12.4 **पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़:** दिनांक 25 अगस्त 2017 को एक धार्मिक संप्रदाय के प्रमुख के विरुद्ध फैसले के बाद आंदोलनकारियों द्वारा विरोध के कारण हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण नागरिक प्रशासन द्वारा की गई माँग के चलते सेना कॉलम को

कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के विभिन्न जिलों में तैनात किए गए थे। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में तैनात किए गए कॉलम क्रमशः 29 अगस्त और 8 सितंबर 2017 को वापस बुला लिए गए।

बाढ़ राहत अभियान असम

12.5 **मोरिगाँव:** दिनांक 12 और 15 जुलाई 2017 को मोरिगाँव जिले और आसपास के गाँवों में बाढ़ की स्थिति के कारण, एक सेना कॉलम और एक ईटीएफ के साथ 3 x बीएयूटी तैनात किए गए थे। सहायता के दौरान 36 नागरिकों को बचाया गया तथा कॉलम को क्रमशः 14 और 17 जुलाई, 2017 को वापस बुला लिया गया।

12.6 **धुबरी:** दिनांक 11 अगस्त, 2017 को धुबरी में बचाव एवं राहत अभियान के लिए एक सैन्य कॉलम उसी दिन तैनात किया गया था। वहाँ 13 नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया था और 20 अगस्त 2017 को सेना कॉलम को वापस बुला लिया गया।

12.7 **कोकराझार:** दिनांक 12 अगस्त 2017 को कोकराझार में बचाव एवं राहत अभियान के लिए, उसी दिन सेना के दो कॉलम वहाँ तैनात किए गए थे। वहाँ 524 नागरिकों को बाहर निकाला गया और 20 अगस्त 2017 को सेना के कॉलम को वापस बुलाया गया।

12.8 **नौगाँव:** दिनांक 13 अगस्त, 2017 को नौगाँव में बचाव एवं राहत अभियान के लिए एक सैन्य कॉलम उसी दिन तैनात किया गया था। जिसमें 68 नागरिकों को बाहर सुरक्षित निकाला गया था और 20 अगस्त 2017 को सेना के कॉलम को वहाँ से वापस बुलाया गया था।

गुजरात

12.9 **सुरेन्द्र नगर:** दिनांक 22 जुलाई 2017 को कुडा और आसपास के गाँवों में बचाव एवं राहत अभियान के लिए सामान्य क्षेत्र कुडा और आसपास के गाँवों में बाढ़ की स्थिति के कारण, एक सैन्य कॉलम और एक ईटीएफ को एक चिकित्सा अधिकारी के साथ तैनात किया गया। सेना कॉलम द्वारा 35 नागरिकों को बचाया गया और 25 जुलाई, 2017 को कॉलम को वहाँ से वापस बुलाया गया था।

12.10 **बनासकांठा:** सामान्य क्षेत्र दीसा, खरिया, थारा और

आसपास के गाँवों में बनास नदी के बाढ़ के कारण, दिनांक 24 जुलाई 2017 को बचाव और राहत कार्य के लिए एक मेडिकल टीम के साथ तीन सेना कॉलम और छह ईटीएफ तैनात किए गए थे। जिसमें 2665 नागरिकों को सेना कॉलम द्वारा सुरक्षित निकाला गया। एक कॉलम को दिनांक 26 जुलाई, 2017 को वापस बुलाया गया था और अन्य कॉलम को 31 जुलाई, 2017 को वहाँ से वापस बुलाया गया था।

12.11 **पाटन:** दिनांक 26 जुलाई, 2017 को सामान्य क्षेत्र राधनपुर, सामी और आसपास के गाँवों में बाढ़ के कारण बचाव और राहत अभियान के लिए उसी दिन तीन सेना कॉलम और सात ईटीएफ तैनात किए गए थे। सेना के कॉलम की सहायता से 665 नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। दिनांक 2 अगस्त 2017 को सेना के कॉलम वहाँ से हटाये गए।

12.12 **आनंद:** सामान्य क्षेत्र आनंद और आस-पास के इलाकों में बाढ़ के कारण बचाव और राहत अभियान के लिए दिनांक 27 जुलाई, 2017 को सेना के दो कॉलम तैनात किए गए थे। सेना कॉलम द्वारा 113 नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया था और कॉलम को उसी दिन वहाँ से वापस बुलाया गया।

12.13 **अहमदाबाद:** सामान्य क्षेत्र विंजोल, अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में बाढ़ के कारण यहाँ दिनांक 27 जुलाई 2017 को एक सेना कॉलम को बचाव और राहत कार्य के लिए तैनात किया गया था और उसी दिन उन्हें वापस बुलाया गया।

राजस्थान

12.14 **अरनियाली:** सामान्य क्षेत्र अरनियाली और आसपास के गाँवों में बाढ़ के कारण बचाव और राहत कार्यों के लिए दिनांक 25 जुलाई, 2017 को एक सेना कॉलम तैनात किया गया था। जिसमें 24 नागरिकों को बाहर निकाला गया और 27 जुलाई, 2017 को सेना कॉलम को वापस बुलाया गया।

12.15 **जालोर:** दिनांक 24, 28 और 29 जुलाई, 2017 को सामान्य क्षेत्र में भेटला, संचोरे, अहोर पावता, गुधा और गंधव गाँव के आसपास के क्षेत्रों में, चार सेना कॉलम और तीन ईटीएफ को बचाव और राहत अभियान के लिए तैनात किया गया था। जिसमें 768 नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया था और 1 अगस्त 2017 सेना के कॉलम वहाँ से हटाये गए।

12.16 **उत्तरलाई:** दिनांक 24 जुलाई, 2017 को, उसी दिन उत्तरलाई के वायु सेना स्टेशन पर एक सेना कॉलम तैनात किया गया था और 2 अगस्त 2017 को सेना कॉलम को वापस बुलाया गया।

बिहार

12.17 **कटिहार और किशनगंज:** कटिहार और किशनगंज में बचाव और राहत अभियान के लिए 14 अगस्त 2017 को कदवा, आजमनगर और कटिहार में एक सेना कॉलम और एक ईटीएफ तैनात किया गया था जिसमें छह बीएसएयूटी और छह ओबीएम शामिल थे। इसमें 282 नागरिकों को बचाया गया, और 1040 नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और 5950 खाद्य पैकेट वितरित किए गए। दिनांक 30 अगस्त 2017 को सेना के कॉलम को वहाँ से वापस बुला लिया गया।

12.18 **अररिया:** अररिया में बचाव और राहत अभियान के लिए दिनांक 14 अगस्त 2017 को अररिया में एक सेना कॉलम और एक ईटीएफ तैनात किया गया था जिसमें चार बीएसएयूटी और चार ओबीएम शामिल थे। इसमें 139 नागरिकों को बचाया गया, और 1515 नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और 1915 की संख्या में भोजन पैकेटों का वितरण किया गया। उसके बाद, दिनांक 31 अगस्त, 2017 को बचाव और राहत अभियान के लिए बेगूसराय स्थानांतरित करते हुए सैन्य कॉलम को वहाँ से हटा लिया गया।

12.19 **मधुबनी:** मधुबनी में बचाव और राहत अभियान के लिए दिनांक 15 अगस्त 2017 को मधुबनी में एक सेना कॉलम और एक ईटीएफ तैनात किया गया, बचाव और राहत अभियान के लिए दो बीएसएटी और दो ओबीएम के साथ कुल 246 नागरिकों को बचाया गया, और 824 नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और 3450 भोजन पैकेट वितरित किए गए। दिनांक 30 अगस्त 2017 को सेना के कॉलम को वहाँ से हटा लिया गया।

12.20 **सीतामढ़ी:** दिनांक 14 अगस्त 2017 को सीतामढ़ी में बचाव एवं राहत कार्य के लिए, एक सेना कॉलम और एक ईटीएफ को तथा दिनांक 15 अगस्त 2017 को बचाव और राहत कार्य के लिए दो बीएसएटी और दो ओबीएम के साथ तैनात किया गया था। जिसमें 90 नागरिकों को बचाया गया, 295 नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और 1775 भोजन पैकेट वितरित किए

गए। उसके बाद सेना के कॉलम को अगस्त 20, 2017 को बचाव और राहत अभियान के लिए मुजफ्फरपुर छावनी स्थानांतरित कर दिया गया और दिनांक 29 अगस्त, 2017 को उन्हें वहाँ से हटा लिया गया।

12.21 **मोतिहारी, पूर्व चंपारण:** मोतिहारी, पूर्व चंपारण में बचाव एवं राहत अभियान के लिए एक सेना कॉलम और एक ईटीएफ को दिनांक 15 अगस्त 2017 को दो बीएसयूटी और दो ओबीएम के साथ तैनात किया गया था। 160 नागरिकों को बचाया गया, 3091 नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और 25455 भोजन पैकेट वितरित किए गए। इसके बाद दिनांक 26 अगस्त, 2017 को बचाव और राहत अभियान हेतु सेना के कॉलम खगरिया के लिए चले गए और दिनांक 31 अगस्त 2017 को वहाँ से उन्हें वापस बुलाया गया।

12.22 **बेतिया, पश्चिम चंपारण:** दिनांक 15 अगस्त 2017 को बचाव और राहत अभियान के लिए बेतिया, पश्चिम चंपारण में एक सेना कॉलम और एक ईटीएफ को दो बीएसएटी और दो ओबीएम के साथ तैनात किया गया। जिसमें 98 नागरिकों को बचाया गया, 755 नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और 16350 भोजन पैकेट वितरित किए गए। उसके बाद दिनांक 27 अगस्त, 2017 को सेना कॉलम को बचाव और राहत अभियान के लिए समस्तीपुर भेज दिया गया जहाँ से दिनांक 31 अगस्त 2017 को उन्हें वापस बुलाया गया।

12.23 **गोपालगंज:** गोपालगंज में बचाव और राहत अभियान के लिए, मधुबनी और सीतामढ़ी में तैनात सेना कॉलम से सैनिक दिनांक 19 अगस्त 2017 को दो बीएसएटी और दो ओबीएम के साथ बचाव और राहत अभियान के लिए गोपालगंज पहुँचे। वहाँ किसी भी नागरिक को बचाया नहीं गया, हालाँकि 100 नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और 2180 भोजन पैकेट वितरित किए गए। दिनांक 30 अगस्त 2017 को सेना के कॉलम को वापस बुला लिया गया।

उत्तर प्रदेश

12.24 **गोरखपुर:** बचाव और राहत अभियान के लिए दिनांक 17 अगस्त 2017 को गोरखपुर में एक सेना कॉलम और एक ईटीएफ को पाँच बीएसएयूटी और पाँच ओबीएम के साथ तैनात किया गया था। जिसमें 550 नागरिकों को बचाया गया, 2700

नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और 34000 भोजन पैकेट वितरित किए गए। वहाँ से उन्हें दिनांक 30 अगस्त 2017 को वापस बुला लिया गया।

नागालैंड

12.25 **दीमापुर:** दीमापुर के सामान्य क्षेत्र और आसपास के गाँवों में बाढ़ की स्थिति के कारण दिनांक 20 जुलाई 2017 को दीमापुर के पास 4 मील गाँव में, दो सेना कॉलम और एक ईटीएफ तैनात किए गए थे। उन्हें उसी दिन वहाँ से वापस बुला लिया गया था।

जम्मू एवं कश्मीर

12.26 **सोपोर, अवन्तिपुर, पंजीपुरा, हामरे:** विभिन्न स्थानों पर बचाव और राहत अभियानों के लिए 4 अप्रैल, 2017 को सोपोर, अवन्तिपुर, पंजीपुरा, हामरे में तीन सेना कॉलम तैनात किए गए थे। वहाँ लगभग 70 नागरिकों को विभिन्न स्थानों से बचाया गया था। सभी टीमों को 6 अप्रैल, 2017 को वापस बुला लिया गया था।

मणिपुर

12.27 **थौबल:** बचाव और राहत कार्यों के लिए एक सेना कॉलम को दिनांक 2 जुलाई, 2017 को हैबिंग, मखुंग, थौबल जिला, मणिपुर में तैनात किया गया था। सेना के कॉलम ने प्रभावित स्थानों से असुरक्षित नागरिकों को निकाला। दिनांक 4 जुलाई 2017 को कॉलम को वापस बुला लिया गया था।

बचाव और राहत अभियान

12.28 **तवाघाट, पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) में बादल फटना:** तवाघाट पांगला रोड पर दिनांक 13 अगस्त 2017 को मंगती में बादल फटने की वजह से भारी बाढ़ के कारण छह सेना कर्मी और दो सेना एएलएस वाहन गायब हो गए थे। सेना के चार कॉलम ने लापता लोगों और वाहनों का पता लगाने के लिए मंगती के पास खोज अभियान चलाया। छह सेना कर्मियों के शवों को प्राप्त नहीं किया जा सका है।

12.29 **इतालवी नागरिक (लद्दाख) का बचाव:** लद्दाख (निमालिंग कैम्पिंग ग्राउंड) में एक इतालवी नागरिक के बचाव के लिए सैन्य खुफिया (विदेशी प्रभाग) के माध्यम से 20 सितंबर, 2017 को डिफेंस अटैचे, इटली से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। खोज अभियान चलाया गया और व्यक्ति के शव को दिनांक 23 सितंबर,

2017 को बरामद किया गया।

अन्य प्रकार की सहायता

12.30 **कानपुर (उत्तर प्रदेश) में इमारत का ढहना:** उत्तर प्रदेश के कानपुर में वायु सेना स्टेशन चकरी के पास दिनांक 1 फरवरी, 2017 को एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई। सेना सहायता के लिए दिनांक 1 फरवरी, 2017 को जिलाधीश, कानपुर से माँग प्राप्त हुई थी। उसी दिन बचाव और राहत अभियान के लिए दो सेना कॉलम और एक ईटीएफ तैनात किए गए थे। 18 लोगों को बचाया गया था और चार शवों को स्थान से बरामद किया गया था। दिनांक 4 फरवरी, 2017 को सेना के कॉलम को वहाँ से वापस बुलाया गया।

12.31 **केरल में बेली ब्रिज का निर्माण:** कल्लड़ा नदी के पार एनाथू में एक अस्थायी बेली ब्रिज के निर्माण के लिए केरल सरकार से माँग प्राप्त हुई थी। सिविल प्रशासन के लिए पहुँच-सड़क हेतु निर्माण के कॉंक्रीट कार्य, इसके मुख्य-सड़क पर मिलान और सड़क निर्माण को 2 अप्रैल 2017 को पूरा कर लिया गया था। पुल निर्माण स्थान पर तैनात इंजीनियरों के एक फील्ड प्लैटून और भारतीय सेना इंजीनियर्स द्वारा अस्थायी बेली ब्रिज का निर्माण पुल-निर्माण दल द्वारा 3 अप्रैल 2017 को पूरा किया गया और इसे लोगों के उपयोग के लिए खोला गया।

12.32 **नमामी ब्रह्मपुत्र महोत्सव (असम):** असम में नमामी ब्रह्मपुत्र महोत्सव के आयोजन के संबंध में, दिनांक 28 मार्च, 2017 को त्योहार स्थल पर एक 86 मीटर फुट-ब्रिज और एक पक्की सड़क का निर्माण किया गया, जिसे दिनांक 4 अप्रैल, 2017 को त्योहार के आयोजन के बाद खत्म कर दिया गया। एक अतिरिक्त क्विक रिएक्शन टीम (क्यूआरटी) और जैमर के साथ एक बम डिस्पोजेबल टीम को दिनांक 31 मार्च 2017 से स्थान पर तैनात किया गया था और इन्हें 5 अप्रैल, 2017 को वापस बुलाया गया था।

12.33 **अररिया (बिहार) में बेली ब्रिज का निर्माण:** अररिया में अस्थायी बेली ब्रिज के निर्माण के लिए दिनांक 19 अगस्त, 2017 को, अस्थायी पुल के निर्माण की व्यवहार्यता की जाँच के लिए स्थल का सैनिक-परीक्षण किया गया। सैनिक-परीक्षण के बाद, 120 फीट बेली ब्रिज का निर्माण सेना अभियंताओं द्वारा किया गया था और इसे दिनांक 28 अगस्त 2017 को सिविल प्रशासन को सौंप दिया गया।

12.34 **कटिहार (बिहार) में पोंटून पुल का निर्माण:** दिनांक 22 अगस्त 2017 को कटिहार जिले के तेलता रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पुल के लिए एक पोंटून ब्रिज के निर्माण हेतु, ब्रिजिंग उपकरणों के साथ एक ईटीएफ को तैनात किया गया था। पुल का निर्माण दिनांक 23 अगस्त 2017 को पूरा किया गया। रेलवे पुल के संधारण के बाद, सिविल प्रशासन द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2017 को पोंटून ब्रिज को खोल दिया गया।

12.35 **कोट्टोपी, जोगिंदर नगर (हिमाचल प्रदेश):** राष्ट्रीय राजमार्ग-154 पर मंडी से 15 किलोमीटर आगे, दो बसों के यात्रियों के बचाव के लिए जो कि कोट्टोपी में गहरी खाई में गिर गई थी, सेना के दो कॉलम के साथ, उसी दिन एक चिकित्सा दल को तैनात किया गया था। सेना के बचाव दल द्वारा 46 शव बरामद किए गए और सेना के कॉलम को दिनांक 16 अगस्त, 2017 को वापस बुलाया गया।

12.36 **मुंबई (महाराष्ट्र) में तीन रेलवे स्टेशनों पर रेलवे फुट ओवर ब्रिज का निर्माण:** हाल ही में मुंबई के एल्फिन्स्टन रोड रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के मद्देनजर, मुंबई में चयनित स्थानीय रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त फुट-ओवर पुलों के निर्माण के दौरान बुनियादी ढाँचे के विस्तार के लिए तत्काल मदद की आवश्यकता थी। तदनुसार, भारतीय सेना अभियंताओं को मुंबई में एल्फिन्स्टन रोड रेलवे स्टेशन, करी रोड रेलवे स्टेशन और आंबिवली रेलवे स्टेशन पर तीन फुट-ओवर ब्रिज के निर्माण का कार्य सौंपा गया है।

12.37 **डॉक्टरों द्वारा हड़ताल (राजस्थान):** दिनांक 6 नवंबर, 2017 को राजस्थान के सर्विग डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा हड़ताल की घोषणा की गई थी। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, तथा जैसलमेर, कोटा, अलवर, सूरतगढ़ और उदयपुर जिले के जिलाधीश से आपातकालीन अस्थायी व्यवस्था हेतु माँग प्राप्त हुई थी। राजस्थान राज्य हेतु चिकित्सा सहायता के लिए पाँच चिकित्सा दल तैनात किए गए थे। जिसमें 2206 मरीजों का इलाज किया गया और सभी मेडिकल टीमों को दिनांक 13 नवंबर, 2017 को वापस कर दिया गया।

12.38 राजस्थान के सर्विग डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा फिर से दिनांक 18 दिसंबर, 2017 को हड़ताल की घोषणा कर दी गई। जोधपुर और अलवर के जिलाधीश से, मुख्यालय दक्षिणी और मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान के माध्यम से सेना द्वारा मेडिकल

सहायता के लिए दिनांक 18 दिसंबर, 2017 को एक माँग प्राप्त हुई थी। कोटा, अलवर और जोधपुर जिलों के रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई थी। सहायता के दौरान कुल 4148 मरीजों का इलाज किया गया था और मेडिकल टीमों को दिनांक 29 दिसंबर, 2017 को वापस बुलाया गया।

12.39 **भोपाल (मध्य प्रदेश) में आग:** दिनांक 17 दिसम्बर 2017 को संत हिरदाराम कॉम्प्लेक्स (कपड़ा मार्केट), बैरागढ़, भोपाल में आग की घटना की सूचना दी गई थी। आग के नियंत्रण के लिए सेना से आग से लड़ने वाले उपकरणों की आपूर्ति हेतु मुख्यालय पश्चिम उप क्षेत्र द्वारा जिलाधीश, भोपाल से एक आग्रह प्राप्त हुआ था। उसी दिन अग्निशमन उपकरण और अग्निशमन दल के साथ स्थान पर सेना के एक कॉलम को तैनात किया गया और इसे उसी दिन वहाँ से वापस भी बुला लिया गया।

अभ्यास प्रलयसहायम: 2017

12.40 संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन दिसंबर 2015, के दौरान प्रधान मंत्री के निर्देशों के अनुसार, मानवीय सहायता आपदा राहत (एचएडीआर) के अभ्यासों को सभी हितधारकों के बीच तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से आयोजित किए जाने की योजना बनाई जा रही है।

12.41 हैदराबाद में दक्षिणी कमान के तत्वावधान के तहत, व्यायाम प्रलय सहायम-2017 का आयोजन दिनांक 22 से 24 सितंबर, 2017 के बीच किया गया था। यह व्यायाम शहरी बाढ़ स्थिति के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) संचालन पर आधारित था। राज्य प्रशासन के साथ मिलकर मुख्यालय एकिकृत रक्षा कर्मचारी (मुख्यालय आईडीएस) के तत्वावधान में 'हैदराबाद में शहरी बाढ़' की स्थापना के साथ सेना द्वारा आयोजित यह पहला अभ्यास था।

12.42 केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला और नगर निगम तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गैर सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों जैसे अन्य एजेंसियों के सभी हितधारकों के प्रयासों के समन्वय के उद्देश्य से इस अभ्यास का आयोजन किया गया था जिससे कि बाढ़ राहत प्रयासों के प्रत्येक चरण में योजनाओं की प्रभाविता, संगठनात्मक कौशल और निर्णय समर्थन प्रणाली का जायजा लिया जा सके। दिनांक 22 और 23 सितंबर, 2017 को हैदराबाद के हुसैन सागर झील में सभी हितधारकों और स्थितिक प्रदर्शन से जुड़े रक्षा प्रबंधन

और मल्टी एजेंसी अभ्यास, कॉलेज में टेबल-टॉप-एक्सरसाइज (टीटीई) के बाद एक सेमिनार से शुरू हुआ। अभ्यास के दौरान कई सीख उभर कर सामने आई और आगे विचार विमर्श के लिए सभी हितधारकों के बीच इन्हें साझा किया गया।

भारतीय नौसेना (आईएन)

12.43 प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारतीय नौसेना विभिन्न बचाव और राहत कार्यों के लिए नागरिक अधिकारियों को सहायता प्रदान करती रही है। इसमें बाढ़ के दौरान स्थानीय आबादी, दूसरे स्थानों से निकासी के संचालन, विभिन्न स्थानों पर डाइविंग सहायता, खोज और बचाव इत्यादि में सहायता शामिल है। वर्ष के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा प्रदान की गई सहायता का विवरण आगामी अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है।

12.44 **राज्य के तटीय सुरक्षा बलों के लिए प्रशिक्षण और सहायता:** भारतीय नौसेना सीआईएसएफ और बीएसएफ कर्मियों के समुद्री अभिविन्यास प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से शामिल है। यह प्रशिक्षण आईएनएस चिल्का में आयोजित किया जाता है, जो भारतीय नौसेना के नवनियुक्त नाविकों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। प्रत्येक वर्ष लगभग 60 सीटों के बैचों में लगभग 240 सीआईएसएफ के कर्मियों हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। सीआईएसएफ तटों के पास, बंदरगाहों और प्रतिष्ठानों के संरक्षण के लिए इन कर्मियों को तैनात करता है।

12.45 **विदेशी पर्यटक के डूबने पर पार्थिव शरीर को निकालने के लिए डाइविंग ऑपरेशन:** गोवा राज्य सरकार को दिनांक 24 सितंबर, 2017 को एक 29 वर्षीय अफगानिस्तानी नागरिक के पार्थिव शरीर की बरामदी के लिए डाइविंग सहायता प्रदान की गई थी, जो प्रतिवेदित तौर पर संकवेलिम, गोवा में डूब गया था।

12.46 **हाइपरबेरिक ऑक्सीजन उपचार:** अंडमान और निकोबार कमांड में, द कमांड डाइविंग यूनिट (सीडीयू) हाइपरबेरिक ऑक्सीजन उपचार (एचबीओटी) और अन्य डाइविंग संबंधित उपचार सहायता उपलब्ध कराने में सबसे आगे रहा है। सीडीयू ने सफलतापूर्वक विदेशी और भारतीय नागरिकों के लिए एचबीओटी को सफलतापूर्वक प्रदान किया है। गोताखोरों के सौहार्दपूर्ण प्रयास से नागरिकों के जीवन को बचाने में मदद मिली है और उन्होंने अंडमान निकोबार कमांड हेतु जबरदस्त सद्भावना और नागरिक प्रशासन से प्रशंसा अर्जित की है। इसके अलावा, इन

प्रयासों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मनोरंजक गोताखोरों के वैश्विक समुदाय द्वारा एक सुरक्षित डाइविंग गंतव्य के रूप में प्रदर्शित किया जा सके।



हाइपरबेरिक ऑक्सीजन उपचार

12.47 **एचएडीआर अभ्यास:** सीसीसी-2016 के दौरान प्रधान मंत्री के निर्देशों के आधार पर, एक बहु-एजेंसी एचएडीआर अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा वार्षिक आधार पर समन्वित किया जाता है। "सुनामी का जवाब" शीर्षक पर वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) संयुक्त अभ्यास 2017 का आयोजन 18 से 20 मई, 2017 को कारवाड़ में किया गया था। अभ्यास के दौरान चार मित्र देशों (श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार) ने पर्यवेक्षकों के रूप में इसमें हिस्सा लिया।

12.48 **आंतरिक रूप से विस्थापित कर्मियों के लिए शिविर:** एचएडीआर-17 के अंतर्गत, आंतरिक रूप से विस्थापित कार्मिकों के लिए एक शिविर 54-आईएनएफ डिवीजन, आईएनएस गोमती और एनसीसी कैडेट्स द्वारा 18 से 20 मई, 2017 को

कारवाड़ में आयोजित किया गया था। यह शिविर सात दिनों तक 2000 पीड़ितों को संभालने में सक्षम था। शिविर में आपातकालीन मामलों के लिए ऑपरेशन थिएटर सुविधा सहित शरण, भोजन, कपड़े और साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई थी। शिविर में आपदा राहत की रसद माँग को संभालने के लिए राहत भंडार और राशन स्टोर भी था।



12.49 **जम्मू एवं कश्मीर में बाढ़ राहत:** बाढ़ राहत और बचाव अभियान के लिए मार्कोस की दो टीमों अप्रैल, 2017 में क्रमशः बहरामपुर और निंगली में तैनात की गईं। टीम ने बाढ़ ग्रसित घरों में फसी 25 महिलाओं और बच्चों को बचाया और 22 आरआर के साथ मिलकर राशन आपूर्ति के संबंध में राहत सहायता प्रदान की, और साथ ही यह स्वयं के कर्मियों और उपकरणों की सुरक्षा को बनाए रखने में सक्षम थी। स्थानीय लोगों ने टीम के प्रयासों की बहुत सराहना की।



जम्मू एवं कश्मीर में बाढ़ राहत

12.50 **ओडिशा में राहत अभियान:** दिनांक 16 जुलाई, 2017

को लगातार बारिश के परिणामस्वरूप दक्षिण ओडिशा के निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई और पूरे इलाके में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई। रायगढ़ जिले के प्रभावित इलाकों में राहत सहायता के लिए विशाखापटनम से भारतीय नौसेना के सी-किंग और यूएच-3एच हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। हेलीकॉप्टर ने दिनांक 17 से 19 जुलाई, 2017 तक प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए 3500 किलोग्राम राहत सामग्री पहुँचाई।

12.51 **गुजरात में राहत अभियान:** गुजरात में 14 और 15 जुलाई, 2017 की रात को लगातार और मूसलाधार बारिश से बाढ़ आ गई और सड़क संपर्क, संचार तथा बिजली आपूर्ति के ठप्प होने की स्थिति निर्मित हो गई। बाढ़ राहत सहायता प्रदान करने के लिए, भारतीय नौसेना आधार वलसुरा ने तुरंत जामनगर, धोल और मोरबी जिले में गोताखोरों और लाईफगार्डों की दो टीमों को तैनात किया। राहत और बचाव का प्रयास नौ डाइविंग टीमों (मुंबई के बाहर) द्वारा प्रदान किया गया, जो 26 जुलाई से 2 अगस्त 2017 तक अहमदाबाद, पोरबंदर, बनासकांठा, पाटण, देसा, गोचनाद, बरगपुर और संधालपुर के प्रभावित इलाकों में तैनात थीं। टीमों ने इन प्रभावित क्षेत्रों से 600 से ज्यादा ग्रामीणों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया।



गुजरात में राहत अभियान

12.52 **मुंबई में बाढ़ राहत अभियान:** मुंबई में दिनांक 29 अगस्त, 2017 को लगातार बारिश हुई, जिसके चलते बाढ़ जैसी स्थिति सामने आई और सड़क-संपर्क, संचार और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। पश्चिमी नौसेना कमान आपदा प्रबंधन समूह ने त्वरित प्रत्युत्तर देते हुए सहायता प्रदान करने में अग्रसक्रिय कार्रवाई की।



मुंबई में बाढ़ राहत अभियान

12.53 **राहत अभियान – चक्रवात 'ओखी'**: चक्रवात 'ओखी' ने दिनांक 30 नवंबर 2017 को दक्षिण तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप तथा मिनीकॉय द्वीप को प्रभावित किया था। भारतीय नौसेना ने "ऑपरेशन सहायम" का संचालन 30 नवंबर 2017 को राहत सहायता के लिए किया। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप तथा मिनीकॉय द्वीप समूह में लापता मछुआरों और एचएडीआर संचालन के लिए एसएआर अभियान शुरू करने हेतु जहाज और विमान तैनात किए गए थे। लक्षद्वीप द्वीप समूह के सभी बसे हुए द्वीपों को स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय में राहत सामग्री प्रदान की गई। नौसेना ने 136 मछुआरों को बचाया और 5 शव भी बरामद किए। इसके अलावा समुद्र में 172 कर्मियों को भी सहायता प्रदान की गई।



चक्रवात 'ओखी' के दौरान सहायता

तटरक्षक बल

12.54 **सिविल प्रशासन को सहायता**

(क) **ओडिशा में बाढ़ के दौरान सहायता**: दिनांक 16

जुलाई, 2017 को, ओडिशा में लगातार बारिश के कारण रायगढ़ जिले में भारी बाढ़ आ गई थी। ओडिशा सरकार के अनुरोध पर, तट-रक्षक डोर्नियर ने 16 और 17 जुलाई, 2017 को प्रभावित क्षेत्रों का आकलन किया और पैकेज भोजन व राहत सामग्री के 450 किलोग्राम दिनांक 18 जुलाई 2017 को सिविल प्रशासन के अनुरोध पर प्रभावित इलाकों में गिराए।

(ख) **गणेश उत्सव-2017**: दिनांक 25 अगस्त से 5 सितंबर, 2017 तक महाराष्ट्र में भगवान गणेश मूर्तियों के विसर्जन समारोह के दौरान एक जहाज, एक होवरक्राफ्ट, 1 इंटरसेप्टर बोट और भारतीय तट-रक्षक के एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से खोज और बचाव (एसएआर) सहायता प्रदान की गई थी।



(ग) **चक्रवात तूफान 'ओखी' के दौरान खोज और बचाव प्रयास**: दिनांक 30 नवंबर, 2017 को, भारतीय तट-रक्षक ने चक्रवाती मौसम के कारण समुद्र में फसे मछुआरों की खोज के लिए केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप और मिनीकॉय तट पर बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया। भारतीय तट-रक्षक जहाज 222 दिनों के लिए तैनात किए गए थे और भारतीय तट-रक्षक विमान ने लापता मछुआरों की खोज और बचाव के लिए उड़ान भरी। 5 श्रीलंकाई मछुआरों सहित कुल 845 लोगों को भारतीय तटरक्षक खोज और बचाव इकाइयों द्वारा बचाया गया और समुद्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा बचाव/सहायता प्रदान की गई है।



तिरुवनन्तपुरम के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में
रक्षामंत्री का दौरा



बचाव ऑपरेशन – आईसीजीएस सारथी



बचाव ऑपरेशन – आईसीजीएस सी-427

- (घ) **गोवा में एमवी लकी सेवन के कर्मियों का बचाव:** दिनांक 16 जुलाई, 2017 को, भारतीय तटरक्षक चेतक विमान सीजी 809 ने गोवा के अगुएदा के तट पर एमवी लकी सेवन के 4 क्रू को सुरक्षित निकाला।

वायु सेना

- 12.55 त्वरित सहायता की आवश्यकता के समय देश में किसी भी संकट के मामले में भारतीय वायु सेना निश्चित रूप से सबसे

पहली सहायक होती है। वर्ष 2017 के दौरान, भारतीय वायु सेना के परिवहन और हेलीकाप्टर बड़े ने नागरिक प्राधिकारियों की सहायता के लिए कई अभियान चलाए।

12.56 **श्रीनगर उप-चुनाव:** श्रीनगर उप-चुनाव के मद्देनजर, सीआरपीएफ कर्मियों को इम्फाल से श्रीनगर लाने के लिए दिनांक 1 से 4 अप्रैल, 2017 के बीच सी-17 एयरक्राफ्ट को कार्य पर लगाया गया था। कुल 856 सीआरपीएफ कर्मियों और 60 टन भार को इन विमानों द्वारा पहुँचाया गया।

12.57 **जंगल की आग (14-20 अप्रैल, 2017):** भारतीय वायुसेना विमान जम्मू-कश्मीर, गंगटोक, तिरुवनन्तपुरम और राजस्थान (माउंट आबू और कोटा) में जंगल की आग से लड़ने के लिए प्रभावी रूप से इस्तेमाल किए गए थे।

12.58 **तरासा द्वीप बचाव:** मई 2017 में, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को तरासा द्वीप से लेकर कारनिकोबार तक चक्रवात वरधा में फसे नागरिकों को बचाने के लिए तैनात किया गया था।

12.59 **गुजरात बाढ़ राहत (15-31 जुलाई, 2017):** भारतीय वायुसेना ने गुजरात में बाढ़ की स्थिति से निबटने में तुरंत सहायता प्रदान की थी। राहत कार्यों में दोनों परिवहन विमान और हेलीकॉप्टरों को सक्रियता से शामिल किया गया था। कुल 1,013 एनडीआरएफ के कर्मियों और 27 टन भार को परिवहन विमान द्वारा अहमदाबाद पहुँचाया गया, जबकि हेलीकॉप्टरों ने 778 कर्मियों को पहुँचाया और 87 टन राहत सामग्री प्रभावितों हेतु गिराई।

12.60 **अमरनाथ यात्री पर हमला:** दिनांक 10 जुलाई, 2017 को आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर हमला किया था। सी-130जे को 11 जुलाई, 2017 को श्रीनगर से सूरत में 7 शवों को लाने, 18 घायल कर्मियों और 33 अन्य नागरिकों को हवाई माध्यम से लाने का काम सौंपा गया था।

12.61 **राजस्थान बाढ़ राहत (24 जुलाई से 2 अगस्त 2017):** भारतीय वायुसेना हेलीकाप्टरों का इस्तेमाल राजस्थान में बाढ़ के दौरान किया गया, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में 3.25 टन खाद्य पदार्थों को प्रभावितों के लिए छोड़ा गया।

12.62 **उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में बाढ़ राहत (13-24 अगस्त, 2017):** अगस्त महीने के मध्य में पूर्णिया और

आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई। भारतीय वायुसेना ने सी-17 और एएन-32 बेड़े की तैनाती से एनडीआरएफ और सेना की टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए वायुसेना स्टेशन पूर्णिया में राहत सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए भी विमान का उपयोग किया गया था। राहत सामग्री का वितरण करने और बचाव कार्य शुरू करने के लिए पूर्णिया में एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए थे। भारतीय वायुसेना ने 570 टन भार वितरण करने वाले 300 मिशन को पूरा किया और 1500 से अधिक लोगों को सुरक्षित तौर पर उठा कर पहुँचाया।



एचएडीआर मिशन के दौरान वायुसेना की कार्रवाई

12.63 **विदेशी नागरिकों का बचाव:** भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टरों ने लद्दाख की ऊँची चोटियों में फसे विदेशियों को बचाया। जुलाई, 2017, इजरायल और जर्मनी में अगस्त 2017 और सितंबर, 2017 में इटली, न्यूजीलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में नागरिकों की खोज और बचाव के लिए हवाई सहायता प्रदान की गई थी।

12.64 **रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के लिए राहत मिशन:** दो सी-17 विमान द्वारा बांग्लादेश में दिनांक 14 और 15 सितंबर, 2017 को 107 टन राहत सामग्री को रोहिंग्या शरणार्थियों की सहायता हेतु दिल्ली से ढाका, बांग्लादेश पहुँचाया गया।

12.65 **रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार के लिए राहत मिशन:** रोहिंग्या शरणार्थियों की सहायता के रूप में एक सी-17 विमान ने 24 नवंबर 2017 को म्यांमार में दिल्ली से यांगून (म्यांमार) तक 42 टन राहत सामग्री पहुँचाई।

ऑपरेशन त्रिवेणी – एलडब्ल्यूई ऑपरेशन पर संक्षिप्त विवरण

12.66 **शासनादेश/तैनाती:** अक्टूबर 2009 के बाद से, चार एमआई-17वी5 एमएलएच, दो एमआई-17 एमएलएच और एक एएलएच एमके-III हेलीकॉप्टर गृह मंत्रालय के समर्थन में 'ऑपरेशन त्रिवेणी' नामक नक्सल-रोधी ऑपरेशन कोड के लिए तैनात किए गए हैं। एक एक एमआई-17वी5 को क्रमशः रायपुर और जगदलपुर में तैनात किया गया है और एमआई-17 को रांची से संचालित किया जा रहा है। एएलएच एमके-III हेलीकॉप्टर को रायपुर/जगदलपुर से संचालित किया जा रहा है। सभी कार्यों को 'संयुक्त एसओपी' और 'ऑपरेशन त्रिवेणी' के लिए गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 'संलग्नता' नियम के अनुसार किया जाता है।

12.67 **फ्लाईंग एफर्ट:** छत्तीसगढ़ सरकार के लिए 95 घंटे और झारखंड सरकार के लिए 25 घंटे निर्धारित किए गए हैं, जो नक्सल विरोधी एओआर में तैनात छह हेलीकॉप्टरों (प्रति हेलीकॉप्टर प्रति 20 घंटे प्रति माह) के लिए प्रति माह 120 घंटे के निर्धारित उड़ान में से हैं। उड़ानों को कम करने के लिए, नागपुर में दूसरी लाइन सर्विसिंग की सुविधा स्थापित की गई है। वायु सेना हेलीकॉप्टर नियमित रूप से वायु सैन्य सामग्री समर्थन, हताहत निकासी, सैनिक परीक्षण, संचार कर्तव्यों और सीएपीएफ के प्रशिक्षण के अन्य हवाई संचालन के साथ-साथ कार्य करते हैं। उड़ानों की जरूरत को जब-जब सीएपीएफ द्वारा रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया, संभवतया इसे मंजूरी दे दी गई है। तीन अलग-अलग हिस्सों में हेलिकॉप्टरों के लिए अनिवार्य उड़ानों की संख्या के अलावा और ऊपर से हताहत निकासी के लिए उड़ानों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक राज्य से दूसरे राज्य में उड़ानों के आवंटन को अनुमत किया गया है।

12.68 **पूर्ण किए गए कार्य:** वर्ष 2009 में इसे नक्सल विरोधी अभियान शामिल किए जाने के बाद से, 22,068 उड़ानों को क्रमशः 17,031 घंटों में पूर्ण किया गया है। इन मिशनों के दौरान कुल 93,652 यात्रियों, 1,210 की संख्या में हताहतों, 528 शवों और 2,094 टन भार के स्थानांतरण को नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशनों के लिए उपयोग में लाया गया है।





राष्ट्रीय कैडेट कोर





राष्ट्रीय कैडेट कोर

13.1 राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 के तहत की गई थी। इसने अपनी स्थापना के 69 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एनसीसी का उद्देश्य प्रतिबद्धताओं, समर्पण, आत्म-अनुशासन और नैतिक मूल्यों के साथ देश के युवाओं हेतु समग्र विकास का अवसर प्रदान करना है, ताकि वे कल के जिम्मेदार नागरिक बनें। एनसीसी का आदर्श वाक्य "एकता और अनुशासन" है।

13.2 भारत सरकार ने वर्ष 2010 में कैडेट की कुल संख्या को 13 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। यह विस्तार प्रत्येक स्तर में 40,000 कैडेटों के पाँच चरणों की योजना के अनुसार किया गया है। तीन चरण पूरे हो चुके हैं। 2 अगस्त 2017 को चौथे चरण हेतु स्वीकृत नए एनसीसी प्रतिष्ठानों का कार्यान्वयन जारी है। आज की तिथि के अनुसार स्वीकृत संख्या 14.20 लाख (नए प्रतिष्ठानों के चरण तीन तक) और एनसीसी इकाइयों की कुल संख्या 814 है।

13.3 30 सितंबर, 2017 तक नामांकित किए गए कैडेट संख्या का स्कंध-वार विवरण निम्नानुसार है:

स्कंध (विंग)	लड़के	लड़कियाँ	कुल	%
थलसेना	8,07,557	369129	1176686	89.45%
नौसेना	57,766	12778	70544	5.36%
वायुसेना	51,173	16998	68171	5.18%
कुल	916496	398905	1315401	100%

13.4 आज की तिथि के अनुसार एनसीसी 16597 संस्थानों में संचालित है, जिसमें देश भर में 11022 स्कूल और 5575 कॉलेज शामिल हैं। मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर एक बड़े पैमाने पर अभ्यास करने के बाद, एनसीसी द्वारा मैपिंग को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था ताकि देश में 716 जिलों में से 709 में एनसीसी कवरेज वर्ष 2017 तक किया जा सके। शेष 7 जिलों को समय के अंतराल में शामिल कर लिया जाएगा।

13.5 **दो लाख अतिरिक्त एनसीसी कैडेट की संख्या की स्वीकृति के चौथे चरण में नई स्थापना:** एक एनसीसी समूह मुख्यालय, आठ एनसीसी थलसेना इकाइयाँ, दो एनसीसी नौसेना इकाइयाँ और एक एनसीसी वायुसेना इकाई (एयर यूनिट) को 2 अगस्त 2017 को चौथे चरण में विस्तारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है और स्थापना का कार्य जारी है, जिसके परिणामस्वरूप एनसीसी इकाइयों की संख्या में वृद्धि को 825 तक और कैडेट की संख्या को 14,60,000 तक लाया जा सके। चौथे चरण का विवरण निम्नानुसार है:

एनसीसी इकाइयाँ/स्थापना	IV चरण
समूह (जीपी) मुख्यालय	समूह मुख्यालय कोरापुट (ओडिशा)
थलसेना इकाइयाँ (लड़कियाँ)	4 हरियाणा गर्ल्स बीएन एनसीसी, नूह
थलसेना इकाई	6 आंध्र प्रदेश बीएन एनसीसी, अनंतपुर
	7 बंगाल बीएन एनसीसी, बालूरघाट
	5 केरल बीएन एनसीसी, वायनाड
	5 कर्नाटक बीएन एनसीसी, चिकबल्लापुर
	1 छत्तीसगढ़ बीएन एनसीसी, कोरबा
	2 अरुणाचल प्रदेश बीएन एनसीसी, तवांग
	2 मिज़ोरम बीएन एनसीसी, लुंगलेई
नौसेना इकाइयाँ	1 लक्षद्वीप नौसेना इकाई एनसीसी, कवारत्ती
	5 ओडिशा नौसेना इकाई एनसीसी, पारादीप
वायुसेना इकाई	2 ओडिशा एयर स्क्वाड्रन एनसीसी, झारसुगुडा

13.6 वर्तमान में एनसीसी में कुल 13,15,401 कैडेटों में से 3,98,905 (30.33%) लड़कियाँ हैं।

13.7 **एनसीसी गर्ल्स बटालियन की स्थापना:** लड़कियों की नई बटालियन (बीएन) की स्थापना के अलावा, लड़कियों को अगले मिश्रित बटालियन में शामिल होने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि अगले वर्ष तक लड़कियों का प्रतिशत 30.33% से बढ़कर 33% हो जाए। इस उपाय के साथ इस उद्देश्य का भी सहारा लिया गया है कि लड़कियों को अधिक से अधिक एनसीसी प्रशिक्षण के फायदे अवश्य प्राप्त होंगे।

एनसीसी कैडेट प्रशिक्षण

13.8 **सामान्य:** एनसीसी देश का एक प्रमुख प्रशिक्षण संगठन है जो युवाओं को संवारने के लिए संबद्ध है। लगातार बढ़ती संख्या और जीवंत एनसीसी पूर्व-छात्रों का समूह इसकी बढ़ती प्रासंगिकता का प्रमाण है। बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी किए गए नए पाठ्यक्रम को शुरू करके प्रशिक्षण दर्शन की समीक्षा की गई है।

13.9 एनसीसी प्रशिक्षण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाता है:

- (क) संस्थागत प्रशिक्षण
- (ख) शिविर प्रशिक्षण
- (ग) साहसिक प्रशिक्षण
- (घ) सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास क्रियाएँ
- (ङ) युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम।

13.10 **संस्थागत प्रशिक्षण:** इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को एक रेजिमेंट आधारित जीवन के तरीके की ओर प्रेरित करना है और उनमें अनुशासन, सुव्यवस्था और व्यक्तित्व विकास को विकसित करना है। एनसीसी की प्रत्येक शाखा हेतु निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के अनुसार सभी नामांकित कैडेट अपने संबंधित विद्यालयों/महाविद्यालयों (स्कूलों/कॉलेजों) में संस्थागत प्रशिक्षण के माध्यम से गुजरते हैं। इस अवधि के दौरान किए जाने वाले उल्लेखनीय सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) कैडेटों और एसोसिएट एनसीसी अधिकारी (एएनओ) के प्रशिक्षकों (दोनों जूनियर एवं सीनियर विंग्स) हेतु प्रशिक्षण मैनुअल को नियमानुसार संशोधित और सामान्य और विशिष्ट, दोनों विषयों के लिए तैयार किया गया है। तदनुसार सभी राज्य निदेशालयों को पुस्तकें जारी की गई हैं और सार्वभौमिक/आसान पहुँच के लिए एनसीसी की वेबपेज पर इसे अपलोड किया गया है।

(ख) पाठ्यक्रम को संशोधित करने के दौरान नेतृत्व प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास, राष्ट्रीय एकता, आपदा प्रबंधन और लड़ाकू जीवन रक्षा आदि क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है।

(ग) एनसीसी प्रशिक्षण दर्शन – 2012 को भी संशोधित किया गया है और इसे और अधिक प्रासंगिक बनाया गया है। नया दस्तावेज़ सभी राज्य निदेशालयों को जारी किया गया है और

एनसीसी की वेबपेज पर इसे अपलोड किया गया है।

(घ) कैंप मैनुअल के रूप में एक अद्यतन और व्यापक योजना और आचरण को, शिविर के समरूप आचरण हेतु दिशानिर्देश/मार्गदर्शन देने के लिए एनसीसी वेबपेज पर तैयार किया गया है और अपलोड किया गया है।

13.11 **शिविर प्रशिक्षण (कैंप ट्रेनिंग):** शिविर प्रशिक्षण एनसीसी पाठ्यक्रम का एक प्रमुख पहलू है जो कैमरडिरी, टीम भावना, परिश्रम के भावना, आत्मविश्वास के विकास और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एकता और अनुशासन को बढ़ाने में सहायता करता है। एनसीसी ने अपने कैडेटों के लिए व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में मानवीय मूल्यों पर विभिन्न कक्षाओं की शुरुआत की है। एनसीसी में आयोजित विभिन्न प्रकार के शिविरों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

(क) **वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (एटीसी):** राज्य निदेशालय स्तर पर 10 दिन की अवधि के लिए वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि जूनियर डिवीजन/जूनियर विंग (जेडी/जेडब्ल्यू) कैडेटों की न्यूनतम 50% संख्या और सीनियर डिवीजन/सीनियर विंग (एसडी/एसडब्ल्यू) की कम से कम 66% संख्या प्रत्येक वर्ष कम से कम एक शिविर में अवश्य भाग ले। इस वर्ष भारत में इकाई/समूह मुख्यालय स्तर पर 1474 वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए जिसमें 6,65,980 कैडेटों ने भाग लिया।

(ख) **केंद्रीय आयोजित शिविर (सीओसी):** ये सभी शिविर भारतीय प्रकृति के होते हैं और डीजी एनसीसी द्वारा नामित निदेशालयों के परामर्श से योजनाबद्ध किए जाते हैं, और प्रत्येक निदेशालय को आवंटित रिक्तियों के अनुसार चयनित कैडेट इसमें भाग लेते हैं। सीओसी की अवधि 12 दिन की होती है। निम्न प्रकार के सीओसी आयोजित किए जाते हैं:

(i) **राष्ट्रीय एकता शिविर (एनआईसी):** राष्ट्रीय एकता शिविरों का आयोजन राष्ट्रीय एकात्मता को बढ़ावा देने और कैडेटों के बीच विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की विरासत और संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस वर्ष कुल 37 एनआईसी और छह विशेष एनआईसी (एसएनआईसी) शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 23,680 कैडेटों ने भाग

लिया। आयोजित किए गए छह विशेष राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों (एसएनआईसी) में शामिल स्थानों और कैडेटों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

(क) **लेह में एसएनआईसी:** 170 कैडेट

(ख) **पेड़डापुरम (काकीनाडा) में एसएनआईसी:** 300 कैडेट

(ग) **बड़ा बाग (जैसलमेर) में एसएनआईसी:** 300 कैडेट

(घ) **उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एसएनआईसी:** 600 कैडेट

(ङ) **पोर्ट ब्लेयर में एसएनआईसी:** 180 कैडेट

(च) **लक्षद्वीप में एसएनआईसी:** 170 कैडेट

(ii) **वायु सैनिक शिविर (वीएससी):** प्रत्येक वर्ष वायु स्कंध के लिए एक अखिल भारतीय वायु सैनिक शिविर एसडी/एसडी कैडेट हेतु 12 दिनों की अवधि के लिए आयोजित किया जाता है। देश के सभी हिस्सों से 600 सीनियर डिवीजन/सीनियर विंग कैडेट इस शिविर में भाग लेते हैं। वर्ष 2017 के लिए, वीएससी का आयोजन जोधपुर में 23 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2017 तक आयोजित किया गया था।

(iii) **नौ सैनिक शिविर (एनएससी):** सभी नौसेना स्कंध गतिविधियों के लिए नौसेना कैडेटों को प्रशिक्षित करने के लिए एक वर्ष में एक बार 12 दिनों की अवधि का एनएससी शिविर का आयोजन किया जाता है। देश के सभी हिस्सों से 386 सीनियर डिवीजन और 204 सीनियर विंग कैडेट इस शिविर में भाग लेते हैं। इस वर्ष एनएससी का आयोजन कारवाड़ में 26 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2017 तक आयोजित किया गया था।

(iv) **थल सैनिक शिविर (टीएससी):** इस वर्ष लड़कों और लड़कियों के लिए दिल्ली कैंट स्थित परेड ग्राउंड में एक टीएससी शिविर आयोजित किया गया, और देश के सभी हिस्सों से कुल 1360 कैडेट (680 लड़के और 680 लड़कियाँ) ने 18 से 29 सितंबर 2017 के बीच इस शिविर में भाग लिया।

(v) **नेतृत्व शिविर (एलसी):** इन शिविरों का आयोजन अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। इस वर्ष दो एसएसबी स्क्रीनिंग कैंपसूल सहित छह अग्रिम नेतृत्व शिविर आयोजित किए गए थे। इन शिविरों में कुल 1800 कैडेट ने हिस्सा लिया। एएलसी का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व कौशल और सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अभिविन्यास पर आधारित था।

(vi) **रॉक क्लाइम्बिंग (पर्वतारोहण) प्रशिक्षण शिविर (आरसीटीसी):** आठ आरसीटीसी शिविरों का आयोजन कैडेटों को रॉक क्लाइम्बिंग (पर्वतारोहण) की मूल बातें और साहसिक कार्य की भावना पैदा करने के लिए किया गया था। इनमें से चार शिविर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए और चार अन्य शिविर एनसीसी निदेशालय, उत्तराखंड द्वारा आयोजित किए गए थे। इन कैम्पों में कुल 1080 कैडेट शामिल हुए।

(vii) **गणतंत्र दिवस शिविर (आरडीसी):** दिल्ली कैंट में दिनांक 1 से 29 जनवरी तक गणतंत्र दिवस शिविर दिल्ली में सेना के परेड मैदान में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इस शिविर में पूरे भारत से 2070 कैडेट (लगभग) और उन मित्र देशों के 100-110 कैडेट भाग लेते हैं, जिनके साथ एनसीसी के युवा आदान-प्रदान (यूथ एक्सचेंज) कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस माह के दौरान इस लंबे शिविर में प्रशिक्षण, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय एकता जागरूकता कार्यक्रमों को अंतर निदेशालय प्रतियोगिताओं के रूप में आयोजन किया जाता है। 26 जनवरी, 2018 को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में दो एनसीसी मार्चिंग दस्तों और दो एनसीसी बैंड ने भाग लिया।

13.12 **अटैचमेंट प्रशिक्षण:** एनसीसी कैडेट सशस्त्र बलों की इकाइयों के साथ अटैचमेंट प्रशिक्षण के माध्यम से अत्यधिक मूल्यों पर प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। वर्ष के दौरान आयोजित अटैचमेंट प्रशिक्षण का विवरण निम्नानुसार है:

(क) लगभग 375 अधिकारियों और 18,000 कैडेटों ने अखिल भारत स्तर पर नियमित थलसेना इकाइयों के साथ आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया जिसमें महिला अधिकारी और 560 सीनियर विंग कैडेट भी शामिल थे।

(ख) 120 सीनियर डिवीजन कैडेटों ने भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में अटैचमेंट प्रशिक्षण में भाग लिया और 48 एसडब्ल्यू कैडेट को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से संलग्न किया गया था।

(ग) विभिन्न सैन्य अस्पतालों के साथ लगभग 725 सीनियर विंग कैडेट जुड़े हुए हैं।

(घ) 16 राज्यों के एनसीसी निदेशालयों (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) के कुल 100 वायु स्कंध एनसीसी कैडेटों (76 एसडी और 24 एसडब्ल्यू) ने वायुसेना अकादमी, डुन्डिगल में प्रशिक्षण लिया। यह प्रशिक्षण हर वर्ष जून और दिसंबर में क्रमशः 13 दिनों के लिए दो बार आयोजित किया जाता है।

(ङ) 16 एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों (एएनओ) और वायु स्कंध के 200 कैडेट (केवल सीनियर डिवीजन) को 14 दिनों की अवधि के लिए विभिन्न वायु सेना स्टेशनों से संलग्न किया गया था।

(च) **नौसेना पोत अटैचमेंट और समुद्री प्रशिक्षण:** नौसेना स्कंध के 295 कैडेट ने नौ दिनों के लिए मुंबई, कोच्चि और विशाखापत्तनम में नौसैनिक जहाजों के साथ प्रशिक्षण लिया और उन्हें 12 दिनों की अवधि के लिए अटैचमेंट प्रशिक्षण भी दिया गया। कैडेटों को विभिन्न नौसैनिक विषयों पर गहन नौसैनिक प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें समुद्र में नौसैनिक अभ्यासों को देखने का भी अवसर मिला।

(छ) **नौसेना अकादमी अटैचमेंट प्रशिक्षण:** कोझिकोड, केरल में 9 से 20 जनवरी, 2017 तक 170 सीनियर विंग कैडेटों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था।

13.13 **फ्लाईंग प्रशिक्षण:** वायु स्कंध एनसीसी कैडेटों (एसडी/एसडब्ल्यू) को उड़ान का अनुभव देने के लिए एनसीसी में फ्लाईंग प्रशिक्षण आयोजित करता है। वर्तमान में देश की सभी राज्यों में 50 एनसीसी एयर स्क्वाड्रन में उड़ान की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 110 नए वायरस एसडब्ल्यू 80 विमान एनसीसी में शामिल किए गए हैं और अक्टूबर, 2019 तक इसका संचालन किया जाएगा।

13.14 **विदेशी क्रूज (नौसेना क्रूज):** 10 कैडेट्स और 01 पर्यवेक्षी कर्मचारी ने नौ सेना जहाजों के बोर्ड पर 3 अक्टूबर से 8

नवंबर, 2017 तक पेनांग (मलेशिया), जकार्ता (इंडोनेशिया) और कोलंबो (श्रीलंका) के बंदरगाह में दौरा किया।

13.15 **नौसेना स्कंध का तकनीकी एनसीसी शिविर:** चेन्नई में इंजीनियरिंग कॉलेजों के 97 सीनियर डिवीजन और 41 सीनियर विंग कैडेट ने 18 से 30 जून, 2017 तक वार्षिक तकनीकी शिविर में हिस्सा लिया। कैडेटों को आईएनएस वालसुरा, शिवाजी और नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना इंजीनियरिंग प्रतिष्ठानों हेतु मुंबई में अध्ययन दौरे पर ले जाया गया।

साहसिक प्रशिक्षण

13.16 **चिल्का में अखिल भारतीय नौकायन प्रतियोगिता (सेलिंग रेगाटा):** सभी 17 निदेशालयों के 51 सीनियर डिवीजन और 51 सीनियर विंग कैडेट ने 2-9 नवंबर, 2017 को आईएनएस चिल्का में आयोजित अखिल भारतीय एनसीसी नौकायन प्रतियोगिता (सेलिंग रेगाटा) में भाग लिया।

13.17 **नौकायन अभियान:** नौ-सैनिक प्रशिक्षण की एक आकर्षक विशेषता है नौकायन अभियान। प्रत्येक एनसीसी निदेशालय न्यूनतम 10 से 12 दिनों की अवधि के लिए नौकायन अभियान चलाता है, और यह 400 से 500 किमी की कुल दूरी को शामिल करता है। प्रत्येक निदेशालय से 40 से 60 कैडेट इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। नौकायन अभियान के दौरान, कैडेटों को बोट पुलिंग और नौकायन में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वे मौसम की स्थिति में परिवर्तन के खतरों और नदियों/समुद्र के बदलते हुए प्रवाह का सामना करते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर कुल 15 नौकायन अभियान आयोजित किए गए, जिसमें शामिल हैं:

- (क) गुजरात निदेशालय के 40 कैडेटों द्वारा 24 फरवरी से 7 मार्च, 2017 तक भावनगर से ओखा (द्वारका) तक (702 किमी)।
- (ख) पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय के 60 कैडेटों द्वारा जून, 2017 में फरक्का से कोलकाता तक (430 किमी)।

13.18 **स्कूबा डाइविंग:** एनसीसी कैडेट के लिए स्कूबा डाइविंग शिविर सामान्य तौर पर भारतीय नौसेना के नौसेना डाइविंग टीमों की सहायता से दिल्ली, कोची, विजाग, मुंबई, गोवा/कारवाड़, चेन्नई/पोर्ट ब्लेयर और कोलकाता में आयोजित किए जाते हैं।

इस वर्ष दिल्ली, केरल और लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पांडिचेरी और अंडमान एवं निकोबार (टीएनपी और एएन) निदेशालयों ने स्कूबा डाइविंग शिविर का आयोजन किया। कुल 137 कैडेटों ने इसमें भाग लिया।

13.19 **विंग सर्फिंग/कयाकिंग:** नौसेना विंग के कैडेट्स को विंग सर्फिंग और कयाकिंग के बुनियादी कौशल में भी प्रशिक्षित किया जाता है और जानकारी दी जाती है।

13.20 **पर्वतारोहण अभियान:** एनसीसी महानिदेशालय ने प्रत्येक वर्ष दो अभियान शुरू किए हैं, लड़कियों और लड़कों के लिए एक-एक। 20 सीनियर डिवीजन/सीनियर विंग कैडेट अभियान में भाग लेते हैं। इस वर्ष निम्नलिखित पर्वतारोहण अभियान चलाए गए:

- (क) अगस्त-सितंबर, 2017 में माउंट जोगिन-III (6116 मीटर) के लिए 20 लड़के कैडेट
- (ख) मई-जुलाई, 2017 में माउंट लद्दाखी (5345 मीटर) के लिए 20 लड़कियाँ कैडेट

13.21 **ट्रेकिंग अभियान:** एनसीसी निदेशालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 28 ट्रेकिंग अभियान आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 13500 कैडेटों ने भाग लिया।

13.22 **पैरा बेसिक कोर्स:** प्रत्येक वर्ष 40 लड़के और 40 लड़कियों को पैरा प्रशिक्षण विद्यालय, आगरा में आयोजित पैरा बेसिक कोर्स के लिए दो बार नामित किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान, 80 सीनियर डिवीजन और 80 सीनियर विंग कैडेटों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

13.23 **साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियाँ:** विभिन्न राज्य एनसीसी निदेशालय द्वारा कई शांति, सामंजस्य और राष्ट्रीय एकीकरण के प्रचार-प्रसार के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियाँ आयोजित की गईं और इसके माध्यम से स्वास्थ्य, समुदाय के विकास और सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन पर ग्रामीण जनता को शिक्षित किया गया।

13.24 **डेजर्ट कैमल सफारी:** राजस्थान निदेशालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जैसलमेर के रेगिस्तान में डेजर्ट कैमल सफारी का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण वर्ष 2017-18 के दौरान कजाखस्तान से 12 कैडेट, रूस से 15 कैडेट, बांग्लादेश से 8

कैडेट और सिंगापुर से 10 कैडेट और 20 भारतीय कैडेट ने 18–29 नवंबर, 2017 के बीच डेज़र्ट कैमल सफारी में हिस्सा लिया।

13.25 युवा आदान-प्रदान (यूथ एक्सचेंज) कार्यक्रम (वाईईपी): वर्तमान में, बांग्लादेश, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदीव, नेपाल, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम सहित ग्यारह अनुकूल देशों के साथ युवा आदान-प्रदान (यूथ एक्सचेंज) कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, ताकि प्रतिभागियों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा सके और एक-दूसरे की सराहना की जा सके और साथ ही सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक वास्तविकताओं और विदेशों में हमारे राष्ट्र की छवि को परिलक्षित करने के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में कार्य किया जा सके। युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन मित्र देशों के साथ किया गया, जिसमें ग्यारह मित्र देशों में 158 भारतीय एनसीसी कैडेट और 158 विदेशी कैडेट का आदान-प्रदान भी शामिल था।

सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास

13.26 सामान्य: एनसीसी में सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास गतिविधियों को आरंभ किया गया है ताकि समुदाय की निस्वार्थ सेवा के गुणों, श्रम की गरिमा, स्वयं सहायता के महत्व, पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में सहायता के लिए इन्हें प्रेरित किया जा सके। यह स्वच्छ भारत अभियान, वयस्क शिक्षा, वृक्षारोपण, रक्त दान, वृद्ध श्रम, अनाथों, मलिन बस्तियों, गांव उत्थान और विभिन्न अन्य सामाजिक योजनाओं के कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। इस वर्ष एनसीसी कैडेट द्वारा व्यापक तौर पर किए गए प्रमुख कार्यकलापों का विवरण बाद के पैरा में दिये गए हैं।

13.27 राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी, 2017): 308661 कैडेटों ने डिजिटल पेमेंट के विभिन्न तरीकों के बारे में 18,32,176 युवाओं/नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाई।

13.28 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2017: भारत भर में 752392 कैडेटों ने इस वर्ष 5832 स्थानों पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70000 से अधिक कैडेट थे।

13.29 स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छता ड्राइव)

(क) **नागरिक जागरूकता पखवाड़ा (12–24 अप्रैल, 2017):** स्वच्छ अभिधायन के हिस्से के रूप में नागरिक जागरूकता पाखवाड़ा में 1,74,650 कैडेटों ने भाग लिया।

(ख) **स्वच्छ ही सेवा अभियान (15 सितंबर – 2 अक्टूबर, 2017):** 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2017 तक स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान 15 दिनों के अभियान में 11,53,308 कैडेट और कर्मचारियों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया।

(ग) **स्वच्छ पाखवाड़ा अभियान (1–15 दिसंबर, 2017):** अखिल भारतीय स्तर पर स्वच्छता पखवाड़े का पुनः 1 से 15 दिसंबर, 2017 के बीच आयोजन किया गया जिसमें कुल 694780 कैडेटों ने सम्पूर्ण अभियान/मुहिम में भाग लिया।

(घ) **स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि:** कुल 5,55,738 कैडेट ने निबंध लेखन में हिस्सा लिया और 1,94,832 कैडेटों ने स्वच्छता विषय पर आधारित फिल्म निर्माण में भाग लिया। 2 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री समारोह के दौरान दोनों श्रेणियों में से तीन-तीन कैडेटों को सम्मानित किया गया।

13.30 वृक्षारोपण अभियान: स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने के लिए विशेष अभियान के तहत कुल 4,10,793 कैडेटों ने इस वर्ष 5,17,593 पौधों का रोपण किया।

13.31 रक्त दान: नवंबर 2017 में एनसीसी दिवस के अवसर पर एक विशेष अभियान के तहत कुल 30,066 कैडेटों ने रक्त दान में भाग लिया। इस अवसर पर कैडेटों ने करीब 20,000 इकाई रक्त दान एकत्र किया।

13.32 मिशन इंद्र-धनुष (टीकाकरण अभियान): अखिल भारत स्तर पर मिशन इंद्र-धनुष टीकाकरण अभियान के एक हिस्से के रूप में, 79,820 कैडेटों ने प्रतिरक्षण के प्रति जागरूकता के प्रचार-प्रसार में अपना योगदान दिया।

13.33 यूथ सिनर्जी: राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन सचिव, युवा मामले मंत्रालय के अधीन किया गया है। एनसीसी महानिदेशालय, इस समिति के सदस्यों में से एक हैं और इसकी बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाती है। विभिन्न युवा संगठनों के बीच तालमेल के एक हिस्से के रूप में, एनसीसी और नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) ने सोशल सर्विस कम्युनिटी डेवलपमेंट के हिस्से के रूप में कई कार्यक्रम आयोजित किए,

जो डिजिटल साक्षरता, सड़क सुरक्षा और स्वच्छता अभियान पर आधारित थे।

13.34 **विश्व तंबाकू निषेध दिवस (31 मई, 2017):** विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर 31 मई, 2017 को 86,608 कैडेटों ने भाग लिया और जागरूकता दी।

13.35 **एंटी ड्रग एब्यूज (नशा विरोधी) दिवस (26 जून, 2017):** एंटी ड्रग एब्यूज (नशा विरोधी) दिवस पर 26, जून 2017 को 82,267 कैडेटों ने भाग लिया और युवाओं/नागरिकों को जागरूकता दी।

13.36 **अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस (22 मार्च, 2017):** 22 मार्च, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस पर अखिल भारतीय स्तर पर 1,20,000 कैडेटों ने भाग लिया।

13.37 **यातायात नियंत्रण/जागरूकता अभियान – विजय**

दिवस (16 दिसंबर, 2017): 16 दिसंबर, 2017 को यातायात नियंत्रण जागरूकता के लिए 86,650 कैडेटों ने भाग लिया।

खेल उपलब्धियाँ

13.38 **सुब्रोतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल कप:** जूनियर लड़कियों की टीम (यू-17) ने बांग्लादेश के साथ फाइनल (अंतिम मैच) खेला और उप जूनियर लड़कों की टीम (यू-14) क्वार्टर फाइनल में पहुंची।

13.39 **जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट:** जूनियर लड़कों की टीम (यू-17) सेमीफाइनल में पहुंची।

13.40 **अखिल भारतीय जी वी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप (एआईजीवीएससी):** एनसीसी शूटिंग टीम ने XXVII, आईजीवीएमएससी में कुल 14 पदक (5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक) जीते।



विदेशों के साथ रक्षा सहयोग





विदेशों के साथ रक्षा सहयोग

14.1 इस वर्ष विदेशी देशों के साथ रक्षा सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई। विभिन्न स्थापित भागीदारियों को काफी लाभ मिला जबकि अन्य का कद काफी ऊंचा हुआ। अनेक प्रमुख नई भागीदारियां स्थापित की गईं जिससे भारत की रक्षा कूटनीति को काफी विविधता प्राप्त हुई। भारतीय प्रशांत क्षेत्र सहित पड़ोसी एवं आसन्न पड़ोसी देशों के साथ क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और अन्य सक्षमताओं पर सहयोग निरंतर एक प्राथमिकता का बिंदु था, और अमेरिका, रूस, यूरोपीय देश, जापान जैसी महाशक्तियों तथा इजराइल जैसे अन्य प्रमुख भागीदारों के साथ बहु-आयामी रक्षा भागीदारियों को सुकर बनाया गया। 'एक्ट ईस्ट' नीति शीर्षक के अंतर्गत और सागर फ्रेमवर्क के प्रमुख घटक के रूप में भारत-प्रशांत में रक्षा एवं सुरक्षा स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। खाड़ी देशों तथा अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बढ़ता सहयोग अन्य उल्लेखनीय पहलु था।

14.2 रक्षा सहयोग को अनेक कार्यकलापों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया, जिनमें उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं रक्षा मंत्री स्तर

पर कूटनीतिक संवाद एवं द्विपक्षीय वार्ता तथा रक्षा सचिव और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर महत्वपूर्ण वार्ताएं, सेनाध्यक्षों के दौरे, रक्षा एवं सैन्य विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग सहयोग, संयुक्त युद्धाभ्यास, प्रेक्षाओं एवं विषय-जन्य विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, नौसेना जहाजों और सैन्य विमानों का दौरा, रक्षा उपकरणों को उपहार स्वरूप दिया जाना, खेल और साहसिक कार्यकलाप, मानवीय सहायता एवं आपदा प्रबंधन और संयुक्त राष्ट्र शांति-स्थापन कार्यों में सहयोग जैसे विषय शामिल थे।

अफ़गानिस्तान

14.3 अफ़गानिस्तान के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के साथ-साथ भारत ने अफ़गानिस्तान में सुरक्षा स्थिति कायम रखने की दिशा में निरंतर प्रयास किए। भारत ने सैन्य प्रशिक्षण के जरिये अफ़गानी राष्ट्रीय थल सेना (एएनए) को उसकी क्षमता का निर्माण करने में सहायता प्रदान की। वर्ष के दौरान

भारतीय सैन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में अफ़गानिस्तान के लगभग 450 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। सैन्य कार्मिकों को चिकित्सा प्रशिक्षण और चिकित्सा सहायता भी जारी रखी गई। अफ़गान वायु सेना के ले. जनरल ने जुलाई 2017 में भारत का दौरा किया। अफ़गान राष्ट्रीय थल सेना के ले. जनरल ने 7–12 दिसंबर 2017 को भारत का दौरा किया।

अर्मेनिया

14.4 अर्मेनिया के साथ रक्षा सहयोग में इस वर्ष काफी वृद्धि हुई। उप रक्षा मंत्री की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय अर्मेनेई प्रतिनिधिमंडल ने 20–12 दिसंबर, 2017 के दौरान भारत का दौरा किया और प्रमुख भारतीय रक्षा उद्योगों का दौरा करने के अलावा, सचिव (डीपी), अध्यक्ष, डीआरडीओ तथा रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। इस बैठक से पहले, मई 2017 में नई दिल्ली में संयुक्त सचिव स्तर पर रक्षा मंत्रालय स्तरीय वार्ता का पहली बार आयोजन किया गया। दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने हेतु द्विपक्षीय एमओयू, जिस पर बढ़ते सैन्य से सैन्य आदान-प्रदान, प्रशिक्षण वार्ताओं और रक्षा औद्योगिक सहयोग सहित व्यावहारिक उपायों के माध्यम से 2003 में हस्ताक्षर किए गए थे, के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय किया।

आस्ट्रेलिया

14.5 भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नवंबर 2014 में अपनी आस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान विमोचित भारत-आस्ट्रेलिया “सुरक्षा सहयोग के लिए फ़्रेमवर्क” शीर्षक के तहत दोनों देशों ने गत कुछ वर्षों के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को त्वरित एवं व्यापक रूप से बढ़ाया है। इस वर्ष अनेक रूपों में निरंतर वार्ताएं हुईं, जिनमें मंत्री स्तरीय बैठकें, उच्च स्तरीय दौरे, नीत संबंधी संवाद, सैन्य से सैन्य मजबूत सहयोग, संयुक्त युद्धाभ्यास एवं प्रशिक्षण सहयोग शामिल थे। रक्षा मंत्री ने अक्तूबर, 2017 में फिलीपिंस में एडीएमएम प्लस बैठक के अवसर पर आस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों ने रक्षा एवं विदेश सचिवों के बीच एक 2+2 संवाद, जिसकी उद्घाटीय बैठक 12 दिसंबर, 2017 को भारत में आयोजित की गई थी, और रक्षा नीति संवाद एवं रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त कार्य-समूह सहित बढ़ते रक्षा सहयोग को समर्थन देने हेतु मजबूत संस्थागत ढांचा विकसित किया गया। वायु सेनाध्यक्ष ने 19–22 सितंबर 2017 के दौरान एक शिष्टाचार यात्रा के रूप में आस्ट्रेलिया का दौरा किया। वर्ष के दौरान सभी

तीनों सेना स्टाफ स्तरीय वार्ताएं आयोजित की गईं: 16–18 अगस्त, 2017 के दौरान केनबेरा में छठी भारतीय वायुसेना (आईएएफ) और रॉयल आस्ट्रेलियाई वायुसेना (आरएएएफ) एअर स्टाफ वार्ता, 10–12 अक्तूबर, 2017 के दौरान आस्ट्रेलिया में 5वीं सेना से सेना स्टाफ वार्ता और 21–23 नवंबर, 2017 के दौरान केनबेरा में 11वीं भारतीय नौसेना (आईएन) और रॉयल आस्ट्रेलियाई नौसेना (आरएएन) स्टाफ वार्ता। काउंटर इनसरजेंसी/ काउंटर टेरोरिज्म पर द्विपक्षीय सेना युद्धाभ्यास ‘ऑस्ट्राहिंद’ का दूसरा चरण नवंबर 2017 में आस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। भारत ने पूर्व में एक प्रेक्षक के रूप में अपनी सहभागिता को बढ़ाते हुए बहु-आयामी वायुसेना युद्धाभ्यास ‘पिच ब्लैक 2018’ में भाग लेने का निर्णय लिया। आस्ट्रेलिया के मुख्य रक्षा वैज्ञानिक ने डीआरडीओ के अध्यक्ष, जिन्होंने गत वर्ष आस्ट्रेलिया का दौरा किया था, के साथ वार्ता करने के लिए भारत का दौरा किया। पूरे विश्व की समुद्री यात्रा पर निकले भारतीय नौसेना के पोत तारिनी, में ऑनबोर्ड समस्त महिला नौकायन दल ने भी आस्ट्रेलिया का दौरा किया।

बांग्लादेश

14.6 दिसंबर 2016 में बांग्लादेश में भारत के पहले रक्षा मंत्रालय स्तरीय दौरे के साथ बांग्लादेश के साथ रक्षा सहयोग इस वर्ष भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। भारत के प्रधानमंत्री की अप्रैल 2017 में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग फ़्रेमवर्क पर एक द्विपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें आपसी संबंधों को और अधिक बढ़ाने के लिए एक औपचारिक संगत ढांचा उपलब्ध कराया गया है। दोनों देशों ने रक्षा सचिव स्तरीय वार्षिक रक्षा संवाद स्थापित करने, जिसे अप्रैल 2018 में भारत में आयोजित किया जाना है, और त्रिपक्षीय-सेना स्टाफ वार्ता आयोजित करने की सहमति जताई। वर्ष के दौरान भारत के सभी तीनों सेनाध्यक्षों द्वारा बांग्लादेश का दौरा किए जाने से दोनों देशों के बीच सैन्य से सैन्य वार्ता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। नौसेनाध्यक्ष ने नवंबर 2017 में बांग्लादेश द्वारा मेजबानी किए गए ‘आईआएनएस एचएडीआर’ युद्धाभ्यास के लिए बांग्लादेश का दौरा किया। थल सेनाध्यक्ष तथा वायु सेनाध्यक्ष ने क्रमशः मई 2017 और मार्च-अप्रैल, 2017 में द्विपक्षीय दौरे किए। बांग्लादेश नौसेना के एडमिरल, सीएनएस ने 26–31 अगस्त 2017 के दौरान भारत का दौरा किया और बांग्लादेश सेनाध्यक्ष ने 6–10 दिसंबर, 2017 के दौरान भारत का दौरा किया। नौसेना के बीच वार्षिक स्टाफ स्तरीय वार्ता जनवरी 2017 में, वायु सेना स्टाफ स्तरीय वार्ता मई 2017 में

तथा सेना स्टाफ स्तरीय वार्ता जनवरी 2018 में आयोजित की गई। दोनों देशों के बीच सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण द्विपक्षीय सहयोग का एक निरंतर महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। भारतीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों ने वर्ष के दौरान बांग्लादेश में अनेक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया। बांग्लादेश सशस्त्र बलों के 400 से भी अधिक कार्मिकों को इस वर्ष भारतीय सैन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित किया गया। सामरिक एवं कार्यात्मक अध्ययनों के क्षेत्र में सैन्य शिक्षा के लिए डीएसएससी, वैलिंगटन और डीएससीएससी, मिरपुर के बीच सामरिक एवं प्रचालन अध्ययनों के क्षेत्र में और राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और सामरिक अध्ययनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेजों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ अग्रणी प्रशिक्षण संस्थाओं के परस्पर संस्थागत संपर्क औपचारिक रूप से स्थापित किए गए। बांग्लादेश एनडीसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त 2017 में भारत का दौरा किया। भारतीय वायु सेना और नौसेना ने सितंबर-अक्तूबर 2017 में म्यांमार मूल के शरणार्थियों के लिए बांग्लादेश को सहायता सामग्री के परिवहन में सहायता प्रदान की। भारतीय सैन्य सामग्री एवं विमानों, जैसे कि जहाज एवं सेना उपकरणों के मॉडल बांग्लादेश के लिब्रेशन वार म्यूजियम में प्रदर्शित करने के लिए भेजे गए। विजय दिवस के अवसर पर युद्ध में शामिल सैनिकों के परस्पर दिसंबर 2017 में एक वार्ता आयोजित की गई।

ब्राजील

14.7 विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान आदान-प्रदानों के साथ ब्राजील के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में निरंतर प्रगति हुई है। रक्षा मंत्री ने अप्रैल 2017 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मास्को सम्मेलन के अवसर पर ब्राजील के रक्षा मंत्री के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की। द्विपक्षीय संयुक्त रक्षा समिति (जेडीसी) की पांचवी बैठक नई दिल्ली में 27-28 नवंबर 2017 के दौरान हुई। जेडीसी ने सहयोग को बढ़ाने की दिशा में वर्तमान प्रयासों की समीक्षा की और प्रशिक्षण, रक्षा उपकरण तथा भावी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों सहित अनेक कार्यकलापों को अभिज्ञात किया।

ब्रुनेई

14.8 ब्रुनेई के साथ रक्षा सहयोग पर एक एमओयू जिस पर फरवरी 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे, के तहत रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाया गया। भारतीय सेना पोलो बल ने 7-11 मार्च, 2017 के दौरान ब्रुनेई का दौरा किया।

कनाडा

14.9 कनाडा के रक्षा मंत्री के अप्रैल 2017 में भारत के दौरे के दौरान रक्षा संबंधों को बढ़ाया गया। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने अपने परस्पर संबंधों की समीक्षा की तथा सहयोग को मजबूती प्रदान करने हेतु विभिन्न स्तरों पर और अधिक संवाद को प्रोत्साहन देने की सहमति जताई। रक्षा राज्य मंत्री ने 14-15 नवंबर 2017 के दौरान संयुक्त राष्ट्र शांति-स्थापन मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु वेनकोवुर, कनाडा के लिए एक प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई की। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री ने कनाडा के रक्षा मंत्री के साथ भी वार्ता करते हुए अनेक आपसी हितों के मामलों पर चर्चा की।

मिश्र

14.10 मिश्र के रक्षा मंत्री की 9-12 नवंबर, 2017 भारत में सफल दौरे के साथ मिश्र के साथ भारत के रक्षा संबंधों को काफी अधिक बढ़ाया गया। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने बढ़ती रक्षा भागीदारी के लिए उच्च स्तरीय राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता महसूस की और प्रशिक्षण एवं संयुक्त युद्धाभ्यास, रक्षा उद्योग सहयोग, नए एवं उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आदान-प्रदान, आर एवं डी सहयोग तथा सूचना का आदान-प्रदान करने जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने की सहमति की। मिश्र सैन्य आसूचना विभाग के निदेशक (डीएमआईडी) की अगुवाई ने मिश्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने 9-12 जुलाई 2017 के दौरान भारत का दौरा किया। मंत्री स्तरीय दौरे का अनुवर्तन करने हेतु संयुक्त सचिव (नौसेना), डीडीपी और भारतीय शिपयार्ड के प्रतिनिधियों की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिसंबर 2017 में मिश्र का दौरा किया। द्विपक्षीय संयुक्त रक्षा समिति ने जनवरी 2017 में केयरो में बैठक की और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में अनेक कदमों को चिन्हित किया गया।

फ्रांस

14.11 भारत और फ्रांस ने अपने बीच बहु-आयामी, व्यापक एवं आपसी हितकारी रक्षा संबंधों को सतत रूप से आगे बढ़ाया। फ्रांस के सशस्त्र बल के मंत्री ने 27-28 अक्तूबर 2017 के दौरान भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की और प्रधानमंत्री से भी भेंट की। दोनों पक्षों ने सैन्य प्रशिक्षण, बढ़ते संयुक्त युद्धाभ्यासों और विभिन्न स्तरों पर दौरो एवं विशेषज्ञ-जन्य वार्ताओं के

आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और अधिक मजबूती प्रदान करने की सहमति जताई। जनवरी 2017 में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच हस्ताक्षरित व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन के आदान-प्रदान पर तकनीकी अनुबंध के तहत सूचना के आदान-प्रदान को आगे बढ़ाया गया। 24-27 अप्रैल 2017 के दौरान संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास 'वरुणा' किया गया और वर्ष की शुरुआत में संयुक्त सेना युद्धाभ्यास 'शक्ति' का आयोजन किया गया। वायु सेनाध्यक्ष और नौसेनाध्यक्ष ने क्रमशः 17-20 जुलाई 2017 के दौरान और 6-9 नवंबर 2017 के दौरान शिष्टाचार के तौर पर फ्रांस की यात्रा की। फ्रांस नौसेना फ्राइगेट ऐनुरजेन ने 2-6 अक्टूबर 2017 के दौरान आईएनएस करवार में अपनी पहली 'पोर्ट काल' यात्रा की। करवार में फ्रांस के जंगी जहाज की यह पहली बंदरगाह यात्रा थी।

इंडोनेशिया

14.12 विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ इंडोनेशिया के साथ भारत का रक्षा सहयोग इस वर्ष ऊंचाई पर पहुंचा। रक्षा मंत्री और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के बीच नई दिल्ली में 17-19 जनवरी, 2018 के दौरान द्विपक्षीय मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया। दोनों रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय नौसेना एवं वायु सेना युद्धाभ्यासों को आयोजित करने की सहमति दी। दोनों पक्षों ने जनवरी 2017 में जकार्ता में आयोजित रक्षा सचिव स्तरीय 5वीं भारत-इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की बैठक के परिणामों, विशेष रूप से दोनों देशों के सशस्त्र बलों के परस्पर बढ़ते सहयोग के परिणामों पर सक्रिय रूप से अनुवर्तन किया। इस वर्ष, विशेष बलों पर सकेंद्रित रहते हुए द्विपक्षीय 'गरुड़ा' सेना युद्धाभ्यास के दो चरणों का आयोजन किया गया जिसमें से एक का आयोजन हाल ही में फरवरी 2018 में भारत में किया गया। इस वर्ष पहली बार युद्धाभ्यास में एमआई-17 विमानों की सहभागिता के साथ वायु सेना घटक को शामिल किया गया। समुद्री सुरक्षा सहयोग एक प्रमुख क्षेत्र उभरकर आया और दिसंबर, 2016 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के भारत के दौरे के दौरान जारी समुद्री सहयोग पर विज्ञप्ति पर आगे चर्चा की गई। 4-7 जुलाई 2017 के दौरान बाली, इंडोनेशिया में नौसेना से नौसेना स्टाफ वार्ता की गई। वायु सेना से वायु सेना स्टाफ की उद्घाटीय वार्ता 18-20 जुलाई 2017 के दौरान आयोजित की गई। रियर एडमाइरल ने 24-25 अगस्त के दौरान इंडोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय

समुद्री सुरक्षा सेमिनार में एक शोध-पत्र का प्रस्तुतीकरण किया। 6वीं सेना से सेना स्टाफ वार्ता 12-14 सितंबर 2017 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई। 2017 में, अधिकारियों द्वारा स्टाफ पाठ्यक्रम में भाग लेने के अलावा, पहली बार चार कनिष्ठ भारतीय सेना अधिकारियों ने भी पैदल सेना, तोपची सेना और बख्तरबंद स्कूलों में 4-6 माह की अवधि के लिए इंडोनेशिया में कंपनी एवं पलटून स्तरीय पाठ्यक्रमों में भाग लिया। भारतीय नौसेना से एक प्रतिनिधिमंडल ने अक्टूबर 2017 में 7वें दक्षिण प्रशांत पनडुब्बी सम्मेलन में सहभागिता की। भारत और इंडोनेशिया के बीच कोरपेट के 30वें चरण का आयोजन अक्टूबर 2017 में किया गया। द्विवार्षिक कोरपेट के अतिरिक्त, ऑनबोर्ड जहाज कमांडर के साथ पूर्वी जहाद दस्ते के चार जहाजों ने मई के अंत में और जून 2017 के आरंभ में क्रमशः जकार्ता और सुराबया में बंदरगाह की यात्रा की। आईएनएस कदमत ने भारत-आसियान संवाद के 25 वर्षों को मनाने हेतु 30 नवंबर 2017 से 2 दिसंबर 2017 के दौरान बेलावन, इंडोनेशिया में बंदरगाह की यात्रा की।

इजराइल

14.13 इजराइल के साथ रक्षा संबंध और निरंतर मजबूत हुए हैं। रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूहों की 13वीं बैठक 25-26 अप्रैल 2017 के दौरान इजराइल में आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा सचिव द्वारा की गई। दोनों देशों ने सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की और सहयोग के लिए रोड मैप को अंतिम रूप दिया। एडमिरल, अध्यक्ष, चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी एवं नौसेनाध्यक्ष ने 12-15 जून 2017 के दौरान शिष्टाचार के रूप में इजराइल की यात्रा की। मेजर जनरल, सेना चीफ ऑफ ग्राउंड फोर्सिस, इजराइल ने 29 अक्टूबर-2 नवंबर 2017 के दौरान भारत की यात्रा की। भारत ने 5-16 नवंबर 2017 के दौरान इजराइल में आयोजित बहु-आयामी युद्धाभ्यास 'बल्यू फ्लैग' में भाग लिया। महानिदेशक वायु सेना (प्रचालन) ने 14 नवंबर 2017 को एक्स बल्यू फ्लैग 17 के विशिष्ट आगन्तुक (डीवी) दिवस में भाग लिया।

जापान

14.14 जापान के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में हाल ही के वर्षों में कर्मिक एवं महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2017 को भारत-जापान वार्षिक रक्षा मंत्री संवाद में भाग लेने हेतु जापान की यात्रा की। दोनों रक्षा मंत्रियों ने टोकियो में प्रथम रक्षा उद्योग

सेमिनार को संबोधित किया जिसमें दोनों देशों के अधिकांश उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने बढ़ती सेना से सेना पारस्परिक वार्ताओं, प्रशिक्षण तथा आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अन्य प्रकार के आदान-प्रदानों सहित विभिन्न उपायों पर सहमति की। इस यात्रा के अवसर पर विभिन्न रक्षा सहयोग पहलों को शामिल करते हुए एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। मंत्री स्तरीय संवाद के अनुक्रम में, द्विपक्षीय रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी संयुक्त कार्यसमूह ने 4 सितंबर 2017 को टोकियो में मुलाकात की। दोनों पक्षों ने रक्षा अनुसंधान और विकास में भावी सहयोग के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की सफलतापूर्वक पहचान की। इससे पहले, वर्ष में टोकियो में 5वें रक्षा नीति संवाद और 2+2 संवाद का आयोजन किया गया। रक्षा सचिव ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। जनरल, चीफ ऑफ स्टॉफ, जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने 11-14 अप्रैल 2017 के दौरान भारत की यात्रा की।

जॉर्डन

14.15 जॉर्डन के रक्षा मंत्री की 18-19 दिसंबर 2017 के दौरान भारत में एक 4 सदस्यीय वरिष्ठ आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के साथ जॉर्डन के साथ रक्षा संबंधों में एक नई शुरुआत हुई है। प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त सचिव (पीआईसी) से मुलाकात की और रक्षा संबंधों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सहयोग तथा प्रशिक्षण संबंधी आदान-प्रदान के लिए एक संगत ढांचा उपलब्ध करने हेतु रक्षा सहयोग पर एक एमओयू को अंतिम रूप देने सहित द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अनेक पहलों पर सहमति की। प्रतिनिधिमंडल ने इस क्षेत्र में सहयोग के कार्यक्षेत्र का निर्धारण करने हेतु विभिन्न भारतीय रक्षा उद्योग इकाइयों का भी दौरा किया।

केन्या

14.16 वर्ष 2016 में हस्ताक्षरित सुरक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय एमओयू पर आगे वार्ता करने के लिए रक्षा सचिव की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी 2018 में केन्या की यात्रा की और केन्या के साथ रक्षा संबंधों पर आगे वार्ता की। प्रतिनिधिमंडल ने केन्या के रक्षा मंत्रालय के नेताओं के साथ अनेक विषयों पर वार्ता की। दोनों देशों ने प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग, तटवर्ती सुरक्षा और रक्षा अनुसंधान एवं विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में सहमति की।

कजाखस्तान

14.17 वर्ष के दौरान कजाखस्तान के साथ रक्षा संबंधों में काफी प्रगति हुई। सेनाध्यक्ष ने 1-4 अगस्त 2017 के दौरान कजाखस्तान की यात्रा की। द्विपक्षीय सेना संयुक्त युद्धाभ्यास 'प्रबल दसित्याक' का आयोजन भारत के बाखलोह में 2-15 नवंबर 2017 के दौरान किया गया। दोनों पक्षों ने भविष्य में युद्धाभ्यासों के कार्य-क्षेत्र व को बढ़ाने हेतु सहमति की। ले. जनरल, कजाखस्तान के उप रक्षा मंत्री ने 6-8 नवंबर 2017 के दौरान भारत की यात्रा की और आरएम, सेनाध्यक्ष तथा रक्षा सचिव से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र शांति-स्थापना सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने की सहमति की और इस संबंध में कार्यविधियों को अंतिम रूप देने हेतु चर्चाएं की जा रही हैं।

किरगिज गणतंत्र

14.18 किरगिज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ (सीजीएस) की 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2017 के दौरान यात्रा के साथ किरगिज के साथ रक्षा सहयोग को काफी गति प्रदान हुई है। सीजीएस ने एक दिसंबर 2017 को रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने तथा आपसी हित के अन्य क्षेत्रों की खोज करने की सहमति की। वार्षिक द्वि पक्षीय संयुक्त सेना युद्धाभ्यास 'खंजर' को किरगिज गणराज्य में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

मेडागास्कर

14.19 संयुक्त सचिव (ईआईसी) की अगुवाई में रक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी 2018 में मेडागास्कर की यात्रा की और रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाया। प्रतिनिधिमंडल ने मेडागास्कर के सशस्त्र बल के नेता के साथ वार्ता की तथा विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग पर एक एमओयू को अंतिम रूप दिया जिस पर मार्च, 2018 में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान हस्ताक्षर हुए। प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा समुद्री सुरक्षा जैसे भावी सहयोग के मुख्य क्षेत्रों की पहचान की।

मलेशिया

14.20 मलेशिया के साथ रक्षा सहयोग निरंतर और अधिक मजबूत हो रहे हैं। नौसेनाध्यक्ष और चीफ आफ स्टाफ कैमेट्री के अध्यक्ष ने 12-15 अप्रैल 2017 के दौरान मलेशिया की यात्रा की।

6वीं सेना से सेना स्टॉफ की वार्ता का आयोजन 16–18 मई 2017 के दौरान नई दिल्ली में किया गया। 7वीं नौसेना से नौसेना स्टाफ वार्ता का आयोजन 3–5 अक्टूबर 2107 के दौरान भारत में किया गया। द्विपक्षीय सेना युद्धाभ्यास 'हरी माऊ शक्ति' के लिए आरंभिक आयोजना सम्मेलन का आयोजन 25–27 अक्टूबर 2017 के दौरान मलेशिया में किया गया। सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों ने मई 2018 के दौरान युद्धाभ्यास आयोजित करने का निर्णय किया। भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच प्रथम फील्ड प्रशिक्षण युद्धाभ्यास का आयोजन 6–7 दिसंबर 2017 के दौरान किया गया। युद्धाभ्यास 'समुद्र लक्ष्मण-2017' एक माननीय सहायता एवं आपदा सहायता (एचएडीआर) युद्धाभ्यास था जिसमें दोनों नौसेनाओं के दो जहाजों, अर्थात् भारत से आईएनएस सतपुडा, आईएनएस कदमत तथा मलेशिया से केडी लिंकर एवं केडी लक्ष्मणा हेंग नेडिम ने भाग लिया।

मालदीव

14.21 मालदीव के साथ कॉमन समुद्री सुरक्षा चिंताएं रक्षा सहयोग का एक प्रमुख पहलु रही हैं। दूसरी संयुक्त स्टाफ वार्ता 23–25 मई 2017 के दौरान भारत में आयोजित की गई जिसमें सहयोग के लिए विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गई। सैन्य प्रशिक्षण, चिकित्सा प्रशिक्षण तथा सेना कार्मिकों को चिकित्सीय सहायता के जरिए क्षमता निर्माण में भारत में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) को सहायता प्रदान की गई। इस वर्ष एमएनडीएफ के 120 से अधिक सैन्य कार्मिकों ने भारतीय सैन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

मंगोलिया

14.22 मंगोलिया के रक्षा मंत्री के 6 से 10 मार्च, 2018 के दौरान भारत के सफल दौरे के साथ ही मंगोलिया के साथ रक्षा कारोबार बढ़ा। इस दौरान उन्होंने माननीय रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की।

म्यांमार

14.23 म्यांमार के साथ रक्षा सहयोग निरंतर मजबूत होते जा रहे हैं। सेनाध्यक्ष ने 28–31 मई 2017 के दौरान म्यांमार की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान 10 एंबुलेंस, 15 जासूसी कुत्ते और 4 अंगेजी भाषीय प्रयोगशालाएं म्यांमार को शिष्टाचार के तौर पर उपहारस्वरूप भेंट की गई। सीनियर जनरल, कमांडर-इन-चीफ,

म्यांमार सशस्त्र बल ने 7–15 जुलाई 2017 के दौरान भारत की यात्रा की। उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात भी की। भारतीय मोबाइल ट्रेनिंग टीमों ने मई एवं अगस्त 2017 के दौरान म्यांमार सेना के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति-स्थापना प्रशिक्षण का आयोजन किया ताकि उन्हें अपने यूएन मिशन के लिए योजना बनाने, तैयारियों तथा सैनिकों को तैनात करने में सहायता प्रदान की जा सके। म्यांमार के कमांडर इन चीफ (वायु सेना) ने 21–25 अगस्त 2017 के दौरान भारत का दौरा किया। एडमिरल सी-इन-सी म्यांमार नौसेना ने 18–21 सितंबर 2017 के दौरान भारत की यात्रा की। म्यांमार के सशस्त्र बल प्रशिक्षण के प्रमुख ने 23–28 अक्टूबर 2017 के दौरान भारत की यात्रा की। दोनों पक्षों ने व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तकनीकी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और समुद्री क्षेत्र में जागरूकता लाने हेतु और अधिक कदम उठाने की सहमति की। भारतीय नौसेना (आईएन) और म्यांमार नौसेना (एमएन) स्टाफ के छठे दौर की वार्ता का आयोजन 6–9 नवंबर 2107 के दौरान ऐनगांव, म्यांमार में किया गया। यूएनपीक्यूओ शीर्षक के आधार पर भारत-म्यांमार 'टेबल टॉप' युद्धाभ्यास (टीटीएक्स) एक्स आईएमबीएक्स-17 के पहले चरण का आयोजन नवंबर 2017 में भारत में किया गया। म्यांमार के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) के बिग्रेडियर जनरल, उप-कमांडेंट की अगुवाई में एक 35 सदस्यीय म्यांमार प्रतिनिधिमंडल ने 20–26 नवंबर 2017 के दौरान एनडीसी, भारत की यात्रा की। रक्षा सहयोग के भाग के रूप में, म्यांमार को बेली ब्रिजिज जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स सहायता उपलब्ध कराई गई। म्यांमार के 35 सेना कार्मिकों के लिए दिसंबर 2017 में काउंटर इनसरजेंसी एंड जंगल वारफेयर (सीआईजेडब्ल्यू) स्कूल, वेरियन गेट में न्यून-गहन जवाबी कार्रवाई में एक 4 सप्ताहिक टेलर मेड प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

नेपाल

14.24 भारत और नेपाल के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से काफी मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। नेपाल में अनेक भारतीय सैन्य कार्मिकों ने पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। नेपाल की थल सेना के 250 से अधिक कार्मिकों ने इस वर्ष भारत में रक्षा संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया। सेनाध्यक्ष ने 12–14 फरवरी, 2018 के दौरान नेपाल की यात्रा की और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के अनेक पहलुओं पर चर्चा की।

नाइजीरिया

14.25 नाइजीरिया के साथ भारत का रक्षा सहयोग इस वर्ष काफी अधिक बढ़ा। भारत के अपर सचिव (रक्षा उत्पादन) की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने 20–21 नवंबर 2017 के दौरान संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की चौथी बैठक के लिए नाइजीरिया की यात्रा की। दोनों पक्षों ने बढ़ते प्रशिक्षण, पारस्परिक चर्चाओं तथा रक्षा उद्योग सहयोग सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु अनेक पहलुओं पर सहमति की। भारत ने नाइजीरिया के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ने और यांत्रिक युद्ध जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ-जन्य प्रशिक्षण प्रदान किए। नौसेना से नौसेना पारस्परिक संवाद में काफी प्रगति हो रही है।

ओमान

14.26 ओमान के साथ रक्षा संबंधों में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। दोनों पक्षों ने 2016 में भारत के रक्षा मंत्री की ओमान यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित 4 एमओयू से प्राप्त गति को और अधिक आगे बढ़ाया। नौसेना से नौसेना की उद्घाटीय वार्ता का आयोजन 22–24 जनवरी 2017 के दौरान ओमान में किया गया। एडमिरल, नौसेनाध्यक्ष ने 1–2 मार्च 2017 के दौरान ओमान की यात्रा की। ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव ने 17 अप्रैल 2017 को 9वीं संयुक्त सैन्य सहयोग समिति में भाग लेने हेतु भारत की यात्रा की। दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग और सैन्य चिकित्सा उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में द्विपक्षीय क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक सबल बनाने के लिए अनेक पहलों पर चर्चा की।

फिलीपींस

14.27 फिलीपींस के साथ रक्षा सहयोग निरंतर एवं सक्रिय रूप से बढ़ा है। भारत के रक्षा मंत्री ने एडीएमएम प्लस बैठक में भाग लेने के लिए अक्टूबर 2017 में फिलीपींस की यात्रा की जिस दौरान उन्होंने अपने सहयोगी, राष्ट्रीय रक्षा सचिव, फिलीपींस के साथ 8–11 मार्च, 2018 तक एक सार्थक द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की दूसरी बैठक, जिसकी सह-अध्यक्षता मार्च 2017 में नई दिल्ली में संयुक्त सचिव (पीआईसी) द्वारा की गई थी, में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को गति प्रदान करने की सहमति की। नवंबर 2017 में प्रधानमंत्री की फिलीपींस की यात्रा के दौरान रक्षा उद्योग एवं संभार-तंत्र सहयोग पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे रक्षा औद्योगिक सहयोग में गति प्रदान किए जाने की उम्मीद की जाती है। दोनों

देशों के बीच प्रशिक्षण का आदान-प्रदान और जहाजों की यात्रा जारी रही। 2017–18 में, लगभग 25 फिलीपींस सशस्त्र बलों ने भारतीय प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

कोरिया गणतंत्र

14.28 कोरिया गणतंत्र (आरओके) के साथ रक्षा सहयोग में गत वर्षों के दौरान काफी प्रगति हुई है। कोरिया गणतंत्र के रक्षा अधिग्रहण एवं कार्यक्रम प्रशासन (डीएपीए) मंत्री ने अप्रैल 2017 में भारत की यात्रा की। जहाज-निर्माण सहयोग पर एक एमओयू तथा भारत में के-9 बंदूकों के विनिर्माण के लिए भारत एवं कोरिया गणतंत्र कंपनियों के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। जून 2017 में सियोल की यात्रा के दौरान वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री ने अपने सहयोगी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कमांडेंट, एनडीसी की अगुवाई में 57वें एनडीसी पाठ्यक्रम से एक 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 27–31 अगस्त 2017 के दौरान कोरिया गणतंत्र की यात्रा की। भारत ने सितंबर 2017 में सियोल में 6वें सियोल रक्षा संवाद (एसडीडी) और साइबर कार्यसमूह में सहभागिता की। कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (केएनडीयू) से एक प्रतिनिधिमंडल ने 12–17 सितंबर 2017 के दौरान भारत की यात्रा की। सचिव (रक्षा उत्पादन) ने 15–18 अक्टूबर 2017 को कोरिया गणतंत्र की यात्रा की और 7वीं संयुक्त समिति बैठक (जेसीएम) की सह-अध्यक्षता की। सचिव (डीआरडीओ) ने चौथी संचालन समिति बैठक (एसएसएम) में भाग लेने हेतु 3–7 दिसंबर 2017 को कोरिया गणतंत्र की यात्रा की। कोरिया गणतंत्र के नौसेना जहाजों, यानी 'चोई यंग (विध्वंसक)' ने जून 2017 में और "केंग गामचंद" एवं "ह्वानचियान" ने अक्टूबर 2017 में मुम्बई का दौरा किया। महानिदेशक, तटरक्षक बल ने 12–15 दिसंबर 2017 के दौरान सियोल में द्विपक्षीय तटरक्षक उच्च स्तरीय बैठक के आठवें दौर में भाग लिया। आईसीजी जहाज 'शौर्या' ने भी 11–15 दिसंबर 2017 को कोरिया गणतंत्र की यात्रा की। कोरिया गणतंत्र सेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीमावर्ती प्रबंधन मुद्दों पर चर्चा करने हेतु दिसंबर 2017 में भारत की यात्रा की।

रूस

14.29 आपसी विश्वास और समझ के आधार पर, भारत और रूस के बीच काफी लंबे समय से रक्षा संबंध रहे हैं। रक्षा उपकरणों के आधार पर, रूस भारत का अति महत्वपूर्ण साझेदार है। रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ रक्षा मंत्री स्तर पर

भारत ने एक संस्थागत रक्षा सहयोग कार्यप्रणाली स्थापित की है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 6वें मास्को सम्मेलन में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री ने 26–27 अप्रैल 2017 के दौरान रूस की यात्रा की, जिस दौरान उन्होंने उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। रक्षा मंत्री ने नोवोसिब्रिस्क में विज्ञान और प्रौद्योगिकी बैठक पर उद्घाटीय भारत-रूस उच्च स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए जून 2017 में और सैन्य तकनीकी सहयोग पर 17वें भारत-रूस अंतर-राजकीय आयोग की मोस्को में क्रमशः 21 एवं 23 जून 2017 को बैठक में भाग लेने के लिए भी रूस की यात्रा की। दोनों रक्षा मंत्रियों द्वारा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कर एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए गए। इस रोड मैप में बढ़ती सेना से सेना पारस्परिक चर्चाओं, प्रशिक्षण और विषयगत आदान-प्रदानों को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर परस्पर वार्ता की परिकल्पना की गई है। रक्षा मंत्री ने अक्टूबर 2107 में फिलीपींस में एडीएमएम प्लस बैठक के अवसर पर अपने रूसी सहयोगी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। डीपीएम के दौरान दिसंबर 2017 में भारत में उप प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान साऊथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों के फलस्वरूप भारत-रूस पारस्परिक वार्ताओं को और अधिक गति प्रदान हुई है। इस वर्ष रक्षा सहयोग की एक विशेष उपलब्धि ऐतिहासिक संयुक्त त्रिपक्षीय सेवा युद्धाभ्यास 'इंद्रा-2017' थी, जिसका आयोजन 20–29 अक्टूबर 2017 के दौरान रूस में किया गया। त्रि-सैन्य फार्मेट में दोनों देशों के लिए यह प्रथम संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास था। रूस की नौसेना के कमांडर इन-चीफ ने 15–18 मार्च 2017 के दौरान भारत का दौरा किया। नौसेना स्टाफ के दूसरे दौर की वार्ता का आयोजन 28–30 जून 2017 के दौरान भारत में किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने 29 जुलाई से 12 अगस्त 2017 के दौरान रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल-2017 में प्रतिभागिता की। तीनों सेनाओं के एक बैंड दस्ते ने 26 अगस्त से 3 सितंबर 2017 के दौरान रैंड स्क्वेयर, मास्को में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सेना संगीत महोत्सव 'स्पास्कया टॉवर' में प्रतिभागिता की। द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए रक्षा सचिव ने सितंबर 2017 में रूस की यात्रा की। रूसी संघ के सशस्त्र बलों और एचक्यू-आईडीएस के जनरल स्टाफ के बीच तीसरी स्टाफ वार्ता का आयोजन 13–15 नवंबर 2017 के दौरान किया गया।

सऊदी अरब

14.30 भारत और सऊदी अरब ने अपने रक्षा संबंधों को हाल

ही के वर्षों में काफी बढ़ाया है। सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल ने 17–21 अप्रैल 2017 के दौरान विभिन्न भारतीय डीपीएसयू और निजी उद्योगों का दौरा किया। सऊदी अरब के साथ तीसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की बैठक 29–30 नवंबर 2017 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी सह-अध्यक्षता संयुक्त सचिव (पीआईसी) द्वारा की गई। बैठक से दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए रक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग के अनेक नए क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिली। नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष तथा नौसेनाध्यक्ष ने फरवरी 2018 में सऊदी अरब की यात्रा की। दोनों देशों के बीच इस स्तर पर यह पहली यात्रा थी। इस दौरान द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यासों, जैसे कि सेना से सेना संबंधों को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलों पर चर्चा की गई। सऊदी अरब कैडेट ने प्रि-कमीशनिंग प्रशिक्षण के लिए पहली बार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में सुमार हुए।

स्वीडन

14.31 स्वीडन के साथ रक्षा संबंधों में अच्छी प्रगति हुई है। रक्षा मंत्री ने 10–13 दिसंबर 2017 के दौरान भारत की यात्रा की। उन्होंने रक्षा सचिव तथा नौसेनाध्यक्ष एवं उप वायु सेनाध्यक्ष के साथ मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सामान्य सुरक्षा अनुबंध पर बातचीत को अंतिम रूप दिया। रक्षा उद्योग पर वार्ताएं निरंतर रूप से चल रही हैं।

सिंगापुर

14.32 सिंगापुर के साथ रक्षा सहयोग में इस वर्ष काफी बढ़ोत्तरी हुई है। रक्षा मंत्री के साथ दूसरे वार्षिक रक्षा मंत्री संवाद (डीएमडी) में भाग लेने हेतु सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने 28–29 नवंबर 2017 के दौरान भारत की यात्रा की। दोनों मंत्रियों ने साझे समुद्री स्थल में नियमित नौसेना युद्धाभ्यासों सहित रक्षा संबंधों को और अधिक सबल बनाने हेतु अनेक पहलों पर सहमति की। आपसी लॉजिस्टिक्स सहायता के लिए प्रावधानों सहित नौसेना सहयोग के लिए द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। सिंगापुर के रक्षा मंत्री पहले ऐसे विदेशी रक्षा मंत्री थे जिन्होंने 'तेजस एलसीए' की यात्रा की। रक्षा नीति संवाद (डीपीडी) की 11वीं बैठक का आयोजन जनवरी 2017 में सिंगापुर में किया गया, जिसकी सह-अध्यक्षता रक्षा सचिव और वरिष्ठ सचिव (रक्षा), सिंगापुर द्वारा की गई। डीपीडी के दौरान भारत में सैन्य प्रशिक्षण एवं

युद्धाभ्यासों के लिए वायु सेना अनुबंध का नवीनीकरण करते हुए उसे अक्तूबर 2022 तक आगे बढ़ाया गया। भारत-सिंगापुर रक्षा कार्यसमूह (डीडब्ल्यूजी) की 10वीं बैठक 29 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसकी सह-अध्यक्षता संयुक्त सचिव (पीआईसी) एवं निदेशक (नीति), सिंगापुर, रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई। नौसेनाध्यक्ष ने आरएसएन 50 समारोह में भाग लेने/ अंतरराष्ट्रीय समुद्री समीक्षा करने और आईएमडीईएक्स एशिया में भाग लेने के लिए 14-18 मई 2017 के दौरान सिंगापुर की यात्रा की। द्विपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास 'सिमबेक्स' का आयोजन मई 2017 में किया गया। सिंगापुर नौसेनाध्यक्ष ने नवंबर 2017 में गोआ समुद्री सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। 11वीं सेना स्टाफ वार्ता का आयोजन फरवरी 2017 में तथा 12वीं नौसेना वार्ता के लिए मार्च 2017 में नई दिल्ली में आयोजन किया गया। यांत्रिक जंगी जहाज के आधार पर, सेना युद्धाभ्यास 'बोल्ड कुरुक्षेत्र' का आयोजन मार्च 2017 में भारत में किया गया। दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण (जेएमटी17) के 10वें दौर का आयोजन 6 नवंबर से 14 दिसंबर 2017 के दौरान कलाईकुंडा में किया गया।

सेशल्ल्स

14.33 भारत सेशल्ल्स के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण सहयोग के आदान-प्रदान, रक्षा उपकरण और क्षमता निर्माण की आपूर्ति के आधार पर काफी घनिष्ठ रक्षा सहयोग हैं। द्विपक्षीय सेना युद्धाभ्यास एल 'अमेटी का आयोजन फरवरी 2018 में सेशल्ल्स में किया गया। हाइड्रोग्राफी पर द्विपक्षीय संयुक्त कार्यसमूह की पहली बैठक मार्च 2018 में सेशल्ल्स में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने साझे खतरों और चुनौतियों से निपटने हेतु समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर निरंतर परामर्श किया। सेशल्ल्स रक्षा बलों के लगभग 70 कर्मिकों ने 2017-18 में भारत में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

दक्षिण अफ्रीका

14.34 दक्षिण अफ्रीका के साथ रक्षा संबंधों में कर्मिक रूप से प्रगति हुई है। 8वीं द्विपक्षीय संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक 6-7 दिसंबर, 2017 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसकी सह-अध्यक्षता रक्षा सचिव द्वारा की गई। बैठक में रक्षा सहयोग को सबल बनाने हेतु वर्तमान प्रयासों की समीक्षा की गई और सहयोग को गति प्रदान करने के लिए नए उपायों की पहचान की गई। फिक्की द्वारा नई दिल्ली में 7 दिसंबर 2017 को एक

द्विपक्षीय रक्षा उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका प्रतिनिधिमंडल ने द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु डीआरडीओ के साथ भी बैठकें कीं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 10वीं नौसेना से नौसेना स्टाफ वार्ता का आयोजन 5 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में किया गया।

श्रीलंका

14.35 भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ठ रक्षा संबंध हैं। रक्षा सचिव स्तर पर द्विपक्षीय वार्षिक रक्षा संवाद का आयोजन जनवरी 2018 में नई दिल्ली में किया गया। एडीडी ने रक्षा सहयोग को सबल बनाने हेतु अनेक पहलों पर सहमति की जिनमें सेना, वायु सेना और नौसेना संबंधी विषय शामिल थे। विशेष रूप से, साझा समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए अनेक पहलों पर चर्चा की गई और शीर्ष निर्णय लिए गए। भारत श्रीलंका के सशस्त्र बलों को उनके क्षमता निर्माण में निरंतर सहायता देता है। श्रीलंका के 1750 से अधिक सैन्य कर्मिकों ने इस वर्ष भारतीय सैन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया। विभिन्न भारतीय सैन्य अधिकारियों ने भी श्रीलंकाई सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थाओं में विशेषज्ञ-जन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। दोनों देशों के बीच सेना से सेना पारस्परिक संवाद नियमित रूप से जारी रहे। श्रीलंका के महानिदेशक तटरक्षक और श्रीलंका नौसेना के कमांडर ने जनवरी 2017 में भारत का दौरा किया। श्रीलंका की सेना कमांडर ने 6 से 9 मार्च, 2018 तक भारत का दौरा किया और श्रीलंका नौसेना कमांडर ने 14-17 मार्च, 2018 तक भारत का दौरा किया। वायु सेनाध्यक्ष ने 11-14 दिसंबर 2017 के दौरान श्रीलंका का दौरा किया। नौसेनाध्यक्ष ने श्रीलंका में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन-गाले संवाद में भाग लिया। वार्षिक सेना स्टाफ वार्ता का आयोजन मार्च 2017 में और नौसेना स्टाफ वार्ता का आयोजन सितंबर 2017 में किया गया।

तजाकिस्तान

14.36 तजाकिस्तान के साथ पारंपरिक रूप से घनिष्ठ रक्षा संबंधों को फरवरी 2018 में तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री के भारत में सफल दौरे से गति प्रदान हुई। रक्षा मंत्री के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के अलावा, तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पुणे का भी दौरा किया। दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग को और अधिक मजबूती प्रदान करने की सहमति की।

थाइलैंड

14.37 थाइलैंड के साथ रक्षा सहयोग में प्रगति हुई है। 9वीं नौसेना से नौसेना स्टाफ वार्ता 29 से 31 मई 2017 के दौरान बैंकाक में आयोजित की गई। उद्घाटीय सेना स्टाफ वार्ता 20-22 जून 2017 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई। काउंटर इनसरजेंसी /काउंटर टैरोरिजम (सीआई/सीटी) शीर्षक के आधार पर, जुलाई 2017 में भारत में 'एक्स मैत्री' का आयोजन किया गया जिसमें दोनों देशों में 45 व्यक्तियों ने भाग लिया। वायु सेना स्टाफ के 8वें दौर की वार्ता 19-21 सितंबर 2017 के दौरान थाइलैंड में आयोजित की गई। भारत में बैंकाक में 6-10 नवंबर 2017 के दौरान 'एक्स कोबरा गोल्ड-2017' में सक्रिय रूप से प्रतिभागिता की। अपर सचिव (रक्षा) स्तर पर वार्षिक रक्षा संवाद फरवरी 2018 में बैंकाक में आयोजित किया गया। रक्षा संबंधों, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए दोनों पक्षों ने उपायों पर चर्चा की।

तुर्कमेनिस्तान

14.38 तुर्कमेनिस्तान के साथ रक्षा संबंधों में जुलाई 2015 में हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय अनुबंध के कारण हाल ही के वर्षों में गति आई है। सेनाध्यक्ष ने 4-6 अगस्त 2017 के दौरान तुर्कमेनिस्तान का दौरा किया। तुर्कमेनिस्तान के उप रक्षा मंत्री की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त 2017 में भारत की यात्रा की और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने हेतु तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय रक्षा उद्योग का भी विस्तृत रूप से दौरा किया।

उगांडा

14.39 रक्षा बल के उप सेनाध्यक्ष ले.जनरल की 2017 में भारत की यात्रा के साथ उगांडा के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत किया गया और फरवरी 2018 में उगांडा रक्षा स्टाफ कॉलेज के एक 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की भारत में मेजबानी की गई।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)

14.40 यूएई के साथ रक्षा सहयोग कूटनीतिज्ञ संबंधों का एक महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर आया है। रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग पर एक द्विपक्षीय एमओयू पर 25 जनवरी 2017 को नई

दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। राज्य रक्षा मंत्री की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी (आईडीएक्स) में भाग लेने तथा द्विपक्षीय बैठकों के लिए 19-21 फरवरी 2017 के दौरान अबु धाबी, यूएई की यात्रा की। नौसेनाध्यक्ष ने 26-27 फरवरी 2017 के दौरान यूएई की यात्रा की। भारत और यूएई के बीच 6वीं नौसेना से नौसेना स्टाफ वार्ता 18-20 सितंबर 2017 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई। संयुक्त रक्षा समिति की 9वीं बैठक 7 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में हुई। यूएई के वायुसेना एवं वायुरक्षा से एक प्रतिनिधिमंडल ने वायु सेना उपकरण से संबंधित लॉजिस्टिक्स प्रौद्योगिकी सहयोग के पहलुओं पर चर्चा करने हेतु 20-21 दिसंबर 2017 के दौरान बैठकें आयोजित की गईं।

संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए)

14.41 विभिन्न स्तरों पर क्रमिक एवं सार्थक वार्ताओं के जरिए तथा भारत- अमेरिका रक्षा संबंधों के लिए नए फ्रेमवर्क और लॉजिकस्टिक आदान-प्रदान समझौता अनुबंध (एलईएमओए) जैसे समझौतों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के साथ भारत के रक्षा संबंध चरणबद्ध रूप से काफी मजबूत और प्रगाढ़ हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने सितंबर 2017 में भारत की यात्रा की जिस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री तथा प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उनकी यात्रा के दौरान अनेक क्षेत्रों में संबंधों को महत्वपूर्ण गति प्रदान हुई और सैन्य से सैन्य संबंधों, रक्षा उद्योग सहयोग एवं प्रौद्योगिकी भागीदारियों को कवर करते हुए बढ़ते सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई। रक्षा मंत्री ने अक्टूबर 2017 में फिलीपींस में एडीएमएम प्लस रक्षा मंत्रियों की बैठक के अवसर पर अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों के संबंधों में समुद्री सुरक्षा सहयोग एक प्रमुख घटक के रूप में उभरकर सामने आया। दूसरे भारत-यूएस समुद्री सुरक्षा संवाद का आयोजन मई 2017 में यूएस नवल वार, कॉलेज रोड आइलैंड में किया गया। नौसेनाओं के बीच तकनीकी मेलजोल को सुकर बनाने के लिए भारत ने दिसम्बर 2017 में पीएसी-एचओएसटीएसी करार किया। भारत, अमेरिका और जापान नौसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास मालाबा मॉर 8-17 जुलाई 2017 के दौरान चेन्नई के नजदीक किया गया। द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास अमेरिका में 14-27 सितंबर 2017 के दौरान आयोजित किया गया। वायु सेनाध्यक्ष ने प्रशांत वायु सेनाध्यक्षों की संगोष्ठी में सहभागिता करने हेतु 26-28 सितंबर 2017 के दौरान एक आमंत्रित दौरे पर यूएसए की यात्रा की। भारत-यूएस सेना युद्ध

भ्यास 'अजेय वेरियर' का आयोजन दिसंबर 2017 में भारत में किया गया। द्विपक्षीय रक्षा व्यापार एवं प्रौद्योगिकी पहल पर अक्टूबर 2017 में यूएसए में एक बैठक आयोजित की गई। द्विपक्षीय सैन्य सहयोग समूह और रक्षा सेवा स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने पूरे वर्ष बैठकें कीं और सहयोग के लिए अनेक व्यावहारिक पहलुओं पर सहमति की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को ऊंचाई पर ले जाने के लिए अनेक सहयोगात्मक प्रयास किए गए।

यूनाइटेड किंगडम

14.42 यूनाइटेड किंगडम के साथ रक्षा सहयोग में अनवरत प्रगति हुई है। दोनों देशों के सशस्त्र सेनाओं के बीच उच्च स्तरीय दौरों, प्रशिक्षण और अन्य व्यावसायिक आदान-प्रदान नियमित रूप से किए गए। यूके के रक्षा मंत्री ने अप्रैल 2017 में भारत की यात्रा की और रक्षा मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक की। द्विपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास 'कोंकण' को यूके में 2-6 मई के दौरान आयोजित किया गया। यूनाइटेड किंगडम के एअर चीफ मार्शल, कमांडर इन-चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसिस ने 19-23 जुलाई 2017 के दौरान भारत का दौरा किया। 18वें रक्षा सलाहकार समूह (डीसीजी) की बैठक 9-10 अक्टूबर 2017 लंदन में आयोजित की गई जिसकी सह-अध्यक्षता रक्षा सचिव द्वारा की गई। यूनाइटेड किंगडम के एअर चीफ मार्शल, चीफ ऑफ एअर स्टाफ, रॉयल एअर फोर्स ने 15-17 नवंबर के दौरान भारत का दौरा किया।

वियतनाम

14.43 वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग बहुत अच्छी तरह प्रगति कर रहा है। रक्षा सचिव ने 10वें भारत-वियतनाम वार्षिक सुरक्षा संवाद के लिए मार्च 2017 में वियतनाम की यात्रा की। द्विपक्षीय कूटनीतिक भागेदारी की स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मनाने हेतु भारतीय थल सेना सिम्फनी बैंड ने 20-23 अप्रैल 2017 के दौरान वियतनाम की यात्रा की। दोनों देशों के बीच सैन्य से सैन्य सहयोग नियमित और व्यापक रूप से बढ़ा है। चेयरमेन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और नौसेनाध्यक्ष ने 4-7 अक्टूबर 2017 के दौरान वियतनाम की यात्रा की। वायु सेनाध्यक्ष ने 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2017 के दौरान वियतनाम की यात्रा की। वियतनाम गणतंत्र सेना के राजनीतिक मामलों के सामान्य विभाग के प्रमुख ने 12-15 नवंबर 2017 के दौरान भारत में एक प्रतिनिधिमंडल की

अगुवाई की। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सचिव, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों के साथ वार्ता की तथा रक्षा मंत्री से मुलाकात की। उद्घाटीय भारत-वियतनाम सेना से सेना स्टाफ वार्ता का आयोजन 11-12 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में किया गया। दूसरी नौसेना स्टाफ वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में 18-20 दिसंबर 2017 को किया गया। रक्षा सहयोग के भाग के रूप में, एक भारतीय थल सेना मोबाइल प्रशिक्षण दल ने दिसंबर 2017 में वियतनाम सेना के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति-स्थापन में प्रशिक्षण का आयोजन किया।

जाम्बिया

14.44 जाम्बिया के साथ रक्षा सहयोग को एक तकनीकी समिति (टीसी) प्रतिनिधिमंडल की अक्टूबर 2017 में भारत की यात्रा के साथ नया रूप प्रदान हुआ। इस प्रतिनिधिमंडल में जाम्बिया मंत्रालय के 9 अधिकारी शामिल थे। इस यात्रा का प्रारंभिक प्रयोजन भारतीय सशस्त्र बलों तथा भारतीय सशस्त्र बलों में सैन्य न्याय व्यवस्था से सर्वश्रेष्ठ विधियों का अध्ययन करना था।

आसियान रक्षा मंत्री बैठक (एडीएमएम)- प्लस

14.45 रक्षा और सुरक्षा मुद्दों से संबंधित सहयोग पर रक्षा मंत्री स्तर पर वार्ता करने हेतु एडीएमएम- प्लस रक्षा मंत्रियों की बैठक एक महत्वपूर्ण प्लेटफार्म बनकर उभरी है, जिसका उद्देश्य क्षमता निर्माण और सहयोग को बढ़ाने के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान देना है। एडीएमएम-प्लस को एडीएमएम-प्लस वरिष्ठ अधिकारी बैठक (एडीएसओएम) द्वारा तथा व्यावहारिक सहयोग के क्षेत्रों में 7 विशेषज्ञ कार्य समूहों, अर्थात् समुद्री सुरक्षा, काउंटर टैरोरिज्म, मानवीय सहायता एवं आपदा प्रबंधन, शांति-स्थापन कार्य, सैन्य चिकित्सा, मानवीय माइन ऐक्शन और साइबर सुरक्षा द्वारा सहायता दी जाती है। भारत ने ईडब्ल्यूजी की बैठकों में तथा विभिन्न एडीएमएम-प्लस व्यावहारिक पहलों में सक्रिय रूप से प्रतिभागिता की। रक्षा मंत्री ने क्लार्क, पैम्पेनगा, फिलीपींस में 23-25 अक्टूबर 2017 के दौरान एडीएमएम-प्लस की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। इस कार्यक्रम के अवसर पर रक्षा मंत्री ने यूएसए, आस्ट्रेलिया, रूस सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।



समारोह और अन्य कार्यक्रम





समारोह और अन्य कार्यकलाप

15.1 रक्षा मंत्रालय स्वायत्त संस्थाओं को नियमित रूप से आर्थिक सहायता देकर अकादमी तथा साहसिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन देता है। ये संस्थाएं हैं:

- (i) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली
- (ii) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (एनआईएम), उत्तरकाशी
- (iii) हिमालयी पर्वतारोहण संस्थान (एचएमआई), दार्जिलिंग
- (iv) जवाहर पर्वतारोहण एवं शीत क्रीड़ा संस्थान (जेआईएम एवं डब्ल्यूएस), पहलगांव।
- (v) राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं संबद्ध क्रीडा संस्थान (एनआईएमएस), दिरांग।

15.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन संस्थानों के महत्वपूर्ण कार्यकलाप उत्तरोत्तर पैराग्राफों में दिए जा रहे हैं।

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए)

15.3 नवंबर, 1965 में स्थापित रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-III, 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) समय-समय पर यथासंशोधित, के तहत एक पंजीकृत संस्था है। यह संस्थान एक स्वायत्तशासी निकाय है जो रक्षा और सुरक्षा के सभी पहलुओं पर उद्देश्यपरक अनुसंधान तथा नीति संबंधित अध्ययनों के प्रति समर्पित है।

15.4 आईडीएसए का वित्तपोषण पूर्ण रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है और संस्थान स्वायत्तता के साथ कार्य करता है। आईडीएसए के विद्वान अकादमियों, रक्षा सेनाओं और सिविल सेवाओं से लिए जाते हैं। आईडीएस के पास 50 विद्वानों का एक अनुसंधान संकाय है जिसमें 8 सेवारत अधिकारी हैं और जो अध्ययन अवकाश पर हैं। आईडीएस की संगठनात्मक

अनुसंधान संरचना को 13 केंद्रों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आईडीएसए भारत सरकार के सिविल, सैन्य बल और अर्द्ध सैनिक बल के अधिकारियों को वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। संस्थान अपने 'अभ्यागत अध्येयतावृत्ति कार्यक्रम' और 'शिक्षुतावृत्ति कार्यक्रम' के तहत विदेशों के क्रमशः अभ्यागत अध्येयताओं और शिक्षुओं की मेजबानी भी करता है।

15.5 संस्थान प्रत्येक वर्ष अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर नियमित रूप से गोलमेज चर्चाओं और कार्यशालाओं का आयोजन करता है। साप्ताहिक अध्येता सेमिनार भी एक मंच के रूप में कार्य करता है जिसमें आईडीएसए के विशेषज्ञ विभिन्न विश्लेषणकर्ताओं, विद्वानों, पत्रकारों और नीति-निर्माताओं के साथ बात करते हैं। इसके अलावा, न्यूज मीडिया भी आम विज्ञापनों, साक्षात्कारों तथा वाद-विवाद में प्रतिभागिता के रूप में आईडीएसए के विशेषज्ञों के विचारों का प्रसार करता है।

15.6 आईडीएसए के विद्वानों के लिए पड़ोसी देशों में नए घटनाक्रम एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र होता है। उप-महाद्वीप

में भारत की बढ़ती भागीदारी के साथ-साथ द्विपक्षीय एवं अन्य वार्ताओं के माध्यम से आईडीएसए की कूटनीतिक समुदाय के साथ वार्ता में भी समरूप वृद्धि हुई है। संस्थान नई चुनौतियों के घटित होने तथा भारत की प्रतिक्रिया पर निरंतर सकेंद्रित रहता है।

15.7 आईडीएसए नीति संबद्ध अध्ययन भी करता है। संस्थान ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य सरकारी विभागों की ओर से अनेक अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ की हैं। संस्थान फील्ड दौरों, पुस्तकालय, वेबसाइट सहित आईटी और संरचना, घटनाक्रमों की रिकॉर्डिंग आदि जैसे क्षेत्रों के अनुसंधान कार्यक्रमों में निरंतर निवेश करता आ रहा है। आईडीएसए की वेबसाइट (www.idsa.in) भी शोधकर्ताओं, छात्रों और संगत नागरिकों के लिए विभिन्न सुरक्षा और रक्षा संबंधी मुद्दों पर एक मूल्यवान सूचना स्रोत उभरकर आई है।

15.8 **अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन:** आईडीएसए द्वारा पूरे वर्ष के दौरान अनेक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन निम्नानुसार हैं:



“पावर ट्रेडिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा” पर आठवां वार्षिक वाईबी चौहान स्मृति व्याख्यान

- **28–29 मार्च, 2017:** “दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी का सुदृढीकरण” शीर्षक पर 10वें दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन आईडीएसए में किया गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार

ने एक शीर्ष संबोधन दिया।

- **15–18 सितंबर, 2017:** आईडीएसए द्वारा “बदलता एशिया 2017: क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग पर परिप्रेक्ष्य” शीर्षक पर आईडीएसए-जीआईजीए (जर्मन वैश्विक

और क्षेत्र अध्ययन संस्थान) द्विपक्षीय सम्मेलन की दूसरी श्रृंखला का आयोजन किया गया।

- **22 सितंबर, 2017:** आईडीएसए ने बिमस्टेक ट्रैक 1.5 सुरक्षा संवाद मंच की पहली बैठक का आयोजन किया गया।
- **7-8 नवंबर, 2017:** आईडीएसए ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से "समुद्री संरक्षा और सुरक्षा" पर दूसरे भारतीय महासागर रिम संघ (आईओआरए) सम्मेलन का आयोजन किया। विदेश सचिव ने एक शीर्ष संबोधन दिया।

15.9 **गोलमेज वार्ताएं:** संस्थान ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित विभिन्न गोल मेज वार्ताओं का आयोजन किया:

- **7 अप्रैल, 2017:** "आतंकवाद और पाकिस्तान-अफगानिस्तान संबंध" पर भारत में अफगानिस्तान के पूर्व राजदूत के साथ एक गोलमेज वार्ता।
- **11 अप्रैल, 2017:** "भारत-वियतनाम संबंध, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, रक्षा और आर्थिक मुद्दे तथा चीन-आसियान संबंध" पर वियतनाम के प्रतिनिधिमंडलों के साथ एक गहन वार्ता।
- **अप्रैल, 2017:** यूएस पारस्परिक शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान अधिनियम (एमईसीईए) के फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत की यात्रा करने वाले यूएस कांग्रेस, कांग्रेस के स्टाफ सदस्यों और फेडरल अधिकारियों के साथ एक गहन वार्ता। इस अवसर पर यूएस-अमेरिका आर्थिक संबंधों से लेकर रक्षा संबंधों तक अनेक विषयों पर वार्ता की गई।
- **20 अप्रैल, 2017:** "कोरिया प्रायद्वीप में घटनाक्रम, भारत-कोरिया संबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधित मुद्दे" पर विदेश मंत्रालय, कोरिया गणतंत्र के नीति नियोजन के महानिदेशक के साथ एक गहन वार्ता।
- **26 अप्रैल, 2017:** "उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र में कट्टरपंथी हिंसा में बढ़ोतरी" पर अंतरराष्ट्रीय सामरिक, सुरक्षा और सैन्य बल अध्ययन केंद्र, टयूनिशिया के राष्ट्रपति के साथ एक गोलमेज वार्ता।

- **8 मई, 2017:** पश्चिमी एशिया में सऊदी अरब की सैन्य बल चिंताओं पर चर्चा करने हेतु कर्नल की अगुवाई में सऊदी अरब कमांड एवं स्टाफ कॉलेज के एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ गहन वार्ता।
- **17 मई, 2017:** अफ्रीकी एकता संगठन के स्थापना दिवस को मनाने के लिए रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान ने अफ्रीकी अध्ययन सहयोग संघ के सहयोग से "अफ्रीका की सुरक्षा की चुनौतियां" पर एक गोल मेज वार्ता आयोजित की।
- **18 मई, 2017:** "प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा" पर भारत में श्रीलंका के पूर्व राजदूत और एडमिरल, पाथ फाइंडर फाउंडेशन, श्रीलंका के साथ एक गोलमेज वार्ता।
- **20 जून, 2017:** "दक्षिण चीन समुद्र और भारत-प्रशांत क्षेत्र ऑर्डर" पर आस्ट्रेलियाई रक्षा बल अकादमी के साथ एक गहन वार्ता।
- **3 जुलाई, 2017:** भारत-इजराइल के बीच 25 वर्षों के राजनयिक संबंधों को मनाने हेतु भारत और आईडीएसए ने सामरिक विश्लेषण "भारत-इजराइल के 25 वर्षों के संबंध" विशेष अंक पर एक गोलमेज वार्ता।
- **10 जुलाई, 2017:** "आतंकवाद से निपटने में न्यायिक विज्ञान और नई प्रौद्योगिकी भूमिका" पर न्यायिक विज्ञान, बर्लिन अर्थशास्त्र और विधि शास्त्र एवं स्कूल के समन्वयक और अपराध शास्त्र के प्राध्यापक के साथ एक गोलमेज वार्ता।
- **21 जुलाई, 2017:** "वर्तमान डोकलाम सीमा तनाव" पर भूटान के पूर्व राजदूत के साथ एक वार्ता।
- **28 जुलाई, 2017:** "भारत-ईरान संबंध" पर भारत में ईरान इस्लामिक गणतंत्र के राजदूत के साथ एक गोलमेज वार्ता।
- **20 सितंबर, 2017:** "भारत-कुवैत संबंध और कतार पर कुवैत के मध्यस्ता प्रयास" पर ले. जनरल, चीफ और जनरल स्टाफ, कुवैत की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ गोलमेज वार्ता।

- **10 नवंबर, 2017:** “बदलते कूटनीतिक संदर्भ में भारत-यूएस संबंध” पर हडसन संस्थान में वरिष्ठ अध्येता के साथ एक गोलमेज वार्ता।
- **13 नवंबर, 2017:** भारतीय महासागर रिम संघ (आईओआरए) सदस्य राष्ट्रों के 16 सदस्यीय पत्रकार प्रतिनिधिमंडल के साथ सदस्य देशों के आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक गोलमेज वार्ता।
- **18 दिसंबर, 2017:** यूएस कांग्रेस के सदस्यों और हैडरल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक गोलमेज वार्ता। चर्चा के मुख्य विषय यूएस-भारत आर्थिक एवं रक्षा संबंध थे।

15.10 **चर्चाएं/द्विपक्षीय वार्ताएं:** संस्थान द्वारा आयोजित चर्चाएं/द्विपक्षीय वार्ताएं निम्नवत हैं:

- **3 अप्रैल, 2017:** “व्यापार और सुरक्षा पर चीन-भारत द्विपक्षीय संबंध; क्षेत्रीय सुरक्षा; बहु आयामी सहयोग” पर शंघाई अंतरराष्ट्रीय संस्थान (एसआईआईएस) के साथ एक द्विपक्षीय वार्ता।
- **17 अप्रैल, 2017:** ले. जनरल (सेवानिवृत्त) ने “भारत-चीन सीमा का प्रबंधन – लद्दाख की एक केश स्टडी” पर एक वार्ता प्रस्तुत की।
- **20 अप्रैल, 2017:** ऊर्जा और सुरक्षा अध्ययन केंद्र (सीईएनईएसएस), मोस्को के प्रमुख ने “निःशस्त्रीकरण और परमाणु-प्रसार-निरोध पर वैश्विक एजेंडा” पर एक वार्ता प्रस्तुत की।
- **20 अप्रैल, 2017:** आईडीएसए में अभ्यागत अध्येता ने “थाइलैंड – सरकार विरोधी प्रतिवादियों के लिए पुलिस व्यवस्था” पर एक वार्ता प्रस्तुत की।
- **22 मई, 2017:** महानिदेशक, इरिट्रेयन सामरिक अध्ययन केंद्र ने “अफ्रीका क्षेत्र में क्षेत्रीय परिदृश्य” पर एक वार्ता प्रस्तुत की।
- **24 मई, 2017:** आईडीएसए ने “साइबर स्पेस की भौगोलिक राजनीति: भारत के लिए स्थान सृजित

करना” पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का उद्देश्य साइबर विवाद और अंतरराष्ट्रीय विधि, विशेष रूप से टालिन मैनुवल 2.0 के संदर्भ में तथा बहुमुखी सहयोग के लिए भारत की भूमिका को समझना था।

- **2 जून, 2017:** राष्ट्रीय रक्षा अध्ययन संस्थान (एनआईडीएस), जापान के साथ एक द्विपक्षीय चर्चा की गई, जहां भारत और जापान से संबंधित अनेक सुरक्षा मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की गई।
- **19 जून, 2017:** चीफ ऑफ स्टाफ कैमेट्री के एकीकृत सेवा स्टाफ प्रमुख (सीआईएससी) ने “भारतीय संदर्भ में एकीकृत युद्ध करने के लिए उपयुक्त संरचनाओं की स्थापना” पर एक वार्ता प्रस्तुत की। थल सेना स्टाफ के पूर्व उप-सेनाध्यक्ष ने वार्ता की अध्यक्षता की।
- **12 जुलाई, 2017:** अंतरराष्ट्रीय अध्ययन, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डी.सी में एक प्रोफेसर ने “काले झंडे फहराना और भारत के लिए खतरा” पर एक वार्ता प्रस्तुत की।
- **7 अगस्त, 2017:** नेपाल के बीड में स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन परामर्श एवं वित्तीय सलाहकार के फाउंडर एवं सीईओ ने “भारत-नेपाल आर्थिक आदान-प्रदान में सुधार लाने हेतु भारत द्वारा उठाए जा सकने वाले कदम” पर एक वार्ता प्रस्तुत की।
- **22 नवंबर, 2017:** “भारत-आस्ट्रेलिया संबंध, कूटनीतिक चुनौतियां और संभावनाएं” पर भारत-आस्ट्रेलिया ट्रैक 1.5 रक्षा कूटनीतिक संवाद का चौथा दौर।

15.11 प्रशिक्षण कार्यक्रम: संस्थान द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया:

- **24-28 अप्रैल, 2017:** आईडीएसए ने नौसेना आसूचना पाठ्यक्रम के लिए सामरिक अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया।
- **3-7 जुलाई, 2017:** आईडीएसए द्वारा सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक के लिए सामरिक अभिविन्यास मॉड्यूल का आयोजन।

- **11–22 सितंबर, 2017:** आईडीएसए द्वारा सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ कमांडेंटों के लिए सामरिक अभिविन्यास मॉड्यूल का आयोजन।

15.12 **आईडीएसए प्रकाशन:** वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों में शामिल हैं :

- **अरब स्प्रिंग एंड सेक्टेरियन फॉल्टीनेस इन वेस्ट एशिया:** बहरीन, यमन एवं सीरिया, प्रशांत कुमार प्रधान, पैटागन प्रेस।
- **दि जियोपॉलीटिक्स ऑफ गैस:** कॉमन प्रोबलम्स, डिस्प्रेट स्ट्रेटीजीज, शिबोती राय डडवाल, पैटागन प्रेस।
- **दि अर्थशास्त्रा इन ए ट्रांसकल्चरल पर्सपेक्टिव:** कम्पेयरिंग कोटल्या विद सन्-टजू, निजाम अल-मुल्क, बारानी एंड मचियावेल्ली, माइकल लीबिग, सौरभ मिश्रा (संपादक), पैटागन प्रेस।
- **फिफ्टी ईयर्स ऑफ दि आउटर स्पेस ट्रीटी:** ट्रेसिंग दि जर्नी, अजय लेले (संपादक), पैटागन प्रेस।
- **इंडिया-चाइना रिलेशंस:** पॉलीटिक्स आफ रिसॉसिज, आइडेंटिटी एंड आर्थोरिटी एन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जगन्नाथ पी. पांडया, रूटलेज।

पर्वतारोहण संस्थान

15.13 रक्षा मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर चार पर्वतारोहण संस्थानों, अर्थात् पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित हिमालय पर्वतारोहण संस्थान (एचएमआई); उत्तराखंड में उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (एनआईएम); जम्मू-कश्मीर में पहलगाम स्थित जवाहर पर्वतारोहण और शीत क्रीड़ा संस्थान (जेआईएम एंड डब्ल्यूएस) तथा अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में स्थित राष्ट्रीय पर्वतारोहण तथा संबद्ध क्रीड़ा संस्थान (एनआईएमएस) को संचालित करता है। ये संस्थान पंजीकृत समितियों के रूप में चलाए जाते हैं और उन्हें स्वायत्तशासी निकायों का दर्जा प्रदान किया गया है। रक्षा मंत्री इन संस्थानों के अध्यक्ष होते हैं और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री इन संस्थानों के उपाध्यक्ष होते हैं। ये संस्थान अलग-अलग कार्यकारिणी परिषदों द्वारा

अभिशासित होते हैं जिनमें प्रत्येक संस्थान की आम सभा द्वारा चुने गए सदस्य, दानदाताओं के नामती और/अथवा पर्वतारोहण के उद्देश्य को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति तथा केंद्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

15.14 ये संस्थान पर्वतारोहण को एक खेल के रूप में प्रोत्साहन देते हैं, पर्वतारोहण को बढ़ावा देते हैं और युवाओं में साहसिक भावना उत्पन्न करते हैं। पर्वतारोहण संस्थानों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- (क) पर्वतारोहण तथा चट्टानों पर चढ़ने की तकनीकों के विषय में सैद्धांतिक ज्ञान तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण देना;
- (ख) युवाओं में पर्वतों तथा अन्वेषण के प्रति रुचि एवं प्रेम उत्पन्न करना;
- (ग) शीत-क्रीड़ाओं के प्रति उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उन्हें प्रशिक्षण देना; और
- (घ) हिमालयी क्षेत्र की प्रकृति पर कार्यशालाओं के जरिए पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के संरक्षण की समझ सृजित करना।

15.15 ये पर्वतारोहण संस्थान आधारभूत और उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम, अनुदेश विधि (एमओआई) पाठ्यक्रम, खोज व बचाव (एस एवं आर) पाठ्यक्रम और साहसिक क्रियाकलापों पर पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। इन पाठ्यक्रमों में भारत के सभी भागों से प्रशिक्षुओं के साथ-साथ थल सेना, वायुसेना, नौसेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्मिक भी प्रशिक्षण लेते हैं। विदेशी नागरिकों को भी इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति है। इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए पाठ्यक्रम, अवधि, ग्रेडिंग, प्रतिभागी की आयु सीमा और अन्य ब्यौरा उपर्युक्त पर्वतारोहण संस्थानों की वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया गया है।

15.16 संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रम सभी संस्थानों में लगभग एक समान हैं। संस्थानों द्वारा अप्रैल, 2017 से दिसंबर, 2017 तक आयोजित नियमित पाठ्यक्रमों और इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या **सारणी सं. 15.1** में दी गई है।

सारणी सं. 15.1

संस्थान	आधारभूत पाठ्यक्रम		उन्नत पाठ्यक्रम		साहसिक पाठ्यक्रम		एमओआई पाठ्यक्रम		खोज एवं बचाव पाठ्यक्रम		विशेष पाठ्यक्रम	
	पाठ्यक्रमों की सं.	प्रशिक्षुओं की सं.	पाठ्यक्रमों की सं.	प्रशिक्षुओं की सं.	पाठ्यक्रमों की सं.	प्रशिक्षुओं की सं.	पाठ्यक्रमों की सं.	प्रशिक्षुओं की सं.	पाठ्यक्रमों की सं.	प्रशिक्षुओं की सं.	पाठ्यक्रमों की सं.	प्रशिक्षुओं की सं.
एचएमआई	06	312	03	149	01	42	07	213
एनआईएम	05	370	03	88	05	262	01	29	01	42	09	363
जेआईएम	06	432	01	62	04	89	01	20
एनआईएमएएस	04	122	02	36	02	266	.	.	01	35	10	116

15.17 जीआईएम ने 75 वायु सेना कार्मिकों के लिए अगस्त-सितंबर 2017 में कारगिल से पहले माउंट टोलोलिंग (द्रास) (6153 मीटर) में तीन अभियान आयोजित किए। जेआईएम के 15 अनुदेशकों ने इन अभियानों में प्रतिभागिता की। एनआईएमएएस ने भी 2 अभियानों का आयोजन किया, अर्थात् पहला माउंट गोरीचेन (6488 मीटर) में मई 2017 में 24 व्यक्तियों के लिए एक मिश्रित (महिला एवं पुरुष) अभियान, जिसमें से 17 व्यक्तियों ने पर्वत के शिखर तक चढ़ाई की और दूसरा अभियान अक्टूबर 2017 में माउंट त्रिशुल (7120 मी.) में 20 व्यक्तियों के लिए आयोजित किया जिसमें 10 व्यक्तियों ने पर्वत शिखर तक चढ़ाई की।

समारोह, सम्मान व पुरस्कार

15.18 गणतंत्र दिवस परेड, समापन समारोह, शहीद दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोहों के आयोजन की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की है। वीरता तथा विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोहों का आयोजन भी रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति सचिवालय के साथ मिलकर किया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित समारोहों का ब्यौरा आगामी पैराग्राफों में दिया गया है।

15.19 **स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह:** स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारंभ, लाल किले पर स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में सामूहिक देशभक्ति गान के साथ हुआ। तीनों सेनाओं तथा दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री को गारद सम्मान दिया। तत्पश्चात, सेनाओं के बैंड द्वारा बजाए गए राष्ट्रीय गान संगीत के साथ प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर इक्कीस तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को संबोधित

किए जाने के बाद समारोह का समापन विद्यालयों से आए बच्चों और एनसीसी कैडेटों द्वारा राष्ट्रीय गान तथा गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। उसके उपरांत दिन के दौरान, राष्ट्रपति ने उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर फूल-माला चढ़ाई जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे।

15.20 स्वतंत्रता दिवस-2017 के अवसर पर वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिनका ब्यौरा सारणी संख्या 15.2 में दिया गया है।

सारणी संख्या 15.2

पुरस्कार	पुरस्कारों की सं.	मरणोपरांत
कीर्ति चक्र	05	03
शौर्य चक्र	17	06
सेना मेडल (जी)	85	10
नौसेना मेडल (जी)	03	—
वायु सेना मेडल (जी)	02	—

15.21 **विजय दिवस:** 16 दिसंबर, 2017 को विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर फूलमाला चढ़ाई।

15.22 **अमर जवान ज्योति समारोह, 2018:** प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी, 2018 को प्रातःकाल इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्पामाला चढ़ाई। उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया जिन्होंने देश की अखंडता की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए थे।

15.23 **गणतंत्र दिवस परेड, 2018:** राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही गणतंत्र दिवस परेड का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने सेनाओं के बैडों द्वारा बजाए गए राष्ट्र गान और 21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रीय सलामी दी। इस अवसर पर 10 आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष/सरकारें मुख्य अतिथि थे।

15.24 इसके अलावा, तीनों सेनाओं के मेकेनाइज्ड दस्तें, मार्चिंग दस्ते और बैंड, डीआरडीओ का दस्ता, अर्द्ध-सैनिक बलों, दिल्ली पुलिस, एनसीसी, एनएसएस इत्यादि के मार्चिंग दस्ते और बैंड परेड का हिस्सा थे।

15.25 जिन अठारह बच्चों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया, उनमें से तीन को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्रदान किया

गया। पन्द्रह वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों ने सेना की सुसज्जित जीपों पर सवार होकर परेड में भाग लिया। राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की झांकियां एवं विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन परेड के अन्य आकर्षण थे। 23 झांकियों तथा स्कूली बच्चों के 5 कार्यक्रमों ने देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत किया। बीएसएफ के महिला दस्ते द्वारा साइकिल पर प्रदर्शन करने और तत्पश्चात भारतीय वायुसेना के विमानों के प्रभावशाली फ्लाई पास्ट के साथ परेड का समापन हुआ।

15.26 गणतंत्र दिवस, 2018 के अवसर पर घोषित वीरता तथा विशिष्ट सेवा पुरस्कारों का ब्यौरा **सारणी संख्या 15.3** में दिया गया है।

सारणी संख्या 15.3

पुरस्कार का नाम	कुल	मरणोपरांत
वीरता पुरस्कार		
अशोक चक्र	01	01
कीर्ति चक्र	01	.
शौर्य चक्र	14	02
सेना मेडल/नौसेना मेडल/वायु सेना मेडल बार (वीरता)	02	.
सेना मेडल/नौसेना मेडल/वायुसेना मेडल बार (वीरता)	90	07
विशिष्ट पुरस्कार		
परम विशिष्ट सेवा मेडल	28	.
उत्तम युद्ध सेवा मेडल	04	.
अति विशिष्ट सेवा मेडल बार	02	.
अति विशिष्ट सेवा मेडल	49	.
विध सेवा मेडल	10	.
सेना मेडल/नौसेना मेडल/वायु सेना मेडल बार (कर्त्तव्यपरायणता)	02	.
सेना मेडल/नौसेना मेडल/वायु सेना मेडल बार (कर्त्तव्यपरायणता)	65	.
विशिष्ट सेवा मेडल बार	01	.
विशिष्ट सेवा मेडल	121	.

15.27 **समापन समारोह, 2018:** समापन समारोह सदियों पुरानी उन दिनों की सैन्य परंपरा है, जब सूर्यास्त होने पर सेना युद्ध बंद कर देती थी। समापन समारोह गणतंत्र दिवस समारोहों में भाग लेने के लिए दिल्ली में एकत्र हुई सैन्य टुकड़ियों के प्रत्यागमन का सूचक है। यह समारोह 29 जनवरी, 2018 को विजय चौक पर आयोजित किया गया जो गणतंत्र दिवस उत्सवों का पटाक्षेप था। इस समारोह में तीनों सेनाओं के बैडों के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और राज्य पुलिस बैडों ने भाग लिया। समारोह के समापन के अवसर पर राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन और इंडिया गेट को बिजली की रोशनी से जगमगाया गया। गणतंत्र दिवस और समापन समारोह, 2018 के दौरान, एक नई पहल के रूप में आमंत्रित महानुभावों द्वारा अपनी कार की रिमोट कंट्रोल चाबी जमा करने के लिए बूथ स्थापित किए गए।

15.28 **शहीद दिवस समारोह 2018:** 30 जनवरी, 2018 को, राष्ट्रपति ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर फूलमाला चढ़ाई। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद 1100 बजे उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे।

15.29 **वीरता पुरस्कार पर ऑनलाइन पोर्टल:** स्वतंत्रता के उपरांत वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैनिकों के लिए समर्पित एक ऑनलाइन पोर्टल, अर्थात् <https://gallantryawards.gov.in> की शुरुआत मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त, 2017 को गई। पोर्टल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को वीरता पुरस्कारों – परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र के बारे में सुग्राह्य करना तथा एक ही स्थान पर सूचना उपलब्ध कराना है।

राजभाषा प्रभाग

15.30 संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु रक्षा मंत्रालय में राजभाषा प्रभाग कार्य कर रहा है। यह प्रभाग राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों तथा इस संबंध में नोडल विभाग अर्थात् राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के संबंध में रक्षा मंत्रालय (सचिवालय), तीनों सेना मुख्यालयों, सभी अंतर-सेवा संगठनों

तथा रक्षा विभाग के उपक्रमों एवं मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। मंत्रालय ने रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 2 अलग-अलग हिंदी सलाहकार समितियां गठित की हैं, एक रक्षा विभाग, भूतपूर्व सैन्य कल्याण विभाग और अनुसंधान एवं विकास विभाग के लिए तथा दूसरी रक्षा उत्पादन विभाग के लिए। इन समितियों का गठन किए जाने का उद्देश्य आधिकारिक प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों पर मंत्रालय के संबंधित विभागों को सलाह देना है। राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित कार्य में, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु प्रत्येक वर्ष जारी किए गए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्रदान करना तथा स्टाफ को बिना झिझक हिंदी में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल है। मॉनीटरिंग कार्य में मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों, रक्षा मंत्रालय के उपक्रमों और प्रभागों/ अनुभागों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण करना, मंत्रालय की दोनों राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकें आयोजित करना, नई दिल्ली स्थित तीनों सेना मुख्यालयों तथा अंतर-सेवा संगठनों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लेना और सुधारात्मक उपाय करने के लिए उपर्युक्त कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करना शामिल है।

15.31 **वार्षिक कार्यक्रम:** राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम को, उसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी रक्षा संगठनों को परिचालित किया गया। हिंदी में मूल पत्राचार बढ़ाने, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजातों को द्विभाषी रूप में जारी करने, हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित करने तथा हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकों में इस संबंध में हुई प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

15.32 **अनुवाद कार्य:** वर्ष के दौरान मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों तथा अनुभागों से काफी मात्रा में प्राप्त सामग्री का अनुवाद कार्य पूरा किया गया जिसमें संसद सदस्यों/ विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्र, रक्षा मंत्री/रक्षा राज्य मंत्री के कार्यालयों से

जारी होने वाले पत्र, मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्ताव, लेखा परीक्षा पैरा, रक्षा संबंधी स्थायी समिति तथा परामर्शदात्री समिति के समक्ष रखे जाने वाले दस्तावेज तथा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय प्रश्न, करार आदि शामिल थे।

15.33 **हिंदी सलाहकार समितियों की बैठक:** रक्षा विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के लिए पुनःगठित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 27 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस समिति का कार्यवृत्त परिचालित किया गया और बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश दिए गए।

15.34 **रक्षा संबंधी विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन हेतु प्रोत्साहन योजनाएं और इन-हाउस जर्नलों के लिए पुरस्कार योजना:** ब्लाक वर्ष 2011-13 की योजना के अंतर्गत श्री हरिशरण और श्री हर्ष कुमार सिन्हा द्वारा लिखित पुस्तक "हिंद महासागर : चुनौतियां एवं विकल्प" के लिए 50,000 रूपयों (रूपए पचास हजार) का प्रथम पुरस्कार तथा कैप्टन राजपल द्वारा लिखित पुस्तक "द्वितीय विश्वयुद्ध" के लिए 30,000/- रूपयों (रूपए तीस हजार) का द्वितीय पुरस्कार दिया गया।

15.35 **राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत रक्षा कार्यालयों को अधिसूचित किया जाना:** 16 रक्षा कार्यालयों, जिनके 80 प्रतिशत या इससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो गया है, के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गईं। नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित कार्यालयों को कर्मचारियों को अपना समस्त सरकारी कार्य हिंदी में निपटाने हेतु नियम 8 (4) के अंतर्गत विभागों/प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को विनिर्दिष्ट करने हेतु निदेशित किया गया। इस संबंध में मुख्यालय स्तर पर गहन समीक्षा करने तथा नियम के तहत पात्र कार्यालय को अधिसूचित करने हेतु कार्रवाई करने के लिए तीनों सेनाओं के मुख्यालयों आदि को अनुदेश जारी किए गए।

15.36 **हिंदी पखवाड़ा:** अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मंत्रालय में 14 से 28 सितंबर, 2017 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि तथा निबंध सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। 200 से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने उपरोक्त प्रतियोगिताओं में भाग लिया और 120 सफल प्रतिभागी अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार/उपहार प्रदान किए गए।

15.37 **संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण:** गत वर्षों की भंति, संसदीय राजभाषा समिति ने इस वर्ष भी देश के विभिन्न भागों में स्थित कई रक्षा संगठनों का निरीक्षण दौरा किया। मंत्रालय ने निरीक्षण प्रश्नावलियों की समीक्षा कर तथा अपेक्षित संशोधनों का सुझाव देकर निरीक्षणाधीन कार्यालयों का मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों द्वारा दिए गए आश्वासनों को समिति के निदेशों और अपेक्षाओं के अनुरूप पूरा किया जा रहा है।

15.38 **संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढीकरण:** "राजभाषा अधिनियम 1963" और "राजभाषा (संघ के कार्यालय प्रयोजनार्थ प्रयोग के लिए) नियम 1976" के अंतर्गत निर्दिष्ट उद्देश्यों को हासिल करने हेतु मंत्रालय में एक गहन समीक्षा की गई और राजभाषा संबंधी कार्य को निपटाने के लिए वर्तमान संस्थागत व्यवस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु तीनों सेना मुख्यालयों सहित रक्षा विभाग में सभी एककों को अनेक निदेश जारी किए गए।

निःशक्त व्यक्तियों का कल्याण

15.39 रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग) तथा रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'क', 'ख', और 'ग' में निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः सारणी संख्या 15.4 और 15.5 में दिया गया है।

सारणी संख्या 15.4
सेवाओं में निःशक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण
(1 जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार)

दृष्टि बाधित (वीएच)/श्रवण बाधित (एचएच)/शारीरिक विकलांग (ओएच) का प्रतिनिधित्व (1.1.2017 की स्थिति के अनुसार)					कैलेंडर वर्ष 2016 में की गई नियुक्तियों की सं.											
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा			
समूह	कुल कर्मी	वी एच	एच एच	ओ एच	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच
क	4430	1	0	27	138	1	0	9	199	0	0	0	21	0	0	0
ख	27899	38	39	227	198	0	0	2	2119	1	2	5	3	0	0	0
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	206310	360	529	1233	7041	27	47	89	3332	4	10	22	83	0	0	0
ग (सफाई कर्मचारी)	7784	52	87	124	243	1	8	3	201	0	0	0	0	0	0	0
कुल	246423	451	655	1611	7620	29	55	103	5851	5	12	27	107	0	0	0

सारणी संख्या 15.5
रक्षा उत्पादन विभाग के संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सेवाओं में निःशक्त व्यक्तियों
के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण
(1 जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार)

दृष्टि बाधित (वीएच)/श्रवण बाधित (एचएच)/शारीरिक विकलांग (ओएच) का प्रतिनिधित्व (1.1.2017 की स्थिति के अनुसार)					कैलेंडर वर्ष 2016 में की गई नियुक्तियों की सं.											
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा			
समूह	कुल कर्मी	वी एच	एच एच	ओ एच	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
क	2579	01	02	14	16	--	--	--	18	--	--	--	--	--	--	--
ख	30357	20	37	261	22	04	02	07	66	--	--	02	--	--	--	--
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	62634	145	239	1297	100	26	24	44	42	07	05	20	--	--	--	--
ग (सफाई कर्मचारी)	114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
कुल	95684	166	278	1572	138	30	26	51	126	7	5	22	0	0	0	0

15.40 **रक्षा उत्पादन विभाग:** रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में निःशक्त व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ उपलब्ध कराने के लिए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा जो

रियायतें और छूट निर्धारित की गई हैं, उनके अलावा भी बहुत-सी रियायतें एवं छूट निःशक्त व्यक्तियों को प्रदान की जाती हैं।

15.41 **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन:** रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के संबंध में

सरकार की नीतियों एवं अनुदेशों को लागू करने में वचनबद्ध है। सरकार के अनुदेशों के अनुसार भर्ती एवं पदोन्नति में 3 प्रतिशत आरक्षण निःशक्त व्यक्तियों को प्रदान किया जा रहा है।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

15.42 **निःशक्त सैनिकों के लिए विशेष चिकित्सा सेवा:** युद्ध के दौरान या दुर्घटनाओं एवं अन्य कारणों से कुछ सैनिक निःशक्त हो जाते हैं और उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। इन भूतपूर्व सैनिकों को स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष चिकित्सा परिचर्या और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे कार्मिकों की

परिचर्या एवं पुनर्वास मोहाली और किर्की स्थित विशेष संस्थाओं अर्थात् पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्रों में किया जाता है जिनका वित्त-पोषण केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि से किया जाता है।

15.43 **कृत्रिम अंग केंद्र:** निःशक्त ईएसएम को नवीनतम कृत्रिम अंग उपचार मुहैया कराने हेतु भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पैनालबद्धता के लिए 40 शहरों में एंडोलाइट और ओटोबोक कंपनियों के 53 कृत्रिम अंग केंद्रों को अनुमोदित किया गया है।



सतर्कता यूनिटों के कार्यक्रमलाप





सतर्कता यूनिटों के कार्यकलाप

16.1 रक्षा मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग को रक्षा मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन विभिन्न यूनिटों के कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरणों, कदाचार और अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतें निपटाने का कार्य सौंपा गया है। यह रक्षा मंत्रालय की ओर से सतर्कता संबंधी मामलों और शिकायतों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) इत्यादि के साथ मध्यस्थता के लिए नोडल प्वाइंट के रूप में कार्य करता है। सतर्कता प्रभाग भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से, अन्य बातों के साथ-साथ, उपाय सुझाता है और कार्यविधियों की समीक्षा करता है।

16.2 प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, रक्षा विभाग का सतर्कता विंग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का सतर्कता कार्य भी देखता है। रक्षा उत्पादन विभाग में अलग सतर्कता विंग मौजूद है।

16.3 केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार, रक्षा मंत्रालय

के अधीन सभी विभागों/संगठनों/यूनिटों, अर्थात् थल सेना नौसेना, वायुसेना, डीआरडीओ, डीजीबीआर ई-इन-सी ब्रांच, डीजीडीई, सीएओ एवं डीजीएएफएमएस आदि में "मेरा विजन – भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय पर 31 अक्तूबर से 4 नवंबर, 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया और विभाग के कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यकलापों का आयोजन किया, जैसे कि कार्यशालाएं, पैम्फलेट वितरण, बैनर/ पोस्टरों का प्रदर्शन, वाद-विवाद, व्याख्यान, निबंध तथा पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आदि।

रक्षा विभाग

16.4 भ्रष्ट आचरणों के विरुद्ध सभी स्टेकहोल्डरों में जागरूकता लाने के लिए रक्षा मंत्रालय में पारदर्शिता, निष्पक्ष व्यवहार, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

16.5 मुख्य सतर्कता अधिकारी, सतर्कता कार्य से संबंधित

विभिन्न रिपोर्टों/मामलों/अन्य कार्यों को समय पर पूरा करने के प्रयोजन से सभी संबंधित कार्यालयों के संपर्क में रहते हैं।

16.6 मंत्रालय संबंधित स्कंधों/प्रभागों में लंबित मामलों सहित विभिन्न चरणों में लंबित सतर्कता मामलों पर कड़ी निगरानी रखता है, ताकि इन मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जा सके। लंबित मामलों की स्थिति की मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा उपयुक्त अंतराल पर मॉनीटरिंग की जाती है। लंबित मामलों की स्थिति की मॉनीटरिंग करने हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा रक्षा मंत्रालय, डीआरडीओ आदि के तहत विभिन्न संगठनों के सतर्कता अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं।

16.7 वर्ष के दौरान कुल 14 शिकायतें (4 सीवीसी से + 10 अन्य से) और दो मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) पैरा प्राप्त किए गए जिन पर कार्रवाई की गई। इस अवधि में सीवीसी/सीवीओ के परामर्श से 42 शिकायतों को बंद किया गया। 26 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए मंजूरी संप्रेषित की गई और सीवीसी अधिकार क्षेत्र के तहत 27 अनुशासनिक मामलों को अंतिम रूप दिया गया। वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए उपर्युक्त 27 मामलों में से, 10 मामलों में 'बड़ी शास्ति'; 4 मामलों में 'लघु शास्ति' लगाई गई और शेष 13 मामलों में आरोपित अधिकारियों को आरोप मुक्त किया गया।

रक्षा उत्पादन विभाग

16.8 **माझगांव डाक लिमिटेड (एमडीएल):** सतर्कता विभाग द्वारा 2017 के दौरान 4 सीटीई प्रकार की जांचें की गईं जिनके कारण समग्र व्यवस्था में सुधार आया। 10 सरजमी जांचें/निरीक्षण किए गए।

16.9 एमडीएल के कर्मियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। सतर्कता इन-हाऊस जर्नल 'सुचरिता' वॉल्यूम XX का प्रकाशन किया गया। 3 कॉलेजों तथा दो स्कूलों में निबंध/वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। ग्राम पारनर, जिला बीड (महाराष्ट्र) में ग्राम सभा आयोजित की गई। एमडीएल के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने हेतु एक विख्यात वार्ताकार को आमंत्रित किया गया। सीवीओ ने एमडीएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक पारस्परिक वार्ता की। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर वेंडर बैठक भी आयोजित की गई।

16.10 6 सुग्राहीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

जिनमें 115 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

16.11 चक्रिक स्थानांतरण नीति का कार्यान्वयन किया गया और संवेदनशील पदों पर कार्यरत 21 वरिष्ठ अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया।

16.12 **भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बीईएमएल:** सतर्कता नियमावली के दूसरे संस्करण के प्रयोक्ता-हितैषी अद्यतित वर्जन का अगस्त 2017 में प्रकाशन किया गया।

16.13 सतर्कता के एक उपाय के रूप में, एक करोड़ रूपयों से अधिक की सभी निविदाएं सत्यनिष्ठा पैक्ट के अंतर्गत रखी गई हैं। वर्ष 2017 के दौरान 417 औचक जांचें, 569 आवधिक जांचें, 633 क्रय आदेश जांचें, 829 प्रतिपूर्ति दावे, 332 वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) जांचें और 6 सीटीई प्रकार की जांचें की गईं।

16.14 संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और बीईएमएल के समस्त परिसरों के प्रमुख स्थलों पर सतर्कता बोर्ड प्रदर्शित किए गए।

16.15 बीईएमएल में नवनि्युक्त प्रशिक्षणार्थियों के लिए सतर्कता जागरूकता पर 3 प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

16.16 मूल्यांकन प्रक्रिया के पश्चात संवेदनशील क्षेत्रों की सूची की समीक्षा की गई और नए क्षेत्रों को संवेदनशील के रूप में अधिसूचित किया गया।

16.17 सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यकलाप चलाए गए, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

(i) स्कूलों और कॉलेजों, जहां बीईएमएल ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2017 को मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए थे, में विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को नागरिक सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई।

(ii) एक वेंडर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीईएमएल की बिजनेस क्षमताओं को साझा करने तथा उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए पूरे देश के वेंडरों को आमंत्रित किया गया।

16.18 **भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल):** निर्माण-कार्य नियामवली और आईएनएम नियमावली को आधुनिक समय की आवश्यकताओं तथा डीपीपी/(जीएफआर)-2005 के

अनुरूप संशोधित किया गया।

16.19 कंप्यूटर आधारित फाइल ट्रेकिंग प्रणाली (एफटीएस) का कार्यान्वयन किया गया।

16.20 सिविल निर्माण कार्य-वेंडर बैठक का आयोजन 24 जून 2017 को बीडीएल, हैदराबाद में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के माध्यम से किया गया।

16.21 पूंजीगत/राजस्व मदों, आदि के प्रापण/क्रय जैसे विभिन्न मुद्दों पर प्रबंधन को सतर्कता रिपोर्टों के साथ-साथ क्रमिक सुधार से अवगत कराया गया।

16.22 “मेरा विजन – भ्रष्टाचार मुक्त भारत” के केंद्रीय शीर्षक के साथ 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

- (i) विभिन्न शहरों में स्थित बीडीएल के अनेक कार्यालयों में कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई।
- (ii) ग्राम भानुर की ग्राम पंचायत कार्यालय में एक ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें सरपंच, वार्ड सदस्यों, एमपीटीसी सदस्य और ग्रामीणों ने प्रतिभागिता की और सीवीओ/बीडीएल के साथ पारस्परिक बातचीत की।
- (iii) “भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाया जाए” पर निबंध लेखन प्रतियोगिता और “भ्रष्टाचार का उन्मूलन” पर स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई जिनमें बीडीएल के कर्मियों, विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों ने प्रतिभागिता की।

16.23 **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल):** वेबसाइट, ई-टैंडरिंग, ऑनलाइन वेंडर पंजीकरण के प्रभावकारी उपयोग के जरिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सीवीसी दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया गया और ई-टैंडरिंग के लिए निर्धारित मूल्य-सीमा को 5 लाख रूपयों से कम कर 2 लाख रूपये किया गया।

16.24 हाल ही में भर्ती किए गए अधिकारियों, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थियों इत्यादि के लिए सतर्कता जागरूकता विषयों पर अभिविन्यास, व्याख्यान तथा प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

16.25 “मेरा विजन – भ्रष्टाचार मुक्त भारत” शीर्षक के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और कॉलेज एवं स्कूल छात्रों के लिए आउटरीच कार्यक्रमों जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए गए। भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं पर डीजीपी, गोवा के साथ एक “वार्ता” और उसके बाद एक ‘पारस्परिक वार्ता सत्र’ आयोजित किया गया।

16.26 निरोधक सतर्कता के रूप में, शिकायतें प्राप्त करने हेतु सीवीओ की आईडी और संपर्क दूरभाष सं. के विवरणों के साथ चयन प्रक्रिया वाले स्थलों पर नोटिस प्रदर्शित किए जाते हैं और ऐसे स्थलों पर सीसीटीवी कवरेज दी जाती है जहां भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। बोर्ड स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में, सतर्कता स्थिति को सरकार के निदेशों के अनुरूप सॉल्व सॉफ्टवेयर पर अद्यतित किया जाता है। जीएसएल में श्रमिक आपूर्ति की सभी निविदाओं में इलेक्ट्रॉनिक हाजरी प्रणाली को अनिवार्य बनाया गया है।

16.27 **हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल):** सतर्कता जांच/निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में पाई गई विसंगतियों को प्रबंधन के ध्यानाकर्षण में लाया गया और कार्यविधि को सुकर बनाने हेतु नए दिशानिर्देश जारी किए गए:

- (i) संविदा श्रमिकों का अनुबंधन
- (ii) जांच अधिकारियों की नियुक्ति
- (iii) मशीनरियों के संस्थापन और प्रवर्तन में विलंब
- (iv) निविदा का मूल्यांकन (बोलियां खोले जाने के बाद विनिर्देशनों में परिवर्तन)

16.28 विभिन्न कार्यक्रमों का अध्ययन किया गया तथा अध्ययन के दौरान पाई गई विसंगतियों को निम्नलिखित क्षेत्रों, जैसे की (i) मांगपत्र भेजे जाने और क्रय आदेश (पीओ) जारी किए जाने के बीच की अवधि में विलंब, (ii) कंपनी के विधिक मामले, (iii) वेंडर मास्टर सूची (आउटसोर्सिंग) और (iv) चिकित्सा प्रणाली आदि में अपेक्षित मध्यस्ता के लिए प्रबंधन के ध्यानाकर्षण में लाया गया।

16.29 छात्रों में सतर्कता जागरूकता सृजित करने हेतु 25 कॉलेजों में अनेक कार्यक्रम चलाए गए। एचएएल के 90 प्रतिशत कर्मियों, 400 एचएएल ग्राहकों और 7270 जन सदस्यों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली। सार्वजनिक प्रापण, निविदा प्रक्रिया, क्रय

कार्यविधि और जीएसटी इत्यादि में पारदर्शिता लाने हेतु सप्ताह के दौरान सत्र/कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

16.30 वेंडरों की शिकायतों को निपटाने हेतु पारस्परिक संवाद सत्र आयोजित किए गए।

16.31 भ्रष्टाचार संवेदनशील क्षेत्रों में 566 नेमी/औचक जांचें की गईं। इनमें से 18 मामलों पर गहन जांच की गई।

16.32 **मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि):** मिधानि में 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2017 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसमें मुख्य विषय सीवीसी शीर्षक "मेरा विजन – भ्रष्टाचार मुक्त भारत" था। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त उच्च न्यायाधीश मुख्य अतिथि थे। आउटरीच कार्यक्रमों के अनुक्रम में, विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

16.33 निधानी के कर्मियों और हितधारकों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली और कंपनी के सभी मोबाइलों में आधिकारिक रिंग बैग धुन के माध्यम से तथा कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से सत्यनिष्ठा शपथ को बढ़ावा देने के लिए संदेश को व्यापक रूप से परिचालित किया गया।

16.34 वर्तमान वर्ष के शीर्षक से संबद्ध आलेखों को शामिल करते हुए इन-हाउस सतर्कता पत्रिका 'जागृति' के पांचवे अंक का प्रकाशन और परिचालन किया गया।

16.35 'सतर्कता प्रबंधन में सुधार' शीर्षक पर मिधानि में 6 अक्टूबर 2017 को एक कार्यशाला एवं पारस्परिक संवाद सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीवीसी द्वारा अद्यतित क्रय नीति एवं कार्यविधि नियमावली, 2017 को विमोचित किया गया।

16.36 निरोधक सतर्कता के भाग के रूप में, इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप भी चलाए गए:

- (i) वर्ष के दौरान 4 सीटीई प्रकार की जांचें की गईं और एडवाइजरी का सुझाव दिया गया।
- (ii) उच्च मूल्य से संबंधित प्रापण फाइलों और कम प्रत्युत्तर वाली फाइलों की जांच की गई।
- (iii) नियमित निरीक्षण और औचक जांचें की गईं।

(iv) 50 लाख से अधिक की सभी निविदाएं सत्यनिष्ठा पैक्ट के अधीन लाई गईं।

16.37 सतर्कता की सलाह के आधार पर, धरोहर राशि जमा और प्रतिभूति जमा लेन-देनों से संबंधित प्राप्ति और प्रतिदेय के लिए 'ऑनलाइन भुगतान' गेटवे को कार्यान्वित किया गया।

16.38 **भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीईएल):** बीईएल की सभी यूनिटों में एसएपी प्लेटफार्म पर फाइल लाइफ साइकिल प्रबंधन का कार्यान्वयन किया गया। पूरे देश में इसका औसत कार्यान्वयन 90.31 प्रतिशत है।

16.39 'भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थागत विधि' की प्रबंधन श्रेणी के तहत बीईएल ने 30 अक्टूबर 2017 को 'सीडीसी सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार' प्राप्त किया।

16.40 बीईएल की सभी 9 यूनिटों में इस वर्ष के दौरान 1378 नियमित निरीक्षण और 762 औचक निरीक्षण किए गए, 1187 क्रय आदेशों/संविदाओं की समीक्षा की गई तथा 66 संविदाओं के संबंध में सीटीई प्रकार की गहन जांच शुरू की गई।

16.41 बीईएल, बंगलुरु में 25 जुलाई 2017 को 'नैतिकता, नैतिक विधियों एवं कार्यविधियों तथा प्रतिनिष्ठा पैक्ट की प्रभावकारिता' पर एक बैठक आयोजित की गई। बंगलुरु स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों एवं पीएसबी के आईईएम, सीवीओ तथा सतर्कता वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभागिता की।

16.42 बीएल द्वारा 20-21 जुलाई 2017 के दौरान 'अनुशासनिक कार्यवाही और आरोप-पत्र तैयार करना' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। सीवीसी के सचिव ने कार्यशाला का उद्घाटन किया जिसमें 29 संगठनों से 66 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की। इसी प्रकार से बीईएल, बंगलुरु में 21-22 सितंबर, 2017 के दौरान एक 2-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीईएल ने आईसीएडीआर के संयोजन में बंगलुरु में 8 दिसंबर 2017 को वैकल्पिक विवाद निवारण पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया।

16.43 बीईएल के कॉरपोरेट कार्यालय और 9 यूनिटों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

16.44 **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई):** निरोधक सतर्कता उपाय के रूप में, जीआरएसई

में नियमित एवं औचक निरीक्षण किए गए तथा फाइलों का सत्यापन किया गया। अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक संपदा विवरणियों की जांच की गई। विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की सतर्कता स्थिति का मूल्यांकन किया गया।

16.45 संवेदनशील पदों की पहचान कर चरणबद्ध प्रक्रिया में अधिकारियों के चक्रिक स्थानांतरण के लिए कार्यवाही शुरू की गई।

16.46 जीआरएसई ने संगठन के भीतर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया और सामान्य नागरिकों/ जनता दोनों के लिए आउटरीच कार्यक्रम चलाया गया। संगठन के भीतर किए गए कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न यूनिटों में बैनर प्रदर्शित करना एवं भ्रष्टाचार निरोधी शीर्षकों को प्रदर्शित करना, कर्मियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाना, निरोधक सतर्कता कार्यक्रमों पर पैम्फलेट वितरण करना, संगठन की नितियों/कार्यविधियों पर कर्मियों एवं अन्य हितधारकों के लिए कार्यशाला तथा सुग्राहीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना जैसे विषय शामिल थे।

16.47 ई-सत्यनिष्ठा शपथ लेने के लिए सीवीसी की वेबसाइट पर लॉग-इन करने के अनुरोध तथा भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नागरिकों/ सामान्य जनता से प्रतिभागिता करने हेतु एक संदेश के साथ जीआरएसई के मुख्य स्थलों पर बैनर प्रदर्शित किए गए। प्रतियोगिता और नागरिक सत्यनिष्ठा तथा भ्रष्टाचार के प्रतिकूल प्रभावों के संदेश को सभी स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचाया गया। सीवीसी की वेबसाइट में ई-शपथ लेकर भ्रष्टाचार से निपटने में प्रतिभागिता करने हेतु वेंडरों को असंख्य ई-मेल संदेश भेजे गए।

16.48 **हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल):** एचएसएल में 4 प्रकार की सीटीपी जांचें की गईं और सतर्कता टिप्पणियों तथा सुधार के लिए सुझाव देते हुए रिपोर्टें तैयार कर सीएमडी को अग्रपिछित की गईं।

16.49 ईएमडी, निविदा शुल्क और वेंडर पंजीकरण के लिए ऑनलाइन भुगतान गेटवे का उद्घाटन किया गया और उसे 15 नवंबर 2017 से चालू किया गया।

16.50 सतर्कता विभाग द्वारा जनरल स्टोर्स, बॉड स्टोर्स, डिस्पोजल यार्ड, क्रय विभाग में सत्यनिष्ठा पैकट, ईएमडी का आवधिक निरीक्षण, वाणिज्यिक विभाग एवं यार्ड डिस्पेंसरी में वेंडर विकास में 12 औचक जांचें की गईं।

16.51 जागरूकता सप्ताह के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए:

- (i) "मेरा विजन – भ्रष्टाचार मुक्त भारत" शीर्षक पर कर्मियों के लिए निबंध लेखन, स्लोगन लेखन और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। "मेरा विजन – भ्रष्टाचार मुक्त भारत" शीर्षक पर स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए चित्रकारिता एवं वाग्मिता प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- (ii) डब्ल्यूआईएसटीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, पीनागढ़ी में एक सतर्कता कार्यशाला आयोजित की गई। छात्रों और संकाय सदस्यों को 'ऑनलाइन सत्यनिष्ठा शपथ' दिलाई गई।
- (iii) वाणिज्यिक विभाग में एक वेंडर बैठक की गई और वेंडरों द्वारा सामूहिक रूप से सत्यनिष्ठा शपथ ली गई।
- (iv) विशाखापटनम के सभी पीएसयू, अर्थात् एचएसएल, डीसीआई, एचपीसीएल, आरआईएनएल द्वारा विशाखापटनम बीच रोड पर वाल्खाथोन का आयोजन किया गया। बीच पर मानव सतर्कता आंख स्थापित की गई और सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई।
- (v) "मेरा विजन – भ्रष्टाचार मुक्त भारत" शीर्षक पर 2 नवंबर 2017 को एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

16.52 कारखानों से विभिन्न डाटा संग्रहण करने के लिए 8 टैम्पलेट अभिकल्पित कर कारखानों के पीपीसी पैकेजों में सृजित किए गए। टैम्पलेट विश्लेषण विभिन्न बिंदुओं, उदाहरण के तौर पर जहां विचलन पाए गए हैं और जहां जांच की आवश्यकता है; सतर्कता कार्यक्रमों/ प्रक्रिया को सुकर बनाने हेतु और अधिक सतर्कता उपाय करने; भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों; जोखिम प्रबंधन कार्यनीति के रूप में चिंताग्रस्त क्षेत्र; वेंडरों की लाम्बदता जैसे अन्य चिंताग्रस्त क्षेत्र, एक ही वेंडर को बार-बार क्रय आदेश जारी किया जाना इत्यादि पर एक्शन रिपोर्ट सृजित करेगा।

16.53 वर्ष के दौरान सीटीई प्रकार के 8 निरीक्षण किए गए, आरोप-सिद्ध अधिकारियों और संदेहहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची बनाई गई।

16.54 विभिन्न कारखानों में 42 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

किए गए। ओएफबी में भर्ती कार्यविधि, क्षमता सत्यापन, प्रापण इत्यादि के संबंध में विभिन्न केस स्टडीज पर सतर्कता कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनकी अध्यक्षता सीवीओ/ओएफबी द्वारा की गई।

16.55 रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई: रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा आयुध निर्माणी बोर्ड के विभिन्न कार्यकलापों में पारदर्शिता का स्तर बढ़ाने के लिए कार्रवाई योग्य बिंदुओं की पहचान की गई तथा उन्हें रक्षा मंत्रालय के सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं आयुध निर्माणी बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजा गया, जिनमें आंतरिक संगठन लेखा परीक्षा, 90 प्रतिशत संविदाओं को सत्यनिष्ठा पैक्ट के अधीन लाना, शनैःशनैः वेंडर विकास के माध्यम से सीमित एकल टेंडर के हिस्से को कम करना, 90 प्रतिशत प्रापण ई-प्रापण (मूल्य द्वारा) के माध्यम से करना, डीपीएसयू में प्रापण प्रक्रिया को सुकर बनाना तथा सभी निर्माण कार्यों एवं प्रापण नियमावलियों का अद्यतन करने जैसे कार्य शामिल हैं।

16.56 सभी डीपीएसयू/ओएफबी के सीवीओ और डीडीपी के सीवीओ के बीच 19 जुलाई 2017 को एक सुविचारित बैठक आयोजित की गई। बैठक में सतर्कता मामलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और डीपीएसयू एवं ओएफबी के सभी सीवीओ को एक समय-सीमा के भीतर वर्ष 2017 की लेखा परीक्षा कराए जाने और सीवीओ द्वारा संबंधित डीपीएसयू/ओएफबी में लेखापरीक्षा कराए जाने के लिए समय-सारणी निर्धारित करने

की सलाह दी गई।

16.57 उपसचिव (सतर्कता), डीडीपी ने ओएफबी के ऐसे अधिकारियों के साथ पारस्परिक सत्रों का आयोजन किया, जो 3 भिन्न स्थानों, कोलकाता, कानपुर और देहरादून में जेडब्ल्यूएम एवं प्रभारी पदों पर कार्यरत हैं ताकि उन्हें सतर्कता पहलु और प्रापण, क्रय तथा श्रम संविदा इत्यादि के संबंध में अपने कतव्यों का निर्वहन करने में नियमों/दिशानिर्देशों की अनुप्रयोज्यता की महत्ता से अवगत कराया जा सके। कुल मिलाकर, लगभग 109 अधिकारियों ने इन पारस्परिक सत्रों में प्रतिभागिता की।

16.58 वर्ष 2017 के दौरान डीडीपी/सतर्कता ने ओएफडी/डीजीक्यूए के समूह 'क' अधिकारियों के संबंध में तथा दंडात्मक सतर्कता के अंतर्गत डीपीएसयू के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई की है:

क्र. सं.	की गई कार्रवाई	आरोप-सिद्ध अधिकारियों की सं.
1.	बड़ी शास्ति अधिरोपित किए गए मामले	8
2.	बड़ी शास्ति आरोप-पत्र जारी किए गए मामले	8
3.	लघु शास्ति आरोप-पत्र जारी किए गए मामले	1





महिलाओं का सशक्तिकरण और कल्याण





महिलाओं का सशक्तिकरण और कल्याण

17.1 राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में निरंतर वृद्धि हो रही है। महिलाएँ रक्षा उत्पादन इकाइयों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और सैन्य बलों में कार्यरत हैं। उड़ान, संभार तंत्र एवं विधि विज्ञान जैसे सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं में महिलाओं के प्रवेश के साथ, उनके लिए अधिक बड़ी भूमिका पर विचार किया गया है।

भारतीय सेना

17.2 **सेना में महिला अधिकार:** महिला अधिकारीगण सशस्त्र बलों में लगभग 80 वर्षों से अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही हैं और उन्होंने प्रतिस्पर्धा और विशिष्टता के साथ अपनी सेवाएँ दी हैं। उनको 1927 में सैन्य परिचर्या सेवा और 1943 में चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में नियुक्त किया गया। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में, वे स्थायी और अल्प सेवा कमीशन अधिकारी (एसएससीओ) के रूप में तैनात थीं।

17.3 एक महत्वपूर्ण कदम के अंतर्गत, अल्प सेवा कमीशन में

महिला अधिकारियों के कार्यकाल को 10 वर्षों से 14 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है जिससे अधिक महिलाएँ सेना में भर्ती के लिए आकृष्ट होंगी। इसके अतिरिक्त, उनका पदोन्नति की संभावनाओं को पर्याप्त सीमा तक बढ़ाया गया है। पूर्व में, वे केवल एक पदोन्नति के लिए योग्य थीं, जैसे— 5 वर्षों की सेवा के पश्चात मेजर का रैंक। उनको अब क्रमशः 2, 6 और 13 वर्षों की उल्लेखनीय सेवा के पश्चात कप्तान, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक तक समय आधारित पर्याप्त पदोन्नति प्रदान की जाती है। यह स्थायी कमीशन अधिकारियों को उपलब्ध पदोन्नति के समकक्ष होती है। इसके अतिरिक्त, लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से सेना के अल्प सेवा कमीशन में महिला अधिकारियों के प्रशिक्षण को पुरुष अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों के समकक्ष रखने के लिए 24 सप्ताह से 49 सप्ताह तक बढ़ाया गया है।

17.4 राष्ट्र की सुरक्षा में सैन्य बलों की भूमिका और उत्तरदायित्व को दृष्टिगत रखते हुए और देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते हुए, सैन्य बलों में महिलाओं के प्रवेश और सेवायोजन पर भविष्य की नीति

को नवम्बर 2011 में निरूपित किया गया, जो निम्नानुसार है:

- (i) महिलाओं को अधिकारी शाखाओं/संवर्गों में अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों (एसएससीओ) के रूप में नियुक्त करना जारी रखा जा सकता है जहाँ पर वर्तमान में उनको तीनों सेवाओं में प्रवेश दिया जा रहा है;
- (ii) महिलाएं एसएससीओ तीनों सेवाओं की विशिष्ट शाखाओं में, उदाहरणस्वरूप – थलसेना के जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स (ईसी) और नौसेना एवं वायुसेना के अपने समकक्ष विभागों; नौसेना में नवल कंस्ट्रक्टर और वायु सेना में लेखा विभाग में पुरुष एसएससीओ के साथ, स्थायी कमीशन प्रदान करने हेतु विचार किये जाने की पात्र होंगी।
- (iii) उपरोक्त के अतिरिक्त, वायु सेना में, महिलाएं एसएससीओ अपने पुरुष एसएससीओ के साथ तकनीकी, प्रशासनिक, संभार-तंत्र और मौसम विज्ञान विभागों में स्थायी कमीशन प्रदान करने हेतु विचार किये जाने के योग्य होंगी।

17.5 स्थायी कमीशन प्रदान करना अभ्यर्थी की स्वेच्छा, रक्तियों की उपलब्धता, अनुकूलता, अभ्यर्थी की योग्यता पर निर्भर करेगा जैसा कि प्रत्येक सेवा द्वारा निर्णित किया जायेगा।

भारतीय नौसेना

17.6 भारतीय नौसेना (आईएन) महिलाओं के कल्याण, कुशलक्षेम और प्रतिष्ठा के प्रति समर्पित है। सभी परिस्थितियों में उच्च मनोबल और प्रेरणा को बनाये रखने के लिए, महिला कर्मचारियों एवं महिला सदस्यों को अधिकतम सहयोग प्रदान करने हेतु, भारतीय नौसेना का यह एक निरंतर प्रयास है। आईएन ने सम्बंधित इकाईयों की गतिविधियों/कार्यों में उनके सक्रिय प्रतिभागिता को सुनिश्चित करने हेतु महिला कर्मचारियों को सशक्त करने के लिए सम्मिलित प्रयास किया है। महिला कर्मचारियों के लिए महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षित कार्य के वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपायों को क्रियान्वित किया गया है:

- (क) कार्यस्थलों में महिलाओं की स्वतंत्रता और पुरुषों के

साथ समान दर्जा प्रदान करते हुए सकारात्मक वातावरण का निर्माण जो महिलाओं के पूरे सामर्थ्य को समझते हुए उनके विकास को सक्षम बनाता है।

- (ख) सभी स्तरों पर इकाई/प्रतिष्ठान के नीति-निर्धारण या गतिविधियों में महिला कर्मचारियों की समान प्रतिभागिता/जुड़ाव।
- (ग) पुरुषों के साथ समान अधिकारों एवं कार्यस्थलों पर अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों को सुग्राही बनाना।
- (घ) कार्यस्थलों पर, महिला कर्मचारियों के प्रति हिंसा/उत्पीड़न के सभी तरीकों का परित्याग करना, चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक।

17.7 **महिला अधिकारी:** महिलाओं को नौसेना में अधिशासी (पर्यवेक्षक, एटीसी, विधि एवं संभार-तंत्र), शिक्षा विभाग और अभियांत्रिकी शाखा के नौसेना वास्तुशिल्प में अल्प सेवा कमीशन (एसएससी) के रूप में भर्ती कराया जा रहा है। मार्च 2016 में, शांतिकाल सैनिक सर्वेक्षण (एमआर) शाखा और नौसेना आयुध निरीक्षणालय (एनएआई) संवर्ग में पायलटों के रूप में महिला अल्प सेवा कमीशन (एसएससी) अधिकारियों की भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन पर सहमति बनी थी। वर्ष 2017 में, एक महिला अधिकारी को एनएआई में एमआर एयरक्राफ्ट पायलट और चार महिला अधिकारियों की नियुक्त की गयी है।

17.8 **एसएससी अधिकारियों को स्थायी कमीशन:** सरकार ने वर्ष 2008 से पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए अधिशासी विभाग (विधि संवर्ग), शिक्षा विभाग और अभियांत्रिकी विभाग (नौसेना वास्तुशिल्प) के अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों को भावी रूप से स्थायी कमीशन प्रदान करना आरंभ किया है।

17.9 **विशाखा और निर्मया अधिनियम:** “विशाखा दिशानिर्देश” और “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013” को एकीकृत मुख्यालय (आईएचक्यू), एमओडी (नौसेना), सभी कमांडों एवं दूरस्थ इकाईयों में लागू किया गया है। कार्यस्थलों में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के पूछताछ के लिए समितियों का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों

में महिला कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार के उत्पीड़न/हिंसा को रोकना और उसे दूर करना है। उपयुक्त महिला अधिकारियों को सभी इकाईयों की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है।

17.10 नौसैनिक पत्नी कल्याण संघ (एनडब्ल्यूडब्ल्यूए): महिलाओं में आत्मविश्वास के निर्माण को प्रोत्साहित करने और नौसेना की महिलाओं के मनोबल में वृद्धि करने हेतु, नौसैनिक अधिकारियों की पत्नियों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर बड़ी संख्या में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। नौसैनिक पत्नी कल्याण संघ (एनडब्ल्यूडब्ल्यूए) अपने असंख्य कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से वास्तविक कल्याण और शैक्षिक गतिविधियों को हाथ में लेने का एक अवसर प्रदान करता है। ऐसे गतिविधियों के उदाहरणों में सम्मिलित है, बच्चों के लिए प्ले स्कूलों का संचालन, समुदाय के बाहर लोगों तक पहुँच बनाना, विशेष बच्चों के लिए स्कूलों का संचालन, वरिष्ठ नागरिकों और दीर्घकालिक रोगों वाले रोगियों की देखभाल, नौसैनिकों के विधवाओं का पुनर्वास, व्यवसायिक परामर्श और मार्गदर्शन के माध्यम से पारिवारिक असामंजस्यता के समाधान में सहायता, अन्य कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन। एनडब्ल्यूडब्ल्यूए नौसैनिक परिवारों को सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के क्षेत्र में उनकी योग्यता को वाणीयुक्त एवं वाद्य संगीत, नृत्य, नाटिका, स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों, योग और संगठित खेलों एवं क्रीड़ाओं के माध्यम से विकसित एवं प्रदर्शित करने के लिए भी अवसर प्रदान करता है।

17.11 नाविका सागर परिक्रमा: यह एक अभियान है जिसमें भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों का एक दल भारत में निर्मित एक 56 फुट लम्बी पाल नौका; आईएनएसवी तारिणी पर चढ़कर भूमंडल की परिधि का चक्कर लगा रही हैं। सभी महिला नाविकगणों द्वारा भूमंडल की परिधि का यह प्रथम भारतीय नौवहन संचालन है। इस अभियान का प्रारंभ रक्षा मंत्री द्वारा 10 सितम्बर, 2017 को गोवा से झंडा फहराकर किया गया। फ्रेमेंटल (ऑस्ट्रेलिया), लिट्टेलटन (न्यूजीलैण्ड), पोर्ट स्टैनले (फ़ॉकलैंड्स) और केपटाउन (दक्षिण अफ्रीका) के बंदरगाहों में ठहरने के पश्चात, इस नौका का अप्रैल 2018 में गोवा वापस लौटकर आना अपेक्षित है।



प्रधानमंत्री के साथ बातचीत

कल्याणकारी गतिविधियाँ

17.12 जीवनसाथी के एक ही स्थान पर तैनाती की संशोधित नीति: सेवा की विवशता के सन्दर्भ में जहाँ तक संभव हो, सशस्त्र सेना में कार्यरत पति-पत्नियों को एक ही स्थान पर तैनात किये जाने का प्रयास होता रहा है। स्पष्ट साधनों और पति-पत्नी के एक ही स्थान पर तैनाती की स्थितियों को रेखांकित करने के लिए, जो व्यक्ति विशेष की आकाँक्षाओं को संगठनात्मक लक्ष्यों के रूप में भी पूरा करता है, पति-पत्नी के एक ही कार्यस्थल पर तैनाती की नीति को संशोधित किया गया है और इसके प्रावधानों को भारतीय थलसेना, भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएवंटी) के दिशानिर्देशों के साथ पंक्तिबद्ध किया गया है।

17.13 नवल रेजिमेंटल सिस्टम (एनआरएस): रक्षा सेवाओं में व्याप्त पारम्परिक सौहार्द और बंधुत्व को ध्यान में रखते हुए, मृत नाविकों के विधवाओं/निकटतम परिजन (एनओके) की समर्थन प्रणाली को संस्थागत करने और उनको अतिसक्रिय और विस्तृत सहयोग प्रदान करने के लिए जनवरी 2011 को नवल रेजिमेंटल सिस्टम (एनआरएस) की स्थापना की गयी। इस प्रणाली के अंतर्गत, सात कमांड रेजिमेंटल सिस्टम ऑफिसर्स (सीआरएसओ) और उनका दल नौसैनिक साथियों की मृत्यु के पश्चात, प्रत्येक परिवार तक पहुँचता है, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि क्या वह व्यक्ति सेवा योग्य था या सेवानिवृत्त था और यह सुनिश्चित करता है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और सभी अधिकृत बकायों की जमापूँजी उन तक समय पर

पहुँच जाये। रेजिमेंटल स्टेट यूनिट्स (आरएसयू) जिनके अपने पदचिन्ह धरातल पर हैं, विधवाओं तक पहुँचते हैं और सम्बंधित कल्याणकारी विषयों, जैसे कि पारिवारिक पेंशन, पहचान-पत्र, कैंटीन कार्ड्स, एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ईसीएचएस) की सदस्यता आदि पर उनको शिक्षित करते हैं।

17.14 **विधवाओं और सेवानिवृत्त समुदाय तक पहुँच बनाना:** अपने स्वास्थ्य में रुकावट पैदा करने वाले सभी मुद्दों से निपटने के लिए निम्नलिखित की व्यवस्था की गई है:

- (क) 'डायरेक्टरेट ऑफ एक्स-सर्विसमैन अफेयर्स टोल फ्री हेल्प लाइन' जो अपने इंटीग्रेटेड वॉयस रिकॉर्डिंग (आईवीआर) सुविधा के माध्यम से दिन-रात लगातार सेवा उपलब्ध करता है।
- (ख) पेंशन संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए 'कमोडोर ब्यूरो ऑफ सेलर्स (सीएबीएस) टोल फ्री हेल्प लाइन'।
- (ग) आईआरएफसी वेबसाइट के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों का विस्तार।
- (घ) त्रैमासिक ई-सूचनापत्र का प्रकाशन जिसमें सेवानिवृत्त सैनिकों से सम्बंधित नवीनतम नीतियाँ/विकास सम्बन्धी विषय सम्मिलित है।
- (ङ) ई-मेलों के माध्यम से पूर्व-सैनिक मामलों के निदेशालय के साथ बातचीत।

17.15 **दिल्ली में विधवाओं के लिए हॉस्टल:** नौसेना द्वारा अपने कर्मचारियों के विधवाओं के लिए एक हॉस्टल के निर्माण हेतु, डीडीए से 2050.39 वर्ग मी. नाप वाले एक भूखंड का अधिग्रहण किया गया था। एमसीडी से "भवन अनुमति-पत्र" सहित, सम्बंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया। छात्रावास का निर्माण प्रगति पर है। इसमें पार्किंग सहित, सभी जनसुविधाओं के साथ 34 आवासीय इकाईयाँ होंगी।

17.16 **स्वस्थ महिला क्लिनिक (वेल वूमैन क्लिनिक):** वरुणिका ऑडिटोरियम (प्रेक्षाग्रह), चाणक्यबाग, चाणक्यपुरी में 20 से 22 फरवरी, 2017 के बीच एनडब्ल्यूडब्ल्यूए के आरोग्य शाखा के तत्वाधान में स्वस्थ महिला क्लिनिक का संचालन किया गया। यह

कार्यक्रम सकारात्मक महिला स्वास्थ्य की योग्यताओं पर नौसेना कर्मचारियों की पत्नियों को संवेदनशील बनाने और सर्वोच्च स्वास्थ्य एवं सुख को प्रोत्साहित करने पर लक्षित था।

भारतीय वायु सेना

17.17 आईएएफ महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने में सबसे आगे रहा है और यह तटस्थ लैंगिक नीतियों का अनुरक्षण करता है। वर्तमान में, आईएएफ के सभी शाखाओं एवं श्रेणियों के द्वार महिलाओं को अधिकारियों के रूप में प्रवेश देने के लिए खुले हुए हैं।

17.18 **लड़ाकू वर्ग में महिला पायलटों का प्रवेश:** भारतीय वायुसेना में महिलाओं का प्रवेश 1992 में आरंभ हुआ। आरंभ में, महिलाओं की नियुक्ति कुछ शाखाओं और वर्गों में अल्प सेवा कमीशन (एसएससी) अधिकारियों के रूप में की गयी। तत्पश्चात, उनके लिए अधिक शाखाओं और वर्गों को खोला गया। आईएएफ में पिछले डेढ़ दशकों के दौरान महिला अधिकारियों को सौंपी गयी भूमिकाओं और कार्यों का भी उत्तरोत्तर विस्तार हुआ।

17.19 **उड़ान शाखा में महिला पायलटों का प्रवेश:** आईएएफ के उड़ान शाखा में महिलाओं का प्रवेश वर्ष 1994 में प्रारंभ हुआ। फिर भी, उनको केवल परिवहन और हेलिकॉप्टर शाखाओं में नियुक्त किया गया। आईएएफ के लड़ाकू शाखा में महिलाओं की नियुक्ति का अनुमोदन 2015 में किया गया, एक ऐसा कदम जिसको सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता के प्रति एक सकारात्मक कदम के रूप में मुख्य रूप से देखा जाता है। 18 जून, 2016 को, तीन उड़ान प्रशिक्षार्थियों-अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह लड़ाकू शाखा में कमीशन प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पायलट बनीं। इन महिला पायलटों को, जो अब उड़ान अधिकारी हैं, लड़ाकू उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न करने पर बाइसन और हॉक इकाईयों में स्क्वार्डन पायलटों के रूप में तैनात किया गया। तीन महिला प्रशिक्षार्थियों के दूसरे बैच का चयन जून 2017 में लड़ाकू शाखा के लिए किया गया। ये अधिकारीगण वायुसेना स्टेशन, हाकिमपेट में प्रशिक्षण ले रहे हैं और प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के पश्चात इनको लड़ाकू शाखा में नियुक्त किया जायेगा।



कॉकपिट में आईएएफ महिला पायलट

भारतीय तटरक्षक बल

17.20 भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) महिला अधिकारियों को 1997 से ही सामान्य ड्यूटी में स्थायी नियुक्ति पाने वाले सहायक कमांडेंट और 1998 से एविएशन कैंडर (पायलट) के रूप में प्रवेश दे रहा है। वर्तमान में, 133 महिला अधिकारी सेवा में सक्रिय भूमिकाओं में है जिसमें अधिकारियों को साधारण ड्यूटी और विमानन संवर्ग में शॉर्ट सर्विस अपॉइंटी (एसएसए) के रूप में सम्मिलित किया जाता है। आईसीजी में महिला अधिकारियों की शक्ति सम्पूर्ण श्रमशक्ति का लगभग 10 प्रतिशत है।

17.21 इस सेवा ने महिला अधिकारियों के सशक्तिकरण और कल्याण के प्रति अतिसक्रिय कदम उठाया है। उनके अनुभव, योग्यता और समर्पण को उन क्षेत्रों में प्रभावशाली रूप में प्रयोग किया गया है जहाँ पर उनकी योग्यता का उपयोग पायलटों, प्रेक्षकों और विमानन जैसे सहायता सेवाओं के लिए पूरी तरह से किया जाता है। उनको तटीय सुरक्षा तंत्र में समान रूप से उत्तरदायी कार्य में भी नियुक्त किया जाता है। महिला अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों के साथ समान रूप से दूरस्थ स्थित स्टेशनों में भी तैनात किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञता प्राप्त महिला अधिकारियों को तटरक्षक बल के भंडारगृहों में कमांड नियुक्तियों का प्रस्ताव दिया जा रहा है। इन सभी उपायों ने कैरियर की प्रगति और सेवा की रूपरेखा बनाने के लिए महिला अधिकारियों को समान अवसर सुनिश्चित किया है।

17.22 आईसीजी में महिला अधिकारियों ने अपने पुरुष प्रतिद्वंद्वियों के साथ कदम दर कदम स्वयं को स्थापित किया है। सेवा में महिला अधिकारियों के लिए नए संभावनाओं को खोलते हुए, आईसीजी ने कनिष्ठ स्तर के महिला अधिकारियों को फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से सम्बंधित एयर कुशन व्हीकल्स (एसीवी) पर सवार सह-पायलटों के रूप में नियुक्त किया है। इस दिशा में, चार महिला अधिकारियों को पहले ही एसीवी में परिचालक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है और बाद में, एसीवी पर नियुक्त किया गया है जबकि तीन अन्य महिला अधिकारी एसीवी का प्रशिक्षण ले रही हैं। इन महिला अधिकारियों को समुद्र में लगभग 8-10 घंटों के लिए तैनात किया जा रहा है। इन्होंने अपने कार्यक्षेत्र की जागरूकता और व्यवसायिक विद्वता को सुधारने में सहायता प्रदान की है।

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ)

17.23 एक नियोक्ता के रूप में, डीआरडीओ एक स्वस्थ, सुरक्षित कार्य वातावरण का निर्माण करने के प्रति कृतसंकल्प है जो कर्मचारियों को स्वागतहीन, आक्रामक एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार से मुक्त कार्य करने में सक्षम बनाता है जो उनको भेदभाव, लैंगिक पक्षपात और यौन उत्पीड़न के भय के बिना अपनी श्रेष्ठ सेवाएँ प्रदान करने के योग्य बनाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि महिला कर्मचारियों को अपने कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि करने और अपनी संभावना को पूरा करने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाये। इसके परिणामस्वरूप, कई महिला वैज्ञानिकों ने डीआरडीओ में उच्चतम पद प्राप्त किया है और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया है।

17.24 प्रत्येक वर्ष डीआरडीओ पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। “अनुसंधान के क्षेत्रों में गतिशीलता को मुक्त करती हुई महिला (मुद्रा-2017)” पर एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन एएसएल द्वारा हैदराबाद में किया गया जहाँ पर सम्पूर्ण देश में स्थित डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठानों से 270 से अधिक महिला वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।



अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस

रक्षा उत्पादन विभाग

17.25 आयुध कारखाना बोर्ड (ओएफबी):

- 21 जुलाई, 2017 को ओएफबी में शिशुसदन सुविधा की स्थापना।
- डीओपीएवंटी द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार, यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए प्रत्येक इकाई में शिकायत समिति का गठन किया गया है। ओएबी ने अनुपालन के लिए सभी ओएफ/इकाईयों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के व्यापक प्रचार के लिए पहले से ही निर्देश जारी कर दिया है।
- महिला कर्मचारियों को विषम घंटों वाली पाली में ड्यूटी देने के लिए तैनात नहीं किया जाता है।
- सभी आधारभूत जनसुविधाओं, जैसे उपयुक्त कार्य

क्षेत्र, पृथक शौचालय, विश्राम-कक्षों को सभी ओएफ/इकाईयों में महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया गया है।

- महिला अधिकारियों को उच्चतम पद, अर्थात् डीजीओएफ/अध्यक्ष/ओएफबी तक पहुँचने के लिए अधिकृत किया गया है।
- महिला कर्मचारियों को अपने पुरुष प्रतिद्वंदी के साथ समान रूप से प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

17.26 हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल): 31 दिसम्बर, 2017 को एचएएल में महिला कर्मचारियों की क्षमता 2393 थी। एचएएल, लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज) (स्कोप) के तत्वाधान में "सार्वजनिक उपक्रम में महिलाएँ (डब्ल्यूआईपीएस)" नामक मंच का एक सदस्य है। विप्स मंच के कार्यक्रमों/ गतिविधियों में भाग लेने के अवसरों को महिला कर्मचारियों तक विस्तारित किया गया है।

17.27 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के अनुरूप, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, आंतरिक शिकायत समितियों का संज्ञान लिया जाता है।

17.28 **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल):** बीईएल में लगभग 2076 महिला कर्मचारी हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए लैंगिक विविधता की सराहना की जाती है और मान्यता दी जाती है। भर्ती, कैरियर की प्रगति, ज्ञानार्जन और विकास, कल्याणकारी उपायों आदि में उचित अवसर प्रदान किये जाते हैं। महिलाओं ने बीईएल में महत्वपूर्ण भूमिकाओं (जीएम एवं निदेशक) में नेतृत्व के पदों का कार्यभार संभाला है और व्यवसाय की वृद्धि में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निषेध' पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के प्रकाश में, एक "आंतरिक शिकायत समिति" की स्थापना की गयी है जो एक वरिष्ठ महिला अधिशासी के साथ इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करती है। महिला और पुरुष कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन किये जा रहे हैं ताकि बीईएल को महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाया जा सके।

17.29 **गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई):** वर्ष 2017-18 (दिसम्बर 2017 तक) के दौरान, जीआरएसई में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कंपनी की कुल श्रमशक्ति का 4.8 प्रतिशत और भर्ती का 12.5 प्रतिशत है। जीआरएसई विप्स चैप्टर ने पूर्वी संभाग के विप्स चैप्टर के साथ नियमित रूप से बातचीत की है और कंपनी ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जैसे कोलकाता एवं उड़ीसा के विप्स शाखा द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए महिला कर्मचारियों को मनोनीत किया है।

17.30 **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल):** जीएसएल में महिलाओं को अपने पुरुष प्रतिद्वंदी के साथ समान अवसर प्रदान किया जाता है। उनके लिए नियमित जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और शिकायतों के निवारण के लिए एक 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया गया है।

17.31 **हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल):** एक

"लैंगिक आधार पर बजट निर्माण और सार्वजनिक क्षेत्र प्रकोष्ठ में महिलाएँ" नाम से एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ में महिला कर्मचारियों के लिए साधारण विकास कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वन के लिए और उनके सेवायोजन, कैरियर प्रबंधन और सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में महिला कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए भी चार महिला अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि प्रशिक्षण, कौशल के विकास और कार्यस्थलों में कल्याणकारी जनसुविधाओं का प्रावधान आदि। वर्तमान में, यार्ड में स्थायी भूमिकाओं में 56 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं।

17.32 **माजगन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल):** एमडीएल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, विभिन्न व्यवसायों में 94 कन्या प्रशिक्षुओं को कौशल में वृद्धि के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के मंच (विप्स) में लगभग 68 महिला कर्मचारी (अधिशासी और स्टाफ) सदस्य हैं।

17.33 **भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) लिमिटेड:** बीईएमएल महिला कर्मचारियों/अधिशासियों के लिए एक सुखमय वातावरण का निर्माण कर रहा है। कंपनी ने महिला कर्मचारियों/अधिशासियों से जुड़े विषयों के समाधान के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस (मुख्य व्यवसायिक कार्यालय) सहित, सभी उत्पादन इकाइयों में महिला प्रकोष्ठों का गठन किया है। कंपनी के महिला कर्मचारियों/अधिशासियों में विचारों एवं दृष्टिकोणों के मुक्त आदान-प्रदान को सरलीकृत करने के लिए एक समर्पित इंटरनेट मेल-आईडी उपलब्ध कराया गया है।

17.34 **भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल):** 01 दिसम्बर 2017 को बीडीएल में 337 महिला कर्मचारी कार्यरत थीं जो कुल कार्यबल का 10.69 प्रतिशत है। महिला कर्मचारियों (अधिशासी एवं गैर-अधिशासी) को व्यवसाय संघ और अधिकारियों के संघ में मनोनीत किया जाता है।

17.35 **मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी):** मिधानी ने अपनी सभी महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए नियमों के अनुसार, सभी सुविधाओं का विस्तार किया है। अधिशासी, निरीक्षणआत्मक और गैर-अधिशासी संवर्ग से सम्बंधित मिधानी के महिला कर्मचारी सामग्री अर्जन, उत्पादन, अनुरक्षण एवं प्रेषणों से लेकर सहायता सेवाओं, जैसे कि नागरिक, वित्त, एचआर, विपणन आदि तक कंपनी के संचालन के सभी क्षेत्रों में सम्मिलित है।

वर्तमान में, 71 महिला कर्मचारी कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामूहिक रूप से कार्य कर रही हैं।

17.36 **गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए):** भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और नीतियों के अनुसार, महिला सशक्तिकरण और कल्याण से सम्बंधित सभी अवसरों और लाभों और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों को समय-समय पर लागू किया जा रहा है।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू)

17.37 भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग पूर्व सशस्त्र बल के कर्मचारियों की विधवाओं और उन पर निर्भर परिवार के सदस्यों सहित, लगभग 30 लाख पूर्व-सैनिक के पुनर्वास और कल्याण का ध्यान रखता है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, कन्याओं और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) सचिवालय ईएसएम की पुत्रियों की शिक्षा और विवाह, विधवाओं के पुनर्विवाह और उनके व्यवसायिक प्रशिक्षण के

लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विधवाएँ भी शर्तों के आधार पर दोहरी पारिवारिक पेंशन पाने के योग्य हैं।

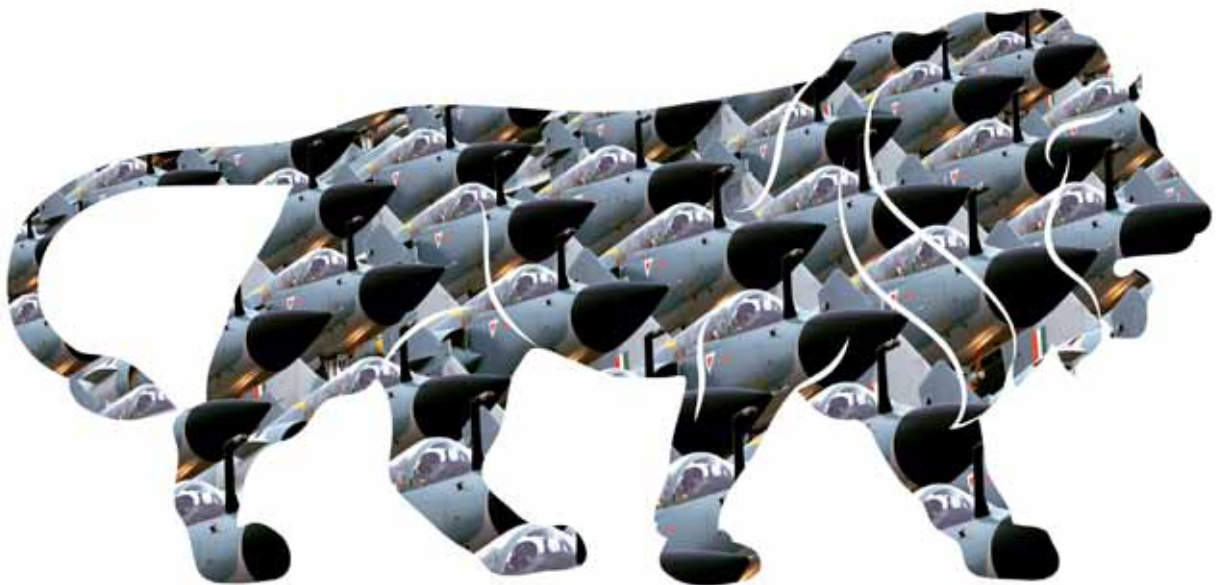
17.38 प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) के अंतर्गत, लड़कियों को उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जा रही है। पीएमएसएस के अंतर्गत, 5500 छात्रवृत्तियों को लड़कों और लड़कियों के बीच समान रूप से बाँट दिया गया है। छात्रवृत्ति की राशि प्रति माह लड़कों के लिए रु. 2,000/- और लड़कियों के लिए रु. 2,250/- है और इसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है।

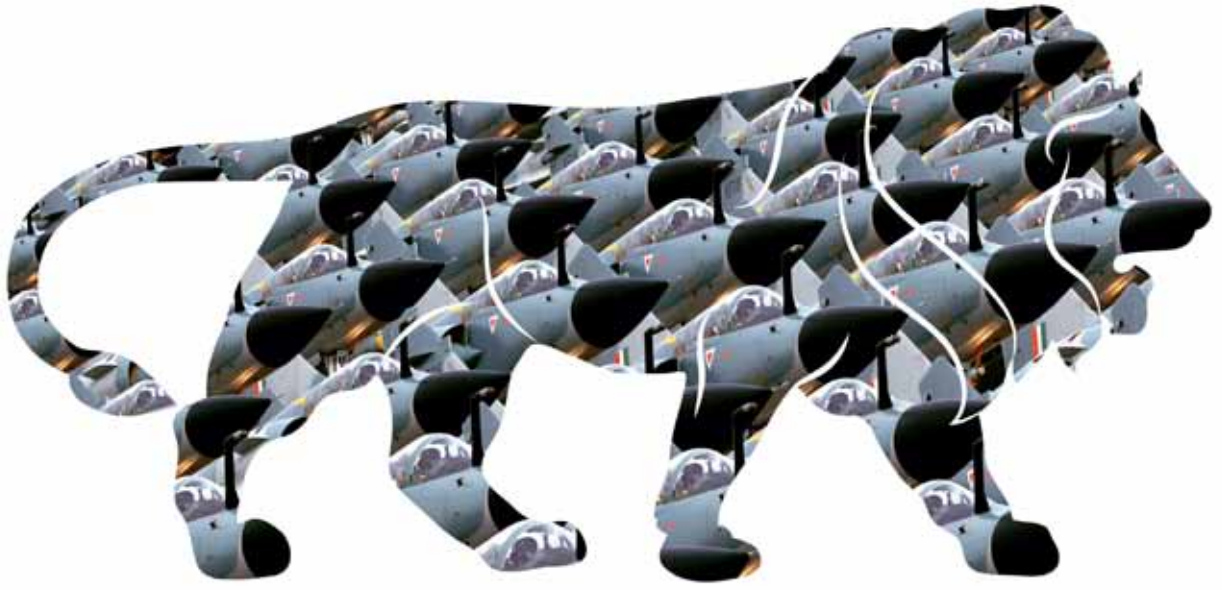
17.39 पुनर्वास महानिदेशालय (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट) (डीजीआर) के अंतर्गत, ईएसएम की विधवा पुनर्वास प्रशिक्षण प्राप्त करने की पात्र हैं। कई डीजीआर सेवायोजन योजनाओं, जैसे- कोयला टिपर स्कीम, तेल उत्पादन एजेंसियाँ, अतिरिक्त वाहन, सफल बूथ आदि को ईएसएम की विधवाओं की कुछ श्रेणियों के लिए प्राथमिकता दी जाती है। युद्ध विधवाओं को ईसीएचएस की सदस्यता के लिए एक बार के योगदान के भुगतान से छूट दी जाती है।





व्यापार के तरीकों का सरलीकरण,
विकेन्द्रीकरण और उन्नयन करने की
दिशा में प्रयास





व्यापार के तरीकों का सरलीकरण, विकेन्द्रीकरण और उन्नयन करने की दिशा में प्रयास

18.1 सरकार के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की कार्यसूची को ध्यान में रखते हुए और व्यापार कुशलता के स्वीकृत उद्देश्यों को गति देने हेतु, वर्ष के दौरान कई प्रयास सरलीकरण और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने और निर्णय लेने के विकेंद्रीकरण के लिए किए गए हैं। अतिरिक्त शक्तियां सेवा मुख्यालयों और अन्य अधीनस्थ संस्थाओं को त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधा प्रदान करने के लिए सौंपी गई हैं। इस अध्याय में इस तरह की पहलों पर एक संक्षिप्त विवरण प्रदान किया गया है।

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन एवं निर्णय-लेने की शक्ति का विकेन्द्रीकरण

18.2 रक्षा मंत्रालय के अधीन सशस्त्र बलों और अन्य अधीनस्थ संस्थाओं को सशक्त बनाने और निर्णय-लेने में समय को कम करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालय द्वारा अब तक निर्वहन की जाने वाली कई शक्तियों का अब सेवा मुख्यालय और अन्य उपक्रमों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ ऐसे क्षेत्रों में

जहां इस तरह की शक्तियों के प्रत्यायोजन की व्यवस्था की गई है उनका विवरण यहां दिया गया है:

(क) सीसीएस के अनुमोदन के साथ, वित्तीय पूंजी से संबंधित पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों की मंजूरी के लिए फरवरी 2017 में सर्विस कैपिटल वार्षिक अधिग्रहण योजना में सम्मिलित निम्नलिखित प्रत्यायोजन को शामिल किया गया था:

150 करोड़ रु. तक	सेवा मुख्यालय (उपाध्यक्ष और डीजी (तटरक्षक बल))
150 करोड़ रु. से ऊपर तथा 300 करोड़ रु. तक	रक्षा सचिव
300 करोड़ रु. से ऊपर तथा 2000 करोड़ रु. तक	रक्षा मंत्री
2000 करोड़ रु. से ऊपर तथा 3000 करोड़ रु. तक	वित्तीय मंत्री
3000 करोड़ रु. से अधिक	सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति

- (ख) कार्य के निष्पादन की गति में सुधार के लिए और सशस्त्र बलों की आवश्यकता के अनुसार वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए सीमा सड़क संगठन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के इरादे से मंत्रालय ने अगस्त, 2017 में बीआरओ को चीफ इंजीनियर और टास्क फोर्स कमांडर के स्तर तक पर्याप्त प्रशासनिक अधिकार सौंपे हैं। अपेक्षा की जाती है कि बीआरओ को शक्तियों के इस महत्वपूर्ण प्रत्यायोजन के साथ, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण की गति में काफी सुधार होगा और बीआरओ कम से कम समयसीमा में जारी और साथ ही नई परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम होगा।
- (ग) सेना विमानन अड्डों के उपयोग के लिए और सेना की निर्धारित उड़ानों के लिए सेना नियंत्रित उन्नत लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) और हेलीपैड के उपयोग के लिए परमिट जारी करने की शक्तियां, जो अब तक रक्षा मंत्रालय के पास निहित थे, को रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय को सौंपे गए हैं जिससे कि सुरक्षा मंजूरी के लिए अनुमोदन के चैनल को कम किया जा सके और अनावश्यक विलंब से बचा जा सके, जो सेना के विमानन अड्डों का उपयोग करने वाले राज्य के गणमान्य व्यक्तियों के लिए असुविधा का कारण बनता था।
- (घ) संवेदनशील सैन्य स्थापना हेतु परिधीय सुरक्षा से संबंधित कार्यों को हाथ में लेने के लिए निर्णय लेने में तेजी लाने की शक्तियों को पूरी तरह से सेवा मुख्यालय को सौंप दिया गया है।
- (ङ) पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों के साथ ही, अब मंत्रालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले राजस्व प्रापण के अनुबंध के बाद, अनुबंध के संबंध में कुछ शक्तियों को सेवा मुख्यालयों को सौंप दिया गया है। इसमें शामिल हैं एलडी लागू करने और साख्र पत्र के विस्तार (एलसी) के साथ प्रदेयता अवधि का विस्तार; संवैधानिक करारोपण में बदलाव के कारण अनुबंधों के वित्तीय निहितार्थों में संशोधन; अतिरिक्त बैंक प्रभार/ एलसी प्रभार/परिवहन प्रभार, एलसी खोलने में अतिरिक्त लागत का भुगतान; विशिष्ट परिचालन कारणों के लिए डिलीवरी शर्तों/

प्रेषिती में सुधार; निःशुल्क मरम्मत/ प्रतिस्थापन सहित गारंटी/वारंटी के नियमों को लागू करने हेतु; सभी एएमसी/सीएमसी को समाप्त करने का अनुमोदन आदि। एसटीई के मामले में 25 करोड़ रूपए तक के मूल्य व ओटीई/एलटीई के मामले में पूर्ण अधिकार के साथ अनुबंध निष्पादित किया जा सकता है।

- (च) अतिरिक्त वित्तीय शक्तियों को राष्ट्रीय कैंडेट कोर (एनसीसी) और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक और अन्य प्राधिकरणों को सौंप दिया गया है।
- (छ) रक्षा मंत्रालय ने सेवा मुख्यालयों के लिए महत्वपूर्ण एम्यूनिशन/पुर्जो हेतु वित्तीय शक्तियों को उनके संबंधित वित्तीय सलाहकार (आईएफए)/प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर (पीआईएफए) के परामर्श से वाइस-चीफ ऑफ द सर्विसेस द्वारा प्रयोग के लिए सौंप दिया है।
- (ज) खराब हो चुके वाहनों की जगह परिचालन वाहनों की खरीद के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन के संबंध में अधिकारियों के वाइस-चीफ ऑफ द सर्विसेस को अधिकार दिया गया है।
- (झ) एक वर्ष के लिए अनुबंध आधार पर सिविलियन शैक्षणिक अधिकारियों की भर्ती के लिए कमांडेंट/श्रेणी 'ए' संस्थान के प्राचार्यों को भी अधिकार सौंप दिया गया था।
- (ञ) पदकों के वितरण के कार्य को भी सेवा मुख्यालयों को सौंप दिया गया है।

अधिग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण

18.3 विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति के प्रस्तावों के शीघ्र प्रसंस्करण के लिए, सरकारी मंजूरी पत्र (जीएसएल)/ अनुबंध/ आपूर्ति आदेश की जांच करने और यूओ संख्या आवंटित करने की प्रक्रिया को सरलीकृत कर दिया गया है।

18.4 नई रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) 2016, जो 1 अप्रैल, 2016 (डीपीपी-2016) से प्रभावी है, संस्थागत, सुव्यवस्थित और प्रक्रिया को सुगम बनाने पर केंद्रित है। रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई की भूमिका को बढ़ाना और विभिन्न खरीद गतिविधियों हेतु समय

सीमा तय करना, डीपीपी—2016 की अन्य परिभाषात्मक विशेषताएं हैं।

18.5 नई डीपीपी ने अन्य देशों के साथ—साथ स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा दिया और युक्तिसंगत बनाया है, सेवाओं की गुणात्मक आवश्यकताओं (एसक्यूआर) का दायरा बढ़ाया है, इससे जुड़ी आवश्यकताओं को ढूँढकर तर्कसंगत बनाया है, उत्पादन एजेंसियां और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भागीदारों जैसे निजी उद्योगों को शामिल करने के लिए नए प्रावधानों को सम्मिलित किया है। एकल विक्रेता मामलों को बोली—प्रस्तुत करने और टीईसी चरणों में अब स्वतः वापस नहीं लिया जाएगा लेकिन डीएसी के उचित औचित्य और अनुमोदन के साथ इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। डीपीपी विशेष रूप से, एओओ मांगने के प्रस्ताव के साथ, आरएफपी प्रस्तुत करने सहित, कई उपायों के माध्यम से इसमें होने वाले विलंब के मुद्दे को संबोधित करता है, और विक्रेता के नाम बदलने के साथ—साथ प्रमाणपत्रों और सिमुलेशन के उपयोग की संभावना को बढ़ाने का भी विकल्प प्रदान करता है।

18.6 इन पहलों को आगे ले जाते हुये, इनसे जुड़ी ऑफसेट नीति पॉलिसी को सुव्यवस्थित कर दिया गया है ताकि विक्रेता को बाद के स्तर पर भारतीय ऑफसेट पार्टनर (आईओपी) / प्रोडक्ट्स का ब्यौरा दिया जा सके। पूर्व के डीपीपी के तहत अनुबंध में आईओपी/ऑफसेट घटक को बदलने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है। ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन के लिए एक 'एवेन्यूज' के रूप में 'सेवाएं' फिर से प्रारम्भ की गई हैं।

18.7 हाल में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के बाद, निर्णय लिया गया कि खरीद मामलों के संबंध में, जिसके लिए आरएफपी पिछले प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के तहत जारी किए गए थे, प्रत्यायोजनकर्ता प्राधिकरण का ध्यान दिये बगैर जिसने प्रस्ताव की सैद्धान्तिक मंजूरी दी हो या खरीद प्रक्रिया के दौरान मामले पर विचार किया हो, वित्तीय अधिकारों के वर्तमान प्रत्यायोजन के अनुसार अंतिम स्वीकृति प्राधिकारी का निर्धारण किया जाएगा।

18.8 एक सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच कर विसंगतियों को व्यापार की सुगमता का एक समान स्तर प्रदान करने के लिए हटा दिया गया है। निजी क्षेत्र में पूर्णतया आयातित सामग्री पर विदेशी मुद्रा दर विविधता (एफईआरवी) संरक्षण को बढ़ा दिया गया है।

व्यापार करने की सरलता बढ़ाना

18.9 व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए लाइसेंसिंग नीति के उदारीकरण के हिस्से के रूप में, आईडीआर अधिनियम के तहत भागों, घटकों आदि सहित 65 से 70 प्रतिशत वस्तुओं का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और औद्योगिक लाइसेंस की वैधता को आगे 3 साल के विस्तार के प्रावधान के साथ 15 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

18.10 ग्रीन चैनल पॉलिसी मार्च, 2017 में लागू की गई थी, जो पूर्व—प्रेषण निरीक्षण की छूट और सप्लायर की वारंटी/गारंटी के तहत स्टोर्स की स्वीकृति के अधीन समतुल्य पंजीकरण स्थिति प्रदान करती है। इसके अलावा, पंजीकरण के नवीकरण को स्व—प्रमाणन के आधार पर अनुमति दी गई है।

18.11 डीपीएसयू को 'समतुल्य पंजीकरण' प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया गया है अर्थात्, एक डीपीएसयू के साथ पंजीकृत विक्रेता, स्वचालित रूप से निर्दिष्ट विशिष्ट उत्पादों के लिए अन्य डीपीएसयू के साथ पंजीकृत हो जाते हैं।

18.12 वैश्विक निविदाओं में भारतीय विक्रेताओं को 'साख पत्र' (एलसी) के माध्यम से भुगतान करने हेतु ओएफबी और डीपीएसयू के प्रावधान बनाए गए हैं।

18.13 सरकारी संस्थाओं की परीक्षण सुविधाएं निजी क्षेत्रों के लिए खुली हैं।

'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन

18.14 स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण के लिए डीपीपी 2016 ने स्पष्ट रूप से 'मेक इन इंडिया' पर काफी जोर दिया है। पहल को आगे बढ़ाते हुए, एक संशोधित 'मेक' प्रक्रिया को लागू किया गया था जो 90 प्रतिशत तक सरकार द्वारा वित्तपोषण और एमएसएमई के लिए अधिमान्य उपचार प्रदान करता है।

18.15 रक्षा खरीद प्रक्रियाओं के तहत 'मेक' प्रक्रिया, जो कि आरंभ में वर्ष 2006 में शुरू की गई थी, रक्षा उपकरणों की स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए सरकार और निजी भारतीय उद्योग के बीच सहयोग प्रदान करती है। 'मेक' की दो उप—श्रेणियां; अर्थात् 'मेक-I' और 'मेक-II' वर्ष 2016 में प्रस्तुत किए गए थे। मेक-II प्रक्रिया सरकारी वित्त पोषण के बगैर प्रोटोटाइप विकास की परियोजनाओं के लिए है। रक्षा क्षेत्र में 'मेक

इन इंडिया' को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में, 16 जनवरी 2018 को रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने उद्योगों के साथ परामर्श के कई क्रमों के बाद एक सरलीकृत 'मेक-II' प्रक्रिया को मंजूरी दी है। सरलीकृत प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- परियोजना के लिए उद्योग से, स्टार्टअप से और व्यक्तियों से सुझाव आमंत्रित करना, विशेषकर उन वस्तुओं के संबंध में जो वर्तमान में आयात किए जा रहे हैं;
- डीआरडीओ, मुख्यालय (आईडीएस), डीओडी को शामिल करते हुए सचिव (डीपी) की अध्यक्षता वाली एक समिति के अधीन एक समतुल्य महाविद्यालय द्वारा परियोजना को "सैद्धान्तिक अनुमोदन" प्रदान किया गया है;
- रक्षा मंत्रालय की वेबसाइटों पर अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को डालना;
- उद्योग के इच्छुक प्रतिभागियों की संख्या की कोई सीमा नहीं है और यह एक प्रोटोटाइप प्रदान कर सकता है;
- परियोजना स्वीकृति आदेश जारी किए जाने के बाद परियोजना को बंद नहीं किया जाएगा। सफल बोलीदाता को एक आपूर्ति का आश्वासन दिया गया है;
- प्रक्रिया की सुविधा के लिए सेवा मुख्यालयों को एक परियोजना सुविधा दल का गठन करना है;
- केवल एक इकाई ने द्वारा अभिनव समाधान प्रस्तुत किए जाने के बावजूद मामलों को आगे बढ़ाया जाएगा;
- जो उद्योग परियोजना को विकसित करता है वह इसके स्वत्वाधिकार, स्वामित्व और आईपीआर (राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विशिष्ट कारणों को छोड़कर) को बनाए रखेगा;
- बहु-विक्रेता अनुबंधों के मामले में आम तौर पर कोई परस्पर बातचीत नहीं।

18.16 सरलीकृत 'मेक-II' प्रक्रिया, सैद्धान्तिक अनुमोदन की अपेक्षा ऑर्डर देने के कुल समय को 50 प्रतिशत तक कम करेगी। पूरी प्रक्रिया समाप्त होने में अनुमानित समय 103 सप्ताह से घटकर 69 सप्ताह तक हो जाएगा।

18.17 वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण विकास, जिसके आने वाले समय में भारत के रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक आधार पर खेल-परिवर्तक बनने की संभावना है, रक्षा क्षेत्र में दिनांक 31.05.2017 को किए गए रणनीतिक साझेदारी मॉडल का परिणाम था, जिसे डीपीपी 2016 के अध्याय-VII में शीर्षक रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरोद्धार के अधीन वर्णित किया गया है। इस नीति का उद्देश्य रक्षा मंचों और उपकरणों के निर्माण में निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह नीति प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, दक्षताओं में वृद्धि, प्रौद्योगिकी को तेज बनाने और इसके महत्वपूर्ण तौर पर अपनाए जाने की सुविधा प्रदान करती है, साथ ही यह एक संरक्षित औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करती है, व्यापक कौशल आधार के विकास को सुनिश्चित करती है और नवाचार को उत्प्रेरित भी करती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता में कमी और आत्म-निर्भरता को बढ़ाना शामिल है।

अन्य सरलीकरण और युक्तिकरण के उपाय

18.18 पैसेज एक्सरसाइज़ (पासेक्स) के लिए रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, पासेक्स के दौरान किए जाने वाली गतिविधियों को उन देशों के परामर्श से परिभाषित किया गया है, जिनके साथ पासेक्स आयोजित किया जा सकता है। भारतीय नौसेना को विदेशों में मुठभेड़ के दौरान और इन देशों के पोर्ट यात्राओं के दौरान, निर्धारित परिभाषित गतिविधियों के मापदंड के भीतर 28 चिन्हित देशों के साथ पासेक्स अभ्यास करने के लिए अधिकृत किया गया है। नौसेना को भारतीय बंदरगाहों में इन देशों के जहाजों की यात्रा के दौरान भी इन देशों के साथ पासेक्स करने के लिए अधिकृत किया गया है। नौसेना मुख्यालय को रक्षा मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता तब होती है, जब वे 28 चिन्हित देशों या पासेक्स के दायरे के अलावा अन्य देशों के साथ संलग्न हों, या चिन्हित की गई गतिविधियों से परे हों।

18.19 दिनांक 25 अगस्त, 1967 के नक्शों की बिक्री, प्रकाशन और वितरण की रोकथाम पर नीति को संशोधित किया गया है। यह उदार आर्थिक व्यवस्था के साथ संगतता और अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नक्काशी और प्रगति के क्षेत्र में हुई तकनीकी परिवर्तनों को समायोजित करने और राष्ट्रीय मानचित्र नीति-2005 के कार्यान्वयन के कारण इसे अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता थी; जिसमें दो नक्शों की श्रृंखला शुरू की गई

है, अर्थात्; रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिफेंस सिरीज़ मैप्स (डीएसएम); और खुले वितरण के लिए ओपन सीरीज़ मैप्स (ओएसएम)। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल 1:50,000 या बड़े पैमाने के नक्शों को पहले दिशानिर्देशों के मुकाबले प्रतिबंधित किए गए हैं, जो वर्गीकृत रूप में 1:1 मिलियन या अधिक के निर्दिष्ट नक्शे हैं। इसके आगे के पैमाने का नक्शा: रक्षा मंत्रालय के पुनरीक्षण की आवश्यकता से 4 मिलियन या उससे कम को हटा दिया गया है।

18.20 भूमि अधिग्रहण के मामलों में रक्षा मंत्री से सैद्धान्तिक अनुमोदन (आईपीए) प्राप्त करने की नीति को संशोधित किया गया है। संशोधित प्रक्रिया के तहत आईपीए रक्षा सचिव के स्तर पर जारी किया जाएगा, और रक्षा मंत्री की मंजूरी केवल जमीन के वास्तविक अधिग्रहण के समय प्राप्त की जानी है। प्रासंगिक नियमों को इस आशय में संशोधित किया गया है।

18.21 सेना ने सेना में भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा परीक्षण से पहले ऑनलाइन परीक्षा हेतु पायलट परियोजना के रूप में मंजूरी दे दी है। आरंभ में, यह परियोजना अंबाला, चेन्नई और जयपुर के तीन मुख्यालय भर्ती क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है।

18.22 चयन की प्रमात्रा प्रणाली (क्यूएसएस) को 31 दिसम्बर, 2008 से आरंभ किया गया है। इस क्वाइंटिफाइड सिस्टम ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ा दी है। क्यूएसएस की पिछली समीक्षा 4 जनवरी, 2011 को की गई थी। वर्ष 2017-18 में, अंकों के कुल आवंटन, सीआर भार और समग्र पाठ्यक्रम भार में कुछ बदलाव लाकर वर्तमान प्रणाली में सुधार के लिए क्यूएसएस की समीक्षा की गई है।

18.23 इस प्रणाली में और अधिक निष्पक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को शामिल करने और चयन बोर्ड के आयोजन को सुचारू बनाने के लिए, मेजर जनरल और इसके ऊपर के रैंक की पदोन्नति के लिए नई पदोन्नति नीति की घोषणा की गई है।

18.24 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीसी) कोर्स और एपीपीए

पाठ्यक्रम नेशनल डिफेंस कॉलेज और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली में प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं। एनडीसी, एपीपीए के लिए सेवा अधिकारियों के नामांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए मौजूदा नीति की समीक्षा की गई है।

18.25 एक प्रमुख पहल में, मौसमी पोर्टलों की भर्ती करने की प्रणाली को सुव्यवस्थित और तर्कसंगत बनाने के लिए और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप इसे लाने के लिए, मंत्रालय द्वारा "मौसमी पोर्टर्स की भर्ती के लिए नियम और शर्तें" को प्रख्यापित किया गया है। सशस्त्र बलों द्वारा अनुबंध पर नियुक्त मौसमी पोर्टर अक्सर सीमावर्ती इलाकों में अधिक ऊँचाई पर और कठोर जलवायु परिस्थितियों में और नियंत्रण रेखा के साथ काम करते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इस योजना में ऐसे पोर्टर्स की भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें शामिल होती हैं, साथ ही इसमें शामिल है उन्हें की जाने वाली मजदूरी का भुगतान, भर्ती की शर्त और नियम, लाभकारी सुविधाएं (चिकित्सा सुविधाएं, आवास, बीमा, मौत पर मुआवजा, बर्खास्त किए जाने पर एक-मुश्त वित्तीय अनुदान आदि)। यह बहु कार्य कर्मचारियों (एमटीएस) के रूप में उन्हें नियमित रोजगार प्रदान करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। यह योजना पूरे कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन को नियंत्रित करने हेतु कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड रखने की सुविधा भी प्रदान करता है।

18.26 **एटीवी की खरीद:** अत्यंत आवश्यक परिचालनात्मक आवश्यकताओं के लिए 14 कोर उत्तरी कमान में 9 ऑल टैरेन व्हीकल (एटीवी) की खरीद हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन, सक्षम अधिकारियों द्वारा वीकोएस को सौंपी गई शक्तियों के तहत प्रदान की गई है।

18.27 **एलबीपीवी की खरीद:** इसी प्रकार अत्यंत आवश्यक परिचालनात्मक आवश्यकताओं हेतु उत्तरी कमान में सैनिकों के लिए 50 हल्के बुलेट प्रूफ वाहन (एलबीपीवी) की एकबारगी खरीद संबंधी सैद्धान्तिक अनुमोदन, सक्षम अधिकारियों द्वारा वीसीओएस को सौंपी गई शक्तियों के तहत प्रदान किए गए हैं।



रक्षा मंत्रालय के विभागों के कार्यों की सूची

क रक्षा विभाग

1. भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा करना, इसमें रक्षात्मक तैयारियां तथा ऐसे सभी काम आते हैं जो युद्ध के समय युद्ध को ठीक ढंग से चलाने तथा युद्ध के बाद सेना को कारगर ढंग से विसंगठित करने के लिए सहायक हैं।
2. संघ की सशस्त्र सेनाएं अर्थात् सेना, नौसेना वायु सेना।
3. रक्षा मंत्रालय के समेकित मुख्यालय जिनमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और रक्षा सेवा मुख्यालय भी शामिल हैं।
4. सेना, नौसेना और वायुसेना के रिजर्व।
5. प्रादेशिक सेना।
6. राष्ट्रीय कैडेट कोर।
7. सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित कार्य।
8. रिमाउंट, वेटरनरी और फार्म संगठन।
9. कैंटीन भंडार विभाग।
10. रक्षा प्राक्कलनों से वेतनभोगी सिविलियन सेवाएं।
11. हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेवीगेशनल चार्ट बनाना।
12. छावनियों की स्थापना, छावनी क्षेत्रों की हदबंदी और कुछ क्षेत्रों को उसकी सीमा के बाहर निकालना, ऐसे क्षेत्रों के स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों में छावनी बोर्डों का गठन तथा प्राधिकारी और उनकी शक्तियां तथा उनमें आवास संबंधी विनियम (इसमें किराया नियंत्रण भी शामिल है)।
13. रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, अभिरक्षा और उसकी वापसी। अनधिकृत कब्जा करने वालों को रक्षा भूमि और संपत्ति से बेदखल करना।
14. रक्षा लेखा विभाग।
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को जिस खाद्य सामग्री की खरीद का काम सौंप गया है उसे छोड़कर, सेना की जरूरतों की पूर्ति के लिए खाद्य सामग्री की खरीद और उसका निपटान।
16. तटरक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले जिनमें निम्नांकित भी शामिल हैं –
 - (i) तेल बिखराव के प्रति समुद्री क्षेत्र की निगरानी।
 - (ii) बंदरगाहों के जल क्षेत्र और अपतटीय खोज और उत्पादन प्लेटफार्मों, तटीय रिफाइनरियों और अनुषंगी सुविधाओं जैसे कि सिंगल बॉय मूरिंग (एस बी एम), क्रूड तेल टर्मिनलों (सी ओ टी) और पाइपलाइनों के 500 मीटर के भीतर के सिवाए विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में तेल बिखराव के प्रति उपाय।
 - (iii) तटीय तथा विभिन्न समुद्री क्षेत्रों के समुद्री पर्यावरण में तेल प्रदूषण को दूर करने के लिए केन्द्रीय समन्वय एजेंसी।
 - (iv) तेल बिखराव आपदा हेतु राष्ट्रीय आकस्मिकता योजना का कार्यान्वयन, और
 - (v) तेल बिखराव रोकथाम और नियंत्रण कार्य हाथ में लेना, देश में जलपोतों और अपतटीय

प्लेटफार्मों का निरीक्षण कार्य करना, इसमें वाणिज्य, पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बंदरगाहों की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र शामिल नहीं है।

17. देश में गोताखोरी और संबंधित कार्यकलापों से संबंधित मामले।
18. केवल रक्षा सेवाओं के लिए अधिप्राप्ति।
19. सीमा सड़क विकास बोर्ड एवं सीमा सड़क संगठन से संबंधित सभी मामले।

ख रक्षा उत्पादन विभाग

1. आयुध निर्माणी बोर्ड और आयुध निर्माणियां
2. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
3. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
4. माझगांव डाक लिमिटेड
5. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
7. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
8. मिश्र घातु निगम लिमिटेड
9. गुणता आश्वासन महानिदेशालय और वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय सहित रक्षा गुणता आश्वासन संगठन।
10. मानकीकरण निदेशालय सहित रक्षा उपस्करों और भंडारों का मानकीकरण।
11. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
12. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
13. वैमानिकी उद्योग का विकास और नागर उड्डयन मंत्रालय तथा अंतरिक्ष विभाग से संबंधित प्रयोक्ताओं को छोड़कर अन्य के बीच समन्वय।
14. रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण, विकास तथा उत्पादन और रक्षा उपस्करों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी।

15. रक्षा निर्यात और रक्षा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

ग रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति का राष्ट्रीय सुरक्षा पर होने वाले प्रभाव का जायजा लेकर रक्षा मंत्री को उसकी जानकारी और सलाह देना।
2. हथियारों, हथियार-प्लेटफार्मों, सैन्य संक्रियाओं, निगरानी, सहायता और संभारिकी आदि से संबंधित सभी वैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में और संघर्ष के सभी संभावित क्षेत्रों में रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं और अंतर सेवा संगठनों को सलाह देना।
3. ऐसी प्रौद्योगिकियों, जिनका भारत को निर्यात विदेशी सरकारों के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नियंत्रण का विषय है, के अर्जन के बारे में विदेशी सरकारों के साथ समझौता प्रलेखों से संबंध सभी मामलों पर रक्षा मंत्रालय की नोडल समन्वय एजेंसी के रूप में विदेश मंत्रालय की सहमति लेकर कार्य करना।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा डिजाइन, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना।
5. विभाग की एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, स्थापनाओं, रेजों, सुविधाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निर्देशन और प्रशासन।
6. वैमानिकी विकास एजेंसी।
7. सैन्य विमानों के डिजाइन, उड़ान योग्यता का प्रमाणन, उनके उपस्करों तथा भंडारों से संबंधित मामले।
8. संसाधन जुटाने के लिए विभाग के कार्यकलापों से तैयार प्रौद्योगिकियों के संरक्षण और हस्तांतरण से संबंधित सभी मामले।
9. रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी शस्त्र प्रणालियों और तत्संबंधी प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण और मूल्यांकन के कार्यों में भाग लेना तथा वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता करना।

10. उत्पादन यूनिटों और उद्यमों द्वारा सशस्त्र सेनाओं के लिए उपस्कर और भंडारों के विनिर्माण या विनिर्माण के प्रस्तावों के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के प्रौद्योगिकीय तथा बौद्धिक संपदा संबंधी सभी पहलुओं पर सलाह देना।
11. पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) की धारा 35 के अंतर्गत प्राप्त मामलों पर कार्रवाई करना।
12. राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी अध्ययन और जनशक्ति को प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन और जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों, संस्थानों तथा कार्पोरेट निकायों को वित्तीय तथा अन्य सामग्री संबंधी सहायता देना।
13. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विदेश मंत्रालय के परामर्श करके निम्नलिखित मामलों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित मामले :-
 - (i) अन्य देशों और अंतः सरकारी एजेंसियों के अनुसंधान संगठनों से संबंधित मामले विशेष रूप से जो अन्य कार्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय पहलुओं से संबंधित हैं।
 - (ii) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों के तहत कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी-विदों को प्रशिक्षण और विदेशी छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए विदेश स्थित विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और अनुसंधान-उन्मुख संस्थाओं के साथ व्यवस्था करना।
14. विभाग के बजट से निर्माण कार्य करना और भूमि खरीदना जो विभाग के बजट के नामे डाले जाते हैं।
15. विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले।
16. इस विभाग के बजट से सभी प्रकार के भंडारों, उपकरणों और सेवाओं का अर्जन।

17. विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरिया।
18. राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पहलुओं को प्रभावित करने वाले कार्यकलापों से संबंधित भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, एजेंसी के साथ समझौता अथवा व्यवस्था करके इस विभाग को सौंपे गए और इस विभाग द्वारा स्वीकार किए गए कोई भी अन्य कार्य।

घ भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

1. भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मामले, जिनमें पेंशनभोगी भी शामिल हैं।
2. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना।
3. पुनर्वास महानिदेशालय तथा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से संबंधित मामले।
4. निम्नलिखित का प्रशासन :
 - (क) सेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और 2);
 - (ख) वायुसेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और 2);
 - (ग) नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964; और
 - (घ) सशस्त्र सैन्य कार्मिकों को हताहत पेंशनरी अवाडों के हकदारी विनियम, 1982

ङ रक्षा (वित्त) प्रभाग

1. सभी रक्षा मामलों की वित्त संबंधी जांच करना।
2. रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालयों के विभिन्न अधिकारियों को वित्तीय सलाह देना।
3. रक्षा मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के रूप में कार्य करना।
4. व्यय संबंधी सभी योजनाओं/प्रस्तावों को तैयार करना और उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।
5. रक्षा योजनाएं तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।

6. रक्षा सेनाओं के लिए रक्षा बजट और अन्य प्राक्कलन, रक्षा मंत्रालय के सिविल प्राक्कलन, रक्षा पेंशनरों के संबंध में प्राक्कलन तैयार करना और बजट के अनुरूप योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखना।
7. बजट बनाने के बाद यह सुनिश्चित करना कि व्यय न तो बहुत कम हो और न ही अनपेक्षित रूप से अधिक हो।
8. सशस्त्र सेना मुख्यालयों की शाखाओं के प्रमुखों को अपने वित्तीय दायित्व का निर्वाह करने के लिए सलाह देना।
9. रक्षा सेवाओं के लिए लेखा प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
10. रक्षा सेवाओं के लिए विनियोजन लेखा तैयार करना।
11. रक्षा लेखा महानियंत्रक के माध्यम से रक्षा व्यय के भुगतानों और आंतरिक लेखापरीक्षा के दायित्व का निर्वाह करना।

1 जनवरी, 2017 से आगे पदासीन मंत्री, सेनाध्यक्ष और सचिव

रक्षा मंत्री

श्री मनोहर पर्रीकर
श्री अरुण जेटली
श्रीमती निर्मला सीतारमण

09 नवम्बर, 2014 से 13 मार्च, 2017
13 मार्च, 2017 से 03 सितम्बर, 2017
03 सितम्बर, 2017 से आगे

रक्षा राज्य मंत्री

श्री सुभाष रामराव भामरे

05 जुलाई, 2016 से आगे

रक्षा सचिव

श्री जी मोहन कुमार,
25 मई, 2015 से 24 मई, 2017

सेनाध्यक्ष

जनरल बिपिन रावत,
यूवाईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम
01 जनवरी, 2017 से आगे

श्री संजय मित्रा

25 मई, 2017 से आगे

सचिव रक्षा उत्पादन

श्री अशोक कुमार गुप्ता
25 मई, 2015 से 31 अक्टूबर, 2017

नौसेनाध्यक्ष

एडमिरल सुनील लांबा,
पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी
01 जून, 2016 से आगे

डॉ. अजय कुमार

01 दिसम्बर, 2017 से आगे

सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण

श्री प्रभुदयाल मीणा
01 नवम्बर, 2014 से 31 जुलाई, 2017

वायुसेनाध्यक्ष

एयर चीफ मार्शल वीएस धनोआ,
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएम, एडीसी
01 जनवरी, 2017 आगे

सुश्री संजीवनी कुट्टी

31 जुलाई, 2017 से आगे

सचिव (रक्षा अनुसंधान एवं विकास)

डॉ. एस क्रिस्टोफर
29 मई, 2015 से आगे

रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार

श्री जी सतीश रेड्डी
05 जून, 2015 से आगे

सचिव रक्षा वित्त

श्री एस.के. कोहली
30 सितम्बर, 2016 से आगे

कार्यकारी सारांश

प्रति वर्ष 25 लाख से अधिक पेंशनरों को रक्षा पेंशन का वितरण किया जाता है, जिसके लिए 60,000 करोड़ से अधिक का वार्षिक व्यय होता है। रक्षा पेंशन प्रबंधन प्रणाली मुख्यतः चार स्तंभों पर आधारित है, जिसमें अभिलेख कार्यालय, जो सेवा अभिलेखों का अनुरक्षण करते हैं, पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी, पेंशन एजेंसियां और आर बी आई, जो सरकार के रोकड़ शेष की देखरेख करता है और पेंशनरों को बैंकों द्वारा वितरित पेंशन की प्रतिपूर्ति करता है, सम्मिलित हैं।

रक्षा लेखा महानियंत्रक, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत इलाहाबाद और मुंबई स्थित रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रकों (नौसेना के लिए) तथा रक्षा लेखा नियंत्रक, नई दिल्ली (वायु सेना के लिए) द्वारा पेंशन संस्वीकृति की जाती है। रक्षा लेखा विभाग के रक्षा पेंशन वितरण कार्यालयों (डी पी डी ओ), बैंकों, भारतीय दूतावास, नेपाल, राज्य कोषागारों, भुगतान एवं लेखा कार्यालयों और डाकघर, कटुआ (जम्मू और कश्मीर) द्वारा पेंशन का वितरण किया जाता है।

हमने यह समीक्षा क्यों की?

यह समीक्षा रक्षा पेंशन प्रणाली के चार स्तंभों अर्थात् अभिलेख कार्यालयों, पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों (पी एस ए), पेंशन वितरण एजेंसियों (पी डी ए) और भारतीय रिजर्व बैंक में विद्यमान बजटिंग, लेखाकरण तथा आंतरिक नियंत्रणों सहित पेंशन वितरण प्रणाली की कार्यक्षमता एवं प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए की गई। इस समीक्षा का उद्देश्य विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी प्रयुक्तियों सहित कार्यक्षमता एवं प्रभावकारिता मुद्दों पर रिपोर्ट करना एवं उपयुक्त सिफारिशें करना था।

प्रमुख निष्कर्ष

1. पेंशन व्यय का अपूर्ण लेखाकरण

हमने देखा कि पेंशन भुगतान स्कॉल, जिसके आधार पर रक्षा लेखा

प्रधान नियंत्रक, पेंशन (पी सी डी ए (पी) अंतिम लेखा शीर्ष में राशियां बुक करता है, प्रदान करने में बैंकों की असमर्थता के कारण प्रत्येक वर्ष व्यय की बड़ी राशि को पेंशन लेखा शीर्ष में बुक नहीं किया गया था तथा वह आर बी आई उच्चत शीर्ष में पड़ी थी। इसके फलस्वरूप पेंशन लेखाओं का गलत अंकन तथा सरकारी राजस्व घाटा संबंधी आंकड़ों के लिए आपत्तियां उपस्थित हुईं। मार्च 2016 के अंत तक उच्चत शीर्ष में पड़ी संचित राशि 6,831.95 करोड़ रुपए थी।

(पैराग्राफ 2.3)

2. पेंशन प्राधिकरण प्रक्रिया में अक्षमताएं

हमने देखा कि पेंशन के प्राधिकरण की प्रक्रिया में अनेक भागीदार एवं बहुत चरण सम्मिलित हैं, जिसके फलस्वरूप प्रायः पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ) जारी करने में परिहार्य विलंब होते हैं। प्राधिकरण प्रक्रिया की समीक्षा की आवश्यकता है, जिससे कि वह कम बोझिल व कम समय लेने वाला हो।

हमने यह भी देखा कि यद्यपि अभिलेख कार्यालयों, पी एस ए और पी डी ए में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना ली जा रही है, किंतु उनके एकीकरण के अभाव के कारण सूचना का अकार्यक्षम प्रवाह होता है, जिसमें प्रतिलेखन त्रुटियों एवं पेंशन भुगतानों में परिणामी त्रुटियों की संभावना रहती है।

(पैराग्राफ 3.2)

3. पेंशन वितरण प्रणाली में कमियां

हमने देखा कि बैंकों में जो कि कुल पेंशन का लगभग 75 प्रतिशत पेंशन वितरण करते हैं, होने वाले प्रेषण त्रुटियों तथा अन्य गलतियों के परिणामस्वरूप अल्प भुगतानों और अधिक भुगतानों के अनेक मामले उत्पन्न हुए थे। देखे गए मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे:

(क) हमने एक महीने की नमूना जांच के आधार पर 21,434 पेंशनरों के मामलों की पहचान की, जिनको 106.17 करोड़ रुपए तक अल्प भुगतान किया गया था। अल्प भुगतानों के लिए मुख्य कारण पेंशनों का गैर संशोधन/ गलत संशोधन, पेंशन के रूपांतरित अंश का पुनः स्थापन न किया जाना, अशक्तता घटक का गलत संशोधन और स्थायी चिकित्सा भत्ता का गैर-संशोधन थे। 2011-12 से 2015-16 की अवधि से संबंधित थोक डाटा के विश्लेषण से 228.85 करोड़ का संभावित अल्प भुगतान सूचित हुआ। इन मामलों की विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 4.2)

(ख) इसी प्रकार, हमने एक महीने के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर 11,973 पेंशनरों को 118.23 करोड़ का अधिक भुगतान देखा। अधिक भुगतान के लिए मुख्य कारण पेंशन का गलत संशोधन, पेंशन के रूपांतरित अंश की गैर-कटौती और स्थायी चिकित्सा भत्ते का अनियमित भुगतान थे। 2011-12 से 2015-16 की अवधि से संबंधित थोक डाटा के विश्लेषण से 518.70 करोड़ का अधिक भुगतान सूचित हुआ। इन मामलों की विस्तृत जांच की आवश्यकता थी।

(पैराग्राफ 4.3)

(ग) हमारी नमूना लेखापरीक्षा से दोहरे भुगतानों के अनेक मामले तथा पेंशन वितरण में अन्य अनियमितताएं जैसे अनेक पेंशनरों की पेंशनों का एक खाते में जमा किया जाना, पेंशन भुगतान आदेशों (पी पी ओ) के बिना पी डी ए द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाना अन्य विभागों के पेंशनरों को रक्षा शीर्ष से पेंशन का भुगतान किए जाने के कुछ उदाहरण आदि देखे गए।

(पैराग्राफ 4.4 एवं 4.5)

(घ) हमने पी डी ए द्वारा अधिदत्त राशियों की उनके द्वारा वसूली करने में विलंबों के उदाहरण भी देखे।

(पैराग्राफ 4.6)

(ङ) पी डी ए द्वारा अनुरक्षित पेंशनरों के थोक डाटा के

विश्लेषण से, अनुरक्षित डाटा में अनेक कमियां जैसे खाता संख्या, नाम या पी पी ओ संख्या का न होना, सिस्टम में दर्ज जन्म तिथि में त्रुटियां, एक ही पी पी ओ के लिए पेंशन का अलग खातों में जमा किया जाना और अलग पी पी ओ के लिए पेंशन का एक बैंक खाते में जमा किया जाना आदि देखी गईं। बैंकों के भुगतान स्कॉलों में उपलब्ध सूचना तथा संस्वीकृति प्राधिकारी अर्थात् पी सी डी ए द्वारा अनुरक्षित सूचना के बीच बेमेलपन भी था।

(पैराग्राफ 4.7)

(च) रक्षा पेंशन वितरण कार्यालयों द्वारा प्रयुक्त आश्रय सोफ्टवेयर में वैधीकरण जांचों का अभाव और सूचना की अनुपलब्धता भी देखी गई।

(पैराग्राफ 4.8)

(छ) स्रोत पर आयकर की गैर-कटौती के अनेक मामले थे।

(पैराग्राफ 4.9)

4. नियंत्रण में कमियां

हमने पेंशन वितरण प्रणाली के सभी चार स्तंभों में नियंत्रण में कमियां देखीं, जिसने प्रणाली की कार्यक्षमता और प्रभावकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। नियंत्रण में कुछ प्रमुख कमियां निम्नलिखित थीं:

(क) इकाइयों से सूचना की प्राप्ति में होने वाले विलंब से पेंशन मामलों के प्रसंस्करण में विलंब हुए।

(पैराग्राफ 5.1)

(ख) पी सी डी ए (पी) में नियंत्रण की कमियों में पेंशनरों की वास्तविक संख्या संबंधी सूचना अनुरक्षित करने में नियंत्रणों का अभाव, सही लेखाकरण पर नियंत्रण का अभाव, अधिक भुगतानों, कपटपूर्ण भुगतानों और विदेशी दावों की अपर्याप्त लेखापरीक्षा और अपर्याप्त निगरानी आदि सम्मिलित थीं।

(पैराग्राफ 5.2)

(ग) इसी प्रकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों ने पेंशन का सही वितरण किया और उनके द्वारा किए गए

वितरणों के लेखे समय पर प्रस्तुत किए, आर बी आई के पास कमजोर और कम नियंत्रण थे। इसका उदाहरण यह तथ्य था कि 2011-12 से 2015-16 के दौरान आर बी आई द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा (बी ओ बी) को प्रतिपूर्ति की गई राशि और पेंशनरों को बी ओ बी द्वारा दत्त राशि में 179.55 करोड़ रुपए का अंतर था।

(पैराग्राफ 5.3)

5. प्रमुख सिफारिशें

लेखा परीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर हमारे द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

- पी सी डी ए (पी) को भुगतान स्कॉल की प्रस्तुति के प्रमाण की शर्त पर आर बी आई को बैंकों को प्रतिपूर्ति करनी चाहिए। दूसरी ओर, आर बी आई को चाहिए कि वह पी सी डी ए (पी) इलाहाबाद को इलेक्ट्रॉनिक स्कॉल (ई-स्कॉल) प्रस्तुत न करने के लिए वित्तीय निरुत्साहन प्रवर्तन में लाए।
- जबकि पेंशन के सामयिक प्राधिकरण के लिए वर्तमान निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए, वर्तमान प्रक्रिया की समीक्षा यह देखने के लिए कि यदि उसे कम बोझिल और कम समय लेने वाला बनाने के लिए सरल बनाया जा सकता था, की जानी चाहिए। पेंशन संस्वीकृत करने के लिए कार्यालयाध्यक्षों को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों सहित गैर-रक्षा, सिविल पेंशन पक्ष से सीखे गए सबक को अपनाने की संभावना खोजी जा सकती है।
- पी सी ए द्वारा पी पी ओ इलेक्ट्रॉनिक रूप में सीधे पी डी ए को प्रेषित किए जाने चाहिए।
- उचित वैधीकरण और सुरक्षा जांचों के साथ, सुरक्षित ढंग से सूचना के स्वचालित प्रवाह को समर्थ बनाने हेतु तीन स्तंभों- अभिलेख कार्यालयों, पी एस ए तथा पी डी ए- को ऑनलाइन संयोजित किया जाना चाहिए।
- अल्प एवं अधिक भुगतानों सहित, विचलनों की समय पर खोज करने और उचित सुधारात्मक कार्रवाई हेतु पी सी डी ए (पी) को स्कॉलों की समग्र ई-लेखापरीक्षा

कार्यान्वित करनी चाहिए।

- अभिलेख कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित मूल प्रोफाइल में पैन (पी ए एन) नंबर प्रविष्टि किया जाना चाहिए और टी डी एस को आसान बनाने हेतु प्रेषण श्रृंखला के माध्यम से पी डी ए तक पहुंचना चाहिए।
- पी डी ए को जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का एक दुविधा-रहित तरीका पेंशनरों को प्रदान करने हेतु सरकार की जीवन प्रमाण पहल का लाभ उठाने के लिए ई-आधार नंबर लिया जाना चाहिए।

विहंगावलोकन

वर्ष 2015-16 के दौरान रक्षा सेवाओं का कुल व्यय 2,43,534 करोड़ रुपए था। इसमें से भारतीय वायुसेना (आईएएफ) ने 53,047 करोड़ रुपए खर्च किए जो रक्षा सेवाओं पर कुल व्यय का 21.78 प्रतिशत था। आईएएफ के व्यय का प्रमुख भाग जो प्रकृति में पूंजीगत था उनके कुल व्यय का 58.81 प्रतिशत था।

यह प्रतिवेदन आईएएफ के वित्तीय लेनदेन तथा रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग, सैन्य अभियांत्रिक सेवाओं (एमईएस), रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) व उसकी मुख्यतः वायुसेना से संबंधित प्रयोगशालाओं के वायुसेना से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा से उद्भूत मामलों से संबंधित है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने से उपरांत 21.57 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई। प्रतिवेदन में शामिल निष्कर्षों के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार से हैं :-

I. 'एस' क्षेत्र में स्ट्रैटजिक मिसाइल प्रणाली का स्थापन

खतरे की अनुभूति को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने आवश्यक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए 'एस' क्षेत्र में स्ट्रैटजिक मिसाइल का स्थापन अनुमोदित किया। 2013 तथा 2015 के मध्य मिसाइल प्रणाली छः निर्धारित स्थलों पर स्थापित की जानी थीं। किन्तु अब तक कोई भी मिसाइल प्रणाली स्थापित नहीं हुई है। 3,619.25 करोड़ में मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से अधिप्राप्त मिसाइल प्रणाली के स्थापन में विलम्ब का मुख्य कारण स्थलों पर सिविल कार्यों में विलम्ब था।

(पैराग्राफ 2.1)

II. जगुआर वायुयान पर ऑटोपायलटों का स्थापन

1197 में 108 जगुआर वायुयान हेतु भारतीय वायुसेना (आईएएफ) द्वारा परियोजित 108 ऑटोपायलटों की आवश्यकता के विपरीत अगस्त 1999 में निर्धारित अनुबंध के माध्यम से 2006 तथा 2008 के मध्य मात्र 35 ऑटोपायलट अधिप्राप्त किए गए। 95 ऑटोपायलटों हेतु पुनरावृत्त अनुबंध मार्च 2014 में निर्धारित किया जा सका। पहले अधिप्राप्त 35 ऑटोपायलटों में से मार्च 2017 तक मात्र 18 ऑटोपायलट जगुआर वायुयान से एकीकृत किए जा सके। एकीकृत ऑटोपायलट भी उनके महत्वपूर्ण घटक अर्थात् ऑटोपायलट इलेक्ट्रॉनिक यूनिट (एपीईयू) की खराबी के कारण यथासंभव सर्वोत्तम कार्य नहीं कर रहे थे। पुनरावृत्त अनुबंध के माध्यम से प्राप्त 30 ऑटोपायलट अभी एकीकृत किए जाने हैं। इस प्रकार, 1997 में आईएएफ द्वारा जगुआर वायुयान के लिए परिकल्पित उड़ान सहायक क्षमता 20 वर्षों के उपरांत भी अधिकांशतः यथार्थ रूप से ग्रहण न कर सका।

(पैराग्राफ 2.2)

III. मिनी क्रैश फायर टैंडर्स की समय से पूर्व अधिप्राप्ति

आईएएफ ने 'सी' कमान में आठ अग्रवर्ती लैंडिंग ग्राउण्ड (एएलजी) पर अवसंरचना कार्यों के पूरा होने से बहुत पहले 31.34 करोड़ रुपए की लागत पर मिनी क्रैश फायर टैंडर्स (सीएफटी) अधिप्राप्त किए। यह इन सीएफटी की सुपुर्दगी से, तीन वर्षों से अधिक के लिए निम्न उपयोग में फलीभूत हुआ तथा 2016 में संबद्ध एएलजी में मात्र पांच सीएफटी तैनात थे।

(पैराग्राफ 2.3)

IV. एयरो-इंजनों के ओवरहॉल में विलम्ब

2013 तथा 2014 के दौरान, ओवरहॉल तथा जीवनावधि-विस्तार करने के लिए एयरो इंजनों की अनुबंधित मात्रा को विदेश न भेजा जाना, ग्राउण्डेड हेलिकॉप्टरों को उपयोग में न लाए जाने का कारण बना। इसके अतिरिक्त, परवर्ती वर्षों में ओवरहॉल की उच्च दरों के कारण 3.86 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.4)

V. 'एस' क्षेत्र में रेकि क्षमता की सीमाबद्धता

'एस' क्षेत्र में सर्वेक्षण (रेकि) तथा निगरानी क्षमता वायुसेना स्टेशन 'बीबी' में सहयोग तथा अनुरक्षण सुविधाओं के निर्माण में विलम्ब के कारण प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त, 2011-16 के दौरान 34.40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ क्योंकि 'एस' क्षेत्र में रेकि मिशन वायु सेना स्टेशन 'सीसी' से कार्यान्वित करने पड़े।

(पैराग्राफ 2.5)

VI. वायुसेना बेसों पर अण्डर व्हीकल स्कैनिंग प्रणालियों की गैर-कार्यात्मकता

भारतीय वायुसेना ने 50 वायुसेना बेसों के प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा सशक्त करने के लिए मार्च 2012 से नवम्बर 2012 के दौरान 17.09 करोड़ रुपए की लागत पर 57 अण्डर व्हीकल स्कैनिंग (यूवीएस) प्रणालियां अधिप्राप्त की। अब तक मात्र 17 यूवीएस प्रणालियां कार्यशील हैं।

(पैराग्राफ 2.6)

VII. आईएल श्रृंखला वायुयान की सेवायोग्यता तथा अनुरक्षण

भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के आईएल फ्लीट की सेवायोग्यता कम थी जिसके कारण, सर्विसिंग तथा मरम्मत में विलम्ब था। पुर्जों की कम उपलब्धता तथा मूल उपस्कर निर्माताओं (ओईएम) के साथ अनुरक्षण सहयोग अनुबंध हस्ताक्षर करने में आईएएफ द्वारा विलम्ब था। आईएल फ्लीट की वैमानिकी को उन्नत नहीं किया गया है, परिणामस्वरूप, वे 1985 की पुरानी वैमानिकी के साथ उड़ रहे हैं। आईएल-76 वायुयान की पहली तथा दूसरी ओवरहॉल संचालित करने में विलम्ब था, जिसका अभिप्राय है कि वायुयान, ओवरहॉल हेतु नियत तिथि के बहुत बाद तक, ओवरहॉल के बिना उड़ रहे थे। युद्ध के साथ-साथ शांति कालीन परिचालनों, दोनों के दौरान वायु में पुनः ईंधन भरना (एएआर) का महत्वपूर्ण क्षमता है। आईएल-78 वायुयान इस प्रयोजन हेतु समर्पित हैं। तथापि, अपर्याप्त अवसंरचना तथा सहयोगी सुविधाओं के कारण, वायु से वायु में पुनः ईंधन भरने की क्षमता बाधित हुई थी।

(पैराग्राफ 2.7)

VIII. 'डी' स्तरीय सुविधा की गैर-परिचालनात्कता

'डी' स्तरीय सुविधा हेतु मंत्रालय/भारतीय वायु सेना की ओर से, एएन-32 वायुयान की पुनः उपकरण/वैमानिकी (आरई) प्रणालियों हेतु तकनीकी के हस्तान्तरण (टीओटी) की उपलब्धता को, अनुबंध/अनुलग्नक के समापन से पहले सुनिश्चित करने में उपयुक्त सावधानी की कमी के परिणामस्वरूप विभिन्न मूल उपकरण निर्माताओं पर निर्भरता बनी रही तथा सेवायोग्यता एवं वित्तीय सरोकारों सहित मरम्मत योग्य सामान संचित हुआ।

(पैराग्राफ 2.8)

IX. भारतीय वायुसेना में अधिकारियों द्वारा विदेशों हेतु उनके निजी दौरों के दौरान एलटीसी का अनियमित उपभोग

भारतीय वायुसेना में अधिकारी व्यक्तिगत आधारों पर अवकाश पर विदेश जाने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमोदन ले रहे थे। यद्यपि, वे संस्वीकृत अवकाश की अवधि के दौरान विदेश की यात्रा पर गये, उसी अवधि में उन्हें भारतीय शहरों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) का उपयोग करने दिया गया, जहां का दौरा उन्होंने नहीं किया था। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विदेशी गंतव्य की यात्रा हेतु एलटीसी की अनुमति तथा 82.58 लाख रुपए का भुगतान अनियमित था तथा रक्षा यात्रा विनियमों में समाविष्ट एलटीसी के प्रावधान का पूरी तरह से उल्लंघन था।

(पैराग्राफ 2.9)

विहंगावलोकन

वर्ष 2015-16 के दौरान रक्षा सेवाओं का कुल व्यय 2,43,534 करोड़ रुपए था। इसमें से, नौसेना ने 35,196 करोड़ रुपए खर्च किए जबकि तटरक्षक ने 3,034 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि कुल रक्षा व्यय का लगभग क्रमशः 14.45 प्रतिशत तथा 1.25 प्रतिशत था। नौसेना के व्यय का मुख्य भाग पूंजीगत स्वरूप का है, जो कुल व्यय का लगभग 56.47 प्रतिशत है जबकि तटरक्षक का कुल व्यय पूंजीगत एवं राजस्व शीर्षों के बीच समान रूप से प्रत्येक के लिए 1,517 करोड़ वितरित किया गया था।

इस प्रतिवेदन में भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक के लेन-देन की लेखापरीक्षा से उद्भूत मुख्य निष्कर्ष शामिल किए

गए हैं। प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुछ मुख्य निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

I. भारतीय नौसेना में नौसैनिक भण्डार तथा उपकरण एवं अतिरिक्त पुर्जों के इनवेंट्री प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

सामग्री नियोजन में जिम्मेदारी के कई क्षेत्र हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, इनवेंट्री प्रबंधन और मुद्दा प्रबंधन हैं। इनवेंट्री वहन की लागत को कम करने के लिए अच्छी इनवेंट्री प्रबंधन महत्वपूर्ण है। एकीकृत रसद प्रबंधन तंत्र के रूप में स्वचालन के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रावधानीकरण और निरंतर सुधार में सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो एक ऑन-लाइन, डेटा से जुड़े कंप्यूटर तंत्र द्वारा नौसेना की सामग्री नियोजन का समर्थन करते हैं।

प्रणाली आधारित प्रोविजनिंग फार्मूला द्वारा सृजित अधिप्राप्ति मात्रा अधिक थी तथा अनुमानित मात्रा, विद्यमान फार्मूले में बीजगणितीय विसंगति के कारण तीन से छः वर्षों के वार्षिक उपभोग की आवश्यकता के समान थी। भारतीय नौसेना में इनवेंट्री कंट्रोल मैकेनिज्म की कमी इस सीमा तक है कि एबीसी वर्गीकरण मानदंडों का पालन नहीं किया गया था। यह इनवेंट्री के अधिकतम और न्यूनतम स्टॉक स्तर की समीक्षा प्रावधान और मूल्यांकन की गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। मांगपत्रों के प्रसंस्करण के लिए निर्धारित समय का पालन नहीं किया गया था जो भंडारों की खरीद में व्यापक प्रभाव का कारण था। मालिकाना हक प्रमाण पत्र और एकल संविदा जांच के तहत खरीदी गई मर्दे, खुली निविदा पूछताछ और दर संविदाओं के तहत खरीदे गए मर्दों की तुलना में काफी अधिक थे, जिससे कम प्रतिस्पर्धा/एकाधिकार की स्थिति हो गई थी। 46.92 करोड़ रुपए की अप्रचलित मर्दों की खरीद का निर्णय करते समय यथोचित परिश्रम की कमी का संकेत मिला। सामग्री संगठनों में औसत मांग अनुपालन लगभग 70 प्रतिशत था। ऊपरी स्टॉक स्तर से ज्यादा सामग्री संगठनों द्वारा 7359.37 करोड़ के मूल्य की इनवेंट्री रखी हुई थी जिसके परिणामस्वरूप भंडारों की खराबी और अप्रचलन से संबंधित जोखिम के साथ प्रतिवर्ष 588.75 करोड़ रुपए की इनवेंट्री वहन की लागत का दायित्व हुआ।

(अध्याय-II)

II भारतीय नौसेना में पोतों एवं पनडुब्बियों की दुर्घटनाएं

एक पोत/पनडुब्बी की हानि भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि नए पोतों/पनडुब्बियों के अधिग्रहण में आठ से दस वर्षों से अधिक की खरीद/निर्माण प्रक्रिया शामिल रहती है। इसलिए, यह अनिवार्य है कि भारतीय नौसेना शांति के समय में दुर्घटनाओं से अपनी संपत्ति को मुक्त रखे। 2007-2008 और 2015-16 के बीच भारतीय नौसेना के पोतों और पनडुब्बियों में मुख्य रूप से आग/विस्फोट/बाढ़ के कारण 38 दुर्घटनाएं हुईं। इन दुर्घटनाओं में दो नौसैनिक पोतों और एक पनडुब्बी के अलावा बहुमूल्य जीवन की हानि हुई। भारतीय नौसेना की स्थापना के बाद से, सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए कोई संस्थागत रूपरेखा नहीं है। सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा एक समर्पित संगठन 2014 में स्थापित किया गया था, हालांकि इसके लिए सरकार की संस्वीकृति प्रतीक्षित है।

(पैराग्राफ 3.1)

III समुद्री गैस टर्बाइन की ओवरहॉल सुविधा की स्थापना

आई.एन.एस एक्सिला 1991 से एम3ई जी.टीज़ का ओवरहॉल कर रहा है, लेकिन जी.टीज़ के ओवरहॉल के पूरा होने में अन्य बातों के साथ-साथ, पुर्जों और जनशक्ति की अनुपलब्धता के कारण असामान्य विलंब का सामना करना पड़ रहा है। एम-15 जी.टीज़ के ओवरहॉल के लिए आवश्यक सुविधाएं अभी तक पूरी नहीं हुई थीं, हालांकि इस सुविधा को स्थापित करने की योजना 1986 के बाद से की गई थी। इस बीच, 1241 आर.ई श्रेणी के बारह पोतों में से दो, जिनमें एम-15 जी.टीज़ को काम में लाया जाता था, को अप्रैल 2006 तक सेवामुक्त कर दिया गया था। 2008 में नियोजित एम-36 जी.टीज़ के लिए ओवरहॉल की सुविधा में उपकरणों की खरीद और निर्माण कार्यों के बीच समकालीनता की कमी के कारण देरी हुई। परिणामतः, नौसेना जी.टीज़ के ओवरहॉल के लिए ओ.ई.एम पर आगे भी निर्भर रही, जिसमें 317.77 करोड़ का व्यय हुआ। लम्बी अवधि के लिए मानवशक्ति को न रखने के कारण, आई.एन.एस एक्सिला तकनीकी उपलब्धता से जुझ रही है।

(पैराग्राफ 3.2)

IV यू.ए.-3 एच हेलीकॉप्टरों का संचालन और रखरखाव

लैंडिंग प्लेटफार्म डेक के एक अभिन्न अंग के रूप में खरीदे गए हेलीकॉप्टरों के यू.एच-3एच बेड़े, स्ववाङ्गन की चार से तीन हेलीकॉप्टरों की यूनिट स्थापना में कमी के बावजूद सात में से छः वर्षों में इसकी सेवाकारिता के वांछित स्तर को बनाए रखने में असमर्थ थे। स्पष्ट लक्ष्यों के अभाव में, डेक आधारित उड़ान काफी कम रही। समर्पित डिपो स्तर की रखरखाव सुविधाओं के न होने और पुर्जों की अनुपलब्धता का बेड़े के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, नौसेना कर्मियों के प्रशिक्षण की कमी के कारण नौसेना रखरखाव, मरम्मत कार्य और रसद मुद्दों के लिए विदेशी मरम्मत एजेंसी पर लगातार निर्भर है।

(पैराग्राफ 3.3)

V पेरिस्कोपों की स्थापना के विलम्ब के कारण सिन्धुघोष वर्ग की पनडुब्बियों का जोखिम भरा उपयोग

पेरिस्कोपों की आपूर्ति के लिए आवश्यक विक्रेता के स्वामित्व में विस्तार के संबंध में अनुबंध में संशोधन करने की मंत्रालय की अनुमति प्रदान करने में की गयी 34 महीनों से अधिक की देरी के कारण पेरिस्कोपों की आपूर्ति करने तथा सिन्धुघोष वर्ग की पनडुब्बियों की स्थापना करने में विलम्ब हुआ। इसके परिणामस्वरूप अगले रीफिट तक 22 से 62 महीनों के लिए पनडुब्बियों का जोखिम भरा उपयोग किया गया।

(पैराग्राफ 3.4)

VI अनिवार्य तंत्रा की स्थापना न करने के कारण विमानों की उड़ान सुरक्षा से समझौता

भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक के विमानों पर एक महत्वपूर्ण उड़ान सुरक्षा उपकरण की अनुपलब्धता ने विगत 12 वर्षों से उनका सुरक्षित परिचालन प्रभावित किया। उपकरण की सुपुर्दगी समयावधि एवं विमान पर उसकी स्थापना में तालमेल न होने के कारण और चार वर्षों के लिए भी यही स्थिति बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त, एक विमान बेड़े का सेवामुक्ति को संज्ञान में लेने में विफलता के परिणामस्वरूप 5.58 करोड़ रुपए की लागत पर 10 उपकरणों की अधिक खरीद हुई।

(पैराग्राफ 3.5)

VII ऑफसेट दायित्व के फलन में देरी के कारण बेड़े के टैंकरों का भेद्य होना

बेड़े के टैंकरों की, 2011 में उनकी सुपुर्दगी से लेकर, रक्षा प्रणालियों की अनुपलब्धता ने उनको वाह्य खतरों के प्रति भेद्य बना दिया। इसके साथ, दो बेड़े के टैंकरों की संविदा के ऑफसेट/स्थापना से भुगतान का संबंध न होने के परिणामस्वरूप विदेशी विक्रेता को 26.73 करोड़ रुपए का समयापूर्व भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.6)

VIII दिल्ली क्षेत्र में नौसैनिक अधिकारियों द्वारा लघु-शस्त्र फायरिंग अभ्यास की कमी

सभी भारतीय नौसेना कार्मिकों से अपेक्षित है कि उन्हें सभी प्रकार के लघु शस्त्रों के संचालन की प्रक्रिया का ज्ञान हो। यह देखा गया कि दिल्ली क्षेत्र में अभ्यास फायरिंग में नौसैनिक अधिकारियों का कवरेज कम था जो लघु-शस्त्रों के संचालन में उनकी योग्यता के बारे में चिन्ताजनक था।

(पैराग्राफ 3.7)

IX एक हेलीकॉप्टर बेड़े के लिए एयरो इंजन की अवांछित अधिप्राप्ति

भारतीय नौसेना ने दुर्घटना में क्षतिग्रस्त दो हेलीकॉप्टरों के लिए चार एयरो इंजनों की अधिप्राप्ति का आदेश देते समय, अनुबंध करने से पूर्व किफायती मरम्मत से परे (बी.ई.आर) घोषित एक हेलीकॉप्टर तथा ओवरहॉल के पश्चात प्राप्त 16 एयरो इंजनों को ध्यान में नहीं रखा। यद्यपि, इन अधिक इंजनों को बाद में पांच हेलीकॉप्टरों की अधिप्राप्ति में मिला लिया था, तथापि एक अन्य हेलीकॉप्टर की बी.ई.आर घोषणा के परिणामस्वरूप तीन एयरो इंजनों की इन्वेन्ट्री धारिता उनके अनुमोदन से अधिक हो गई तथा इन तीन अधिक एयरो इंजनों की अधिप्राप्ति पर 16.62 करोड़ रुपए का अनुत्पादक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.8)

X एक मोबाइल के लिए मोबाइल सैटेलाइट सर्विस टर्मिनल की परिहार्य अधिप्राप्ति एवं स्थापना

भारतीय नौसेना की टी.यू-142एम विमान बेड़े की सेवामुक्ति योजना का संज्ञान लेने में विफलता के परिणामस्वरूप 0.95 करोड़

रुपए की लागत पर विमान के लिए अतिरिक्त मोबाइल सैटेलाइट सर्विस (एम.एस.एस) टर्मिनल की अधिप्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त, 2017 तक अन्य तीन विमानों को सेवामुक्त करने के कारण इन विमानों पर एम.एस.एस टर्मिनलों की स्थापना बड़े पैमाने पर निष्फल हो जाएगी।

(पैराग्राफ 3.9)

XI डोर्नियर विमानों के लिए मौसम राडारों की अधिप्राप्ति

मौसम राडारों के लिए अधिप्राप्ति के भाग के रूप में एक महत्वपूर्ण संघटक अर्थात्, प्रदर्शन यूनिटों की आपूर्ति न होने से डोर्नियर विमान बेड़े का परिचालन उपयोग प्रभावित होता है।

(पैराग्राफ 3.10)

XII चावल की खरीद पर परिहार्य व्यय

सूखे राशन के प्रावधान और खरीद पर मौजूदा नीति की अवहेलना करते हुए, भारतीय नौसेना ने दिल्ली क्षेत्र में नौसैनिक दल के लिए चावल की स्थानीय खरीद का सहारा लिया, जिससे चावल की खरीद में 0.89 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.11)

XIII एक पोत निर्माणी को विदेशी विनिमय दर में अन्तर के कारण 5.23 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान

भारतीय तटक्षक ने संविदागत प्रावधानों की गलत व्याख्या के कारण विदेशी विनिमय दर में अन्तर के रूप में मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा को 5.23 करोड़ रुपए का भुगतान किया।

(पैराग्राफ 4.1)

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए थल सेना, आयुध निर्माणियां, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सैन्य अभियंता सेवाएं तथा सीमा सड़क संगठन से संबंधित रक्षा मंत्रालय की परियोजनाओं/स्कीमों की वित्तीय लेनदेन की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन समीक्षाओं के परिणाम समाविष्ट हैं।

प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष संक्षिप्त रूप से इस प्रकार हैं:—

विवाहितों के लिए आवास परियोजना महानिदेशालय (एम ए पी) का कार्यचालन

रक्षा सेना कार्मिकों के लिए विवाहितों के आवास की कमी को दूर करने हेतु शीघ्र तथा समयबद्ध तरीके से आवासों का निर्माण करने के लिए एक विशेष संगठन के रूप में विवाहितों के लिए आवास परियोजना महानिदेशालय (डी जी एम ए पी) का गठन किया गया था। निदेशालय की लेखापरीक्षा से पता चला कि 1,98,881 आवास यूनिटों (डीयू), जिनका 2002 से लेकर प्रत्येक चार वर्ष के चार चरणों में निर्माण किया जाना था, उसके लक्ष्य के प्रति मार्च 2016 तक केवल 80,692 डी यू का ही निर्माण किया गया था। स्टेशनों का गलत वरीयता निर्धारण, आवास की कमी का गलत निर्धारण तथा प्राधिकरण से अधिक आवास के निर्माण ने इस कमी के प्रभाव को अधिक तीव्र बनाया।

(पैराग्राफ 2.1)

जेली फिल्ड केबिल की अधिप्राप्ति में हानि

महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (डी जी क्यू ए) से परीक्षण के आयोजन, जिनकी सुविधा उनके पास उपलब्ध नहीं है, के संबंध में स्पष्ट निर्देश के अभाव के कारण जेली फिल्ड केबल के मूल्यांकन के पूरा होने में 15 महीने का अत्यधिक विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप, विक्रेता द्वारा वाणिज्यिक प्रस्ताव में संशोधन किया गया, जिससे 3000 कि.मी. जेली फिल्ड केबिल की अधिप्राप्ति में सरकार को 1.28 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.2)

माइक्रो लाइट वायुयान की अधिप्राप्ति एवं पूर्ण मरम्मत

महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर (डी जी एन सी सी) द्वारा प्रचलित नीति से विचलित होते हुए उपलब्ध माइक्रो लाइट वायुयान के 34 इंजिनों की पूर्ण मरम्मत के लिए, नए इंजिनों की लागत के 50 प्रतिशत से ज्यादा कीमत पर संविदा की गई। इसके अलावा, उपलब्ध बेड़े के कम उपयोग के बावजूद 52.91 करोड़ रुपए की लागत पर 110 अतिरिक्त माइक्रो लाइट वायुयान खरीदे गये।

(पैराग्राफ 2.3)

रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले रेल वैगनों/डिब्बों का प्रबंधन

रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले रेल वैगनों/डिब्बों के प्रबंधन की लेखापरीक्षा में 17 ए सी डिब्बों/सैन्य लंगरों का अधिक स्केलिंग (50 करोड़ रुपए), अग्रिम भुगतान पर ब्याज की हानि (23.87 करोड़ रुपए), सैन्य स्पेशल ट्रेनों के लागत परिकलन में एकरूपता न होने के कारण अधिक भुगतान (30.44 करोड़ रुपए), अतिरिक्त रेल सुविधा (ए आर एफ) परियोजनाओं की निगरानी न करना तथा ए आर एफ परियोजनाओं के कारण रेलवे को दिए गए 356 करोड़ रुपए का असमायोजन जैसी विभिन्न कमियां देखी गईं। इन कमियों के बावजूद, रेलवे द्वारा रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले इन रेल वैगनों/डिब्बों के वाणिज्यिक उपयोग की जांच करने के लिए सेना मुख्यालय में कोई तंत्र नहीं है।

(पैराग्राफ 3.1)

थल सेना में गोलाबारूद प्रबंधन—अनुवर्ती लेखापरीक्षा

थलसेना में गोलाबारूद प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा में गंभीर चिन्ताओं को दर्शाये जाने के बावजूद मार्च 2013 से गोलाबारूद की उपलब्धता में चिन्ताजनक कमी तथा आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ एफ बी) द्वारा आपूर्ति किये गए गोला बारूद की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। ओ एफ बी द्वारा उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने में कमी जारी रही। इसके अलावा ओ एफ बी के अलावा अन्य से अधिप्राप्ति के मामले, जो थलसेना मुख्यालय द्वारा 2009—13 के दौरान शुरू किए गए थे, इनमें से बहुत सारे मामले जनवरी 2017 तक लंबित थे। डी जी क्यू ए द्वारा दोष जांच को पूरा करने में तथा ओ एफ बी द्वारा अस्वीकृत/अप्रयोज्य गोलाबारूद को प्रतिस्थापन/मरम्मत करने में विलंब बने रहे। गोला बारूद डिपों में अग्निशमन कर्मचारियों और उपकरणों की कमी के कारण दुर्घटना होने का खतरा बना रहा।

(पैराग्राफ 3.2)

सैन्य स्टेशन में लगे मोबाइल टावरों के संदर्भ में किराए एवं प्रीमियम की गैर वसूली के कारण हानि

चण्डीमंदिर सैन्य स्टेशन में निजी टेलीफोन कंपनियों के 13 मोबाइल टावरों को रक्षा मंत्रालय के अपेक्षित अनुमोदन के बिना ही लगा दिया गया, जिससे किराए एवं प्रीमियम की गैर वसूली के कारण 4.33 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(पैराग्राफ 3.4)

बेमेल उपकरण की अधिप्राप्ति पर व्यर्थ व्यय

सेना कमांडर को प्राप्त विशिष्ट वित्तीय शक्तियों के उपयोग से उत्तरी कमान में तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1.26 करोड़ रुपए की लागत पर अधिप्राप्ति की गयी आउटबोर्ड मोटर्स (ओ बी एम) का उपयोग नहीं किया जा सका। सात वर्षों में की गयी आउटबोर्ड मोटर्स (ओ बी एम) का उपयोग नहीं किया जा सकता। सात वर्षों में 50 में से 46 ओ बी एम को 10 घंटों से कम अवधि के लिए उपयोग किया गया। प्रयोक्ता इकाइयों ने मोटरों के कम उपयोग के लिए नावों के साथ समायोजन का अभाव एवं उपलब्ध इलाके में प्रशिक्षण की न होने की गुंजाइश को जिम्मेदार ठहराया।

(पैराग्राफ 3.5)

कैटल पेरीमीटर फेंसिंग पर अनावश्यक व्यय

जेनरल ऑफिसर कमांडिंग (जी ओ सी), मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र ने दिल्ली छावनी में विवाहित अधिकारियों के आवास के चारों ओर कैटल पेरीमीटर फेंसिंग के निर्माण हेतु कार्य को खण्डशः संस्वीकृति प्रदान की, यद्यपि परिसर के चारों तरफ पहले से ही चारदीवारी मौजूद थी। जिसके परिणामस्वरूप 3.42 करोड़ रुपए का अनावश्यक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.6)

दोषपूर्ण उपकरणों की खरीद की वजह से नुकसान

महानिदेशक सैन्य आसूचना ने 20 फोटो अंकन प्रणालियों की अधिप्राप्ति में संविदा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रत्येक प्रणाली के लिए अलग-अलग निष्पादन बांड और वारंटी बांडों को स्वीकार किया था। ग्यारह प्रणालियां 3 से 22 महीने के अंदर निष्क्रिय हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप 21.88 करोड़ रुपए की हानि हुई। प्रणालियों की सुपुर्दगी तथा वारंटी अवधि के दौरान फर्म के खराब निष्पादन के बावजूद वारंटी बांडों को उनके नकदीकरण के बिना ही समाप्त होने दिया गया।

(पैराग्राफ 3.7)

केन्द्रीय आयुध डिपो आगरा एवं छावनी क्षेत्र देहरादूर की पूर्वी सीमा पर सुरक्षा दीवारों के आंशिक निर्माण पर 4.46 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय स्थल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में विफलता के कारण सुरक्षा दीवारों का केवल आंशिक निर्माण ही हो पाया और

इससे 4.46 करोड़ रुपए के निष्फल व्यय के अलावा केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा तथा छावनी क्षेत्र देहरादून की सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ा।

(पैराग्राफ 4.2 एवं 4.4)

कार्य के निष्पादन पर अनुचित व्यय

फस्ट-इन-फस्ट आऊट ऑपरेशन की प्रणाली पर कैंटीलीवर टाइप रैक्स की आवश्यकता के प्रति 2000 रैक्स लास्ट-इन-फस्ट-आऊट ऑपरेशन प्रणाली के साथ 5.58 करोड़ रुपए की लागत पर निर्माण कराये थे। इस प्रकार 5.88 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ। इसके अतिरिक्त, अनुचित विचलन आदेश देकर संविदाकार को 1.57 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ 4.3)

विद्युत प्रभारों के लिए 32.13 करोड़ का अधिक भुगतान

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एम एस ई डी सी एल) ने अगस्त 2012 में लोक सेवाएं प्रदान करने वाले उपभोक्ताओं, जिनमें रक्षा स्थापनाएं भी सम्मिलित थीं, के लिए एक नयी शुल्क-दर लागू की। एम एस ई डी सी एल ने इसके अतिरिक्त, लोक सेवाओं को श्रेणी में आने वाली सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं एवं अस्पतालों तथा अन्य रक्षा स्थापनाओं के लिए जून 2015 में एक अलग शुल्क-दर लागू की। तथापि, सात दुर्ग अभियंता, जिन्हें रक्षा शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों तथा अन्य रक्षा स्थापनाओं को आपूर्ति करने हेतु एम एस ई डी सी एल से थोक में विद्युत की प्राप्ति हुई, एम एस ई डी सी एल को भुगतान करने से पूर्व लगाई गई शुल्क-दर की परिशुद्धता की जांच करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप 32.13 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 4.5)

परिसंपत्तियों का उपयोग न होना

मुख्य अभियंता, बरेली द्वारा ड्राइंग्स में बाइपास सड़क का स्पष्ट प्रावधान करने और संविदा में पूर्ण कार्य क्षेत्र को शामिल करने में विफल होने के परिणामस्वरूप सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया था। परिणामस्वरूप, 7.65 करोड़ रुपए की लागत पर मई 2014 में निर्मित विस्फोटक डम्प का उपयोग नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ 4.6)

परिहार्य अतिरिक्त व्यय

वैधता अवधि के अंदर निविदाओं को स्वीकार करने में महानिदेशक, सीमा सड़क की विफलता तथा निविदा प्रलेखों की अपर्याप्तताओं के परिणामस्वरूप पुनः निविदाएं आमंत्रित करनी पड़ीं तथा 6.47 करोड़ रुपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.1)

एक एकीकृत ऐरोस्टेट निगरानी प्रणाली का विकास

ऐरोस्टेट निगरानी प्रणाली के विकास के लिए एक परियोजना के अंतर्गत डी आर डी ओ की प्रयोगशाला द्वारा 6.20 करोड़ रुपए की लागत पर एक गुब्बारे का आयात तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा, 49.50 करोड़ रुपए व्यय करने के बावजूद परियोजना अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकी।

(पैराग्राफ 6.1)

परियोजना के समापन के बाद वाहन परीक्षण ग्राउंड के निर्माण के लिए अनियमित संस्वीकृति और 5.20 करोड़ रुपए का व्यय

महानिदेशक, अनुसंधान एवं विकास ने 2.5 टन 'बी' वाहन पर विकसित किए जा रहे मानव-रहित ग्राउंड वाहन (यू जी वी) के परीक्षण की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति हेतु वाहन अनुसंधान एवं विकास स्थापना (वी आर डी ई) के मार्च 2005 के प्रस्ताव के आधार पर अप्रैल 2009 में 5.20 करोड़ रुपए की लागत पर वी आर डी ई, अहमदनगर में वाहन परीक्षण ग्राउंड के निर्माण के लिए संस्वीकृति प्रदान की। तथापि, यू जी वी परियोजना तब तक बंद हो चुकी थी। इसलिए, उस पर किया गया व्यय निष्फल हो गया है, क्योंकि परीक्षण ग्राउंड का लाभकर उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सेना की आवश्यकता 50 कि.ग्रा. यू जी वी की है, जिसके लिए वी आर डी ई का वर्तमान परीक्षण ट्रैक पर्याप्त होगा।

(पैराग्राफ 6.2)

19.53 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय

सेना की मांग के अनुसार 1200 मी. और 1500 मी. की दूरी में मिसाइल को प्रदर्शित करने के लिए युद्ध वाहन अनुसंधान एवं विकास स्थापना (सी वी आर डी ई), आवाड़ी ने 20 एल ए एच ए टी मिसाइलों की अधिप्राप्ति की। मिसाइल की स्थिरता से संबंधित

तकनीकी कमियों के कारण विदेशी आपूर्तिकर्ता के प्रतिबंध के बावजूद यह अधिप्राप्ति की गई थी। प्रदर्शन परीक्षणों के दौरान 1200 मी. से 1500 मी. के निर्धारित मानक/दूरी प्राप्त करने में मिसाइलें विफल रहीं। सेना ने उस मिसाइल को लेने से इंकार किया। इस प्रकार, आपूर्तिकर्ता को किया गया 19.53 करोड़ रुपए का भुगतान निष्फल हुआ।

(पैराग्राफ 6.3)

आयुध फैक्ट्री संगठन

आयुध फैक्ट्री बोर्ड का कार्यनिष्पादन

आयुध फैक्ट्रियां पांच प्रचालन समूहों में विभक्त कुल 41 फैक्ट्रियां कार्यरत हैं जो रक्षा सेवाओं के लिए हर प्रकार के शस्त्र, गोलाबारूद, हथियार, शस्त्रसज्जित एवं पैदल युद्धक वाहन तथा पैराशूट सहित वस्त्र मदों का उत्पादन करती हैं। वे आयुध फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत कार्य करती हैं।

अपने राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय को क्रमशः पूरा करने के लिए 2015-16 में बोर्ड ने 14,750 करोड़ रुपए और 687 करोड़ रुपए का बजट अनुदान प्राप्त किया। पिछले पांच वर्षों के दौरान दोनों राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में बढ़ोत्तरी का रुझान देखने को मिलता है।

2015-16 के दौरान क्रमशः 57 प्रतिशत, 11 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 30 प्रतिशत पर भंडारों, श्रम, प्रत्यक्ष खर्चों और उपरिव्यय लागतों के अंश के साथ बोर्ड पर उत्पादन लागत 18,294 करोड़ रुपए था। 2014-15 की अपेक्षा उत्पादन लागत ने 11 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दिखाई। 2011-16 की अवधि के दौरान, प्रतिवर्ष औसत उपरिव्यय प्रभार 4674 करोड़ रुपए था जो आयुध फैक्ट्री संगठन के औसत वार्षिक उत्पादन लागत (16,462 करोड़ रुपए) का लगभग 28 प्रतिशत था। 2011-12 से 2015-16 के दौरान कुल उपरिव्यय लागत का 60 से 70 प्रतिशत भाग पर्यवेक्षण प्रभार तथा अप्रत्यक्ष श्रम लागत का था, जो उपरिव्यय के प्रमुख अवयव हैं।

निर्गम का मूल्य 2014-15 के 16,664 करोड़ रुपए से 12 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में 18,624 करोड़ रुपए हो गया। 2015-16 के दौरान कुल निर्गम के 80 प्रतिशत के साथ आयुध फैक्ट्रियों के उत्पादों का प्रमुख मांगकर्ता थल सेना है। 2014-15 के 161 करोड़ रुपए के आधिक्य के प्रति 2015-16 में थलसेना को निर्गम में 128 करोड़ रुपए की हानि हुई। यद्यपि, 2015-16 में कुल रक्षा

निर्गम में 91 करोड़ रुपए की हानि दर्ज की गई, उनके निर्गम में हुई हानि आई.एफ .डी. फैक्ट्रियों के आधिक्य से समायोजित हो गई (227 करोड़ रुपए) जिसके परिणामस्वरूप 2015-16 में 167 करोड़ रुपए का सम्पूर्ण लाभ हुआ।

(पैराग्राफ 7.1)

आयुध फैक्ट्रियों में आयात अनुबंध का प्रबंधन

आयुध फैक्ट्रियां संयंत्र एवं मशीनरियों के एवं उसके भंडारों के अत्यंत महत्वपूर्ण भागों का आयात करती हैं। 2012-15 के दौरान पांच फैक्ट्रियों द्वारा सम्पन्न किए गए चयनित आयात अनुबंधों के लेखापरीक्षा परीक्षण ने यह उजागर किया कि अनुबंध से पूर्व के साथ-साथ अनुबंध के पश्चात के चरणों में अनुबंधों के प्रबंधन में कमियां थीं।

लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि परक्रामण एवं पूर्वापेक्षित समय-सारणी के भीतर प्रस्तावित 28 परीक्षण जांच किए गए आपूर्ति आदेशों में से केवल 2 आपूर्ति आदेशों का अनुमोदन लेने में असंगत समय लिया गया था। परक्रामण एवं अनुमोदन के लिए गए समय में ह्रास के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा निर्देशित कलीजिएट समिति के गठन के लिए प्रावधान को अधिप्राप्ति नियम पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त दो आदेशों में लागत अनुमान के साथ 'निर्णीत हर्जाने' के अनुबंध से संबंधित उसे समावेशित न करने के कारण फैक्ट्रियों को आपूर्तिकर्ताओं से भंडारों के सही समय में सुपुर्दगी प्रचलित न कर पाने पर उन्हें कमजोर प्रतिपादित किया गया।

2 से 17 महीनों तक किए गए आपूर्ति में भी विलंब हुआ: आठ मामलों में फैक्ट्रियों द्वारा एल.सी. को खोलने/प्रेषण पूर्व निरीक्षण (पी.डी.आई.) को सम्पन्न करने में विलंब हुआ तथा बचे हुए मामलों में आपूर्तिकर्ताओं के कारण हुआ। हमने दोनों सात से दस महीनों तक निपटान के लिए बचे हुए 2.24 करोड़ रुपए की कीमत के गुणवत्ता दावे के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उसी के अनुवर्ती विश्लेषण और फैक्ट्रियों द्वारा गुणवत्ता दावे के संदर्भ में हुए विलंब के घटनाओं को देखा। ओ.एफ.बी. गुणवत्ता दावे के लिए विलंब के साथ-साथ विलंबित आपूर्ति के लिए एल.डी. के एक प्रावधान को सम्मिलित कर विचार-विमर्श कर सकता है।

(पैराग्राफ 7.2)

सी.एन.सी. मशीनों के चलन के बाद श्रम अनुमानों में संशोधन न करना एवं उजरती कार्य लाभ का गलत

आयुध फैक्ट्रियों को कम्प्यूटर नियंत्रित संख्यानुसार (सी.एन.सी.) मशीनों के समावेशन के पश्चात श्रम अनुमानों को संशोधित करने की आवश्यकता है। उत्पादन के प्रत्येक मद के लिए अनुमान इकाई श्रम लागत को परिमाणित करता है एवं श्रम नियोजन, परिनियोजन और लागतों पर नियंत्रण के लिए एक नमूने के रूप में कार्य करता है। परंतु परीक्षित किए गए दो-तिहाई प्रतिदर्श मामलों में चयनित चार फैक्ट्रियों ने श्रम अनुमानों का संशोधन नहीं किया था।

बोर्ड द्वारा दिए गए प्रतिमानों के व्यतिक्रम में दो फैक्ट्रियों ने 2013-14 और 2014-15 में उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक श्रम घंटों (एस.एम.एच.) का अतिरिक्त आंकलन किया। सभी चार फैक्ट्रियों ने 2012-15 के दौरान अनुचित प्रतिमानों का प्रयोग करते हुए 10 में से आठ मामलों में उपलब्ध एस.एम.एच. को कम आंका। लक्षित एस.एम.एच. के अविश्वसनीय होने पर फैक्ट्रियों में श्रम नियोजन उस हद तक त्रुटिपूर्ण था। एस.एम.एच., इशापुर में 102 में से 99 मामलों में तीन उत्पादन कारखानों में वास्तविक परिणामी एस.एम.एच. प्रतिवेदित किए गए से कम था। परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष औद्योगिक कर्मचारियों को समुदित 2.60 करोड़ रुपए के उजरती कार्य लाभ (पी.डब्ल्यू.पी) को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त सभी चार फैक्ट्रियों में अप्रत्यक्ष कर्मचारियों को (पी.डब्ल्यू.पी के लिए अनुपयुक्त) दिए गए पी.डब्ल्यू.पी. के भुगतानों पर भी ध्यान दिया गया।

वाह्यश्रोतिकरण के बावजूद भी अनुमानों के आधार पर अंतर्वर्ती आई.ई. को भुगतान किए गए जिसमें से वाह्यश्रोतिकृत तत्व को (एस.एम.एच. के रूप में) व्यकलित नहीं किया गया था। इसके कारण 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रतिदर्श मदों के लिए दो फैक्ट्रियों में आई.ई. को 10.94 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

(पैराग्राफ 7.3)

निर्माण अधिपत्रों का प्रबंधन

निर्माण अधिपत्र फैक्ट्री को दिए गए कार्य के उत्तरदायित्व के श्रम के परिनियोजन के लिए उत्पादन कारखाने के आयुध फैक्ट्री प्रबंधन का प्राधिकार है। यह अनुमान पर आधारित आदेशित परिमाणों के निर्माण के लिए आवश्यक प्राधिकृत मानक श्रम घंटों (एस.एम.एच)

के संख्या को अभिलेखित करता है।

अपने मुद्दे के अनुबंधित छह: महीनों से अधिक अनावश्यक लंबे अवधि के लिए अधिपत्रों को खुला रखने पर अनाधिकृत समायोजन को अनुमति देने का पूरा खतरा रहता है। चार प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में 2012-13 और 2014-15 के दौरान जारी एवं लेखा परीक्षा में 693 प्रतिदर्शित अधिपत्रों में से केवल 189 (27 प्रतिशत) को छह: महीनों की अवधि में बंद किया गया था। जबकि अनुबंधित अवधि के पश्चात बचे हुए 403 (80 प्रतिशत) अधिपत्रों को बंद किया गया था, वहीं 101 अधिपत्र (15 प्रतिशत) अभी भी खुले हुए थे तथा समापन की प्रतीक्षा (मार्च 2015) कर रहे थे। खुले अधिपत्र फैक्ट्रियों को स्थानांतरण वाउचरों के द्वारा अन्य अधिपत्रों के लिए अतिरिक्त श्रम को लेना या अतिरिक्त सामग्री का स्थानांतरण या अधिपत्रों के लिए अस्वीकृतियों के फैलाव (साधारण अस्वीकृत सीमाओं के भीतर रखने के लिए) के लिए अवसर प्रदान करते हैं। आवश्यक आंतरिक नियंत्रणों का अनुगमन न करते हुए फैक्ट्रियों में स्थानांतरण वाउचरों का प्रयोग किया जा रहा था।

(पैराग्राफ 7.4)

दोषयुक्त रेडिएटर्स की अधिप्राप्ति

भारी वाहन फैक्ट्री (एच यू वी) अवाडी ने, टी-90 में संयोजित होने वाले टैंकों के रेडिएटर्स के लिए एक ऐसी फर्म को आदेश प्रस्तुत किया जिसे आवश्यक रेडिएटर्स के निर्माण का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। फैक्ट्री ने 2.78 करोड़ रुपए मूल्य के रेडिएटर, जो कि निर्धारित तकनीकी आवश्यकता को पूरा नहीं करते थे, को स्वीकृत कर लिया जिसके कारण टी-90 टैंक, जिनमें ये रेडिएटर संयोजित थे, थलसेना द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए।

(पैराग्राफ 7.5)

अपूर्ण अन्वेषण में विलंब के कारण खाली फ्यूज ए-670 एम के अस्वीकृति के लिए 31.32 करोड़ रुपए की परिहार्य हानि

2008-09 से दो फैक्ट्रियों में खाली फ्यूज ए-670 एम के उत्पादन में बारंबार असफलता के बावजूद भी ओ.एफ.बोर्ड ने अप्रैल 2014 में ही संयुक्त दल का गठन किया जा जुलाई 2016 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता था। इस दौरान उत्पादन जारी रहा और जुलाई 2016 तक दो फैक्ट्रियों में 31.32 करोड़ रुपए मूल्य के खाली फ्यूज ए-670 एम अस्वीकृत रूप में पड़े रहे।

(पैराग्राफ 7.6)

पूर्ववर्ती अस्वीकृति के यथार्थ कारणों को निरूपित करने में विफलता के कारण परिहार्य अस्वीकरण

अस्वीकृति के यथार्थ कारणों के सही पहचान में आयुध निर्माणियां एवं गुणवत्ता गारन्टी अधिष्ठान की विफलता के परिणामस्वरूप 2013-16 के दौरान 10.02 करोड़ रुपए मूल्य के अनेको 105 एम.एम.एच.ई. उपकरण का लगातार अस्वीकरण।

(पैराग्राफ 7.7)

महंगी मशीनों की परिहार्य अधिप्राप्ति

लक्ष्यों को प्राप्त करने के वर्तमान क्षमता के बावजूद राफइल फैक्ट्री इशापुर द्वारा 9.32 करोड़ रुपए के कुल लागत के दो सामग्री से लैस किए हुए सी.एन.सी. मशीनों की खरीददारी की गई। विशेष उद्देश्य उपकरण की प्राप्ति के लिए (अप्रैल 2016 तक) जुलाई 2014 से एक सामग्री से लैस मशीन क्रियान्वित नहीं रही और दो अव्यवों के उत्पादन में लगे हुए अन्य मशीन के उपयोग का पूर्वक्षण काफी कम दर पर व्यवसाय से इन अव्यवों के अधिप्राप्ति के संबंध में भी निराशाजनक है।

(पैराग्राफ 7.8)

टैंक टी-72 के बी.एल.टी. रूपांतर के उत्पादन में विलंब

मांगपत्र के अनुसार, 2012-17 के दौरान चरणबद्ध रूप में एच.वी. एफ. अवाडी से टी-72 ब्रिज लेंडिंग टैंको (बी.एल.टी.) के रूपांतरों की आपूर्ति पूर्वनिर्धारित थी। बुनियादी ढांचे की परियोजना की पूर्णता में देरी एवं टी-72 बी.एल.टी. की मुहरबंद डिजाइन में बार-बार किए जाने वाले परिवर्तनों के कारण एच.वी.एफ., टी-72 बी.एल.टी. रूपांतरों का उत्पादन अब तक शुरू नहीं कर सका एवं इसलिए कवचित रेजीमेंटों के प्रगामी टैंक स्तंभ इस सीमा तक अपूर्ण रहे।

(पैराग्राफ 7.9)

परिशिष्ट IV

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों/ लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों के संबंध में वर्ष 2017-18 के लिए की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों की स्थिति

क्रम संख्या	वर्ष	लोक लेखा समिति की रिपोर्टों/पैराओं के ब्यौरे जिनपर 31.1.2017 की स्थिति के अनुसार एटीएन लंबित हैं।				लंबित लेखा परीक्षा पैराओं की कुल संख्या
		उन एटीएन की संख्या जो लेखा परीक्षा को मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजी गई	लेखा परीक्षा को पुनरीक्षा के लिए भेजी गई ए टी एन की संख्या	उन ए टी एन एस की संख्या जो भेजी गई लेकिन अभ्युक्तियों के साथ वापस भेज दी गई और लेखा परीक्षा जिनकी मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा कर रहा है		
1	1991	0	0	0	0	
2	1993	0	0	0	0	
3	1997	0	0	0	0	
4	1998	0	0	0	0	
5	2001	0	0	1	1	
6	2003	0	0	0	1	
7	2004	0	0	1	1	
8	2005	0	0	1	1	
9	2006	0	0	0	0	
10	2007	0	0	1	1	
11	2008	0	0	0	0	
12	2009	0	0	2	2	
13	2010	0	0	1	1	
14	2011	0	1	5	6	
15	2012	0	0	1	1	
16	2013	0	2	3	5	
17	2014	0	12	3	15	
18	2015	0	9	9	18	
19	2016	0	4	8	12	
20	2017	21	12	12	45	
	कुल	21	41	48	110	



आईएनएस सतपुड़ा से पनडुब्बीरोधी रॉकेट की फायरिंग

पिछला कवर— आर्टिलरी मिसाइलों की लांचिंग

